भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

अक्टूबर 2022

खंड 76 अंक 10

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
अजित आर. जोशी
देब प्रसाद रथ
मुनिश कपूर
रेखा मिश्र
इन्द्रनील भट्टाचार्य
स्नेहल हेरवाडकर
पंकज कुमार
तुषार बरन दास
वी. धन्या
श्वेता कुमारी
सुजाता कुंडू

संपादक
जी. वी. नथनएल

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के
निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा
मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए
बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है।
हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए
लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2022

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
https://bulletin.rbi.org.in पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य 1

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प सितंबर 28-30, 2022 7

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 11

मौद्रिक नीति रिपोर्ट

मौद्रिक नीति रिपोर्ट - सितंबर 2022 13

भाषण

गुणात्मक ताकत के रूप में फिनटेक
शक्तिकांत दास 107

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 113

भारत के लिए हरित सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 149

वित्तीय डोमेन में 'बिगटेक': प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को संतुलित करना 165

डेट म्यूचुअल फंड में बाज़ार प्रतिलाभ और प्रवाह 177

भारत में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय देयताएं - एक आकलन 193

वर्तमान सांख्यिकी 207

हाल के प्रकाशन 260

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य

*गवर्नर का वक्तव्य**

शक्तिकांत दास

पिछले ढाई वर्षों में, दुनिया ने दो बड़े झटके देखे हैं – कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में संघर्ष। इन झटकों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसे कि वह पर्याप्त नहीं था, अब हम एक तीसरे बड़े झटके के बीच में हैं - एक तूफान – जो आक्रामक मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और उन्नत अर्थव्यवस्था (एई) केंद्रीय बैंकों से और भी अधिक आक्रामक संचार से उत्पन्न हो रहा है। इस तरह की कार्रवाइयों की आवश्यकता उनके घरेलू विचारों से प्रेरित होती है, लेकिन एक अत्यधिक एकीकृत वैश्विक वित्तीय प्रणाली में, वे अनिवार्य रूप से वैश्विक स्पिलओवर के माध्यम से नकारात्मक बाहरीपन का कारण बनते हैं। हाल ही में तेज दरों में बढ़ोतरी और आगे की बड़ी दर वृद्धि के बारे में आगे के मार्गदर्शन ने वित्तीय स्थितियों को कड़ा कर दिया है, अत्यधिक अस्थिरता हुई है और जोखिम विमुखता हुई है। इक्विटी, बॉन्ड और मुद्रा बाजार सहित वित्तीय बाजार के सभी खंड पूरे देश में उथल-पुथल में हैं। वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के संभावित परिणामों के साथ वित्तीय बाजारों में घबराहट है। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नए तूफान की नज़र में है।

इस अस्थिर वैश्विक वातावरण के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी लचीली बनी हुई है। व्यापक आर्थिक स्थिरता है। बेहतर प्रदर्शन मानकों के साथ वित्तीय प्रणाली बरकरार है। देश ने कोविड-19 और यूक्रेन में संघर्ष के झटकों को झेला है। पिछले ढाई वर्षों की हमारी यात्रा, विभिन्न चुनौतियों से निपटने का हमारा दृढ़ संकल्प हमें इस नए तूफान से निपटने का विश्वास दिलाता है जिसका हम सामना कर रहे हैं।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 28, 29 और 30 सितंबर 2022 को हुई। समष्टि आर्थिक स्थिति और इसकी संभावना के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने छह में से पांच सदस्यों के बहुमत से तत्काल प्रभाव से नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंक से 5.9 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.65 प्रतिशत; और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 6.15 प्रतिशत तक समायोजित हो गई है। एमपीसी ने 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति संवृद्धि का समर्थन करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

अब मैं नीतिगत दर और रुख पर एमपीसी के निर्णयों के औचित्य के बारे में बताऊंगा। वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण निराशाजनक बना हुआ है। वित्तीय स्थितियां सख्त हो रही हैं और मंदी की आशंका बढ़ रही है। पूरे क्षेत्राधिकार में मुद्रास्फीति खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर बनी हुई है। महामारी और भू-राजनीतिक संघर्ष के स्थायी प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं की मांग-आपूर्ति बेमेल में प्रकट हो रहे हैं। केंद्रीय बैंक आक्रामक दरों में बढ़ोतरी के साथ नए क्षेत्र की योजना बना रहे हैं, भले ही इसके लिए निकट अवधि में संवृद्धि का त्याग करना पड़े। इस माहौल में, घबराए हुए निवेशक की भावनाओं ने सुरक्षा की उड़ान शुरू कर दी है। अमेरिकी डॉलर दो दशक के उच्च स्तर पर तेजी से मजबूत हुआ है। कई उन्नत और उभरती बाजार मुद्राएं तेज मूल्यह्रास दबावों का सामना कर रही हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई), विशेष रूप से, वैश्विक संवृद्धि में धीमी गति, खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि, उन्नत अर्थव्यवस्था नीति सामान्यीकरण से स्पिलओवर, ऋण संकट और तेज मुद्रा मूल्यह्रास की चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत में आर्थिक गतिविधियां स्थिर बनी हुई हैं। जबकि 2022-23 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि हमारी उम्मीदों से कम रही, खरीफ की बुवाई में देर से सुधार, आरामदायक जलाशय स्तर, क्षमता उपयोग में सुधार, तेज़ बैंक ऋण विस्तार और पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर से 2022-23 की दूसरी छमाही में कुल मांग और उत्पादन के लिए समर्थन की उम्मीद है।

* गवर्नर का वक्तव्य – 30 सितंबर 2022

गवर्नर का वक्तव्य

बड़े प्रतिकूल आपूर्ति झटके, घरेलू मांग में कुछ मजबूती और वैश्विक वित्तीय बाजारों से स्पिलओवर के कारण, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ऊपर और लक्ष्य के ऊपरी सहिष्णुता बैंड से ऊपर बनी हुई है। कच्चे तेल सहित वैश्विक पण्य कीमतों में हालिया सुधार, यदि जारी रहता है, तो आने वाले महीनों में लागत दबाव कम हो सकता है। भू-राजनीतिक तनावों और घबराई वैश्विक वित्तीय बाजार की भावनाओं से उत्पन्न अनिश्चितताओं के साथ मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र धूमिल बना हुआ है।

इस पृष्ठभूमि में, एमपीसी का विचार था कि उच्च मुद्रास्फीति के बने रहने से मूल्य दबावों के विस्तार को रोकने, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर करने और दूसरे दौर के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक निभाव को और अधिक मात्रा में वापस लेने की आवश्यकता होगी। यह कार्रवाई मध्यम अवधि की संवृद्धि की संभावनाओं का समर्थन करेगी। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.9 प्रतिशत करने और संवृद्धि को समर्थन देते हुए निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।

मैं एक कदम पीछे हटकर अपने मौद्रिक नीति रुख के बारे में विस्तार से बताता हूं। जून 2019 में मौद्रिक नीति तटस्थ से निभावकारी रुख बनी । उस समय, रेपो दर 5.75 प्रतिशत था ; हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति लगभग 3 प्रतिशत रहा था और 2019-20 की दूसरी छमाही में 3.4 से 3.7 प्रतिशत की सीमा में रहने की उम्मीद थी; और, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत मई 2019 में ₹0.3 लाख करोड़ के औसत दैनिक शुद्ध अंतर्वेशन के साथ, चलनिधि घाटे की स्थिति में थी। आज, मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत के आसपास मँडरा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि यह 2022-23 की दूसरी तिमाही में लगभग 6 प्रतिशत के ऊपर बनी रहेगी। सितंबर 2022 (28 सितंबर तक) में एलएएफ के तहत ₹1.1 लाख करोड़ के औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण के साथ चलनिधि अधिशेष बनी हुई है। जैसे-जैसे उच्च जीएसटी और प्रत्यक्ष कर संग्रह के कारण सरकारी खर्च बढ़ता है, प्रणालीगत चलनिधि और भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार, भले ही अब तक (आज की वृद्धि सहित) सांकेतिक नीति रेपो दर में 190 आधार अंकों की वृद्धि की गई है, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नीति दर 2019 के स्तर की है। इसलिए, समग्र मौद्रिक और चलनिधि स्थितियां निभावकारी बनी हुई हैं और इसलिए, एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

संवृद्धि

2022-23 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 13.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो पूर्व-महामारी के 3.8 प्रतिशत के स्तर से अधिक है। यह निजी खपत और निवेश मांग में मजबूत वृद्धि के कारण हुआ।

दूसरी तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति डेटा इंगित करते हैं कि आर्थिक गतिविधि लचीली बनी हुई है। निजी खपत में तेजी आई है। शहरी मांग में निरंतर पुनरुद्धार हो रहा है, जिसे कोविड-19 के साथ रहने के ढाई साल के बाद आने वाले त्योहारों के निरंकुश उत्सव से और गति मिलनी चाहिए। ग्रामीण मांग भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। निवेश की मांग बढ़ रही है और यह जुलाई और अगस्त में घरेलू उत्पादन और पूंजीगत वस्तुओं के आयात की मजबूत वृद्धि से स्पष्ट है। 9 सितंबर 2022 को बैंक ऋण 16.2 प्रतिशत की त्वरित गति से बढ़ा, जबकि एक वर्ष पहले यह 6.7 प्रतिशत था। बैंकों और गैर-बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह, पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹1.7 लाख करोड़ से इस वित्तीय वर्ष में अब तक (9 सितंबर तक) ₹9.3 लाख करोड़ हो गया है। आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र की मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग 2021-22 की चौथी तिमाही में 73.0 प्रतिशत से बढ़कर Q1: 2022-23 की पहली तिमाही में 74.3 प्रतिशत हो गया - यह तीन वर्षों में इसका उच्चतम स्तर है[1]। तेल से इतर एवं स्वर्ण से इतर का आयात लचीला रहा, जो घरेलू मांग में निरंतर पुनरुद्धार का संकेत देता है। हालांकि, व्यापारिक निर्यात वृद्धि को अस्थिर बाहरी वातावरण में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

आपूर्ति पक्ष में कृषि क्षेत्र लचीला बना हुआ है। 29 सितंबर को मॉनसून की बारिश लंबी अवधि के औसत (एलपीए) से 7 प्रतिशत

[1] यह मौसमी पैटर्न को दर्शाते हुए इसी अवधि में असमायोजित क्षमता उपयोग में 75.3 प्रतिशत से 72.4 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद है।

गवर्नर का वक्तव्य

अधिक थी। खरीफ की बुवाई 23 सितंबर को सामान्य बुवाई क्षेत्र से 1.7 प्रतिशत अधिक थी। पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन पिछले वर्ष के पहले अग्रिम अनुमान से केवल 0.4 प्रतिशत कम है। 29 सितंबर 2022 को जलाशय का स्तर पूरी क्षमता का 87 प्रतिशत है, जबकि दशकीय औसत 77 प्रतिशत है। यह आगामी रबी फसल के लिए शुभ संकेत है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि में परिलक्षित औद्योगिक गतिविधि, जुलाई में घटकर 2.4 प्रतिशत हो गई। हालांकि, भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अगस्त में 56.2 पर निरंतर विस्तार का संकेत देता है। जैसा कि विनिर्माण पीएमआई में परिलक्षित होता है, कारोबारी धारणा छह वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर आशावाद के साथ मजबूत हुई।

सेवा क्षेत्र के संकेतक[2] जुलाई और अगस्त में मजबूत वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। अगस्त में सेवाओं का पीएमआई 57.2 पर पहुंच गया, जो जुलाई में 55.5 था। व्यापार विश्वास 51 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

आगे देखते हुए, इन सभी कारकों[3] को समग्र मांग और गतिविधि का समर्थन करना चाहिए। विस्तारित भू-राजनीतिक तनावों, सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियां और कुल मांग के बाहरी घटक में संभावित गिरावट से, संवृद्धि के लिए अधोगामी जोखिम उत्पन्न हो सकती है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.0 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत पर; और 2022-23 की चौथी तिमाही में 4.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम व्यापक रूप से संतुलित हैं। 2023-24 की पहली तिमाही के लिए विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति

वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियां घरेलू मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र पर भारी पड़ रहे हैं। अगस्त में मुद्रास्फीति बढ़कर 7.0 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 6.7 प्रतिशत थी।

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में महसूस किए गए तीव्र आयातित मुद्रास्फीति दबाव में कमी आई है, लेकिन यह खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं में ऊंचा बना हुआ है। प्रमुख उत्पादक देशों से बेहतर आपूर्ति और सरकार द्वारा किए गए उपायों से खाद्य तेल मूल्य दबाव नियंत्रित रहने की संभावना है। आगे चलकर आपूर्ति की स्थिति में नरमी और औद्योगिक धातु तथा कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण बिक्री मूल्य वृद्धि में कुछ कमी आ सकती है। तथापि, सेवा गतिविधियों में मजबूत वापसी और मूल्य निर्धारण शक्ति में कुछ सुधार के साथ, इनपुट लागत के उच्च प्रभाव अंतरण का जोखिम बना हुआ है।

खाद्य कीमतों में ऊर्ध्वगामी वृद्धि का भी जोखिम है। खरीफ धान का उत्पादन कम होने की संभावना के कारण अनाज की कीमतों का दबाव गेहूं से चावल में फैल रहा है। खरीफ दलहन की कम बुवाई से भी कुछ दबाव हो सकता है। मानसून का देरी से जाना और विभिन्न क्षेत्रों में तेज बारिश ने सब्जियों की कीमतों, खासकर टमाटर की कीमतों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। खाद्य मुद्रास्फीति के लिए ये जोखिम मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमत 2022-23 की पहली छमाही में लगभग 104 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। आगे, हम अब इसका आकलन 2022-23 की दूसरी छमाही में 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कर रहे हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, जोखिमों के समान रूप से संतुलन के साथ, मुद्रास्फीति अनुमान 2022-23 में 6.7 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 7.1 प्रतिशत पर; तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत पर; और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है । सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 की पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है।

असाधारण वैश्विक परिस्थितियों, जिनके कारण मुद्रास्फ़ीतिकारी दबाव बढ़े हैं, ने एई और ईएमई दोनों को प्रभावित किया है। तथापि, भारत इनमें से कई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। यदि उच्च मुद्रास्फीति को देर तक रहने दिया जाता है, तो यह सदैव दूसरे क्रम के प्रभावों को उत्प्रेरित करता है और प्रत्याशाओं को अस्थिर करता है। अतः, मौद्रिक नीति को नीतिगत दरों और चलनिधि स्थितियों पर अपनी

[2] रेलवे माल ढुलाई ट्राफिक; बंदरगाह माल ढुलाई ट्राफिक; घरेलू हवाई यात्री ट्राफिक; ई-वे बिल; टोल संग्रह, आदि।

[3] खरीफ की बुवाई में सुधार, पर्याप्त जलाशय स्तर, विवेकाधीन खर्च में वृद्धि, कमोडिटी की कीमतों में कमी, कैपेक्स पर सरकार का निरंतर जोर, विनिर्माण में क्षमता उपयोग में सुधार, बैंक ऋण में वृद्धि और कोविड-19 संक्रमण में कमी।

गवर्नर का वक्तव्य

कैलिब्रेटेड कार्रवाई को विकसित हो रही मुद्रास्फीति संवृद्धि गतिशीलता के अनुरूप आगे बढ़ाना होगा। इसे सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य में मार्च 2022 की तुलना में चरणबद्ध तरीके से (28 सितंबर तक) 196 बीपीएस की संचयी रूप से वृद्धि हुई है। यह एसडीएफ और रेपो दर पर हमारी कार्रवाइयों के अनुरूप है। परिणामस्वरूप, वित्तीय बाजार विविधता[4] में ब्याज दरों में वृद्धि हुई है, हालांकि यह अलग-अलग स्तरों पर हुआ है।

बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि, जैसा कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) [एसडीएफ और परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों दोनों] के अंतर्गत औसत दैनिक अवशोषण में परिलक्षित होता है, जून-जुलाई के दौरान ₹3.8 लाख करोड़ से अगस्त-सितंबर 2022 (28 सितंबर तक) के दौरान कम होकर ₹2.3 लाख करोड़ हो गया। विदेशी मुद्रा बहिर्वाह के साथ जीएसटी और अग्रिम कर भुगतान ने सितंबर के तीसरे सप्ताह में अधिशेष चलनिधि की स्थिति को नियंत्रित किया। इससे बैंकों को सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का सहारा लेना पड़ा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामियों के माध्यम से चलनिधि अंतर्वेशन की आवश्यकता पड़ी। अधिशेष चलनिधि के इस अस्थायी कमी को सरकारी खर्च में अपेक्षित वृद्धि, जो आमतौर पर वर्ष की दूसरी छमाही में होती है, से उत्पन्न होने वाली प्रणाली में बृहत संभावित चलनिधि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, अतिरिक्त आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और बैंकों की अतिरिक्त सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) धारिताओं की कमी भी प्रणाली में चलनिधि को बढ़ा सकती है।

अक्टूबर 2021 के अपने नीति वक्तव्य में, मैंने कहा था कि भारतीय रिज़र्व बैंक 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामियों के माध्यम से किए जाने वाले पाक्षिक मुख्य परिचालन को उभरती चलनिधि स्थितियों के आधार पर 28-दिवसीय वीआरआरआर नीलामियों से पूरक प्रदान करेगा। अधिशेष चलनिधि में कमी को देखते हुए, अब 28-दिवसीय वीआरआरआर को पाक्षिक 14-दिवसीय मुख्य नीलामी के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, अब से केवल 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी आयोजित की जाएगी। समय-समय पर आवश्यक होने पर चलनिधि के अवशोषण के साथ-साथ अंतर्वेशन के लिए विभिन्न परिपक्वताओं का परिष्कृत कार्य परिचालन जारी रहेगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (28 सितंबर तक) के दौरान, प्रमुख मुद्रा समूह के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे विश्व स्तर पर मुद्रा बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है। तथापि, भारतीय रुपये (आईएनआर) में उतार-चढ़ाव अधिकांश अन्य देशों की तुलना में व्यवस्थित रही है। इसी अवधि के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसमें 7.4 प्रतिशत की गिरावट आई है - जो कई आरक्षित मुद्राओं के साथ-साथ कई ईएमई और एशियाई मुद्राओं की तुलना में काफी बेहतर है।

एक स्थिर विनिमय दर, वित्तीय और समग्र समष्टि आर्थिक स्थिरता और बाजार विश्वास की द्योतक होती है। हाल के दिनों में, रुपये की विनिमय दर और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता पर अलग-अलग विचार रहे हैं। मैं पुनः समग्र स्थिति के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहला, रुपया एक स्वतंत्र चलायमान मुद्रा है और इसकी विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोई निश्चित विनिमय दर निर्धारित नहीं की है। यह अत्यधिक अस्थिरता को रोकने और प्रत्याशाओं को स्थिर करने के लिए बाजार में मध्यक्षेप करता है। व्यापक ध्यान समष्टि आर्थिक स्थिरता और बाजार के विश्वास को बनाए रखने पर है। जैसा कि जुलाई से पूंजी प्रवाह की वापसी में परिलक्षित होता है, हमारी कार्रवाइयों ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में मदद की है। मध्यम अवधि में, हमारे लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) ढांचे में अंतर्निहित मूल्य स्थिरता की प्रधानता विनिमय दर स्थिरता के लिए सहारा प्रदान करती है। तीसरा, विदेशी मुद्रा बाजार में हमारे मध्यक्षेप हमारे दृष्टिकोण, जिसे मैंने अभी समझाया है, के सापेक्ष मौजूदा और विकसित हो रही परिस्थिति के निरंतर मूल्यांकन पर आधारित हैं। विदेशी मुद्रा

[4] 91-दिवसीय खजाना बिल, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और जमा प्रमाणपत्र (सीडी), बॉण्ड प्रतिफल। (दरों में बढ़ोतरी ने बैंकों की बेंचमार्क उधार दरों में ऊर्ध्वगामी समायोजन भी उत्प्रेरित किया। साथ में, सावधि जमा दरों में भी वृद्धि हुई है क्योंकि बैंक बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।)

गवर्नर का वक्तव्य

भंडार की पर्याप्तता के पहलू को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। छत्र मजबूत बना हुआ है।

महामारी के दौरान, रिज़र्व बैंक की संचार कार्यनीति में आगे के मार्गदर्शन को प्रमुखता मिली। यह बाजार की प्रत्याशाओं को स्थिर करने में मददगार था। तथापि, एक नीति को सख्त करने के चक्र में, विशेष रूप से अत्यधिक अनिश्चित वातावरण में, निरंतर आगे का मार्गदर्शन प्रदान करना मुश्किल है। वास्तव में, आगे का मार्गदर्शन वित्तीय बाजारों को अस्थिर भी कर सकता है। दर सख्ती चक्र में अक्सर चरम और अंतिम दरों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी आगे का मार्गदर्शन, जो वर्तमान संदर्भ में खतरनाक हो सकता है, में शामिल हुए बिना, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी कार्रवाइयों को नीति निर्माण के लिए पारंपरिक या किसी पाठ्यपुस्तक दृष्टिकोण से बाधित हुए बिना प्राप्त आंकड़ों और विकसित होने वाले परिदृश्य में सावधानी से अंशशोधित किया जाएगा।

बाह्य क्षेत्र

2022-23 की पहली तिमाही के लिए चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के 2.8 प्रतिशत पर और व्यापार घाटा जीडीपी के 8.1 प्रतिशत पर रखा गया है। वैश्विक पीएमआई सहित विभिन्न प्रमुख संकेतक वैश्विक संवृद्धि की गति के कमजोर होने और वैश्विक व्यापार में अधोगामी जोखिम की ओर इशारा करते हैं। भारत की आयात संवृद्धि, यद्यपि मंद[5] हो रही है, निर्यात संवृद्धि से आगे निकल गई। परिणामस्वरूप, जुलाई-अगस्त 2022 में व्यापार घाटा उच्च बना रहा। सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं की आघात-सह मांग और यात्रा सेवाओं में मामूली सुधार के बीच सेवाओं का निर्यात मजबूत गति से बढ़ा। भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर, जिसके लिए कल आंकड़े जारी किए गए थे, सेवाओं का निर्यात इस वर्ष अप्रैल-जून में 35.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मजबूत गति से बढ़ा। इसी अवधि के लिए विप्रेषण में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेवाओं के निर्यात पर शुद्ध अधिशेष आंशिक रूप से उच्च व्यापार घाटे की भरपाई करने की आशा है।

बाह्य वित्त पोषण पक्ष से, निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ़डीआई) एक वर्ष पहले के 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-जुलाई 2022 में 18.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ़पीआई) निरंतर नौ महीनों तक बहिर्वाह के बाद जुलाई-सितंबर के दौरान 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध अंतर्वाह के साथ घरेलू बाजार में वापस आए हैं। 23 सितंबर 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 537.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि अधिकांश समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अनुकूल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भंडार में लगभग 67 प्रतिशत की गिरावट अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि और उच्च अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल से उत्पन्न मूल्यांकन परिवर्तनों के कारण है। संयोग से, 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी। भारत के अन्य बाह्य संकेतक, यथा, जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण अनुपात; जीडीपी की तुलना में निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति अनुपात; आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पकालिक ऋण का अनुपात; और ऋण सेवा अनुपात भी अधिकांश अन्य प्रमुख ईएमई[6] की तुलना में कम सुभेद्यता को दर्शाता है। वास्तव में, भारत के जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण अनुपात प्रमुख ईएमई में सबसे कम है। निर्णायक विश्लेषण में, हम अपनी बाह्य वित्तीय अपेक्षाओं को सहज रूप से पूरा करने के प्रति आश्वस्त हैं।

अतिरिक्त उपाय

अब मैं कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा करूंगा।

बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधानीकरण के लिए प्रत्याशित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र

बैंक वर्तमान में अपनी ऋण आस्तियों पर प्रावधानीकरण के लिए उपगत हानि दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जिसके अंतर्गत ऋण आस्तियों पर प्रावधान, दबाव होने के बाद किए जाते हैं। प्रत्याशित हानि आधारित दृष्टिकोण, एक अधिक विवेकपूर्ण और प्रगामी दृष्टिकोण है, जिसके अंतर्गत बैंकों को संभावित हानि के आकलन के आधार पर प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत विवेकपूर्ण मानदंडों के साथ अभिसरण की दिशा में एक कदम के रूप में, हम हितधारकों की टिप्पणियों के लिए प्रस्तावित परिवर्तन पर एक चर्चा पत्र जारी करेंगे।

[5] व्यापारिक आयात में संवृद्धि 2022-23 को पहली तिमाही में 49.5 प्रतिशत से घटकर जुलाई में 43.6 प्रतिशत और अगस्त 2022 में 37.3 प्रतिशत हो गई।

[6] जीडीपी की तुलना में निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का अनुपात भारत पर अनिवासियों के निवल दावों के संदर्भ में है और भंडार की तुलना में अल्पावधि ऋण का अनुपात अवशिष्ट परिपक्वता के संदर्भ में मापा जाता है।

गवर्नर का वक्तव्य

दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण ढांचा (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर 2021 में मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए संशोधित ढांचा जारी किया गया था। अब दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। यह मौजूदा एआरसी मार्ग के अलावा, एनपीए के प्रतिभूतिकरण के लिए एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान करेगा। हितधारकों की टिप्पणियों के लिए प्रस्तावित ढांचे पर एक चर्चा पत्र (डीपी) जारी किया जा रहा है।

आरआरबी के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को वर्तमान में कुछ मानदंडों को पूरा करने के अधीन अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की अनुमति है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग के प्रसार को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। संशोधित दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

ऑफ़लाइन भुगतान एग्रीगेटर्स को विनियमित करना

ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) को मार्च 2020 से रिज़र्व विनियमों के दायरे में लाया गया है। अब इन विनियमों को ऑफ़लाइन पीए, जो निकट/ भौतिक लेनदेन करते हैं, तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इस उपाय से डेटा मानकों पर विनियामक तालमेल और अभिसरण लाने की आशा है।

निष्कर्ष

इस समय हमारे सामने कठिन चुनौतियाँ हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के मूल तत्व और वर्षों में बने सुरक्षित भंडार ने हमें अच्छी स्थिति में खड़ा किया है। हमने अप्रैल 2022 से भू-राजनीतिक तनावों, प्रतिबंधों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की पृष्ठभूमि में कई उपाय किए हैं। हम संवृद्धि का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में कृतसंकल्प और दृढ़ रहेंगे। आज की हमारी नीतिगत कार्रवाई इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के हमारे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। जैसा कि हम दो दिन बाद महात्मा गांधी की जयंती मनाएंगे, मैं अपने वक्तव्य का उनके अंतर्दृष्टिपूर्ण शब्दों के साथ समापन करता हूं: "...हम सदैव जागृत रहते हैं, सदैव सतर्क रहते हैं, सदैव प्रयास करते हैं।"[7] आज वैश्विक अर्थव्यवस्था पर छाए बादलों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था आशावाद और आत्मविश्वास को प्रेरित करती है।

धन्यवाद। नमस्कार।

[7] आर.के. प्रभु और यू.आर.राव द्वारा लिखित द माइंड ऑफ महात्मा गांधी, नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद, भारत; पृष्ठ 153

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प सितंबर 28-30, 2022

*मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प**

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (30 सितंबर 2022) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत कर दिया जाए।

परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.15 प्रतिशत हो गई है।

- एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

ये निर्णय, संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।

इस निर्णय में अंतर्निहित मुख्य विचार नीचे दिए गए विवरण में व्यक्त की गई हैं।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. यूक्रेन में दीर्घकालिक संघर्ष और दुनिया भर में आक्रामक मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और रुख के प्रभाव में वैश्विक आर्थिक गतिविधि कमजोर हो रही है। जैसे-जैसे वित्तीय स्थितियां सख्त होती जा रही हैं, इक्विटी और बॉण्ड बाजारों में छिटपुट बिकवाली और अमेरिकी डॉलर मजबूत होकर 20 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच जाने के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव का अनुभव हो रहा है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) को वैश्विक मुद्रास्फीति के झटके के अलावा पोर्टफोलियो प्रवाह में कमी, मुद्रा मूल्यह्रास, आरक्षित भंडारों में कमी और वित्तीय स्थिरता जोखिमों से तीव्र दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जैसे-जैसे बाहरी मांग बिगड़ती है, उनकी समष्टि आर्थिक संभावना तेजी से प्रतिकूल होती जा रही है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

3. 2022-23 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) 13.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। जबकि घरेलू सकल मांग के सभी घटकों ने वर्ष-दर-वर्ष विस्तार किया और अपने महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर लिया, निवल निर्यात में अवरोध ने एक ऑफसेट प्रदान किया। आपूर्ति पक्ष पर, 2022-23 की पहली तिमाही में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें सभी घटकों, विशेष रूप से सेवाओं ने वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की।

4. आपूर्ति की सकल स्थिति में सुधार हो रहा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा का 29 सितंबर को दीर्घकालिक औसत (एलपीए) से 7 प्रतिशत अधिक होने और इसके कमी वाले कुछ क्षेत्रों में इसके स्थानिक वितरण के कारण, खरीफ की बुवाई जोर पकड़ रही है। इसका क्षेत्रफल 23 सितंबर को सामान्य बुवाई क्षेत्र से 1.7 प्रतिशत अधिक था और पिछले वर्ष के कवरेज से केवल 1.2 प्रतिशत कम था। प्रथम अग्रिम अनुमान (एफएई) के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन पिछले वर्ष के चौथे अग्रिम अनुमान (पिछले वर्ष के एफएई से केवल 0.4 प्रतिशत कम) से 3.9 प्रतिशत कम था। उद्योग और सेवा क्षेत्रों में गतिविधि विस्तार में बनी हुई है, विशेष रूप से उत्तरवर्ती, जैसा कि क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) और अन्य उच्च आवृत्ति संकेतकों में परिलक्षित होता है। हालांकि, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि का सूचकांक जुलाई में 2.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक धीमा हो गया।

5. मांग पक्ष पर, त्योहारी समय से पहले विवेकाधीन खर्च से शहरी खपत में वृद्धि हो रही है और ग्रामीण मांग में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। निवेश की मांग भी बढ़ रही है, जैसा कि बढ़ते आयात और पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू उत्पादन, स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन में परिलक्षित होता है। पण्य निर्यात ने अगस्त में

* 30 सितंबर 2022 को जारी।

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23

मामूली बढ़ोत्तरी हुई। तेल से इतर एवं स्वर्ण से इतर के आयात में तेजी रही।

6. अगस्त 2022 में सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर 7.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो जुलाई में 6.7 प्रतिशत थी, क्योंकि अनाज, सब्जियों, दालों, मसालों और दूध की कीमतों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति अधिक हो गई थी। केरोसिन (पीडीएस) की कीमतों में कमी के कारण ईंधन मुद्रास्फीति में नरमी आई, हालांकि यह दोहरे अंकों में बनी रही। मूल सीपीआई (अर्थात्, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति, विभिन्न घटक वस्तुओं और सेवाओं में ऊर्ध्वमुखी दबाव के साथ उच्च स्तर पर बनी हुई है।

7. जून-जुलाई में ₹3.8 लाख करोड़ की तुलना में अगस्त-सितंबर (28 सितंबर 2022 तक) के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत ₹2.3 लाख करोड़ की औसत दैनिक अवशोषण के साथ सकल प्रणाली चलनिधि अधिशेष में बनी रही। 9 सितंबर 2022 तक मुद्रा आपूर्ति (एम3) में वर्ष-दर-वर्ष 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में 9.5 प्रतिशत और बैंक ऋण में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 23 सितंबर 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 537.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

संभावना

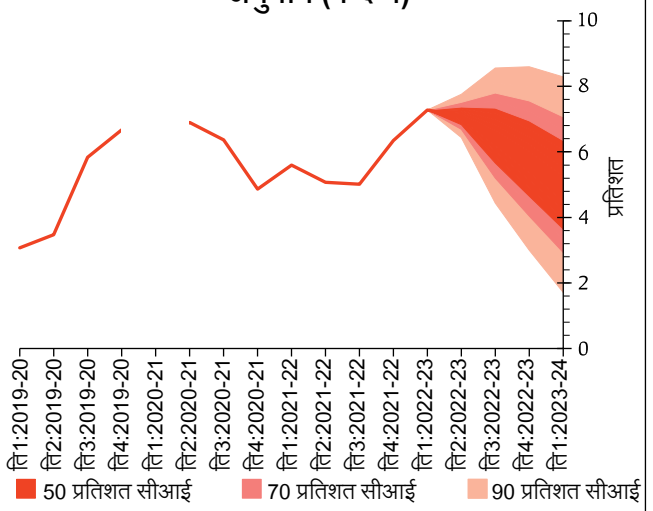
8. उच्च और दीर्घकालिक अनिश्चिताओं से घिरी भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने मुद्रास्फीति की संभावनाओं को काफी प्रभावित किया है। हालांकि, कोमोडिटी की कीमतों में नरमी आई है और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मंदी के जोखिम बढ़ रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर, बुवाई में देरी से हुए सुधार खरीफ उत्पादन के लिए शुभ संकेत है। जलाशयों के पर्याप्त स्तर के कारण रबी फसल की बफर में रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि, अत्यधिक / बेमौसम बारिश से फसल के नुकसान का खतरा बना रहता है। इन कारकों का खाद्य मूल्य संभावना पर प्रभाव पड़ता है। उच्च आयातित मुद्रास्फीति दबाव, मुद्रास्फीति के भावी प्रक्षेपवक्र के लिए एक अर्ध्वगामी जोखिम बना हुआ है, जो अमेरिकी डॉलर की निरंतर मूल्यवृद्धि से बढ़ा है। आपूर्ति और मांग दोनों से संबंधित परिचारक चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित संभावना काफी अनिश्चित है और भू-राजनीतिक गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक का उद्यम सर्वेक्षण, विनिर्माण, सेवाओं और अवसंरचना फर्मों में इनपुट लागत और आउटपुट मूल्य दबावों में कुछ कमी की ओर इशारा करता है; हालांकि, कीमतों के लिए इनपुट लागत का प्रभाव-अंतरण अधूरा है। इन कारकों और कच्चे तेल की औसत कीमत (भारतीय समूह) 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 में मुद्रास्फीति के 6.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसका दूसरी तिमाही में 7.1 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है और जोखिम समान रूप से संतुलित है। 2023-24 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत पर अनुमानित है (चार्ट 1)।

9. संवृद्धि के संबंध में, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बेहतर संभावना और सेवाओं में सुधार से सकल आपूर्ति की संभावनाएं बढ़ रही हैं। पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर जोर, विनिर्माण में क्षमता उपयोग में सुधार और गैर-खाद्य ऋण में वृद्धि से जुलाई में रुकी औद्योगिक गतिविधि में सुधार होना चाहिए। ग्रामीण मांग में तेजी और वर्ष की दूसरी छमाही में सामान्य वृद्धि से शहरी मांग के और मजबूत होने की उम्मीद के कारण समग्र मांग की संभावना सकारात्मक है। भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षणों के अनुसार, उपभोक्ता संभावना स्थिर बना हुआ है और विनिर्माण, सेवा और अवसंरचना क्षेत्रों के फर्म, मांग की स्थिति और बिक्री की संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं। दूसरी ओर, भू-राजनीतिक तनावों से संबंधित बाधाओं, वैश्विक वित्तीय स्थितियों की सख्ती और धीमी बाह्य मांग से प्रतिकूल परिस्थितियों ने निवल निर्यात और इसके कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद की संभावना के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न किया है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 7.0 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका दूसरी तिमाही 6.3 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 4.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है तथा जोखिम व्यापक रूप से संतुलित हो। 2023-24 की पहली तिमाही के लिए, यह 7.2 प्रतिशत पर अनुमानित है (चार्ट 2)।

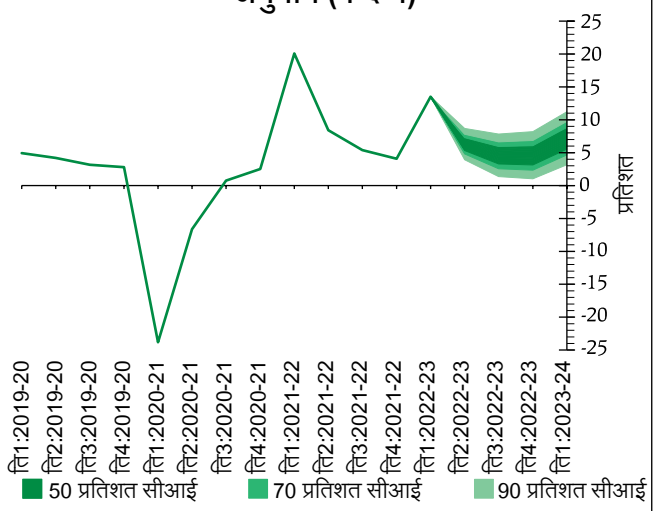
10. एमपीसी के विचार में, मुद्रास्फीति 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान 6 प्रतिशत के ऊपरी सहन-सीमा स्तर से ऊपर रहने की संभावना है, जिसमें मूल मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23

चार्ट 1: सीपीआई मुद्रास्फीति का तिमाही अनुमान (व-द-व)



चार्ट 2: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि का तिमाही अनुमान (व-द-व)



है। अस्थिर भू-राजनीतिक स्थिति, वैश्विक वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति में व्यवधान को देखते हुए संभावना काफी अनिश्चित बनी हुई है। इस बीच, घरेलू आर्थिक गतिविधि में सुधार हो रहा है और उपभोक्ता और व्यापार आशावाद के बीच त्योहारी समय की मांग के कारण 2022-23 की दूसरी छमाही में इसके तेज होने की उम्मीद है। एमपीसी का विचार है कि मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नियंत्रित रखने, मूल्य दबावों के विस्तार को रोकने और दूसरे दौर के प्रभावों को स्थानांतरित करने के लिए और सुविचारित मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता है। एमपीसी को लगता है कि इस कार्रवाई से मध्यम अवधि की संवृद्धि की संभावनाओं को समर्थन मिलेगा। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया कि आगे चलकर मुद्रास्फीति संवृद्धि का समर्थन करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

11. डॉ. शशांक भिड़े, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि करने के लिए मतदान किया। डॉ. आशिमा गोयल ने रेपो दर में 35 आधार अंकों की वृद्धि के लिए मतदान किया।

12. डॉ. शशांक भिड़े, डॉ. आशिमा गोयल, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए मतदान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे। प्रो. जयंत आर. वर्मा ने संकल्प के इस हिस्से के विरुद्ध मतदान किया।

13. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 14 अक्टूबर 2022 को प्रकाशित किया जाएगा।

14. एमपीसी की अगली बैठक 5-7 दिसंबर 2022 के दौरान निर्धारित है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन और पर्यवेक्षण; और (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन और पर्यवेक्षण

1. बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र

बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए उपगत हानि दृष्टिकोण की अपर्याप्तता और इसकी प्रचक्रीयता, जिसने 2007-09 के वित्तीय संकट के बाद मंदी को बढ़ा दिया था, को व्यापक रूप से प्रलेखित किया गया है। इन निष्कर्षों पर वैश्विक प्रतिक्रिया के प्रमुख तत्वों में से, प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) व्यवस्था में अंतरण रहा है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत विवेकपूर्ण मानदंडों के साथ अभिसरण की दिशा में एक और कदम के रूप में, बैंकों द्वारा अपने एक्सपोजर के लिए आवश्यक हानि प्रावधान हेतु अपेक्षित हानि दृष्टिकोण को अपनाने का प्रस्ताव है। पहले चरण के रूप में, परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा पत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

2. दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण ढांचा (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र

सितंबर 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए संशोधित ढांचा जारी किया था। गैर-निष्पादित आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफ़एईएसआई) अधिनियम, 2002 वर्तमान में अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा किए जाने वाले ऐसे प्रतिभूतिकरण के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। तथापि, बाजार की प्रतिक्रिया, हितधारक परामर्श और कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर कार्य बल (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2019) की सिफारिशों के आधार पर, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एआरसी मार्ग के अलावा मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण ढांचे के समान एक ढांचा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार, प्रस्तावित ढांचे की प्रासंगिक रूपरेखा का विवरण देते हुए एक चर्चा पत्र (डीपी) कुछ विशिष्ट पहलुओं पर टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा

कुछ वित्तीय और गैर-वित्तीय मानदंडों को पूरा करने के अधीन, आरआरबी को वर्तमान में भारतीय रिज़र्व के पूर्व अनुमोदन से अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की अनुमति है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग के प्रसार को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आरआरबी को इंटरनेट बैंकिंग प्रदान करने के पात्रता मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है और दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

4. ऑफलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स को विनियमित करना

भुगतान एग्रीगेटर (पीए) भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए उन्हें मार्च 2020 में विनियमों के अधीन लाया गया था और भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के रूप में नामित किया गया था। तथापि, वर्तमान विनियम, ऑनलाइन या ई-कॉमर्स लेनदेन को संसाधित करने वाले पीए पर लागू होते हैं। इन विनियमों में ऑफ़लाइन पीए शामिल नहीं हैं जो निकट/ भौतिक लेनदेन करते हैं और डिजिटल भुगतान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन पीए द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की समान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान विनियमों को ऑफलाइन पीए पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। इस उपाय से डेटा संग्रह और भंडारण के मानकों पर अभिसरण के अलावा पीए की गतिविधियों और परिचालन को कवर करने वाले विनियमन में सहक्रिया लाने की आशा है। विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट 2022-23

मौद्रिक नीति रिपोर्ट - सितंबर 2022

I. समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण

समग्र आपूर्ति स्थितियों में सुधार हो रहा है। यह त्योहार का मौसम शुरू होने से पहले मांग के लिए एक अच्छा संकेत है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति लक्ष्य के आसपास ऊपरी सीमा से ऊपर बनी हुई है। मौद्रिक नीति निभावकारी दाव को वापस लेने के दौर में आ गई है और उसका ध्यान यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि वृद्धि को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य पर लौट आए। चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण मौद्रिक नीति दृष्टिकोण के समक्ष काफी अनिश्चितता पैदा कर रहा है ।

I.1 अप्रैल 2022 एमपीआर से अब तक के प्रमुख घटनाक्रम

अप्रैल 2022 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) के जारी होने के बाद से, वैश्विक आर्थिक वातावरण में मंदी के बढ़ते जोखिमों, उच्च मुद्रास्फीति दबावों, तथा आक्रामक एवं एक ही समय में किए जा रहे समेकित मौद्रिक नीतिगत उपायों और रुखों से उत्पन्न सख्त वित्तीय स्थितियों के साथ वृद्धि धीमी पड़ती दिखाई देती है। उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए, इन घटनाक्रमों से मुद्रा का मूल्यह्रास हुआ है जो अमेरिकी डॉलर की बढ़ती कीमतों और पूंजी बहिर्वाह के कारण हुआ है जिसके परिणामस्वरूप आरक्षित निधि को हानि हुई है। यूक्रेन में युद्ध जारी है और महामारी आर्थिक गतिविधियों पर भारी पड़ रही है, यहां तक कि पर्यावरण संरक्षण (ग्रीन ट्रैन्ज़िशन) से जुड़ी समस्याओं, वास्तविक और वित्तीय विखंडन, व्यापार प्रतिबंध और रीशोरिंग के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को विकट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय बाज़ार अस्थिर बने हुए हैं और वैश्विक स्पिलओवर्स अत्यधिक विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रही हैं।

हालिया सुधार के बावजूद, तंग मांग-आपूर्ति संतुलन को देखते हुए, ब्रेंट क्रूड की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। वैश्विक खाद्य कीमतों में मार्च के सर्वकालिक उच्च स्तर से 14 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन यह पिछले वर्ष के स्तर[1] से 8 प्रतिशत अधिक है। जून के बाद कुछ नरमी के बावजूद ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स 27 सितंबर (वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) आधार) को 10 प्रतिशत अधिक था। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल बढ़ने लगे हैं और पिछले कई वर्षों के बाद अपने उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं क्योंकि निवेशक दुनिया भर में मौद्रिक नीति की भावी कार्यप्रणाली के लिए तैयार हैं। प्रतिफल वक्र उलट गए हैं, जो भावी मंदी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एई और ईएमई के इक्विटी बाज़ारों में मार्च के अंत से उच्च अस्थिरता के बीच (27 सितंबर 2022 तक) क्रमशः 21 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का तेजी से सुधार हुआ। मुद्रा बाज़ारों में, अमेरिकी डॉलर 20 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि अन्य सभी प्रमुख मुद्राओं में गिरावट आई है।

घरेलू अर्थव्यवस्था पर नज़र डालें तो, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2022-23 की पहली तिमाही में 13.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो आधार प्रभावों से प्रेरित थी, भले ही शुद्ध निर्यात पिछड़ने और सरकारी खर्चों को सीमित करने की वजहों से गति में गिरावट आई। समग्र आपूर्ति स्थितियों में लगातार सुधार हो रहा है और यह त्योहार के मौसम में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की मांग के लिए एक अच्छा संकेत है। दक्षिण-पश्चिम मानसून का देर से जोर पकड़ने और कमी वाले क्षेत्रों में मानसून के हाल में फैलने से *खरीफ* की बुवाई में तेजी आई है, हालांकि धान और दलहन एक साल पहले की तुलना में कम बोए गए हैं। विनिर्माण लगातार मजबूत हो रहा है और सेवाएं मजबूत वृद्धि दर्ज कर रही हैं, और यह वृद्धि संपर्क-संवेदनशील क्षेत्रों द्वारा प्रेरित है।

तथापि, स्फीतिकारी दबाव 2022-23 की पहली छमाही के दौरान उच्च स्तरों पर बना रहा और एक प्रमुख नीतिगत चिंता बना हुआ है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जनवरी 2022 से 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन सीमा में यो उससे ऊपर रही है, जो भू-राजनीतिक तनाव से उत्पन्न प्रतिकूल आपूर्ति झटकों से प्रेरित है। यद्यपि, मुद्रास्फीति अप्रैल के 7.8 प्रतिशत की ऊंचाई से कम हो गई है, तथापि यह अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर पर बनी हुई है। मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर करने और दूसरे दौर के प्रभाव को नियंत्रण में करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अप्रैल में नीतिगत दायरे को संकुचित कर दिया और मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मई-अगस्त के दौरान नीतिगत रेपो दर में 140 आधार अंकों (बीपएस) का इजाफा किया। मौद्रिक नीति निभावकारी दाव को वापस लेने पर केंद्रित है।

[1] अगस्त 2022 के लिए खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित।

मौद्रिक नीति समिति : अप्रैल-सितंबर 2022

अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान, एमपीसी की चार बार बैठक हुई, जिसमें मई 2022 में एक ऑफ-साइकिल बैठक भी शामिल है। अप्रैल 2022 में एमपीसी की बैठक के समय, अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में तेज उछाल और वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति की सामान्य होने की गति को लेकर अनिश्चितताओं के कारण वैश्विक आर्थिक और वित्तीय माहौल चुनौतीपूर्ण हो गया था। सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी और फरवरी 2022 में लगातार दो महीनों के लिए 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा में या उससे ऊपर थी। एमपीसी ने आकलन किया कि भू-राजनीतिक तनावों के बढ़ने, वैश्विक पण्य कीमतें सामान्य रूप से बढ़ने, लंबे समय तक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, व्यापार और पूंजी प्रवाह में अव्यवस्था, मौद्रिक नीति के स्तर पर की गई विभिन्न कार्रवाइयों और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता की संभावनाओं की वजह से मुद्रास्फीति आगे चलकर काफी बढ़ने (अपसाइड) और घरेलू वृद्धि घटने (डाउनसाइड) की आशंका (रिस्क) जताई गई है। तदनुसार, 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को 120 बीपीएस (फरवरी 2022 के अनुमानों के सापेक्ष) बढ़ाकर 5.7 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि वास्तविक जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान को 60 बीपीएस से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया गया। उच्च मुद्रास्फीति और बिगड़ते वृद्धि संबंधी दृष्टिकोण की दोहरी चुनौती को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। हालांकि वह अभी भी उदार है, मौद्रिक नीति का रुख उदारता से पीछे हटने पर केंद्रित है ताकि वृद्धि को समर्थन देते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे चलकर मुद्रास्फीति लक्ष्य के आसपास बनी रहे। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में स्थायी दर रिवर्स रेपो दर से 40 बीपीएस ऊपर स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरुआत की। इस प्रकार कॉरिडोर को नीतिगत रेपो दर के आसपास +/- 25 बीपीएस के दायरे के समान किया गया (अध्याय IV देखें)।[2]

मार्च 2022 का सीपीआई मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़ा तेजी से बढ़कर 7 प्रतिशत होने के साथ और भू-राजनीतिक तनावों और प्रतिबंधों के कारण खाद्य, कच्चे तेल और पण्यों की उच्च कीमतों से निकट अवधि में मुद्रास्फीति काफी बढ़ने की आशंका को देखते हुए एमपीसी ने मई 2022 में एक ऑफ-साइकिल बैठक करने का निर्णय लिया। उसने गौर किया कि जबकि आर्थिक गतिविधि आघात सहनीय है, मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर होने की वजह से मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर करने और दूसरे दौर के प्रभाव को नियंत्रण में करने के लिए दृढ़ और नपे-तुले कदम उठाने की आवश्यकता है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 40 बीपीएस बढ़ाने के लिए मतदान किया और अप्रैल के संकल्प में निर्धारित रुख को दोहराया।

जून 2022 की एमपीसी बैठक होने तक, अप्रैल 2022 में सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई थी, जिसमें भू-राजनीतिक स्थिति की वजह से दृष्टिकोण को लेकर काफी अनिश्चितता थी। एमपीसी का सोचना था कि खाद्य मुद्रास्फीति को निरंतर झटका लगने, उच्च कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और इनपुट लागत का बिक्री कीमतों में लंबित व्यापक प्रभाव की वजहों से हेडलाइन मुद्रास्फीति पर दबाव बने रहने की संभावना है। तदनुसार, 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को अप्रैल की बैठक से 100 बीपीएस बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया था। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, एमपीसी ने निर्णय लिया कि मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर रखने और मूल्य दबावों के विस्तार को रोकने के लिए सुविचारित मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। तदनुसार, इसने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में 50 बीपीएस की वृद्धि करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने निभावकारी रूख को वापस लेने पर नीति को केंद्रित किया है।

एमपीसी की अगस्त 2022 की बैठक के समय, सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल के 7.8 प्रतिशत से घटकर मई-जून 2022 के दौरान 7 प्रतिशत हो गई, लेकिन 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन सीमा से ऊपर रही। एमपीसी ने पाया कि वैश्विक पण्य कीमतों में कुछ कमी आई है, लेकिन भू-राजनीतिक झटकों का असर पड़ने से मुद्रास्फीति की ट्रैजेक्टरी को लेकर काफी अनिश्चितता बन रही है। घरेलू आर्थिक गतिविधि को आघातसह्य पाया । 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के

[2] महामारी चरण के दौरान प्रभावी ढंग से अतिरिक्त चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए, मार्च-अप्रैल 2020 के दौरान एलएएफ कॉरिडोर को असमान बना दिया गया था, जिसमें रेपो दर से 65 बीपीएस (महामारी से पहले 25 बीपीएस) नीचे रिवर्स रेपो दर और रेपो दर से 25 बीपीएस ऊपर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर थी।

ऊपरी सहन स्तर से ऊपर रहने का अनुमान लगाने के साथ, जो मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को अस्थिर करने और दूसरे दौर के प्रभाव प्रारंभ कर देने के जोखिम से मुक्त है, एमपीसी का विचार था कि स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रण में करने, हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्ष्य के करीब सहन सीमा के भीतर वापस लाने और सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर रखने के लिए आगे सुविचारित मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि करने का निर्णय लिया और जून 2022 के अपने रुख को 5 के मुकाबले 1 के बहुमत के साथ बनाए रखा।

एमपीसी का मतदान पैटर्न व्यक्तिगत सदस्यों के आकलन, अपेक्षाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं में विविधता को दर्शाता है, यह विशेषता अन्य केंद्रीय बैंकों के मतदान पैटर्न में भी परिलक्षित होती है (सारणी I.1).

समष्टिआर्थिक दृष्टिकोण

अध्याय II और III में 2022-23 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के दौरान मुद्रास्फीति और आर्थिक गतिविधि से संबंधित समष्टिआर्थिक विकास का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पिछले छह महीनों में प्रमुख समष्टिआर्थिक और वित्तीय चरों के विकास

सारणी I.1: मौद्रिक नीति समिति तथा नीति दर मतदान पैटर्न

देश	नीति बैठकें: अप्रैल-सितंबर 2022			
	कुल बैठकें	पूर्ण सहमति के साथ बैठक	असहमति के साथ बैठक	नीति दर में उतार-चढ़ाव (आधार अंक)
ब्राज़ील	4	3	1	200
चिली	4	3	1	375
कोलंबिया	3	1	2	400
चेक गणराज्य	3	0	3	200
हंगरी	6	6	0	735
भारत	4	4	0	140
इजरायल	4	4	0	190
जापान	4	1	3	0
दक्षिण अफ्रीका	3	0	3	200
स्वीडन	3	3	0	175
थाईलैंड	3	1	2	50
यूके	4	0	4	150
यूएस	4	3	1	275

स्रोत: केंद्रीय बैंक वेबसाइट।

सारणी I.2: पूर्वानुमानों के लिए आधारभूत अनुमान

संकेतक	एमपीआर अप्रैल 2022	एमपीआर सितंबर 2022
कच्चा तेल (भारतीय बास्केट)	2022-23 के दौरान प्रति बेरल यूएस$ 100	2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान प्रति बेरल यूएस$ 100
विनिमय दर	2022-23 के दौरान ₹ 76/US$	2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान ₹ 80/US$
मानसून	2022-23 के लिए सामान्य	2022-23# के लिए दीर्घावधि औसत से 7 प्रतिशत ऊपर
वैश्विक संवृद्धि	2022 में 3.5 प्रतिशत 2023 में 3.5 प्रतिशत	2022 में 3.2 प्रतिशत 2023 में 2.9 प्रतिशत
राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	बीई 2022-23 के भीतर रहेगी केंद्र: 6.4 संयुक्त: 9.0	बीई 2022-23 के भीतर रहेगी केंद्र: 6.4 संयुक्त: 9.3
पूर्वानुमान की अवधि के दौरान घरेलू समष्टि आर्थिक/स्ट्रक्चरल नीतियां	कोई बड़ा परिवर्तन नहीं	कोई बड़ा परिवर्तन नहीं

#: 29 सितंबर 2022 तक।

टिप्पणियाँ : 1. कच्चे तेल का भारतीय बास्केट ऐसे व्युत्पन्न मूल्य मापन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सॉअर ग्रेड (ओमान और दुबई औसत) और स्वीट ग्रेड (ब्रेंट) कच्चा तेल शामिल है।

2. यहाँ अनुमानित विनिमय दर पथ आधारभूत अनुमान हासिल करने के उद्देश्य के लिए है तथा यह विनिमय दर के स्तर पर कोई "मत" प्रकट नहीं करता है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अतिरिक्त अस्थिरता नियंत्रित करने के लिए निर्देशित है, न कि विनिमय दर के आसपास किसी भी विशिष्ट स्तर के और/या बैंड के उतार-चढ़ाव से।

3. बीई: बजट अनुमान।

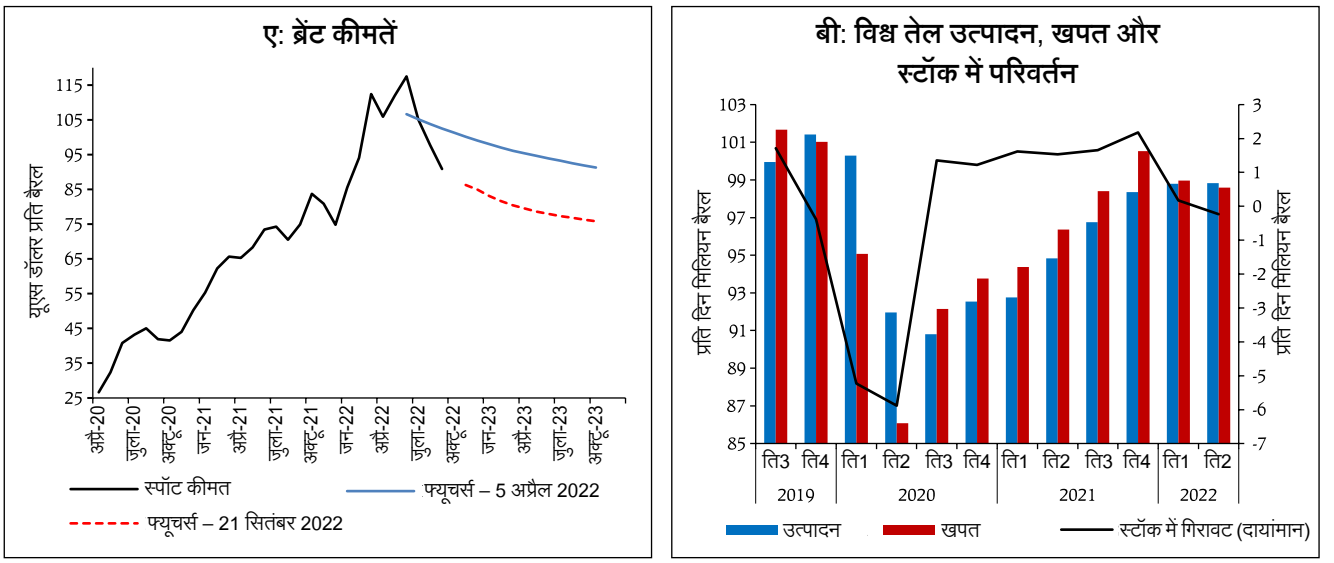
4. संयुक्त राजकोषीय घाटे में केंद्र और राज्यों को एक साथ लिया है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान; बजट दस्तावेज़; और आईएमएफ।

के लिए आधारभूत मान्यताओं में संशोधन की आवश्यकता है (सारणी I.2).

पहला, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में पहली छमाही में बड़ी अस्थिरता परिलक्षित हुई है। रूस पर प्रतिबंधों के कारण जून के मध्य तक ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 121 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ गईं, जो आपूर्ति संबंधी चिंताओं से प्रेरित था। तब से कीमतों में गिरावट आई है, क्योंकि वैश्विक मांग कमजोर हो रही है। हालांकि भू-राजनीतिक संघर्ष और प्रतिबंधों का दृष्टिकोण पर भारी असर पड़ रहा है लेकिन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) प्लस द्वारा निरंतर आपूर्ति प्रबंधन और प्राकृतिक गैस की रिकॉर्ड कीमतों के कारण गैस-से-तेल स्विचिंग ने कच्चे तेल की कीमतों को समर्थन दिया है, (चार्ट I.1.ए) और चार्ट I.1.बी)। इन घटनाक्रमों को ध्यान में

चार्ट I.1: कच्चा तेल कीमतें



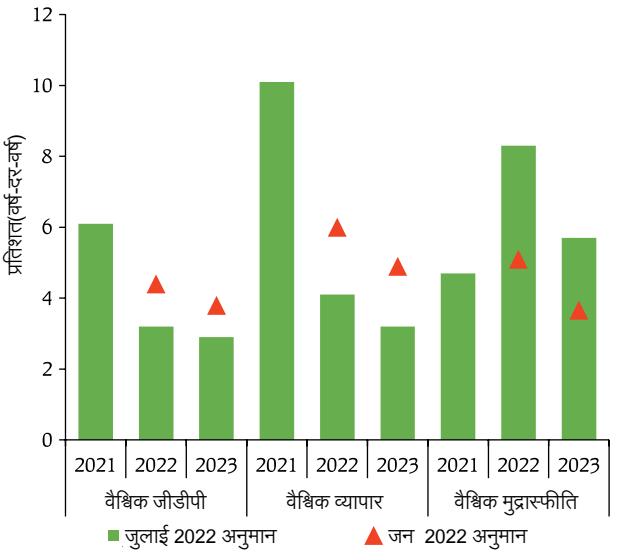
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए)।

रखते हुए, कच्चे तेल की कीमतें (भारतीय बास्केट) बेसलाइन में 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल माना गया है, जो अप्रैल एमपीआर बेसलाइन की तरह है।

दूसरा, मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का सामान्य रूप से मजबूत होने, उच्च कच्चा तेल कीमतों और पोर्टफोलियो बहिर्वाह की वजह से पहली छमाही के दौरान भारतीय रुपये ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मूल्यह्रास पूर्वाग्रह दर्शाया। मार्च 2022 के अंत और 27 सितंबर के बीच अमेरिकी डॉलर सूचकांक 16 प्रतिशत मजबूत हुआ, जो यूएस फेड द्वारा आक्रामक मौद्रिक नीति सख्ती और भावी बढ़ोतरी संबंधी प्रत्याशाओं को दर्शाता है। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, विनिमय दर को बेसलाइन में अप्रैल 2022 एमपीआर के 76 रुपये की तुलना में 80 रुपया प्रति अमेरिकी डॉलर पर माना गया है, जो 5 प्रतिशत का मूल्यह्रास दर्शाता है।

तीसरा, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं अप्रैल एमपीआर के बाद से काफी कमजोर हो गई हैं, जो कि पहले चर्चा की गई बहु-आयामी प्रतिकूल स्थितियों के कारण है (चार्ट I.2)। वैश्विक व्यापार धीमा हो रहा है और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की चिंता बढ़ रही है। वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जून 2020 के

चार्ट I.2: वैश्विक जीडीपी और मुद्रास्फीति



स्रोत: आईएमएफ।

बाद से घटकर पहली बार अगस्त 2022 में संकुचन क्षेत्र में आ गया। वैश्विक कारक विभिन्न चैनलों के माध्यम से घरेलू गतिविधि में अधोगामी और घरेलू मुद्रास्फीति में ऊर्ध्वगामी दबाव डालते रहे हैं (बॉक्स I.1)।

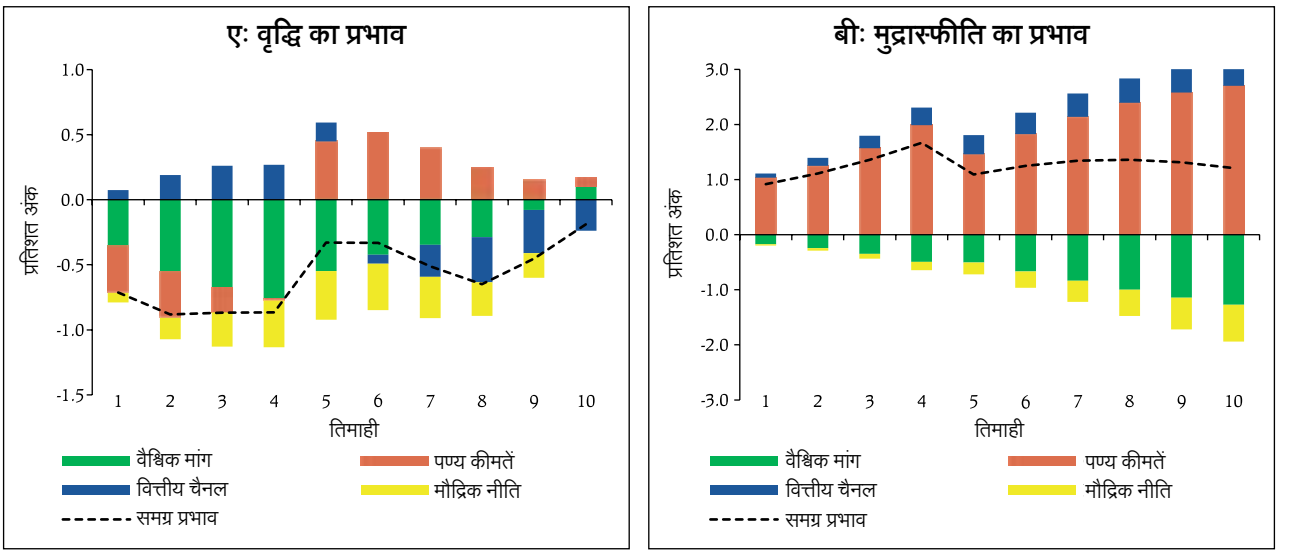
बॉक्स I.1: निम्न वैश्विक वृद्धि और उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति के समष्टिआर्थिक प्रभाव

वैश्विक वृद्धि 2021 में 6.1 प्रतिशत से घटकर 2022 में 3.2 प्रतिशत होने का अनुमान है और दृष्टिकोण "निराशाजनक एवं अधिक अनिश्चितपूर्ण" है, जिसमें गिरावट की तरफ जोखिम दिखाई दे रहे हैं (आईएमएफ, 2022)। आईएमएफ द्वारा वैश्विक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2021 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 8.3 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

ये वैश्विक मुद्रास्फीतिजनित दबाव कई चैनलों के माध्यम से घरेलू वृद्धि और मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले, कम बाहरी मांग निर्यात मांग और समग्र घरेलू मांग एवं वृद्धि को कम करती है। वहीं, कमजोर वैश्विक मांग के कारण वैश्विक पण्य कीमतों में गिरावट आ सकती है। दूसरा, उच्च वैश्विक पण्य कीमतें प्रत्यक्ष और लागत-प्रेरित चैनलों के माध्यम से घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ाती हैं और समग्र मांग के कमजोर होने से घरेलू वृद्धि में गिरावट आती है। तीसरा, उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति और वैश्विक ब्याज दरें पूंजी प्रवाह को प्रभावित करती हैं, घरेलू मुद्रा पर गिरने का दबाव डालती हैं और परिणामस्वरूप आयातित मुद्रास्फीति उच्च हो जाती है।

आरबीआई के तिमाही प्रोजेक्शन मॉडल[3] के 'शेष विश्व (आरओडब्ल्यू) ब्लॉक' के आधार पर, भारत की मुद्रास्फीति और वृद्धि पर सभी चैनलों के माध्यम से उच्चतम प्रभाव चार तिमाहियों तक होता है। दूसरे दौर के प्रभाव मुद्रास्फीति को 8 तिमाहियों के बाद भी ऊंचे स्तर पर रख सकते हैं, नतीजतन मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर करने के लिए उचित मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों की आवश्यकता होगी (चार्ट I.1.1)। ऐसी परिस्थितियों में, मुद्रास्फीति के लक्ष्य के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाते हुए फ्रंट लोडेड मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों से विश्वसनीयता और बढ़ती है एवं कम आउटपुट नुकसान के साथ मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने में मदद मिलती है (जॉन, कुमार और पात्र, 2022)।

चार्ट I.1.1: वैश्विक झटका और घरेलू जीडीपी वृद्धि एवं मुद्रास्फीति



स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

संदर्भ :

Benes, J., K. Clinton, A. George, P. Gupta, J. John, O. Kamenik, D. Laxton, P. Mitra, G. Nadhanael, R. Portillo, H. Wang, and F. Zhang (2016), "Quarterly Projection Model for India: Key Elements and Properties", RBI Working Paper Series No. 08.

International Monetary Fund (2022), *World Economic Outlook*, July.

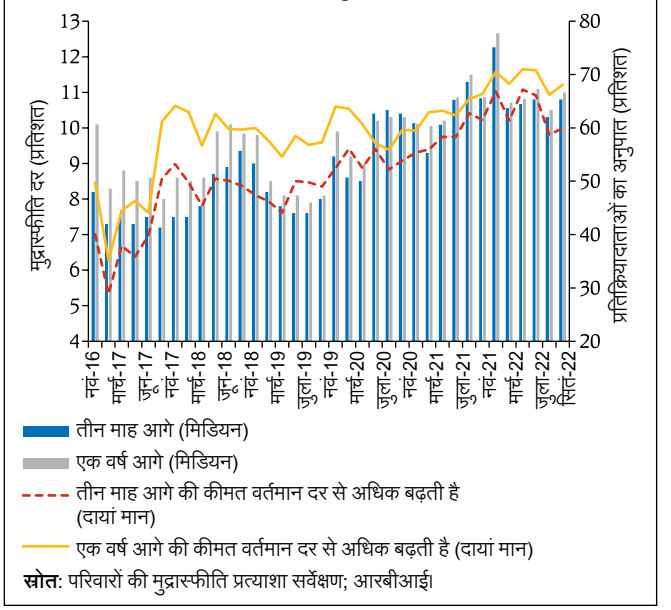
John, J., D. Kumar, and M. D. Patra (2022), "Monetary Policy: Confronting Supply-driven Inflation", *RBI Bulletin* July, Volume LXXVI (7), pp. 97-109.

[3] क्यूपीएम कन्सेन्सस मैक्रोइकनामिक न्यू कीनेसियन ओपन इकानमी स्ट्रक्चरल मॉडल की शैली से संबंधित है और इसमें भारत-विशिष्ट विशेषताओं को शामिल करने का विचार किया गया है (बेन्स एवं अन्य, 2016).

I.2 मुद्रास्फीति दृष्टिकोण

सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी 2022 के बाद से 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन सीमा में या उससे ऊपर रही है, हालांकि हाल के महीनों में कुछ कमी आई है (अध्याय II)। आगे देखते हुए, पिछले दौर[4] की तुलना में रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के सितंबर 2022 के दौर में शहरी परिवारों की तीन महीने और एक वर्ष आगे की औसत मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में प्रत्येक में 50 बीपीएस की वृद्धि की गई। सामान्य मूल्य स्तर में मौजूदा दर से अधिक वृद्धि की उम्मीद करने वाले उत्तरदाताओं के अनुपात में भी पिछले दौर की तुलना में तीन महीने और एक वर्ष आगे की सीमा दोनों में वृद्धि देखी गई (चार्ट I.3)।

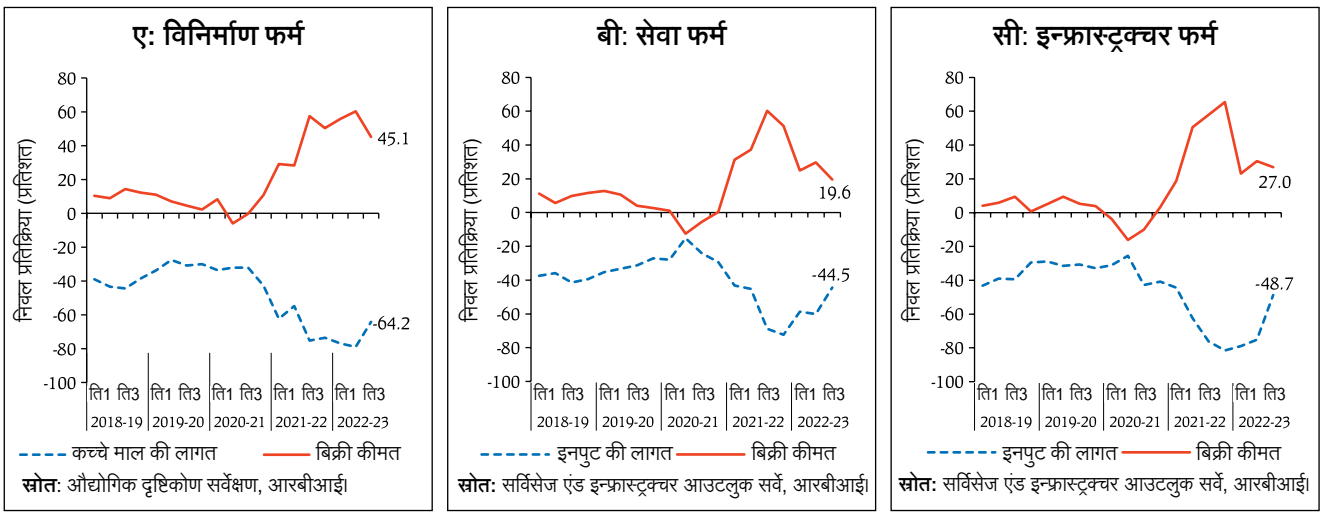
चार्ट I.3: परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं



स्रोत: परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण; आरबीआई।

रिज़र्व बैंक के औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण के जुलाई-सितंबर 2022 के दौर में विनिर्माण फर्मों ने 2022-23 की तीसरी तिमाही में कच्चे माल की लागत के साथ-साथ बिक्री कीमतों में कमी की उम्मीद की (चार्ट I.4ए)।[5] सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों को भी 2022-23 की तीसरी तिमाही में इनपुट लागत और बिक्री कीमतों में गिरावट की उम्मीद थी (चार्ट I.4बी और I.4सी)।[6] विनिर्माण और सेवा पीएमआई में उत्तरदाताओं ने, यद्यपि स्फीतिकारी दबावों की गति में कुछ कमी के साथ, अगस्त 2022 में इनपुट और आउटपुट कीमतों में वृद्धि रिपोर्ट की।

चार्ट I.4: कच्चे माल/इनपुट की लागत और बिक्री कीमत संबंधी प्रत्याशाएं



स्रोत: औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण, आरबीआई।

स्रोत: सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे, आरबीआई।

स्रोत: सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे, आरबीआई।

टिप्पणी: आशादायी और निराशाजनक सूचना देनेवाले उत्तरदाताओं के बीच का अंतर निवल प्रतिक्रिया हैं। यह रेंज -100 से 100 तक है। निवल प्रतिक्रिया का एक सकारात्मक/नकारात्मक मूल्य प्रतिवादी फर्मों के दृष्टिकोण से आशावादी/निराशावादी माना जाता है। इसलिए, बिक्री मूल्य के उच्च सकारात्मक मूल्य आउटपुट कीमतों में वृद्धि का संकेत देते हैं जबकि कच्चे माल/इनपुट की लागत के लिए कम मूल्य उच्च इनपुट मूल्य दबाव और इसके विपरीत संकेत करते हैं।

[4] मार्च 2021 से 19 शहरों में रिज़र्व बैंक का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण किया जा रहा है (पिछले दौर में 18 शहर) और सितंबर 2022 के दौर के परिणाम 6,052 परिवारों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

[5] औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण के जुलाई-सितंबर 2022 दौर के परिणाम 1,234 कंपनियों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

[6] सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण सर्वेक्षण के जुलाई-सितंबर 2022 दौर के मतदान में शामिल 469 सेवा और 124 इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर आधारित।

सितंबर 2022 में रिज़र्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण किए गए पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने सीपीआई मुद्रास्फीति 2022-23 की पहली तिमाही में 7.3 प्रतिशत से घटकर चौथी तिमाही में 6.0 प्रतिशत और 2023-24 की पहली छमाही में 4.9-5.0 प्रतिशत होने की प्रत्याशा की है (चार्ट I.5ए और सारणी I.3)।[7] पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं की लंबी अवधि की मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएं – जो उनकी 5- और 10-वर्ष आगे की प्रत्याशाओं द्वारा मापी गई हैं – मोटे तौर पर मुद्रास्फीति के लक्ष्य के आसपास रहीं, हालांकि वे महामारी की अवधि के दौरान मामूली रूप से ऊपर थीं। सितंबर के दौर में, 5 साल आगे की प्रत्याशित मुद्रास्फीति 10 बीपीएस बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो गई, जबकि 10 साल आगे की प्रत्याशा 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही (चार्ट I.5बी)।

आगे, कई बाह्य कारक - वैश्विक और घरेलू - मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण पर प्रभाव डालेंगे। वैश्विक पण्य कीमतें कमजोर वैश्विक संभावनाओं के कारण अपने उच्च स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन उच्च और अस्थिर बनी हुई हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलां धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, हालांकि वे भू-राजनीतिक व्यवधानों, प्रमुख उत्पादन केंद्रों में महामारी से संबंधित लॉकडाउन और वित्तीय बाज़ार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हैं। घरेलू स्तर पर, 2021-22 में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, 2022 के दौरान

सारणी I.3: अनुमान - रिज़र्व बैंक और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता

(प्रतिशत)

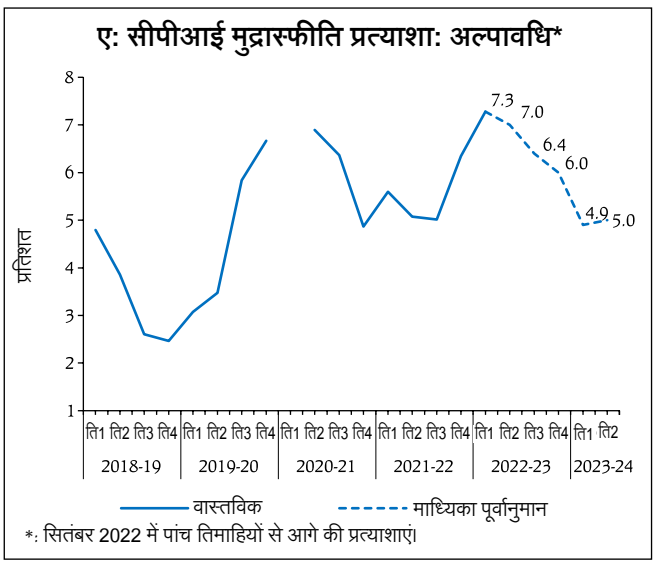
	2022-23	2023-24
रिज़र्व बैंक का बेसलाइन अनुमान		
मुद्रास्फीति,चौथी तिमाही (वर्ष-दर-वर्ष)	5.8	5.2
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संवृद्धि	7.0	6.5
पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के माध्यिका अनुमान		
मुद्रास्फीति, चौथी तिमाही (वर्ष-दर-वर्ष)	6.0	5.0@
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि	7.0	6.1
सकल घरेलू बचत (जीएनडीआई का प्रतिशत)	28.0	28.7
सकल पूंजी निर्माण (जीडीपी का प्रतिशत)	31.3	31.5
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण में वृद्धि	13.0	11.0
संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	9.7	9.0
केंद्र सरकार सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	6.4	6.0
रेपो रेट (समाप्त-अवधि)	6.00	6.00@
91-दिवसीय खजाना बिल पर प्रतिफल (समाप्त-अवधि)	6.2	6.0
10-वर्षीय केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल (समाप्त-अवधि)	7.5	7.4
समग्र भुगतान शेष (यूएस $ बिलियन)	-57.6	-7.4
पण्य निर्यात वृद्धि	7.2	6.3
पण्य आयात वृद्धि	19.0	5.7
चालू खाता शेष (जीडीपी का प्रतिशत)	-3.4	-2.7

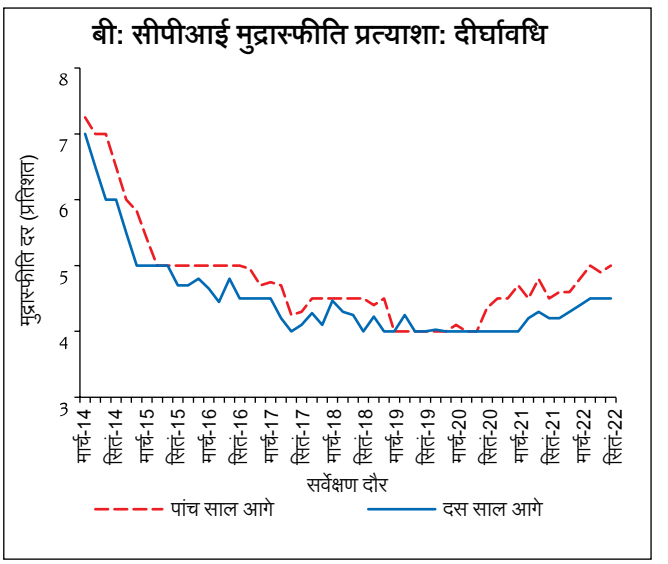
@: ति2:2023-24

टिप्पणी: जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय।

स्रोत: रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान; और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण(सितंबर 2022)।

चार्ट I.5: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं





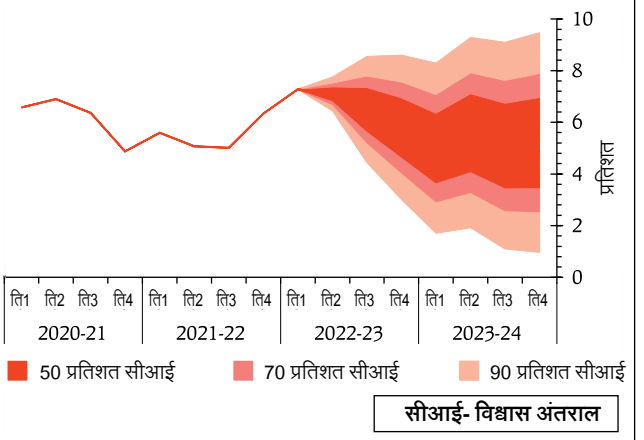
स्रोत: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण,आरबीआई; और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

[7] रिज़र्व बैंक के पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण के सितंबर 2022 के दौर में 41 पैनलिस्टों ने भाग लिया।

सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून, खरीफ़ बुवाई में बहाली, पर्याप्त बफर स्टॉक और बेहतर जलाशय की स्थिति कृषि संभावनाओं और खाद्य मुद्रास्फीति की भावी ट्रैजक्टरी के लिए एक अच्छा संकेत है। प्रारंभिक स्थितियों, प्रगतिशील सर्वेक्षणों के संकेतों और संरचनात्मक एवं अन्य समय-श्रृंखला मॉडल के अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति 2022-23 में औसतन 6.7 प्रतिशत – दूसरी तिमाही में 7.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसमें जोखिम को लेकर समान रूप से संतुलन बना हुआ है (चार्ट I.6)। 2022-23 की चौथी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति हेतु 50 प्रतिशत और 70 प्रतिशत विश्वास अंतराल क्रमशः 4.7-6.9 प्रतिशत और 4.0-7.6 प्रतिशत हैं। 2023-24 के लिए, सामान्य मानसून, आपूर्ति श्रृंखला के प्रगतिशील रूप से सामान्य होने, और आगे कोई बाह्य या नीतिगत झटका नहीं होने को मानते हुए, संरचनात्मक मॉडल अनुमानों से संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति औसतन 5.2 प्रतिशत रहेगी। 2023-24 की चौथी तिमाही में, सीपीआई मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत पर रहने के साथ 50 प्रतिशत और 70 प्रतिशत विश्वास अंतराल क्रमशः 3.5-7.0 प्रतिशत एवं 2.5-7.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।

आधारभूत पूर्वानुमान कई ऊर्ध्वगामी और अधोगामी जोखिमों के अधीन हैं। भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ने, कच्चे तेल और पण्य की उच्च वैश्विक कीमतों, आक्रामक मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों की वजह से वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ने, अत्यधिक एकीकृत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से फैलते झटकों के साथ उम्मीद से अधिक समय तक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान (बॉक्स I.2), *खरीफ* उत्पादन में संभावित कमी, बेमौसम बारिश और मांग के मजबूत होने पर इनपुट लागत दबाव के उत्पादन कीमतों पर व्यापक प्रभाव से ऊर्ध्वगामी जोखिम उत्पन्न होता है। भू-राजनीतिक तनावों के शीघ्र समाधान, वैश्विक मांग में कमी के कारण वैश्विक पण्य कीमतों में और गिरावट एवं महामारी के कम होने के साथ आपूर्ति की स्थिति में और सुधार होने से अधोगामी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।

चार्ट I.6: सीपीआई मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान (वर्ष-दर-वर्ष)



टिप्पणी: फ़ैन चार्ट बेसलाइन प्रोजेक्शन पथ के आस-पास अनिश्चितता दर्शाता है। बेसलाइन अनुमान सारणी I.2 में निर्धारित धारणाओं पर आधारित हैं। गहरा लाल छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका अर्थ है कि वास्तविक परिणाम गहरे लाल छायांकित क्षेत्र द्वारा दी गई सीमा के भीतर होने की 50 प्रतिशत संभावना है। समान रूप से, 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत विश्वास अंतराल के लिए, वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्र के रूप में दर्शाई गयी सीमा के भीतर होने की क्रमशः 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत संभावना है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बॉक्स I.2: मुद्रास्फीति पर वैश्विक लागत-प्रेरित प्रभाव : विश्व इनपुट-आउटपुट सारणियों से परिज्ञान

मुद्रास्फीति में वैश्विक उछाल की शुरूआत - कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में युद्ध – एक के तुरंत बाद दूसरे इन दो बड़े प्रतिकूल झटकों से हुई है – जिसे बड़े पैमाने पर मौद्रिक-राजकोषीय प्रोत्साहन से उत्पन्न मांग दबावों के द्वारा बल प्रदान किया गया। अधिक एकीकृत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ, क्षेत्रीय और देश-विशिष्ट झटके अब पहले से कहीं अधिक तेजी से प्रसारित होते हैं (डी सोयर्स और फ्रेंको, 2020)[8]। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक झटकों के लागत-प्रेरित स्फीतिकारी प्रभाव को दो देशों के बीच इनपुट-आउटपुट (आईसीआईओ) सारणियों (ओईसीडी, 2021) के माध्यम से देखा जा सकता है। देश-विशिष्ट क्षेत्रीय झटकों के संभावित प्रभाव का अनुमान *लियोन्टीफ इनवर्स मैट्रिक्स* का उपयोग करके लगाया जाता है ताकि उन देशों और क्षेत्रों की पहचान की जा सके जो उच्चतम लागत-प्रेरित स्फीतिकारी जोखिम पैदा कर सकते हैं।

(जारी)

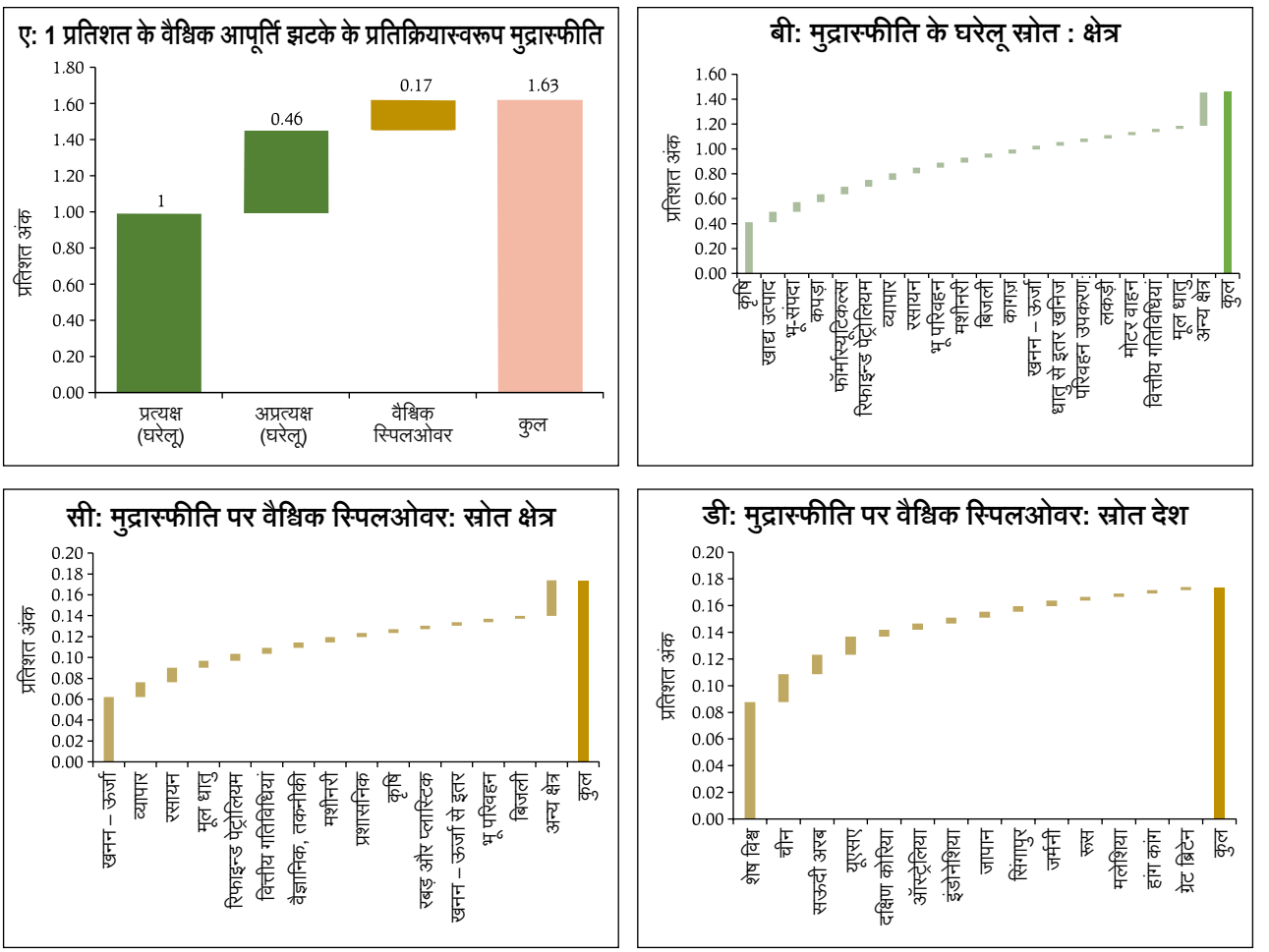
[8] सभी वैश्विक व्यापार का लगभग आधा हिस्सा मध्यवर्ती वस्तुओं का है, जिसमें व्यापार का 2021 में विश्व उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, 2022).

$L = (I - A)^{-1}$; $[e_{jk,jk}] = SHK.L$; $\Pi = [\sum_{k=1}^{K} w_k * e_{.k,k.}]$; $[C_j] = \sum_{k=1}^{K} \pi_{jk}$; $[I_k] = \sum_{j=1}^{J} \pi_{jk}$

L लियोन्टीफ इनवर्स है, *I* एक पहचान मैट्रिक्स है और *A* आईसीआईओ से प्राप्त तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स है, जिसमें आयाम (*J*K x J*K*) - *J* और *K* क्रमशः अर्थव्यवस्थाओं (71) और उद्योग (45) की कुल संख्या हैं। *SHK* झटका वेक्टर है जिसे यूनिट झटके (एक प्रतिशत) के रूप में तैयार किया गया है, और वैश्विक झटके में क्षेत्र एवं मूल देश के झटके के आकार के सापेक्ष हिस्से के लिए समायोजित किया गया है। Π एक (*J x K*) घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति प्रतिक्रिया मैट्रिक्स है जिसे सीपीआई भार (wk) का उपयोग करके समुच्चित किया गया है। C_j देश j^{th} से स्पिलओवर है और I_k सेक्टर k^{th} से स्पिलओवर है।

अनुभवजन्य विश्लेषण दर्शाते हैं कि एक प्रतिशत बिंदु का वैश्विक मुद्रास्फीति झटका – जिसे सभी देशों और क्षेत्रों में कीमतों में एक साथ एक प्रतिशत की वृद्धि के रूप में तैयार किया गया है - दूसरे दौर के प्रभावों के माध्यम से भारत में मुद्रास्फीति को लगभग 63 बीपीएस तक बढ़ा सकता है, जिसमें 100 बीपीएस के प्रत्यक्ष प्रभाव के अलावा, घरेलू अप्रत्यक्ष प्रभाव (46 बीपीएस) और वैश्विक स्पिलओवर (17 बीपीएस)[9] शामिल हैं (चार्ट I.2.1)। मुद्रास्फीति

चार्ट I.2.1: वैश्विक आपूर्ति झटके: मुद्रास्फीति पर प्रभाव



स्रोत: ओईसीडी आईसीआईओ का उपयोग कर आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

(जारी)

[9] ये अनुमान विनिमय दर और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं जैसे संचरण के अन्य चैनलों की अनुपस्थिति और कोई ऑफसेटिंग समष्टिआर्थिक नीतिगत कार्रवाइयों के न होने को मानते हैं।

के घरेलू स्रोत (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों, आवास, वस्त्र, और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों से उपजते हैं। वैश्विक स्पिलओवर, जो आयातित मुद्रास्फीति चैनल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऊर्जा, खनन, रसायन, व्यापार, बुनियादी धातुओं और मशीनरी में कीमतों के दबाव से प्रेरित होते हैं। स्रोत देशों के संदर्भ में, भारत में मुद्रास्फीति में सबसे बड़े योगदानकर्ता तेल निर्यातक देश, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

वैश्विक मुद्रास्फीति का वर्तमान दौर मुख्य रूप से वैश्विक ऊर्जा और कृषि उत्पाद की कीमतों में उछाल से प्रेरित है (जिसमें 2021-22 की दूसरी छमाही के दौरान क्रमशः लगभग 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई)। अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि 2021-22 की दूसरी छमाही के दौरान अनुभव किए गए वैश्विक खाद्य और ऊर्जा झटके लागत-प्रेरित चैनल के माध्यम से समय के साथ घरेलू मुद्रास्फीति पर लगभग 2.5 प्रतिशत अंक का दबाव बढ़ा सकते हैं, *यदि अन्य बातें पूर्ववत रहें तो*।

संदर्भ :

de Soyres, F. and S. Franco. (2019), "Inflation Dynamics and Global Value Chains", World Bank Policy Research Working Paper No. 9090.

UNCTAD (2022), "The Effects of the COVID-19 Pandemic on International Trade", *Key Statistics and Trends in International Trade 2021*, https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2022d3_en.pdf

OECD (2021), *Inter-Country Input-Output Tables*, available at https://www.oecd.org/sti/ind/inter-country-input-outputtables.htm

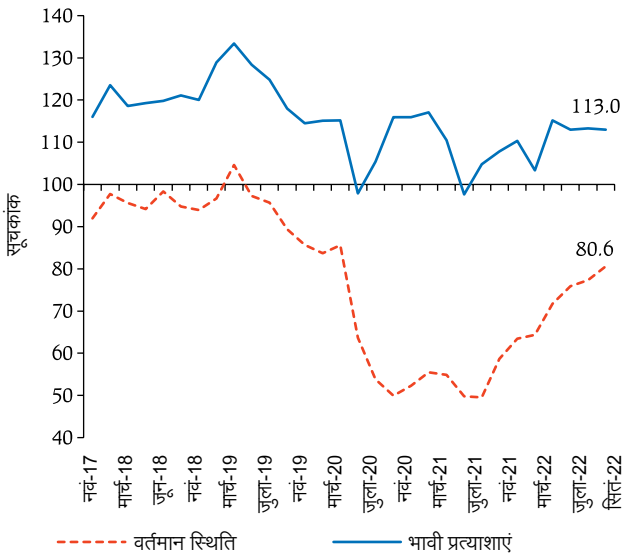
I.3 संवृद्धि दृष्टिकोण

कोविड-19 संक्रमणों के कमजोर पड़ने और उपभोक्ता मनोभाव में सुधार की बदौलत संपर्क-गहन सेवाओं की मांग में वापसी हुई है और 2022-23 की पहली छमाही में घरेलू मांग को सहारा मिला है। उद्योग और सेवा क्षेत्र जोर पकड़ रहे हैं और खरीफ की बुआई में तेजी से बहाली आई । सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून की बदौलत जलाशय का स्तर बेहतर हुआ है जो सर्दियों की फसलों के लिए अच्छा है। निवेश गतिविधि को सरकार के पूंजीगत व्यय में इजाफा, बैंक ऋण में वृद्धि, मांग की स्थिति में सुधार और क्षमता उपयोग में वृद्धि से लाभ होने की उम्मीद है। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक वित्तीय बाज़ार में बढ़ते उतार-चढ़ाव और सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियां, दृष्टिकोण पर भारी पड़ती हैं।

प्रगतिशील सर्वेक्षणों के प्रमुख संदेशों की बात करें तो, सामान्य आर्थिक स्थिति और समग्र खर्च के संबंध में बेहतर धारणा होने के कारण सितंबर 2022 सर्वेक्षण के दौर में उपभोक्ता विश्वास (वर्तमान स्थिति सूचकांक) में और वृद्धि हुई, हालांकि समग्र विश्वास निराशावादी क्षेत्र में बना रहा। जुलाई 2022 के सर्वेक्षण दौर की तुलना में भावी प्रत्याशा सूचकांक अपरिवर्तित रहने के साथ, हाउसहोल्ड्स आगामी वर्ष के लिए आशावादी बने रहे (चार्ट I.7)।[10]

रिज़र्व बैंक के औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण के जुलाई-सितंबर 2022 के दौर में आगामी तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र में मांग की

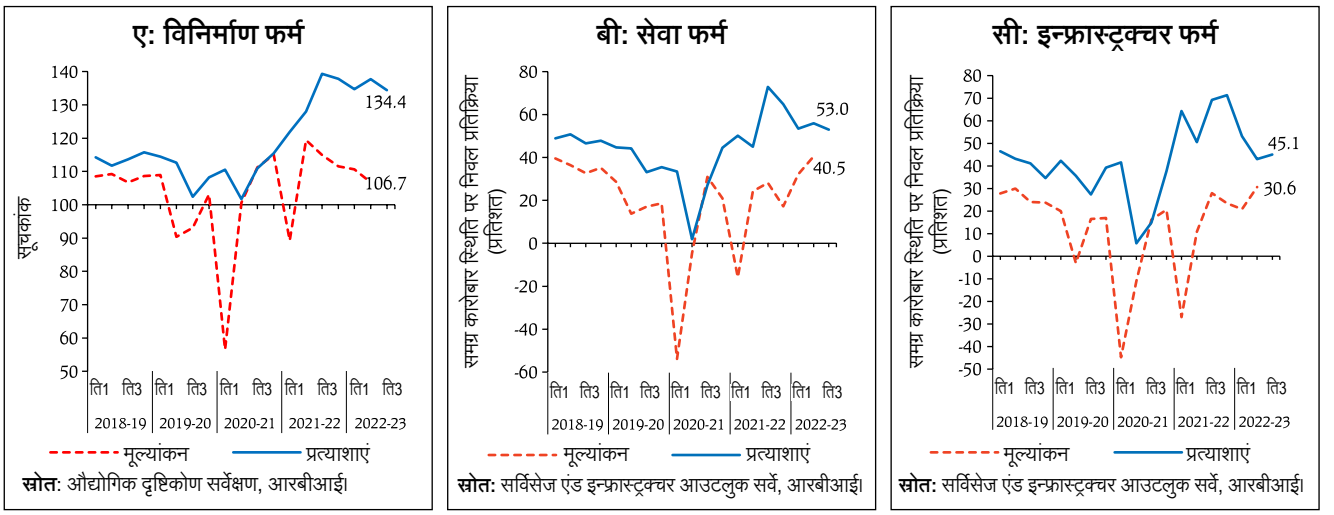
चार्ट: 1.7: उपभोक्ता विश्वास



स्रोत: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, आरबीआई।

[10] रिज़र्व बैंक का उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण मार्च 2021 (पिछले दौर में 13 शहर) से 19 शहरों में किया जा रहा है और सितंबर 2022 के दौर के परिणाम 6,062 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

चार्ट 1.8: कारोबार मूल्यांकन और प्रत्याशाएं



स्रोत: औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण, आरबीआई। **स्रोत:** सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे, आरबीआई। **स्रोत:** सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे, आरबीआई।

स्थिति को लेकर आशावाद मामूली रूप से कम हो गया, हालांकि यह काफी हद तक विस्तार क्षेत्र में बना रहा (चार्ट I.8ए)। समग्र कारोबार स्थिति के संदर्भ में 2022-23 की तीसरी तिमाही में मांग की स्थिति के संबंध में सेवा क्षेत्र की कंपनियों में मामूली कमी आने की उम्मीद थी जबकि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद थी (चार्ट I.8बी और I.8सी)।

अन्य एजेंसियों द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षणों से उनके संबंधित पिछले दौरों की तुलना में कारोबार संबंधी प्रत्याशाओं में गिरावट का संकेत मिलता है (सारणी I.4)। पीएमआई सर्वेक्षण के अगस्त 2022 के दौर में, बढ़ती मांग को लेकर आशावाद की बदौलत विनिर्माण और सेवा फर्मों की कारोबार संबंधी प्रत्याशाओं ने बहु-वर्षीय ऊंचाइयों को प्राप्त किया।

रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के सितंबर 2022 के दौर में मतदान में शामिल पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2022-23 की दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.2 प्रतिशत और 2023-24 की पहली छमाही में 6.4-6.6 प्रतिशत पर होने की उम्मीद की है (चार्ट I.9 और सारणी I.3)।

आधारभूत अनुमानों, सर्वेक्षण संकेतकों और मॉडल पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2022-23 में 7.0 प्रतिशत - दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत; तीसरी और चौथी तिमाही प्रत्येक में 4.6 प्रतिशत है – जिसमें इस आधारभूत पथ के आसपास जोखिम को लेकर व्यापक रूप से संतुलन बना हुआ है (चार्ट I.10 और सारणी I.3)। 2023-24 के लिए, सामान्य मानसून, और कोई बड़ा बाह्य या नीतिगत झटका न होने को मानते हुए, संरचनात्मक मॉडल अनुमान वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत पर होने का संकेत देते हैं।

आधारभूत वृद्धि पथ के संबंध में ऊर्ध्वगामी और अधोगामी जोखिम हैं। महामारी के घटते खतरे के साथ संपर्क-गहन सेवाओं की मांग में अपेक्षा से अधिक मजबूत विस्तार और त्योहार के खर्च; सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि, बैंक ऋण में सुधार, क्षमता

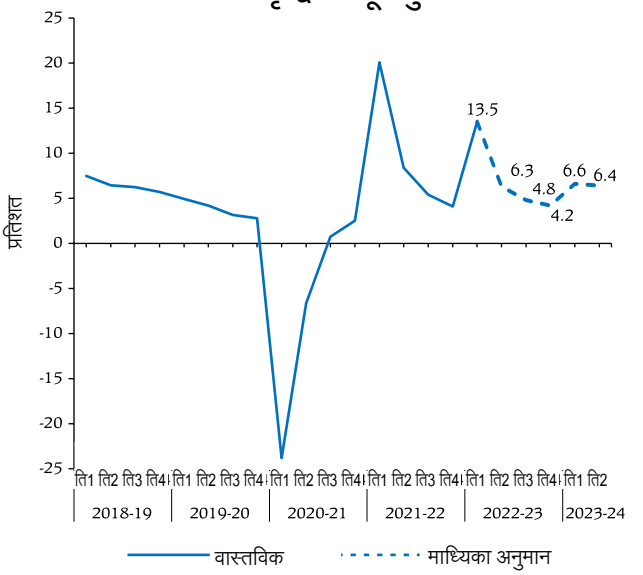
सारणी I.4: कारोबारी प्रत्याशा सर्वेक्षण

मद	एनसीईआर बिजनेस कांफिडेंस इंडेक्स (जुलाई 2022)	फिक्की समग्र बिजनेस कांफिडेंस इंडेक्स (अगस्त 2022)	दून और ब्रेडस्ट्रीट कम्पोजीट बिजनेस आप्टिमिज्म इंडेक्स (सितंबर 2022)	सीआईआई बिजनेस कांफिडेंस इंडेक्स (सितंबर 2022)
सूचकांक का वर्तमान स्तर	138.5	65.0	69.9	62.2
पिछले सर्वे के अनुसार सूचकांक	142.9	67.6	96.6	66.9
% परिवर्तन (ति-दर-ति) क्रमिक	-3.1	-3.8	-27.6	-7.0
% परिवर्तन (वर्ष-दर -वर्ष)	124.1	-8.8	-5.8	-0.6

टिप्पणी : 1. एनसीईआर: नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च।
2. एफआईसीसीआई: फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
3. सीआईआई: कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री।

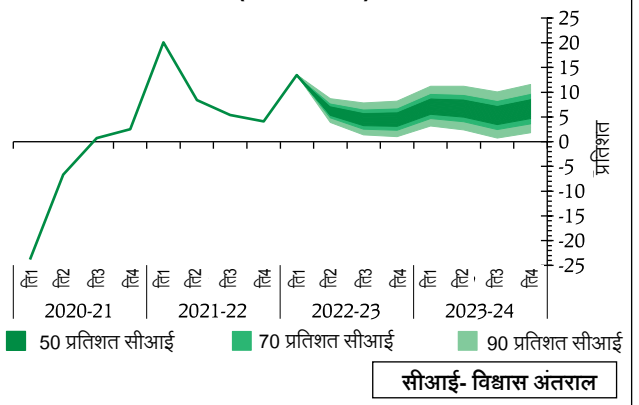
स्रोत: एनसीईआर; फिक्की; सीआईआई; और दून और ब्रेडस्ट्रीट इन्फॉर्मेशन सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

चार्ट 1.9: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान



स्रोत: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण; आरबीआई; और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

चार्ट I.10: वास्तविक जीडीपी वृद्धि का तिमाही पूर्वानुमान (वर्ष-दर-वर्ष)



टिप्पणी: फ़ैन चार्ट बेसलाइन प्रोजेक्शन पथ के आस-पास अनिश्चितता दर्शाता है। बेसलाइन अनुमान सारणी I.2 में निर्धारित धारणाओं पर आधारित हैं। गहरा हरा छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका अर्थ है कि वास्तविक परिणाम गहरे हरा छायांकित क्षेत्र द्वारा दी गई सीमा के भीतर होने की 50 प्रतिशत संभावना है। समान रूप से, 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत विश्वास अंतराल के लिए, वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्र के रूप में दर्शाई गयी सीमा के भीतर होने की क्रमशः 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत संभावना है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

उपयोग में वृद्धि, और स्वस्थ कॉर्पोरेट तुलन-पत्रों से निजी निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिलने; और कच्चे तेल एवं पण्य की कीमतों में तीव्र कमी के मामले में व्यापार शर्तों को लेकर अनुकूल झटके से आधारभूत ट्रैजक्टरी के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इसके विपरीत, भू-राजनीतिक तनाव का बढ़ना, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल एवं अन्य पण्य की कीमतों में और वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं में निरंतर व्यवधान, वैश्विक वित्तीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव में वृद्धि, और वैश्विक व्यापार और मांग में गति का तेजी से धीमा पड़ना आधारभूत वृद्धि पथ के लिए अधोगामी जोखिम पैदा करता है।

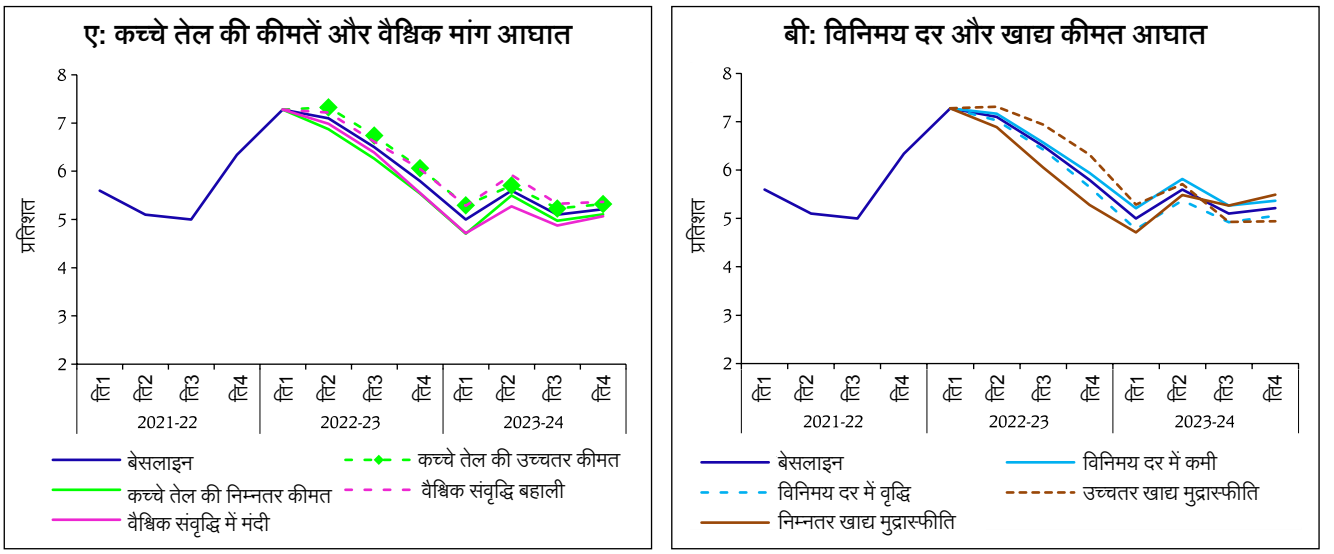
I.4 जोखिम संतुलन

मुद्रास्फीति और वृद्धि के आधारभूत अनुमान सारणी I.2 में निर्धारित प्रमुख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समष्टिआर्थिक चरों की भावी राह संबंधी मान्यताओं पर पूरी तरह से निर्भर करेंगे। हालांकि, जैसा कि पहले कहा गया है, आधारभूत मान्यताओं के आसपास काफी अनिश्चितताएं हैं। यह खंड आधारभूत अनुमानों के आसपास जोखिमों के संतुलन का आकलन करने के लिए संभावित वैकल्पिक परिदृश्यों की खोज करता है।

(i) वैश्विक संवृद्धि संबंधी अनिश्चितताएं

अप्रैल 2022 एमपीआर में चिह्नित वैश्विक वृद्धि के लिए अधोगामी जोखिम को मूर्त रूप मिला है। युद्ध से प्रतिकूल परिस्थितियां, उच्च पण्य कीमतें, सख्त वित्तीय स्थितियां, उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी का बहिर्वाह, और धीमी होती हुई वैश्विक गतिविधियां वैश्विक संवृद्धि को बेसलाइन से नीचे ला सकती हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की चिंता बढ़ रही है और वैश्विक दृष्टिकोण धूमिल है और जोखिम नीचे की ओर झुके हुए हैं। ऐसे परिदृश्य में, यदि वैश्विक वृद्धि बेसलाइन से 100 बीपीएस नीचे है, तो घरेलू वृद्धि और मुद्रास्फीति बेसलाइन ट्रैजक्टरी के नीचे क्रमशः 40 बीपीएस और 20 बीपीएस के आसपास हो सकती है। इसके विपरीत, यदि भू-राजनीतिक तनावों में शीघ्र कमी आती है, पण्यों की कीमतों में गिरावट का हालिया रुझान जारी रहता है, और वैश्विक मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक तेजी से घटती है, तो वैश्विक संवृद्धि को गति मिल सकती है। इस परिदृश्य में, यह मानते हुए कि वैश्विक संवृद्धि में आश्चर्यजनक रूप से 50 बीपीएस की वृद्धि होती है, घरेलू वृद्धि और मुद्रास्फीति क्रमशः लगभग 20 बीपीएस और 10 बीपीएस तक बढ़ सकती है (चार्ट I.11ए और I.12ए)।

चार्ट I.11: बेसलाइन मुद्रास्फीति पथ पर जोखिम परिदृश्य का प्रभाव



स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(ii) कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें

कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं, जो कि भू-राजनीतिक तनाव, प्रतिबंधों और ओपेक *प्लस* द्वारा आपूर्ति प्रबंधन से प्रेरित है। ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन में और कटौती एवं प्राकृतिक गैस की उच्च कीमतों के बीच सर्दियों के मौसम में ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी से कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतों (भारतीय बास्केट) को प्रति बैरल 100 अमेरिकी डॉलर के बेसलाइन से 10 प्रतिशत ऊपर मानते हुए, घरेलू मुद्रास्फीति और वृद्धि बेसलाइन से क्रमशः 30 बीपीएस अधिक और लगभग 20 बीपीएस कमजोर हो सकती है। इसके विपरीत, वैश्विक मांग में कमी और भू-राजनीतिक तनाव में कमी के कारण कच्चे तेल की कीमतें बेसलाइन से नीचे आ सकती हैं। परिणामस्वरूप, यदि कच्चे तेल की कीमतों का भारतीय बास्केट बेसलाइन के सापेक्ष 10 प्रतिशत गिर जाता है, तो मुद्रास्फीति में लगभग 30 बीपीएस की गिरावट और वृद्धि में 20 बीपीएस की बढ़त हो सकती है (चार्ट I.11ए और I.12ए)।

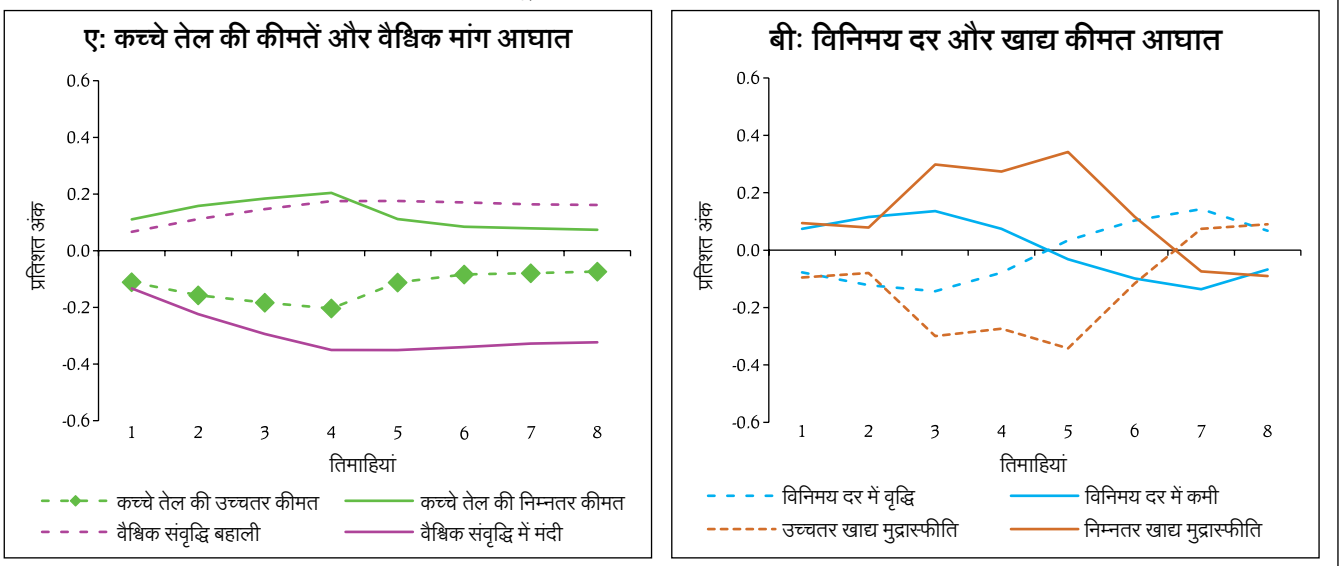
(iii) विनिमय दर

अमेरिकी डॉलर का सामान्य रूप से मजबूत होने, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बिक्री के कारण पहली छमाही में भारतीय रुपये का मूल्यह्रास हुआ। अमेरिका और अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के आसपास अनिश्चितता के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बनी रहने की उम्मीद है, जो भारतीय रुपये पर अधोगामी दबाव डाल सकती है। अगर भारतीय रुपये में बेसलाइन से 5 प्रतिशत की गिरावट आती है, तो मुद्रास्फीति लगभग 20 बीपीएस तक बढ़ सकती है, जबकि निर्यात को बढ़ावा देने के माध्यम से जीडीपी वृद्धि लगभग 15 बीपीएस अधिक हो सकती है। दूसरी ओर, भारत के अपेक्षाकृत बेहतर वृद्धि प्रदर्शन और दृष्टिकोण एवं मजबूत घरेलू समष्टिआर्थिक मूलभत तत्वों को देखते हुए, पोर्टफोलियो इक्विटी प्रवाह अगस्त 2022 में काफी सकारात्मक हो गया और आगे बढ़ सकता है। इस परिदृश्य में, यदि भारतीय रुपये में बेसलाइन के सापेक्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो मुद्रास्फीति और जीडीपी वृद्धि क्रमशः लगभग 20 बीपीएस और 15 बीपीएस तक कम हो सकती है (चार्ट I.11बी और I.12बी)।

(iv) खाद्य मुद्रास्फीति

वैश्विक खाद्य कीमतों में युद्ध-प्रेरित उछाल के कारण पहली छमाही के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रही। वैश्विक खाद्य कीमतों का कम होना शुरू हो गया है और यह घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट से मालूम होता है। इसके अलावा, *खरीफ* की बुवाई ने अपने दीर्घकालिक औसत के साथ जोर पकड़ा है।

चार्ट I.12: आधारभूत संवृद्धि पथ पर जोखिम परिदृश्य का प्रभाव



स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जलाशय का स्तर पिछले वर्ष की और दशकीय औसत से ऊपर है, जो *रबी* फसल के लिए शुभ संकेत है। यद्यपि दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा के असमान वितरण के कारण धान की बुवाई का क्षेत्रफल एक साल पहले की तुलना में कम रहा है, चावल के पर्याप्त बफर स्टॉक, और प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन उपायों से खाद्य मुद्रास्फीति प्रत्याशा से अधिक कम हो सकती है, और हेडलाइन मुद्रास्फीति बेसलाइन से 50 बीपीएस नीचे आ सकती है। इसके विपरीत नाजुक भू-राजनीतिक दृष्टिकोण तथा ऊर्जा तथा उर्वरकों जैसे महत्वपूर्ण इनपुट पर निरंतर इनपुट कीमत दबावों के परिप्रेक्ष्य में खाद्य की वैश्विक कीमतों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही, कटाई के समय बेमौसम की बारिश का घरेलू फसल पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे परिदृश्य में खाद्य कीमतों पर ऊर्ध्वगामी प्रभाव पड़ सकता है और हेडलाइन मुद्रास्फीति बेसलाइन से 50 बीपीएस अधिक हो सकती है (चार्ट I.11बी और I.12बी)।

I.5 निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, और 2022 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की उम्मीद है। सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून, जलाशय की बेहतर स्थिति, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि, क्षमता उपयोग में सुधार, ऋण वृद्धि में व्यापक-आधारित सुधार, सुदृढ़ कॉर्पोरेट और बैंक तुलन-पत्र, आशापूर्ण उपभोक्ता एवं कारोबार विश्वास, महामारी का घटता खतरा, सभी वृद्धि को गति देने के संभावित कारक हैं। जबकि मुद्रास्फीति अप्रैल के उच्च स्तर से कुछ हद तक कम हुई है, वैश्विक कीमतों में कुछ गिरावट के कारण मदद मिली है, यह जनवरी 2022 से लक्ष्य के आसपास ऊपरी सहन सीमा से ऊपर रही है। मौद्रिक नीति निभावकारी दाव को वापस लेने लगी है और उसका ध्यान यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि वृद्धि को सहारा देते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य पर लौट आए। चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण दृष्टिकोण के समक्ष काफी अनिश्चितता पैदा कर रहा है।

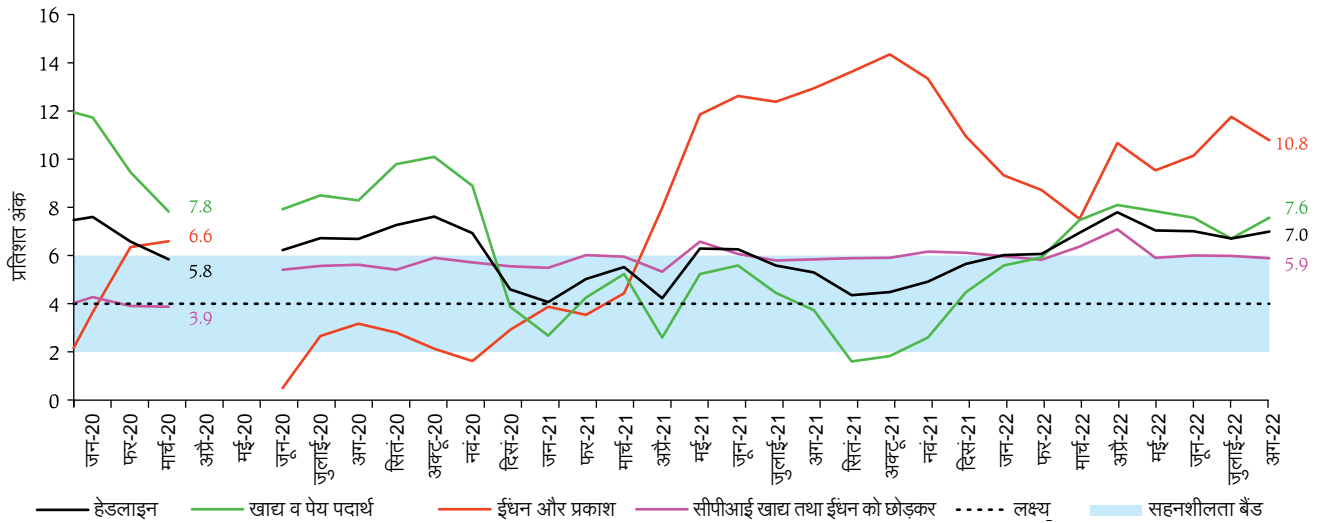
II. मूल्य और लागत

यूक्रेन में टकराव के प्रभाव के चलते फरवरी 2022 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति की वक्र के मार्ग में बदलाव हुआ है। सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में चरम पर थी और तब से इसमें नरमी आई है, लेकिन यह युद्ध-पूर्व के स्तर से ऊपर और ऊपरी स्वीकार्य सीमा के भी ऊपर बनी हुई है। 2022-23 की पहली छमाही के दौरान कुछ नरमी के बावजूद, औद्योगिक और कृषि इनपुट दबाव स्थिर रहे। सांकेतिक ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि मंद रही।

फरवरी 2022 से, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति[1] के प्रक्षेपवक्र (ट्रेजेक्टरी) यूक्रेन में टकराव से उत्पन्न प्रतिकूल वैश्विक पण्य कीमत के आघातों के प्रभाव (स्पिलओवर) से बदल गया है। फरवरी में, यह अनुमान लगाया गया था कि कोविड-19 संक्रमण के कम होने से महामारी की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आया व्यवधान कम हो जाएगा, घरेलू आपूर्ति पक्ष उपायों और वर्ष के दौरान सामान्य मानसून होने के संयोजन से घरेलू मुद्रास्फीति में टिकाऊ नरमी आएगी। वैश्विक पण्य कीमतों के संयोजन में व्यापक रूप से बढ़त, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और रसद बाधाओं, प्रतिबंधों और दूसरे दौर के प्रभावों के साथ युद्ध ने इस धारणा को उलट दिया। वैश्विक वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव आक्रामक मौद्रिक सख्ती और घरेलू वित्तीय बाजारों में परिणामी स्पिलओवर से उत्पन्न मुद्रास्फीति दबावों को बढ़ा देता है।

प्रतिकूल आधार प्रभावों और स्थिर मूल घटक के कारण, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी-फरवरी 2022 के दौरान पहले से ही 6 प्रतिशत की ऊपरी स्वीकार्य सीमा तक पहुंच गई थी।[2] मार्च में आरंभ हुए प्रतिकूल वैश्विक पण्य कीमतों के आघात का प्रसार सभी वस्तुओं पर हुआ। अप्रैल में, गर्मी की लहर और इसके परिणामस्वरूप होने वाली उत्पादन हानि से कीमतों में तेज उछाल आया। परिणामस्वरूप, खाद्य, ईंधन और मुख्य घटकों में हेडलाइन मुद्रास्फीति दो महीनों में 173 आधार अंकों - फरवरी में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में 7.8 प्रतिशत हो गई। आपूर्ति पक्ष में सरकार के विवेकपूर्ण हस्तक्षेप और मार्च 2022

चार्ट II.1: सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष- दर -वर्ष)



टिप्पणी: अप्रैल और मई 2020 के लिए अध्यारोपित सीपीआई प्रिंट को सीपीआई श्रृंखला में एक अंतराल माना गया है।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

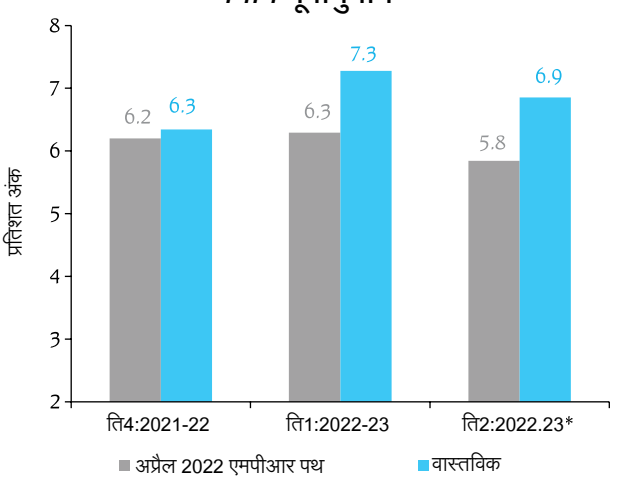
[1] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा उत्पादित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में साल-दर-साल बदलाव से हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापा जाता है।

[2] कोर सीपीआई, यानी वह सीपीआई जिसकी गणना खाद्य और ईंधन को छोड़कर, हेडलाइन सीपीआई से 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और प्रकाश' समूहों को हटाकर की जाती है।

के अपने चरम स्तर से वैश्विक पण्य की कीमतों में कुछ नरमी आई, खाद्य मुद्रास्फीति में अगस्त में 7.0 प्रतिशत की तेजी आने से पहले जुलाई में यह थोड़ा नरम होकर 6.7 प्रतिशत पर रही (चार्ट II.1)।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम में भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुमानों, यदि कोई हो, से वास्तविक मुद्रास्फीति परिणामों में विचलन को निर्धारित करने और उसके अंतर्निहित कारणों की व्याख्या करने का आदेश दिया गया है। अप्रैल 2022 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में 2022-23 की पहली तिमाही के लिए 6.3 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए 5.8 प्रतिशत मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया गया। युद्ध-प्रेरित मूल्य दबावों के साथ-साथ घरेलू आपूर्ति के आघात प्रत्याशा से अधिक मजबूत और सतत रूप से बने रहे, जिसके परिणामस्वरूप पहली तिमाही और दूसरी तिमाही (जुलाई-अगस्त) (चार्ट II.2) में वास्तविक मुद्रास्फीति अनुमानों से लगभग 100 आधार अंक (बीपीएस) अधिक हो गई। ऐसा मोटे तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति में हुई भारी वृद्धि के कारण हुआ।[3] मार्च में वैश्विक खाद्य कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण खाद्य तेलों, उच्च फ़ीड लागत के माध्यम से पशु-आधारित प्रोटीन और निर्यात लिंकेज के माध्यम से गेहूं की घरेलू कीमतों में तेज वृद्धि हुई। इसी समय, भीषण गर्मी की लहर के प्रतिकूल प्रभाव से *रबी* गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा, जून 2022 में टमाटर की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 158.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि उच्च इनपुट लागतों को बिक्री कीमतों में समायोजित किया गया था। अगस्त-सितंबर तक भारतीय रुपये का ₹76 प्रति अमेरिकी डॉलर से लगभग ₹79-80 प्रति अमेरिकी डॉलर तक हुए मूल्यह्रास के

चार्ट II 2: सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष): वास्तविक *बनाम* पूर्वानुमान



*: 2022-23 की संपूर्ण दूसरी तिमाही के लिए पूर्वानुमानों की तुलना में जुलाई-अगस्त 2022 के दौरान वास्तविक औसत मुद्रास्फीति।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

कारण इसमें आई गिरावट ने भी अनुमानिक त्रुटियों में योगदान दिया और आंशिक रूप से मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इसमें समायोजन हुआ।

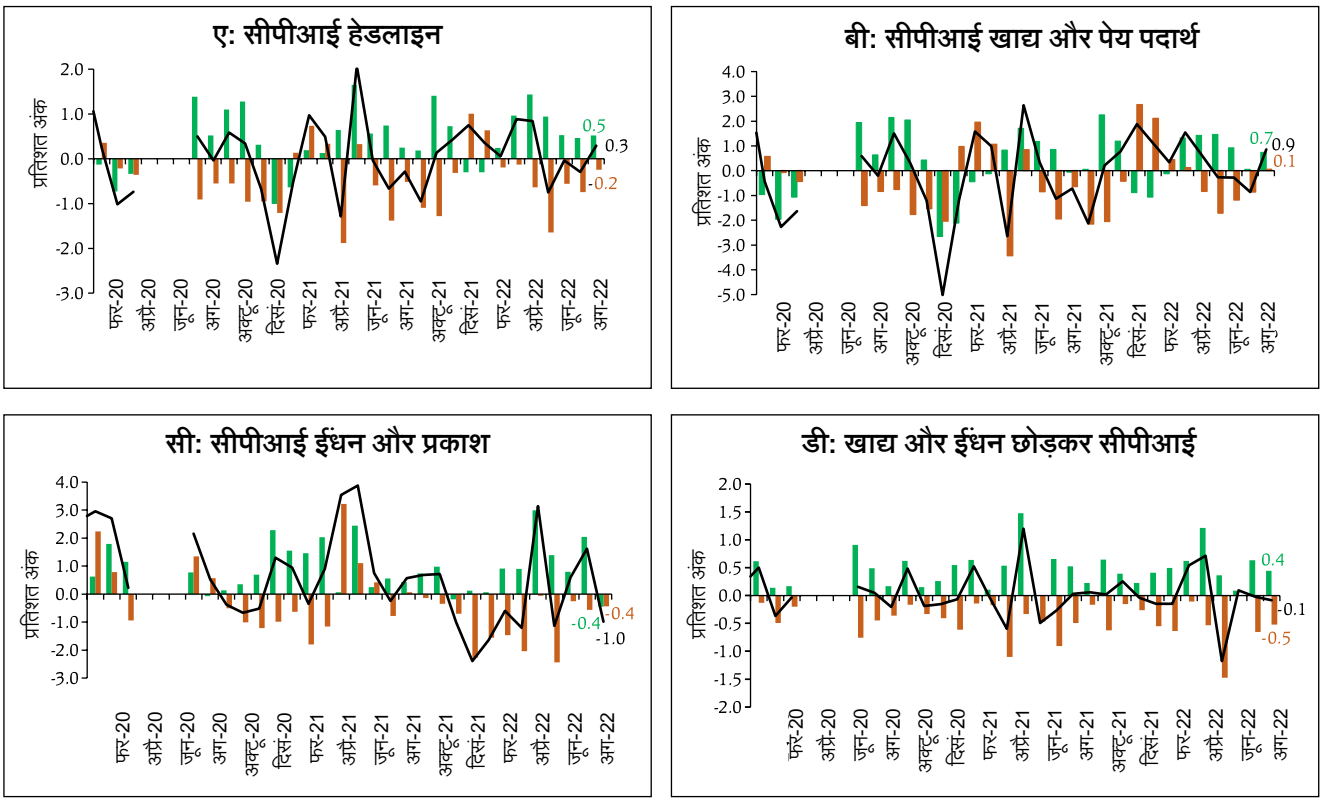
II.1 उपभोक्ता मूल्य

जैसा कि पिछले खंड में बताया गया है, अप्रैल में हेडलाइन मुद्रास्फीति में आया उछाल तेज और व्यापक था। इसके बाद, वृहद अनुकूल आधार प्रभाव द्वारा समर्थित कीमतों की गति में गिरावट से मई-जून[4] में मुद्रास्फीति को 7.0 प्रतिशत तक नीचे ला दिया। मई में गति में गिरावट मुख्य घटक में थी, भले ही खाद्य कीमतों की गति मजबूत बनी रही। जून में, सभी प्रमुख समूहों में हेडलाइन की गति में और नरमी आई। जुलाई में, भले ही हेडलाइन सीपीआई गति जून के स्तर पर अपरिवर्तित रही, अनुकूल आधार

[3] 100 अमरीकी डालर प्रति बैरल की मान्यता को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2022 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में इसे मोटे तौर पर 2022-23 के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

[4] किन्हीं दो महीनों के बीच सीपीआई वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) मुद्रास्फीति में होने वाला परिवर्तन, मूल्य सूचकांक (संवेग) में वर्तमान माह-दर-माह (एम-ओ-एम) में होने वाले परिवर्तन और 12 महीने पहले मूल्य सूचकांक में माह-दर-माह (एम-ओ-एम) में होने वाले परिवर्तन के बीच का अंतर है (आधार प्रभाव)। अधिक विवरण के लिए, सितंबर 2014 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट का बॉक्स I.1 देखें।

चार्ट II.3: सीपीआई मुद्रास्फीति – गति तथा आधार प्रभाव

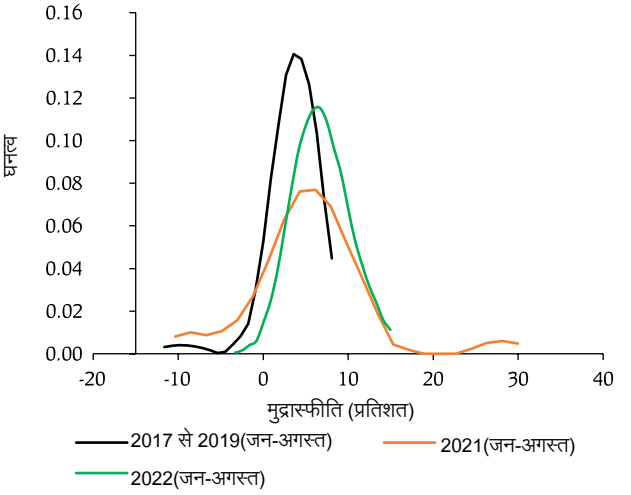


टिप्पणी: अप्रैल और मई 2021 के लिए वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति की गणना एनएसओ द्वारा जारी अप्रैल और मई 2020 के लिए अध्यारोपित सूचकांक के आधार पर की गई है।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रभावों के कारण मुद्रास्फीति में 30 आधार अंकों (बीपीएस) से 6.7 प्रतिशत की कमी आई। 0.5 प्रतिशत की स्थिर गति के साथ अगस्त लगातार तीसरा महीना था; तथापि, अनुकूल आधार प्रभावों के कम होने के कारण मुद्रास्फीति में लगभग 30 आधार अंकों की वृद्धि हुई (चार्ट II.3)।

सीपीआई मुद्रास्फीति वितरण का औसत 2022(जनवरी-अगस्त) में बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गया, जो 2021 में इसी अवधि के दौरान 5.3 प्रतिशत था और 2017-19 (जनवरी-अगस्त) का कोविड-पूर्व औसत 3.4 प्रतिशत था। इसके साथ उच्च औसत दर और मुद्रास्फीति दर के उप-समूह/समूह-वार संवितरण में कम था, जो मुद्रास्फीति के सामान्यीकरण को दर्शाता है (चार्ट II.4), और भविष्य की मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता बढ़ गई (बॉक्स II.1)।

चार्ट II.4: औसत सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) (केरनेल घनत्व अनुमान)



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बॉक्स II.1 : भारत में मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति अनिश्चितता

निरंतर उच्च मुद्रास्फीति उच्च अनिश्चितता और आवंटन अक्षमता को जन्म दे सकती है (फ्रीडमैन, 1977; बॉल, 1992)। हालांकि, मुद्रास्फीति परिवर्तनशीलता का प्रभाव अस्पष्ट हो सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या केंद्रीय बैंक उच्च मुद्रा-स्फीति को सहन करता है (कुकिरमैन और मेल्टज़र, 1986) या यह मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और एक संकुचन नीति (हॉलैंड, 1995) को अपनाता है।

अप्रैल 2005 से जुलाई 2022 की अवधि के लिए सीपीआई डेटा (मौसमी रूप से समायोजित डेटा के आधार पर महीने-दर-महीने प्रतिशत परिवर्तन) का उपयोग करते हुए, समय-भिन्न मुद्रास्फीति अनिश्चितता (या मुद्रास्फीति अस्थिरता) का अनुमान एक सामान्यीकृत ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी (गार्च) मॉडल को नियोजित करके लगाया जाता है। गार्च (2,1)[5] अनुमानों का उपयोग करते हुए विभिन्न परिकल्पनाओं का पता लगाने के लिए तीन विशिष्टताएं अनुमानित हैं। मॉडल I आधारभूत मॉडल है; मॉडल II में, फ्रीडमैन-बॉल परिकल्पना का आकलन करने के लिए मुद्रास्फीति दर को जोड़ा जाता है; मॉडल III में, अनिश्चितता (यानी, मुद्रास्फीति का अंतर) को कूकिरमैन-मेल्टज़र/हॉलैंड परिकल्पना का पता लगाने के लिए माध्य समीकरण में शामिल किया गया है।

सारणी II.1.1: मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति अस्थिरता: गार्च मॉडल का अनुमान

चर	मॉडल I	मॉडल II	मॉडल III
औसत समीकरण			
स्थिरांक	0.46***	0.32***	-0.37***
	(0.05)	(0.04)	(0.14)
मुद्रास्फीति (-1)	0.22***	0.27**	0.25***
	(0.06)	(0.06)	(0.06)
लॉग (गार्च)	-	-	-0.50***
			(0.07)
असंगति समीकरण			
स्थिरांक	0.04	-0.01	0.01*
	(0.03)	(0.01)	(0.01)
एआरसीएच(-1)	0.25***	0.15**	0.47***
	(0.09)	(0.07)	(0.10)
एआरसीएच (-2)	-0.23***	-0.15**	-0.45***
	(0.08)	(0.06)	(0.10)
गार्च(-1)	0.83***	0.82***	0.94***
	(0.18)	(0.06)	(0.03)
मुद्रास्फीति	-	0.09***	-
		(0.02)	
नैदानिकी			
एआरसीएच-एलएम (3)	0.43	1.58	0.46
	(0.73)	(0.20)	(0.71)
एआरसीएच-एलएम (6)	0.61	0.94	0.82
	(0.72)	(0.47)	(0.55)
क्यू^{2}(3)	1.41	4.20	1.39
	(0.77)	(0.24)	(0.71)
क्यू^{2}(6)	3.21	6.01	4.85
	(0.78)	(0.42)	(0.56)
एंगल-एनजी साइन-बायस टेस्ट	2.20	4.34	2.69
	(0.53)	(0.23)	(0.44)

टिप्पणी: ***, ** और * क्रमशः 1, 5 और 10 प्रतिशत के स्तर के महत्व को दर्शाता है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े माध्य और असंगत समीकरणों के लिए मानक त्रुटियों और नैदानिक परीक्षणों के लिए p-मान दर्शाते हैं। मुद्रास्फीति की गणना कीमतों में मौसमी रूप से समायोजित महीने-दर-महीने वृद्धि के रूप में की गई है। विश्लेषण के लिए नमूना अवधि अप्रैल 2005 -जुलाई 2022 है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

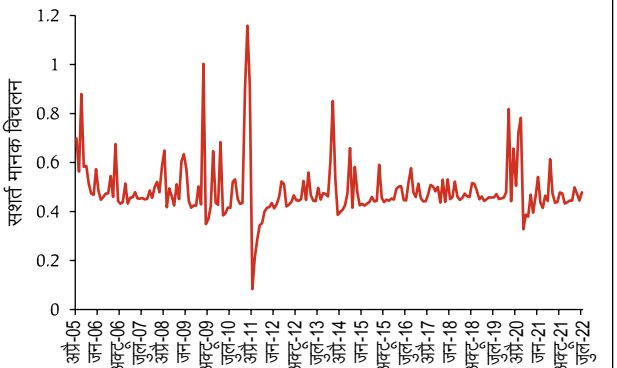
निरंतर उच्च मुद्रास्फीति उच्च अनिश्चितता और आवंटन अक्षमता को जन्म दे सकती है (फ्रीडमैन, 1977; बॉल, 1992)। हालांकि, मुद्रास्फीति परिवर्तनशीलता का प्रभाव अस्पष्ट हो सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या केंद्रीय बैंक उच्च मुद्रा-स्फीति को सहन करता है (कुकिरमैन और मेल्टज़र, 1986) या यह मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और एक संकुचन नीति (हॉलैंड, 1995) को अपनाता है।

अप्रैल 2005 से जुलाई 2022 की अवधि के लिए सीपीआई डेटा (मौसमी रूप से समायोजित डेटा के आधार पर महीने-दर-महीने प्रतिशत परिवर्तन) का उपयोग करते हुए, समय-भिन्न मुद्रास्फीति अनिश्चितता (या मुद्रास्फीति अस्थिरता) का अनुमान एक सामान्यीकृत ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी (गार्च) मॉडल को नियोजित करके लगाया जाता है। गार्च (2,1)[5] अनुमानों का उपयोग करते हुए विभिन्न परिकल्पनाओं का पता लगाने के लिए तीन विशिष्टताएं अनुमानित हैं। मॉडल I आधारभूत मॉडल है; मॉडल II में, फ्रीडमैन-बॉल परिकल्पना का आकलन करने के लिए मुद्रास्फीति दर को जोड़ा जाता है; मॉडल III में, अनिश्चितता (यानी, मुद्रास्फीति का अंतर) को कूकिरमैन-मेल्टज़र/हॉलैंड परिकल्पना का पता लगाने के लिए माध्य समीकरण में शामिल किया गया है।

एआरसीएच और जीएआरसीएच गुणांकों का योग 0.83 और 0.96 (अर्थात, 1 से कम) की सीमा में है, जो यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति की अस्थिरता उच्च स्तर की दृढ़ता किंतु औसत की ओर वापसी का संकेत देती है। महामारी; युद्ध-प्रेरित आपूर्ति व्यवधान; और आवर्तक घरेलू मौसम की गड़बड़ी जैसे बड़े झटकों के अनुक्रम के प्रभाव को दर्शाते हुए मुद्रास्फीति की अस्थिरता ऊंची बनी हुई है (चार्ट II.1.1)।

मुद्रास्फीति के स्तर का मुद्रास्फीति के विचरण (मॉडल II) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो फ्रीडमैन-बॉल परिकल्पना के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराता है। दूसरी ओर, मुद्रास्फीति की अस्थिरता का मुद्रास्फीति की दर (मॉडल III) पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि, ग्रेंजर करणीय विश्लेषण उच्च मुद्रास्फीति से उच्च मुद्रास्फीति अस्थिरता और इसके विपरीत चलने वाली द्वि-दिशात्मक कार्य-कारणता को इंगित करता है (सारणी II.1.2)। कुल मिलाकर, इस विश्लेषण से पता चलता है कि मुद्रास्फीति का उच्च स्तर भविष्य की मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता बढ़ा सकता है और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को प्रभावित कर सकता है जिससे यह संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति को लक्ष्य के आसपास रखने की आवश्यकता है।

चार्ट II.1.1: जीएआरसीएच (2,1) पर आधारित मुद्रास्फीति का सशर्त मानक विचलन



टिप्पणी: अप्रैल और मई 2020 के लिए, एनएसओ द्वारा जारी किए गए अध्यारोपित सूचकांक का उपयोग किया गया है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी.)

[5] एआरएमए (1,1) मॉडल का सशर्त न्यूनतम वर्ग अनुमान इस बात की पुष्टि करता है कि महत्वपूर्ण एआरसीएच प्रभाव हैं।

सारणी II.1.2: मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की अस्थिरता के बीच कारकता

शून्य परिकल्पना	अंतराल 3	अंतराल 6
ग्रेंजर कॉज़ मुद्रास्फीति अस्थिरता का कारण मुद्रास्फीति नहीं है	6.75***	3.54***
ग्रेंजर कॉज़ मुद्रास्फीति का कारण मुद्रास्फीति अस्थिरता नहीं है	1.90	1.02

टिप्पणी: *** और ** क्रमश: 1 और 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्व दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई कर्मचारियों का अनुमान

सन्दर्भ:

फ्राइडमैन, एम. (1977), "नोबेल लेक्चर: इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट", जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 85(3), 451-472

बॉल, एल. (1992), "हाई इन्फ्लेशन राइज इन्फ्लेशन अनसर्टन्टी?", जर्नल ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, 29(3), 371-388

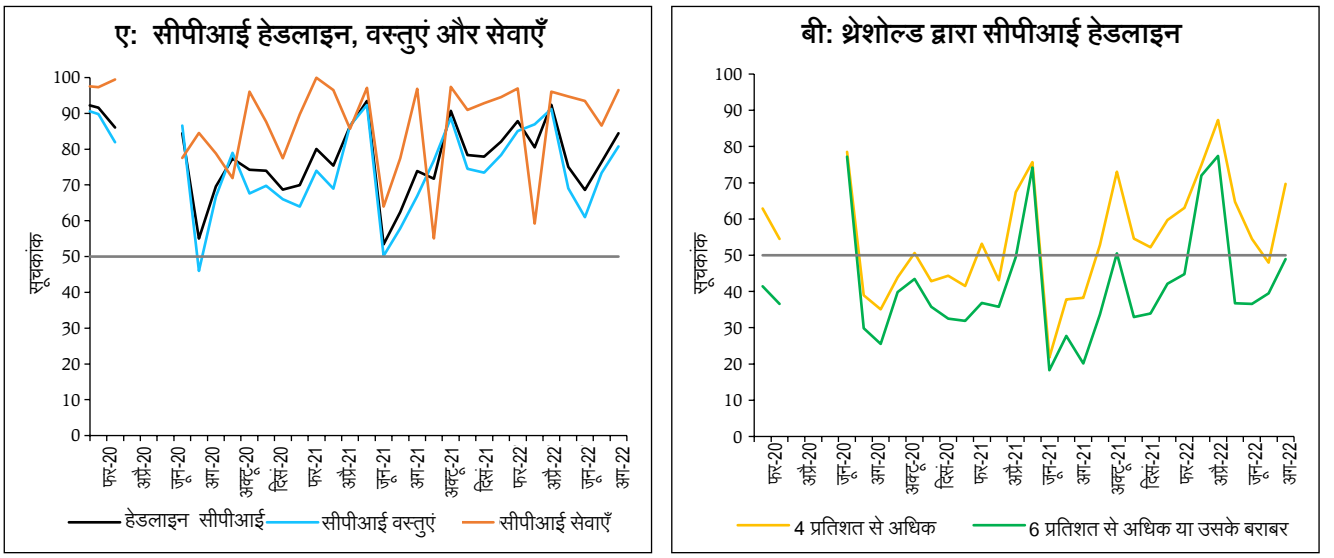
कुकीरमैन, ए., और मेल्टज़र, ए.एच. (1986), "ए थ्योरी ऑफ़ एम्बिगुइटी, क्रेडिबिलिटी, एंड इन्फ्लेशन अंडर डिस्क्रीशन एंड एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन", इकोनोमेट्रिका, 54(5), 1099-1128

हॉलैंड, ए.एस. (1995), "इन्फ्लेशन एंड अंसर्टन्टी: टेस्ट्स फॉर टेम्पोरल ऑर्डरिंग ", जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट एंड बैंकिंग, 27(3), 827-837

बालाजी, बी., दुरई, एस., और रामचंद्रन, एम. (2016)। "द डायनैमिक्स बिट्वीन इंफ्लेशन एंड इंफ्लेशन अंसर्टन्टी: एविडेंस फ्रॉम इंडिया", द जर्नल ऑफ क्वांटिटेटिव इकनॉमिक्स, 14(1), 1-14

प्रसार सूचकांक (डीआई)[6] मार्च-अप्रैल 2022 के दौरान सीपीआई बास्केट में सामान्यीकृत मूल्य वृद्धि को भी प्रमाणित करते हैं (चार्ट II.5ए)। सीपीआई बास्केट की अधिकांश मदें मौसमी समायोजित वार्षिक दर (एसएएआर) के आधार पर थ्रेशोल्ड डीआई[7] 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत से अधिक हैं। हालांकि मई-जून के दौरान कुछ कमी आई लेकिन जुलाई-अगस्त के दौरान कीमतों में बढ़ोतरी में तेजी आई। अगस्त में, अधिकांश सीपीआई बास्केट पंजीकृत कीमतों में 4 प्रतिशत (एसएएआर) से अधिक की वृद्धि हुई (चार्ट II.5बी)।

चार्ट II.5: सीपीआई डिफ्यूज़न सूचियाँ (माह –दर- माह मौसमी रूप से समायोजित)



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[6] सीपीआई प्रसार सूचकांक, जो मूल्य परिवर्तनों के विकीर्णन को मापने का साधन है, सीपीआई बास्केट में वस्तुओं को वर्गीकृत करता है कि पिछले महीने की तुलना में क्या उनकी कीमतें बढ़ी हैं, स्थिर हैं या गिर गई हैं। प्रसार सूचकांक के लिए रीडिंग 50 से अधिक होने का अर्थ है, मूल्य वृद्धि का विस्तार व्यापक रूप से या आम है; यदि 50 से नीचे है, तो सभी वस्तुओं की कीमतों में, व्यापक गिरावट है।

[7] थ्रेशोल्ड डिफ्यूजन इंडेक्स सीपीआई बास्केट में मूल्य वृद्धि के फैलाव को 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की निर्दिष्ट एसएएआर सीमा से ऊपर के मूल्य को दर्शाता है।

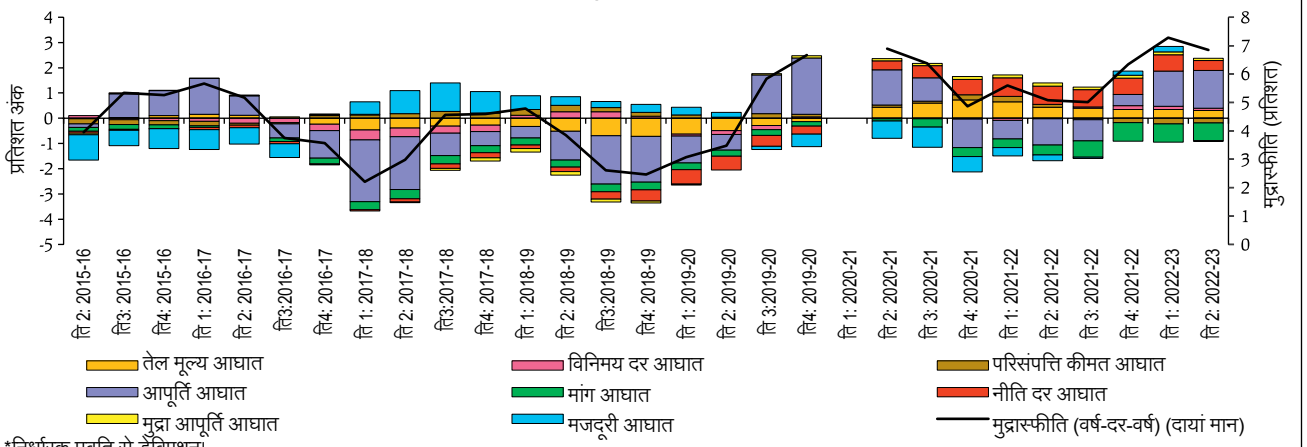
II.2 मुद्रास्फीति के चालक

विभिन्न मैक्रो-कारकों की सापेक्ष भूमिका का पता लगाने के लिए वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (वीएआर)[8] विश्लेषण का उपयोग करते हुए मुद्रास्फीति का एक ऐतिहासिक अपघटन इंगित करता है कि 2022-23 की पहली छमाही के दौरान मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि के लिए मुख्य रूप से ईंधन की कीमत के साथ-साथ खाद्य से प्रतिकूल आपूर्ति-पक्ष के आघातों को कारण माना जा सकता है जबकि समग्र मांग की स्थिति मुद्रास्फीति पर नीचे की ओर दबाव डालती रही (चार्ट II.6ए)।

मार्च-अगस्त 2022 के दौरान वस्तुओं की मुद्रास्फीति ने हेडलाइन मुद्रस्फीति में 86 प्रतिशत का योगदान दिया। नाशवान सामान (7-दिवसीय रिकॉल वाले गैर-टिकाऊ सामान[9]) जैसे

चार्ट II.6: सीपीआई मुद्रास्फीति के संचालक

ए: सीपीआई मुद्रास्फीति का वियोजन*

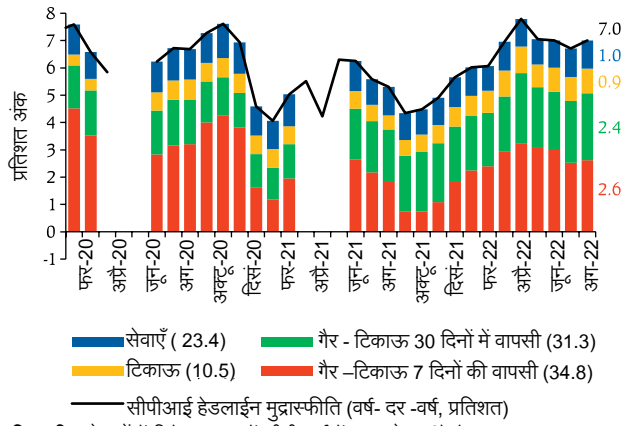


*निर्धारक प्रवृति से डेविएशन।

टिप्पणी: वेक्टर आटो रिग्रेशन का प्रयोग करते हुये अनुमानित (विस्तृत जानकारी के लिए फूटनोट 8 देखें)।

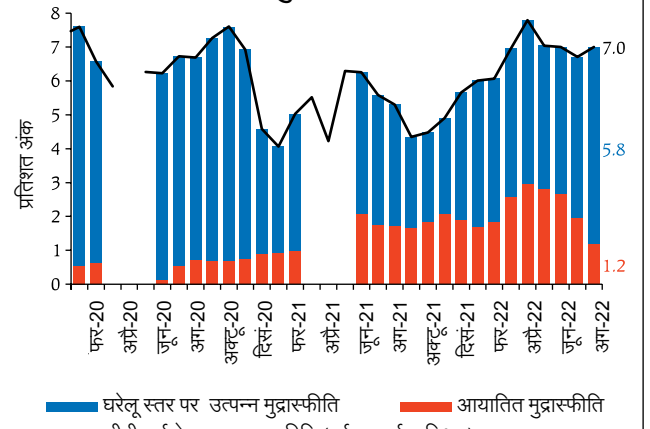
स्रोत: एनएसओ; आरबीआई; पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष(पीपीएसी); बीएसई; श्रमिक ब्यूरो; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बी: वस्तुओं तथा सेवाओं का योगदान



टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई में भार को दर्शाते हैं।

सी: आयातित मुद्रास्फीति का योगदान



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[8] वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (वीएआर) पर आधारित ऐतिहासिक विश्लेषणों का प्रयोग किसी प्रतिदर्श अवधि (2010-11 की चौथी तिमाही से 2022-23 की दूसरी तिमाही तक) के दौरान मुद्रास्फीति में उचार-चढ़ाव पर प्रत्येक आघात के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है जिसके चर (वेक्टर Yt के रूप में दर्शाया गया) इस प्रकार हैं - कच्चे तेल की कीमतें (प्रति बैरल यूएस डॉलर); विनिमय दर (रुपया प्रति अमरिकी डॉलर), परिसंपत्ति मूल्य (बीएसई सेंसेक्स), सीपीआई; उत्पादन अतंर; ग्रामीण मजदूरी; नीतिगत रेपो दर; और मुद्रा आपूर्ति (एम3)। नीतिगत रेपो दर को छोड़कर अन्य सभी चर वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर हैं। वीएआर को सक्षिप्त रूप में Yt =c + A Yt-1 + et के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर et आघातों के एक वेक्टर को दर्शाता है। वोल्ड विश्लेषण का प्रयोग करके, Y_t इसकी निर्धारक प्रवृत्ति के फलन और सभी आघातों के योग et के रूप में दर्शाए जा सकते हैं। इसका निरूपण मुद्रास्फीति की निर्धारक प्रवृत्ति में विचलन को विभिन्न आघातों के योगदान के योग के रूप में विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है।

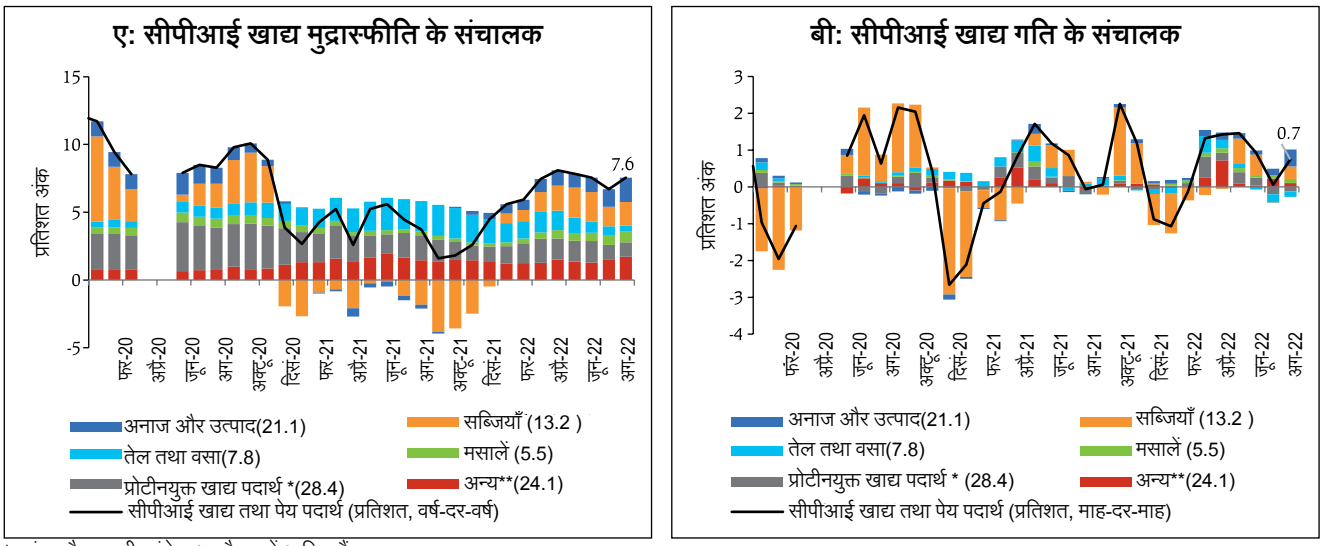
दूध, टमाटर, आलू, खाद्य तेल, पका हुआ भोजन और चिकन के साथ-साथ अधिक अवधि तक टिकने वाले सामान (30-दिवसीय रिकॉल वाले गैर-टिकाऊ सामान), विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पाद जैसे - मिट्टी का तेल, एलपीजी और पेट्रोल के साथ-साथ अनाज और दवाएं, वस्तुओं की मुद्रास्फीति की मुख्य चालक थीं (चार्ट II.6बी)। टिकाऊ वस्तुओं ने समग्र मुद्रास्फीति में 12.8 प्रतिशत का योगदान दिया। सेवाओं का योगदान (भारांक: समग्र सीपीआई में 23.4 प्रतिशत) हेडलाइन मुद्रास्फीति के 14 प्रतिशत के आस-पास रहते हुए स्थिर रहा (चार्ट II.6बी)।

यूक्रेन में टकराव के बाद बढ़ी हुई वैश्विक पण्य कीमतों ने मार्च-जून 2022 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में आयातित घटकों[10] की हिस्सेदारी में वृद्धि की। इसके बाद, जुलाई-अगस्त 2022 में अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में गिरावट ने आयातित मुद्रास्फीति को कम कर दिया। मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती ने घरेलू स्तर पर उत्पन्न मुद्रास्फीति को कम कर दिया (चार्ट II.6सी)।

खाद्य पदार्थ

वैश्विक आपूर्ति में कमी और प्रतिकूल घरेलू मौसम की स्थिति के कारण खाद्य और पेय पदार्थ मुद्रास्फीति (भारांक: सीपीआई में 45.9 प्रतिशत) अप्रैल 2022 में बढ़कर 8.1 प्रतिशत हो गई। इसके बाद, जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 6.7 प्रतिशत पर आ गई जो सरकार के आपूर्ति-पक्ष उपायों, अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतों में कमी और टमाटर की कीमतों में पर्याप्त गिरावट द्वारा समर्थित थी। अगस्त में खाद्य मुद्रास्फीति में काफी वृद्धि दर्ज की गई जिसमें अनाज और सब्जियां इसके प्रमुख चालक थे (चार्ट II.7ए और II.7बी)।

चार्ट II.7: सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति



*: मांस और मछली, अंडे, दूध और दालें शामिल हैं।
**: फल, चीनी, गैर-एल्कोहोलिक पेय पदार्थ और तैयार भोजन शामिल हैं।
टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई खाद्य पदार्थ और पेय में भार को दर्शाते हैं।
स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[9] सीपीआई भार आरेख में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए 2011-12 उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर आशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी) के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। एमएमआरपी के अंतर्गत, पिछले सात दिनों के दौरान अक्सर खरीदी गई वस्तुओं पर किए गए खर्च के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जैसे- खाद्य तेल, अंडे, मछली, मांस, सब्जियां, फल, मसाले, पेय पदार्थ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पान, तंबाकू और मादक पदार्थ- पिछले 365 दिनों के दौरान खरीदे गए कपड़े, बिस्तर, जूते, शिक्षा, चिकित्सा (संस्थागत), टिकाऊ वस्तुएं; और पिछले 30 दिनों में खरीदे गए अन्य सभी खाद्य, ईंधन और प्रकाश, विविध वस्तुएं और सेवाएं जिनमें गैर-संस्थागत चिकित्सा सेवाएं, किराए और कर के आंकड़े शामिल हैं।

[10] घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाली वैश्विक वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद; कोयला; इलेक्ट्रॉनिक सामान; सोना; चांदी; रासायनिक उत्पाद; धातु उत्पाद; कपड़ा; अनाज; दुग्ध उत्पाद, और वनस्पति तेल शामिल हैं - इनका सीपीआई बास्केट में कुल भारांक 36.4 प्रतिशत है।

चार्ट II.8: वित्तीय वर्ष का कीमत बिल्ड अप
(मार्च की तुलना में अगस्त)

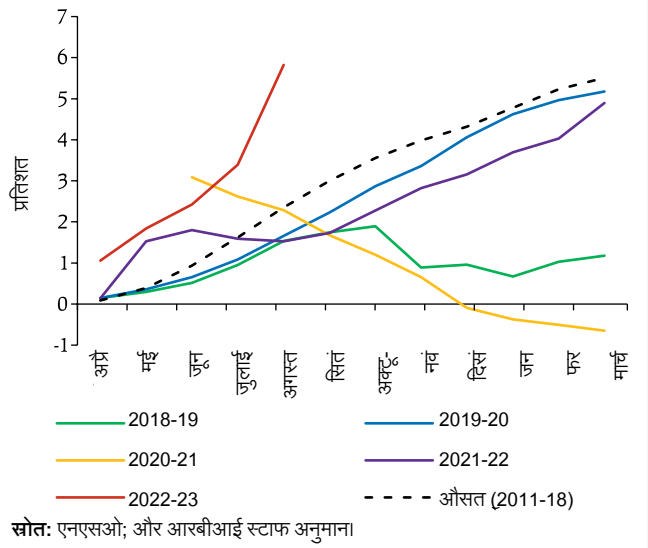


टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई – खाद्य और पेय पदार्थ में भार को दर्शाते हैं।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

भले ही खाद्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी रही, चालू वित्त वर्ष में अब तक (अगस्त से मार्च तक) खाद्य कीमतें ऐतिहासिक आंकड़ों की तुलना में स्थिर रहीं। पहला, मुख्य रूप से मांस और मछली तथा खाद्य तेलों के कारण मार्च 2022 में ही खाद्य कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। दूसरा, जहाँ अनाज (जिनका खाद्य टोकरी में उसके पांचवें हिस्से से अधिक का हिस्सा है) की कीमतों में हुई वृद्धि फलों, मसालों, तैयार भोजन और दूध की ही तरह अपने दीर्घकालिक औसतों से ज्यादा रही थी, परंतु खाद्य तेलों की कीमतों में आयी भारी गिरावट तथा मांस और मछली की कीमतों में मई और जून के ऐतिहासिक उच्च स्तर की तुलना में आयी गिरावट के कारण उसका समायोजन हो गया। तीसरा, अधिक उत्पादन के मद्देनजर प्याज, लहसुन और कुछ अन्य सब्जियों की कीमतों में रही नरमी के कारण सब्जियों की कीमतों में गर्मी की मौसमी वृद्धि सामान्य से कम थी (चार्ट II.8)।

अनाज (जिसकी भारिता सीपीआई में 9.7 प्रतिशत और खाद्य और पेय समूह में 21.1 प्रतिशत है) की कीमतों में तेज उछाल के कारण मुद्रास्फीति मार्च 2022 में 5.0 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में 9.6 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.9)। अनाजों के बीच प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गर्मी की लहर के प्रकोप, यूक्रेन में युद्ध के कारण वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी, उच्च निर्यात (अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान सालाना आधार पर 157 फीसदी), और स्टॉक में गिरावट (1 सितंबर को बफर मानदंडों का 0.9 गुना) उत्पादन कम होने (2021-22 में (-) 2.5 प्रतिशत) के कारण मार्च से गेहूं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, मई 2022 से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए थे, और 27 अगस्त, 2022 से गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मई-सितंबर 2022 के लिए *प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पीएमजीकेएवाई) के तहत गेहूँ का स्थान चावल द्वारा ले लिए जाने, निर्यात के बढ़ जाने (अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान सालाना 9.0 प्रतिशत) और खरीफ की बुवाई-क्षेत्रफल

चार्ट II.9: सीपीआई-अनाज और उत्पाद
(संचयी गति)



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

में गिरावट तथा कम उत्पादन की आशंका के कारण चावल की कीमतों में वृद्धि हुई। ऐसी आशा की जा रही है कि चावल के बड़े स्टॉक (1 सितंबर, 2022 तक बफर मानदंड का 2.6 गुना) और बासमती तथा उबला चावल को छोड़कर अन्य चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाए जाने के साथ-साथ चावल निर्यात पर प्रतिबंध के कारण कीमतों पर पड़ने वाले अनुचित दबाव को रोका जा सकेगा।

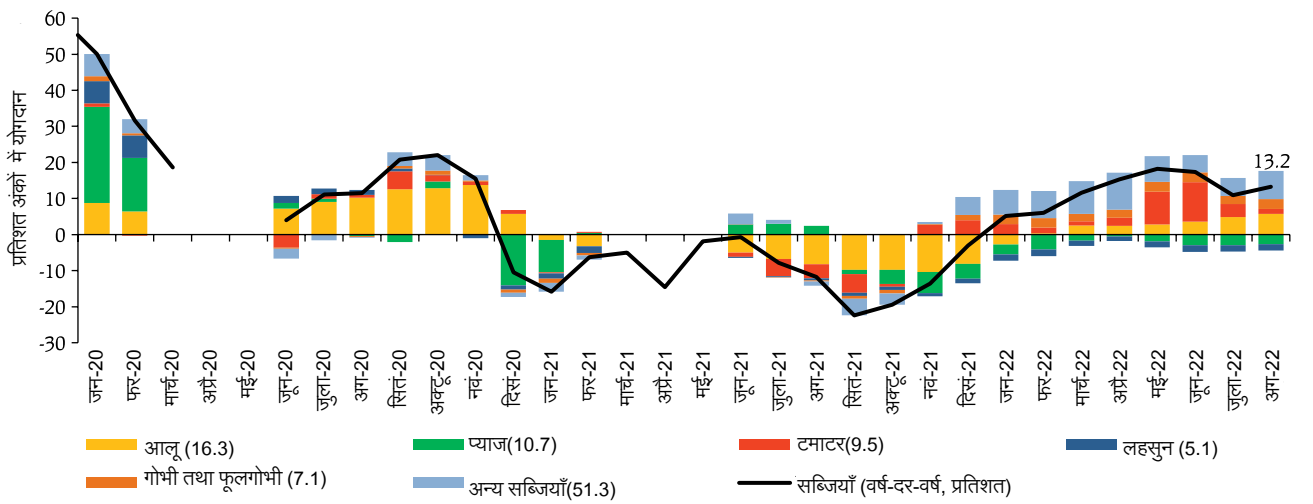
सब्जियों की कीमतों (सीपीआई में 6.0 प्रतिशत भारिता एवं खाद्य और पेय समूह में 13.2 प्रतिशत) में मुद्रास्फीति मार्च-अगस्त 2022 के दौरान दोहरे अंकों में रही, जो मई में चरम पर थी। टमाटर की कीमतों में तीव्र वृद्धि (अप्रैल-जून 2022 के दौरान 113.5 प्रतिशत) और साथ ही अन्य सब्जियों की कीमतों में वृद्धि जो कि गर्मी के दिनों में सामान्यतया होने वाली मूल्यवृद्धि को दर्शाती है, वही इसकी प्रमुख वाहक रही (चार्ट II.10)। अप्रैल-अगस्त के दौरान प्याज और लहसुन के औसतन नकारात्मक योगदान ने मुद्रास्फीति के दबाव को आंशिक रूप से कम किया।

प्रमुख सब्जियों में, मार्च-मई 2022 के दौरान प्याज की कीमतों में नरमी आयी क्योंकि उत्पादन अधिक हुआ था (2021-22 में 19 प्रतिशत की वृद्धि) और खरीद रिकॉर्ड स्तर पर की गयी थी (2022-23 में 2.5 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) का बफर स्टॉक)। इसके बाद, जून-अगस्त 2022 के दौरान कीमतें सामान्य मौसमी पैटर्न के अनुरूप ही बढ़ीं। आलू की कीमतों में मार्च-अगस्त 2022 के दौरान कम उत्पादन (2021-22 में (-) 4.6 प्रतिशत) के कारण वृद्धि हुई। बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भूटान से 30 जून, 2023 तक आलू के मुक्त आयात की अनुमति दी गयी। उत्तर भारत में निचले क्षेत्रों में कम उत्पादन होने और गर्मी की लहर के प्रभाव और कर्नाटक में हुई अत्यधिक बारिश और चक्रवात के कारण उत्पादन में आयी गिरावट (2021-22 में (-) 4.0 प्रतिशत) के परिणामस्वरूप अप्रैल-जून 2022 के दौरान टमाटर की कीमतों में नाटकीय वृद्धि हुई। ऊंची कीमतों की आशा में आयी उत्पादन प्रतिक्रिया के कारण मंडी में भारी आवक हुई और जुलाई-अगस्त 2022 के दौरान टमाटर की कीमतों में नरमी आयी।

केला, सेब, अंगूर और सूखे मेवों की बढ़ी हुई कीमतों के कारण फलों (जिसकी भारिता सीपीआई में 2.9 प्रतिशत और खाद्य और पेय समूह के भीतर 6.3 प्रतिशत है) की कीमतों में मुद्रास्फीति मार्च 2022 में 2.5 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में 7.4 प्रतिशत हो गई। गर्मी की लहर के प्रभाव और बेमौसम बारिश के कारण फसल को हुई क्षति के कारण अप्रैल 2022 में आम की कीमतों में उछाल के कारण भी फलों की कीमतें बढ़ीं।

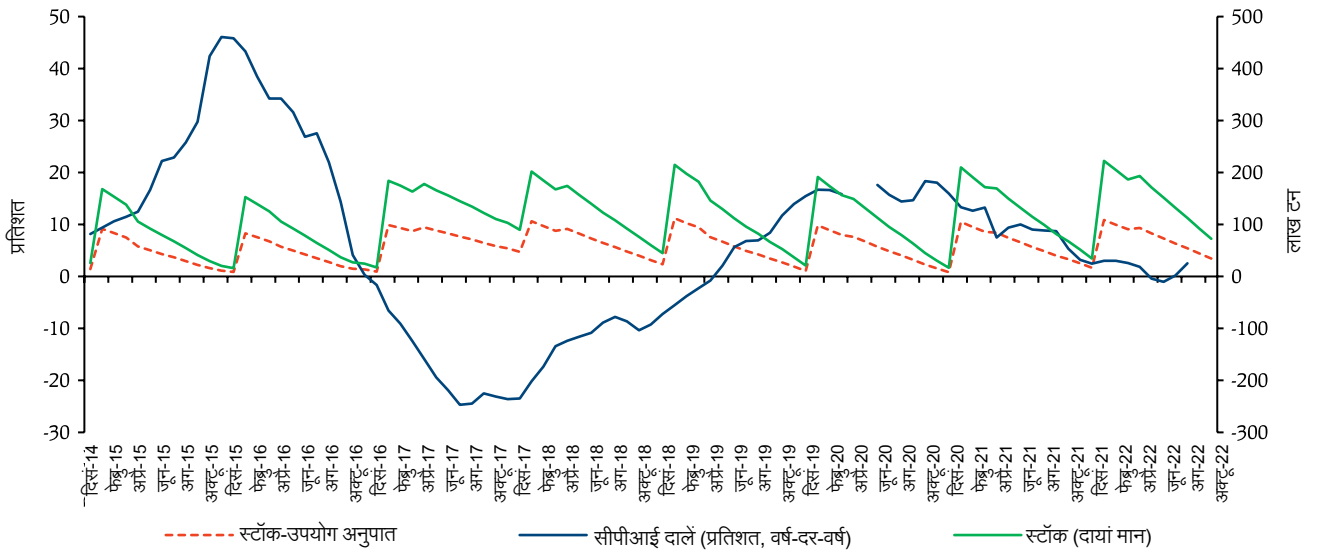
दलहन (वनस्पति-आधारित प्रोटीन) की कीमतों की मुद्रास्फीति (जिसकी भारिता सीपीआई में 2.4 प्रतिशत और खाद्य और पेय समूह में 5.2 प्रतिशत है) में मार्च 2022 से जून तक मंदी रही, जिसके बाद जुलाई-अगस्त के दौरान इसमें तेजी

चार्ट II.10: सब्जी मुद्रास्फीति के संचालक (वर्ष-दर-वर्ष)



टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई –सब्जियों में भार को दर्शाते हैं। मार्च, अप्रैल और मई 2020 माह के लिए एनएसओ द्वारा मदवार आंकड़े जारी नहीं किए गए थे।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.11: दालें मुद्रास्फीति और स्टॉक-उपयोग अनुपात– मासिक तुलन पत्र



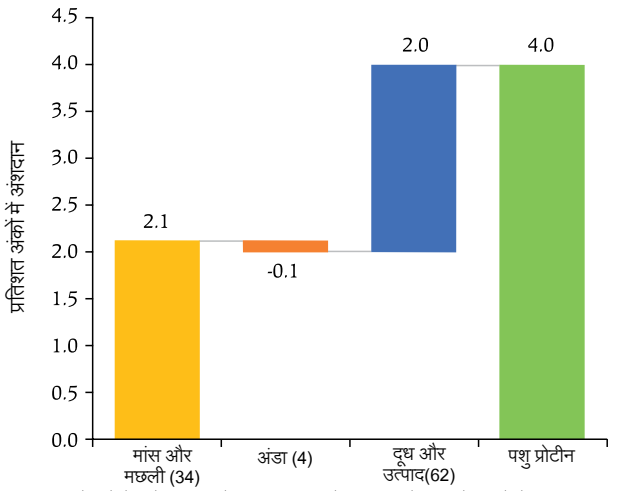
स्रोत: एमओएसपीआई; डीजीसीआईएस; सीएसीपी; कृषि मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

आई(चार्ट II.10)। सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष में किए गए उपायों के अनुरूप 2022-23 की पहली तिमाही में कीमतों में नरमी आई, जिसमें शामिल हैं- 'मुक्त श्रेणी' के तहत अरहर और उड़द आयात का 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाना; 31 मार्च 2023 तक मसूर की दाल पर कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर (एआईडीसी) को 10 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत करना; और अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन (2021-22 में 8.8 प्रतिशत)। हालांकि, जुलाई-अगस्त के दौरान दलहन की मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई, जो खरीफ बुवाई में कमी और तुअर और उड़द के उत्पादन में अपेक्षित कमी के कारण प्रेरित थी। प्रतिकूल आधार प्रभावों ने भी दलहन की मुद्रास्फीति में वृद्धि में योगदान दिया। हालांकि स्टॉक-टू-यूज (एसटीयू) अनुपात अपेक्षाकृत अधिक रहने (चार्ट II.11), केंद्रीय पूल स्टॉक के लिए की गयी जोरदार खरीद और आपूर्ति-पक्ष में किए गए हस्तक्षेप- जैसे कि खुला बाजार परिचालन और साथ ही, कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को छूट पर चना दाल मुहैया कराने का निर्णय – को देखते हुए ऐसी आशा की जा रही है कि दूसरी छमाही में दलहनों की कीमतों पर दबाव कम होगा।

पशु आधारित प्रोटीनयुक्त वस्तुओं की बात करें तो, कीमतें 2022-23 की पहली छमाही में तेजी से बढ़ीं जिसका कारण था मांस और मछली (जिसकी भारिता सीपीआई में 3.6 प्रतिशत एवं खाद्य और पेय समूह के भीतर 7.9 प्रतिशत है) तथा दूध और उससे बने उत्पादों (जिनकी भारिता सीपीआई में 6.6 प्रतिशत एवं खाद्य और पेय समूह के भीतर 14.4 प्रतिशत है) की कीमतों में आया उछाल। मांस और मछली के मामले में, मार्च-जून 2022 के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि गर्मी जल्दी शुरू हो गयी थीं और साथ में गर्मी की लहर का प्रकोप भी था जिसके कारण चारे की लागत बढ़ गयी थी। जुलाई-अगस्त 2022 के दौरान मांग में आयी मौसमी कमी (श्रावण माह के कारण) और आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सोयामील के आयात के कारण कीमतों पर दबाव कम हुआ। इसके विपरीत, अनुकूल आधार प्रभावों के साथ-साथ कीमतों में गिरावट ने अप्रैल-अगस्त 2022 के दौरान अंडे की कीमत में अपस्फीति उत्पन्न कर दी। मार्च-अगस्त 2022 के दौरान दूध और उससे बने उत्पादों की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई, क्योंकि प्रमुख दुग्ध सहकारी समितियों (जैसे अमूल और मदर डेयरी) ने इनपुट लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए मार्च और अगस्त 2022 में खुदरा कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की थी। इसी का अनुकरण करते हुए अन्य राज्य सहकारी समितियों द्वारा भी कीमतें बढ़ा दी गयी (चार्ट II.12)।

तेल और वसा की मुद्रास्फीति (जिसकी भारिता सीपीआई में 3.6 प्रतिशत एवं खाद्य और पेय समूह के भीतर 7.8 प्रतिशत है) में 2022-23 की पहली छमाही के दौरान नरमी आयी, जो दो वर्षों से अधिक समय तक दोहरे अंकों में रहने के बाद अगस्त में 4.6 प्रतिशत तक पहुंच गई (चार्ट II.13)। मुद्रास्फीति में

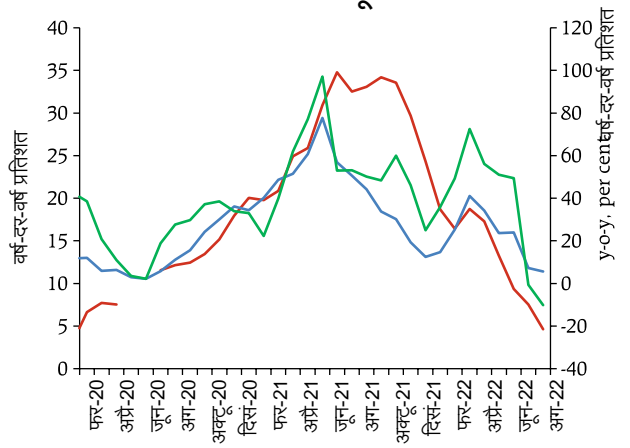
चार्ट II.12: पशु प्रोटीन की कीमतों के संचालक (2021-22 की दूसरी छमाही की तुलना में 2022-23 की पहली तिमाही)



टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई-पशु प्रोटीन समूह में भार को दर्शाते हैं।
छ1: 2022-23 अप्रैल-अगस्त को संदर्भित करता है।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

आयी कमी को वैश्विक कीमतों में आ रही नरमी, सरकार द्वारा किए गए आपूर्ति पक्ष के उपायों और अपेक्षाकृत अधिक घरेलू उत्पादन (2021-22 में 4.9 प्रतिशत) से सहारा मिला। खाद्य तेलों की वैश्विक कीमतें, जो यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के साथ मार्च में तेजी से बढ़ी थीं, 23 मई 2022 से निर्यात प्रतिबंध (जो 28 अप्रैल 2022 को लगाए गए थे) को हटाने, 31 अगस्त 2022 तक निर्यात लेवी को हटाने और इंडोनेशिया द्वारा निर्यात

चार्ट II.13: खाद्य तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव: वैश्विक बनाम घरेलू



स्रोत: विश्व बैंक पिंक शीट; एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

शुल्क में कमी किए जाने के कारण उनमें कमी आयी। सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के संबंध में उठाए गए कदमों के कारण भी कीमतों पर दबाव कम हुआ। इसमें खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाना, 31 मार्च 2023 तक मूल सीमा शुल्क(बीसीडी) को घटाकर 0 प्रतिशत करना, वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के लिए प्रत्येक 2.0 मिलियन टन आयात के लिए टैरिफ रेट कोटा(टीआरक्यू) का 0 प्रतिशत बीसीडी और एआईडीसी पर आबंटन तथा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि (5.4 प्रतिशत से 8.9 प्रतिशत की वृद्धि) शामिल है। दूसरी ओर दूध की बढ़ती कीमतों के कारण घी और मक्खन की कीमतों में तेजी का दबाव बना।

चीनी और कन्फेक्शनरी (जिसकी भारिता सीपीआई में 1.4 प्रतिशत एवं खाद्य और पेय समूह में 3.0 प्रतिशत है) की कीमतों में मार्च-जुलाई 2022 के दौरान नरमी बनी रही क्योंकि उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक हुआ था (2022-23 में गन्ने के उत्पादन में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि) और पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 जून 2022 से चीनी पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हालांकि, अगस्त 2022 में कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि निर्यात सीमा में ढील दिए जाने से निर्यात अपेक्षाकृत अधिक रहा (जो अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान सालाना आधार पर 32.5 प्रतिशत बढ़ गया) और त्योहारी मांग अच्छी रहने की आशा थी।

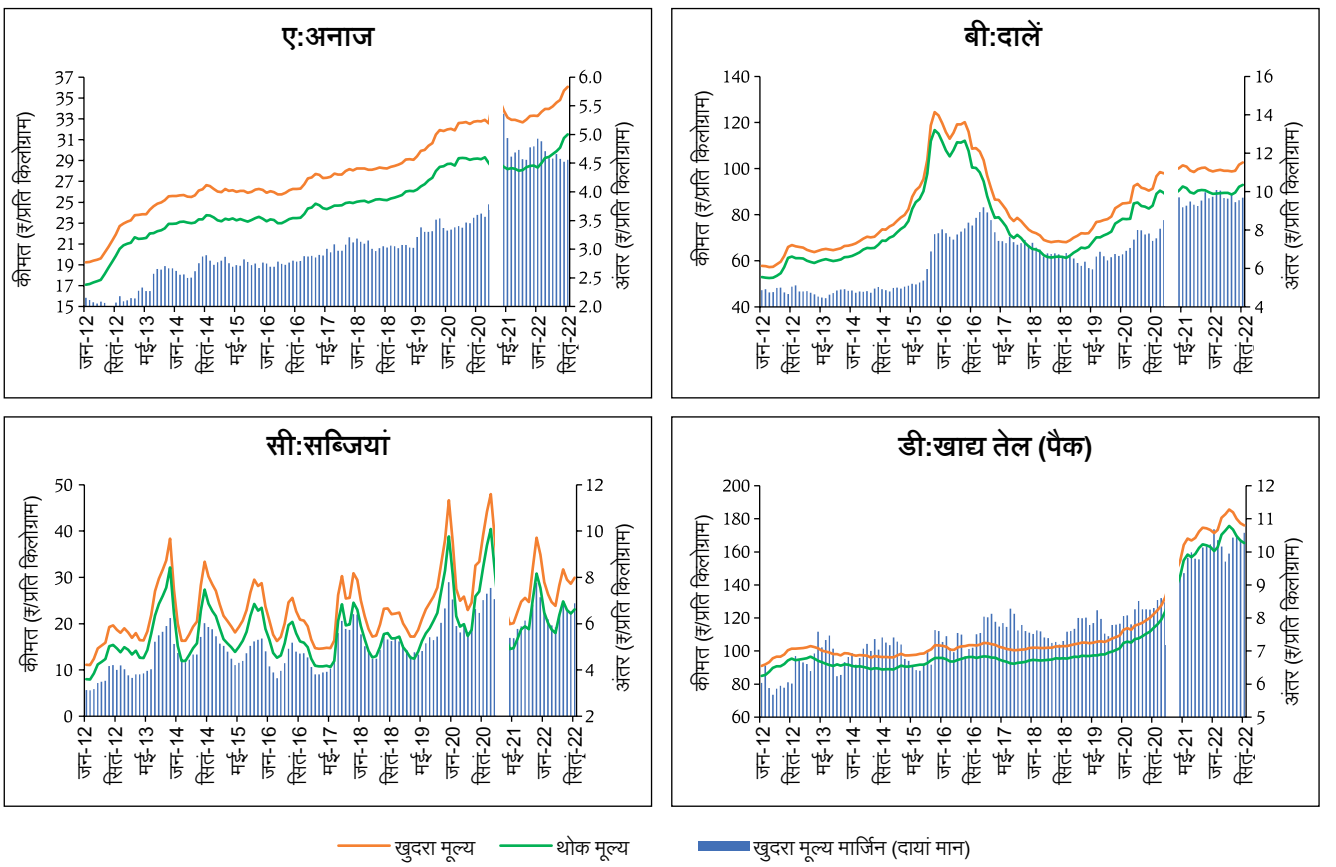
अन्य खाद्य वस्तुओं में मसालों की कीमतों में मुद्रास्फीति 2022-23 की पहली छमाही के दौरान दहाई अंकों में बनी रही, जो (2021-22 में (-) 1.9 प्रतिशत), विशेष रूप से धनिया, जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च जैसे प्रमुख मसालों के मामले में उत्पादन कम रहने को प्रतिबिंबित करते हैं। इसके अलावा, तैयार भोजन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, जो खाद्य तेलों, एलपीजी और परिवहन खर्च जैसी इनपुट लागत में वृद्धि को दर्शाती है।

खुदरा मार्जिन

अनाज और दालों के लिए खुदरा मूल्य मार्जिन - खुदरा और थोक मूल्यों का अंतर - जो कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के

[11] मद स्तर की खुदरा और थोक कीमतों को मद स्तर के सीपीआई भार का उपयोग करके संबंधित उपसमूह पर एकत्रित किया गया है। डीसीए द्वारा मूल्य संग्रह तंत्र और मद प्रकारों में किए गए बदलाव के कारण जनवरी-मार्च 2021 के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है।

चार्ट II.14: खुदरा, थोक मूल्य और मार्जिन



स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग;उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बाद से बढ़ रहा था, पहली छमाही के दौरान ऊंचे स्तर पर बना रहा। खाद्य तेलों में मार्जिन थोक मूल्यों की तुलना में खुदरा सरसों तेल की कीमतों में उच्च स्तर की नरमी के कारण अप्रैल, 2022 में कुछ हद तक नरम हुआ। सब्जियों के मामले में, मई-जून 2022 में टमाटर की खुदरा कीमतों में तेज वृद्धि के कारण मार्जिन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बाद में टमाटर की कीमतों में सुधार के साथ वे नरम हो गए। (चार्ट II.14)

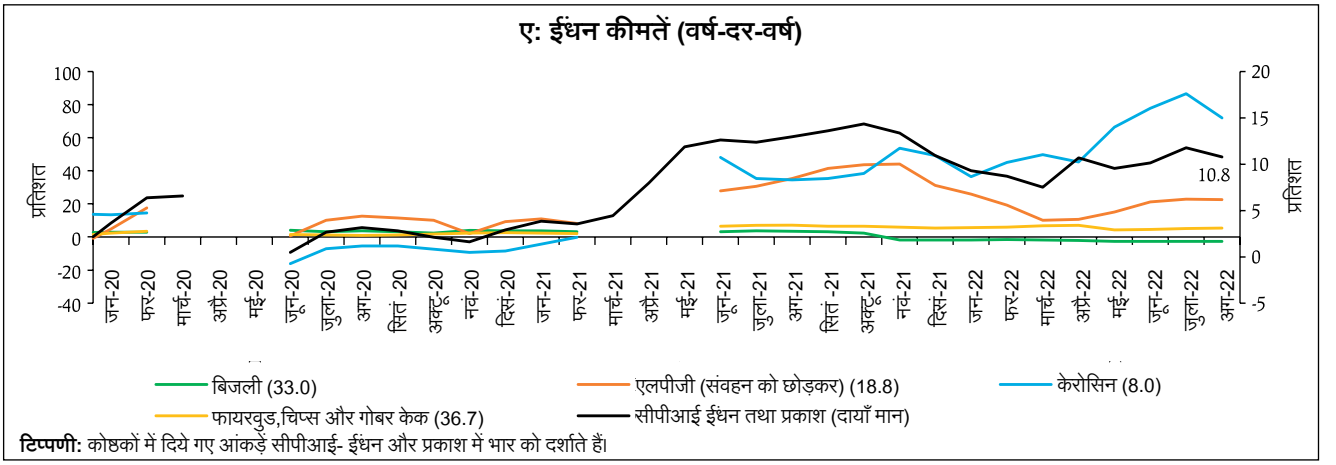
ईंधन

यूक्रेन में टकराव के बाद से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल को दर्शाती तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और सब्सिडी-प्राप्त मिट्टी के तेल (पीडीएस) की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण सीपीआई ईंधन मुद्रास्फीति मार्च, 2022 में 7.5 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई,2022 तक 11.8 प्रतिशत हो गई। किरोसिन तेल (पीडीएस) की कीमतों में गिरावट के कारण अगस्त में ईंधन मुद्रास्फीति नरम होकर 10.8 प्रतिशत पर आ गई जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट को दर्शाती है । 2022 में अब तक बिजली की कीमतों में अपस्फीति बनी हुई है। (चार्ट II.15)

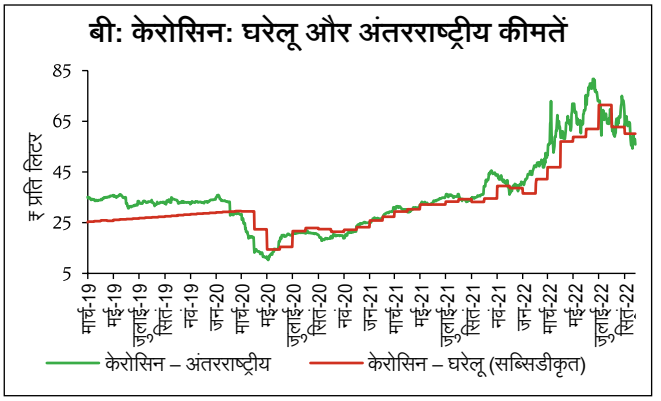
कोर

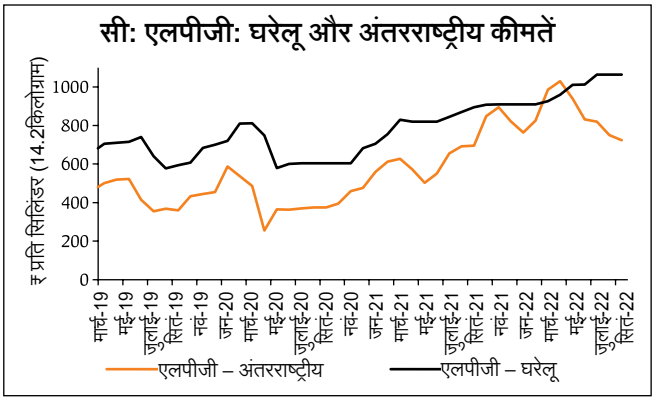
कोर मुद्रास्फीति, यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति, युद्ध की शुरुआत के बाद फरवरी में 5.8 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर अप्रैल,2022 में 7.1 प्रतिशत हो गई। इसके बाद अनुकूल आधार प्रभावों, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी तथा कीमतों की गति में कुछ गिरावट के कारण यह थोड़ी कम हुई। जून-अगस्त के दौरान, मूल मुद्रास्फीति लगभग 6.0 प्रतिशत पर स्थिर रही और यह पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी जैसी अन्य अस्थिर वस्तुओं को शामिल नहीं करने पर भी रही (सारणी II.1)।

चार्ट II.15: सीपीआई ईंधन समूह मुद्रास्फीति



टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े सीपीआई- ईंधन और प्रकाश में भार को दर्शाते हैं।





टिप्पणी: (1) केरोसिन के लिए अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक मूल्य सिंगापुर जेट केरो स्पॉट मूल्य है।
(2) एलपीजी के लिए अंतरराष्ट्रीय मूल्य सऊदी ब्यूटेन और प्रोपेन के लिए ब्लूमबर्ग स्पॉट मूल्य पर आधारित है, जो क्रमश: 60:40 के अनुपात में संयुक्त है। ये अंतरराष्ट्रीय उत्पाद मूल्य संकेतक आयात मूल्य हैं। अधिक जानकारी www.ppac.org.in पर उपलब्ध है।
(3) एलपीजी और केरोसिन की घरेलू कीमतें इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड(आईओसीएल) के चार महानगरों की औसत कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
स्रोत: एनएसओ; ब्लूमबर्ग; आईओसीएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी II.1: मूल मुद्रास्फीति के अपवाद-आधारित उपाय (वर्ष-दर-वर्ष)

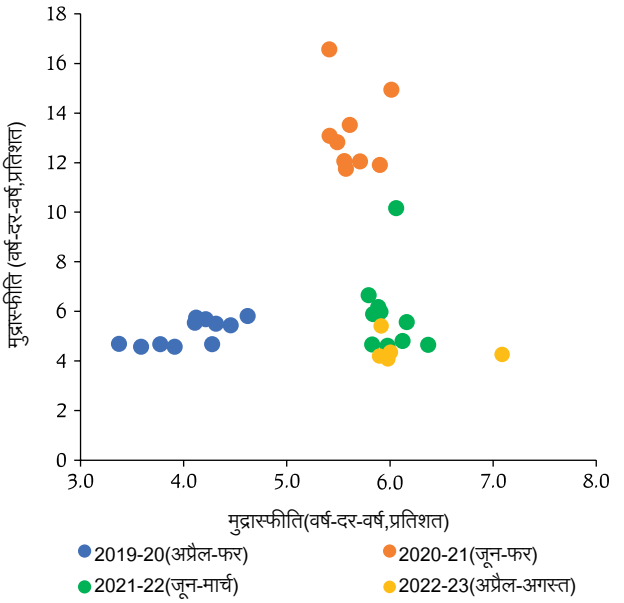
अवधि	खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई (47.3)	खाद्य,ईंधन, पेट्रोल और डीज़ल को छोड़कर सीपीआई (45.0)	खाद्य,ईंधन, पेट्रोल, डीज़ल स्वर्ण और चांदी को छोड़कर सीपीआई (43.8)
जून-21	6.1	5.3	5.4
सितंबर -21	5.9	5.2	5.6
दिसं-21	6.1	5.6	5.9
जन-22	6.0	5.6	5.8
फर-22	5.8	5.6	5.7
मार्च-22	6.4	6.2	6.1
अप्रैल-22	7.1	6.5	6.4
मई-22	5.9	5.5	5.5
जून-22	6.0	6.1	6.1
जुलाई-22	6.0	6.3	6.4
अगस्त-22	5.9	6.2	6.2

टिप्पणी: (1) कोष्ठकों में दिए गए आंकडें सीपीआई में भार को दर्शाते हैं।
(2) हेडलाइन सीपीआई से अवशिष्ट के रूप में व्युत्पन्न।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

वर्ष 2021 के बाद से कोर मुद्रास्फीति विनिर्माण और सेवाओं में बार-बार होने वाले लागत-प्रेरित आघातों (चार्ट II.16) के कारण लगातार बनी और बढ़ी हुई है। वर्ष 2022-23 (अप्रैल-अगस्त) के दौरान कोर मुद्रास्फीति औसतन 6.2 प्रतिशत (एक साल पहले 5.9 प्रतिशत) रही जिसका दबाव व्यापक रूप से, विशेषत: वस्तुओं वाले घटक पर पड़ा था (चार्ट II.17)।

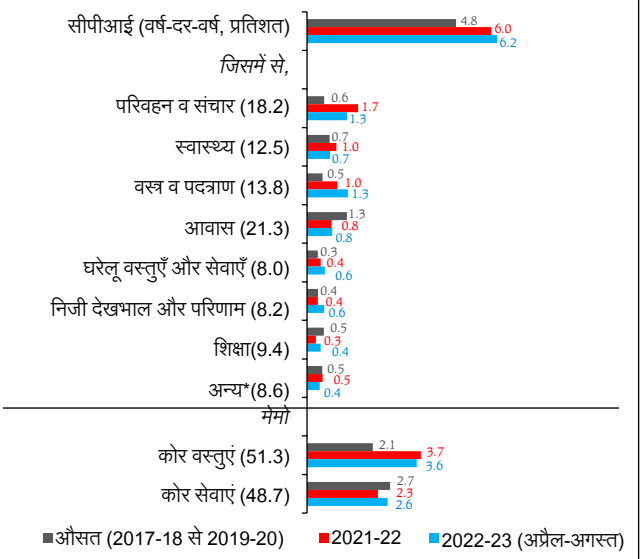
फरवरी और अप्रैल, 2022 के बीच कोर मुद्रास्फीति में 126 आधार अंकों का उछाल काफी हद तक फरवरी के अंत में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और सोने की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव-विस्तार (स्पिलओवर) से प्रभावित था। चूंकि मार्च में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गईं, घरेलू पेट्रोल और डीजल पंप

चार्ट II.16: खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति: सातत्य



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

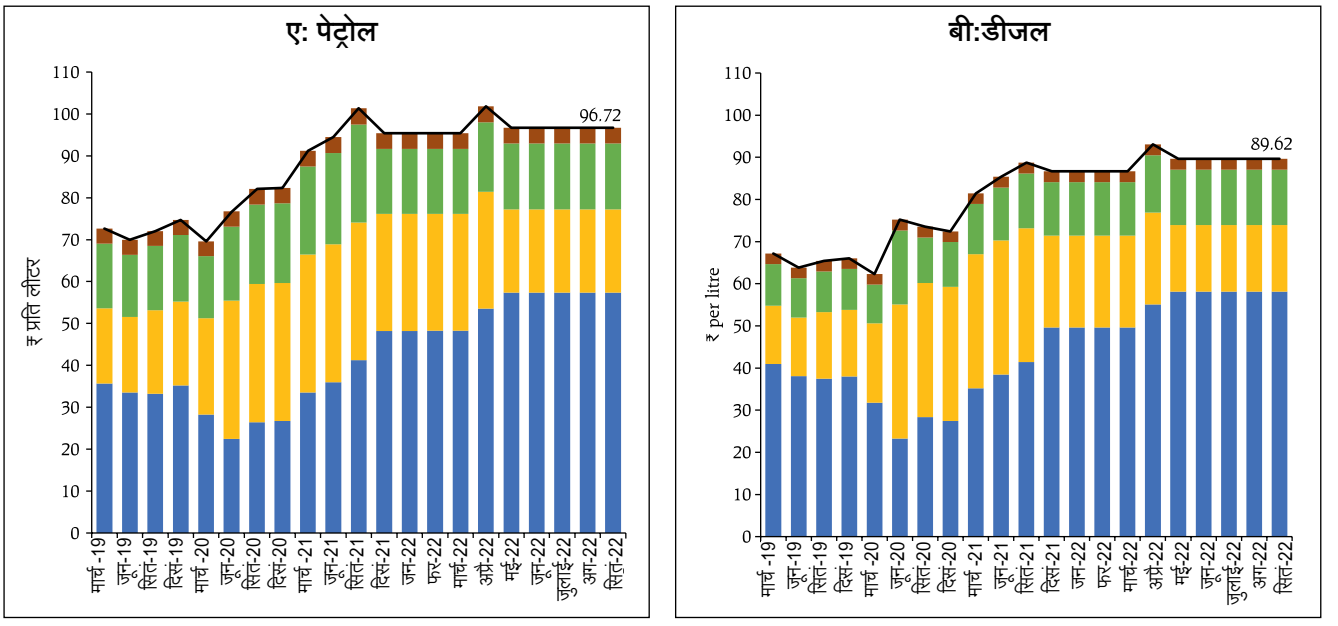
चार्ट II.17: खाद्य ईंधन (कोर) मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई में योगदान प्रतिशत अंकों में



* अन्य में पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ; तथा मनोरंजन और आमोद शामिल हैं।
टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गए आँकड़े खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर सीपीआई में भार को दर्शाते हैं।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

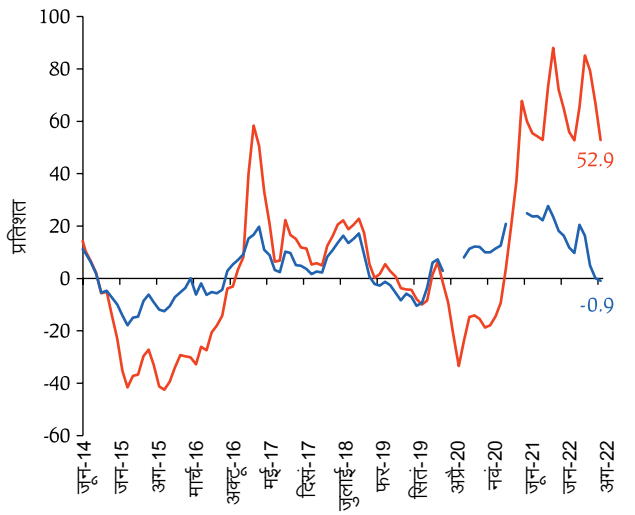
की कीमतें 22 मार्च और 6 अप्रैल 2022 के बीच लगभग 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई और फिर 22 मई 2022 तक अपरिवर्तित रहीं। उत्पाद शुल्क में ₹8 प्रति लीटर पेट्रोल में और ₹6 प्रति लीटर डीजल में कमी के बाद पंप की कीमतें गिर गईं (चार्ट II.18)।

चार्ट II.18: मूल्य बिल्ड-अप(आईओसीएल दिल्ली की कीमतें)



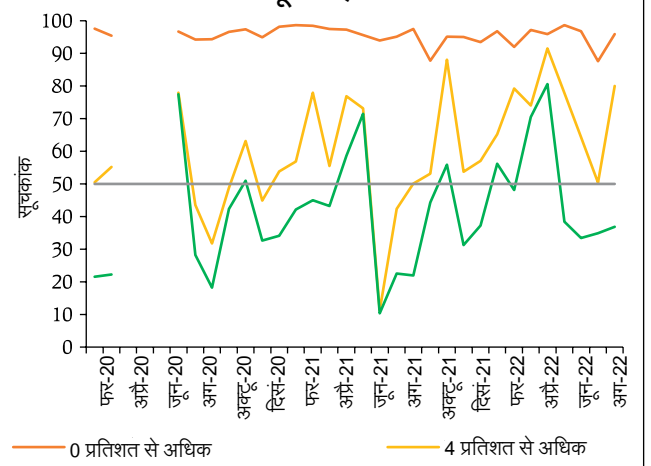
स्रोत: आईओसीएल; पीपीएसी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.19: पेट्रोल और डीज़ल मुद्रास्फीति(वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: एनएसओ; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.20: खाद्य पदार्थ, ईंधन,पेट्रोल, डीजल,स्वर्ण और चांदी को छोड़कर सीपीआई थ्रेसहोल्ड द्वारा एसएएआर डिफ्यूजन इंडेक्स



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

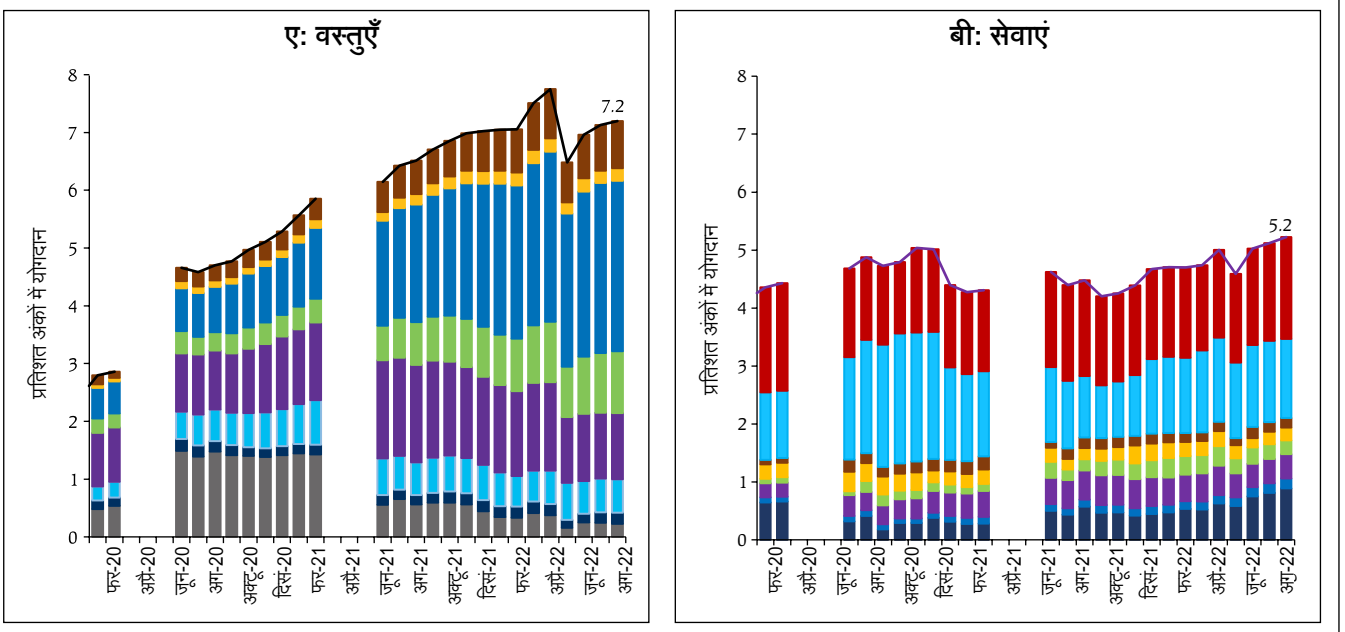
उत्पाद शुल्क में कटौती के साथ अनुकूल आधार प्रभावों के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरूप सीपीआई पेट्रोल और डीजल की कीमतें गिरकर अगस्त 2022 तक अपस्फीति क्षेत्र में चली गईं। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि अगस्त में 53 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) अधिक थी, जो इस तथ्य को दर्शाती है कि अप्रत्यक्ष करों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में शामिल किया गया है लेकिन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से बाहर रखा गया है (चार्ट 11.19)। कुल मिलाकर, उत्पाद शुल्क में कमी का कोर मुद्रास्फीति पर लगभग 43 आधार अंक और हेडलाइन मुद्रास्फीति पर लगभग 20 आधार अंक का प्रत्यक्ष नरम प्रभाव पड़ा। मई-जुलाई के दौरान सोने की कीमतों में गिरावट ने भी कोर मुद्रास्फीति के नरम होने में योगदान दिया।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए सीमाओं का व्याप्ति (थ्रेशोल्ड डिफ्यूज़न) सूचकांक यह दर्शाता है कि अधिकतर वस्तुओं में मार्च-अप्रैल 2022 के दौरान 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक की मूल्य वृद्धि (एसएएआर के आधार पर) हुई, इसमें खाद्य, ईंधन, पेट्रोल, डीज़ल, स्वर्ण और चांदी शामिल नहीं हैं। तथापि, मई-जुलाई के दौरान दबाव में कुछ कमी आई परंतु अगस्त में अधिकतर सामग्रियों में फिर तेजी दर्ज की गई (चार्ट II.20)।

खाद्य, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति में मार्च-अगस्त 2022 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं दोनों में वृद्धि दर्ज की गई, आउटपुट कीमतों में यह वृद्धि दमित इनपुट-लागत दबावों का अंतरण दर्शाती है (चार्ट II.21ए)। इस अवधि के दौरान, प्रमुख सेवाओं में मुद्रास्फीति की तुलना में प्रमुख वस्तुगत मुद्रास्फीति काफी अधिक रही। वस्तुओं संबंधी घटक में मुद्रास्फीति (शीर्ष सीपीआई में 20.7 प्रतिशत के भार के साथ) फरवरी 2022 के 7.1 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में 7.7 प्रतिशत हो गई। इसका मुख्य कारण कपड़ों और जूता निर्माण वस्तुओं, घरेलू सामान और व्यक्तिगत देखभाल वस्तुओं (एफएमसीजी सामानों और घरेलू बर्तनों सहित), स्वास्थ्य, परिवहन और संचार सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि होना रहा। यद्यपि, प्रमुख वस्तुओं की मुद्रास्फीति मई में कम होकर 6.5 प्रतिशत हो गई, लेकिन यह राहत अल्पकालिक थी क्योंकि जून-अगस्त के दौरान इसमें लगभग 72 आधार अंकों तक की बढ़ोतरी हो गई थी, जो मुख्य रूप से कपड़े और जूते, घरेलू सामान तथा व्यक्तिगत देखभाल के सामानों में हुई मुद्रास्फीतिक वृद्धि के कारण हुआ था।

कोर सेवागत मुद्रास्फीति भी (शीर्ष सीपीआई में 23.0 प्रतिशत के भार के साथ) फरवरी 2022 के 4.7 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त (चार्ट II.21बी) में 5.2 प्रतिशत हो गई और इसका मुख्य कारण शिक्षा (ट्यूशन और अन्य शुल्क), परिवहन सेवाओं (बस/ट्राम/टैक्सी किराया, विमान किराया, स्टीमर/नाव शुल्क) और आवास क्षेत्र में आया दबाव रहा। कुछ वृद्धि के बावजूद,

चार्ट II.21: खाद्य पदार्थ, ईंधन,पेट्रोल, डीजल,स्वर्ण और चांदी को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति में योगदान



टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई में भार को दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएसओ तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पहली छमाही (अप्रैल-अगस्त के बीच औसतन 3.8 प्रतिशत के साथ) में आवास क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा घटक है, में मुद्रास्फीति, अपेक्षाकृत शांत रहीं।

व्यतिरेक आधारित प्रमुख मुद्रास्फीतिक उपायों के समान ही तराशे गए माध्य उपाय [12] अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति में सामान्य तौरपर एक शिखर की ओर संकेत करते हैं और जुलाई तक इसमें कुछ गिरावट परिलक्षित होती है। तराशे गए उपायों में अगस्त में फिर तेजी दिखाई पड़ती है (सारणी II.2)।

मुद्रास्फीति संबंधी अन्य उपाय

कृषि श्रमिकों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण श्रमिकों (सीपीआई-आरएल) के लिए क्षेत्रीय सीपीआई द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति जुलाई 2020-जून 2022 के दौरान सीपीआई की शीर्ष मुद्रास्फीति दर नीची रही। कमतर खाद्य मुद्रास्फीति और सीपीआई की तुलना में सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल में खाद्य को दिए गए उच्च भार के कारण इस दौरान मुद्रास्फीति का कम दबाव रहा। अगस्त 2022 में, खाद्य कीमतों में वृद्धि के साथ, सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल मुद्रास्फीति, सीपीआई की शीर्ष मुद्रास्फीति के करीब/उससे मामूली रूप से ऊपर चली गई। औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के लिए सीपीआई द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति मार्च-जुलाई 2022

सारणी II.2: मूल मुद्रास्फीति के ट्रिम्ड मीन उपाय (वर्ष-दर-वर्ष)

माह	5% ट्रिम्ड	10% ट्रिम्ड	25% ट्रिम्ड	भारित माध्य
जून-21	5.7	5.2	5.0	5.2
सितं -21	5.0	4.9	4.8	4.3
दिसं-21	5.8	5.4	5.2	4.7
जन-22	5.9	5.6	5.3	5.1
फर-22	6.0	5.7	5.3	5.6
मार्च-22	6.6	6.3	6.1	6.1
अप्रैल-22	7.3	7.0	6.6	6.5
मई-22	6.4	6.1	5.5	5.7
जून-22	6.2	6.0	5.7	5.7
जुलाई-22	6.1	6.0	5.7	5.7
अगस्त-22	6.6	6.4	6.2	6.5

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

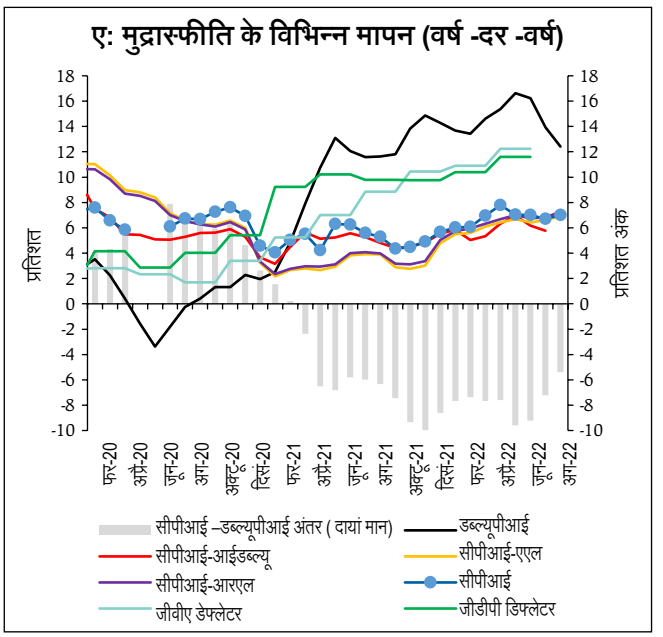
[12] जबकि व्यतिरेक-आधारित उपाय प्रत्येक अवधि में अस्थिर वस्तुओं (उदाहरण के लिए, खाद्य और ईंधन) के एक निश्चित सेट को गणना में नहीं लेते हैं, तराशे गए उपायों में मुद्रास्फीतिक वितरण के अंतिम छोर पर स्थित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है अर्थात् प्रत्येक महीने कीमतों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक परिवर्तन प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं को गणना में नहीं लिया जाता है और माह-दर-माह गणना में न ली जाने वाली वस्तुएं भिन्न-भिन्न होती हैं।

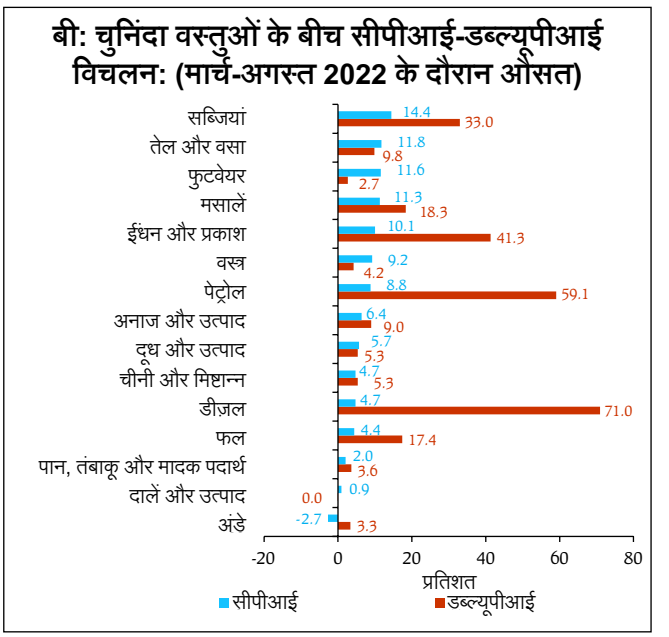
के दौरान शीर्ष सीपीआई से नीचे बनी रही क्योंकि सीपीआई-आईडब्ल्यू में सीपीआई की तुलना में खाद्य मुद्रास्फीति आम तौर पर कम थी। इसके अलावा, सीपीआई-आईडब्ल्यू में शीर्ष की तुलना में आवास क्षेत्र का भार अधिक होने के कारण भी सीपीआई-आईडब्ल्यू में मुद्रास्फीति का प्रदर्शन नरम रहा।

थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 से दोहरे अंकों में है और थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में जून-अगस्त के दौरान कमी आने के पूर्व मई 2022 में यह अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 16.6 प्रतिशत पर (डब्ल्यूपीआई श्रृंखला, 2011-12 = 100 के अनुसार) पहुँच गई। मजबूत अनुकूल आधार प्रभावों के बावजूद, युद्ध के बाद कच्चे तेल और पण्य की कीमतों में हुई वृद्धि ने मूल्य गतिशीलता में तेजी और व्यापक वृद्धि ने मार्च-मई 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय पण्य कीमतों में तेज वृद्धि के परिणामस्वरूप थोक मूल्य सूचकांक गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति मई 2021-मई 2022 के दौरान दोहरे अंकों में बनी रही। अनुकूल आधार प्रभावों वाले वातावरण में, मूलभूत धातुओं, वस्त्र और खाद्य उत्पादों, विशेष रूप से वनस्पति और पशु तेलों और वसा की कीमतों के दबाव में कमी से अगस्त 2022 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कम होकर 12.4 प्रतिशत तक हो गई। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के अनुरूप ही योजित सकल मूल्य संबंधी अपस्फीतिकारकों (जीवीए) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2021-22 की चौथी तिमाही से 2022-23 की पहली तिमाही (चार्ट II.22ए) के दौरान तेज वृद्धि हुई।

मार्च-अगस्त 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक के सभी प्रमुख उप-समूह अपने तदनुरूपी सीपीआई उपसमूहों की तुलना में ऊपर बने रहे (चार्ट II.22बी)। थोक मूल्य सूचकांक में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों संबंधी मुद्रास्फीति, सीपीआई मुद्रास्फीति से अधिक रही, जो मोटे तौर पर उत्पाद शुल्क और राज्य की वैट दरों में कमी को दर्शाता है, क्योंकि ये दरें सीपीआई में शामिल होती हैं परंतु थोक मूल्य सूचकांक में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का ईंधन और शक्ति समूह अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की अधिक कीमत बने रहना प्रदर्शित करता है। अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों और औद्योगिक मध्यस्थों में हुई बढ़ोतरी के फलस्वरूप गैर-खाद्य विर्निर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति सबंधी थोक मूल्य सूचकांक की कठोरता के कारण भी सीपीआई की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अधिक बनी रही। खाद्य पदार्थों के संबंध में जैसे कि अनाज, वनस्पतियों, फलों, अंडों और मसालों के संबंध में थोक मूल्य सूचकांक, सीपीआई की तुलना में अधिक बना रहा। इसके अतिरिक्त, थोक मूल्य सूचकांक में वे सेवाएं शामिल नहीं हैं जिनमें सीपीआई में शामिल वस्तुओं की तुलना में कमतर मुद्रास्फीति सामने आई है।

चार्ट II.22: मुद्रास्फीति के वैकल्पिक मापन



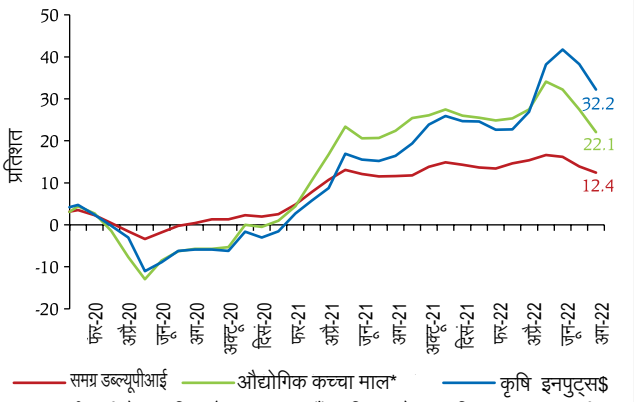


स्रोत: एनएसओ; श्रमिक कार्यालय;वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.3 लागत

2022-23 की पहली छमाही के दौरान, औद्योगिक कच्चे माल और कृषि इनपुट में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति द्वारा मापी जाने वाली लागत संबंधी दबाव कुछ नरमी के बावजूद स्थिर रहा। औद्योगिक आदानों की कीमतों में मुद्रास्फीति - जैसे हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी), नेफ्था, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ), बिटुमेन, पेट्रोलियम कोक, और फर्नेस ऑयल - जो कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण मई 2022 में 34.1 प्रतिशत पर पहुंच गया था, तब से उसकी कीमतों में सुधार हुआ है और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ ही अगस्त में यह सुधरकर 22.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट II.23)। मार्च-मई 2022 के दौरान कठोर होने के बाद, जून 2022 से गैर-खाद्य प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, क्योंकि फाइबर/तिलहन की कीमतों में कमी अंतरराष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तियों को दर्शाती है। मिश्रित प्रवृत्तियों और उच्च अस्थिरता के बावजूद खनिजों की कीमतों में मार्च-अगस्त 2022 के दौरान व्यापक रूप से कमी आई। जुलाई -अगस्त 2022 के दौरान, धातुओं की वैश्विक कीमतों में नरमी के अनुरूप ही औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों पर दबाव में कमी आई है। लौह अयस्क और कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क वृद्धि ने भी कीमतों पर आए दबाव को नियंत्रित करने में मदद की (चार्ट II.23)। कृषि इनपुट संबंधी मूल्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से एचएसडी कीमतों, कृषि और वानिकी मशीनरी, शुष्क मौसम की स्थिति के कारण चारे और उर्वरकों में हुई वृद्धि से प्रेरित रही।

चार्ट II.23: कृषि तथा गैर-कृषि कार्य इनपुट लागत मुद्रास्फीति(वर्ष - दर - वर्ष)



*: डब्ल्यूपीआई से प्राथमिक गैर-खाद्य वस्तुएँ, खनिज, कोयला, विमानन टरबाइन ईंधन, उच्च गति डीजल, नेफ्था, बिटुमेन, फर्नेस तेल, चिकनाई तेल, पेट्रोलियम कोक, बिजली, सूती धागे और कागज व लुगदी शामिल हैं।

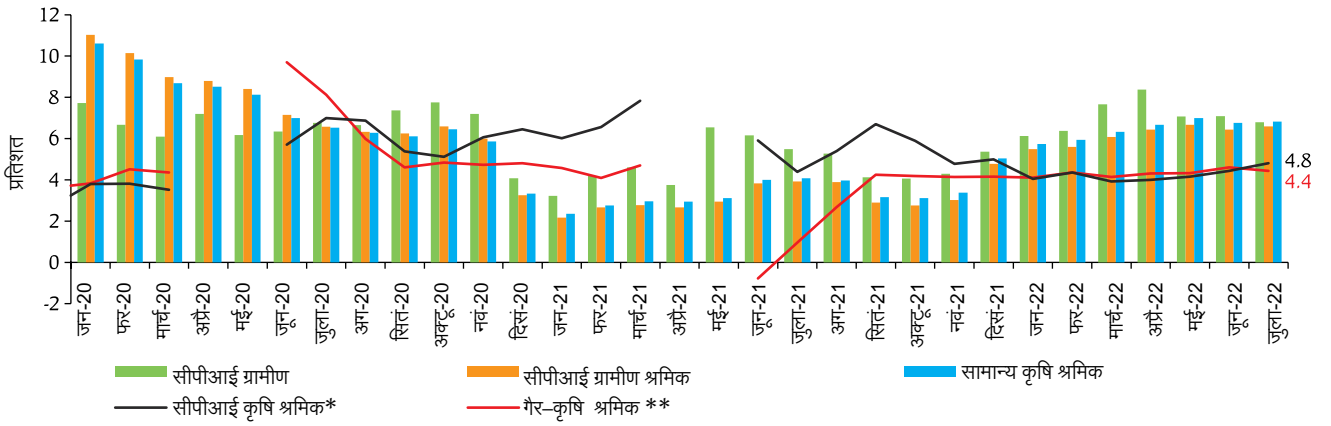
$: डब्ल्यूपीआई से उच्च गति डीजल, चारा, बिजली, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि एवं वानिकी मशीनरी शामिल हैं।

स्रोत: वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

औद्योगिक और कृषि दोनों में एक प्रमुख इनपुट होने के कारण विद्युत संबंधी थोक मूल्य सूचकांक में बिजली की कीमत संबंधी मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण सकारात्मक गति के साथ-साथ प्रतिकूल आधार प्रभावों में हुई तेज बढ़ोतरी रही।

2022-23 की पहली छमाही (जुलाई तक) के दौरान कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों के मजदूरों की सांकेतिक ग्रामीण मजदूरी वृद्धि मंद रही (चार्ट II.24)। उम्मीद है कि यह मजदूरी-कीमत उत्तरोत्तर वृद्धि को रोकेगा (बॉक्स II.2)

चार्ट II.24: ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी में वृद्धि(वर्ष- दर- वर्ष) और मुद्रास्फीति(वर्ष- दर- वर्ष)



*: जुताई, बुवाई, कटाई, तुड़ाई, बागवानी मजदूर, मछुआरे, मछुआरे कोस्टल, लकड़हारे और लकड़ी काटने वाले, पशुपालन, पैकेजिंग, सामान्य कृषि मजदूर, पौध संरक्षण मजदूर शामिल हैं।

**: बढ़ई, लोहार, मेसन, बुनकर, बीड़ी बनाने वाले, बांस-बेंत की टोकरी बुनकर, हस्तशिल्प कामगार, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, निर्माण मजदूर, एलएमवी और ट्रैक्टर चालक, झाड़-पोछ/सफाई कर्मचारी और अन्य गैर-कृषि मजदूर शामिल हैं।

टिप्पणी: अप्रैल-मई 2020 और 2021 के लिए डेटा जारी नहीं किया गया।

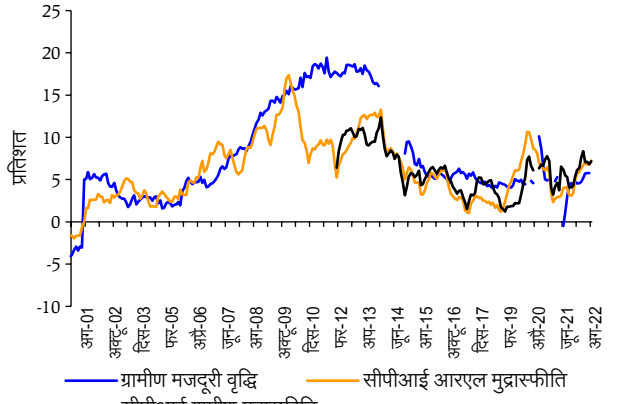
स्रोत: एनएसओ; श्रम ब्यूरो; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बॉक्स II.2: भारत में ग्रामीण कीमतों और मजदूरी के समीकरण का परीक्षण

ग्रामीण मजदूरी और ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से संबंधित उपलब्ध आंकड़े सह-गतिशीलता के साथ-साथ स्पष्ट विचलन की घटनाएँ दर्शाते हैं (खासकर जुलाई 2010-अक्टूबर 2013 के बीच, जब वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जिसने सीपीआई मुद्रास्फीति को पीछे छोड़ दिया)(चार्ट II.2.1)।

मजदूरी-कीमत समीकरण का विश्लेषण करने के लिए, अप्रैल 2017 से फरवरी 2020 तक की कोविड-पूर्व अवधि हेतु ग्रामीण कीमतों (सीपीआई-ग्रामीण डेटा का उपयोग कर) और ग्रामीण मजदूरी (कृषि और गैर-कृषि मजदूरों के लिए) के बीच संबंधों का एक राज्य-स्तरीय कोइंटीग्रेशन पैनल विश्लेषण किया गया। पेड्रोनी पैनल टेस्ट मजदूरी और कीमतों के बीच दीर्घकालिक कोइंटीग्रेटिंग संबंध का होना दर्शाते हैं। दीर्घ और अल्पकालिक समीकरणों की जांच पूल्ड मीन ग्रुप (पीएमजी) एस्टीमेटर (पेसरन और अन्य , 1999) के आधार पर की जाती है। कीमत और मजदूरी दोनों ही समीकरणों में दीर्घकालिक गुणांक एकक से नीचे (क्रमशः 0.41 और 0.57), जो मजदूरी आघातों के परिणामस्वरूप कीमतों में आनुपातिक से कम वृद्धि तथा इसके विपरीत संकेत देते हैं। अल्पकालिक समीकरण की ओर देखें तो दोनों समीकरणों में त्रुटि सुधार टर्म(ईसीटी) के गुणांक महत्वपूर्ण और बड़े हैं: किसी भी आघात की स्थिति में, कीमतें और मजदूरी दोनों जल्दी ही अपने दीर्घकालिक स्तरों तक समायोजित हो जाते हैं

चार्ट II.2.1: ग्रामीण मजदूरी वृद्धि और ग्रामीण मुद्रास्फीति



स्रोत: एनएसओ; श्रम ब्यूरो; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी II.2.1 ग्रामीण मजदूरी और ग्रामीण कीमतें - पैनल कोइंटीग्रेशन परिणाम

कीमत समीकरण: Δln(कीमत)		**मजदूरी समीकरण:** Δln(मजदूरी)	
दीर्घकालिक समीकरण: ln(कीमत) = a x ln(मजदूरी) + ईसीटी		*अल्पकालिक समीकरण: ln(मजदूरी) = a x ln(कीमत) + ईसीटी*	
a	0.40*** (0.04)	a	0.57*** (0.07)
अल्पकालीन समीकरण			
ईसीटी	-0.14*** (0.02)	ईसीटी	-0.12** (0.05)
Δln(मजदूरी)	-0.05 (0.06)	Δln(मजदूरी)	-0.03 (0.08)
Δln(*कीमत*) (-1)	0.16*** (0.05)	Δln(*कीमत*) (-1)	-0.00 (0.06)
Δln(मजदूरी) (-1)	-0.11* (0.06)	Δln(मजदूरी) (-1)	-0.22 (0.15)
बारिश में विचलन	0.00*** (0.00)	बारिश में विचलन	-0.00 (0.00)
स्थिरांक	0.37** (0.05)	स्थिरांक	0.39** (0.15)

टिप्पणी: ***, ** और * क्रमशः 1,5 और 10 प्रतिशत स्तर पर सिग्निफिकेन्स दर्शाते हैं। कोष्ठक में अंक मानक त्रुटि दर्शाते हैं।

1. नमूने में अप्रैल 2017 से फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए 17 प्रमुख राज्य शामिल हैं।
2. ग्रामीण मजदूरी की गणना ग्रामीण कृषि और ग्रामीण गैर-कृषि मजदूरी का सरल औसत निकालकर की गई है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

और कीमतों में समायोजन की गति मजदूरी की तुलना में कुछ तेज है (सारणी II.2.1)। कुल मिलाकर, अनुभवजन्य विश्लेषण दर्शाते हैं कि ग्रामीण मजदूरी और ग्रामीण कीमतें परस्पर प्रभावकारी हैं और द्वितीयक प्रभाव आरंभ कर सकती हैं।

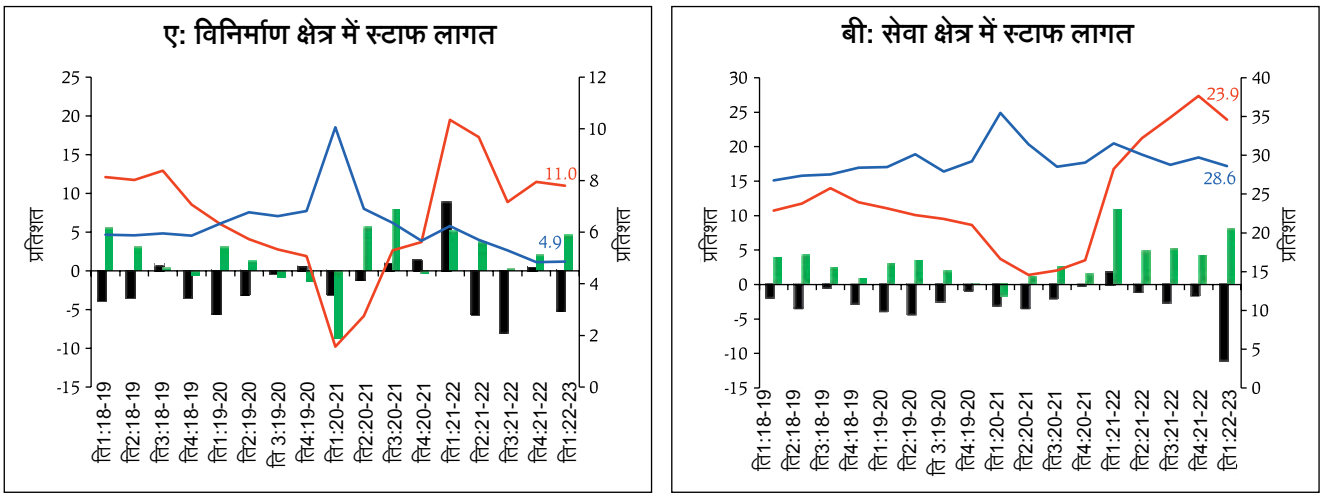
संदर्भ:

पेसरन, एम हशेम, योंगच्यल शिन, और रॉन स्मिथ (1999), "पूल्ड मीन ग्रुप एस्टीमेशन ऑफ डायनेमिक हेटेरोजीनस पैनल्स", जर्नल ऑफ द अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोशिएशन, 94.446, पृ. 621-634।

कुंडु, सुजाता (2019), "रूरल वेज डायनेमिक्स इन इंडिया: वॉट रोल डज इंफ्लेशन प्ले", आरबीआई ओकेजनल पेपर, 40, पृ. 51-84।

संगठित क्षेत्र में, 2022-23 की पहली तिमाही में विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों की लागत में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) कम रही। उत्पादन मूल्य में से कर्मचारियों पर लागत का भाग विनिर्माण क्षेत्र में पिछली तिमाही की तुलना में पहली तिमाही में लगभग अपरिवर्तित था, जबकि सेवा क्षेत्र में इसमें थोड़ी कमी आई (चार्ट II.25)।

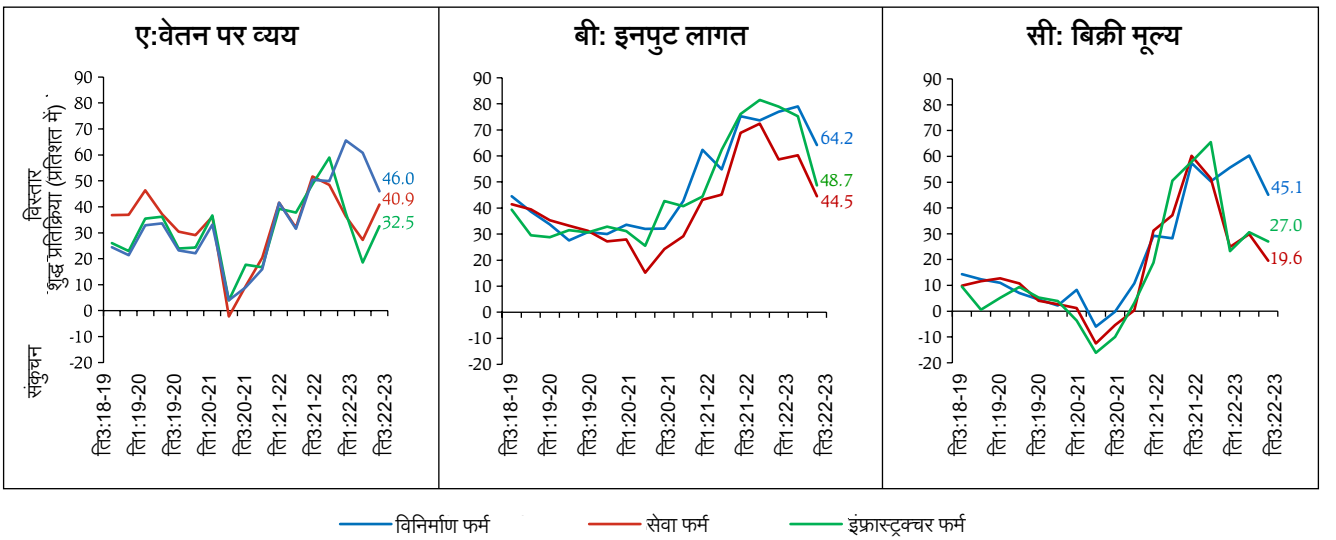
चार्ट II.25: विनिर्माण और सेवाओं में श्रम लागत



टिप्पणी: स्टाफ लागत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) कंपनियों के सामान्य समूह पर आधारित है।
स्रोत: कैपिटलाइन डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

रिज़र्व बैंक के उद्यम सर्वेक्षण[13] में अपना मत देने वाली फर्मों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में वेतन पर व्यय की गति 2022-23 की तीसरी तिमाही में धीमे होने की अपेक्षा है, जबकि सेवा और आधारभूत ढांचा क्षेत्रों में उच्चतर दबाव देखा जा सकता है। विनिर्माण, सेवा और आधारभूत ढांचा क्षेत्र की फर्मों के लिए निविष्टि लागत और विक्रय मूल्य दबाव तीसरी तिमाही में कम होने की संभावना है (चार्ट II.26)।

चार्ट II.26: लागत स्थितियों की अपेक्षाएं (कुल प्रतिक्रिया)



टिप्पणी: 'शुद्ध प्रतिक्रिया' कीमतों में वृद्धि और घटने की रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत के बीच का अंतर है।
स्रोत: रिज़र्व बैंक इंडस्ट्रियल आउटलूक सर्वे; सर्विसेस एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलूक सर्वे; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[13] औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वे ;और अवसंरचना दृष्टिकोण सर्वे।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रैल 2022 में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के बाद मई-जुलाई के दौरान एक वर्ष आगे की व्यावसायिक मुद्रास्फीति प्रत्याशा नीचे आई लेकिन अगस्त 2022 में बढ़ गई।[14] सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि अगस्त में लागत दबाव पुनः बढ़ा है, और बिक्री तथा लाभ मार्जिन के प्रति आशावाद में कमी हुई।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) सर्वेक्षणों में मतदान करने वाली विनिर्माण फर्मों के अनुसार, जबकि निविष्टि कीमतों में वृद्धि हुई, मई-अगस्त 2022 के दौरान धातु और मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतों में नरमी के कारण गति में कमी आई। सेवा संबंधी पीएमआई में, जून-अगस्त 2022 में गति में कमी के साथ-साथ निविष्टि कीमत ऊंची बनी रही। विनिर्माण और सेवा, दोनों क्षेत्रों के लिए आउटपुट कीमत मुद्रास्फीति, निविष्टि कीमत मुद्रास्फीति के सापेक्ष सौम्य थी और निविष्टि कीमत गति के कम होने और साथ ही लागत भार की क्रमिक निकासी के कारण इनपुट-आउटपुट कीमत अंतर कम हो गया है (चार्ट II.27)।

चार्ट II.27: इनपुट-आउटपुट मूल्य अंतर



स्रोत: एसएण्डपी ग्लोबल और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.4 निष्कर्ष

लगातार ब्लैक स्वान घटनाओं - कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में टकराव के कारण वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति दबाव बढ़ा है। वैश्विक घटनाक्रम को प्रतिबिम्बित करते हुए, वैश्विक पण्य कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ देश में प्रतिकूल मौसम संबंधी झटकों के कारण भारत ने भी पहली छमाही में मुद्रास्फीति दबाव में तीव्र वृद्धि का अनुभव किया। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में चरम पर थी। तब से इसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन यह युद्ध पूर्व स्तर से और ऊपरी स्वीकार्य सीमा से भी ऊपर बनी हुई है। इसकी लक्ष्य तक वापसी क्रमिक रूप से ही होने की संभावना है। तथापि, अत्यधिक अस्थिर भू-राजनीतिक स्थिति, वैश्विक वित्तीय बाजार में तीव्र अस्थिरता के प्रभाव विस्तार और आवर्ती प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए, दृष्टिकोण काफी अनिश्चितताओं से ग्रस्त है। मौद्रिक नीति यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि भविष्य में विकास को सहयोग देने के साथ-साथ मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

[14] भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के मासिक व्यापार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वे (बीआईईएस) में प्रमुख रूप से विनिर्माण क्षेत्र सहित, व्यवसायों के एक पैनल से उनके अल्पकालिक और दीर्घकालिक मुद्रास्फीति प्रत्याशा के बारे में मत लिए जाते हैं। नवीनतम सर्वे (अगस्त 2022 सत्र) लगभग 900 कंपनियों के प्रतिसाद पर आधारित था।

III. मांग और उत्पादन

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधियों में आघात सहनीयता की स्थिति देखी गयी। समग्र मांग में आया उछाल निजी खपत और निवेश मांग के कारण था। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक वित्तीय बाजारों में कठोरता और वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से, घरेलू संभावनाओं के प्रति नकारात्मक जोखिम पैदा हो गया।

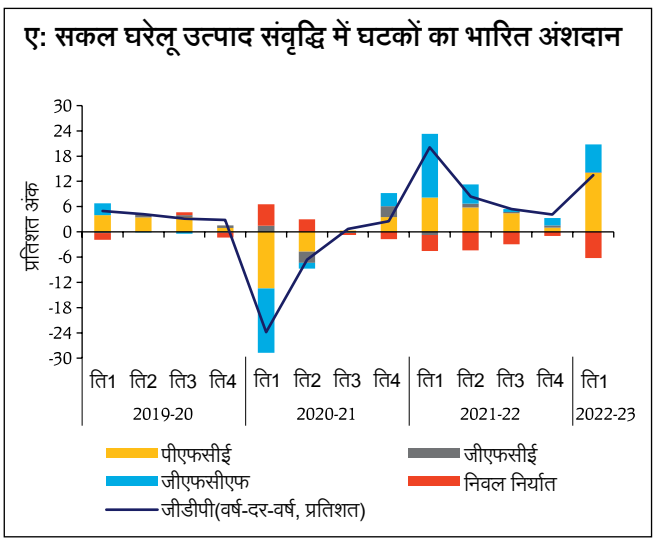
वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही की तुलना में वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधि में अपेक्षाकृत धीमी गति समुत्थानशीलता दिखाई दी। विनिर्माण और संपर्क-गहन सेवाओं में सुधार के साथ समग्र आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो रहा है और साथ ही साथ बेहतर हो गई हैं। समग्र मांग निजी खपत पर टिकी है, जो अच्छी तरह से पकड़ बनाए हुए है और त्यौहार के समय में इसका बढ़ना निश्चित है। मजबूत सरकारी पूंजी व्यय (केपैक्स) के साथ निवेश गतिविधि में वृद्धि आई है। दूसरी ओर, कम सरकारी खपत और निवल निर्यात में कमी ने अवरोध का काम किया है। तीव्र भू-राजनीतिक तनावों को लेकर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पण्य वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतें, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता और विश्व आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी घरेलू संभावनाओं के प्रति प्रमुख नकारात्मक जोखिम रहे हैं।

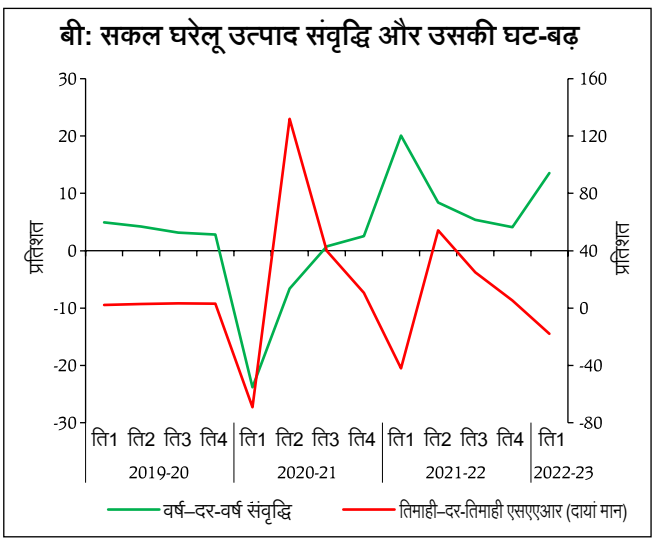
III.1 समग्र मांग

वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अनुकूल आधारगत प्रभावों की सहायता से 13.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई। तदनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, महामारी पूर्व के स्तर से 3.8 प्रतिशत से अधिक हो गया था (चार्ट III.1 और सारणी III.1)। समग्र मांग के सभी घटकों ने पहली तिमाही में बढ़ोतरी दर्ज की और यह उनके महामारी पूर्व के स्तरों से अधिक थी।

हालांकि गतिविधि की यह गति वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में - तिमाही-दर-तिमाही (क्यू-ओ-क्यू) मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक विकास दर (एसएएआर) नकारात्मक थी जो सरकारी खपत और निवेश तथा आयात में तेज उछाल के कारण कम हो गई थी (चार्ट III .1ए और बी)। दूसरी तिमाही के लिए उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि निजी खपत और निवेश मांग में जारी सुधार के कारण समग्र मांग में उछाल बना रहा।

चार्ट III.1: जीडीपी संवृद्धि और उसके घटक





टिप्पणी: एसएएआर - मौसमी समायोजित वार्षिकी दर।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी III.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

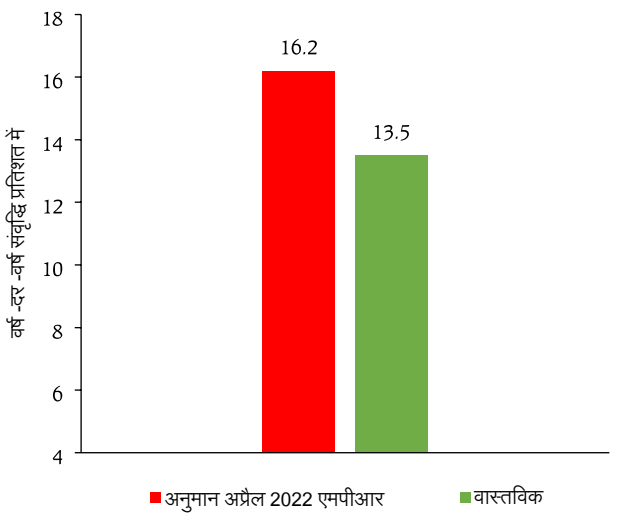
मद	2020-21 (एफआरई)	2021-22 (पीई)	भारित योगदान*		2020-21				2021-22				2022-23
			2020-21	2021-22	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1
निजी अंतिम उपभोग व्यय	-6.0	7.9 (1.4)	-3.4	4.5	-23.7	-8.3	0.6	6.5	14.4 (-12.7)	10.5 (1.3)	7.4 (8.0)	1.8 (8.3)	25.9 (9.9)
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	3.6	2.6 (6.3)	0.4	0.3	13.6	-22.9	-0.3	29.0	-4.8 (8.2)	8.9 (-16.1)	3.0 (2.6)	4.8 (35.1)	1.3 (9.6)
कुल निश्चित पूंजी निर्माण	-10.4	15.8 (3.8)	-3.3	4.8	-45.3	-4.5	-0.6	10.1	62.5 (-11.2)	14.6 (9.5)	2.1 (1.5)	5.1 (15.7)	20.1 (6.7)
निर्यात	-9.2	24.3 (12.8)	-1.8	4.6	-25.5	-6.4	-8.6	3.7	40.8 (4.8)	20.7 (12.9)	23.1 (12.5)	16.9 (21.2)	14.7 (20.2)
आयात	-13.8	35.5 (16.8)	-3.2	7.5	-41.1	-17.9	-5.2	11.7	61.1 (-5.1)	41.0 (15.7)	33.6 (26.7)	18.0 (31.8)	37.2 (30.3)
बाज़ार मूल्यों पर जीडीपी	**-6.6**	**8.7 (1.5)**	**-6.6**	**8.7**	**-23.8**	**-6.6**	**0.7**	**2.5**	**20.1 (-8.5)**	**8.4 (1.2)**	**5.4 (6.2)**	**4.1 (6.7)**	**13.5 (3.8)**

टिप्पणी: *: संवृद्धि के लिए घटक-वार योगदान को जीडीपी संवृद्धि के साथ नहीं जोड़ा है क्योंकि स्टाक, कीमती वस्तुओं में परिवर्तन और विसंगतियों को शामिल नहीं किया है| कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े 2019-20 की संवृद्धि दरें हैं। **एफआरई:** पहला संशोधित अनुमान। **पीई:** अनंतिम अनुमान।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय(एनएसओ)|

जीडीपी अनुमान बनाम वास्तविक परिणाम

अप्रैल 2022 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) ने वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि रहने का अनुमान लगाया था। निवल निर्यात उम्मीद से कहीं ज्यादा कम रहने और सरकारी व्यय धीमा होने से वास्तविक वृद्धि का अनुमान 270 आधार अंक (बीपीएस) (चार्ट III.2) तक घट गया। पहली तिमाही में आयात में 37.2 प्रतिशत की वृद्धि ने सकारात्मक रूप से अत्यधिक आश्चर्यचकित किया था।

चार्ट III.2: सकल देशी उत्पाद संवृद्धि: अनुमानित बनाम वास्तविक - ति1:2022-23



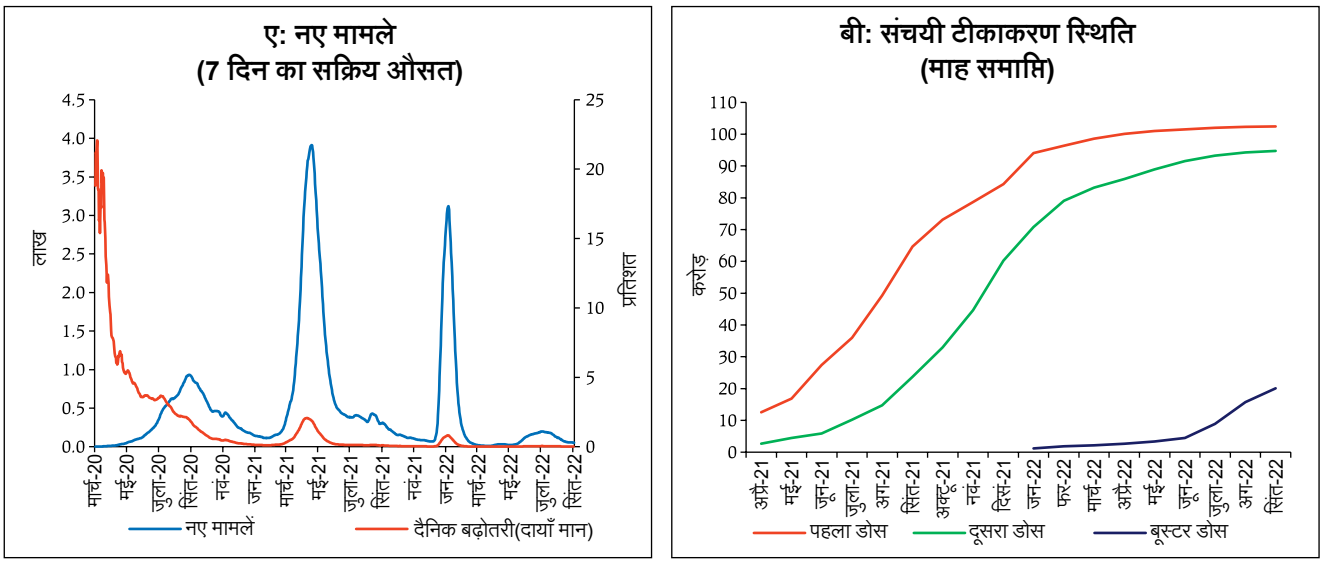
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

III.1.1 निजी अंतिम उपभोग व्यय

निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) - समग्र मांग का मुख्य आधार – वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 25.9 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई और समग्र सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी एक वर्ष पहले के 54.0 प्रतिशत से बढ़कर 59.9 प्रतिशत हो गई। बढ़े हुए टीकाकरण कवरेज और कम हुए नए कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण (चार्ट III.3) ने उपभोक्ता विश्वास और विवेकाधीन खर्च को बढ़ावा दिया और यह विशेष रूप से यात्रा, होटल और रेस्तरां, मनोरंजन और संस्कृति के कारण हुआ था।

शहरी खपत के उच्च आवृत्ति संकेतकों (एचएफआई) के मध्य, घरेलू हवाई यात्री यातायात ने लगातार सुधार दर्ज की, तथापि अभी भी यह पूर्व-महामारी के स्तर (चार्ट III.4ए) से पीछे है। लंबी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों (चार्ट III.4बी) से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, यात्री वाहनों की बिक्री ने पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में भारी वृद्धि दर्ज की, जिससे - महामारी पूर्व का जो पिछला स्तर था उसमें में बढ़ोतरी हुई। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में खिंचाव विवेकाधीन खर्च से पैदा हुआ (चार्ट III.4सी)। शहरी खपत में सुधार, परिवारों के लिए बैंक द्वारा दिए गए ऋण में बढ़ोतरी को भी दर्शाता है (चार्ट III.4डी)।

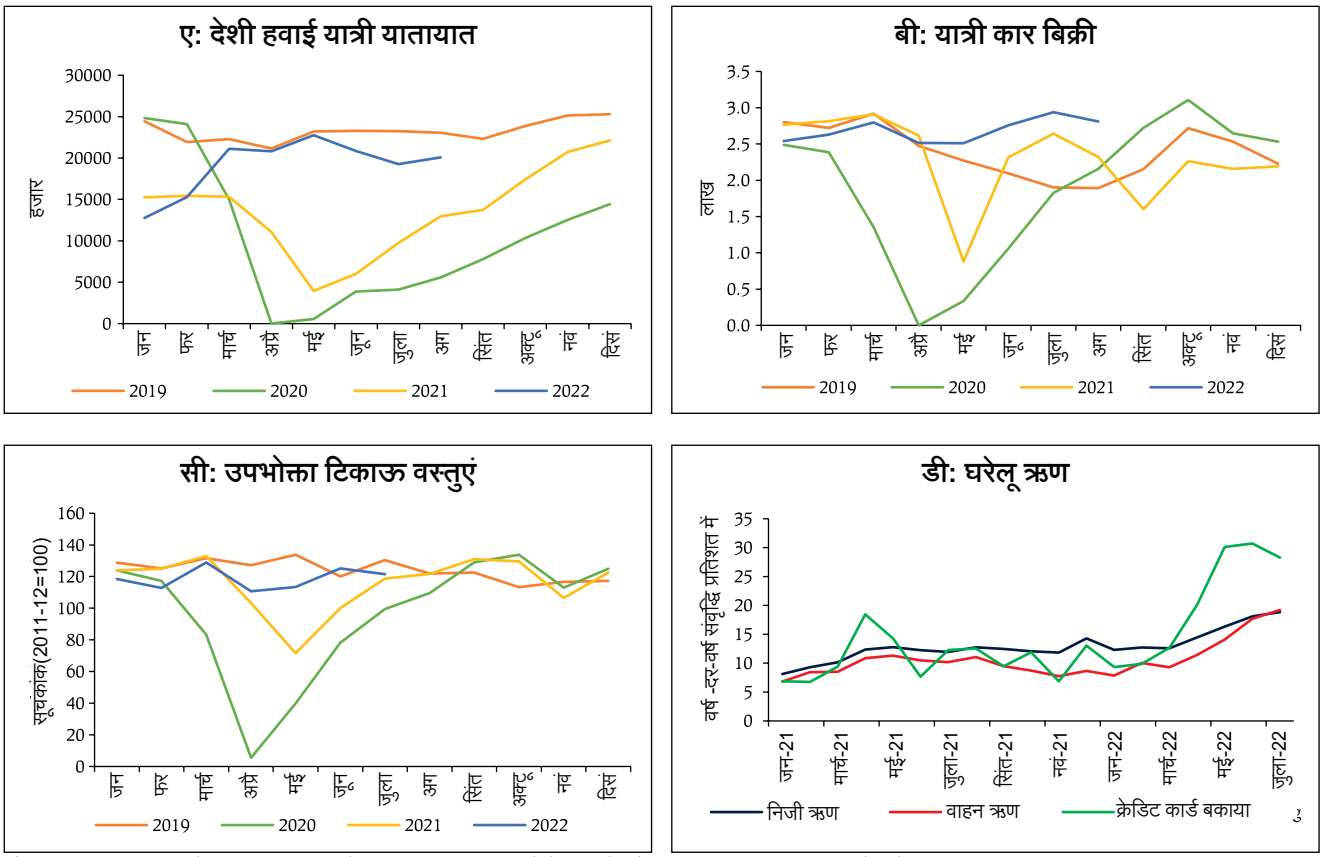
चार्ट III.3: कोविड संक्रमण और टीकाकरण



स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू)।

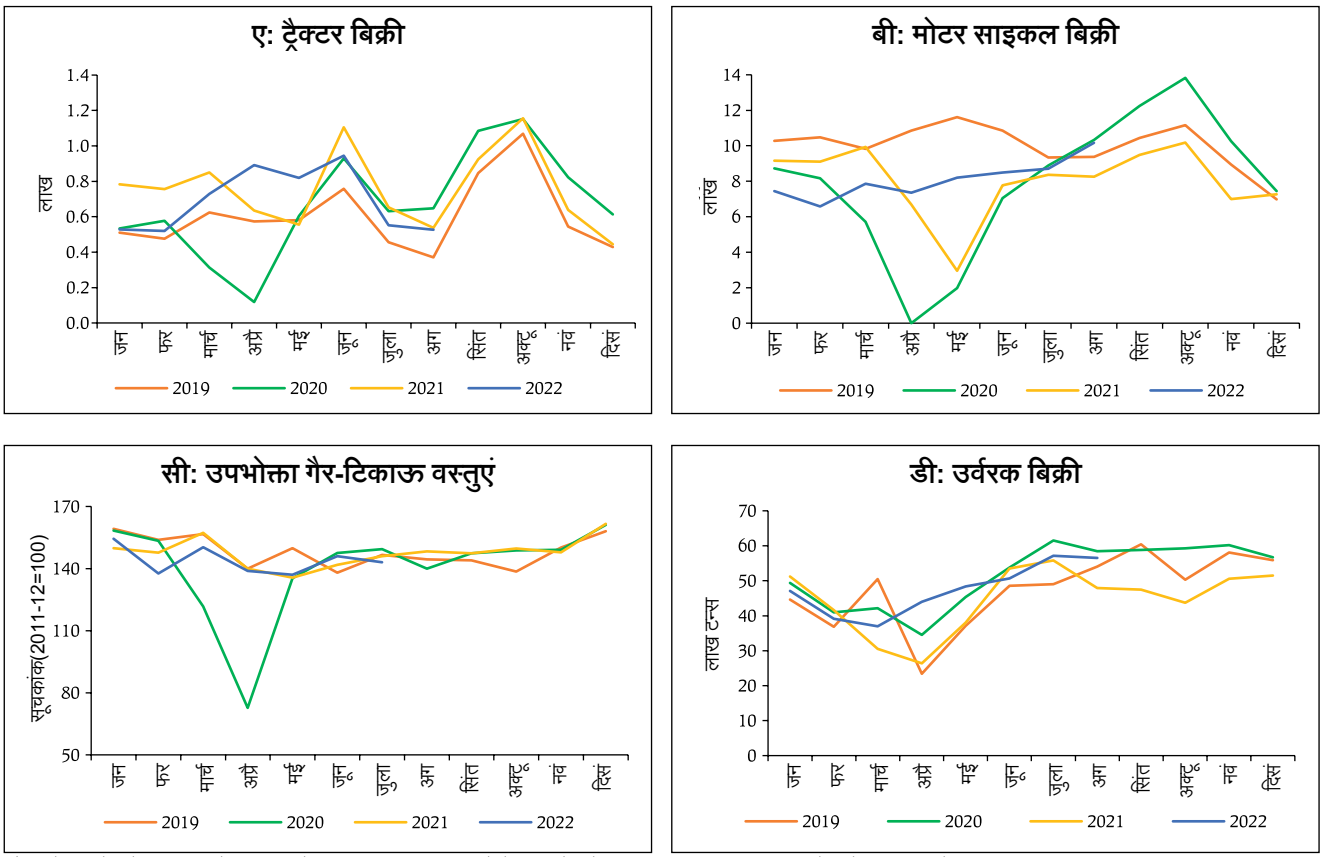
2022-23 की पहली तिमाही में ग्रामीण मांग सुस्त रही और दूसरी तिमाही में सुधार के कुछ संकेत मिले। ग्रामीण कृषि श्रम बाजार में स्थितियों में सुधार के कारण जुलाई-अगस्त 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

चार्ट III.4: शहरी मांग - उच्च-आवृत्ति संकेतक



स्रोत: नागर विमानन महानिदेशालय(डीजीसीए); सोसाइटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम); एनएसओ; और आरबीआई।

चार्ट III.5: ग्रामीण मांग - उच्च आवृत्ति संकेतक



स्रोत: ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स असोसिएशन; सोसाइटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम); एनएसओ; और रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

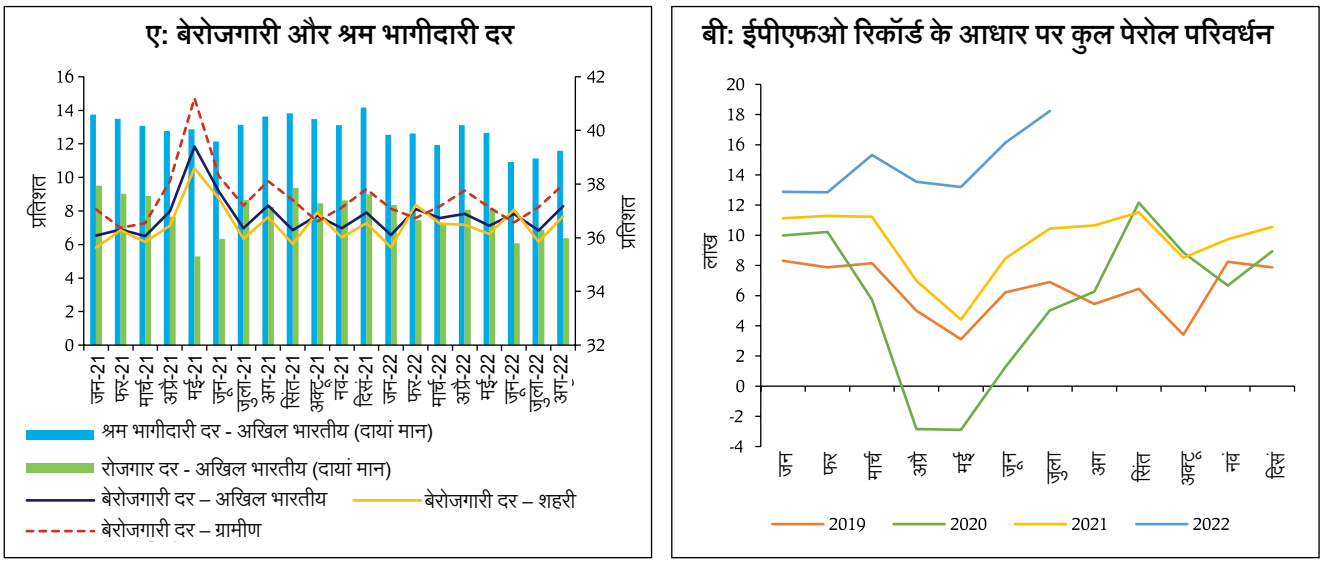
(मनरेगा) के अंतर्गत मांगे गए काम में तेजी से गिरावट आई। मोटरसाइकिल की बिक्री साल-दर-साल बढ़ी और अगस्त में महामारी से पहले के स्तर को पार कर गई। पहली छमाही में उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन सुस्त रहा। ट्रैक्टर की बिक्री महामारी से पहले के स्तर से ऊपर बनी हुई है, हालांकि आंशिक रूप से पिछले साल दर्ज रिकॉर्ड बिक्री के उच्च आधार के कारण जुलाई-अगस्त में बिक्री सालाना आधार पर कम दर्ज की गई। खरीफ फसल की बुवाई बढ़ने के साथ अगस्त में उर्वरक की बिक्री में सुधार हुआ (चार्ट III.5)।

भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) के उपभोक्ता पिरामिड आंकड़ों के अनुसार, श्रमशक्ति प्रतिभागिता दर में जून में देखी गई गिरावट की तुलना में दूसरी तिमाही में सुधार हुआ, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अगस्त में बेरोजगारी दर कम हुई (चार्ट III.6ए)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेरोल डेटा से जुलाई 2022 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में सुधार का संकेत मिलता है (चार्ट III.6बी)। नौकरी जॉब्सपीक के आंकड़ों के अनुसार, आतिथ्य, खुदरा, बीमा, स्थावर संपदा, बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में नौकरी बढ़ी है।

III.1.2 सकल स्थायी पूंजी निर्माण

सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; इसके परिणामस्वरूप, पहली तिमाही में जीडीपी में जीएफसीएफ की हिस्सेदारी बढ़कर 34.7 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 32.8 प्रतिशत थी। 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान आवास क्षेत्र की इकाइयों के प्रारंभ होने और उनकी बिक्री में वृद्धि के साथ निर्माण गतिविधियों में तेज उछाल दिखा। पहली छमाही में निर्माण गतिविधि के निकटवर्ती मिलते-जुलते संकेतकों - इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई

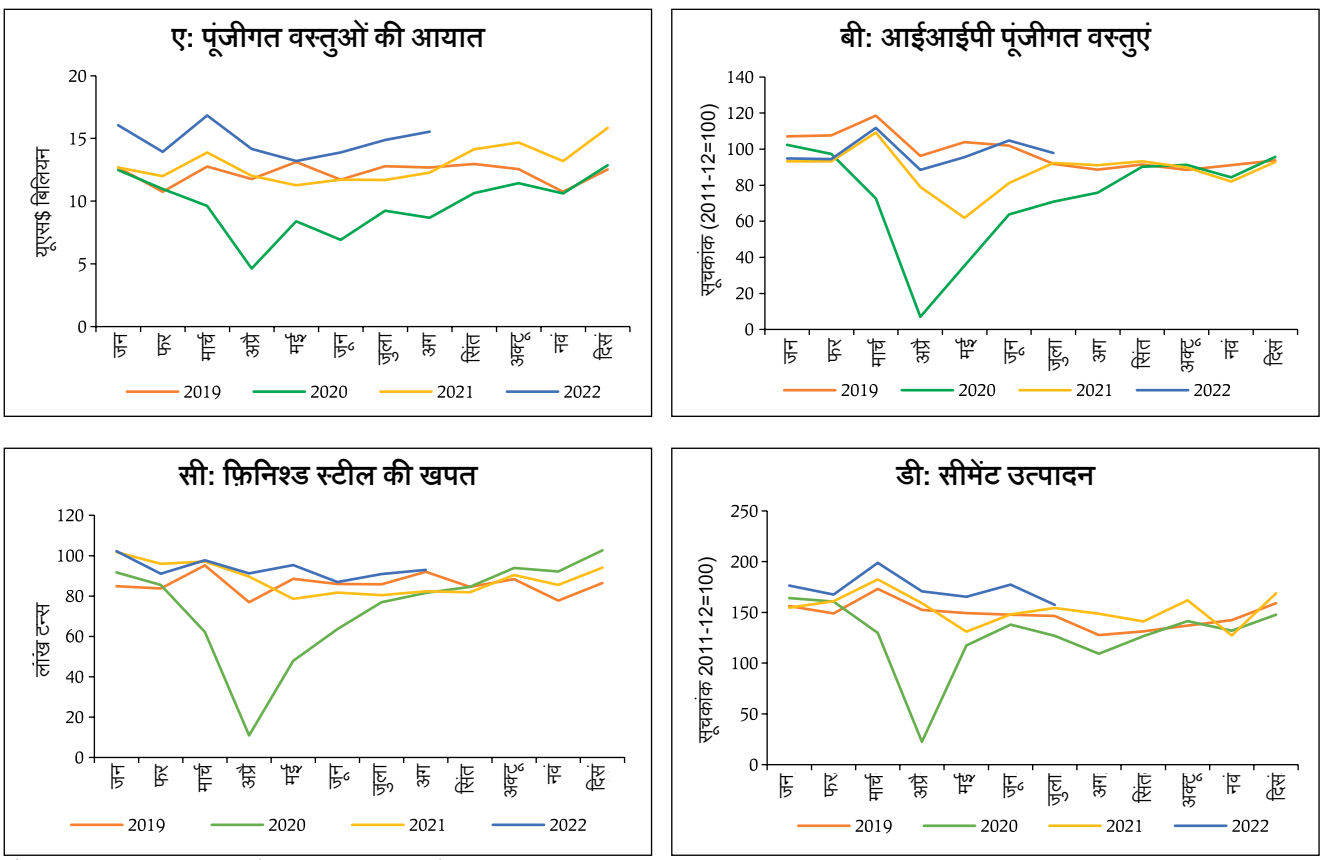
चार्ट III.6: भारत में रोजगार की स्थिति



स्रोत: सीएमआईई; और कर्मचारी भविष्य - निधि संस्था(ईपीएफओ)।

(चार्ट III.7)। पूंजीगत वस्तुओं के आयात में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं अग्रणी रहीं, जबकि जून-जुलाई 2022 में पूंजीगत वस्तुओं का घरेलू उत्पादन अपने महामारी के पहले के स्तर को पार कर गया था।

चार्ट III.7: निवेश मांग के संकेतक

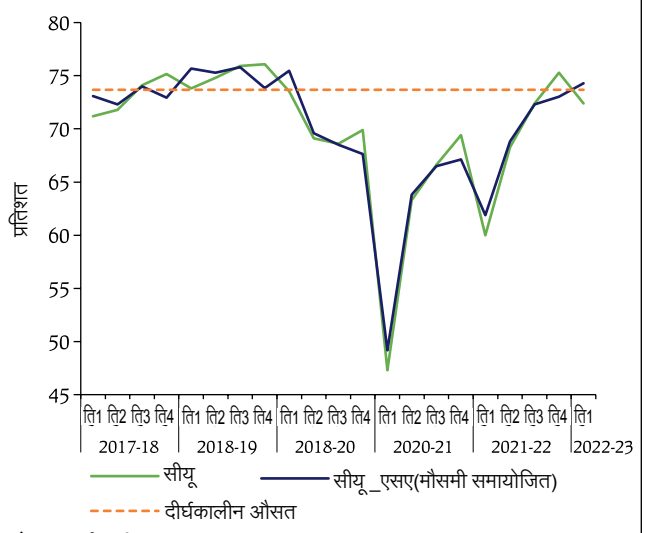


स्रोत: डीजीसीआई एंड एस; एनएसओ; संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय।

आरबीआई के सर्वेक्षण[1] के अनुसार, 2022-23 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) पिछली तिमाही के 75.3 प्रतिशत से घटकर 72.4 प्रतिशत रह गया, जो मौसमी कारकों को दर्शाता है। हालांकि, 2022-23 की पहली तिमाही में मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग पिछली तिमाही में 73.0 प्रतिशत से बढ़कर 74.43 प्रतिशत हो गया, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है (चार्ट III.8)। 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान विनिर्माण कंपनियों में नए ऑर्डर में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई। समग्र कारोबारी स्थिति, कारोबार और रोजगार में 2022-23 की दूसरी तिमाही में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में आशावाद दिखा।

2022-23 की पहली तिमाही में विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्रों में सूचीबद्ध गैर-वित्तीय निजी कंपनियों का ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर)[2] ऊंचा रहा, और यह उनकी सहज ऋण चुकौती क्षमता और क्षमता विस्तार के लिए अनुकूल स्थितियों को दर्शाता है (अध्याय III.9)।

चार्ट III.8: विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग

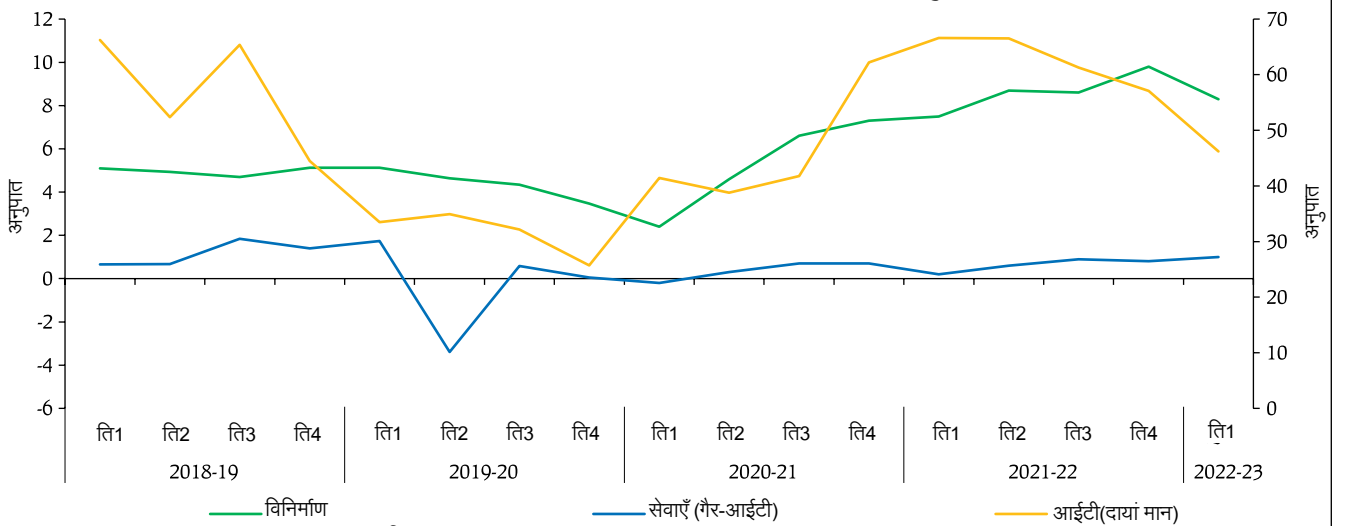


स्रोत: आरबीआई।

III.1.3 सरकारी खपत

2022-23 की पहली तिमाही में सरकारी अंतिम खपत व्यय (जीएफ़सीई) में वृद्धि 1.3 प्रतिशत [(-)4.8 प्रतिशत एक वर्ष पहले] रहने के साथ मंद रही, जिसने जीडीपी संवृद्धि को सुस्त कर दिया (सारणी III.2)। केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय में एक वर्ष पहले रहे 7.0 प्रतिशत संकुचन के मुक़ाबले अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान 4.8 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि हुई।

चार्ट III.9: विनिर्माण और सेवा फर्मों में ब्याज कवरेज अनुपात



टिप्पणी: 2022-23 की पहली तिमाही के लिए डाटा 1,709 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों और 722 सूचीबद्ध गैर-वित्तीय निजी सेवा कंपनियों के परिणामों पर आधारित है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[1] ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग का सर्वेक्षण

[2] ब्याज कवरेज अनुपात, ब्याज एवं कर से पहले आय (ईबीआईटी) और ब्याज पर हुए व्यय का अनुपात है और किसी कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज पर ब्याज भुगतान करने उसकी क्षमता का आकलन करता है। व्यवहार्य आईसीआर का न्यूनतम मान 1 है।

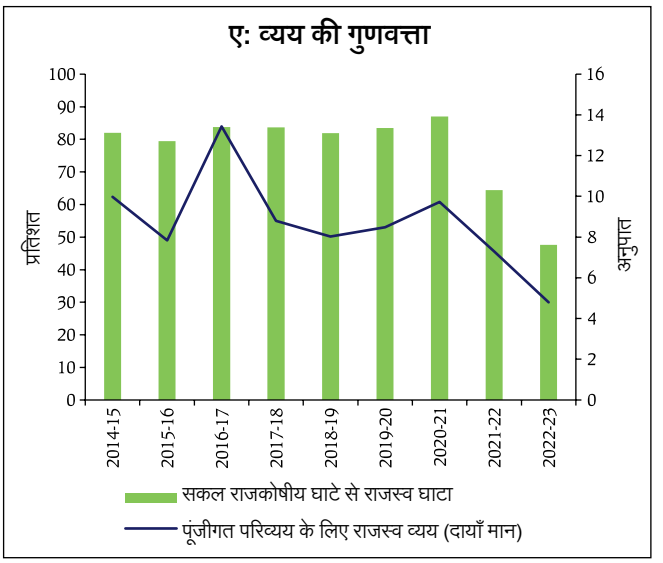
सारणी III.2: केंद्र सरकार का कर संग्रहण

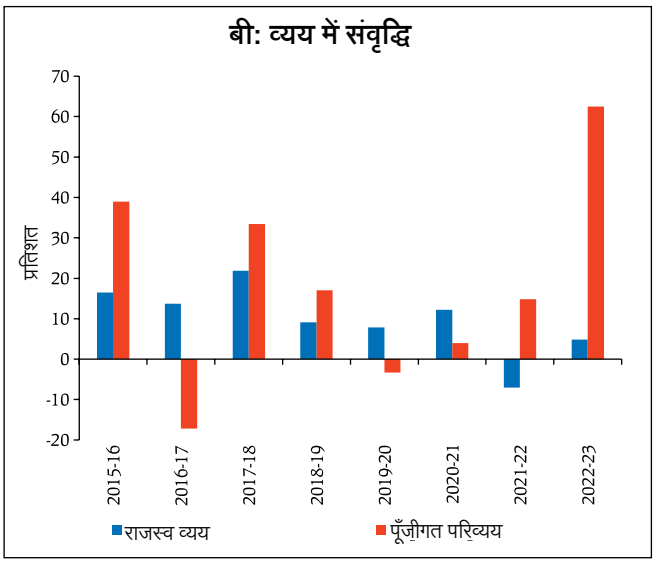
मद	₹ हजार करोड़				प्रतिशत			
	बजट अनुमान		वास्तविक		बीई का प्रतिशत		संवृद्धि दर	
	2021-22	2022-23	अप्रैल-जुलाई 2021	अप्रैल-जुलाई 2022	अप्रैल-जुलाई 2021	अप्रैल-जुलाई 2022	अप्रैल-जुलाई 2021	अप्रैल-जुलाई 2022
ए. प्रत्यक्ष कर	**1,108.00**	**1,420.00**	**314.5**	**446.4**	**28.4**	**31.4**	**110.9**	**41.9**
जिसमें								
1. निगम कर	547	720	145.9	196.5	26.7	27.3	171.5	34.7
2. आय कर	548.5	680	161.2	241.8	29.4	35.6	76.7	50
बी. अप्रत्यक्ष कर	**1,109.10**	**1,337.80**	**381.4**	**423.0**	**34.4**	**31.6**	**65.2**	**10.9**
जिसमें								
1. जीएसटी	633.3	783.7	221.0	284.2	34.9	36.3	60.4	28.6
2. सीमा शुल्क	136	213	58.0	51.0	42.6	23.9	144.1	-12.0
3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क	335	335	100.4	85.1	30	25.4	47.9	-15.2
सी. सकल कर राजस्व	**2,217.10**	**2,757.80**	**695.9**	**869.5**	**31.4**	**31.5**	**83.1**	**24.9**
डी. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुपुर्द	**665.6**	**816.6**	**165.1**	**201.1**	**24.8**	**24.6**	**-6.2**	**21.8**
ई. निवल कर राजस्व	**1,545.40**	**1,934.80**	**529.2**	**666.2**	**34.2**	**34.4**	**161.0**	**25.9**

टिप्पणी: जीएसटी में यूटी- जीएसटी भी शामिल है।
स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज; और महालेखा महानियंत्रक।

घटक-वार देखें तो प्रमुख सब्सिडियों, खासकर खाद्य पदार्थों पर अपेक्षाकृत कम खर्च के कारण, ब्याज भुगतानों पर हो रहे उच्चतर व्यय का असर कम पड़ा। दूसरी तरफ, अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान पूंजीगत परिव्यय में 59.4 प्रतिशत का उछाल आया, जो विनिर्माण पर सरकार के निरंतर ज़ोर दिये जाने को दर्शाता है। इससे व्यय में गुणवत्तापूर्ण सुधार हुआ- अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय अनुपात (आरईसीओ) पिछले वर्ष इसी अवधि में रहे 7.3 से घटकर 4.8 हो गया (चार्ट 10ए)। वर्ष के आरंभ में ही होने वाले व्यय सड़क और रेलवे क्षेत्रों में बढ़े हुये व्यय से प्रेरित थे (चार्ट III.10बी)।

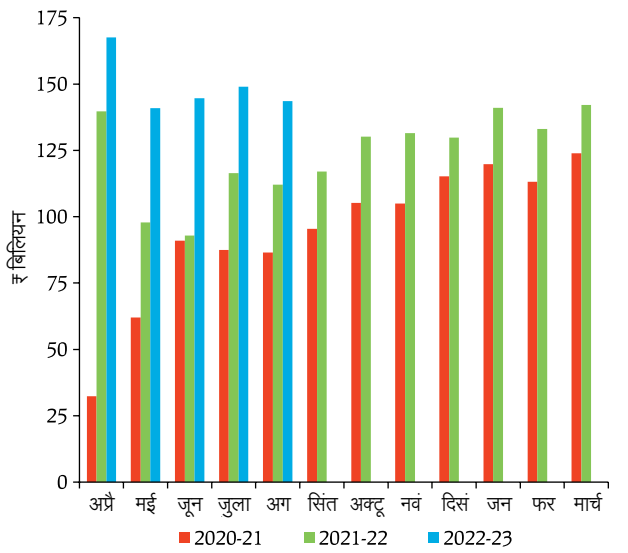
चार्ट III.10: अप्रैल-जुलाई के दौरान केंद्र के व्यय





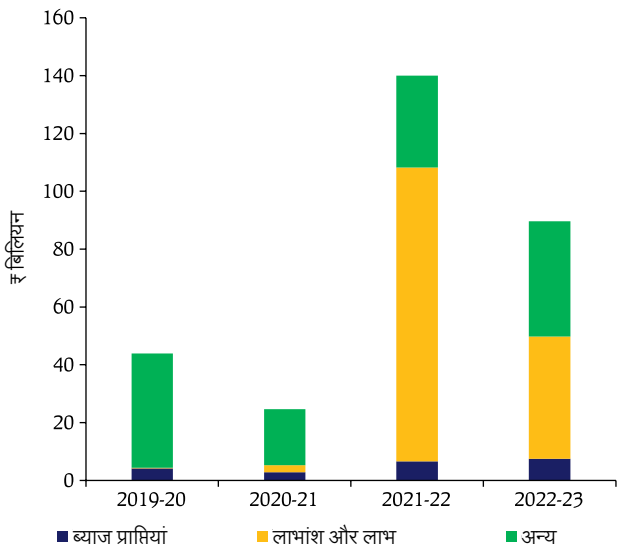
स्रोत: महालेखा नियंत्रक(सीजीए); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.11: जीएसटी संग्रहण (केंद्र और राज्य)



स्रोत: पीआईबी।

चार्ट III.12: गैर-कर राजस्व: अप्रैल-जुलाई



स्रोत: सीजीए।

प्राप्तियों के मामले में, केंद्रीय सरकार का सकल कर राजस्व संग्रहण उत्साहपूर्ण रहा और अप्रैल-जुलाई, 2022 के दौरान इसमें 24.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो प्रत्यक्ष कर और जीएसटी संग्रहों (सारणी III.2) से प्रेरित था। बेहतर होती आर्थिक गतिविधि और अनुपालन का लाभ उठाते हुए, मासिक जीएसटी संग्रहण (केंद्र एवं राज्यों का) मार्च, 2022 से ही 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक बना रहा (चार्ट III.11)। तथापि, मई, 2022 में पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती और कपास एवं पाम तेल जैसे जिंसों पर सीमा शुल्क में की गई कमी के कारण, केंद्रीय उत्पाद शुल्कों और सीमा शुल्कों के संग्रहण में संकुचन आया।

हालांकि, कम लाभांश और कम मुनाफे के कारण, अप्रैल-जुलाई के दौरान केंद्रीय सरकार के गैर-कर राजस्व संग्रहण में गिरावट आयी। हाल ही में सम्पन्न हुई 5जी स्पेक्ट्रम नीलामियों से 1.5 लाख करोड़ रुपये का कुल राजस्व मिलेगा; इसमें से, पहली वार्षिक किस्त 17,875 करोड़ रुपये की होगी (चार्ट III.12)। जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावों की कमाई से प्रेरित होकर, विनिवेश की प्राप्तियाँ 8,371 करोड़ रुपये से बढ़कर 24,560 करोड़ रुपये हो गईं।

अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान, केंद्रीय सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफ़डी) और राजस्व घाटा (आरडी) क्रमशः सम्पूर्ण-वर्ष के बजट अनुमान (बीई) का 20.5 प्रतिशत और 16.4 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम था।

जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, उनका समेकित जीएफ़डी, 2022-23[3] में उनका समेकित जीएसपीडी का 3.3 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान है- जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत[4] की सीमा के भीतर है– और राजस्व प्राप्तियों में स्वस्थ वृद्धि से समर्थित है (सारणी III.4 और चार्ट 13.ए)। पूंजीगत परिव्यय में 36 प्रतिशत की बजटित वृद्धि के

सारणी III.3: राज्य सरकार वित्त – प्रमुख घाटा संकेतक*

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

मद	2020-21 (ए)	2021-22 (बीई)	2021-22 (पीए)	2022-23 (बीई)
राजस्व घाटा	1.8	0.8	0.4	0.4
सकल राजकोषीय घाटा	3.8	3.6	2.7	3.3
प्राथमिक घाटा	2.0	1.7	1.1	1.5

ए: लेखा; बीई: बजट अनुमान; पीए: अनंतिम लेखा।

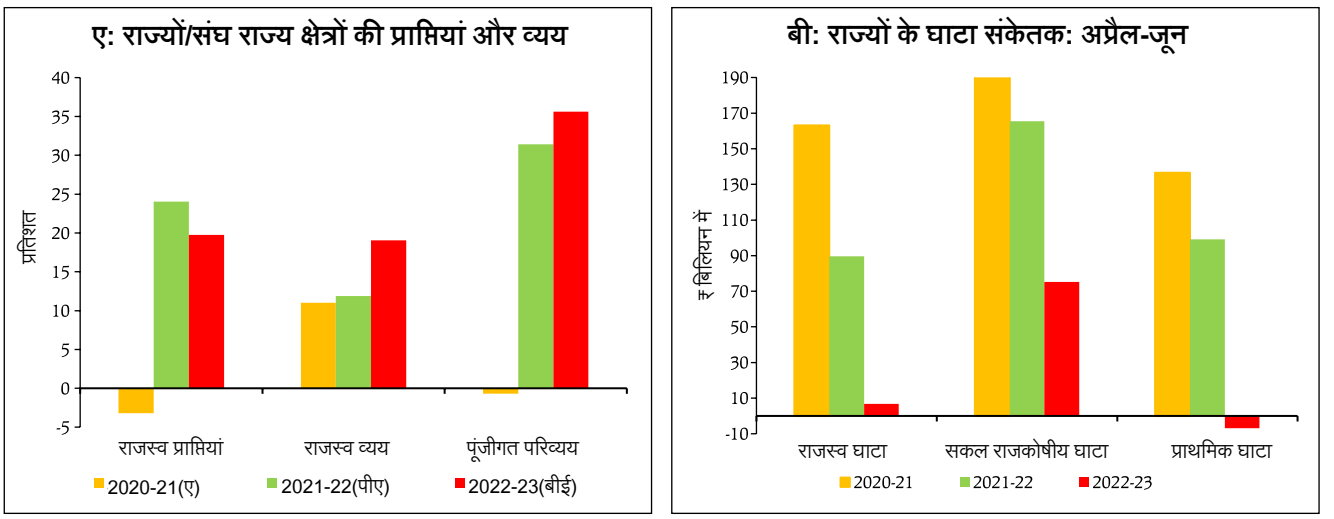
टिप्पणी: डाटा 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज; महालेखा महानियंत्रक (सीएजी)।

[3] 2022-23 के आंकड़े 29 राज्यों/यूटी से संबंधित हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त 27 राज्यों के लेखा (ए) आंकड़ों और 2 राज्यों/यूटी के 2021-22 के बजट दस्तावेजों में से 2021-22 के उनके बजट अनुमानों को मिलाकर, 2021-22 का अनुमान (पीए) आकलित किया गया है।

[4] इसमें से 0.5 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र सुधार से संबन्धित है।

चार्ट III.13: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख संकेतकों में प्रवृत्ति



टिप्पणी: 1. पैनल ए में डेटा 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
2. पैनल बी में डेटा 26 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: राज्य सरकारों और सीएजी के बजट दस्तावेज।

साथ, राज्य सरकारों ने पूंजीगत व्यय पर अपना ध्यान केन्द्रित रखना जारी रखा है। इससे पूंजीगत परिव्यय-जीएसडीपी अनुपात 2021-22 में रहे 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 2.7 प्रतिशत हो जाएगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उच्चतर राजस्व और केंद्र से अंतरण के कारण, राज्यों के जीएफ़डी 2022-23 की पहली तिमाही में उल्लेखनीय रूप से कम हुए हैं (चार्ट 13.बी)। जहां एक ओर, राज्यों के राजस्व व्यय में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं पूंजीगत व्यय में 9.6 प्रतिशत का संकुचन हुआ।

केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में "पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता" योजना के अंतर्गत राज्यों को जीएसडीपी की उधार सीमा 4 प्रतिशत के अतिरिक्त 50 वर्षों के लिए ₹ 1 लाख करोड़ ब्याज-मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। सितंबर 2022 तक केंद्र ने इस योजना के अंतर्गत दस राज्यों को ₹ 40,000 करोड़ अनुमोदित किया है। राज्यों के कैपेक्स को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2022 में केंद्र द्वारा कुल ₹1.16 लाख करोड़ के कर अंतरण की दो किस्तें राज्यों को दी गई हैं।

वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में, सकल और निवल बाजार उधारियां क्रमश: ₹ 14.95 लाख करोड़ और ₹ 11.19 लाख करोड़ रहीं। केंद्रीय बजट 2022-23 के तुरंत पहले किए गए स्विच परिचालन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-23 के लिए डेटेड प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल उधार ₹ 14.31 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। केंद्र द्वारा वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (26 सितंबर 2022 तक) के दौरान जारी सकल बाजार उधारियां कैलेंडर की पहली छमाही के लिए योजनाबद्ध ₹8.45 लाख करोड़ की तुलना में ₹7.96 लाख करोड़ (पूरे वर्ष के लिए निर्धारित बजट राशि का 55.6 प्रतिशत) रहीं (सारणी III.5)। वर्ष 2021-22 की प्रथम छमाही के 6.2 प्रतिशत और 16.7 वर्ष की तुलना में पहली छमाही (27 सितंबर 2022 तक)

सारणी III.4: सरकारी बाज़ार उधार

(₹. करोड़)

	2020-21			2021-22			2022-23 (27 सितंबर तक)		
	केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल
निवल उधार	11,43,114	6,51,777	17,94,891	8,63,103	4,92,483	13,55,586	5,68,639	1,79,878	7,48,517
सकल उधार	13,70,324	7,98,816	21,69,140	11,27,382	7,01,626	18,29,008	7,96,000	2,76,347	10,72,347

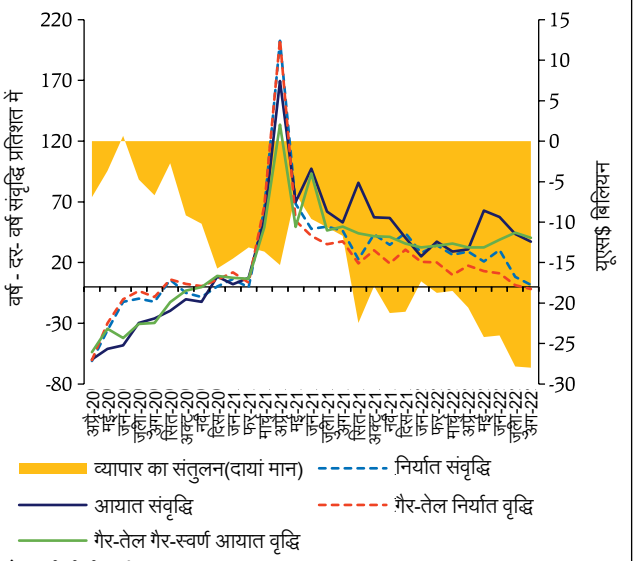
स्रोत: भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

के दौरान भारित औसत लागत और निर्गमों की परिपक्वता क्रमश: 7.3 प्रतिशत और 15.7 वर्ष रहीं। राज्यों द्वारा जुटाई गई सकल बाजार उधारियां पहली छमाही (27 सितंबर 2022 तक) के दौरान 2.76 लाख करोड़ थी जो, सांकेतिक कैलेंडर का 68.8 प्रतिशत है। प्राप्तियों और व्यय के बीच अस्थायी अंतर को पाटने के लिए वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (27 सितंबर 2022 तक) के लिए केंद्र सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा (डब्ल्यूएमए) ₹1.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹1.5 लाख करोड़ कर दी गई। राज्य सरकारों हेतु अर्थोपाय अग्रिम के लिए सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) की सिफारिश के अनुसार 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डब्ल्यूएमए सीमा ₹47,010 करोड़ निश्चित कर दी गई है।

III.1.4 बाह्य मांग

भू-राजनीतिक तनावों और बाह्य मांग में कमी के कारण पहली तिमाही में आघात-सह रहने के बाद वाणिज्य वस्तुओं के निर्यात की गति में दूसरी तिमाही(जुलाई-अगस्त) के दौरान इसमें कमी देखी गई। पहली और दूसरी तिमाही (जुलाई-अगस्त) में उत्साहवर्धक घरेलू मांग के कारण वाणिज्य वस्तुओं के आयात में बढ़त देखी गई। इसके कारण वाणिज्य वस्तुओं के व्यापार की कमी में विस्तार देखा गया (चार्ट III.14)। पहली तिमाही में निर्यात और आयात के दोनों क्षेत्रों में सेवाओं से जुड़े व्यापार ने प्रभावी निष्पादन दर्ज किया। वर्ष

चार्ट III.14: माल व्यापार



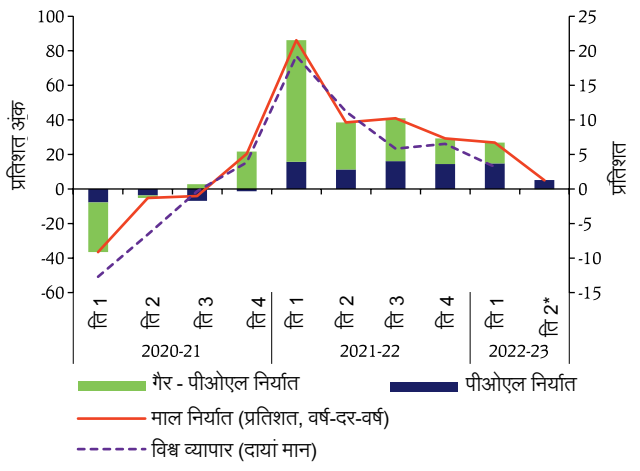
स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस।

2022-23 की पहली तिमाही में निर्यात से अधिक आयात में वृद्धि से, निवल निर्यात ने कुल मांग को कम कर दिया [जीडीपी का वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में (-) 5.0 प्रतिशत और एक वर्ष पूर्व (-) 3.0 प्रतिशत की तुलना में (-) 8.1 प्रतिशत]।

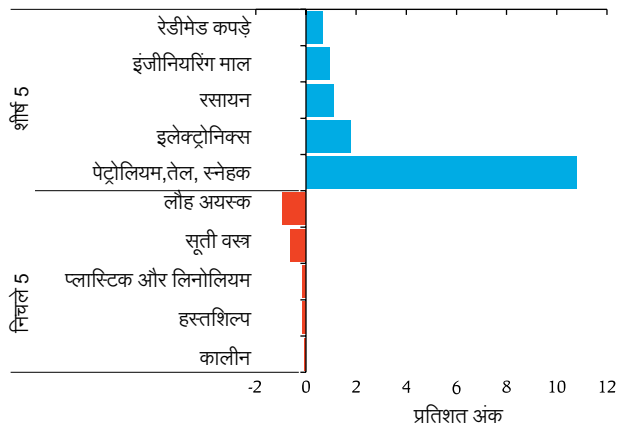
वाणिज्य वस्तुओं के निर्यात का संचालन अप्रैल-अगस्त 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक,रसायनों, अभियांत्रिक सामानों और तैयार वस्त्रों ने किया। तथापि, लौह-अयस्क,सूती

चार्ट III.15: निर्यात संवृद्धि

ए: निर्यात संवृद्धि के प्रति संबंधित अंशदान

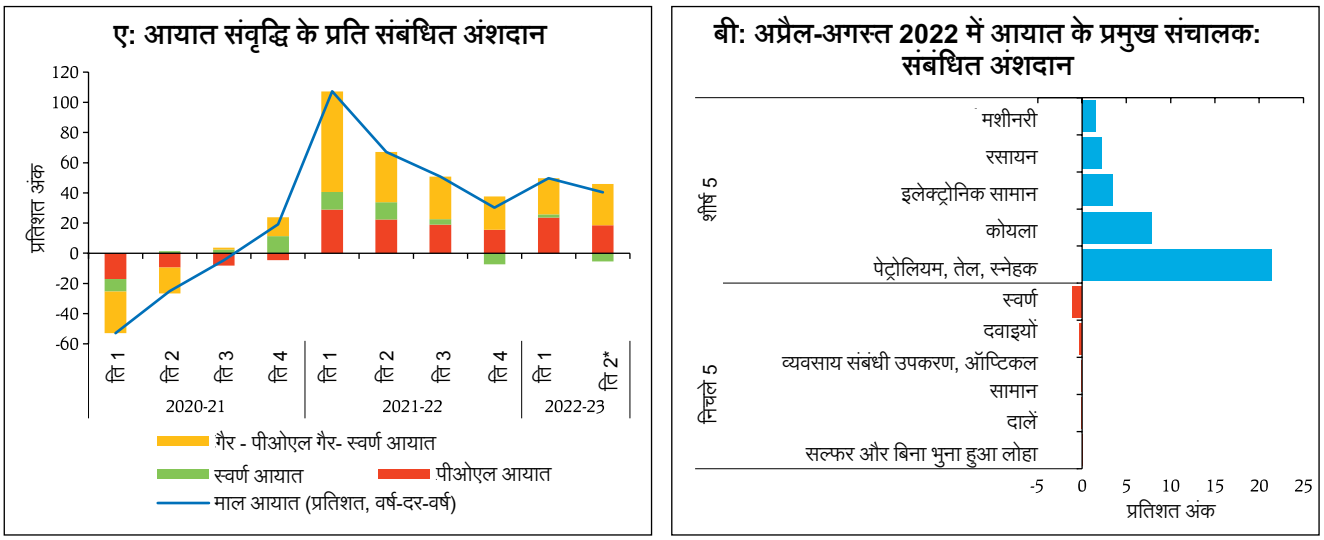


बी: अप्रैल-अगस्त 2022 में निर्यात के प्रमुख संचालक: संबंधित अंशदान



टिप्पणी: *ति2: जुलाई-अगस्त।
स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस; और सीपीबी, नेदरलैंड्स।

चार्ट III.16: आयात संवृद्धि



टिप्पणी: *.ति2: जुलाई-अगस्त।
स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस।

धागे, प्लास्टिक और लिनोलियम, हस्तशिल्प और कालीन का निर्यात सीमित रहा(चार्ट III.15)। घरेलू मांग-पूर्ति संतुलन बैठाने के कारण गेहूं,स्टील और चीनी जैसी कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगने के कारण वाणिज्य वस्तुओं के निर्यात पर असर पड़ा।

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (अप्रैल-अगस्त) में बढ़ती घरेलू मांग और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों से वाणिज्य वस्तुओं के आयात को बढ़ावा दिया। इस वृद्धि में तेल आयात का हिस्सा लगभग आधा रहा। कोयला, इलेक्ट्रॉनिक,रसायन और मशीनरी से संचालित गैर-तेल, गैर सोना आयात में मजबूती रही। ऊर्जा की घरेलू मांग के बढ़ने से कोयला आयात में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बावजूद पर्याप्त वृद्धि देखी गई (चार्ट III.16)। अप्रैल-अगस्त 2022 में व्यापार घाटा एक वर्ष पूर्व के 53.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से दोगुना बढ़कर 124.5 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। वैश्विक व्यापार की मात्रा के प्रति वाणिज्य वस्तुओं का निर्यात अत्यधिक संवेदनशील है जबकि वाणिज्य वस्तुओं का आयात घरेलू मांग से संचालित होता है; वास्तविक विनिमय दर मूल्यह्रास निर्यात को बढ़ावा देता है और आयात मांग को नियंत्रित करने में सहायक है (बाक्स III.1)।

बॉक्स III: 1 भारत के व्यापारिक माल निर्यात और आयात के संवाहक

वैश्विक व्यापारिक माल के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 2019 (महामारी से पहले) में 1.7 प्रतिशत हो गई है। कोविड-19 से उत्पन्न व्यवधानों के बाद, निर्यात और आयात दोनों क्षेत्रों में 2021-22 में मजबूत सुधार देखे गए। भारतीय निर्यात और आयात के संवाहकों को समझना और अलग-अलग आधार पर प्रासंगिक विनिमय दर और आय में घट-बढ़ का आकलन करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए, एक पैनल सह-एकीकरण विश्लेषण किया गया – जिसमें 62 निर्यातित वस्तुएं और 41 आयातित वस्तुएं शामिल हैं और जो चार प्रमुख समूहों अर्थात कृषि वस्तुओं, धातुओं, खनिजों और धातु उत्पादों, पेट्रोलियम उत्पादों और रासायनिक और फार्मास्यूटिकल उत्पादों से संबंधित हैं।

निर्यात और आयात की मात्रा निर्यात/आयात[5] की मद-स्तरीय सापेक्ष कीमतों, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर), वैश्विक मांग

(जारी)

[5] भारत के निर्यात की सापेक्ष कीमतें भारत की निर्यातित वस्तुओं की निहित कीमतों को मद-स्तर (मात्रा के अनुसार डॉलर मूल्य) पर संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से विभाजित करके प्राप्त की जाती हैं, जबकि आयात की सापेक्ष कीमतें मद-स्तरीय आयात (मात्रा से विभाजित आयातित वस्तुओं का मूल्य) की थोक कीमतों तथा संबंधित वस्तु समूहों के थोक मूल्य सूचकांकों का अनुपात होता है।

(निर्यात के लिए), और घरेलू मांग (आयात के लिए) (रायसी एट अल 2015) द्वारा निर्धारित की जाती है । सापेक्ष कीमतें उद्योग-विशेष आधारित प्रतिस्पर्धा को मापती हैं जबकि आरईईआर (40-मुद्रा व्यापार- या निर्यात-भारित) समग्र बाहरी प्रतिस्पर्धा का एक संकेतक है; नीचे दिया गया अनुभवजन्य विश्लेषण इन दोनों संकेतकों के परिणामों की संवेदनशीलता की पड़ताल करता है।

विश्व व्यापार की मात्रा[6] और घरेलू मांग (स्थिर मूल्यों पर आयात को छोड़कर जीडीपी) का उपयोग क्रमशः वैश्विक मांग और घरेलू गतिविधि के संकेतक के रूप में किया जाता है। अनुभवजन्य विश्लेषण महामारी के पूर्व के आंकड़ों (2011-12 की पहली तिमाही से 2019-20 की तीसरी तिमाही) पर आधारित है, जिसमें पूल्ड मीन ग्रुप (पीएमजी) अनुमानक (पेसारन एट अल 1999)

परिणाम एक तरफ निर्यात में, सापेक्ष कीमतों, आरईईआर और वैश्विक मांग के बीच दीर्घकालिक सह-एकीकृत संबंध की उपस्थिति तथा दूसरी ओर आयात में, सापेक्ष मूल्य, आरईईआर और घरेलू मांग का संकेत देते हैं । उत्पादकता लाभ निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं जो वैश्विक मांग के प्रति अत्यधिक लोचदार भी हैं। व्यापारिक आयात से यह प्रदर्शित होता है कि वह घरेलू आर्थिक गतिविधि के साथ मजबूत से आगे बढ़ रहा है और उनका लचीलापन उनके बीच नजदीकी एकरूपता को दर्शाता है। आरईईआर के संबंध में निर्यात की अनुमानित लचीलापन वैकल्पिक विनिर्देशों में (-) 0.37 से (-) 0.39 तक और आयात के लिए (+) 0.41 से (+) 0.63 तक है । मुद्रा की वृद्धि से निर्यात कम हो सकता है और आयात को प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन भारत के निर्यात को उत्पादकता लाभ, एक जनपद, एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना और हाल ही में हस्ताक्षरित और प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौतों जैसी नीतिगत पहलों से कुछ बढ़ावा मिल सकता है।

सारणी III.1.1: भारतीय व्यापारिक माल निर्यात और आयात के निर्धारक: पूल्ड मीन ग्रुप परिणाम

आश्रित चर	लॉग (निर्यात मात्रा)			लॉग (आयात मात्रा)		
	1	2	3	4	5	6
लॉग (आरईईआर)	-0.39* (0.22)		-0.37* (0.21)	0.41** (0.16)		0.63*** (0.16)
लॉग (सापेक्ष मूल्य, मद-स्तर)		-0.43*** (0.04)	-0.38*** (0.04)		-0.17*** (0.04)	-0.16*** (0.04)
लॉग (विश्व व्यापार मात्रा)	1.03*** (0.15)	1.30*** (0.11)	1.48*** (0.15)			
लॉग (घरेलू मांग)				1.00*** (0.05)	0.96*** (0.04)	0.86*** (0.05)
ईटीसी $_{t-1}$	-0.46*** (0.03)	-0.41*** (0.03)	-0.40*** (0.03)	-0.58*** (0.05)	-0.51*** (0.05)	-0.51*** (0.05)

टिप्पणी: ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर पर सांख्यिकीय महत्व को इंगित करते हैं। कोष्ठक में आंकड़े मजबूत मानक त्रुटियां हैं । ईसीटी: त्रुटि सुधार शब्द ।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ

रायसी, एम. और वोलोदिमीर तुलिन, 2015, "प्राइस एंड इंकम एलास्टिसिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट – द रोल ऑफ सप्लाई -साइड बॉटल नेक्स". आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यू पी/15/161

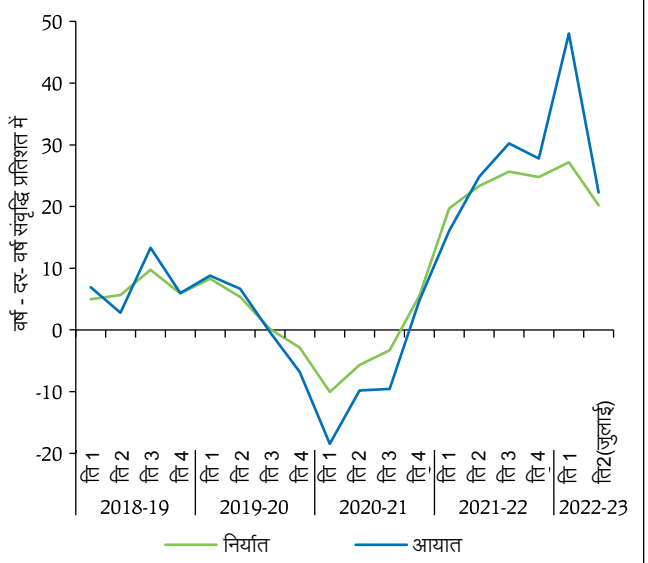
पेसारन, एम. एच., वाय. शीन एंड आर. पी. स्मिथ, 1999, "पुल्ड मीन ग्रुप इस्टिमेशन ऑफ डाईनेमिक हेटरोजीनियस पैनल्स." जर्नल ऑफ अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन 94 (446), पीपी. 621-634।

सेवा क्षेत्र व्यापार ने 2021-22 के दौरान महत्वपूर्ण सुधार के कारण 2022-23 की पहली छमाही (अप्रैल-जुलाई) में मजबूत वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.17)। सॉफ्टवेयर सेवाओं, कारोबार, यात्रा और परिवहन संबंधी सेवाओं से उत्साहित पहली तिमाही में सेवा निर्यात वृद्धि लगातार पांचवीं तिमाही में दहाई अंक में रहा। सॉफ्टवेयर और व्यापार सेवाएं मिलाकर भारत के कुल सेवा निर्यात में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। यद्यपि अमेरिका और यूरोप में मंदी संबंधी जोखिम सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र पर भारी पड़ते हैं, लेकिन भारत की अपतटीय क्षमताओं और दक्षताओं तथा स्वचालन, लागत दक्षता, क्लाउड अपनाने और प्रौद्योगिकी की दिशा में प्रमुख आईटी कंपनियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश से इस क्षेत्र को मजबूत बनाए रखने की उम्मीद है । यात्रा, परिवहन और व्यावसायिक सेवाओं के तहत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण पहली तिमाही के दौरान सेवाओं के आयात में वृद्धि हुई। जुलाई में सेवा निर्यात और आयात में तेजी बनी रही, हालांकि संवृद्धि में कमी आई।

वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत रहा वाणिज्यिक माल व्यापार घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 8.1 प्रतिशत था जबकि निवल अप्रत्यक्ष अधिशेष सकाल घरेलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत रहा।

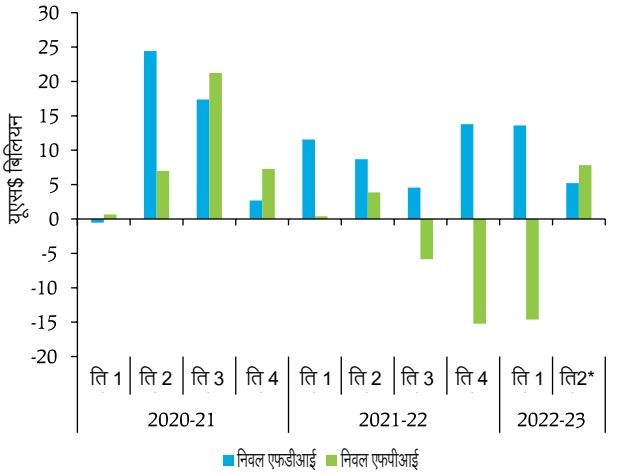
[6] सीपीबी नीदरलैंड ब्यूरो फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एनालिसिस द्वारा जारी ।

चार्ट III.17: सेवाएँ व्यापार



स्रोत: आरबीआई।

चार्ट III.18: निवल प्रत्यक्ष विदेशी और पोर्टफोलियो निवेश



टिप्पणी: *: निवल एफडीआई डेटा जुलाई 2022 से संबंधित हैं; निवल एफपीआई डेटा सितंबर 27, 2022 तक का है।
स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड(एनएसडीएल); और आरबीआई।

वित्तीय खाते की बात करें तो अप्रैल-जुलाई 2022-23 के दौरान निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 18.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मजबूत रहा (चार्ट III.18)। पहली तिमाही के दौरान भारत में विनिर्माण, खुदरा और थोक व्यापार, कंप्यूटर सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और संचार सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा रहा। सिंगापुर, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और नीदरलैंड भारत में आवक एफडीआई के प्रमुख स्रोत देश थे, जो कुल प्रवाह का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा थे।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने पहली तिमाही में घरेलू पूंजी बाजार में अपना निवेश घटाया, जो अमेरिकी डॉलर की मजबूती, तेज भूराजनीतिक तनाव, वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा तेजी से नीतिगत सख्ती के मद्देनजर ईएमई परिसंपत्तियों के प्रति सामान्यीकृत जोखिम विमुखता को दर्शाता है। हालांकि, एफपीआई जुलाई 2022 से दूसरी तिमाही (28 सितंबर तक) में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ निवल खरीदार बन गए।

भारत की बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) ने 2021 के दौरान 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल बहिर्गमन के बाद अप्रैल-अगस्त 2022 के दौरान 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया। एफसीएनआर (बी) जमाराशियों से बहिर्वाह और एनआरई जमाओं में कम अंतर्वाह के कारण अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान अनिवासी जमाराशियों के तहत निवल अंतर्वाह घटकर 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो एक साल पहले 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 23 सितंबर, 2022 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 537.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

III.2 समग्र आपूर्ति

समग्र आपूर्ति की माप आधार दर कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) के द्वारा की गई है। वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में इसमें 12.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई (एक वर्ष पूर्व 18.1 प्रतिशत)। इसने वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के अपने महामारी-पूर्व के स्तर को 4.7 प्रतिशत से पार किया है (सारणी III.5)। कृषि और सेवा क्षेत्र मजबूत बना रहा जबकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में लंबे समय से खिंचे आ रहे व्यवधानों की वजह से और इनपुट लागत बढ़ने के दबाव से औद्योगिक जीवीए वृद्धि में कमी आई। तिमाही-दर-तिमाही एसएएआर द्वारा मापी गई जीवीए की रफ्तार वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में ऋणात्मक थी। (चार्ट III.19)।

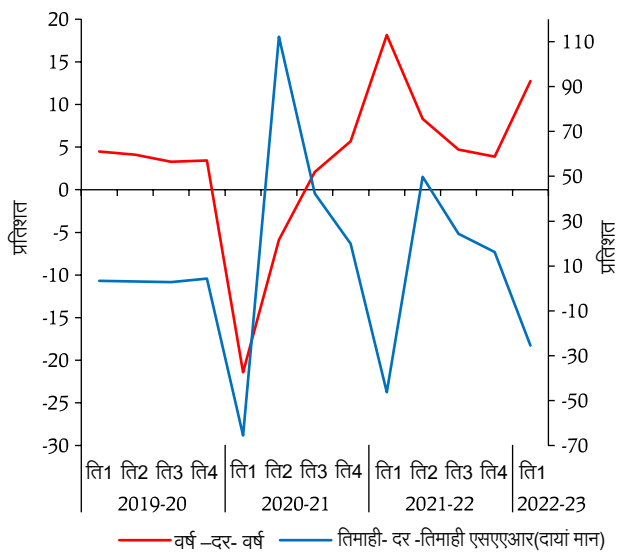
सारणी III.5: जीवीए में क्षेत्र-वार संवृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष; प्रतिशत)

मद	2020-21 (एफआरई)	2021-22 (पीई)	भारित योगदान		2020-21				2021-22				2022-23
			2020-21	2021-22	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1
कृषि, फोरेस्टरी और फिशिंग	**3.3**	**3.0 (6.4)**	**0.5**	**0.5**	**3.0**	**3.2**	**4.1**	**2.8**	**2.2 (5.2)**	**3.2 (6.4)**	**2.5 (6.7)**	**4.1 (7.1)**	**4.5 (9.9)**
उद्योग	**-1.8**	**9.8 (7.9)**	**-0.4**	**2.2**	**-28.1**	**3.0**	**6.2**	**11.6**	**40.4 (0.9)**	**6.6 (9.9)**	**1.5 (7.8)**	**1.0 (12.7)**	**6.0 (7.0)**
खनन तथा उत्खनन	-8.6	11.5 (1.9)	-0.2	0.3	-17.8	-7.9	-5.3	-3.9	18.0 (-3.0)	14.5 (5.5)	9.2 (3.4)	6.7 (2.6)	6.5 (3.3)
विनिर्माण	-0.6	9.9 (9.3)	-0.1	1.8	-31.5	5.2	8.4	15.2	49.0 (2.1)	5.6 (11.0)	0.3 (8.7)	-0.2 (15.0)	4.8 (7.0)
विद्युत,गैस, जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोज्यता	-3.6	7.5 (3.6)	-0.1	0.2	-14.8	-3.2	1.5	3.2	13.8 (-3.0)	8.5 (5.0)	3.7 (5.2)	4.5 (7.9)	14.7 (11.2)
सेवाएँ	**-7.8**	**8.8 (0.4)**	**-4.9**	**5.4**	**-24.3**	**-10.4**	**0.0**	**4.3**	**15.5 (-12.6)**	**10.0 (-1.4)**	**6.6 (6.6)**	**5.0 (9.4)**	**17.5 (2.8)**
निर्माण	-7.3	11.5 (3.4)	-0.6	0.9	-49.4	-6.6	6.6	18.3	71.3 (-13.3)	8.1 (0.9)	-2.8 (3.6)	2.0 (20.6)	16.8 (1.2)
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	-20.2	11.1 (-11.3)	-4.1	1.9	-49.9	-18.8	-10.1	-3.4	34.3 (-32.7)	9.6 (-11.0)	6.3 (-4.4)	5.3 (1.7)	25.7 (-15.5)
वित्त, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएँ	2.2	4.2 (6.6)	0.5	1.0	-1.1	-5.2	10.3	8.8	2.3 (1.1)	6.1 (0.6)	4.2 (14.9)	4.3 (13.4)	9.2 (10.5)
लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	-5.5	12.6 (6.4)	-0.7	1.6	-11.4	-10.2	-2.9	1.7	6.2 (-5.9)	19.4 (7.3)	16.7 (13.3)	7.7 (9.5)	26.3 (18.9)
मूल कीमतों पर जीवीए	**-4.8**	**8.1 (2.9)**	**-4.8**	**8.1**	**-21.4**	**-5.9**	**2.1**	**5.7**	**18.1 (-7.2)**	**8.3 (1.9)**	**4.7 (6.9)**	**3.9 (9.8)**	**12.7 (4.7)**

टिप्पणी: एफआरई : पहला संशोधित अनुमान; पीई: अनंतिम अनुमान।
कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें 2019-20 की संवृद्धि दरें हैं।
स्रोत: एनएसओ।

चार्ट III.19 : जीवीए संवृद्धि और गति



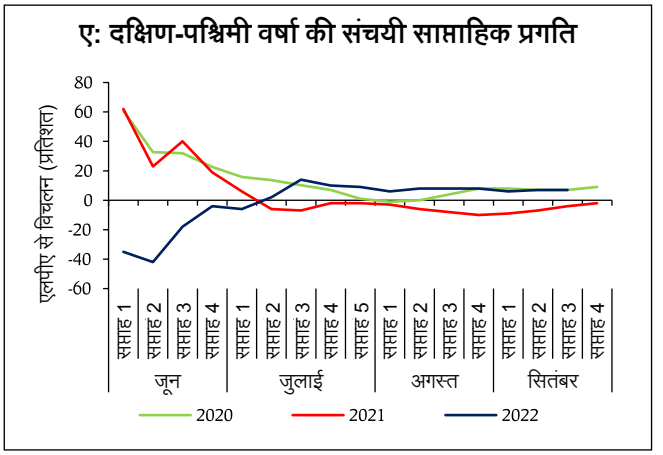
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

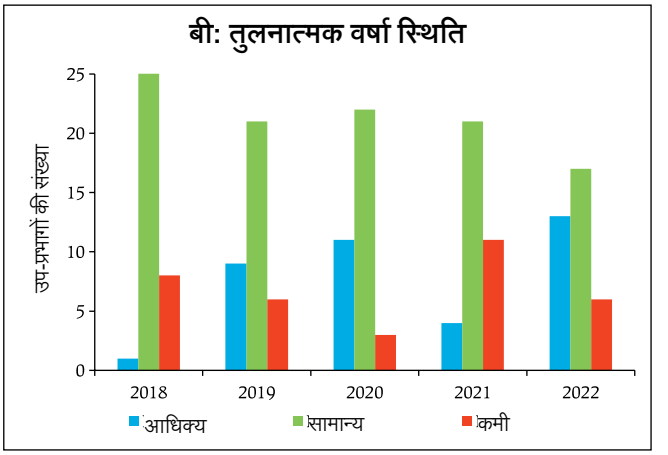
III.2.1 कृषि

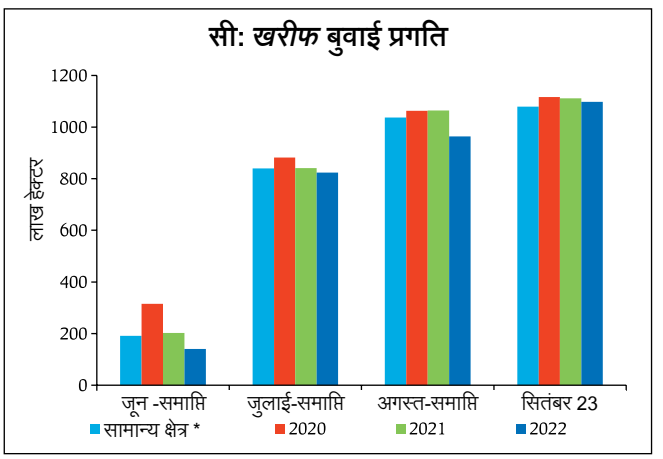
रिकॉर्ड रबी और बागवानी उत्पादन तथा संबद्ध गतिविधियों की समुत्थानशक्ति से सहारा पाकर वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में कृषि, वानिकी और मत्स्यन जीवीए ने 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है (एक वर्ष पूर्व 2.2 प्रतिशत)। धीमी शुरुआत के बाद, दक्षिण-पश्चिमि मानसून (एसडब्ल्यूएम) ने जुलाई-अगस्त में रफ्तार पकड़ी और इस मौसम में 29 सितंबर 2022 तक की वर्षा लंबी अवधि के औसत (एलपीए) से 7 प्रतिशत अधिक (एक वर्ष पहले एलपीए से 4 प्रतिशत कम) थी, जिसमें 36 उप-मंडलों में से 30 में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई (चार्ट III.20ए और बी)। हालांकि, कुछ प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों - उत्तर प्रदेश (-28 प्रतिशत), बिहार (-31 प्रतिशत), झारखंड (-21 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (16 प्रतिशत) में सामान्य से काफी कम वर्षा हुई। जून- जुलाई में पिछड़ने के बाद, अगस्त में खरीफ बुवाई वाले क्षेत्र में आकर्षक सुधार हुआ। 23 सितंबर 2022 तक, कुल खरीफ बुवाई क्षेत्र सामान्य क्षेत्र (5 साल के औसत) से 1.7 प्रतिशत अधिक था; हालांकि चावल (-5.5 प्रतिशत), दलहन (-3.9 प्रतिशत) और तिलहन (-0.8 प्रतिशत) में कमी के कारण यह एक वर्ष पूर्व से 1.2 फीसदी कम था (चार्ट 3.20सी)। 23 सितंबर 2022 के अनुसार उत्पादन भारित वर्षा (पीआरएन) सूचकांक 100 पर था, जो पिछले वर्ष की स्थिति (101 प्रतिशत) से थोड़ा कम था और कपास, तिलहन, दलहन

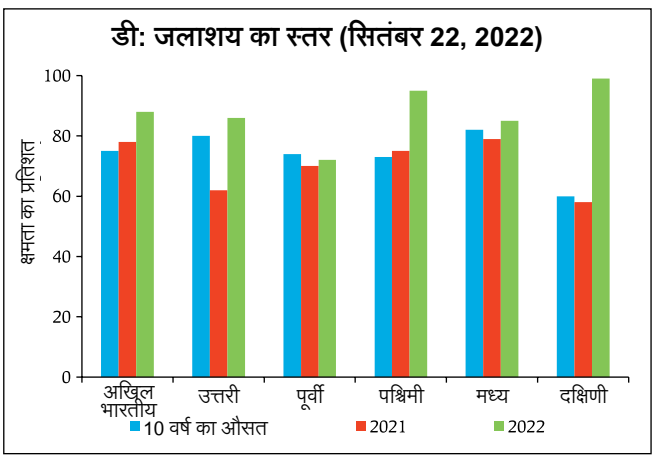
और मोटे अनाज के लिए पीआरएन 5 साल के औसत से अधिक था(चार्ट III.20ई और एफ़)। 22 सितंबर, 2022 तक, जलाशय का स्तर पूर्ण क्षमता का 88 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष के 73 प्रतिशत से ऊपर और साथ ही 73 प्रतिशत के दशकीय औसत से ऊपर है जो आगामी रबी के मौसम की बेहतरीन संभावनाओं को दर्शाता है।

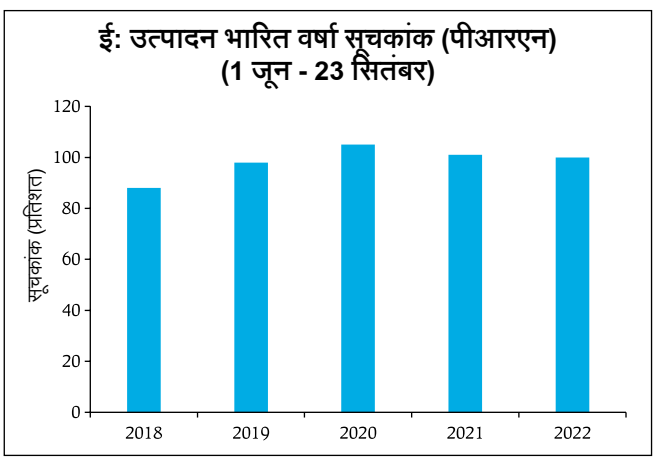
चार्ट III.20: वर्षा और खरीफ बुआई की प्रगति

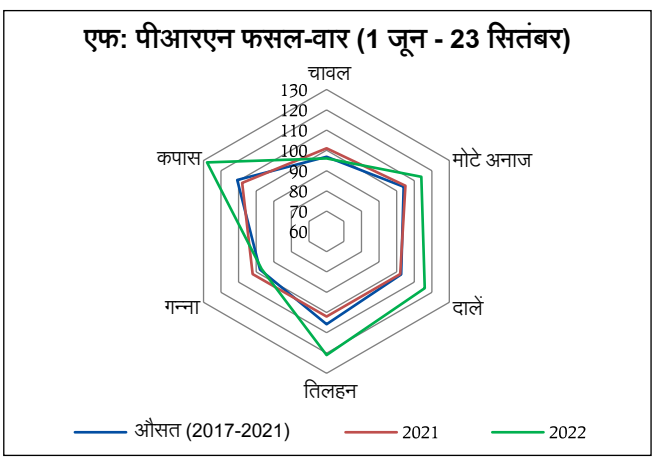












*आज की तारीख के अनुसार सामान्य क्षेत्र 5 वर्ष - 2017-18 से 2021 का औसत है।

स्रोत: भारत मौसम विज्ञान विभाग(आईएमडी); केंद्रीय जल आयोग; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2022 में खरीफ़ का उत्पादन 1,499.2 लाख टन अनुमानित है जो पिछले वर्ष के चौथे अग्रिम अनुमान (पिछले वर्ष के प्रथम अग्रिम अनुमान से 0.4 प्रतिशत कम) तुलना में – 3.9 प्रतिशत कम है (सारणी III.6)। अन्य फसलों में कपास और गन्ना के उत्पादन का अनुमान पिछले वर्ष के स्तर से अधिक 9.6 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत, जबकि तिलहन का उत्पादन 1.3 प्रतिशत कम रहेगा।

सरकार ने वर्ष 2022-23 की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 4.4 - 8.9 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की, जो उत्पादन लागत (ए2 और एफएल[7] को जोड़कर मापा गया) पर कम से कम 50 प्रतिशत का रिटर्न सुनिश्चित करता है। वर्ष 2021-22 (26 सितंबर, 2022 तक) के दौरान खरीफ विपणन के समय चावल की 592.8 लाख टन की खरीददारी हुई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1 प्रतिशत अधिक थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत खाद्यान्न वितरण को बढ़ाए जाने के बावजूद चावल के बफर मानदंड (352.9 लाख टन) के 2.6 गुना पर्याप्त भंडार होने में इसका योगदान है। गेहूं के मामले में, कम घरेलू उत्पादन के परिणामस्वरूप कम खरीददारी हुई।

सारणी III.6 खरीफ फसल उत्पादन

(लाख टन्स)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2022-23	
				पहला एई	संवृद्धि (प्रतिशत) 2021-22	
					पहला एई	चौथा एई
1. खाद्यान्न	**1433.8**	**1495.6**	**1560.4**	**1499.2**	**-0.4**	**-3.9**
चावल	1019.8	1044.1	1117.6	1049.9	-1.9	-6.1
मोटे अनाज	336.9	364.6	359.1	365.6	7.5	1.8
दलहन	77.2	86.9	83.7	83.7	-11.4	0
तूर	38.3	42.8	43.4	38.9	-12.2	-10.4
उड़द	13.0	16.0	19.4	18.4	-10.2	-5.2
मूंग	17.9	20.1	14.8	17.5	-14.6	18.2
2. तिलहन (कुल)	223.2	240.3	238.9	235.7	0.8	-1.3
मूंगफली	83.7	85.6	83.8	83.7	1.4	-0.1
सोयाबीन	112.2	129.0	130.0	128.9	1.4	-0.8
3. कपास#	354.9	353.8	312.0	341.9	-5.6	9.6
4. जूट और मेस्ता##	99.1	95.6	103.2	100.9	5	-2.2
5. गन्ना	3557.0	3992.5	4318.1	4650.5	10.9	7.7

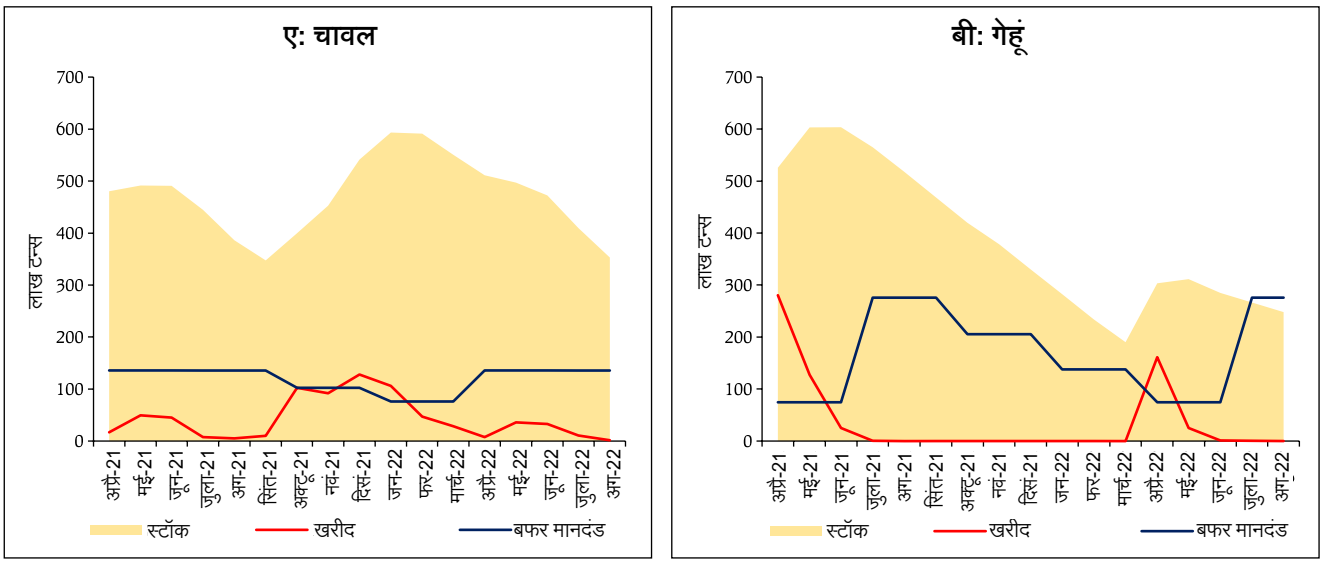
#: प्रत्येक170 किलोग्राम की लाख गांठें।

#: प्रत्येक 180 किलो की लाख गांठें।

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

31 अगस्त 2022 तक 248.2 लाख टन का बफर भंडार मानदंड से थोड़ा ही नीचे था (चार्ट III.21ए और बी)।

चार्ट III.21: स्टॉक, खरीद और बफर मानदंड की स्थिति - गेहूं और चावल



स्रोत: भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार (जीओआई)।

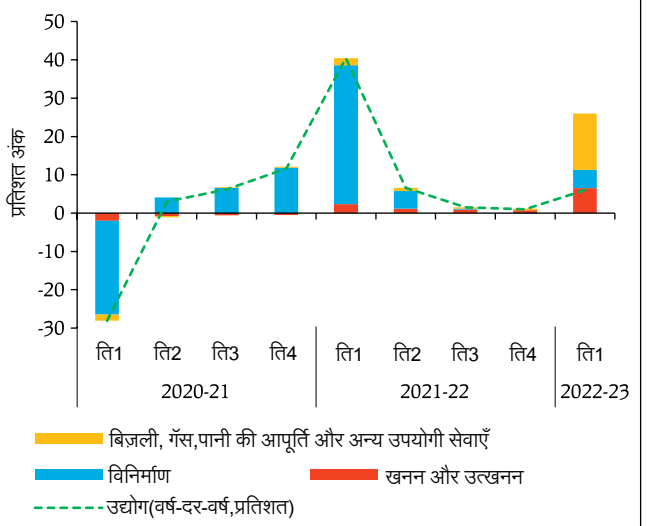
[7] ए2 (तुरंत देय खर्च) और एफएल (पारिवारिक श्रमशक्ति) के जोड़ में भुगतान की गई सभी लागतें शामिल हैं जैसे कि किराए की श्रमशक्ति, मशीनों, पट्टे की भूमि के लिए अदा किया गया किराया, बीज, उर्वरक, सिंचाई शुल्क, मूल्यह्रास और साथ ही साथ पारिवारिक श्रम का अभ्यारोपित मूल्य।

III.2.2 उद्योग

औद्योगिक जीवीए ने वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 6.0 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की (आधार प्रभावों द्वारा संचालित एक वर्ष पहले इसी अवधि में 40.4 प्रतिशत)। उच्च इनपुट लागत और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, सभी घटकों ने वर्ष-दर-वर्ष विस्तार करते हुए, वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के अपने स्तर को पार कर लिया (चार्ट III.22)। औद्योगिक गतिविधि के पुनरुद्धार और सेवाओं के सामान्यीकरण द्वारा समर्थित बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं ने मजबूत वृद्धि दर्ज की।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) अपने सभी घटकों - खनन, विनिर्माण और बिजली द्वारा समर्थित होकर अप्रैल-जुलाई के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 10.0 प्रतिशत बढ़ा (महामारी पूर्व स्तर से 4.2 प्रतिशत ऊपर) (चार्ट III.23)।

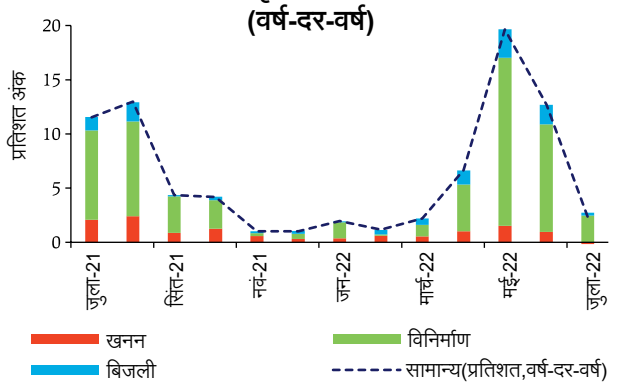
चार्ट III.22: उद्योग जीवीए संवृद्धि में भारित अंशदान



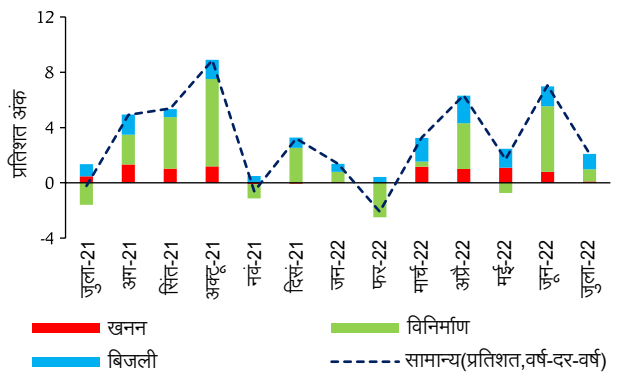
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.23: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक(आईआईपी)

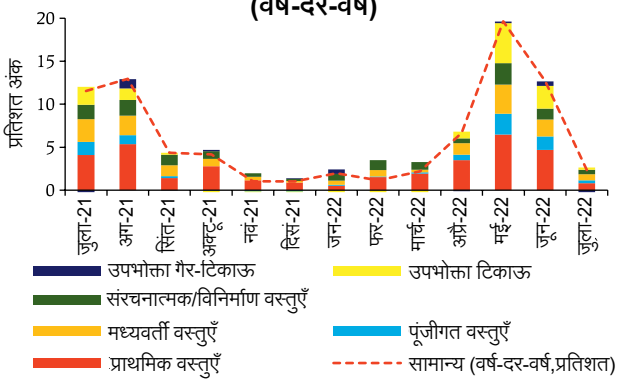
ए: आईआईपी संवृद्धि के प्रति क्षेत्रीय योगदान (वर्ष-दर-वर्ष)



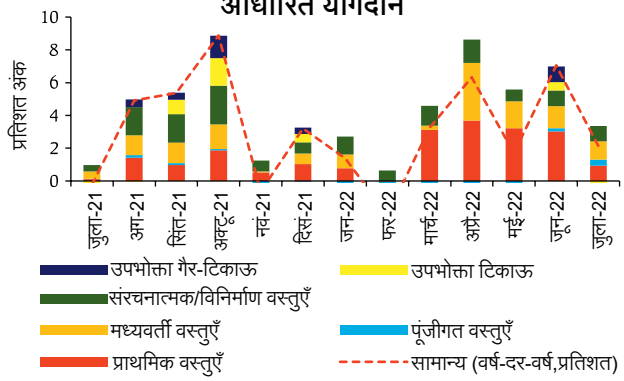
बी: 2019 के बाद आईआईपी संवृद्धि के प्रति क्षेत्रीय योगदान



सी: आईआईपी संवृद्धि के प्रति उपयोग- आधारित योगदान (वर्ष-दर-वर्ष)

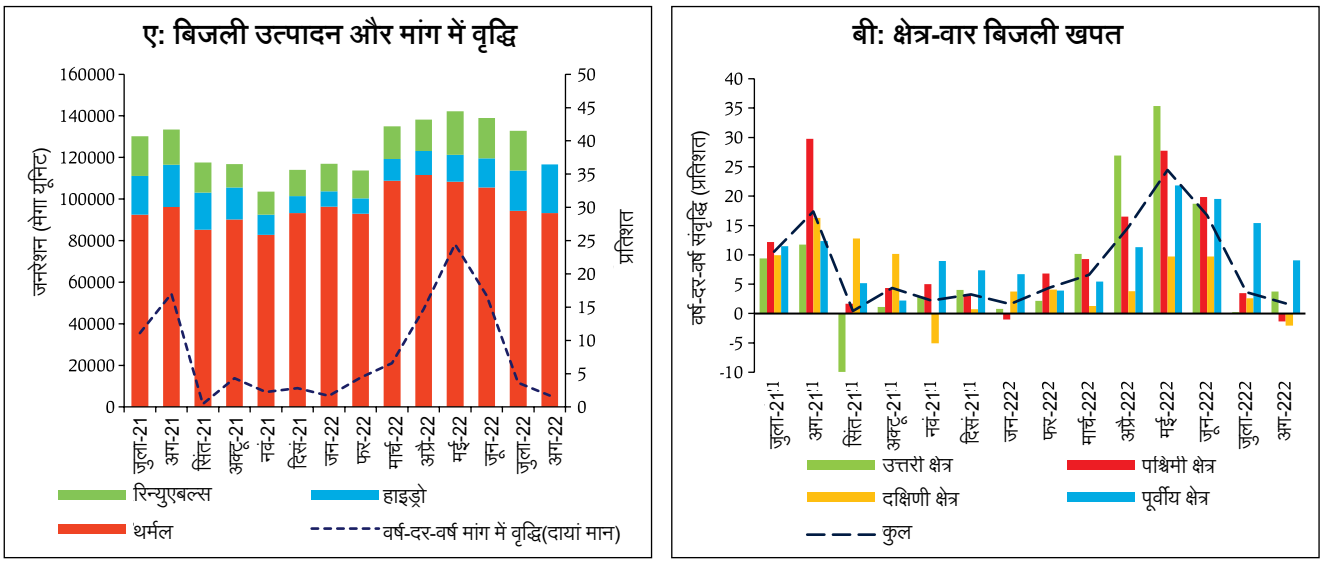


डी: 2019 के बाद आईआईपी संवृद्धि के प्रति उपयोग-आधारित योगदान



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.24: बिजली उत्पादन और खपत



स्रोत: केंद्रीय बिजली प्राधिकरण और भारत का बिजली व्यवस्था संचालन निगम(पीओएसओसीओ)।

विनिर्माण गतिविधि में विस्तार पेय, परिधान, फर्नीचर, छपाई और रिकॉर्ड किए गए मीडिया की प्रतिकृति करने और अन्य परिवहन उपकरणों द्वारा संचालित था। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, अप्रैल-जुलाई के दौरान सभी श्रेणियों में वर्ष-दर-वर्ष विस्तार हुआ। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो निवेश गतिविधि में पुनरुद्धार का संकेतक है। निजी खपत, विशेषकर शहरी मांग में सुधार से लाभ हुआ जिससे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में भी मजबूत वृद्धि हुई।

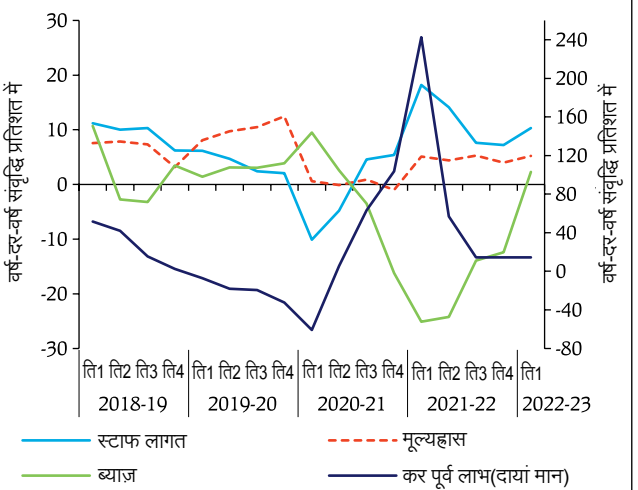
वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में बिजली उत्पादन में 17.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (महामारी पूर्व स्तर से 15.3 प्रतिशत ऊपर)। थर्मल और नवीकरणीय स्रोतों में क्रमशः 17.7 प्रतिशत और 28.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी तिमाही (जुलाई-अगस्त) में, प्रचुर वर्षा के कारण समग्र बिजली उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से कम होकर 2.7 प्रतिशत तक हो गई (चार्ट III.24ए)। प्रथम छमाही के दौरान क्षेत्रवार बिजली की मांग व्यापक बनी रही (चार्ट III.24बी)।

सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों के सांकेतिक जीवीए में उच्च लाभ और कर्मचारियों की लागत के कारण एक स्वस्थ विस्तार बना रहा (चार्ट III.25)। रिज़र्व बैंक के औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का रुख सकारात्मक रहा।

बिक्री में वृद्धि, क्षमता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण के कारण मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) पहली तिमाही में 54.4 से सुधरकर दूसरी तिमाही में 56.3 (जुलाई में 56.4 और अगस्त में 56.2) हो गया है (चार्ट III.26ए)।

कुल मिलाकर, विनिर्माण, प्राथमिक वस्तुएं, बुनियादी संरचना और निर्माण और पूंजीगत वस्तुएं आदि महामारी-पूर्व स्तर तक सामान्य हो गए हैं, जबकि उपभोक्ता वस्तुएं पिछड़ रही

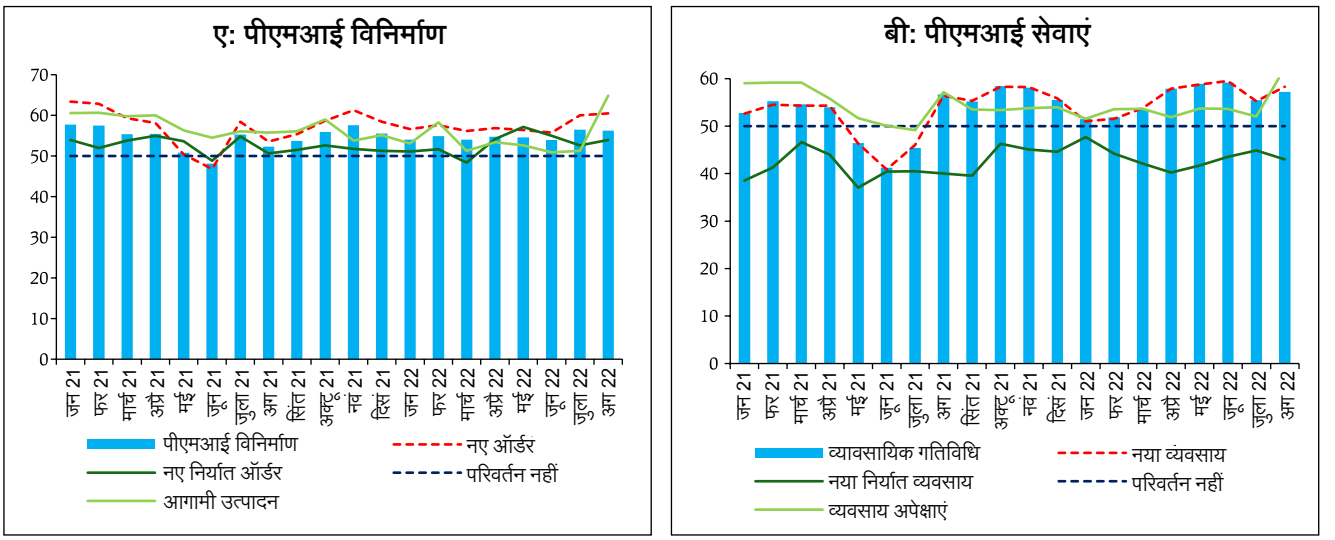
चार्ट III.25: विनिर्माण क्षेत्र की लाभप्रदता



टिप्पणी: 2022-23 की पहली तिमाही के लिए डाटा 1,707 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों के परिणाम पर आधारित है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रकाशित डाटा पर आधारित।

चार्ट III.26: पीएमआई विनिर्माण और सेवाएं



टिप्पणी: > 50: विस्तार, < 50: संकुचन।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

हैं (सारणी III.7)। प्रमुख उप-क्षेत्रों में, इस्पात की खपत, सीमेंट उत्पादन, बिजली उत्पादन, यात्री वाहन और दोपहिया वाहन, उछाल का संकेत देते हैं और अपने 2019-20 के उत्पादन स्तर से ऊपर हैं।

सारणी III.7: औद्योगिक क्षेत्र: सामान्यीकरण की दिशा में प्रगति

(2019-2020 के संबंधित माह/तिमाही के लिए अनुपात)

	संकेतक	2020-21				2021-22				2022-23		
		ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	जुलाई	अगस्त
I	औद्योगिक उत्पादन											
	पीएमआई: विनिर्माण (>50 पिछले महीने की तुलना में वृद्धि दर्शाता है)	35.1	51.6	57.2	56.9	51.5	53.8	56.3	54.3	54.4	56.4	56.2
II	**औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक**	64	94	102	106	93	103	104	108	105	102	
	आईआईपी: विनिर्माण	60	94	102	107	91	102	103	108	103	101	
	आईआईपी: पूंजीगत वस्तुएं	35	87	99	109	74	102	97	111	96	107	
	आईआईपी: इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण वस्तुएं	53	98	105	110	98	110	109	117	108	107	
	आईआईपी: उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	32	90	107	118	72	99	103	111	92	93	
	आईआईपी: उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	83	100	103	105	98	101	103	102	99	98	
III	**आठ कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स**	76	95	100	103	96	104	105	109	109	106	
	ईसीआई: स्टील	51	100	103	113	97	108	105	118	103	108	
	ईसीआई: सीमेंट	62	89	96	110	97	110	104	119	114	107	
	बिजली की मांग	84	99	106	108	98	108	110	113	116	110	117
IV	**ऑटोमोबाइल का उत्पादन**											
	यात्री वाहन	16	94	120	123	83	95	100	120	106	121	125
	टू व्हीलर्स	22	95	118	129	60	89	91	102	83	87	100
	थ्री व्हीलर्स	23	45	66	84	61	60	67	83	64	71	77
	ट्रैक्टर्स	60	123	162	153	133	143	118	99	152	145	141

स्रोत: सीएमआईई; सीआईईसी;एनएसओ;एसआईएएम; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

← पूर्व-कोविड स्तर से नीचे गतिविधि का सामान्यीकरण/पुनर्प्राप्ति →

III.2.3 सेवाएं

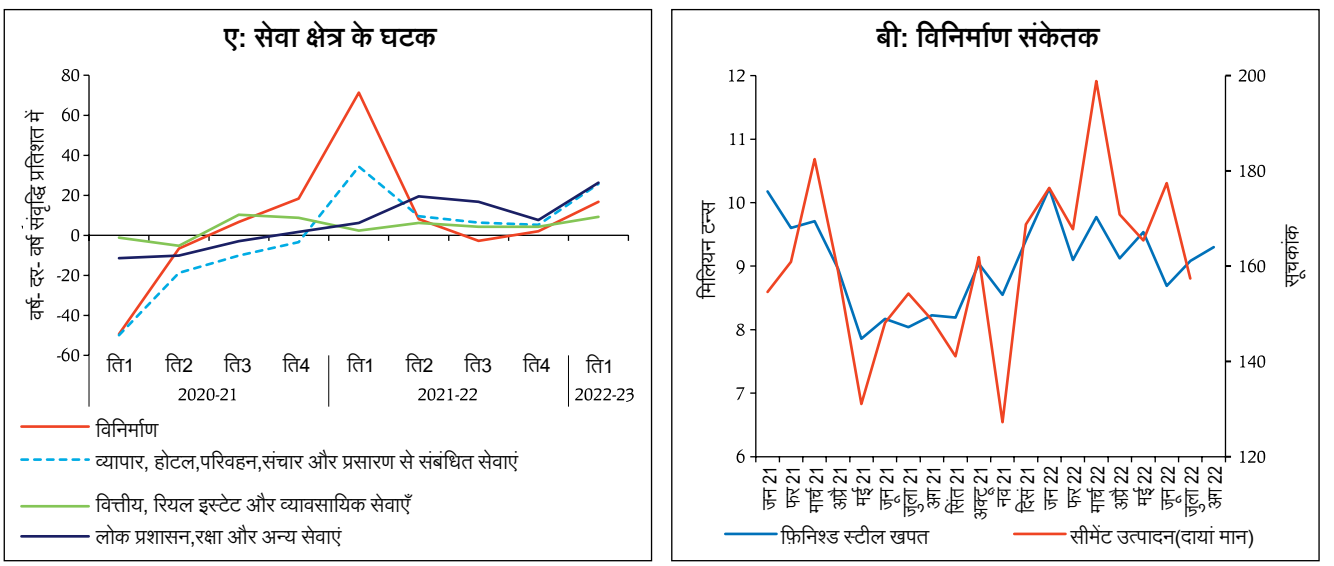
संपर्क-गहन गतिविधियों में निरंतर सुधार, उपभोक्ता विश्वास और व्यावसायिक भाव में सुधार के समर्थन से वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र के जीवीए (महामारी पूर्व स्तर से 2.8 प्रतिशत ऊपर) में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.27ए)। परिचालन के पुनरारंभ और दमित मांग में वृद्धि ने व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को पुनर्जीवित किया, लेकिन यह अभी भी महामारी पूर्व स्तर से 15.5 प्रतिशत नीचे रहा।

उच्च आवृत्ति संकेतक, सेवा गतिविधि में तनाव के निरंतर विस्तार का संकेत करते हैं (सारणी III.8)। अगस्त माह में जीएसटी संग्रह और ई-वे बिल जारी करना - थोक और खुदरा व्यापार और अंतर्निहित समग्र आर्थिक गतिविधि के संकेतक - लगातार चौदहवें महीने के लिए महामारी पूर्व के स्तर से ऊपर रहा। जैसा कि सीमेंट उत्पादन और स्टील की खपत से परिलक्षित होता है, पहली छमाही में निर्माण क्षेत्र की गतिविधि स्वस्थ रही, , बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और स्थावर संपदा गतिविधि में सुधार पर सरकार के निरंतर ध्यान से इसे लाभ मिला (चार्ट III.27बी)।

विवेकाधीन खर्च और दमित मांग में हुई वृद्धि के कारण पहली तिमाही में, यात्रा और आतिथ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। मई-जून 2022 में होटल उद्योग में अतिथियों के ठहरने का स्तर महामारी पूर्व के स्तर से अधिक हो गया लेकिन इसमें जुलाई-अगस्त में मामूली गिरावट आई। पहली छमाही में परिवहन गतिविधि मजबूत रही- पहली तिमाही में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दोगुनी से अधिक हो गई, जबकि पहली तिमाही में रेलवे माल ढुलाई में 11.8 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई (अगस्त तक)। अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी के कारण पोत माल आवागमन में पहली तिमाही में 9.2 प्रतिशत और दूसरी तिमाही (अगस्त तक) में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी III.8)। पर्यटन के साथ-साथ व्यवसाय से संबंधित यात्राओं में बेहतरी के कारण हवाई माध्यम से यात्री आवागमन में पहली तिमाही में 206.2 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में (अगस्त तक) 74.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी III.9)।

वित्तीय सेवाओं में उछाल और स्थावर संपदा में पुनरुद्धार की सहायता से वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाओं में वृद्धि, पिछले वर्ष के 2.3 प्रतिशत से बेहतर होकर 2022-23 की पहली तिमाही में 9.2 प्रतिशत हो गई। वित्तीय सेवाओं को समर्थन प्रदान करते हुए, 9 सितंबर को बैंक ऋण वृद्धि, 16.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई। स्थावर संपदा क्षेत्र में, पहली तिमाही में नई परियोजना आरंभ, 25 तिमाही के उच्च स्तर पर पहुंच गए और बिक्री 10 तिमाहियों में उच्चतम स्तर पर थी, लेकिन अभी भी महामारी-पूर्व के स्तर से पीछे हैं (चार्ट III.28ए)। आरबीआई के अखिल भारतीय आवासीय मूल्य सूचकांक के अनुसार, 2022-23 की पहली तिमाही में आवास की कीमतों में 3.5 प्रतिशत (वर्ष-दर- वर्ष) की वृद्धि दर्ज हुई जिसका प्रमुख कारण चेन्नई और

चार्ट III.27: सेवा क्षेत्र



स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय; संयुक्त आयोजना समिति; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय|

सारणी III.8: सेवा क्षेत्र: सामान्यीकरण की दिशा में प्रगति

(2019-2020 के संबंधित माह/तिमाही के लिए अनुपात)

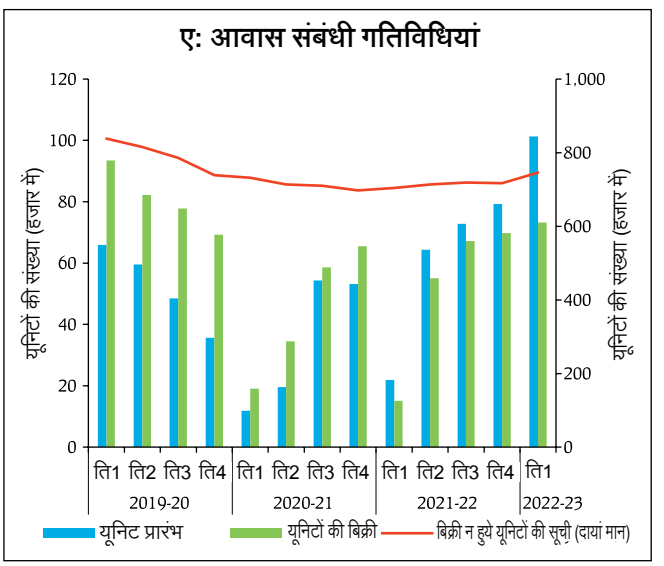
संकेतक	2020-21				2021-22				2022-23		
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	जुलाई	अगस्त
पीएमआई: सेवाएं (>50 पिछले महीने की तुलना में वृद्धि दर्शाता है)	17.2	41.9	53.4	54.2	47.2	52.4	57.3	52.3	58.7	55.5	57.2
I **निर्माण**											
स्टील की खपत	49	93	114	123	99	93	107	122	109	106	101
सीमेंट उत्पादन	62	89	96	110	97	110	104	119	114	107	
II **व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं**											
वाणिज्यिक वाहन की बिक्री (तिमाही औसत)	15	80	99	143	51	99	100	170	108		
घरेलू हवाई यात्री यातायात	7	25	50	72	31	53	81	77	95	83	87
घरेलू एयर कार्गो	26	68	90	105	78	86	92	101	103	98	91
अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो	43	77	87	101	94	96	100	103	92	91	90
माल ढुलाई	79	105	111	113	110	118	119	121	123	122	131
पोर्ट कार्गो	80	91	103	107	102	97	104	106	111	107	109
टोल संग्रहण: मात्रा	184	349	295	174	548	699	513	259	1035	973	979
पेट्रोलियम की खपत	74	88	101	100	85	93	98	105	100	98	104
जीएसटी ई-वे बिल	50	100	115	128	98	127	128	140	143	145	153
जीएसटी राजस्व	59	92	108	114	106	118	130	133	144	146	146
III **वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ**											
क्रेडिट बकाया वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि (प्रतिशत)	6.2	5.2	6.6	5.6	5.8	6.7	9.3	9.6	13.2	14.5	15.5
बैंक जमाराशि वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि (प्रतिशत)	11.0	10.5	11.5	11.4	10.3	9.4	10.3	8.9	8.3	9.1	9.5
जीवन बीमा: प्रथम वर्ष का प्रीमियम	81	116	97	135	87	122	107	169	122	182	139
गैर-जीवन बीमा प्रीमियम	95	105	104	115	107	118	113	127	133	163	153

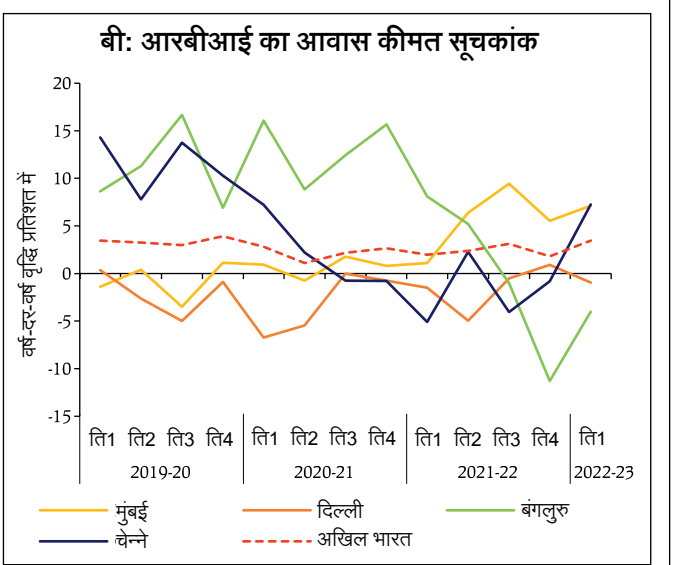
टिप्पणी: 3 दिसंबर 2021 से बैंक ऋण समृद्धि को अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिये समायोजित किया हैं।
स्रोत: सीएमआईई; सीआईईसी;एनएसओ; एमओएसपीआई;आईआरडीएआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

← पूर्व-कोविड स्तर से नीचे गतिविधि का सामान्यीकरण/पुनर्प्राप्ति →

मुंबई में हुई वृद्धि रही (चार्ट III.28)। सरकारी खपत में मंद वृद्धि दर्ज होने पर भी, अन्य सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सांस्कृतिक आदि) की सहायता से सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) में वर्ष 2022 की पहली तिमाही

चार्ट III.28: आवास क्षेत्र – प्रारंभ,बिक्री और कीमतें





स्रोत: प्रोप टाईगर; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 26.3 प्रतिशत (एक साल पहले 6.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

पहली छमाही में पीएमआई सेवाएं विस्तार क्षेत्र में रहीं। पहली तिमाही के 58.7 से घटकर जुलाई में 55.5 पर आ जाने के बाद अगस्त में यह 57.2 पर पहुंच गई (चार्ट III.27बी) । संमिश्र पीएमआई सूचकांक पहली तिमाही में 58.0 और दूसरी तिमाही में (जुलाई-अगस्त) में 57.4 था।

III. निष्कर्ष

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधि, आघात-सह बनी रही थी। उपभोक्ता आशावादिता और व्यावसायिक भावना में हुए सुधार से विवेकाधीन खर्च, संपर्क-गहन गतिविधियों की मांग और निवेश गतिविधियों में वृद्धि हुई। इसके आगे, खरीफ बुवाई के तहत अच्छी प्रगति, पर्याप्त जलाशय स्तर, पूंजीगत खर्च पर सरकार का निरंतर जोर, विनिर्माण में बेहतर क्षमता उपयोग, गैर-खाद्य ऋण में तेजी और घटते कोविड-19 संक्रमणों आदि की वजह से दूसरी छमाही में समग्र मांग और गतिविधि को सहयोग मिलना चाहिए। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक वित्तीय बाजारों का सख्त होना और वैश्विक आर्थिक मंदी, घरेलू आउटलुक के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करते हैं।

IV. वित्तीय बाज़ार और चलनिधि स्थितियां

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान, घरेलू वित्तीय बाजारों ने मौद्रिक नीति की अवस्थिति में परिवर्तन के साथ आसानी से अपने आपको व्यवस्थित कर लिया और वैश्विक वित्तीय बाजार की विपरीत स्थितियों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए गए नीति उपायों के प्रभाव-विस्तार (स्पिलओवर) के प्रति आघात सहनीयता को दर्शाया है। बाजार दरों में वृद्धि दर्ज की गई है और बैंक ऋणों के उठाव के स्तर में सुधार हुआ है। आगे भी, आरबीआई अपने चलनिधि प्रबंधन कार्यों के प्रति सतर्क, सावधान और मुस्तैद रहेगा और घरेलू वित्तीय बाजारों के संबंध में वैश्विक वित्तीय बाजारों की अस्थिरता के कारण उत्पन्न होने वाले स्पिलओवर को कम करने के लिए अपने पास उपलब्ध उपायों का उपयोग करेगा।

प्रस्तावना

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान, वैश्विक वित्तीय बाजारों को भू-राजनीतिक संघर्षों तथा तीव्र नीतिगत कार्रवाइयों एवं मुद्रास्फीति के बढ़ते हुए दबावों से निबटने के लिए अपनाए गए रुख के बीच उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। जैसे-जैसे वित्तीय स्थितियाँ कड़ी होती गईं बॉन्ड प्रतिफल कम होते गए और निवेशकों के बीच मंदी का भय बढ़ते जाने से उनका हौसला पस्त होने के कारण पहली छमाही में शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर मजबूती के साथ अपने प्रमुख वैश्विक समकक्षों के मुकाबले सितंबर के प्रारंभ तक 20 वर्ष के अब तक के सबसे उच्च स्तर पर बना रहा जिसमें फेड के फ्रंट-लोडेड उच्च दरों, मात्रात्मक सख्ती और बढ़ती हुई सुरक्षित जगह वाली मांग से उत्साहजनक वृद्धि हुई। इन गतिविधियों ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) से पोर्टफोलियो बहिर्वाह को गति दी और उनकी मुद्राओं पर तेज मूल्यह्रासकारी दबाव डाला, जिससे समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के प्रति जोखिम बहुत बढ़ गया।

IV.1 घरेलू वित्तीय बाजार

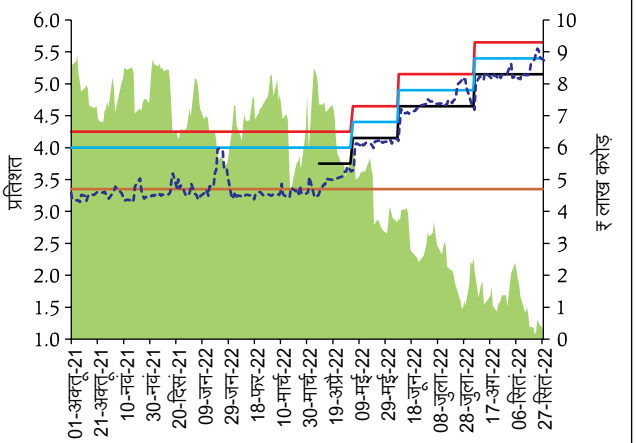
घरेलू वित्तीय बाजार को बार-बार के वैश्विक स्पिलओवर, विशेषतौर पर इक्विटी और विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) सेग्मेंट के स्पिलओवर ने प्रभावित किया। मुद्रा बाजार अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा, हालांकि, घरेलू रूप से मौद्रिक निभाव को वापस लेने के फलस्वरूप अकोमोडेशन की समाप्ति के प्रति ब्याज दरें सख्त हो गईं। इसके विपरीत, बॉन्ड प्रतिफल जून के मध्य के अपने उच्च स्तर से नीचे आया लेकिन बीच-बीच में सख्त हुआ।

IV.1.1 मुद्रा बाजार

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान मुद्रा बाजार दरों में मजबूती आई, जो आरबीआई द्वारा नीतिगत रेपो दर में वृद्धि और अधिशेष चलनिधि में कमी को दर्शाता है। 8 अप्रैल 2022 को नियत दर रिवर्स रेपो (एफआरआरआर) के 40 आधार अंक से अधिक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर की शुरुआत ने प्रारंभिक गति प्रदान की। वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (8 अप्रैल - 27 सितंबर) में औसतन, भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) ने 2 आधार अंक (बीपीएस) नीचे कारोबार किया जो एसडीएफ दर से नीचे था, जो वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही की तुलना में एफआरआरआर से 2 आधार अंक के नीचे था (चार्ट IV.1)। जुलाई के चौथे सप्ताह में और सितंबर के उत्तरार्ध में उच्चतर कर बहिर्वाह और सरकारी नकदी शेष के निर्माण के कारण अस्थायी चलनिधि की तंग स्थिति ने परिणामतः अस्थायी रूप से डब्ल्यूएसीआर को नीति रेपो दर से अधिक मज़बूत कर दिया था। परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामियों के माध्यम से चलनिधि उपलब्ध कराए जाने से अस्थायी चलनिधि तनाव कम हुआ।

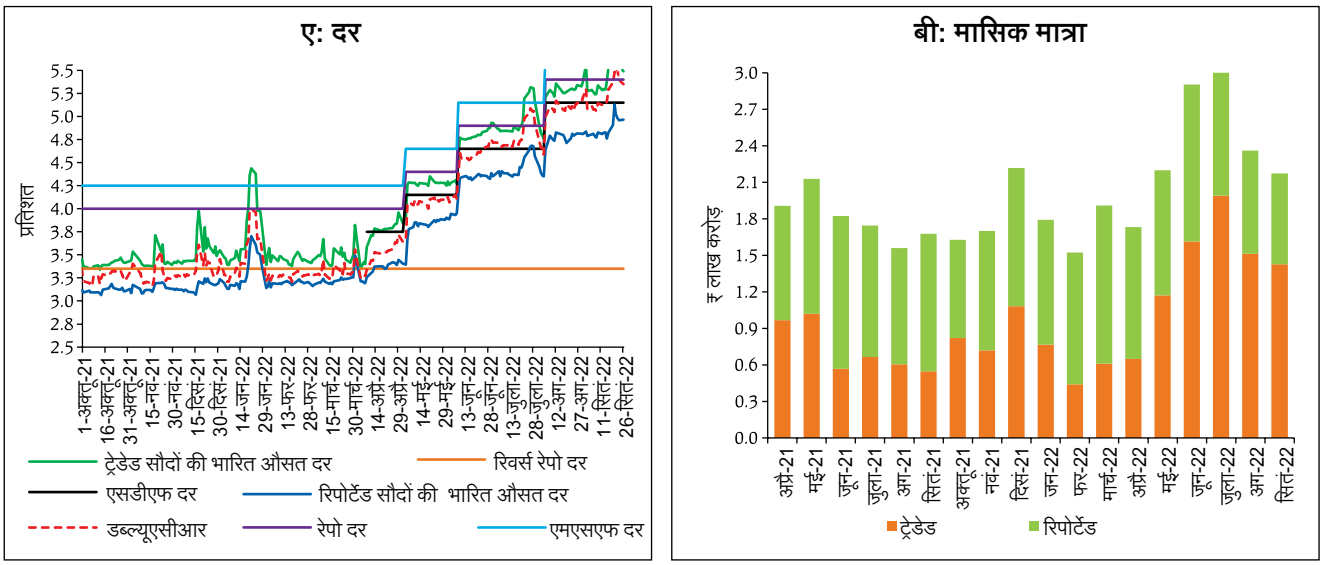
ओवरनाइट मांग मुद्रा सेग्मेंट में, ट्रेडेड लेनदेनों की भारित औसत दर (डब्ल्यूआर) एसडीएफ दर से 18 आधार अंक अधिक थी जबकि वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (8 अप्रैल -

चार्ट IV.1: चलनिधि, पॉलिसी कॉरीडोर तथा डब्ल्यूएसीआर



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई)।

चार्ट IV.2: मांग मुद्रा बाजार में ट्रेडेड और रिपोर्टेड सौदे – मात्रा और दर

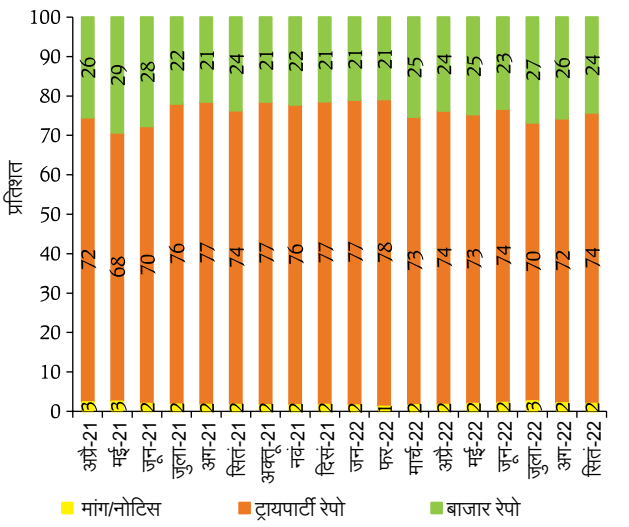


स्रोत: क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(सीसीआईएल); आरबीआई।

26 सितंबर) में रिपोर्ट किए गए लेनदेनों[1] के दौरान 30 आधार अंक से नीचे थी जो बाजार सेग्मेंटेशन को लघु सहकारी बैंकों के रूप में दर्शाती है- जो रिपोर्ट किए गए लेनदेनों में प्रमुख ऋणदाता हैं- बाजार बंद होने के समय कम दरों पर निधियां लाए (चार्ट IV.2ए)। ₹ 1.39 लाख करोड़ के कारोबार वाले लेनदेनों की औसत मासिक मात्रा रिपोर्ट किए गए खंड के ₹1.01 लाख करोड़ से अधिक थी (चार्ट IV.2बी)। सार्वजनिक क्षेत्र और विदेशी बैंकों की बढ़ी हुई भागीदारी के कारण कुल मांग मुद्रा बाजार की मात्रा में रिपोर्ट किए गए लेनदेनों की हिस्सेदारी मार्च 2022 में 68 प्रतिशत से सितंबर 2022 में घटकर लगभग 34 प्रतिशत रह गई।

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (सितंबर 27 तक) में गैर-संपार्श्विक मांग मुद्रा बाजार की हिस्सेदारी सहित मुद्रा बाजार गतिविधि संपार्श्विक सेग्मेंटों द्वारा 2.0 प्रतिशत के साथ हावी रही है। त्रिपक्षीय रेपो (टीआरईपीएस) की हिस्सेदारी एक साल पहले के 76 प्रतिशत से घटकर 73 प्रतिशत हो गई, साथ ही बाजार रेपो की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.3)। निवेशकों के मध्य, म्युच्युअल फंड (एमएफ) का हिस्सा - संपार्श्विक सेग्मेंट में प्रमुख ऋणदाता - बाजार रेपो 56 प्रतिशत से घटकर 46 प्रतिशत हो गया और यह आंशिक रूप से डेट म्युच्युअल फंड में कम अंतर्वाह के कारण हुआ। पहली छमाही में टीआरईपीएस में म्युच्युअल फंड (अगस्त तक) की हिस्सेदारी 72 प्रतिशत थी, हालांकि यह अपरिवर्तित रही। उधार वाले पक्ष में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की हिस्सेदारी टीआरईपीएस

चार्ट IV 3: ओवरनाइट मुद्रा बाज़ार मात्रा में शेयर



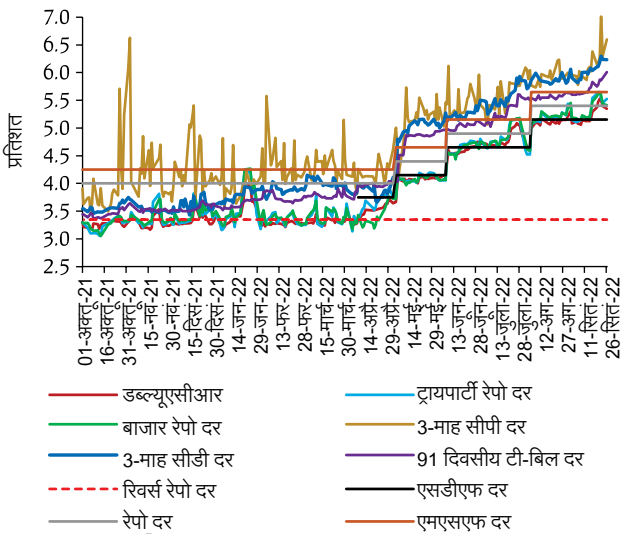
स्रोत: सीसीआईएल; आरबीआई।

[1] 'ट्रेडेड डील' सीधे एनडीएस-कॉल प्लेटफॉर्म पर बातचीत के आधार पर किए जाते हैं, जबकि 'रिपोर्टेड डील' ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) पर किए जाते हैं, जिनकी सूचना सौदे के लिए बातचीत के पूरा होने के बाद एनडीएस-कॉल प्लेटफॉर्म को दी जाती है।

में 64 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई और इसी अवधि में बाजार रेपो 16 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत हो गई।

3 महीने के टी-बिल (टीबी), जमाराशि प्रमाण पत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जैसे दीर्घावधि मुद्रा बाजार लिखतों पर ब्याज दरें 2022-23 की पहली छमाही के दौरान अधिक बढ़ीं। वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही के दौरान टी-बिल, सीडी और सीपी का स्प्रेड एफआरआरआर के ऊपर क्रमशः 26 आधार अंक, 38 आधार अंक और 88 आधार अंक था, जबकि इसकी तुलना में यह स्प्रेड 2022-23 की पहली छमाही में (8 अप्रैल - 26 सितंबर) एसडीएफ दर के ऊपर क्रमशः 51 आधार अंक, 72 आधार अंक और 87 आधार अंक रहा (चार्ट IV.4)।

चार्ट IV.4: मुद्रा बाज़ार दरें और पॉलिसी कॉरीडोर

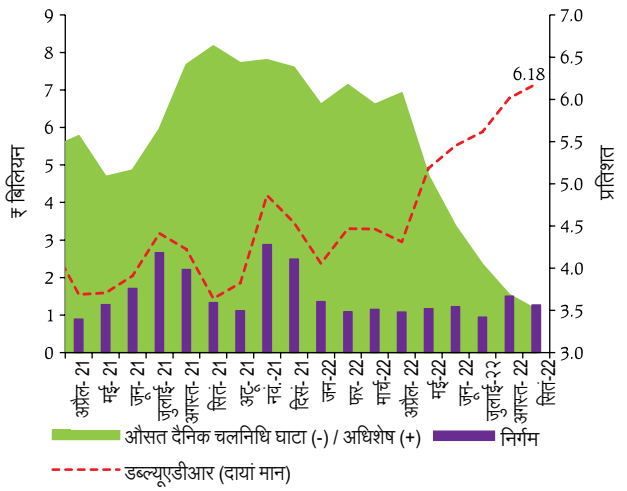


स्रोत: एफबीआईएल; और आरबीआई।

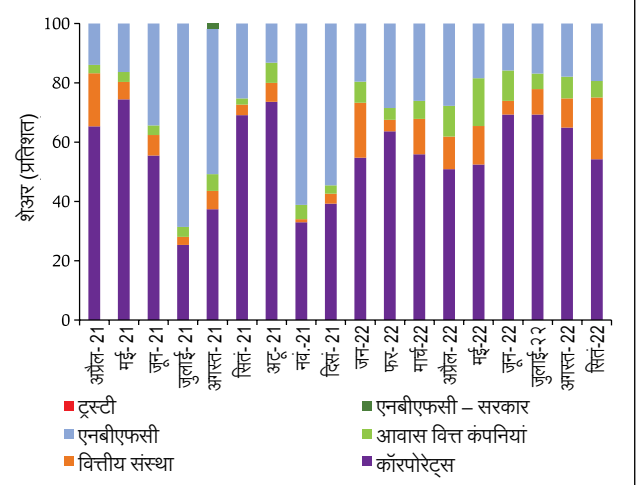
सीडी निर्गमों की मात्रा 2021-22 की दूसरी छमाही के 1.73 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 की पहली छमाही (23 सितंबर तक) में 2.96 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो ऋण उठाव में आई उत्साहवर्द्धक वृद्धि को पूरा करने के लिए बैंकों की निधियों की मांग को दर्शाती है। हालांकि, बैंक ऋण की मांग में सुधार के कारण सीपी जारी किए जाने के माध्यम से संसाधनों का जुटाने की मात्रा 2021-22 की दूसरी छमाही के 10.09 लाख करोड़ रुपये से घटकर 2022-23 की पहली छमाही (26 सितंबर तक) के दौरान 7.20 लाख करोड़ रुपये हो गयी (चार्ट IV.5ए)। सीपी निर्गमों की भारित औसत बट्टा दर (डब्ल्यूएडीआर) 2021-22 की दूसरी छमाही के 4.47 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 की पहली छमाही में 5.50 प्रतिशत हो गई। सीपी जारी करने में कॉरपोरेट्स की हिस्सेदारी 2021-22 की दूसरी छमाही के 53.3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 की पहली छमाही में 60.2 प्रतिशत हो गई जिससे वे सीपी के प्रमुख जारीकर्ता बने रहे (चार्ट IV.5बी)।

चार्ट IV.5: वाणिज्यिक पत्र का प्राथमिक निर्गम

ए: प्रणालीगत चलनिधि, निर्गम और डब्ल्यूएडीआर



बी: संस्थागत ब्यौरा



स्रोत: आरबीआई; सीसीआईएल-एफ-टीआरएसी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी IV.1: सीपी निर्गम की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

(₹ लाख करोड़)

अवधि	छ1:2021-22	छ2:2021-22	छ1:2022-23 (सितंबर 26 तक)
7- 30 दिन	4.13	4.14	0.69
31-90 दिन	3.12	3.30	3.93
91-180 दिन	2.05	1.82	1.84
181-365 दिन	0.80	0.83	0.74
कुल	10.11	10.09	7.20
बकाया (अवधि के अंत में)	3.71	3.52	4.33

स्रोत: सीसीआईएल; एफ-टीआरएसी; और आरबीआई।

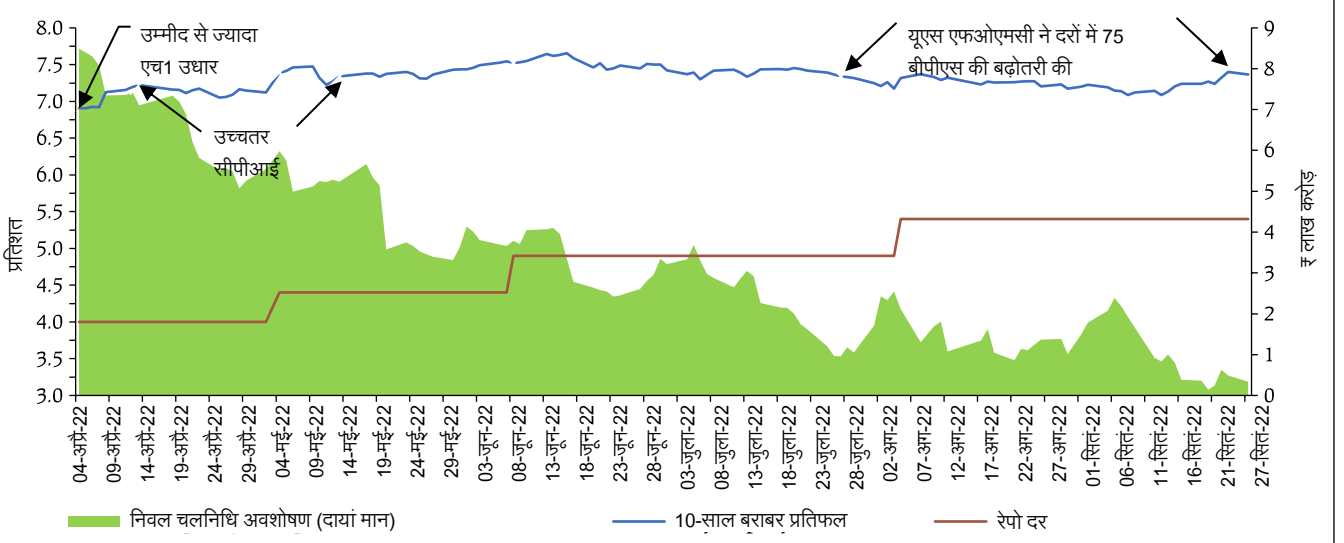
अधिकतर सीपी निर्गम 31-90 दिनों की परिपक्वता अवधि वाले खंड में थे (सारणी IV.1)। इस परिपक्वता अवधि वाले खंड में निर्गमों का डब्ल्यूएडीआर 2021-22 की दूसरी छमाही के 3.97 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 की पहली छमाही (26 सितंबर तक) में 5.45 प्रतिशत हो गया।

IV.1.2 सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान, जी-सेक प्रतिफल में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव दिखा (चार्ट IV.6)। पहली तिमाही के दौरान जेनेरिक 10-वर्षीय प्रतिफल में 64 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई जो (i) अमेरिकी प्रतिफल और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि (ii) वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वानुमान से अधिक उधार नीलामी कैलेंडर की घोषणा; (iii) मार्च और अप्रैल के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट अपेक्षा से अधिक होने और (iv) आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंकों की वृद्धि के साथ-साथ मई में एक असूचीबद्ध बैठक में रेपो दर में 40 आधार अंकों की वृद्धि के कारण थी (बॉक्स IV.1)।

दूसरी तिमाही (27 सितंबर तक) में, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, जून की तुलना में जुलाई में कम सीपीआई मुद्रास्फीति, अगस्त-सितंबर में निवल खरीददारों के रूप में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की वापसी और वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत के संभावित समावेश की बढ़ती उम्मीदों के कारण, बेंचमार्क प्रतिफल में 20 आधार अंकों की कमी आई। इन कारकों को दर्शाते हुए, 10-वर्षीय प्रतिफल 7.66 प्रतिशत (16 जून, 2022 को) के अपने शीर्ष स्तर से कम होकर 13 सितंबर को 7.09 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गया; हालांकि 27 सितंबर, 2022 को यह बढ़कर 7.30 प्रतिशत हो गया, जो उच्च वैश्विक बॉण्ड प्रतिफल को दर्शाता है।

चार्ट IV.6: 10-वर्षीय सामान्य जी-सेक प्रतिफल, रेपो दर और चलनिधि स्थितियाँ



स्रोत: आरबीआई और एफबीआईएल।

बॉक्स IV.1 : मौद्रिक नीति अप्रत्याशाएँ और वित्तीय बाजार

ऐसा माना जाता है कि सक्षम वित्तीय बाजार नीतिगत कार्रवाइयों के प्रत्याशित घटक के अनुरूप कीमतों को समायोजित कर लेते हैं। बाजार ब्याज दरों पर नीतिगत घोषणाओं के असली प्रभाव का आकलन करने के लिए, मौद्रिक नीति के प्रत्याशित घटक से अप्रत्याशित घटक (बाजार जिसका पूर्वानुमान लगाने में सक्षम न रहा हो) को पृथक करना आवश्यक है (कुट्टनर, 2001)। नीतिगत अप्रत्याशित घटकों की पहचान करने के लिए, वित्तीय बाजार के उच्च आवृत्ति वाले चर घटकों यथा- ओवरनाइट इंडेक्सड स्वैप (ओआईएस), फ्युचर्स और स्टॉक कीमतों का उपयोग किया जा सकता है (गर्टलर और कराडी, 2015)।

वैश्विक साक्ष्यों के अनुरूप, ऐसा पाया गया है कि भारत में नीतिगत दर के भावी पथ की बाजार प्रत्याशाओं को ओआईएस विश्वसनीय तरीके से पकड़ता है। नीतिगत घोषणा के दिन ओआईएस दर में 2-माह के अंतर (द्विमासिक मौद्रिक नीति चक्र को देखते हुए) का प्रयोग कर, मौद्रिक नीति संबंधी अप्रत्याशाओं की पहचान की जाती है, वहीं शेष को प्रत्याशित नीतिगत परिवर्तन के रूप में मान लिया जाता है। नीतिगत घोषणा के दिन के आसपास ओआईएस दर के समयान्तराल (विंडो) को कम करने पर, ओआईएस दर में आए परिवर्तन का श्रेय यथोचित रूप से मौद्रिक नीति की अप्रत्याशाओं को दिया जा सकता है। नीतिगत घोषणाओं के दिन, 2-माह पर्यंत ओआईएस दर में आए परिवर्तन में, केंद्रीय बैंक के भावी मार्गदर्शन द्वारा प्रदत्त प्रत्याशित भावी नीतिगत दरों के पथ में भी कोई अप्रत्याशा निहित हो सकती है। नीतिगत अप्रत्याशा की पहचान, नीतिगत दर/मौद्रिक नीति निर्णय में परिवर्तन को दो भागों में विभक्त करके की जा सकती है- प्रत्याशित और अप्रत्याशित नीतिगत परिवर्तन (समी.1) (अहोकपोसी एवं अन्य, 2020) – जो निम्नानुसार है:

$$\Delta i_t = (i_t - i_{t-1}) = (i_t - E_{t-1} i_t) + (E_{t-1} i_t - i_{t-1}) = \Delta i_t^u + \Delta i_t^a \quad \dots (1),$$

जहां *i* नीतिगत दर है, *t* समय सूचकांक है और $E_{t-1} i_t$ समय *t* पर नीतिगत दर की समय *t-1* पर बाजार प्रत्याशा है। Δi_t नीतिगत दर में परिवर्तन है जिसे अप्रत्याशित घटक (Δi_t^u) और प्रत्याशित अंश (Δi_t^a) में द्विभाजित किया जाता है। इस अवधारणा का परीक्षण कि सिर्फ अप्रत्याशित निर्णयों/अप्रत्याशाओं का बाजार दरों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है, एक घटना अध्ययन (ईएस) फ्रेमवर्क[2] में, प्रमुख बाज़ारों (91-दिवसीय खजाना बिल, 10-वर्षीय जी-सेक और एएए श्रेणी के 5-वर्षीय बॉण्ड) के लिए किया जाता है और इसमें निम्नलिखित विनिर्देशों का उपयोग किया जाता है:

$$\Delta m_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta i_t^u + \alpha_2 \Delta i_t^a + \alpha_3 D_1 + \alpha_4 D_2 + \alpha_5 D_3 + \alpha_6 D_4 + \alpha_7 \Delta Brent_t + \alpha_8 \Delta US\ market\ rates_{t-1} + \varepsilon_t \quad \dots \quad (2)$$

जहां Δm_t बाजार के ब्याज दरों में परिवर्तन (आश्रित चर) है; Δi_t^u अप्रत्याशित नीतिगत परिवर्तन/मौद्रिक नीति अप्रत्याशा है; Δi_t^a नीतिगत परिवर्तन है; D_1 से D_4 प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों को मापने के लिए प्रत्युक्त प्रतिरूप (डमी) हैं[3]; $\Delta Brent_t$ ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में परिवर्तन दर्शाता है; और $\Delta US\ market\ rates_{t-1}$ नीतिगत घोषणा के एक दिन पहले, यूएस दरों में होने वाले तदनुरूपी परिवर्तनों को दर्शाता है।

प्रायोगिक विश्लेषण इंगित करता है कि 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों और 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्डों के लिए प्रत्याशित नीतिगत परिवर्तन उल्लेखनीय नहीं हैं- इन प्रतिभूतियों के प्रतिफलों पर केवल अप्रत्याशित घटक का प्रभाव पड़ता है (सारणी IV.1.1)। इसका संचयी प्रभाव पहले दिन के प्रभाव की तुलना में दूसरे दिन के अंत में ज्यादा (और

सारणी IV.1.1: वित्तीय बाजारों पर वित्तीय प्रभाव

चरांक	91-दिवसीय टी-बिल		10-वर्षीय जी-सेक		एएए 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉण्ड	
	1-दिवसीय प्रभाव	2-दिवसीय प्रभाव	1-दिवसीय प्रभाव	2-दिवसीय प्रभाव	1-दिवसीय प्रभाव	2-दिवसीय प्रभाव
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अप्रत्याशित	0.721*** (0.153)	1.094*** (0.121)	0.284*** (0.072)	0.792*** (0.224)	0.875*** (0.196)	1.060*** (0.221)
प्रत्याशित	0.216*** (0.053)	0.211*** (0.039)	0.025 (0.033)	0.005 (0.067)	0.011 (0.033)	0.001 (0.071)
D_1	0.119*** (0.012)	0.240*** (0.013)	0.101*** (0.008)	0.030 (0.022)	0.076*** (0.012)	0.095*** (0.022)
D_2	-0.599*** (0.047)	-0.434*** (0.061)	0.049 (0.029)	-0.057 (0.067)	-0.141*** (0.020)	-0.069** (0.032)
D_3	0.139*** (0.013)	0.145*** (0.037)	0.052*** (0.016)	0.169*** (0.030)	0.248*** (0.018)	0.260*** (0.017)
D_4	-0.172*** (0.054)	-0.262*** (0.038)	0.024 (0.035)	0.023 (0.084)	0.056 (0.053)	0.018 (0.087)
ब्रेंट कीमतों में परिवर्तन	-0.010 (0.009)	-0.024*** (0.008)	0.000 (0.008)	0.000 (0.012)	0.001 (0.009)	0.010 (0.011)
यूएस 91-दिवसीय टी-बिल में परिवर्तन, लैग 1	0.063 (0.336)	-0.405 (0.330)	-	-	-	-
यूएस 5-वर्षीय जी-सेक में परिवर्तन, लैग 1	-	-	-	-	0.161 (0.304)	-0.070 (0.272)
यूएस 10-वर्षीय जी-सेक में परिवर्तन, लैग 1	-	-	0.258 (0.160)	-0.127 (0.373)	-	-
स्थिरांक	-0.036*** (0.011)	-0.027** (0.010)	-0.011* (0.006)	-0.006 (0.015)	-0.017 (0.010)	-0.018 (0.013)
प्रेक्षण	37	37	37	37	37	37
समयोजति आर[2]	0.861	0.896	0.310	0.518	0.698	0.626
एलएम टेस्ट (पी-वैल्यू)	0.69	0.81	0.03	0.10	0.16	0.03

टिप्पणी: कोष्टक में दिए गए आंकड़े नीवे-वेस्ट स्टैंडर्ड एरर हैं (हेट्रोसेडास्टिसिटी और ऑटोकोरिलेशन के लिए संशोधित)
***, **, * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्ता के स्तर दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

[2] नमूना अवधि में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) व्यवस्था (अक्तूबर 2016 - अगस्त 2022) शामिल है।

[3] D_1 6 अप्रैल, 2017 की नीति बैठक के लिए डमी को संदर्भित करता है जब आरबीआई ने एलएएफ कॉरिडोर के दायरे को 100 बीपीएस से 50 बीपीएस तक सीमित कर दिया था; D_2 27 मार्च, 2020 की बैठक के लिए डमी को संदर्भित करता है जब महामारी के प्रकोप के बाद एक ऑफ-साइकिल बैठक के माध्यम से नीतिगत उपायों की घोषणा की गई थी; D_3 8 अप्रैल, 2022 की बैठक के लिए डमी को संदर्भित करता है जब आरबीआई ने एसडीएफ की स्थापना की थी; D_4 4 मई, 2022 को एक ऑफ-साइकिल बैठक के लिए डमी को संदर्भित करता है जब आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में 40 बीपीएस और सीआरआर में 50 बीपीएस की वृद्धि की और घोषणा की थी।

उल्लेखनीय) रहता है, और यह दर्शाता है कि बाजार नीतिगत अप्रत्याशाओं को समाहित करने में समय लेते हैं। खजाना बिलों के मामले में, प्रत्याशित और अप्रत्याशित नीतिगत परिवर्तन- दोनों मायने रखते हैं, लेकिन अप्रत्याशित घटक ही प्रमुख प्रेरक होता है। समग्रत:, ऐसा पाया गया है कि भारत के मुद्रा और बॉण्ड बाजार की दरें मुख्य रूप से नीतिगत अप्रत्याशाओं से प्रभावित होती हैं, जो सक्षम बाजार की धारणा के अनुरूप ही है।

संदर्भ:

कुट्टनर, के. एन. (2001), "मौद्रिक नीति अप्रत्याशाएं और ब्याज दरें: फेड फंड फ्यूचर्स बाजारों से साक्ष्य", जर्नल ऑफ मोनेटरी इकॉनॉमिक्स, वॉल्यूम. 47, अंक 10, पीपी. 523-544

गर्टलर, एम., और कराडी पी. (2015), "मौद्रिक नीति अप्रत्याशाएं, क्रेडिट लागत, और आर्थिक गतिविधि", अमेरिकन इकॉनॉमिक जर्नल: मैक्रोइकॉनॉमिक्स, वॉल्यूम 7(1), पीपी. 44-76

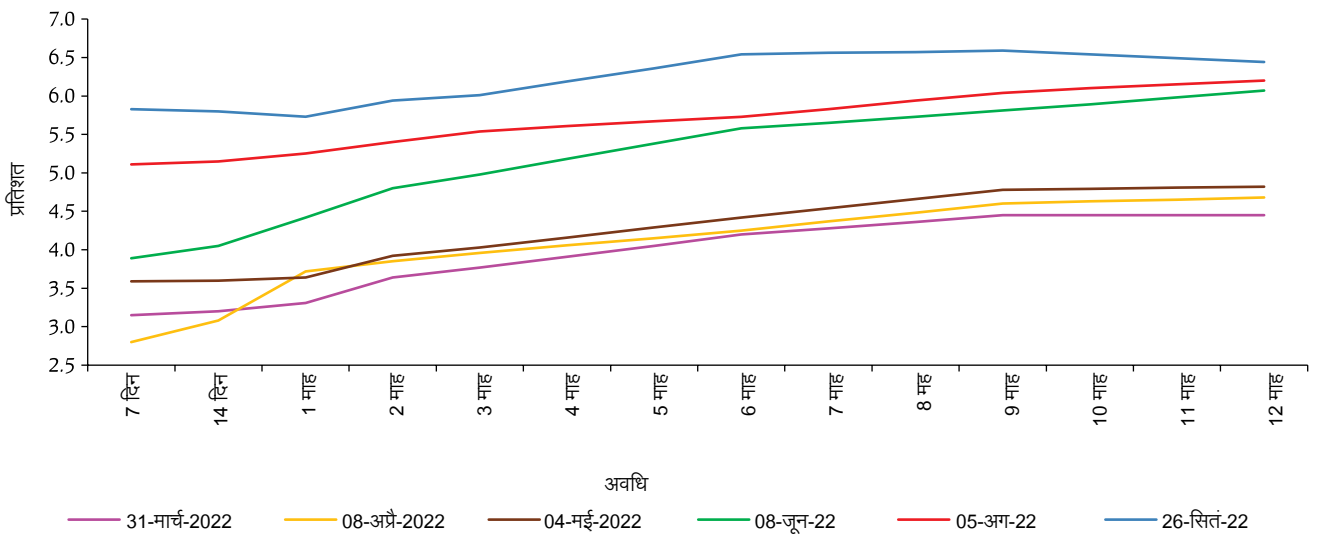
अहोकपोसी, सी., इस्नवांगसिह, ए., नाओज, एम.एस., और यान, टी. (2020), " उभरती अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति संचार का प्रभाव: इंडोनेशिया का मामला", आईएमएफ वर्किंग पेपर, डब्ल्यूपी/20/109

पॉलिसी रेपो दर में वृद्धि और एसडीएफ की शुरुआत से तालमेल बिठाते हुए, टी-बिलों पर प्रतिफल सभी अवधियों में मजबूत हुए (चार्ट IV.7)।

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (सितंबर 26 तक) में जी-सेक और टी-बिल दोनों में औसत लेन-देन की मात्रा में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़ोतरी हुई(चार्ट IV.8)। जी-सेक और टी-बिल के भारित औसत प्रतिफल की व्यापारित परिपक्वता में क्रमश: 95 आधार अंक और 144 आधार अंक की बढ़त हुई ।

प्रतिफल वक्र के उतार-चढ़ाव की गतिशीलता को उसके स्तर,ढलान और वक्रता[4] से लिया गया है। जबकि नीति में सख्ती के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अल्पावधि दरों की अधिक बढ़ोत्तरी से वर्ष 2022- 23 की पहली छमाही (सितंबर 26 तक) के दौरान प्रतिफल का औसत स्तर 64 आधार अंक बढ़ा और ढलान 206 आधार अंक समतल हो गया (चार्ट IV.9)। इसके साथ, वक्रता में स्पष्ट रूप से 190 आधार अंक की गिरावट आई जो वक्र के उभार में कमी का संकेत देती है क्योंकि

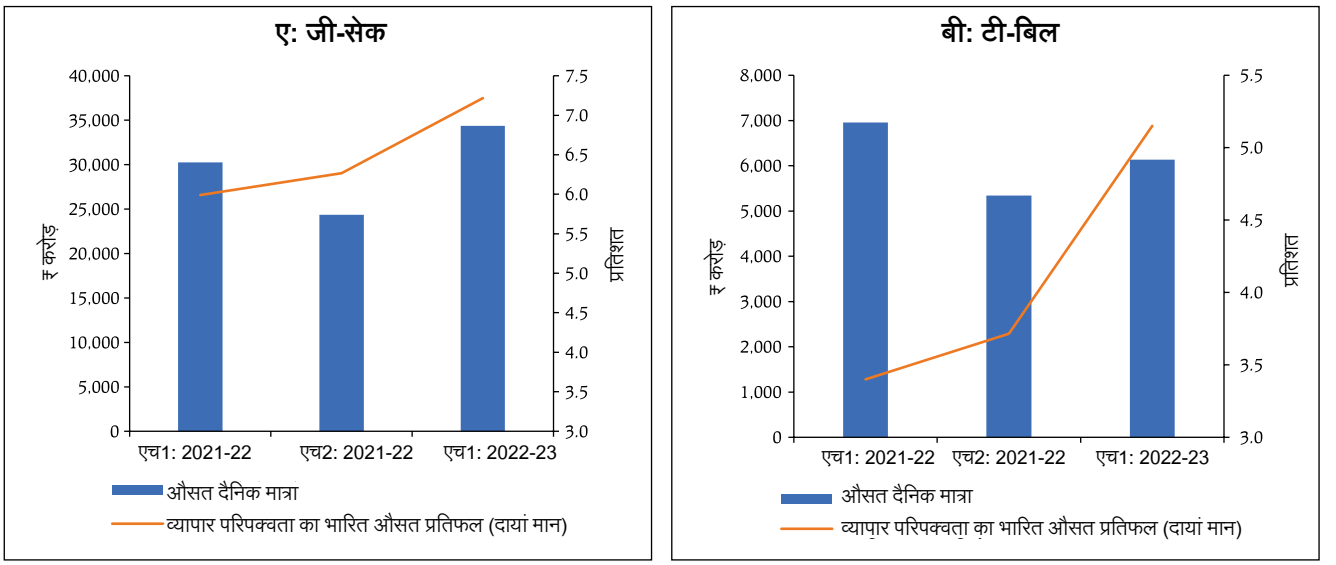
चार्ट IV.7: एफबीआईएल: टी-बिल बेंचमार्क (परिपक्वता पर प्रतिफल)



स्रोत: एफबीआईएल।

[4] यह स्तर एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित 30 साल तक की सभी अवधि के समान प्रतिफल का औसत है और ढलान (मीयादी स्प्रेड) 3 महीने और 30 साल की परिपक्वता के समान प्रतिफल में अंतर है। वक्रता की गणना 14 साल के प्रतिफल के दोगुने रूप में से 30 साल और 3-महीने के प्रतिफल के योग को घटाकर की जाती है।

चार्ट IV.8: व्यापार मात्रा और प्रतिफल

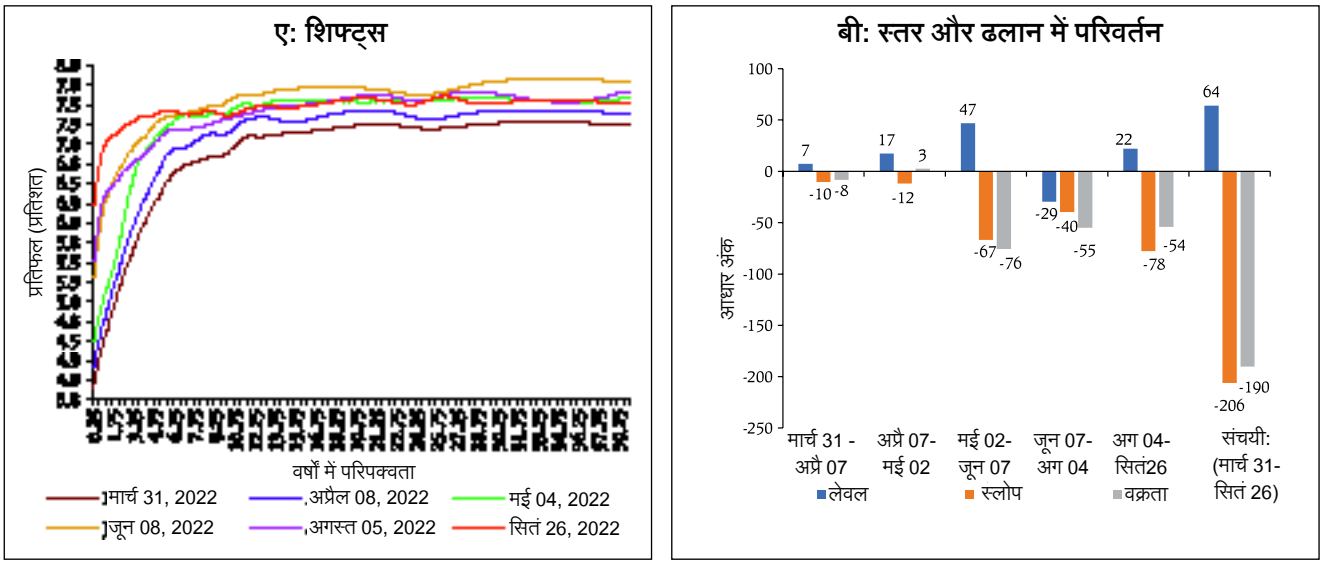


स्रोत: सीसीआईएल और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

वक्र के मध्य-खंड में वर्धित प्रतिफल छोटे और लंबे खंडों में प्रतिफल की तुलना में कम ही था। भारतीय संदर्भ में, एई के विपरीत, भविष्य के समष्टि आर्थिक परिणामों पर ढलान[5] की तुलना में प्रतिफल वक्र के स्तर और वक्रता में अधिक जानकारी उपलब्ध है।

ऋण समेकन को सुविधाजनक बनाने के लिए, वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (27 सितंबर, 2022 तक) के दौरान केंद्र सरकार की ओर से रिज़र्व बैंक द्वारा कुल ₹ 56,103 करोड़ की छह स्विच नीलामियां आयोजित की गई। सरकारी प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) मार्च

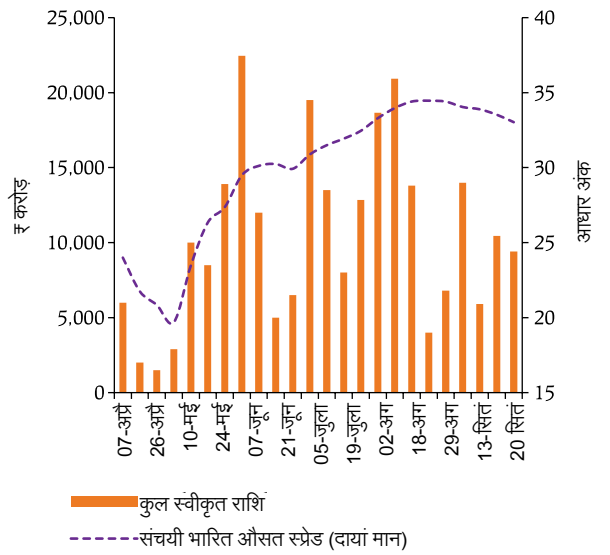
चार्ट IV.9: जी-सेक प्रतिफल वक्र



स्रोत: एफबीआईएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[5] पात्रा, एमडी, जॉइस, जे, कुशवाहा, के.एम, और आई. भट्टाचार्य (2022)। व्हाट इज यील्ड कर्व टेलिंग अस एबाउट द इकॉनॉमी ? भारतीय रिज़र्व बैंक का बुलेटिन, जून।

चार्ट IV.10: एसजीएस – जुटाई गई राशि और स्प्रेड



स्रोत: आरबीआई।

2022 के अंत में 11.71 वर्ष से बढ़कर 27 सितंबर 2022 को 11.94 वर्ष हो गई। पहली छमाही (27 सितंबर तक) के दौरान भारित औसत कूपन (डब्ल्यूएसी) का प्रतिशत 7.15 था, जो मार्च 2022 के अंत में 7.11 प्रतिशत से कुछ अधिक था।

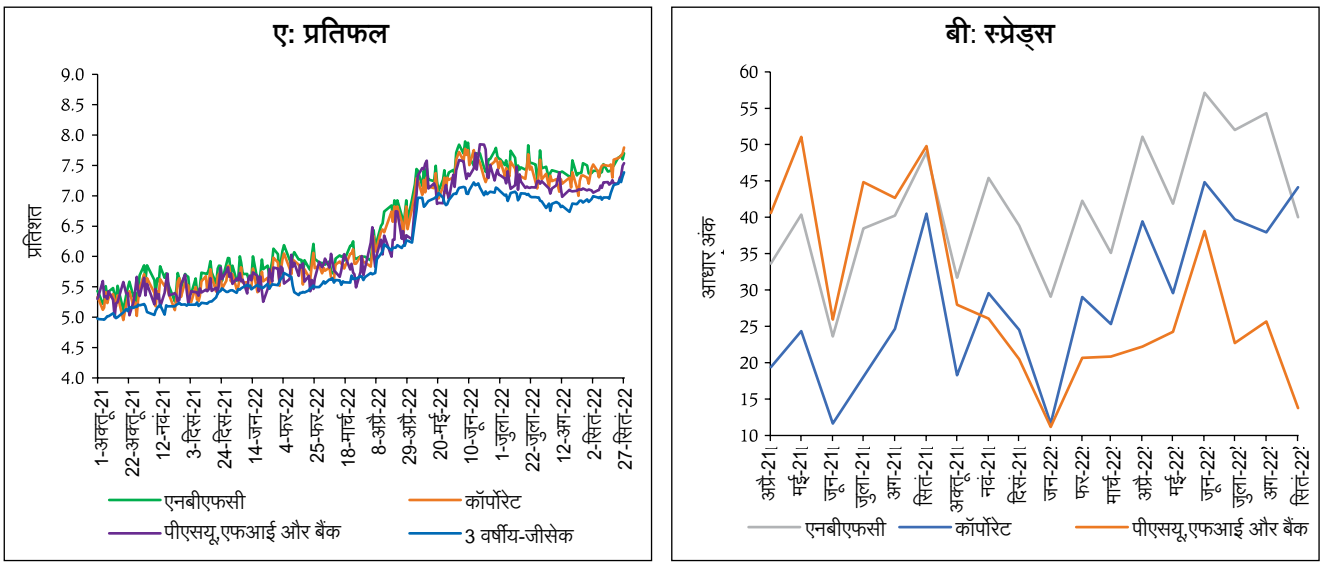
वर्ष 2022-23 की पहली छमाही(27 सितंबर तक) में तुलनीय परिपक्वताओं की जी-सेक प्रतिफल पर राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) पर कट-ऑफ प्रतिफल का भारित औसत स्प्रेड 32 आधार अंक था (चार्ट IV.10)। वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में 4 आधार अंक) में 10 साल की अवधि(नए निर्गम) की प्रतिभूतियों पर औसत अंतर-राज्य स्प्रेड 3 आधार अंक था।

IV.1.3 कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार

पहली छमाही में कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल, जी-सेक प्रतिफल का अनुसरण करती हुई बढ़ी। वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (27 सितंबर तक) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और कॉरपोरेट्स द्वारा जारी एएए-श्रेणीकृत 3-वर्ष के बॉण्ड में औसत प्रतिफल क्रमशः 156 आधार अंक (7.52 प्रतिशत) और 170 आधार अंक (7.56 प्रतिशत) बढ़ गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों द्वारा जारी निर्गमों पर प्रतिफल 143 आधार अंक से बढ़कर 7.25 प्रतिशत हो गए(चार्ट IV.11ए)। औसत जोखिम प्रीमियम (3 साल के जी-सेक प्रतिफल में स्प्रेड द्वारा मापित) एनबीएफसी के लिए 35 आधार अंक से बढ़कर 41 आधार अंक हो गया, कॉर्पोरेट्स के लिए 25 आधार अंक से बढ़कर 45 आधार अंक, जबकि पीएसयू, एफआई और बैंकों के लिए यह 21 आधार अंक से घटकर 14 आधार अंक हो गया (चार्ट IV.11बी)।

अन्य अवधि के दौरान (*यद्यपि* लंबे खंडों में अधिक) और रेटिंग स्पेक्ट्रम में जोखिम प्रीमिया में वृद्धि देखी गई थी (सारणी IV.2)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आईसीआईसीआई

चार्ट IV.11: एएए- श्रेणीकृत 3-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और स्प्रेड: क्षेत्र-वार



स्रोत: फिक्स इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्डा)

सारणी IV.2: वित्तीय बाज़ार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज़ दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम-रहित दर से अधिक)		
	मार्च 2022	सितं 2022	परिवर्तन (बीपीएस में)	मार्च 2022	सितं 2022	परिवर्तन (बीपीएस में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉर्पोरेट बॉण्डस						
(i) एएए (1-वर्षीय)	5.03	6.84	181	28	13	-15
(ii) एएए (3-वर्षीय)	5.86	7.56	170	25	45	20
(iii) एएए (5-वर्षीय)	6.43	7.50	107	-1	22	23
(iv) एए (3-वर्षीय)	6.57	8.31	174	96	120	24
(v) बीबीबी- माइनस (3-वर्षीय)	10.24	11.97	173	463	486	23

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है। डेटा 27 सितंबर 2022 तक है।
स्रोत: एफआईएमएमडीए (फिम्डा)।

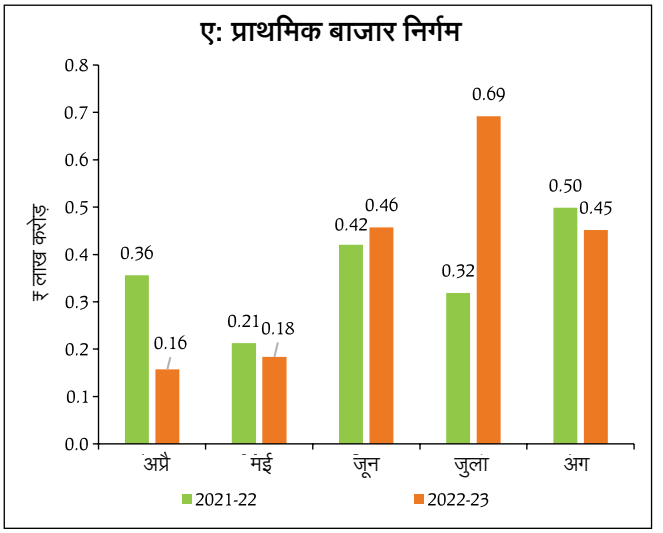
बैंक के विदेशों में पेपर ट्रेडिंग के लिए 3 साल के क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) स्प्रेड में वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (27 सितंबर 2022 तक) में क्रमशः 32 और 33 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई।

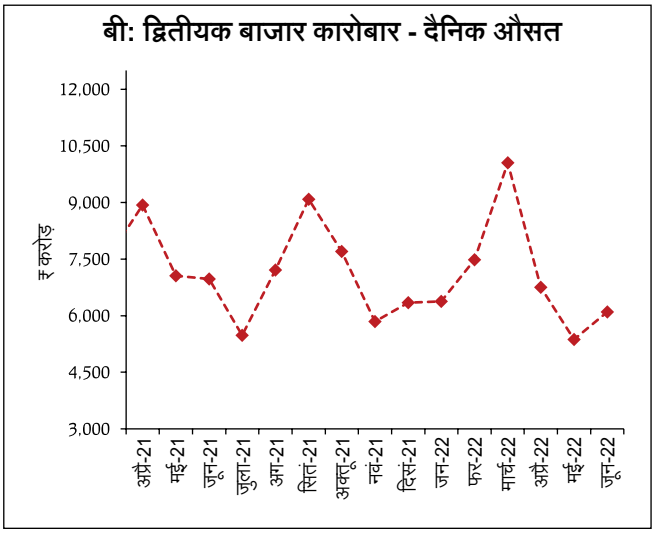
प्राथमिक बाजार में कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गम वर्ष 2021-22 की इसी अवधि के दौरान ₹1.81 लाख करोड़ से बढ़कर पहली छमाही (अगस्त 2022 तक) के दौरान ₹1.94 लाख करोड़ हो गया (चार्ट IV.12 ए), जो 2021-22 की पहली छमाही में विदेशों में जुटाए गए ₹55,152 करोड़ रुपये की तुलना में विदेशी निर्गमों के अभाव की भरपाई करते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार (98.4 प्रतिशत) में लगभग संपूर्ण संसाधन निजी नियोजन के माध्यम से जुटाए गए। कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा बकाया निवेश मार्च के अंत में ₹1.21 लाख करोड़ से घटकर 27 सितंबर 2022 को ₹1.16 लाख करोड़ हो गया, जिससे अनुमोदित सीमा का उपयोग 19.9 प्रतिशत से घटकर 18.3 प्रतिशत हो गया। पहली तिमाही के दौरान द्वितीयक बाजार में दैनिक औसत व्यापार की मात्रा ₹6,054 करोड़ हो गई जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20 प्रतिशत कम थी (चार्ट IV.12)।

IV.1.4 इक्विटी बाजार

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में घरेलू इक्विटी बाजार में लघु घाटा हुआ जिससे यह अधिकांश वैश्विक समकक्षों (चार्ट IV.13ए) से अधिक आघातसहनीय बना रहा। पण्य कीमतों में गिरावट, मानसून के अच्छे होने, कंपनियों के अच्छे आय परिणामों और एफपीआई प्रवाह की वापसी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा जिससे बेंचमार्क सूचकांकों ने जून 2022 में पण्यों में दर्ज अपने कई महीने के निचले स्तर से उछाल दर्शाया है। यद्यपि, सितंबर 2022 में यूएस फेड के सख्त रुख के साथ नीतिगत दर में 75 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी से वैश्विक इक्विटी बाजार में बिकवाली हुई। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 2022-23 की पहली छमाही

चार्ट IV.12: कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार गतिविधि

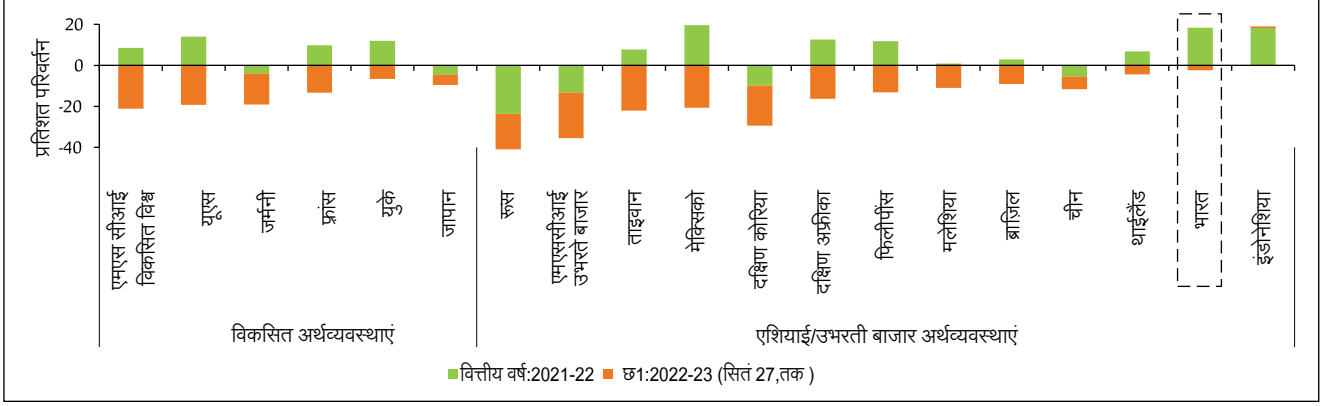




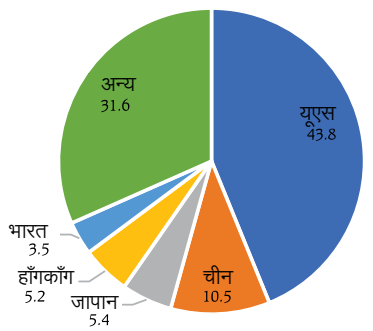
स्रोत: सेबी।

चार्ट IV.13: शेयर बाजार का कार्यनिष्पादन

ए: वैश्विक इक्विटी बाजार कार्यनिष्पादन



बी: विश्व बाजार पूंजीकरण में वैश्विक इक्विटी बाजारों का हिस्सा (प्रतिशत)



सी: भारत वीआईएक्स

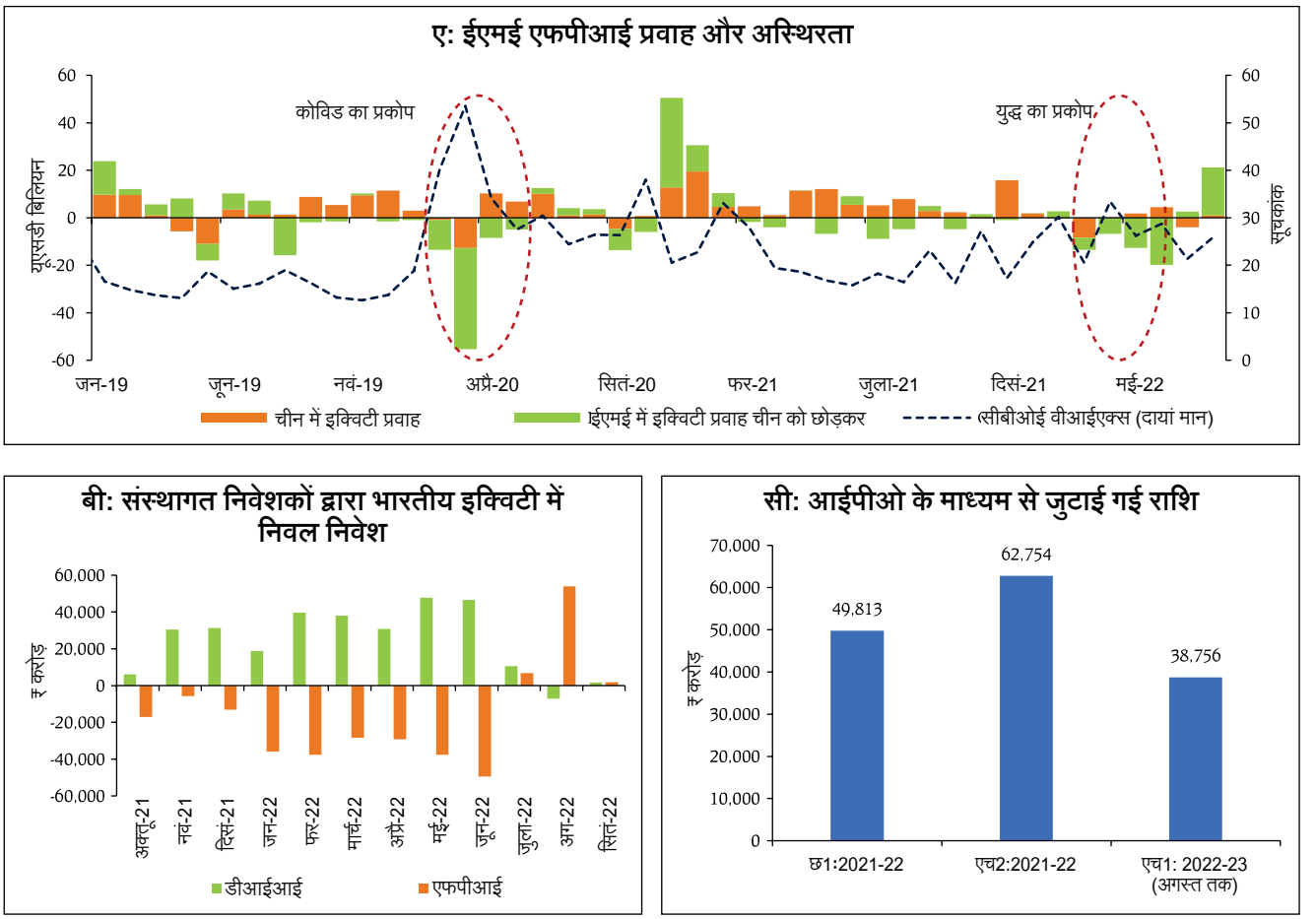


स्रोत: ब्लूमबर्ग।

(27 सितंबर 2022 तक) में 2.4 प्रतिशत घटकर 57108 पर बंद हुआ। कुल विश्व बाजार पूंजीकरण में भारतीय इक्विटी का योगदान 3.5 प्रतिशत है, जो विश्व में पांचवां सबसे बड़ा है (चार्ट IV.13बी)। इक्विटी कीमतों में उछाल के साथ बाजार की अस्थिरता में कमी आई है। इंडिया वीआईएक्स - जो निफ्टी 50 की अल्पकालिक अपेक्षित अस्थिरता को कैप्चर करता है - 24 फरवरी 2022 के 32.0 के अपने 20 महीने के उच्च स्तर से गिरकर 27 सितंबर 2022 को 21.6 हो गया (चार्ट IV.13 सी)।

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के तेजी से सामान्यीकरण के बीच ईएमई को 2022 में परिसंपत्ति वर्ग के रूप में एफपीआई से बिकवाली का दवाब झेलना पड़ा (चार्ट IV.14ए)। भारत में लगातार नौ महीनों (अक्तूबर 2021-जून 2022) तक इक्विटी बाजारों में बिकवाली देखी गई, जो 2000 के बाद से बिकवाली का सबसे लंबा दौर है। हालांकि, विदेशी निवेशकों ने जुलाई में कॉरपोरेट आय में सुधार और मजबूत वृहद बुनियादी सुविधाओं से आकर्षित होकर घरेलू इक्विटी बाजार में वापसी की। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने लगातार 17 महीनों (मार्च 2021-जुलाई 2022) तक एफपीआई बिकवाली के दबाव को अवशोषित करते हुए इक्विटी बाजार में भारी खरीदारी की, और बाजार को वैश्विक और अन्य उभरते बाजार साथियों से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाया। वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में एफपीआई 58438 करोड़ रुपये के निवल विक्रेता रहे, जबकि डीआईआई 1.3 लाख करोड़ रुपये के निवल खरीददार रहे (चार्ट IV.14बी)। इसके अलावा, अस्थिर परिस्थितियों के कारण घरेलू प्राथमिक बाजार में गतिविधियां वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (मेगा एलआईसी आईपीओ को छोड़कर) में सुस्त रहीं (चार्ट IV.14सी) ।

चार्ट IV.14: भारत में ईएमई प्रवाह, संस्थागत निवेश और आईपीओ जारी करना



स्रोत: इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल फाइनेंस; ब्लूमबर्ग, केपिटालाइन; एनएसडीएल; और सेबी।

IV.1.5. विदेशी मुद्रा बाजार

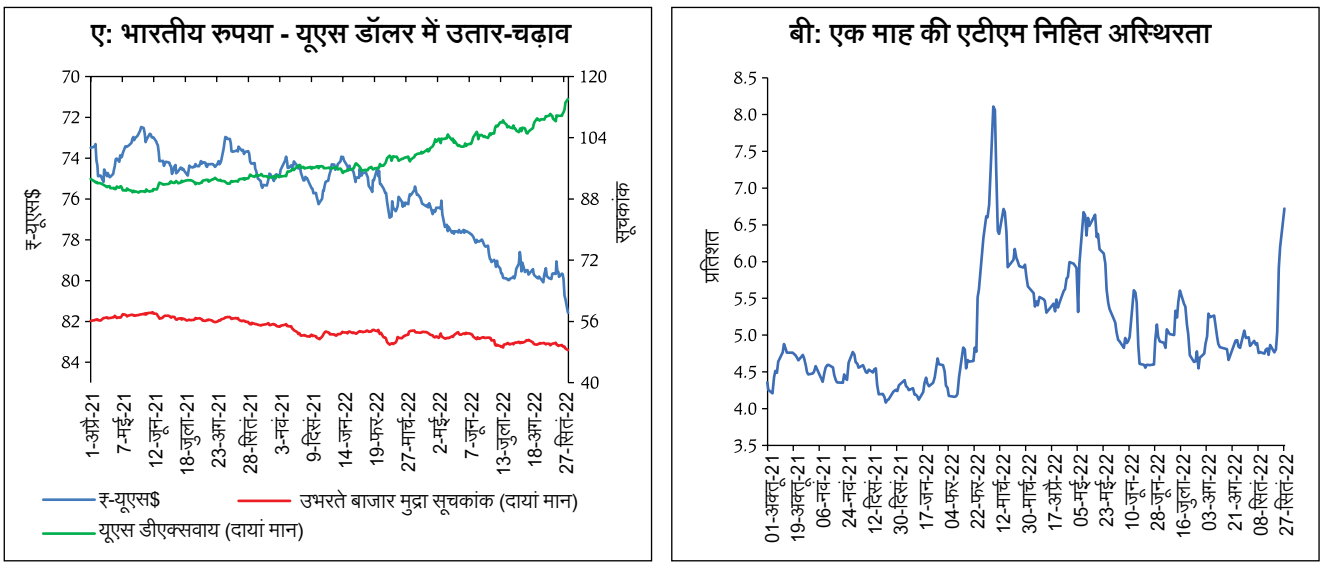
भारतीय रुपये (आईएनआर) ने वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) के मुकाबले मूल्यह्रास की संभावनाओं के साथ कारोबार किया (चार्ट IV.15ए)। वैश्विक कारकों को प्रतिबिंबित करते हुए, भारतीय रुपये में अस्थिरता[6] – मुद्रा(एटीएम) विकल्प द्वारा एक महीने पर मापी गई निहित अस्थिरता – पहली छमाही के दौरान औसतन 5.25 प्रतिशत तक बढ़ गई (27 सितंबर तक) जो वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही के दौरान 4.8 प्रतिशत थी (चार्ट IV.15 बी)। आरबीआई द्वारा बाजार में हस्तक्षेप के कारण अस्थिरता को नियंत्रित किया गया और भारतीय रुपये के सुव्यवस्थित चलन को सुनिश्चित किया गया। रिज़र्व बैंक ने समग्र समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता[7] सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूंजी प्रवाह बढ़ाने के लिए 6 जुलाई, 2022 को कई उपायों की घोषणा की।

वर्ष 2022-23 (27 सितंबर तक) के दौरान, अमेरिकी डॉलर में प्रमुख मुद्राओं की बास्केट के मुकाबले 16.1 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 6.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कई एई और ईएमई समकक्षों की तुलना में बेहतर है (चार्ट IV.16)। मजबूत समष्टि आर्थिक

[6] निहित अस्थिरता एक आप्शंस के मूल्य से ली गई है और भविष्य में मुद्रा की अस्थिरता के बारे में बाजारों की अपेक्षाओं को दर्शाती है।

[7] इन उपायों में वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) और एनआरई सावधि जमाओं पर सीआरआर और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से अस्थायी छूट, बैंकों को अस्थायी रूप से 7 जुलाई, 2022 से प्रभावी ब्याज दरों पर मौजूदा विनियमों के संदर्भ के बिना नए एफसीएनआर (बी) और एनआरई जमा जुटाने की अनुमति देना, बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए स्वचालित मार्ग के तहत सीमा में वृद्धि और ऋण बाजार में एफपीआई निवेश मानदंडों और अधिकृत डीलर श्रेणी 1(एडी कैट -1) बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा उधार से संबंधित छूट शामिल है।

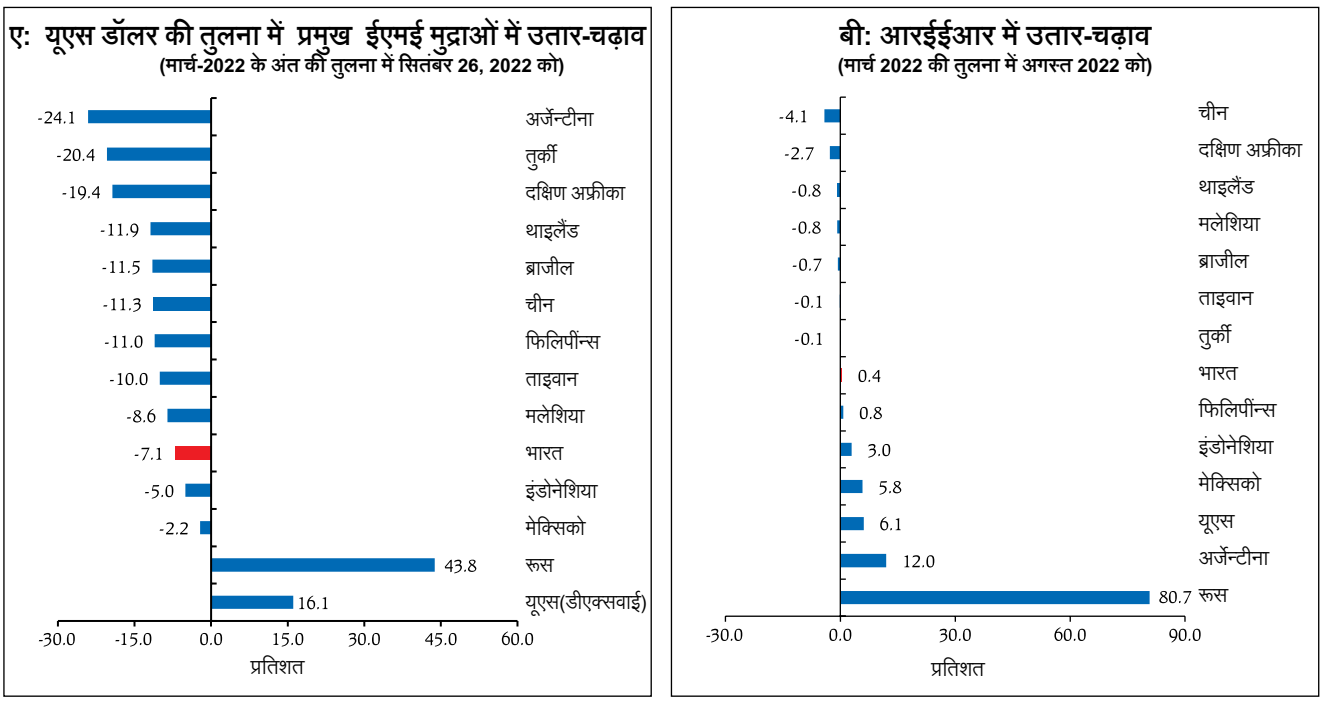
चार्ट IV.15: भारतीय रुपया - यूएस डॉलर में उतार-चढ़ाव



स्रोत: एफबीटीएल; ब्लूमबर्ग और थॉमसन रूटर्स।

संरचना और बफर के कारण भारतीय रुपये ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया और भारत की मुद्रास्फीति अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों[8] के भारित औसत से कम है। आहरण द्वारा कमी होने के बावजूद, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 537.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (23 सितंबर तक) था जो मात्रा में वैश्विक[9] स्तर पर पांचवे क्रम पर है, और निवल फॉरवर्ड खरीद के साथ

चार्ट IV.16: विभिन्न मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव



स्रोत: आरबीआई;एफबीआईएल; आईएमएफ; थॉमसन रूटर्स; और बैंक ऑफ इंटरनैशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस)।

[8] 40 मुद्राओं वाले आरईईआर में, व्यापार सहयोगी भारत के व्यापारिक माल व्यापार का 91 प्रतिशत, विश्व जीडीपी का 88.4 प्रतिशत और विश्व व्यापार में 86.4 प्रतिशत का योगदान करते हैं। अगस्त 2022 में भारत की मुद्रास्फीति इन 40 व्यापारिक सहयोगियों की तुलना में 0.8 प्रतिशत कम थी।

मिलकर, आघातसहनीयता और बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है।

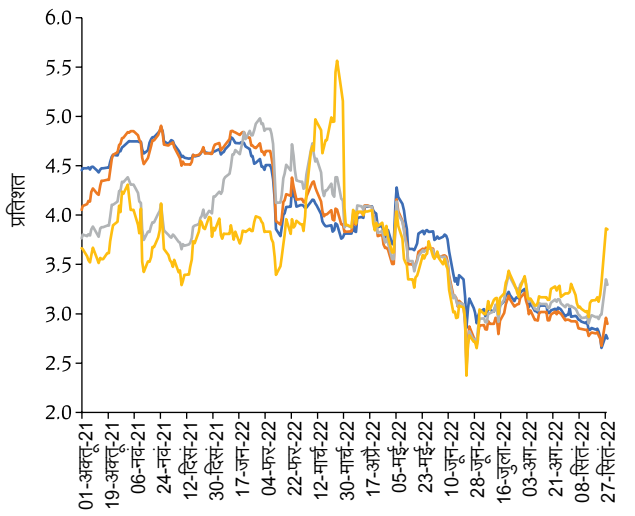
40 मुद्रा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) के संदर्भ में, मार्च 2022 और 23 सितंबर 2022 के बीच भारतीय रुपये में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.3)। इस दौरान 40 मुद्राओं की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में भी इसमें 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रथम छमाही के दौरान फॉरवर्ड प्रीमियम में गिरावट आई, जो यूएस फेड के अपेक्षा से अधिक तेजी से कठोर रुख के परिणामस्वरूप ब्याज दर के अंतर में कमी को परिलक्षित करता है। प्रथम छमाही (27 सितंबर तक) के दौरान एक महीने का फॉरवर्ड प्रीमियम कम होकर औसतन 3.36 प्रतिशत हुआ, जो वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही के दौरान 3.93 प्रतिशत था (चार्ट IV.17)।

IV.1.6 ऋण बाजार

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान, आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ बैंक ऋण[10] संवृद्धि में तेजी आई। गैर-खाद्य बैंक ऋण मार्च 2022 के अंत में 9.7 प्रतिशत से बढ़कर

चार्ट IV.17: फॉरवर्ड प्रीमियम में उतार-चढ़ाव



स्रोत: ब्लूमबर्ग।

सारणी IV.3: सांकेतिक तथा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचियां – (व्यापार भारित)

(आधार: 2015-16=100)

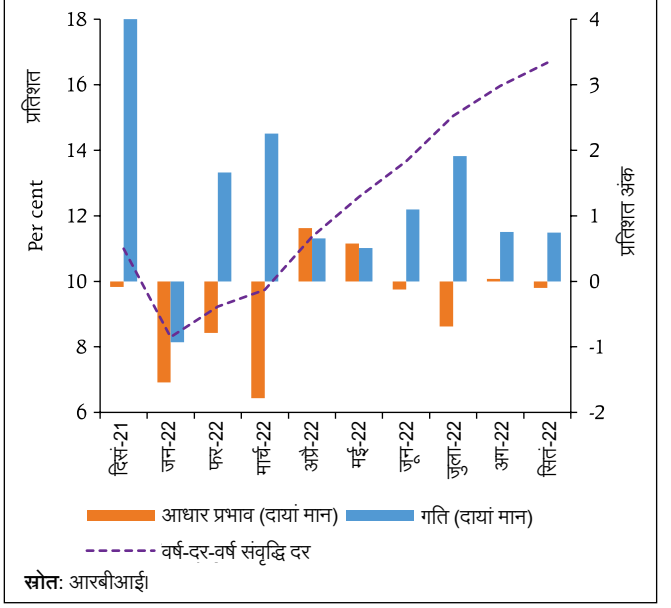
मद	सूचकांक : सितं 23, 2022 (पी)	वृद्धि (+) / कमी (-) (प्रतिशत)
		मार्च (औसत) 2022 की तुलना में सितं 23, 2022
40-करेंसी आरईईआर	104.6	1.1
40-करेंसी एनईईआर	92.9	0.2
6- करेंसी आरईईआर	104.7	3.7
6- करेंसी एनईईआर	88.0	1.8
₹/यूएस$*	81.37	-6.3

*: सितं 27, 2022 को।
पी: अनंतिम।
स्रोत: आरबीआई; और एफबीआईएल।

9 सितंबर, 2022 को 16.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट IV.18)।

हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी), दोनों के लिए, वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) में तेजी आई, लेकिन पीवीबी (पीएसबी के 13.9 प्रतिशत की तुलना में 20.4 प्रतिशत) के मामले यह अधिक रही (चार्ट IV.19ए)। हालांकि, इस ऋण वृद्धि में, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए गए ऋणों में पीएसबी का हिस्सा पीवीबी की तुलना में अधिक था (चार्ट IV.19बी)।

चार्ट IV.18: एससीबी की गैर- खाद्य ऋण संवृद्धि

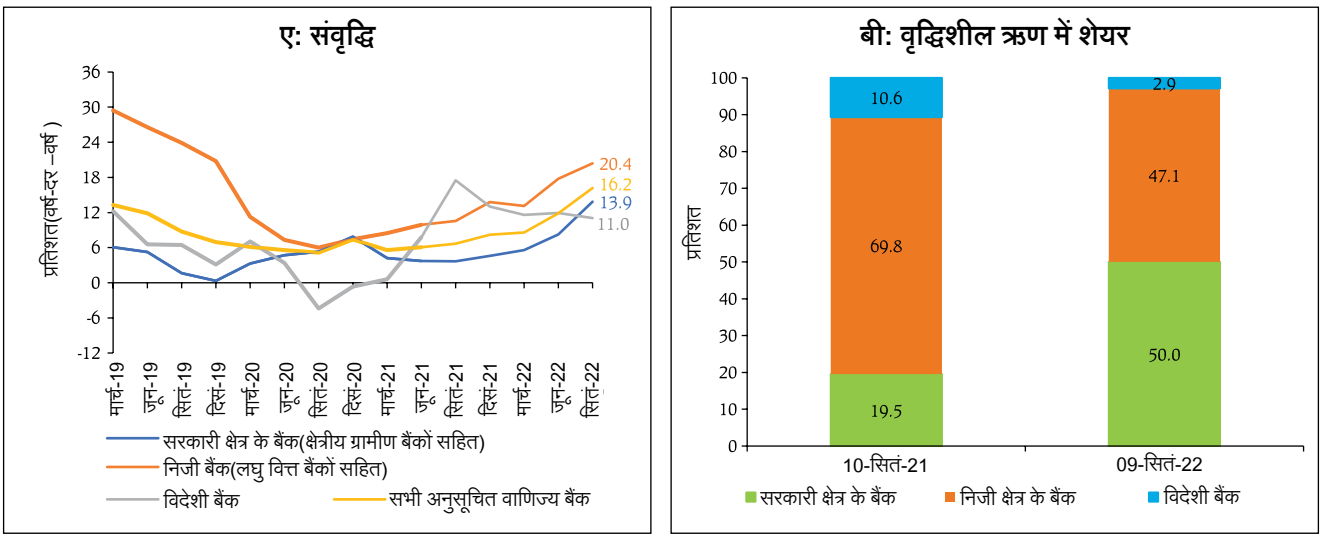


स्रोत: आरबीआई।

[9] 16 सितंबर 2022 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तुलना की गई है।

[10] दिनांक 03 दिसंबर, 2021 से सभी पखवाड़ों के लिए बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित विचरण / अनुपात को चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।

चार्ट IV.19: बैंक समूहों में ऋण वृद्धि

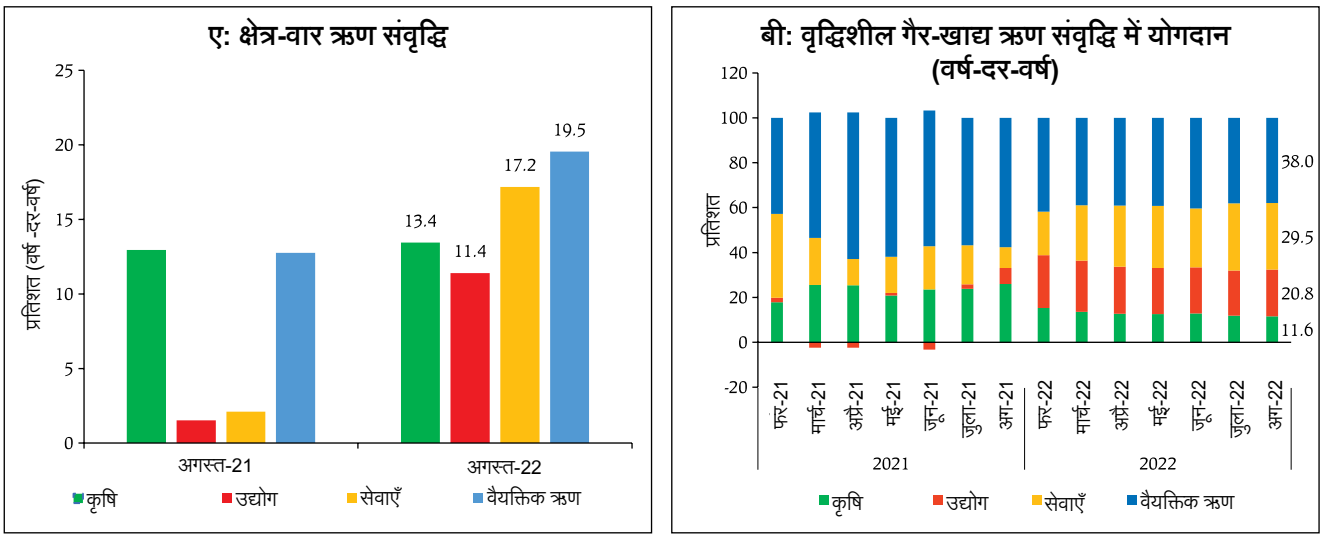


स्रोत: आरबीआई।

सभी प्रमुख क्षेत्रों में बैंक ऋण में सुधार देखा गया[11] (चार्ट IV.20)। सामान्य से अधिक मानसून और कृषि ऋण के लिए बढ़े हुए लक्ष्य के समर्थन से अगस्त 2022 (एक वर्ष पहले 13.0 प्रतिशत) में कृषि क्षेत्र[12] के लिए ऋण में 13.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

बड़े उद्योग के आगे आने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खंड में निरंतर वृद्धि से उद्योगक्षेत्र की ऋण

चार्ट IV.20: बैंक ऋण का क्षेत्रगत परिनियोजन



स्रोत: आरबीआई।

[11] गैर-खाद्य ऋण के आंकड़े, वर्ग - वार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें उन चुनिंदा बैंकों को शामिल किया गया है जिनका सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण में लगभग 93 प्रतिशत हिस्सा है।

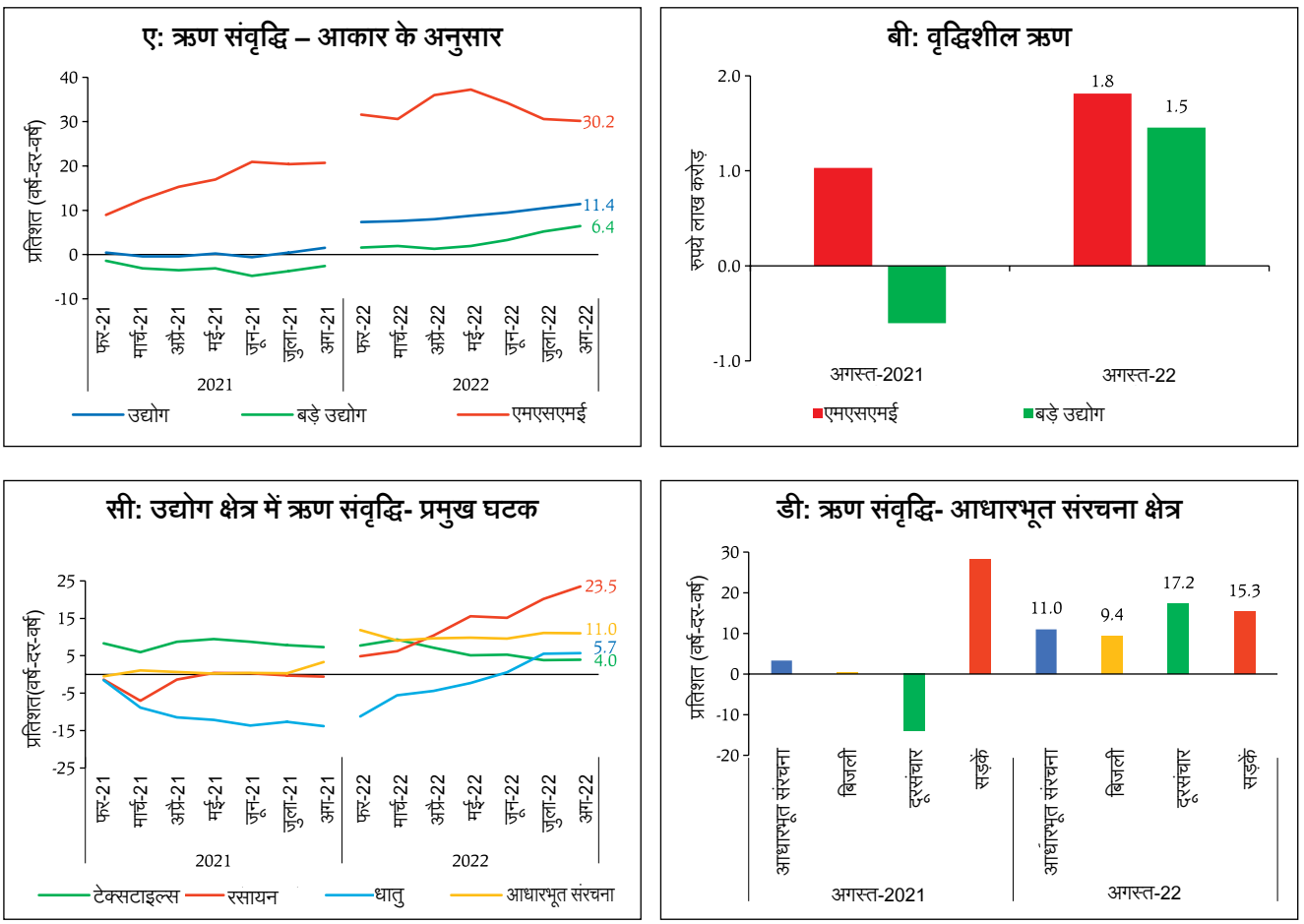
[12] सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को, जो 2021-22 के लिए ₹16.5 लाख करोड़ था, बढ़ाकर 2022-23 के लिए ₹18 लाख करोड़ कर दिया।

की मांग पिछले वर्ष के 1.5 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में 11.4 प्रतिशत हो गई। लंबे समय तक संकुचित दौर में रहने के बाद, अधिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और औद्योगिक गतिविधि के कारण, अगस्त में बड़े उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीजीएलएस) के विस्तार ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण वृद्धि में मदद की। यह एक वर्ष पहले 12.1 प्रतिशत की तुलना में अगस्त 2022 में 28.2 प्रतिशत हो गई। एमएसएमई के लिए वृद्धिशील ऋण प्रवाह (वर्ष-दर-वर्ष) बड़े उद्योगों से अधिक रहा (चार्ट IV.21ए और बी)। प्रमुख उद्योगों में, बुनियादी संरचना क्षेत्र की ऋण वृद्धि (बकाया औद्योगिक ऋण का 38 प्रतिशत) एक वर्ष पहले के 3.3 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2022 में 11.0 प्रतिशत हो गई। बुनियादी संरचना की यह ऋण वृद्धि बिजली क्षेत्र द्वारा संचालित थी, जो बिजली उत्पादन में मजबूत वृद्धि को दर्शाती है (चार्ट IV.21सी और डी) ।

कोविड-19 महामारी के दौरान गिरावट के बाद, मुख्यतया एनबीएफसी को हुए संवितरण से (जिसने एक साल पहले 1.0 प्रतिशत के संकुचन के मुकाबले अगस्त 2022 में 27.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की) वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र की ऋण वृद्धि ने गति पकड़ी। पर्यटन, होटल और रेस्तरां जैसे संपर्क गहन क्षेत्रों में ऋण वृद्धि व्यापक रूप से स्थिर रही (चार्ट IV.22)।

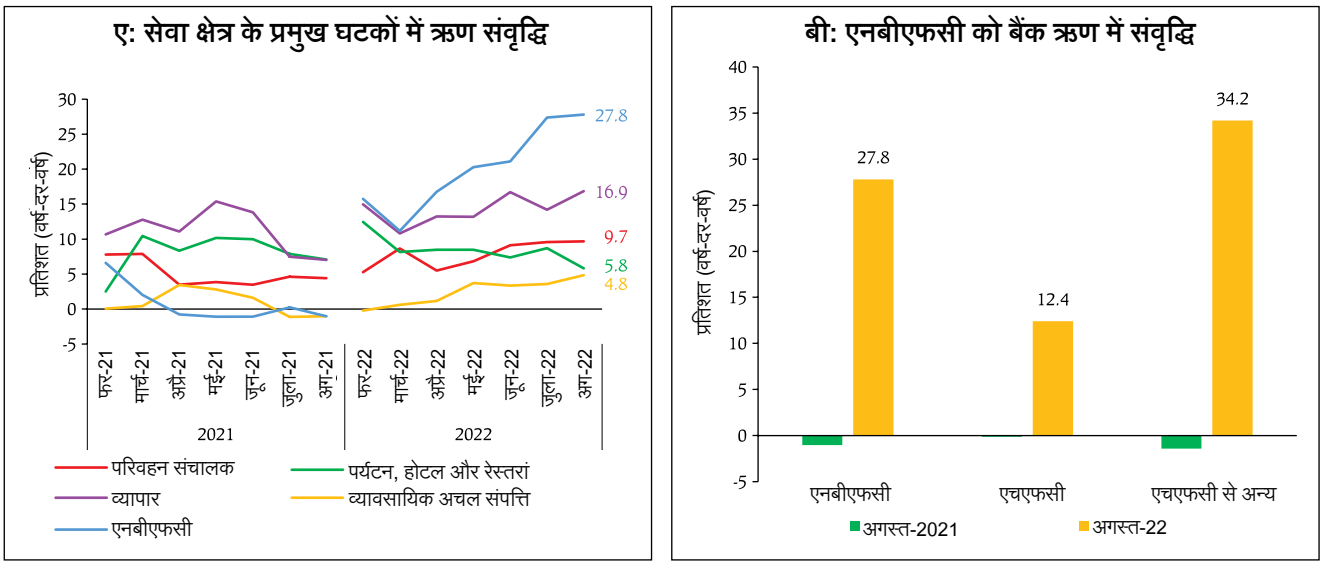
खुदरा ऋण, समग्र ऋण वृद्धि का प्रमुख वाहक बना रहा। नए कोविड-19 संक्रमणों में कमी और उपभोक्ता मांग में सुधार के साथ, खुदरा ऋणों के भीतर, 2022-23 की पहली छमाही में आवास ऋण में वृद्धि मजबूत थी (एक वर्ष पहले 11.6 प्रतिशत

चार्ट IV.21: उद्योग क्षेत्र में बैंक ऋण -आकार-वार और प्रकार-वार



स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.22: सेवा क्षेत्र में ऋण संवृद्धि



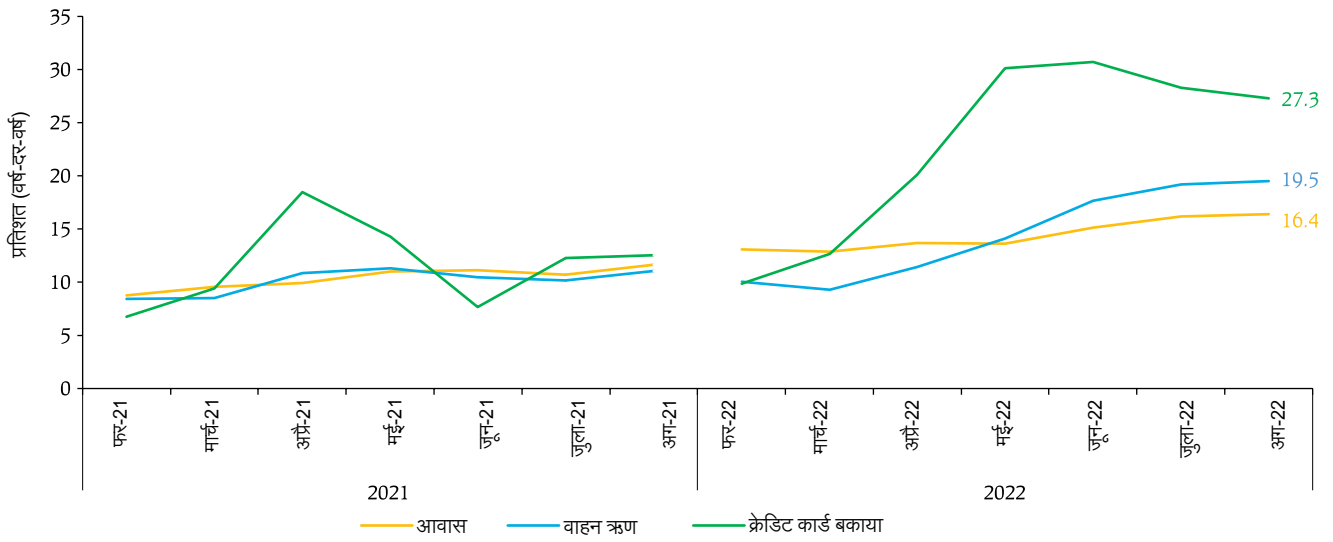
स्रोत: आरबीआई।

की तुलना में अगस्त 2022 में 16.4 प्रतिशत) वही वाहन ऋण क्षेत्र मजबूत हुआ (एक वर्ष पहले 11.1 प्रतिशत *की तुलना में* अगस्त 2022 में 19.5 प्रतिशत) क्रेडिट कार्ड ऋणों में वापस उछाल आया (**चार्ट** IV.23)।

समग्र गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का अनुपात जून 2022 में घटकर 5.6 प्रतिशत हो गया जो एक साल पहले 7.5 प्रतिशत था जिससे एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ (चार्ट IV.24ए)। सभी प्रमुख क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ (चार्ट IV.24बी)।

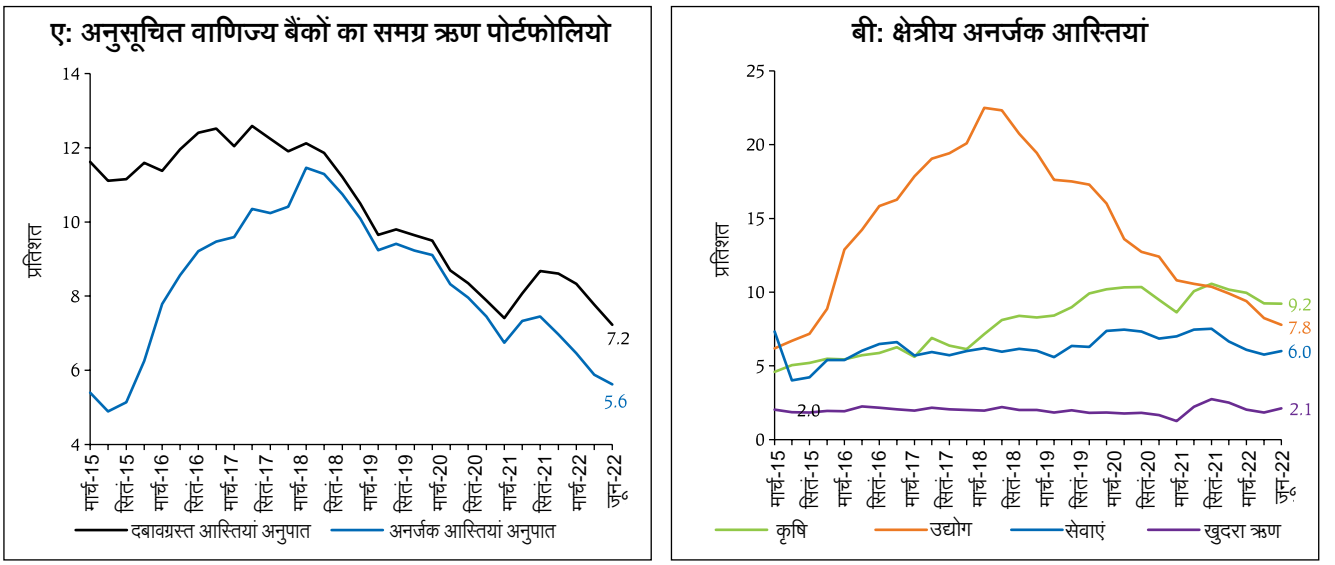
वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान बैंकों का गैर-एसएलआर निवेश – जिसमें सीपी, बांड, डिबेंचर और सार्वजनिक और निजी कंपनियों के शेयर शामिल हैं, कम थे। यह कमी मुख्य रूप से बांड/डिबेंचर में निवेश में गिरावट के कारण थी(चार्ट IV.25ए)। 9 सितंबर (वर्ष-दर-वर्ष) की स्थिति के अनुसार

चार्ट IV.23: निजी ऋण संवृद्धि



स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.24: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियां और अनर्जक आस्तियां

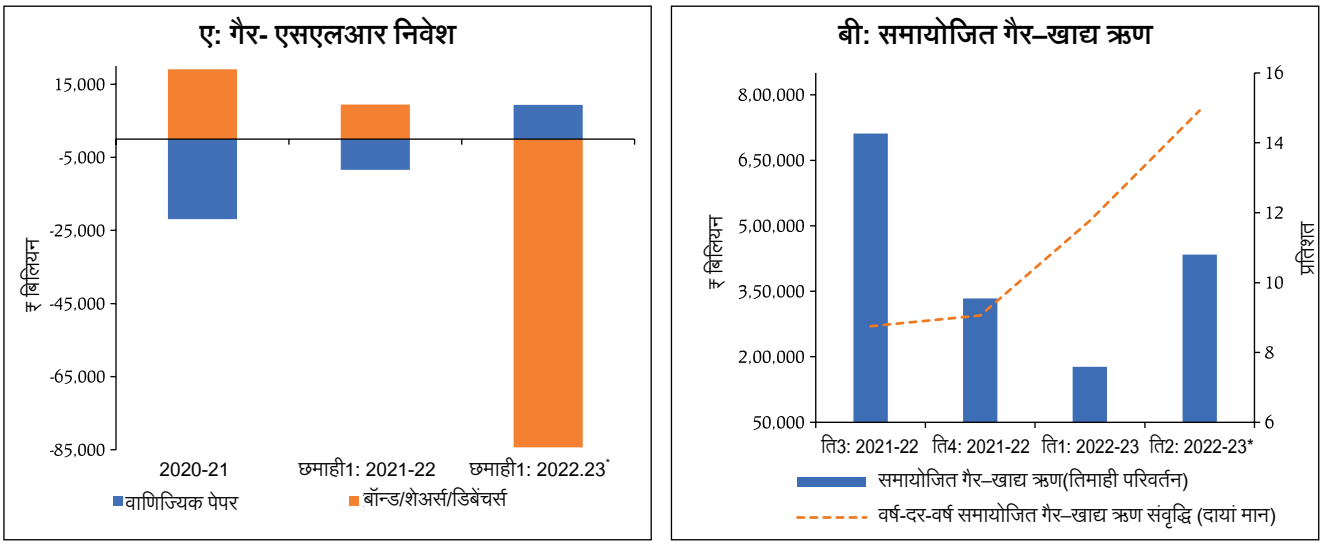


स्रोत: आरबीआई।

समायोजित गैर-खाद्य[13] ऋण वृद्धि 14.9 प्रतिशत पर रही जो मार्च 2022 के अंत में 9.1 प्रतिशत से बहुत अधिक थी (चार्ट IV.25बी)।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों की अतिरिक्त धारिता, जो मार्च 2022 के अंत में 10.4 प्रतिशत थी, कम होकर 26 अगस्त 2022 को उनकी निवल मांग और मीयादी देयता (एनडीटीएल) के 8.8 प्रतिशत हो गई, जो ऋण उठाव में सुधार से परिलक्षित होता है। अतिरिक्त एसएलआर धारिता बैंकों को एलएएफ के तहत निधि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक बफर प्रदान करती हैं और वह चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का एक घटक भी हैं।

चार्ट IV.25: गैर- एसएलआर निवेश और समायोजित गैर–खाद्य ऋण



*: सितंबर 9,2022 तक
स्रोत: आरबीआई।

[13] समायोजित गैर-खाद्य ऋण का तात्पर्य बैंकों के गैर-खाद्य ऋण और उनके गैर-एसएलआर निवेशों के जोड़ है। यह बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र में निधियों के समग्र प्रवाह को बेहतर ढंग से अभिग्रहण करता है।

सारणी IV.4: रेपो दर से बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंकों में परिवर्तन)

अवधि	रेपो दर	मियादी जमा दरें			उधार दरें			
		डब्ल्यूएडीटीडीआर (नयी जमाराशियां)		डब्ल्यूएडीटीडीआर (बकाया जमा)	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएएलआर (नए रुपए ऋण)	डब्ल्यूएएलआर (बकाया रुपए ऋण)
		खुदरा जमा	खुदरा और थोक जमा	खुदरा और थोक जमा				
फरवरी 2019 से मार्च 2022	-250	-209	-259	-188	-	-155	-232	-150
अप्रैल से अगस्त/सितंबर 2022*	+140	39	91	26	140	70	70	39
जिसमें से								
अप्रैल 2022	0	0	-9	0	0	0	-12	-2
मई से अगस्त/सितंबर 2022*	+140	39	100	26	140	66	82	41

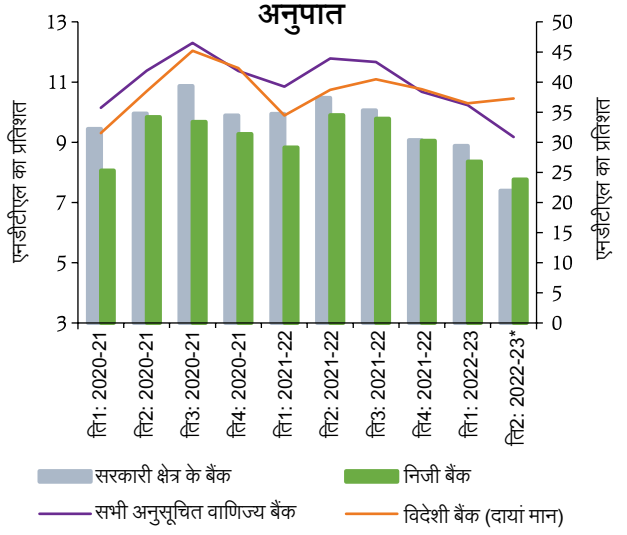
टिप्पणी: डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूडीटीआर : भारित औसत घरेलू मियादी जमा दर; ईबीएलआर: बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर; एमसीएलआर: निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत।

ईबीएलआर पर डेटा 31 घरेलू बैंको से संबंधित हैं।

*: डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीआर पर अद्यतन डाटा अगस्त 2022 से संबंधित है।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.26: बैंकों का अतिरिक्त सांविधिक चलनिधि अनुपात



*: अगस्त 2022 तक

स्रोत: आरबीआई।

IV.2 मौद्रिक नीति संचारण

मई 2022 से शुरू होने वाली नीतिगत रेपो दर में वृद्धि के साथ वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में बैंकों की जमा और उधार दरें अधिक हो गईं। मई-अगस्त 2022 के दौरान स्वीकृत नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 82 बीपीएस की वृद्धि हुई, जबकि बकाया रुपया ऋणों में 41 बीपीएस की वृद्धि हुई। इससे मौद्रिक नीति के सुलभ होने के दौरान (फरवरी 2019-मार्च 2022) जो नरमी दर्ज की गई थी वह काफी हद तक विपरीत दिशा में चली गई (सारणी IV.4)।

चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण मूल्य निर्धारण के लिए अक्तूबर 2019 में शुरू की गई अधिदेशित बाह्य बेंचमार्क व्यवस्था ने मौद्रिक संचारण के ब्याज दर चैनल को मजबूत किया है। बाह्य बेंचमार्क से जुड़े बकाया चलायमान दर ऋणों का अनुपात मार्च 2020 के 9.1 प्रतिशत से बढ़कर जून 2022 में 46.9 प्रतिशत हो गया। उसी समय, निधि आधारित सीमांत लागत उधार दर (एमसीएलआर) से जुड़े ऋणों का हिस्सा जून 2022 में कम होकर 46.5 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.5)।

बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) ऋणों का बड़ा हिस्सा (जून 2022 में कुल ऋणों का 80 प्रतिशत) नीतिगत रेपो दर से जुड़ा है। तदनुसार, मई-सितंबर 2022 के दौरान बैंकों नें नए ऋणों के लिए अपनी ईबीएलआर को 140 आधार अंकों से

सारणी IV.5: ब्याज दर बेंचमार्क पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया फ्लोटिंग दर रुपया ऋण

(कुल का प्रतिशत)

	मार्च 2020	मार्च 2021	मार्च 2022	जून 2022
आधार दर व्यवस्था	10.3	6.4	4.9	4.3
एमसीएलआर व्यवस्था	78.3	62.3	48.6	46.5
बाहरी बेंचमार्क व्यवस्था	9.1	29.5	44.0	46.9
अन्य	2.3	1.8	2.5	2.3

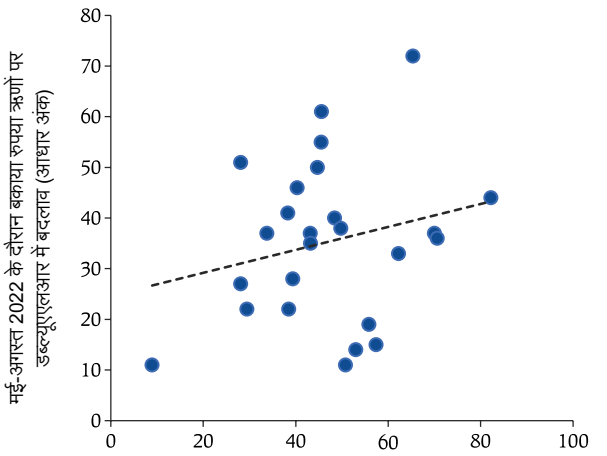
टिप्पणी: डेटा 74 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं।

स्रोत:आरबीआई।

बढ़ा दिया। एससीबी की एक वर्षीय माध्यिका एमसीएलआर- जो कि आंतरिक बेंचमार्क पर आधारित है- उनकी जमाराशियों की लागत और अन्य निधीयन स्रोतों पर दबाव के अनुरूप, पहली छमाही में 70 आधार अंकों तक बढ़ गई। कुल मिलाकर, रेपो से जुड़े ईबीएलआर के हिस्से में हुई बढ़ोत्तरी, ऐसे ऋणों की अपेक्षाकृत छोटी रीसेट अवधि और एमसीएलआर में ऊर्ध्व समायोजन ने डब्ल्यूएएलआर बकाया ऋणों पर संचारण की गति को बढ़ाया है चार्ट (IV.27)।

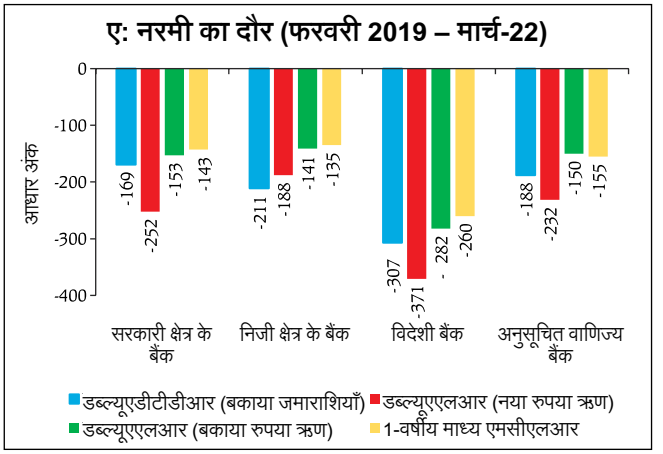
घरेलू बैंकों में, मई-अगस्त 2022 के दौरान पीएसबी के मामले में नए रुपया ऋण पर डब्ल्यूएएलआर में वृद्धि पीवीबी से अधिक हो गई, जो आंशिक रूप से यह दर्शाता है कि पीएसबी का चलायमान दर पर ऋण में बड़ा हिस्सा है। नरमी के दौर का असर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उधार दरों पर पीवीबी की तुलना से अधिक रहा (चार्ट IV.28 ए और बी)। पीएसबी की उधार दरें

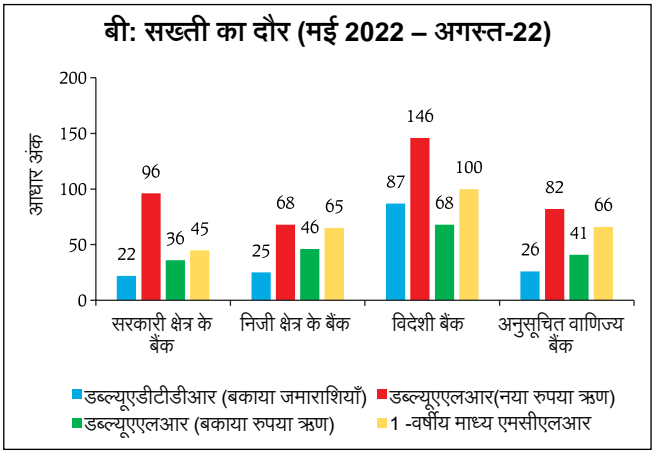
चार्ट IV.27: बैंक-वार उधार दरें और ईबीएलआर से जुड़े ऋणों का योगदान

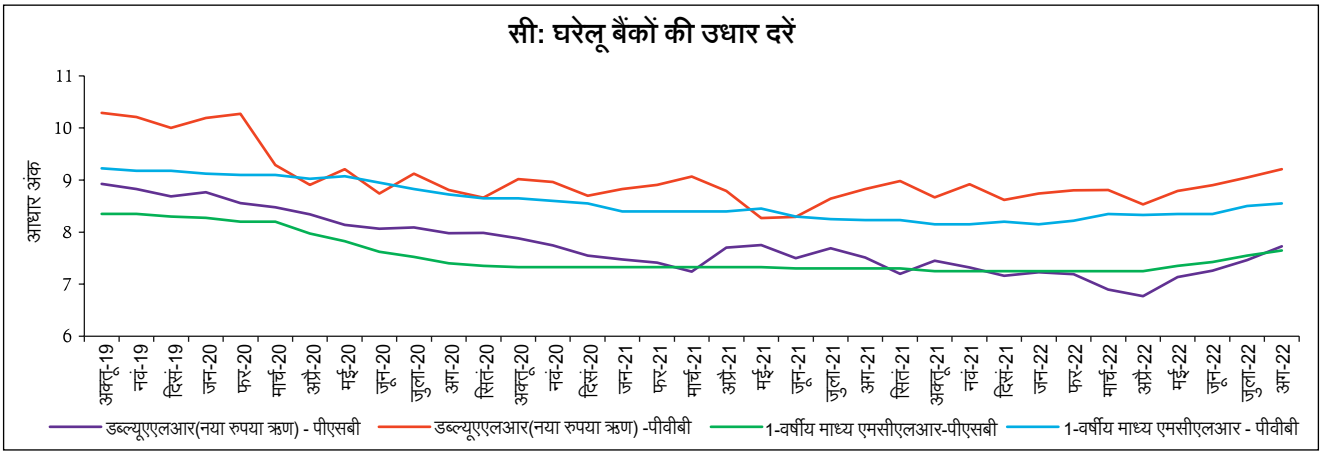


स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.28: उधार और जमा दरों के लिए बैंक समूह-वार संचरण

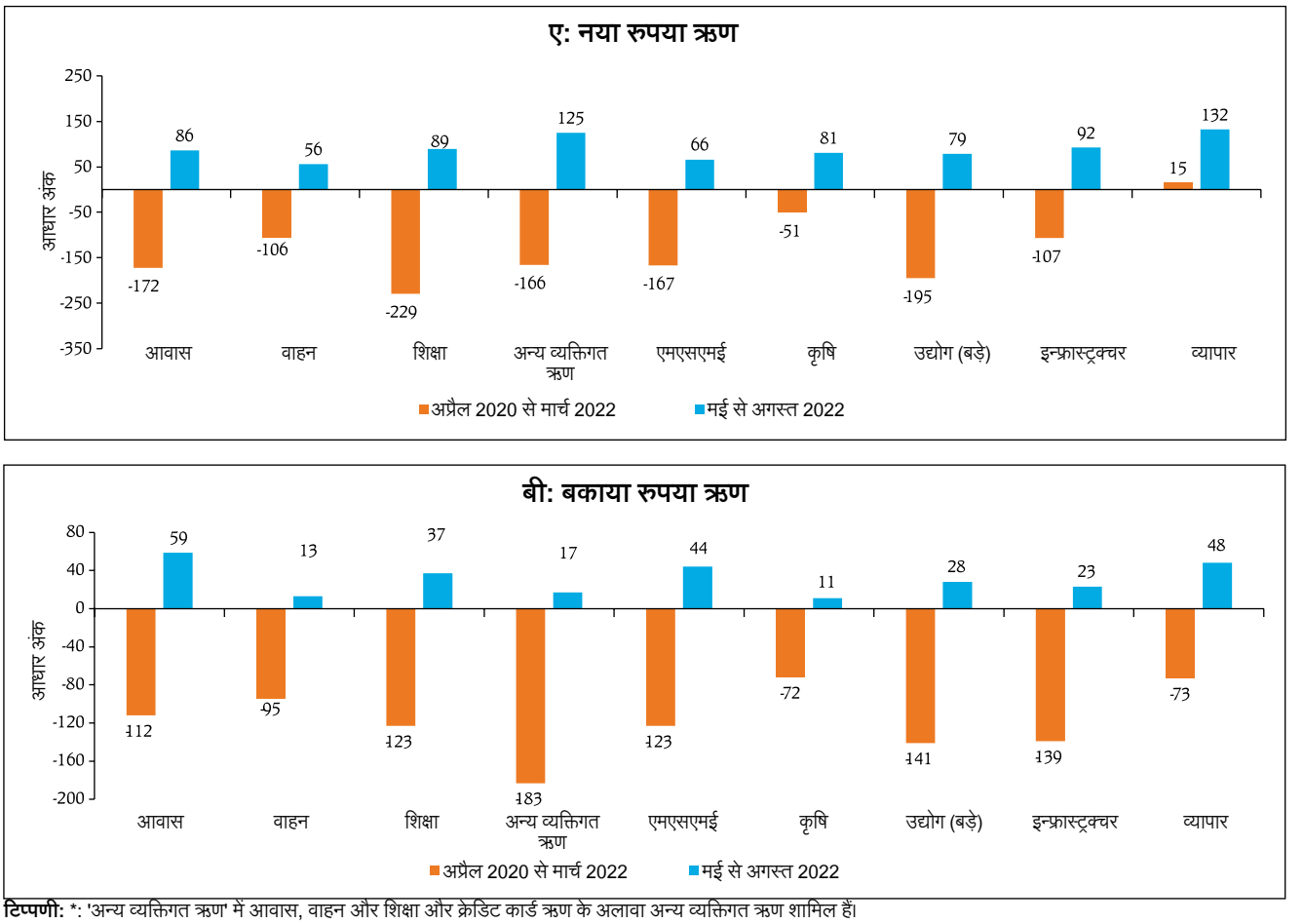






स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.29: घरेलू बैंकों के डब्ल्यूएएलआर को क्षेत्र-वार संचरण



टिप्पणी: *: 'अन्य व्यक्तिगत ऋण' में आवास, वाहन और शिक्षा और क्रेडिट कार्ड ऋण के अलावा अन्य व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

पीवीबी की तुलना में कम बनी हुई हैं(चार्ट IV.28सी)। विदेशी बैंकों के मामले में उधार और जमा दरों का संचरण अधिकतम था जो उनकी कुल देनदारियों में कम लागत और कम अवधि की थोक जमाराशियों के उच्च हिस्से को दर्शाता है।

मई-अगस्त 2022 के दौरान सभी क्षेत्रों में नए और बकाया रुपया ऋण दोनों पर डब्ल्यूएएलआर में वृद्धि हुई (चार्ट IV.29)।

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में घरेलू बैंकों द्वारा पॉलिसी रेपो दर (अस्थायी दर के नए रुपया ऋणों के मामले में जहां रेपो दर बाहरी बेंचमार्क है) पर लगाए गए स्प्रेड को एमएसएमई, आवास और शिक्षा ऋण के मामले में कम किया गया (सारणी IV.6)।

सारणी IV.6: बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋण – रेपो दर पर डब्ल्यूएएलआर (नए ऋण) का स्प्रेड

(प्रतिशत)

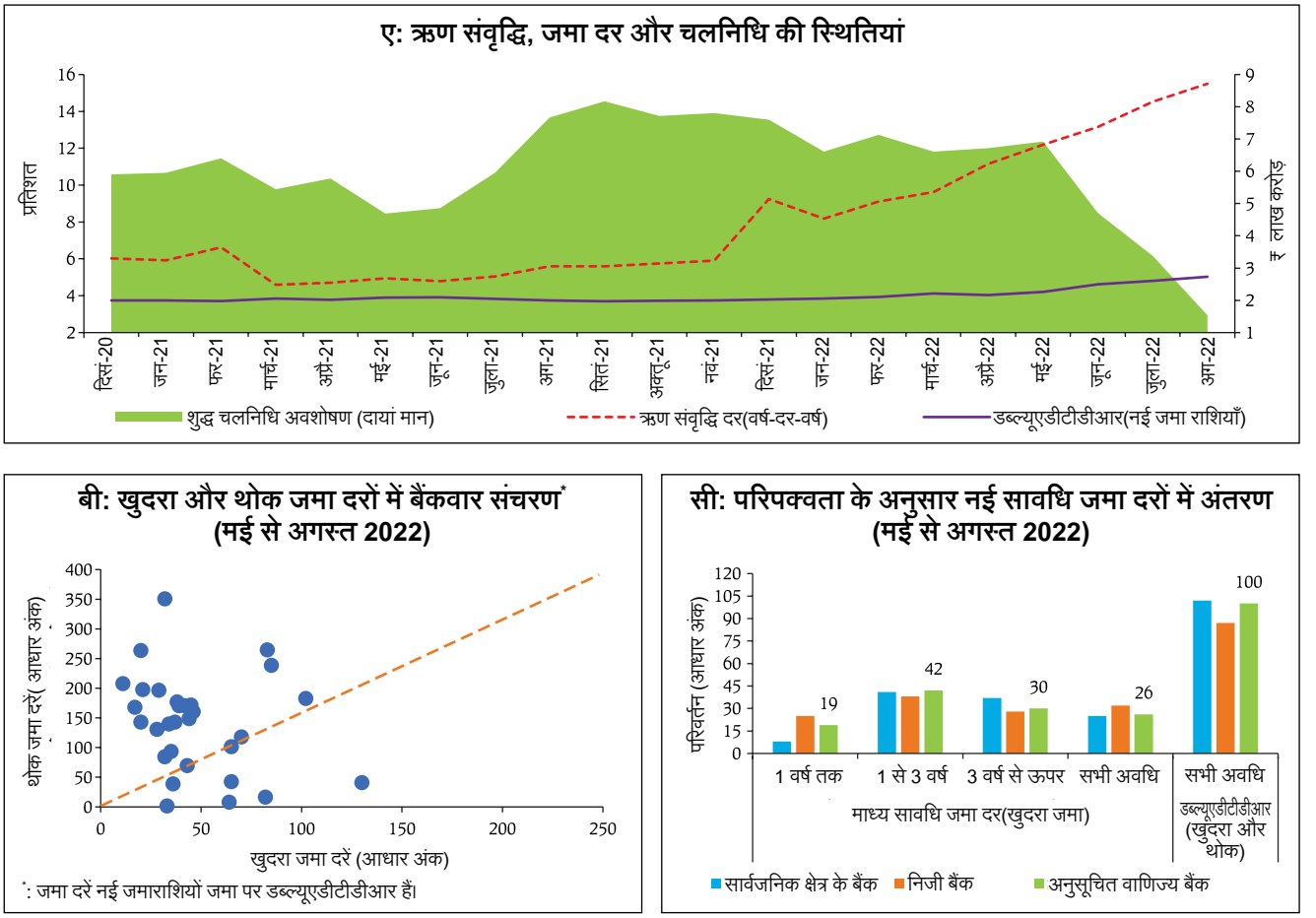
क्षेत्र	मार्च 2022			अगस्त 2022		
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी बैंक	घरेलू बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी बैंक	घरेलू बैंक
एमएसएमई ऋण	4.32	4.12	4.23	4.14	3.53	3.76
वैयक्तिक ऋण						
आवास	2.85	3.47	3.15	2.66	2.43	2.52
वाहन	3.23	2.79	3.06	3.09	3.21	3.10
शिक्षा	4.28	5.45	4.51	4.25	4.64	4.37
अन्य वैयक्तिक ऋण	3.17	6.06	3.36	3.75	6.39	3.97

स्रोत: आरबीआई।

बैंकों ने प्रणालीगत चलनिधि में नरमी के बीच 2022-23 की पहली छमाही में अपनी मीयादी जमा दरों में भी वृद्धि की (चार्ट IV.30ए)[14]। बैंकों ने खुदरा जमा दरों (चार्ट IV.30बी) के सापेक्ष अपनी थोक मीयादी जमा[15] दरों में अधिक वृद्धि की - मई-अगस्त 2022 के दौरान नई खुदरा जमाओं पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर(डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 39 आधार अंकों की वृद्धि हुई, जबकि कुल नई जमाओं (खुदरा और थोक जमा दोनों) पर डब्ल्यूएडीटीडीआर में 100 आधार अंकों की वृद्धि हुई। मई-सितंबर 2022 के दौरान नई खुदरा जमाओं पर औसत मीयादी जमा दर – प्रचलित कार्ड दरें – 26 आधार अंक बढ़ीं (चार्ट IV.30सी)। बकाया जमाराशियों पर डब्ल्यूएडीटीडीआर को संचरण भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो निश्चित दरों पर अनुबंधित मीयादी जमाओं की प्रधानता को दर्शाता है (सारणी IV.4)। अगस्त 2022 में एससीबी की भारित औसत बचत जमा दर अप्रैल 2022[16] से अपरिवर्तित, 3.0 प्रतिशत रही।

विभिन्न लघु बचत साधनों (एसएसआई) पर ब्याज दरें - जो तुलनीय परिपक्वताओं की सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल के ऊपर 0-100 आधार अंक के प्रसार के साथ तिमाही आधार पर तय की जाती हैं – लगातार नौवीं तिमाही के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल बढ़ने के साथ, विभिन्न योजनाओं पर

चार्ट IV.30: अधिशेष चलनिधि, ऋण की स्थिति और सावधि जमा दरों में संचरण



टिप्पणी: नई जमाराशियों पर औसत सावधि जमा दर के आंकड़े मई-सितंबर 2022 की अवधि से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

[14] जमाओं के अनुपात में वृद्धिशील ऋण 9 अप्रैल, 2021 को 37 प्रतिशत से बढ़कर 9 सितंबर, 2022 को 111.6 प्रतिशत हो गया।

[15] थोक जमा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपये की मीयादी जमा है।

[16] जून 2022 में एससीबी की कुल जमा में मीयादी जमा की हिस्सेदारी 57.1 प्रतिशत थी, जबकि चालू खाता और बचत खाता जमा क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 34 प्रतिशत थे।

सारणी IV.7: अल्प बचत लिखतों पर ब्याज दरें

अल्प बचत योजना	परिपक्वता (वर्ष)	स्प्रेड (प्रतिशत अंक) $	संगत परिपक्वता का औसत जी-सेक यील्ड (%) (जून 2022 -अग 2022)	फार्मूला- आधारित ब्याज दर(%) (तिमाही 3: 2022-23 के लिए लागू)	तिमाही 3: 2022-23 में सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर (%)	अंतर (आधार अंक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (6) - (5)
जमा बचत	-	-	-	-	4.00	-
सार्वजनिक भविष्य निधि	15	0.25	7.47	7.72	7.10	-62
मियादी जमा						
1 वर्ष	1	0	6.09	6.09	5.50	-59
2 वर्ष	2	0	6.33	6.33	5.70	-63
3 वर्ष	3	0	6.57	6.57	5.80	-77
5 वर्ष	5	0.25	7.04	7.29	6.70	-59
आवर्ती जमा खाता	5	0	6.57	6.57	5.80	-77
मासिक आय योजना	5	0.25	7.00	7.25	6.70	-55
किसान विकास पत्र	123 माह#	0	7.47	7.47	7.00	-47
एनएससी VIII इश्यु	5	0.25	7.23	7.48	6.80	-68
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	5	1.00	7.04	8.04	7.60	-44
सुकन्या समृद्धि खाता योजना	21	0.75	7.47	8.22	7.60	-62

$: फरवरी 2016 की भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अल्प बचत दरों के निर्धारण के लिए स्प्रेड्स।

#: वर्तमान परिपक्वता 123 महीने है।

टिप्पणी: कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अलग-अलग लिखतों में भिन्न होती है।

स्रोत: भारत सरकार; एफबीआईएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रचलित ब्याज दरें 2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए निहित दरों के फार्मूले से 44-77 आधार अंक नीचे हैं, 2022-23 की तीसरी तिमाही में 10-30 आधार अंक के दायरे में बढ़ी (सारणी IV.7)।

IV.3 चलनिधि संबंधी स्थितियां और परिचालन प्रक्रिया

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार रिज़र्व बैंक से यह अपेक्षित है कि वह मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं और समय-समय पर उसमें होने वाले परिवर्तनों, यदि कोई हो, को पब्लिक डोमेन में रखे। अप्रैल 2022 में, एसडीएफ को 3.75 प्रतिशत- यानि नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे (तब 4.00 प्रतिशत पर प्रचलित) और एफआरआरआर से 40 आधार अंक ऊपर रखते हुए- एफआरआरआर की जगह एलएएफ कॉरिडोर के आधार के रूप में प्रस्तुत करके परिचालन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। एसडीएफ़ दर एक दिवसीय असंपार्श्विक जमाराशियों पर लागू होती है। एसडीएफ़ केंद्रीय बैंक पर बाध्यकारी संपार्श्विक बाधा को हटाकर, मौद्रिक नीति के परिचालन फ्रेमवर्क को मजबूत करता है। इतना ही नहीं, चलनिधि प्रबंधन में इसकी भूमिका के साथ-साथ यह एक वित्तीय स्थिरता का साधन भी है। एमएसएफ़ दर को नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक ऊपर बनाए रखा गया, इस प्रकार, एलएएफ़ कॉरीडोर के विस्तार को 50 आधार अंक के महामारी-पूर्व के स्तर पर बहाल कर लिया गया और यह नीतिगत दर के लगभग समरूप हो गया। एफ़आरआरआर को 3.35 प्रतिशत पर कायम रखा गया। रेपो/प्रतिवर्ती रेपो, खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) आरबीआई के विवेकाधीन होते हैं। इसके विपरीत, एसडीएफ़ अभिगम्यता एमएसएफ़ की भांति बैंकों के विवेक पर निर्भर करती है।

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में चलनिधि प्रबंधन का फोकस बिना कोई बाधा उत्पन्न किए अधिशेष चलनिधि को धीरे-धीरे, नपे-तुले अंदाज़ में हटा लेने की ओर बढ़ा। यह 2021-22 के दौरान मौद्रिक नीति के फोकस को निभावकारी बनाए रखने से लेकर मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को रोकने के लिए निभावकारी रुख को वापस लेने हेतु किए गए बदलाव के अनुरूप था। मई-अगस्त 2022 के दौरान एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 140 आधार अंक बढ़ाया। अप्रैल

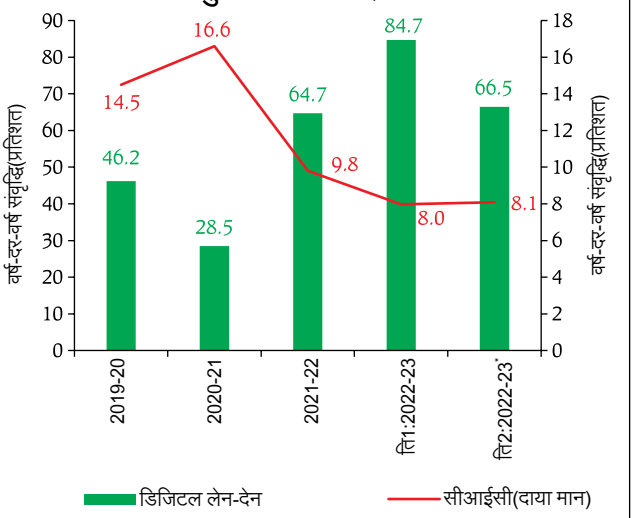
में एसडीएफ़ के एफ़आरआरआर से 40 आधार अंक ऊपर बने रहने के साथ ही प्रभावी ब्याज दर में संचयी वृद्धि 180 आधार अंक की हुई। इसके अतिरिक्त, सीआरआर को 50 आधार अंक बढ़ाकर (21 मई 2022 से प्रभावी पखवाड़े में) 4.50 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे बैंकिंग प्रणाली से प्राथमिक चलनिधि की निकासी हुई।

चलनिधि के संचालक और प्रबंधन

अधिशेष चलनिधि 2022-23 की पहली छमाही में कम हुई, जो जनता की मुद्रा मांग, निवल विदेशी मुद्रा बहिर्वाह और सरकार के नकदी शेष में वृद्धि से प्रेरित थी। पहली छमाही में संचलन में मुद्रा (सीआईसी) में विस्तार के कारण चलनिधि में कमी एक साल पहले की तुलना में कम थी, जो कि आंशिक रूप से डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग को दर्शाती है (चार्ट IV.31)। सरकारी नकदी शेष में वृद्धि ने बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि के रिसाव में भी योगदान दिया। बैंकों द्वारा अपनी अतिरिक्त प्रारक्षित निधि में से आहरण द्वारा की गई कमी ने चलनिधि दबाव को आंशिक रूप से कम कर दिया (सारणी IV.8)।

आरबीआई द्वारा चलनिधि प्रबंधन के संदर्भ में, ओएमओ बिक्री और सीआरआर में 50 आधार अंक की वृद्धि ने पहली छमाही में बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि को अवशोषित कर लिया।

चार्ट IV.31: डिजिटल भुगतान की मात्रा की तुलना में सीआईसी



*: जुलाई 2022 तक।
स्रोत: आरबीआई।

अधिशेष चलनिधि में परिणामी कमी एलएएफ के तहत कम अवशोषण में परिलक्षित हुई - एलएएफ के तहत औसत दैनिक चलनिधि अवशोषण अप्रैल में ₹7.8 लाख करोड़ से गिरकर सितंबर में ₹2.1 लाख करोड़ हो गई (27 सितंबर तक)। जीएसटी भुगतानों के अस्थायी चलनिधि दबावों के कारण, एमएसएफ विंडो के तहत उधार 25 जुलाई 2022 को बढ़कर ₹59,312 करोड़

सारणी IV.8: चलनिधि - प्रमुख संचालक और प्रबंधन

(₹ करोड़)

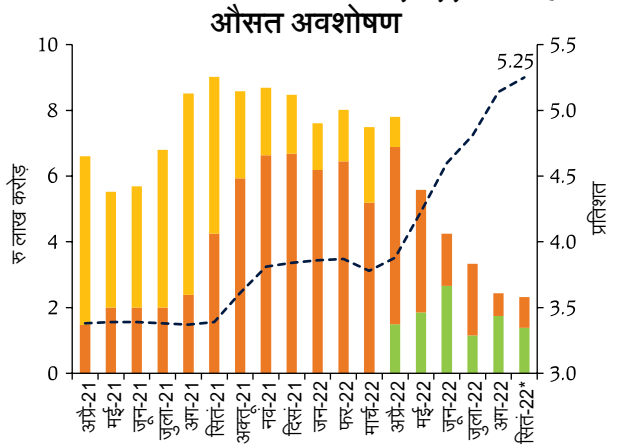
	2021-22			2022-23	
	ति1	ति2	छ1	ति1	ति2*
संचालक					
(i) सीआईसी [आहरण(-)/ वापसी(+)]	-1,26,266	54,921	-71,344	-83,887	50,530
(ii) शुद्ध विदेशी मुद्रा खरीद (+)/बिक्री(-)	1,60,843	1,42,395	3,03,238	16,159	-1,68,975#
(iii) भारत सरकार नकद शेष[बिल्ड-अप(-)/ड्रॉडाउन(+)]	-2,23,740	-5,600	-2,29,340	-3,73,117	67,863#
iv) अतिरिक्त रिजर्व [बिल्ड-अप(-)/ड्रॉडाउन(+)]	1,17,219	-9,884	1,07,335	1,50,165	-48,559#
प्रबंधन					
i) शुद्ध ओएमओ खरीद (+)/बिक्री(-)	1,38,965	97,960	2,36,925	-6,620	-14,460
(ii) आवश्यक आरक्षित निधियां [एनडीटीएल और सीआरआर दोनों में परिवर्तन सहित]	-87,827	-6,586	-94,463	-1,03,054	-10,463
मेमो आइटम					
अवधि के अंत में बकाया शुद्ध एलएएफ	4,71,970	7,58,132	7,58,132	2,44,891	26,152 ^

*: डेटा सितंबर 23, 2022 तक का है। #: डेटा जुलाई 29, 2022 तक का है। ^: डेटा सितंबर 27, 2022 तक का है।
टिप्पणी: (+)/(-) चिह्न बैंकिंग प्रणाली की तरलता में वृद्धि/कमी का संकेत देता है।
संचालकों और प्रबंधन पर डेटा संबंधित अवधि के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
स्रोत: आरबीआई।

(बकाया राशि) हो गया, जो 1 अप्रैल 2019 (₹94,263 करोड़) के बाद उच्चतम स्तर पर है। अग्रिम कर बहिर्गमन और जीएसटी भुगतान ने सितंबर के तीसरे सप्ताह में अस्थायी रूप से अधिशेष चलनिधि को नियंत्रित किया। आरबीआई ने ₹50,000 करोड़ की परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) प्रत्येक नीलामियां 3 दिनों के लिए और ओवरनाइट परिपक्वता क्रमशः 26 जुलाई और 22 सितंबर 2022 को आयोजित की। आरबीआई चलनिधि के संबंध में सतर्क रहता है और आवश्यकतानुसार दो-तरफा परिष्करण (फाइन ट्यूनिंग) परिचालनों का संचालन करेगा - विभिन्न अवधि के परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) और परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) दोनों – उभरती चलनिधि और वित्तीय स्थितियों के आधार पर।

8 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत से, एसडीएफ के तहत मासिक औसत अवशोषण 2022-23 की पहली छमाही (27 सितंबर तक) के दौरान ₹1.2-2.7 लाख करोड़ रुपये की सीमा में रहा है, जबकि शेष राशि को परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी (मुख्य और परिष्करण परिचालन दोनों) के माध्यम से अवशोषित किया गया (चार्ट IV.32)। अधिशेष चलनिधि में कमी को ध्यान में रखते हुए, लंबी परिपक्वता अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के पास निधियां रखने की बैंकों की आवश्यकता कम हो गई। परिणामस्वरूप, परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामियों के माध्यम से अवशोषित राशि सितंबर 2022 (27 सितंबर तक) में कुल अवशोषण का 40 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2022 में लगभग 74 प्रतिशत थी। सितंबर 2022 में (27 सितंबर तक) 5.25 प्रतिशत की प्रभावी अवशोषण दर[17] 5.15 प्रतिशत की एसडीएफ दर से अधिक थी।

चार्ट IV.32: अधिशेष चलनिधि - एलएएफ के तहत औसत अवशोषण



*: सितंबर 27, 2022 तक।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

IV.4 निष्कर्ष

घरेलू वित्तीय बाजारों ने वैश्विक वित्तीय बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से नीतिगत प्रभाव के प्रति आघातसहनीयता प्रदर्शित करते हुए, निभावकारी दृष्टिकोण को हटाना, नीतिगत दरों में वृद्धि और अधिशेष चलनिधि में कमी लाने के संबंध में मौद्रिक नीति के फोकस पर हुए बदलाव को सुचारू रूप से समायोजित किया है। बाजार दरें परिपक्वता स्पेक्ट्रम में उच्च स्तर पर चली गई हैं हालांकि बाजार क्षेत्रों और लिखतों में अलग-अलग स्तर पर बनी हुई हैं। आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप बैंक ऋण उठाव में सुधार हुआ है, यहां तक कि उधार और जमा दरों में वृद्धि शुरू हो गई हैं। अमेरिकी डॉलर की सामान्य मजबूती के कारण मूल्यह्रास की प्रवृत्ति के साथ विदेशी मुद्रा बाजार को भारतीय रुपए के एक व्यवस्थित समायोजन के रूप में निरूपित किया गया। आगे बढ़ते हुए, आरबीआई अपने चलनिधि प्रबंधन कार्यों में सतर्क, चुस्त और सक्रिय रहेगा और घरेलू वित्तीय बाजारों पर वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को कम करने के लिए अपने प्रयासों में सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करेगा।

[17] एफआरआरआर/एसडीएफ और लंबी परिपक्वता के वीआरआरआर के तहत अवशोषण की भारित औसत दर जिसमें प्रत्येक सुविधा के तहत अवशोषित राशि भार है।

V. बाह्य परिवेश

यूक्रेन में लंबे समय से चल रहे संघर्ष एवं आक्रामक और समकालिक मौद्रिक सख्ती के समग्र प्रभाव से वैश्विक परिदृश्य और खराब हो गया है। ये गतिविधियां वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारी अस्थिरता और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़े प्रतिकूल प्रभाव-विस्तार उत्पन्न कर रही हैं। आपूर्ति शृंखला में बाधाएं, ऊर्जा एवं खाद्य संकट और सख्त वित्तीय स्थितियां वैश्विक मंदी के जोखिम को बढ़ा रही हैं।

लंबे समय से चल रहे युद्ध और कई दशकों के उच्च स्तर पर पहुंच गई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए की गई आक्रामक और समकालिक मौद्रिक सख्ती के संयुक्त प्रभाव के कारण, अप्रैल 2022 एमपीआर के बाद से वैश्विक परिदृश्य और खराब हो गया है। राष्ट्रिक बॉन्ड प्रतिफलों में वृद्धि हुई है जबकि इक्विटी बाजारों में मौद्रिक कार्रवाई की प्रतिक्रिया में गिरावट आई है। भू-राजनीतिक तनाव, यूएस फेड द्वारा मौद्रिक सख्ती की तेज गति और सुरक्षित निवेश के लिए अमेरिकी डॉलर की मांग ने अमेरिकी डॉलर को 20 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। इसके कारण बड़े पोर्टफोलियो बहिर्वाह के परिवेश में प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की मुद्राओं पर मूल्यह्रास का दबाव पड़ने लगा है। आपूर्ति शृंखला में चली आ रही बाधाएं, ऊर्जा एवं खाद्य संकट और सख्त वित्तीय स्थितियां वैश्विक मंदी के जोखिम को बढ़ा रही हैं।

V.1 वैश्विक आर्थिक स्थितियां

वैश्विक विकास ने गति खो दी और 2022 की दूसरी तिमाही में संकुचन में डूब गया। उच्च आवृत्ति संकेतक तीसरी तिमाही में और मंदी की ओर इशारा करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2022 की पहली छमाही [तिमाही दर तिमाही मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दरों (एसएएआर) के अनुसार पहली और दूसरी तिमाही में इन्वेंटरी और व्यावसायिक निवेश के कारण क्रमशः (-) 1.6 प्रतिशत और (-) 0.6 प्रतिशत] में संकुचित हुई (सारणी V.1)। इसके विपरीत, निरंतर वेतन वृद्धि और घटती बेरोजगारी दर के कारण अमेरिकी श्रम बाजार मजबूत बना हुआ है। सांकेतिक वेतन वृद्धि मजबूत रही है हालांकि इसके स्थिर होने के संकेत हैं। अगस्त में यूएस संमिश्र क्रय प्रबन्धक सूचकांक(पीएमआई)[1] 44.6 पर विनिर्माण और सेवा उत्पादन दोनों में गिरावट के साथ लगातार दूसरे महीने संकुचन क्षेत्र में रहा।

2022 की दूसरी तिमाही में यूरो क्षेत्र की जीडीपी 3.1 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही एसएएआर) बढ़ी जो कि कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील और पर्यटन में पुनरुत्थान वृद्धि के कारण तीन तिमाहियों में इसकी सबसे तेज़ गति रही है। हालांकि, तीसरी तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक भविष्य में गैस आपूर्ति के आसपास बढ़ती अनिश्चितता और निर्वाह व्यय की बढ़ती लागत के कारण गति में मंदी का संकेत देते हैं। यूरो क्षेत्र के लिए संमिश्र पीएमआई ने अगस्त 2022 में विनिर्माण और सेवाओं दोनों में मंदी के साथ 48.9 पर लगातार दूसरा संकुचन दर्ज किया। युद्ध और अति उच्च मुद्रास्फीति के कारण परिदृश्य में बादल छाए हुए हैं और आगे सख्त वित्तीय स्थितियां अपेक्षित हैं।

यूके में, सरकार और उपभोक्ता व्यय में गिरावट, उत्पादन आउटपुट में गिरावट और श्रमिकों की कमी से बाधित सेवाओं में संकुचन के कारण सकल घरेलू उत्पाद 2022 की दूसरी तिमाही में 0.3 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही एसएएआर) की कमी आई। कुछ फर्मों में सामान्य से अधिक क्षमता उपयोग के साथ-साथ श्रम बाजार सख्त बना हुआ है। विनिर्माण उत्पादन में भारी गिरावट और सेवा व्यवसाय गतिविधि में मंदी के कारण अगस्त 2022 में संमिश्र पीएमआई घटकर 49.6 हो गया जो 18 महीनों में पहला संकुचन है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, ऊर्जा और व्यापार योग्य वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि के ब्रिटेन के परिवारों की वास्तविक आय पर प्रतिकूल प्रभाव के तहत, 2022 की तीसरी तिमाही से शुरू होकर 2023 के अंत तक मंदी का पूर्वानुमान लगाया है।

पहली तिमाही में निकट गतिहीनता के बाद कोविड-19 के प्रतिबंधों के हटने के साथ निजी खपत में तेजी और लगातार दूसरी तिमाही के लिए सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण 2022 की दूसरी तिमाही में जापान के सकल घरेलू उत्पाद में 3.5 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही एसएएआर) की वृद्धि हुई। निभावकारी मौद्रिक नीति के कारण रोजगार और आय की स्थिति में सामान्य

[1] पीएमआई के संदर्भ एस एंड पी ग्लोबल इंडेक्स के लिए हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

रूप से सुधार हुआ। विनिर्माण और सेवा कंपनियों दोनों के उत्पादन में गिरावट के कारण संमिश्र पीएमआई (*एयू जिबुन* बैंक) अगस्त 2022 में 49.4 पर तेजी से गिरा जो कि फरवरी के बाद पहला संकुचन था। दमित मांग में कमी और वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से भविष्य में संवृद्धि की गति धीमी होने की अपेक्षा है।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच, चीन की जीडीपी संवृद्धि 2022 की पहली तिमाही में 4.8 प्रतिशत थी जो कि दूसरी तिमाही में तेजी से गिरकर 0.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) कम हुई जो 30 वर्षों में दूसरी सबसे खराब तिमाही संवृद्धि रही (सारणी V.1)। कोविड से संबंधित लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध के साथ स्थावर संपदा क्षेत्र में भारी गिरावट और ऊर्जा की कमी के कारण 2022 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में तिमाही-दर-तिमाही(वार्षिक) आधार पर 10 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2022 की पहली छमाही में 2.6 प्रतिशत(वर्ष-दर-वर्ष) की संवृद्धि, 2022 के 5.5 प्रतिशत के वार्षिक विकास लक्ष्य से कम थी। अगस्त में संमिश्र पीएमआई (कैक्सिन) 53.0 पर था जो कि सेवा गतिविधि में विस्तार से संचालित था जिसमें विनिर्माण विकास में एक उल्लेखनीय मंदी समायोजित हुई आगे देखते हुए, शून्य-कोविड नीति, बाधित बिजली आपूर्ति और स्थावर संपदा क्षेत्र में तरलता संकट का आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना है।

अन्य बड़ी ईएमई के बीच, ब्राजील की जीडीपी विकास दर निजी और सरकारी खर्च और निवेश के कारण 2022 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 3.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई जो कि पहली तिमाही में 1.7 प्रतिशत थी। जून में बेरोजगारी दर गिरकर कई साल के निचले स्तर पर आ गई। विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय मंदी के साथ, सम्मिश्र पीएमआई अगस्त में घटकर 53.2 पर आ गया। आगे चलकर , सख्त मौद्रिक स्थितियां, दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति और युद्ध संबंधी अनिश्चितता विकास परिदृश्य के लिए प्रमुख जोखिम बने हुए हैं। क्वाज़ुलु-नताल क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ और औद्योगिक गतिविधि में बाधा डालने वाली बिजली अनुभाजन के कारण दक्षिण अफ्रीका की जीडीपी वृद्धि दूसरी तिमाही में तेजी से 0.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक गिर गई। जुलाई के, 14 महीने में सबसे उच्च, 52.7 की तुलना में, अगस्त 2022 में सम्मिश्र पीएमआई कम होकर 51.7 की कगार पर आ गया। आगे, निम्न टीकाकरण दर के कारण आया कोविड-19 संक्रमणों का जोखिम, कमजोर रोजगार संभावनाएं और विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आर्थिक गतिविधियों पर असर डाल सकते हैं। यूक्रेन से हुए युद्ध के नतीजों एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में रूसी अर्थव्यवस्था 4.1 प्रतिशत तक (वर्ष-दर-वर्ष) संकुचित हुई। उपभोक्ता गतिविधि मंद बनी

सारणी V.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि

(प्रतिशत)

देश	ति3-2021	ति4-2021	ति1-2022	ति2-2022	2021	2022 (पी)	2023 (पी)
तिमाही-दर-तिमाही मौसमी समायोजित वार्षिकीकृत दर (ति-दर-ति, एसएएआर)							
कनाडा	5.3	6.6	3.1	3.3			
यूरो क्षेत्र	9.0	2.0	2.7	3.1			
जापान	-1.8	3.9	0.2	3.5			
दक्षिण कोरिया	0.9	5.5	2.6	3.0			
यूके	3.8	5.2	3.1	-0.3			
यूएस	2.7	7.0	-1.6	-0.6			
वर्ष-दर-वर्ष							
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ							
कनाडा	3.8	3.2	2.9	4.6	4.5	3.4	1.8
यूरो क्षेत्र	3.7	4.6	5.4	4.1	5.4	2.6	1.2
जापान	1.2	0.5	0.6	1.6	1.7	1.7	1.7
दक्षिण कोरिया	4.1	4.4	3.0	2.9	4.1	2.3	2.1
यूके	6.9	6.6	8.7	2.9	7.4	3.2	0.5
यूएस	5.0	5.7	3.7	1.8	5.7	2.3	1.0
उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ							
ब्राज़ील	4.0	1.7	1.7	3.2	4.6	1.7	1.1
चीन	4.9	4.0	4.8	0.4	8.1	3.3	4.6
भारत	8.4	5.4	4.1	13.5	8.7	7.4	6.1
इंडोनेशिया	3.5	5.0	5.0	5.4	3.7	5.3	5.2
फिलीपींस	7.0	7.8	8.2	7.4	5.7	6.7	5.0
रूस	4.0	5.0	3.5	-4.1	4.7	-6.0	-3.5
दक्षिण अफ्रीका	3.0	1.7	2.7	0.2	4.9	2.3	1.4
थाईलैंड	-0.2	1.8	2.3	2.5	1.5	2.8	4.0

मेमो:

विश्व	2021	2022 (पी)	2023 (पी)
वर्ष-दर-वर्ष			
उत्पादन	6.1	3.2	2.9
व्यापार मात्रा	10.1	4.1	3.2

पी: पूर्वानुमान।

टिप्पणी: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के अनुरूप है। उदा. अप्रैल 2021 - मार्च 2022 वर्ष 2021 से संबंधित है।

स्रोत: आधिकारिक सांख्यिकीय एजेंसी; ब्लूमबर्ग; और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डब्ल्यूईओ अपडेट, जुलाई 2022; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी V.2: ब्रिक्स[2] अर्थव्यवस्थों के लिए चुनिंदा समष्टि आर्थिक संकेतक

वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर वर्ष-दर-वर्ष, (प्रतिशत)	देश	2021	2022(पी)	2023(पी)	सामान्य सरकारी सकल ऋण (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)	देश	2021	2022(पी)	2023(पी)
	ब्राज़ील	4.6	1.7	1.1		ब्राज़ील#	93.0	91.9	92.8
	रूस	4.7	-6.0	-3.5		रूस	17.0	16.8	18.9
	भारत	8.7	7.4	6.1		भारत	86.8	86.9	86.6
	चीन	8.1	3.3	4.6		चीन	73.3	77.8	81.8
	दक्षिण अफ्रीका	4.9	2.3	1.4		दक्षिण अफ्रीका	69.1	70.2	73.4
सीपीआई मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)	**देश**	**2021**	**2022(पी)**	**2023(पी)**	**चालू खाता शेष (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)**	**देश**	**2021**	**2022(पी)**	**2023(पी)**
	ब्राज़ील	8.3	8.2	5.1		ब्राज़ील	-1.7	-1.5	-1.6
	रूस	6.7	21.3	14.3		रूस	6.9	12.4	8.1
	भारत	5.5	6.1	4.8		भारत	-1.2	-2.9	-2.5
	चीन	0.9	2.1	1.8		चीन	1.8	1.1	1.0
	दक्षिण अफ्रीका	4.5	5.7	4.6		दक्षिण अफ्रीका	3.7	1.3	-1.0
सामान्य सरकारी निवल उधार/ कर्ज (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)	**देश**	**2021**	**2022(पी)**	**2023(पी)**	**विदेशी मुद्रा भंडार * (अमेरिकी डॉलर में)**	**देश**	**2020**	**2021**	**2022**
	ब्राज़ील	-4.4	-7.6	-7.4		ब्राज़ील	355.6	362.2	339.7
	रूस	0.7	-4.0	-5.3		रूस	596.1	630.6	565.7
	भारत	-10.4	-9.9	-9.1		भारत	588.4	635.3	545.7
	चीन	-6.0	-7.7	-7.1		चीन	3536.0	3606.2	3454.4
	दक्षिण अफ्रीका	-6.4	-5.8	-6.1		दक्षिण अफ्रीका	54.2	57.8	59.6

पी: पूर्वानुमान|

*: 2022 के लिए विदेशी मुद्रा भंडार चीन और दक्षिण अफ्रिका (जुलाई 2022) और भारत (16 सितंबर 2022) को छोड़कर अगस्त 2022 से संबंधित है।

#: सकल ऋण का तात्पर्य गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र से है जिसमें एलेट्रोब्रास और पेट्रोब्रास को छोड़कर केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए स्वायत्त ऋण शामिल हैं।

टिप्पणी: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से संबंधित है।

स्रोत: आधिकारिक सांख्यिकीय एजेंसियां; डब्ल्यूईओ अप्रैल 2022 डाटाबेस और जुलाई 2022 अपडेट; आईएमएफ; राजकोषीय मॉनिटर अपडेट, अप्रैल 2022, आईएमएफ; और इंटरनैशनल रिजर्व एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी (आईआरएफसीएल), आईएमएफ।

रही किन्तु अब इसमें सुधार शुरू हो रहा है, वहीं निवेश, प्रतिबंधों एवं पूंजी बहिर्गमन का समाघात सह रहा है। बढ़ती हुई ऊर्जा कीमतों ने बाह्य क्षेत्र की धारणीयता को अपेक्षाकृत रूप से बेहतर बनाए रखने में सहायता दी है। युद्ध एवं प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023, दोनों में, अर्थव्यवस्था के संकुचन की संभावना है (सारणी V.2)।

वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में, युद्ध के कारण कम हुई मांग के चलते, एएसईएएन[3] अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि मंद हुई। इन अर्थव्यवस्थाओं के विनिर्माण पीएमआई ने, उत्पादन एवं मांग आदेशों में विस्तार एवं बेरोजगार और क्रय गतिविधि में वृद्धि के चलते, व्यावसायिक स्थितियों में सुधार की ओर संकेत दिया। आपूर्ति व्यवधानों एवं कमज़ोर निर्यात के अधिप्लावित प्रभावों के कारण, चीन में आई मंदी इस भूभाग में जोखिम का प्रमुख मूल स्रोत है।

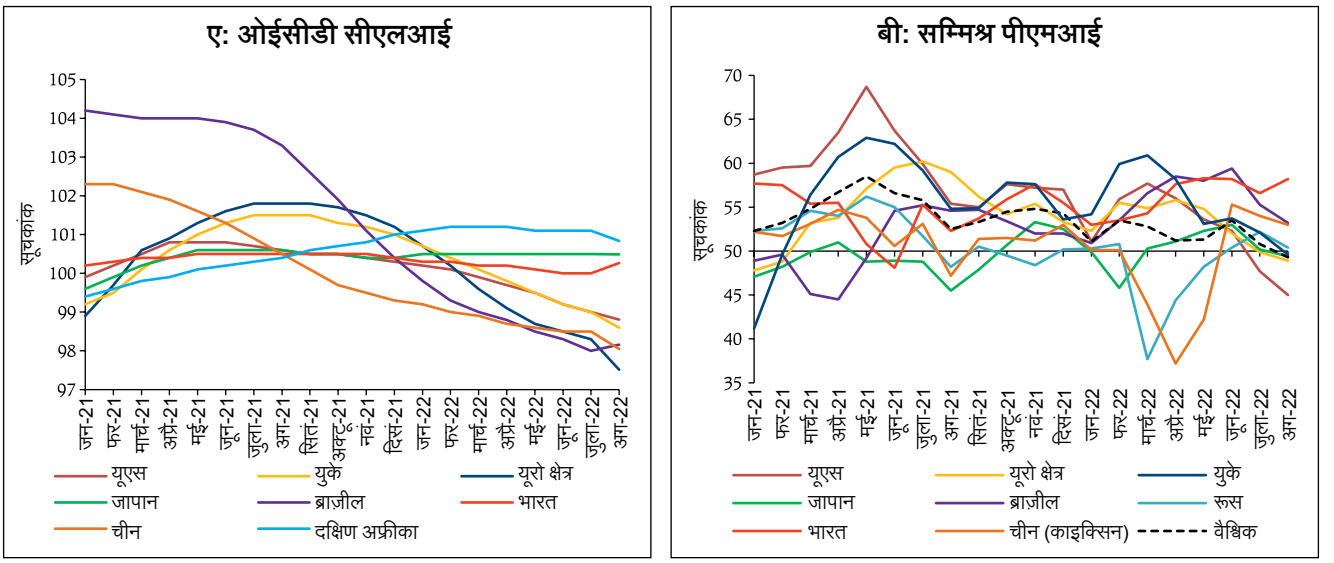
उच्च आवृत्ति के संकेतकों में, ओईसीडी सम्मिश्र अग्रता संकेतक अगस्त 2022 में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए रुझान से नीचे बना रहा, जो कि बहुदशकीय उच्च मुद्रास्फीति, उपभोक्ता विश्वास में कमी और स्टॉक कीमतों में गिरावट के कारण बने अवनति के परिदृश्य की ओर संकेत करता है (चार्ट V.1ए)। वैश्विक सम्मिश्र पीएमआई जुलाई के 50.8 से गिरकर अगस्त में 49.3 हो गया, जो कि सेवाओं एवं विनिर्माण दोनों के उत्पादन में गिरावट के साथ, जून 2020 से पहली बार,वैश्विक उत्पादन के संकुचन को दर्शाता है (चार्ट V.1बी)।

युद्ध और एक ख़स्ता-हाल समष्टि-आर्थिक वातावरण में वैश्विक संवृद्धि में हुई मंदी के कारण विश्व व्यापार में वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में शुरू हुआ समभाव, वर्ष 2022 की पहली छमाही में तीव्रीकृत हो गया (चार्ट V.2ए)। इसे दर्शाते हुए, पण्य व्यापार मात्रा की वृद्धि 2022 की पहली तिमाही में रहे 4.6 प्रतिशत से

[2] ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

[3] दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (एएसईएएन) में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम शामिल हैं।

चार्ट V.1: सर्वेक्षण संकेतक



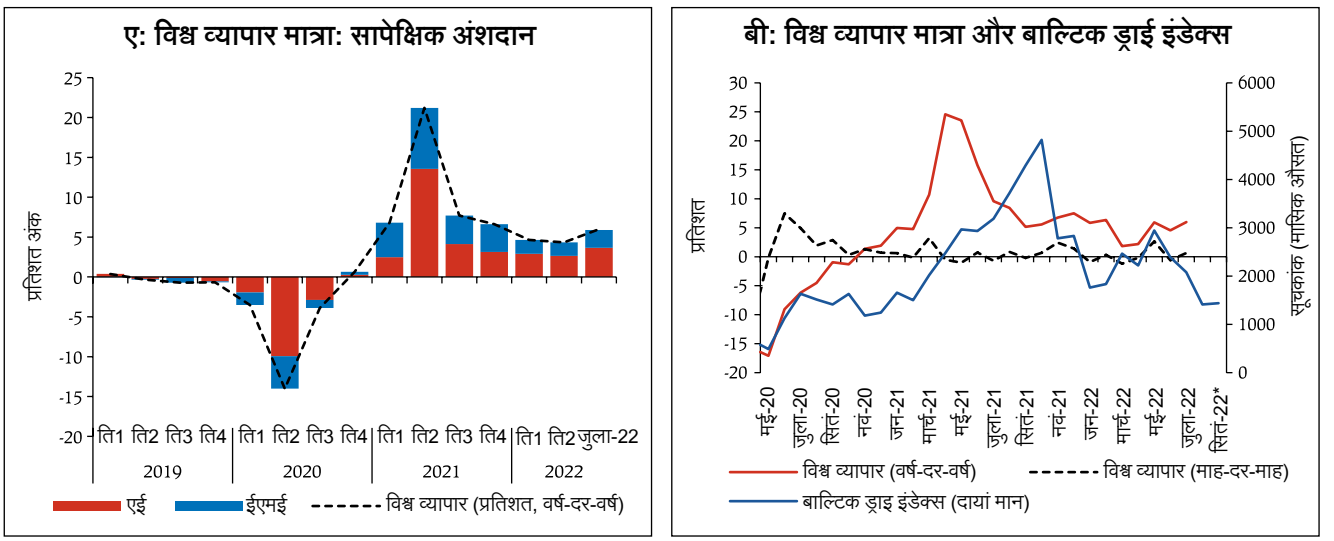
स्रोत: ओईसीडी; और ब्लूमबर्ग।

घटकर 2022 की दूसरी तिमाही में 4.3 प्रतिशत हो गई; तथापि जुलाई 2022 में इसमें तेजी दिखी। डबल्यूटीओ यह उम्मीद करता है कि व्यापार विस्तार संवृद्धि, वर्ष 2021 के 9.8 प्रतिशत से वर्ष 2022 में 3.0 प्रतिशत तक संयत हो जाएगी। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो कि कोयला एवं लौह खनिज जैसे थोक पण्यों के एक व्यापक समूह की लदान लागत को मापता है, भी सितंबर 2022 में संयत हुआ – यह अक्तूबर 2021 के अपने शीर्ष स्थान से 70.1 प्रतिशत नीचे आ गया है लेकिन अपने कोविड-पूर्व स्तर से ऊपर बना हुआ है (चार्ट V.2बी)।

V.2 पण्य कीमतें एवं मुद्रास्फीति

युद्ध के बाद, फरवरी से वैश्विक पण्य कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है। युद्ध शुरू होते ही मार्च-मई 2022 के दौरान पण्य-कीमतों में, आरंभ में 14.7 प्रतिशत (ब्लूमबर्ग

चार्ट V.2: विश्व व्यापार मात्रा

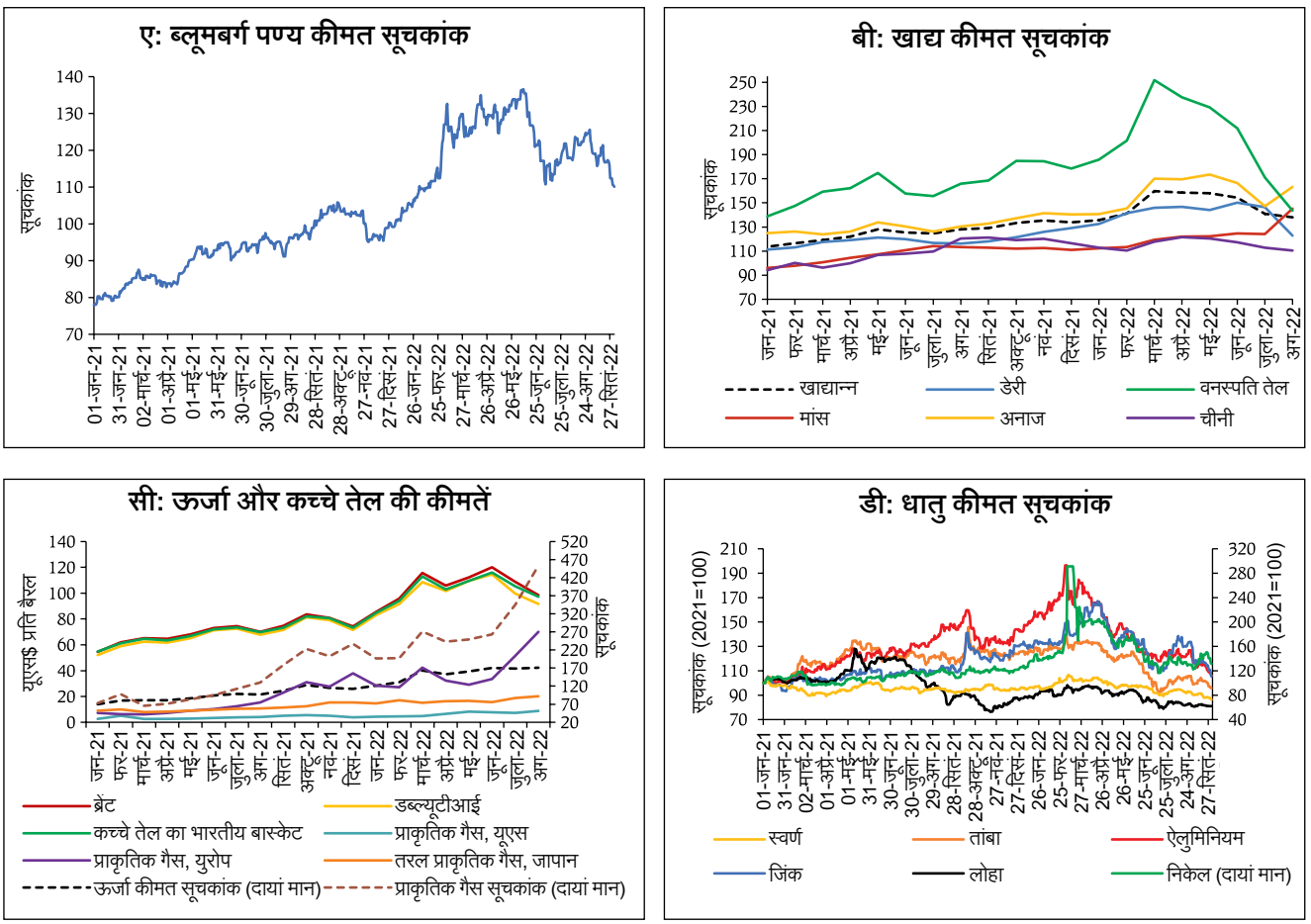


*: सितंबर-22 के लिए डेटा 1- 27 सितंबर, 2022 का है।
स्रोत: सीपीबी नीदरलैंड्स; और सीएआईसी।

कमोडिटी प्राइस इंडेक्स के अनुसार) की वृद्धि हुई। तब (जून-28 सितंबर 2022) से, कीमतों में 14.2 प्रतिशत की गिरावट आई है क्योंकि धीमे होते हुये वैश्विक विकास ने मांग को कम कर दिया है। इस सुधार के बावजूद, ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में वर्ष में अब तक (28 सितंबर तक) 13.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है (चार्ट V.3ए)। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार मौसमी उत्पादन में वृद्धि और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों में कमी ने आपूर्ति की स्थिति को कुछ सहज बनाया जिससे वैश्विक खाद्य कीमतें अगस्त 2022 में 13.6 प्रतिशत घटीं जो मार्च के दौरान सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर थीं। हालांकि, 2022 (अगस्त तक) में सूचकांक 3.2 फीसदी बढ़ा (चार्ट V.3बी)।

2022 की पहली छमाही में कच्चे तेल की कीमतें अत्यधिक अस्थिर थीं। अप्रैल और जुलाई के बीच युद्ध और प्रतिबंधों से संबंधित अनिश्चितता के कारण, अत्यधिक तंग आपूर्ति स्थितियों के चलते, कीमतें यूएस $100 प्रति बैरल से ऊपर रहीं (चार्ट V.3सी)। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) एवं संगठन में शामिल अन्य देशों *(प्लस)* ने बहुत कम इन्वेंट्री के साथ उत्पादन मात्रा में सावधानी बरतते हुए परिवर्तन जारी रखे। ओपेक *प्लस* ने अगस्त 2022 में प्रति दिन 100,000 बैरल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया लेकिन सितंबर में उसने अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्पादन में उतनी ही मात्रा की कटौती करने का फैसला किया। धीमी वैश्विक मांग, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और ईरानी आपूर्ति उपलब्ध होने की उम्मीदों के कारण, जुलाई-सितंबर

चार्ट V.3: पण्य कीमतें



स्रोत: एफएओ; विश्व बैंक; और ब्लूमबर्ग।

2022 के दौरान कच्चे तेल की कीमतें तेजी से घटीं। फिर भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में वर्ष में अब तक (28 सितंबर तक) 15.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। युद्ध के बाद से प्राकृतिक गैस की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है; अगस्त 2022 में कीमतें (विश्व बैंक के प्राकृतिक गैस सूचकांक के अनुसार) वर्ष के प्रारंभ से अब तक 91.7 प्रतिशत और वर्ष-दर-वर्ष 249.2 प्रतिशत अधिक थीं।

ब्लूमबर्ग के बेस मेटल स्पॉट इंडेक्स द्वारा मापी गई सामान्य धातु कीमतों में, जो युद्ध के कारण 17.1 प्रतिशत बढ़ गई थी, अप्रैल और सितंबर 2022 (28 सितंबर तक) के बीच 34.8 फीसदी की नरमी आई जो कमजोर वैश्विक संभावनाओं को दर्शाता है। अप्रैल के बाद से सोने की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई और बॉन्ड प्रतिफल सख्त होने और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण, यह सितंबर में 1,618 अमेरिकी डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के निचले स्तर पर पहुंच गई। अगस्त में ज़िंक और एल्यूमीनियम जैसी कुछ धातुओं के उत्पादन में उच्च ऊर्जा कीमतों के कारण कटौती ने इसकी कीमत को सहारा दिया। हालांकि, सितंबर में कीमतें अन्य धातुओं की कीमतों की तरह गिरने लगीं (चार्ट V.3डी)।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

खाद्य और ऊर्जा की उच्च कीमतों से लागत में वृद्धि के निरंतर दबाव, बढ़ती मजदूरी लागत तथा महामारी के शेष प्रभाव से उत्पन्न आपूर्ति शृंखला बाधाओं और कई अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू मांग बड़ी मात्रा में पुन: बढ़ जाने से कीमतों पर पड़े दबाव के कारण सभी अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि होती गई। 2022 में अब तक हेडलाइन मुद्रास्फीति सभी एई और ईएमई में मुद्रास्फीति लक्ष्यों से पार हो गई (सारणी V.3)। उच्च ऊर्जा और खाद्य कीमतें मुद्रास्फीति में उछाल के प्रमुख चालक रहे। वस्तुओं की मुद्रास्फीति आम तौर पर सेवाओं की तुलना में बहुत अधिक रहती है, यद्यपि इधर कुछ समय से सेवा क्षेत्र ने भी गति पकड़ना शुरू कर दिया है। लागत-प्रेरित (कॉस्ट-पुश) आघातों और मांग-प्रेरित (डिमांड-पुल) दबावों की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण कई अर्थव्यवस्थाओं में कोर मुद्रास्फीति भी ऊंचे स्तर पर कायम है।

ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण जून 2022 में यूएस में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 40 साल के उच्चतम स्तर 9.1 प्रतिशत तक पहुंच गई। गेसोलीन की कीमतों में गिरावट के कारण अगस्त में यह घटकर 8.3 प्रतिशत

सारणी V.3: उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

(प्रतिशत)

देश	मुद्रास्फीति का लक्ष्य	ति3: 2021	ति4: 2021	ति1: 2022	ति2: 2022	जुलाई 2022	अगस्त 2022
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ							
कनाडा	2.0	4.1	4.7	5.8	7.5	7.6	7.0
यूरो क्षेत्र	2.0	2.9	4.7	6.1	8.0	8.9	9.1
जापान	2.0	-0.2	0.5	0.9	2.5	2.6	3.0
दक्षिण कोरिया	2.0	2.5	3.6	3.8	5.4	6.3	5.7
यूके	2.0	2.8	4.9	6.2	9.2	10.1	9.9
यूएस	2.0	5.4 (4.3)	6.7 (5.5)	8.0 (6.3)	8.7 (6.5)	8.5 (6.3)	8.3
उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ							
ब्राज़ील	3.50 ± 1.5	9.6	10.5	10.7	11.9	10.1	8.7
रूस	4.0	6.9	8.3	11.5	16.9	15.1	14.3
भारत	4.0 ± 2.0	5.1	5.0	6.3	7.3	6.7	7.0
चीन		0.8	1.8	1.1	2.2	2.7	2.5
दक्षिण अफ्रीका	3.0-6.0	4.8	5.5	5.8	6.6	7.8	7.6
मेक्सिको	3.0 ± 1.0	5.8	7.0	7.3	7.8	8.2	8.7
इंडोनेशिया	3.0 ± 1.0	1.6	1.8	2.3	3.8	4.9	4.7
फिलीपींस	3.0 ± 1.0	4.1	3.6	3.3	5.5	6.4	6.3
थाईलैंड	1.0-3.0	0.7	2.4	4.7	6.5	7.6	7.9
तुर्की	5.0	19.3	25.8	54.8	74.0	79.6	80.2

टिप्पणी: (1) यूएस के लिए मुद्रास्फीति व्यक्तिगत उपभोग व्यय मूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन के संदर्भ में है।
(2) बैंक ऑफ कनाडा का लक्ष्य मुद्रास्फीति को 1-3 प्रतिशत की मुद्रास्फीति नियंत्रण लक्ष्य सीमा के 2 प्रतिशत मध्य-बिंदु पर रखना है।
(3) 2021 के लिए ब्राजील का मुद्रास्फीति लक्ष्य 3.75 ± 1.5 प्रतिशत था।

स्रोत: सेंट्रल बैंक वेबसाइट; और ब्लूमबर्ग।

हो गई। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक, जिसे फेडरल रिज़र्व (फेड) द्वारा प्राथमिकता दी जाती है, के अनुसार मुद्रास्फीति जून के 6.8 प्रतिशत से घटकर जुलाई में 6.3 प्रतिशत हो गयी, जिसका मुख्य कारण था टिकाऊ और गैर-टिकाऊ वस्तुओं, दोनों की कीमतों में कमी आना जबकि, सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई। कोर पीसीई मुद्रास्फीति मार्च के 5.2 प्रतिशत से घटकर जुलाई में 4.6 प्रतिशत हो गई (चार्ट V.4ए)।

यूरो क्षेत्र में, सीपीआई मुद्रास्फीति अगस्त 2022 में 9.1 प्रतिशत की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई, जो जुलाई 2021 से यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी ऊपर है। ऊर्जा की कीमतों, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस और साथ ही खाद्य कीमतों, में तेज वृद्धि, मुद्रास्फीति का प्रमुख का कारण बनी रही। गैर-ऊर्जा औद्योगिक सामान, परिवहन और उर्वरक लागत ने भी कीमतों पर दबाव डाला । यूके में सीपीआई मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़कर 10.1 प्रतिशत हो गई – जो जनवरी

1997 में डेटा की उपलब्धता के बाद से सर्वाधिक - तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर है, जिसमें आवास और घरेलू सेवाएं, परिवहन और खाद्य प्रमुख कारक थे। अगस्त में यह मामूली रूप से घटकर 9.9 प्रतिशत हो गई क्योंकि परिवहन उपसूचकांक में गिरावट आई। जापान में, ताज़ा खाद्य को छोड़कर सभी वस्तुओं में सीपीआई मुद्रास्फीति, जिससे बैंक ऑफ जापान द्वारा लक्ष्य मापा जाता है, में बढ़ोतरी हुई और वह अगस्त में 2.8 प्रतिशत तक बढ़ गयी, जो 7 वर्षों में सबसे अधिक है। यह अप्रैल 2022 से 2 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर चली गई है। ईंधन और खाद्य लागत में वृद्धि के साथ-साथ तेजी से कमजोर होते येन के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति भी जुलाई के 2.6 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2022 में 3.0 प्रतिशत हो गई।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तरह, प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति ऊंची बनी रही और संबंधित लक्ष्यों से काफी ऊपर रही। ब्राजील में सीपीआई मुद्रास्फीति अगस्त 2022 में 8.7 प्रतिशत थी (चार्ट V.4बी)। रूस में, प्रतिबंधों और रूबल के तेज अवमूल्यन के कारण, मुद्रास्फीति फरवरी के 9.2 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में 17.8 प्रतिशत हो गई। इसके पश्चात मुद्रा में आंशिक मूल्यवृद्धि के कारण यह अगस्त में धीरे-धीरे घटकर 14.3 प्रतिशत पर आ गई। दक्षिण अफ्रीका में परिवहन ईंधन, खाद्य और गैर-मादक पेय पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति अगस्त में 7.6 प्रतिशत तक बढ़ गई – वह मई 2022 से केंद्रीय बैंक की लक्षित सीमा से अधिक रही। चीन में सीपीआई मुद्रास्फीति नरम रही, हालांकि मार्च-जुलाई 2022 के दौरान, मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में उछाल और मांग में मजबूत सुधार के कारण, यह तेज हो गई। तथपि अगस्त में यह नरम होकर 2.5 प्रतिशत हो गई क्योंकि खाद्य और गैर-खाद्य सूचकांक नरम हुए।

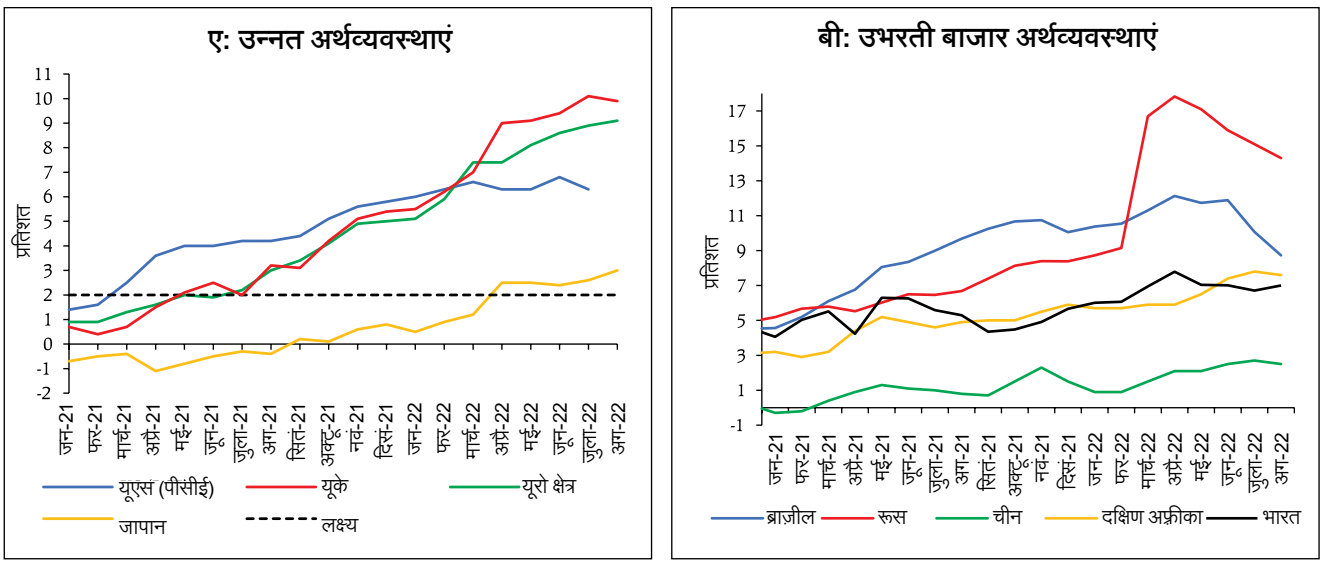
V.3 मौद्रिक नीति रुख

मुद्रास्फीति की दर दशकों के अपने उच्चतम स्तर और लक्ष्य से काफी अधिक हो जाने के कारण, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने, आर्थिक गतिविधि गति कम हो जाने के बावजूद, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को सीमा में रखने के लिए 2022 में सामान्य से अधिक दर वृद्धि के साथ आक्रामक मौद्रिक कठोरता का सहारा लिया। कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक 2021 से ही कठोरता का रुख अपनाए हुए थे।

सार्वत्रिक रूप से समान मौद्रिक सख्ती ने यह प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि क्या इससे मंदी आएगी या केंद्रीय बैंक सामान्य स्थिति प्राप्त कर पाएंगे (बॉक्स V.1)।

मार्च 2022 में कठोरता चक्र शुरू करने के बाद, यूएस फेड ने अपनी सभी उत्तरवर्ती नीतिगत बैठकों में दरों में बढ़ोत्तरी की। यूएस फेड ने मई में फेडरल निधि दर में 50 बीपीएस की वृद्धि की। इसके बाद जून, जुलाई और सितंबर की बैठकों में 75 बीपीएस की वृद्धि हुई – इस प्रकार मौजूदा कठोरता चरण में 300 बीपीएस की

चार्ट V:4 सीपीआई मुद्रास्फीति -चुनिन्दा अर्थव्यवस्थाएं



स्रोत: आधिकारिक सांख्यिकीय एजेंसियां; और ब्लूमबर्ग।

बॉक्स V.1: उच्च मुद्रास्फीति और आक्रामक मौद्रिक सख्ती: सॉफ्ट या हार्ड लैंडिंग ?

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 1970 और 1980 के दशक के बाद से मुद्रास्फीति की दर अपने उच्चतम स्तर पर और लक्ष्य से काफी अधिक होने की परिस्थिति में केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रण में रखने और मुद्रास्फीति को लक्ष्य के करीब लाने के लिए दरों में बढ़ोतरी की गति और मात्रा बढ़ा दी है। ऐसे में यह चिंता उभर रही है कि एक साथ सार्वत्रिक मौद्रिक सख्ती कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी (एक हार्ड लैंडिंग) में न ले जाए। केंद्रीय बैंकों को उम्मीद है कि वे एक अनुकूल स्थिति (सॉफ्ट लैंडिंग) (आर्थिक गतिविधियों में अत्यधिक संकुचन के बजाय संवृद्धि की गति में कमी करके) निर्माण करने में सक्षम होंगे (बीआईएस, 2022; ब्लाइंडर, 2022)।

1997 की पहली तिमाही से – 2022 की दूसरी तिमाही की अवधि में 8 देशों के 23 कठोरता चक्रों का पैनल विश्लेषण बताता है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं दोनों के संबंध में, सॉफ्ट लैंडिंग की तुलना में हार्ड लैंडिंग से पहले मुद्रास्फीति का औसत स्तर बहुत अधिक होता है[4] (सारणी V.I.1) । सख्ती का दौर शुरू होने से पहले यदि कम जीडीपी संवृद्धि का दौर हो तो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हार्ड लैंडिंग की संभावना बढ़ जाती है। उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में उच्च जीडीपी के साथ-साथ यदि उच्च मुद्रास्फीति हो हार्ड लैंडिंग की स्थिति निर्माण होती है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के मामले में, मौद्रिक कठोरता की शुरुआत से पहले यदि राजकोषीय घाटा और लोक ऋण अधिक हो तो कठोर रुख अपनाने के बाद उनके मंदी में जाने का जोखिम बढ़ जाता है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के एक नमूने का औपचारिक पैनल लॉगिट रिग्रेशन विश्लेषण यह इंगित करता है कि यदि मौद्रिक कठोरता से पहले उच्च मुद्रास्फीति, उच्च जीडीपी वृद्धि और ऋण/जीडीपी के अनुपात में उच्च वृद्धि हो तो हार्ड लैंडिंग की संभावना बढ़ जाती है; वहीं दूसरी ओर यह प्रतीत होता है कि कठोरता वाले दौर की शुरुआत से पहले यदि वास्तविक नीतिगत दरें उच्च हों तो वित्तीय जोखिम निर्माण (बिल्डिंग अप ऑफ फिनान्शियल एक्सेसेस) कम हो जाने पर हार्ड लैंडिंग की संभावना कम हो सकती है (समीकरण 1)।

मौजूदा समय में, मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर चल रही है जबकि बेरोजगारी दर कम बनी रहने के बावजूद जीडीपी वृद्धि दर धीमी पड़ रही है। यह व्यापक मिश्रित स्थिति इन अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिकूल स्थिति को बढ़ाती है।

सारणी V.I.1: समष्टि आर्थिक कारक - हार्ड और सॉफ्ट लैंडिंग

	चर	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं		उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं	
		सॉफ्ट लैंडिंग	हार्ड लैंडिंग	सॉफ्ट लैंडिंग	हार्ड लैंडिंग
कठोरता चक्र की शुरुआत में स्थितियां[5]	मुद्रास्फीति (%)	1.5***	2.2***	4.0**	4.9**
	जीडीपी वृद्धि (%)	3.3*	2.5*	3.1*	4.4*
	वास्तविक नीतिगत दर (%)	3.5***	0.0***	2.3***	4.2***
	जीडीपी के अनुपात में घरेलू ऋण में परिवर्तन (% अंक) [6]	0.7	0.5	-0.7*	0.1*
	जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटा (% अंक)	-1.6	-3.1	-1.5	-2.2
	जीडीपी के अनुपात में ऋण (% अंक)	37.4	56.0	37.9	48.9
कठोरता के दौरान की स्थितियां	वास्तविक नीतिगत दर वृद्धि (% अंक)	-0.1	2.0	1.2	0.6
	औसत त्रैमासिक वास्तविक दर वृद्धि (% अंक)	0.0	0.1	0.1	0.0
	कठोरता की अवधि (तिमाहियां)	6.0	10.3	5.2	6.4

टिप्पणी: ***,**,* छात्रों के टी परीक्षण का उपयोग करके हार्ड और सॉफ्ट लैंडिंग के बीच साधनों की समानता का परीक्षण करने के लिए क्रमशः 1%, 5% और 10% पर महत्व के स्तर को निरूपित करें।
स्रोत: बीआईएस; ब्लूमबर्ग; आईएमएफ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2022)। बीआईएस एनुअल इकनॉमिक रिपोर्ट 2022 (बॉक्स 1 सी: "हाऊ लाइकली इज़ अ सॉफ्ट लैंडिंग ?")।

ब्लाइंडर, ए., (2022) "ऑन लैंडिंग्स हार्ड एंड सॉफ्ट: दी फ़ेड, 1965-2020", मार्कस अकादमी में व्याख्यान, फरवरी, https://bcf.princeton.edu/events/alan-blinder-on-landings-hard-and-soft-the-fed-1965-2020/.

$$\text{संभावना (हार्ड लैंडिंग)}_t = \underset{(0.000)}{-3.99} + \underset{(0.004)}{0.31}\ \text{सीपीआई}_{t-1} + \underset{(0.056)}{0.30}\ \text{जीडीपी}_{t-1} - \underset{(0.021)}{0.15}\ \text{आरपीआर}_{t-1} + \underset{(0.100)}{1.34}\ \text{क्रेडिट}_{t-1} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

सीपीआई, जीडीपी, आरपीआर और क्रेडिट का संदर्भ क्रमशः उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति, वास्तविक जीडीपी वृद्धि, वास्तविक नीति दर और क्रेडिट / जीडीपी अनुपात में परिवर्तन के चार-तिमाही औसतों से है। कोष्ठक में आंकड़े पी-वैल्यू हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान

[4] इस विश्लेषण के उद्देश्य के लिए हार्ड लैंडिंग, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मामले में 2 या अधिक लगातार तिमाहियों के लिए नकारात्मक जीडीपी विकास दर (वर्ष-दर-वर्ष) है; ईएमई के मामले में, यह नमूना अवधि में औसत जीडीपी विकास दर से लगातार 2 या अधिक तिमाहियों के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 60 प्रतिशत (या अधिक) की गिरावट है। दूसरी ओर, सॉफ्ट लैंडिंग से तात्पर्य कठोर दौर के बाद तीन वर्षों के भीतर कोई मंदी नहीं होने का परिदृश्य है जिसमें नीति दर कम से कम तीन लगातार तिमाहियों और अत्युच्च अवसरों पर बढ़ाई गई हों।

[5] कठोरता चक्र की शुरुआत से एक साल पहले।

[6] कठोर चक्र से पहले एक वर्ष के दौरान ऋण वृद्धि में औसत तिमाही परिवर्तन

संचयी बढ़ोत्तरी हुई। उसने जून-अगस्त के दौरान अपने तुलन पत्र को 47.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति माह और सितंबर से 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति माह कम करने के लिए मात्रात्मक कड़ाई की योजनाओं की भी घोषणा की। सितंबर 2022 में जारी किए गए आर्थिक पूर्वानुमानों के सारांश के अनुसार, माध्य फेडरल फंड दर 2022 के अंत तक 4.4 प्रतिशत और 2023 के अंत तक 4.6 रहेगी।

तेजी से बढ़ते मुद्रास्फीति दबावों के मध्य, ईसीबी ने अपनी जून 2022 की बैठक में 1 जुलाई 2022 तक के आस्ति खरीद कार्यक्रम (एपीपी) के तहत निवल आस्ति खरीद को समाप्त करने का निर्णय लिया, जबकि अपने महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम (पीईपीपी) के तहत परिपक्व प्रतिभूतियों का पुनर्निवेश कम से कम 2024 के अंत तक जारी रखेगा। बढ़ती मुद्रास्फीति स्थिति को देखते हुए ईसीबी ने वर्ष के आरंभिक समय में, दरों में वृद्धि करते हुए जुलाई में 50 बीपीएस और सितंबर में 75 बीपीएस की बढ़ोत्तरी की। दिसंबर 2021 में शुरू हुए सख्ती के चक्र को जारी रखते हुए, बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने मई और जून 2022, दोनों बैठकों में अपनी नीतिगत दर 25 बीपीएस और अगस्त एवं सितंबर की प्रत्येक बैठक में 50 बीपीएस बढ़ा दी, जिससे बैंक दर 2.25 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही, समिति ने सितंबर से शुरू होने वाले बारह महीनों में अपने गिल्ट के स्टॉक में 80 बिलियन पाउंड को कम करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया।[7] गिल्ट बिक्री कार्यक्रम की शुरुआत के साथ-साथ, बीओई ने अल्पावधि बाजार दरों को बैंक दर के आस-पास रखने में मदद की दृष्टि से एक नई अल्पावधि रेपो (एसटीआर) सुविधा शुरू करने का भी निर्णय लिया।

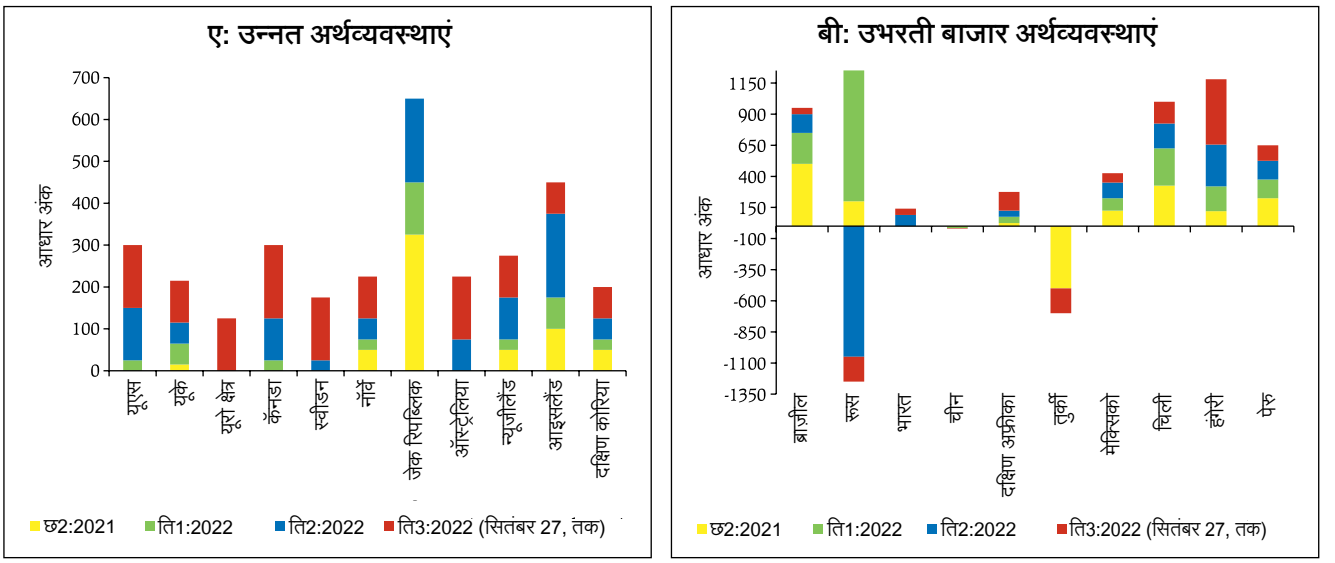
अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) ने भी महामारी के कारण शुरू किए गए उपायों को कम करते हुए और अपनी मौद्रिक स्थितियों को सामान्य करना शुरू कर दिया है। बैंक ऑफ कनाडा ने मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मात्रात्मक सख्ती के साथ-साथ अप्रैल से अपनी नीतिगत दर में 275 बीपीएस की - अप्रैल और जून, प्रत्येक में 50 बीपीएस की, जुलाई में 100 बीपीएस की और सितंबर में 75 बीपीएस की वृद्धि की। रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया ने मई से अपने नकद दर लक्ष्य में 225 बीपीएस - मई में 25 बीपीएस और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर प्रत्येक में 50 बीपीएस की वृद्धि की। नॉर्जेस बैंक और बैंक ऑफ कोरिया ने 2022 में क्रमशः 125 बीपीएस और 150 बीपीएस तक अपनी नीतिगत दरों में वृद्धि की, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ आइसलैंड और चेक नेशनल बैंक ने क्रमशः 350 बीपीएस और 325 बीपीएस की संचयी बढ़ोत्तरी को प्रभावी किया (चार्ट V.5ए)। स्वेरियस रिक्सबैंक (स्वीडन) ने 2022 में अब तक नीतिगत दर में 175 बीपीएस वृद्धि की है, जिसमें सितंबर 2022 में 100 बीपीएस बढ़ोत्तरी शामिल है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में बैंक ऑफ जापान (बीओजे) इनसे अलग बना रहा। उसने 2022 में एक निभावकारी रुख बनाए रखा और मौद्रिक नीति मापदंडों यथा- प्रमुख नीतिगत दरों और आस्ति खरीद की मात्रा को अपरिवर्तित रखा।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने 25 अप्रैल 2022 से अधिकांश बैंकों और छोटे बैंकों के लिए आरक्षित निधि अपेक्षा अनुपात में क्रमशः 25 बीपीएस और 50 बीपीएस की कटौती करते हुए एक निभावकारी मौद्रिक नीति का रुख अपनाया, जिससे अर्थव्यवस्था में 530 बिलियन युआन उपलब्ध हुए। उसने अगस्त में 1-साल के ऋण मूल दर (एलपीआर) को 5 बीपीएस, 5-साल के एलपीआर को 15 बीपीएस और 1-साल के मध्यम अवधि के उधार सुविधा ऋण और 7-दिवसीय रिवर्स पुनर्खरीद करारों को 10 बीपीएस घटा दिया।

इसके विपरीत अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत सख्ती को जारी रखा। ब्रिक्स देशों में, बैंको सेंट्रल डू ब्राज़ील ने मार्च के अपने 100 बीपीएस दर बढ़ोत्तरी के अनुसरण में मई में 100 बीपीएस की दर बढ़ोत्तरी और जून एवं अगस्त प्रत्येक में 50 बीपीएस की दर बढ़ोत्तरी की। दी साउथ अफ्रीकन रिज़र्व बैंक ने अपनी नीतिगत दर को मई की बैठक में 50 बीपीएस और जुलाई एवं सितंबर दोनों बैठकों में 75 बीपीएस बढ़ा (चार्ट V.5बी)। एशियाई ईएमई में, बैंक ऑफ थाईलैंड और बैंक इंडोनेशिया दोनों ने अगस्त 2022 में 25 बीपीएस की बढ़ोत्तरी करके एक सख्त चक्र शुरू किया। इसके बाद दोनों बैंकों ने सितंबर में क्रमशः 25 बीपीएस एवं 50 बीपीएस की बढ़ोत्तरी की। लैटिन अमेरिका में मेक्सिको, चिली और पेरू के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक सख्ती जारी रखी। यूरोपीय उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हंगरी ने अप्रैल के बाद से संचयी रूप से 860 बीपीएस की नीति दर में वृद्धि

[7] यूके और वैश्विक वित्तीय आस्तियों के उल्लेखनीय पुनर्मूल्यन के आलोक में, बीओई ने 28 सितंबर को घोषणा की कि वह जिस भी पैमाने पर आवश्यक हो, दीर्घकालिक सरकारी बॉन्डों की अस्थाई खरीद करेगी ताकि व्यवस्थित बाज़ार स्थितियों को फिर से बहाल किया जा सके। इसी के साथ, बीओई ने £80 बिलियन स्टॉक घटाने के कार्यक्रम के तहत पहले से तय गिल्ट बिक्री को स्थगित करने का निर्णय लिया।

चार्ट V.5: नीति दर परिवर्तन- चुनिंदा प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं



स्रोत: ब्लूमबर्ग।

की है, जिसमें जुलाई में एक ऑफ-साइकिल बैठक में 200 बीपीएस की वृद्धि भी शामिल है।

कीमत और वित्तीय स्थिरता जोखिम कम होने पर बैंक ऑफ रशिया ने पहली छमाही में अपना रुख बदल दिया। उसने फरवरी 2022 में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति दबावों को रोकने के लिए अपनी प्रमुख दर में 11.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की थी। मूल्यह्रास दबाव कम होने पर उसने अप्रैल से अपनी नीतिगत दर में 1250 बीपीएस की कटौती की – जिनमें अप्रैल और मई में आयोजित दो ऑफ-साइकिल बैठकों में प्रत्येक में 300 बीपीएस की कटौतियां शामिल हैं। इससे फरवरी में की गई दरों में वृद्धि का समायोजन हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की ने अगस्त और सितंबर में हुई बैठकों में अपनी प्रमुख नीतिगत दर में हर बार 100 बीपीएस की कटौती की, जबकि मुद्रास्फीति काफी ज्यादा बढ़कर अगस्त में 80.2 प्रतिशत हो गई थी।

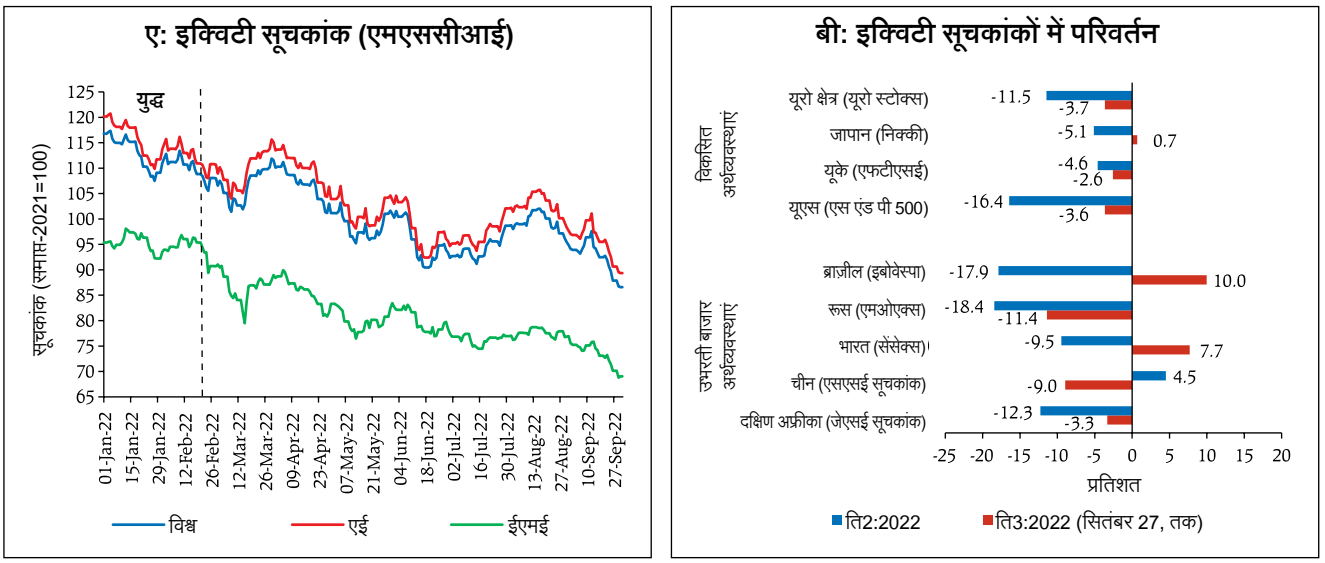
समग्र रूप से, 2022 के दौरान केंद्रीय बैंकों की दरों में वृद्धि ऐतिहासिक मानकों की तुलना में काफी आक्रामक रही है। 2022 (28 सितंबर 2022 तक) में अपनी नीतिगत दरें बढ़ाने वाले 31 बैंकों (13 एई और 18 ईएमई) के नमूने में, 23 केंद्रीय बैंकों ने अपनी नीतिगत दरों में 75 बीपीएस या उससे अधिक की वृद्धि की। इनमें से 8 केंद्रीय बैंकों ने दरों में 100 बीपीएस से अधिक की वृद्धि की।

V.4 वैश्विक वित्तीय बाजार

वैश्विक वित्तीय बाजार अप्रैल-सितंबर के दौरान चिंताग्रस्त बने रहें क्योंकि वे लंबे समय तक भूराजनैतिक तनाव, कई अर्थव्यवस्थाओं में दशकों के उच्चतम मुद्रास्फीति दर होने, अत्यधिक मौद्रिक सख्ती और वैश्विक मंदी की चिंताओं से जूझ रहे थे। बॉन्ड प्रतिफल में मजबूती आई, इक्विटी बाजारों में सुधार हुआ और फेड के ब्याज दर बढ़ाने वाले वक्तव्यों और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जबकि ईएमई मुद्राएं व्यापक रूप से कमजोर हुईं।

इक्विटी बाजारों में, यूएस एस एंड पी इंडेक्स अप्रैल 2022 की शुरुआत से निचले स्तर पर गिर गया क्योंकि यूएस फेड द्वारा बढ़ती संवृद्धि चिंताओं के साथ-साथ मौद्रिक घोषणाओं के बारे में अनिश्चितता ने निवेशकों के मनोभावों को विचलित कर दिया। फेड द्वारा दरों में बड़ी बढ़ोत्तरी के कारण जून की पहली छमाही में हुई अल्पकालिक बहाली सितंबर में उलट गई। अनिश्चितता कम होने और मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रत्याशाओं के साथ, अमेरिकी इक्विटी ने जुलाई में धीरे-धीरे बहाली की, लेकिन अगस्त और सितंबर में लाभ कम हुआ क्योंकि फेड ने आक्रामक रुख को जारी रखा। कुल मिलाकर, यूएस एस एंड पी इंडेक्स मार्च 2022 के अंत और 28 सितंबर, 2022 के बीच 17.9 प्रतिशत गिर गया।

चार्ट V.6: इक्विटी बाजार



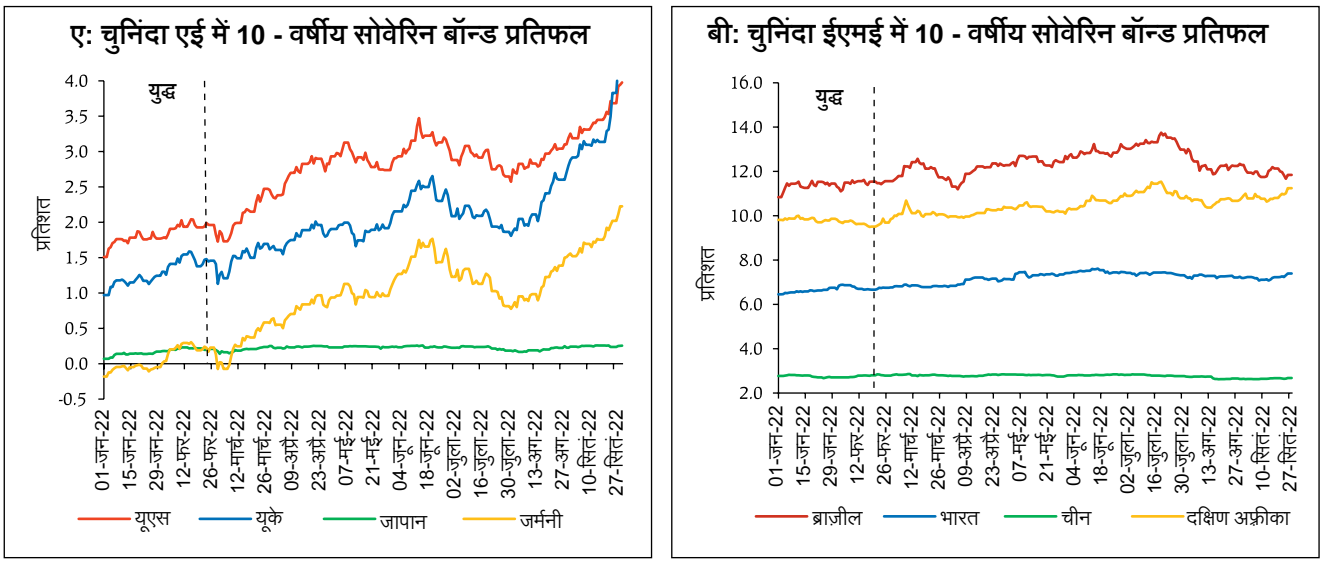
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

यूरोपीय शेयर बाजारों ने व्यापक रूप से अमेरिकी बाजारों को प्रतिबिंबित किया। बढ़ती मंदी की आशंकाओं और बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि की चिंताओं के कारण इन बाज़ारों में अप्रैल और मई में गिरावट आई। मई के अंत और जून की शुरुआत में अल्पकालिक वृद्धि के बाद, बढ़ती मुद्रास्फीति की आशंकाओं, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों, निराशाजनक व्यावसायिक गतिविधि के आंकड़ों और ईसीबी द्वारा दरों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना के कारण बाजारों में गिरावट आई। यू.के. शेयर सूचकांकों ने भी वैश्विक संकेतों का अनुसरण किया। इसके विपरीत, जापान में स्थिर मुद्रास्फीति और आर्थिक बहाली के समर्थन में अति निभावकारी मौद्रिक नीति निरंतर रहने से जापानी बाजार ने अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि 28 सितंबर 2022 को 3 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के शेयर बाजारों का प्रदर्शन 2022 की दूसरी तिमाही में विकसित बाजारों की तुलना में कम रहा क्योंकि बढ़ते मुद्रास्फीति दबावों, मंदी की आशंकाओं और प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक सख्ती ने निवेशकों के मनोभावों को प्रभावित किया (चार्ट V.6ए)। 2022 की तीसरी तिमाही में खासकर ईएमई के स्टॉक बाज़ारों ने ऋणात्मक प्रतिलाभ दर्ज किए, जिसमें ब्राज़ील और भारत अपवाद थे। सुरक्षित निवेश के लिए दौड़ के कारण पोर्टफोलियो निवेशों का बहिर्गमन हुआ और इक्विटी पर अधोगामी दबाव पड़ा (चार्ट V.6बी)।

बढ़ती मुद्रास्फीति और दर में उच्च वृद्धि की प्रत्याशाओं के कारण सभी प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के सरकारी बॉन्ड प्रतिफलों में 2022 की दूसरी तिमाही में वृद्धि हुई। मंदी की चिंताओं के कारण जुलाई में दीर्घावधि बॉन्ड प्रतिफलों में गिरावट आई, परंतु आगे मौद्रिक सख्ती की प्रत्याशाओं के कारण अगस्त-सितंबर के दौरान प्रतिफलों में बढ़ोत्तरी हुई। अप्रैल में, यूएस के 10-वर्षीय ट्रेजरी प्रतिफल 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए क्योंकि बाज़ार का अनुमान था कि फेड पहले के पूर्वानुमान की अपेक्षा अधिक सख़्त होगा। अल्पकालिक दरों में भी तेजी से वृद्धि होने के कारण प्रतिफल वक्र अधिक सपाट हुआ। वृद्धि की संभावना मंद दिखाई देने पर मंदी का भय बढ़ा, अल्पावधि प्रतिफल वक्र में वृद्धि हुई, जबकि दीर्घावधि प्रतिफल वक्र में गिरावट आई, जिसके फलस्वरूप जुलाई में प्रतिफल वक्र की दिशा पलट गयी। तथापि, यूएस 10 वर्षीय प्रतिफल, उम्मीद से अधिक मजबूत पे-रोल डेटा, और फेड चेयर और एफओएमसी सदस्यों की आक्रामक टिप्पणी और फेड द्वारा 75 बीपीएस की लगातार तीसरी बार दर वृद्धि के कारण मजबूत हुए (चार्ट V.7ए)। यूके और जर्मनी के 10 वर्षीय बॉन्ड प्रतिफलों ने यूएस बाजार का अनुसरण किया। विस्तारित राजकोषीय नीति में शामिल व्यापक कर कटौती के कारण 28 सितंबर को समाप्त सप्ताह में यूके के 10 वर्षीय बांड प्रतिफल में 70 बीपीएस की वृद्धि हुई। इनके विपरीत, जापानी बॉन्ड प्रतिफल, निभावकारी मौद्रिक नीति रुख निरंतरता से, निर्धारित सीमा के भीतर बने रहे। हालांकि, मुद्रास्फीति और पूंजी बहिर्वाह में तेज वृद्धि के कारण, सितंबर में 10 वर्षीय प्रतिफल ने, बैंक ऑफ जापान (बीओजे) द्वारा निर्धारित अपने लगभग 0

चार्ट V.7: बॉन्ड प्रतिफल



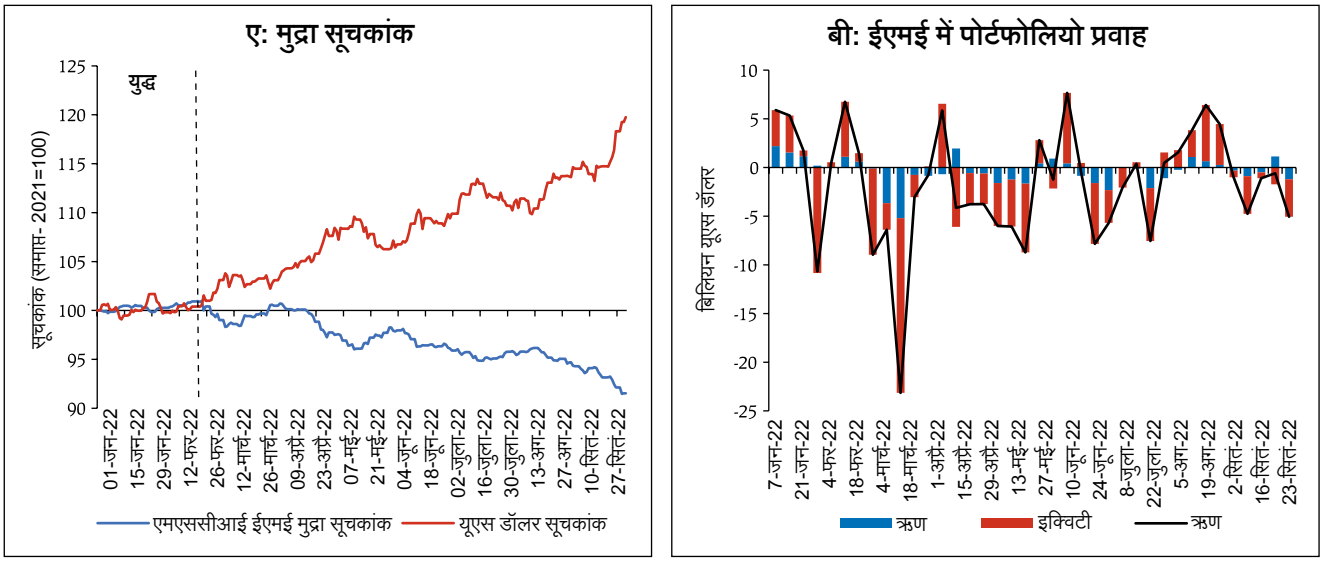
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

प्रतिशत लक्ष्य वाले बैंड की ऊपरी सीमा को छू दिया, जिससे बीओजे को पूर्व योजना से अधिक बांड खरीदने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड प्रतिफल घरेलू मौद्रिक सख़्ती के साथ-साथ वैश्विक संकेतों द्वारा संचालित होकर मजबूती की ओर बढ़े (चार्ट V.7बी)। तथापि, मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों के कारण चीन और ब्राज़ील के बॉन्ड प्रतिफलों में मामूली गिरावट आई।

मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर प्रमुख वैश्विक समकक्षों के मुकाबले 2022 की दूसरी और तीसरी तिमाही में अधिक मजबूत हुआ है, जो अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष दरों में वृद्धि की अपेक्षाकृत तीव्र गति और मात्रात्मक सख़्ती की योजनाओं

चार्ट V.8: मुद्रा उतार-चढ़ाव और पूंजी प्रवाह



टिप्पणी: ईएमई को पोर्टफेलियो हेतु डाटा साप्ताहिक है।

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

को परिलक्षित करता है (चार्ट V.8ए)। मौजूदा भू-राजनैतिक उथल-पुथल और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बीच सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने अमेरिकी डॉलर को और मजबूत किया। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, निवेशकों की घटती रूचि के बीच उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं के कमजोर होने में प्रतिबिंबित हुई । मार्च-जुलाई के दौरान पूंजी बहिर्गमन ने ईएमई मुद्राओं में अस्थिरता को बढ़ा दिया। पूंजी प्रवाह अगस्त में बहाल हुआ लेकिन इक्विटी बहिर्वाह के कारण यह रुझान उलट गया (चार्ट V.8बी)। इक्विटी प्रवाह प्रमुखता के साथ, अगस्त में पूंजी प्रवाह फिर से शुरू हुआ। एमएससीआई उभरते बाजार मुद्रा सूचकांक 2022 की दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत और 2022 की तीसरी तिमाही (28 सितंबर 2022 तक) में 5.4 प्रतिशत घट गया ।

V.5 निष्कर्ष

चूंकि मौद्रिक प्राधिकारी उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आक्रामक रूप से सख़्ती का रुख अपना रहे हैं, इसलिए वैश्विक विकास संभावनाओं के लिए जोखिम काफी कम हुए हैं। युद्ध के कारण बनी अनिश्चितता और आगे भी मौद्रिक सख़्ती में तेजी से वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारी अस्थिरता आ रही है, और इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर में सुरक्षित निवेश करने की मांग भी बढ़ रही है। ये घटनाक्रम उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापक प्रतिकूल प्रभाव-विस्तार पैदा कर रहे हैं और उनकी विकास संभावनाओं के लिए बहुत अधोगामी जोखिम खड़े कर रहे हैं।

भाषण

गुणात्मक ताकत के रूप में फिनटेक
शक्तिकांत दास

*गुणात्मक ताकत के रूप में फिनटेक**

शक्तिकांत दास

ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (जीएफएफ) के तीसरे संस्करण में आज यहां आकर मुझे खुशी हो रही है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों - भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (एफसीसी) और भारतीय भुगतान परिषद (पीसीआई) को बधाई देना चाहूंगा। कार्यक्रम का विषय - एक संधारणीय वित्तीय विश्व का सृजन - वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिक है।

हाल के वर्षों में, भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र में तेजी से प्रगति देखने को मिली है। प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष और फिनटेक मिलकर काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र की गतिशीलता में योगदान दे रहे हैं। संधारणीय विकास और वित्तीय समावेशन के उच्च स्तर की दिशा में हमारी यात्रा में, ये ताकत गुणात्मक ताकत में बदल गए हैं। हमने इन ताकतों का काफी फायदा उठाया है; हमें और भी अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है।

अब मैं बारीकियों पर आता हूँ। भारत में प्रौद्योगिकीय सक्षमकर्ताओं की जबर्दस्त वृद्धि हुई है। दूरसंचार पैठ, इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता, क्रेडिट तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना, अधिक कुशल भुगतान प्रणाली और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और आगे भी प्रगति जारी है।

जुलाई 2022 के अंत में भारत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 80.7 करोड़ थी[1]। 46.5 करोड़ से अधिक जन धन खाते, 134 करोड़ आधार नामांकन और 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शन से सेवाओं के एकीकरण और उसे प्रदान करने के अभिनव तरीकों को लागू करने के नए अवसर खुल रहे हैं। इसका अंदाजा पिछले साल स्थापित रिकॉर्ड 44 यूनिकॉर्न के साथ देश में 100 यूनिकॉर्न के उभरने से लगाया जा सकता है[2]।

तेजी से विकास करने के इच्छुक किसी भी समाज के लिए, उसके वित्तीय संस्थानों को मजबूत, सक्षम और सुलभ होना चाहिए। वित्त का अगला दशक दो केंद्रीय विषयों पर अधिक केंद्रित होगा: (i) संधारणीय विकास और (ii) प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेष जो आम लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। इसलिए, संधारणीय विकास और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करना हमारी नीतिगत संरचना का आधार है।

जैसा कि हम सभी ने देखा है, विशेष रूप से दुनिया भर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 महामारी का सामना करने में प्रौद्योगिकी सुदृढ़ता का केंद्र रही है। यह संकट के प्रति हमारी प्रतिक्रिया और बहाली को संबल प्रदान करने मे प्रमुख रहा है। वित्त के साथ-साथ प्रौद्योगिकी ने ऋणों के निर्बाध वितरण, मजबूत 24x7 भुगतान प्रणाली, वित्तीय बाजारों तक पहुंच, बीमा, एमएसएमई क्रेडिट, पेंशन सेवाओं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा की।

विश्व बैंक के अनुसार, विकासशील देशों में कम से कम 58 सरकारों ने कोविड-19 राहत प्रदान करने के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग किया है[3]। इस संबंध में भारत में परिचालन का पैमाना निश्चित रूप से अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा था। ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021[4] ने दुनिया भर में वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। विकासशील देशों में, 71 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते हैं, जो एक दशक पहले 42 प्रतिशत से अधिक थे। अपने खाते से डिजिटल भुगतान करने (किसी व्यापारी या उपयोगिता सेवा के लिए) वालों में लगभग 40 प्रतिशत ऐसे लोग थे जिन्होंने महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार ऐसा किया।

भारत में, महामारी ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण की ओर जोर दिया। मार्च 2020 से अगस्त 2022 की अवधि में यूपीआई लेनदेन में 427 प्रतिशत की भारी वृद्धि

---

* 20 सितंबर 2022 को ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल, मुंबई में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का संबोधन।

1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)।

2 पीआईबी प्रेस प्रकाशनी

3 डिजिटल वित्तीय समावेशन पर कोविड-19 के प्रभाव संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट

4 https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex

देखी गई है, जो अकेले अगस्त 2022[5] में 657 करोड़ लेनदेन के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। जुलाई 2022 के अंत तक यूपीआई क्यूआर कोड सक्षम भुगतान स्वीकार करने वाले केन्द्रों[6] की संख्या लगभग 9 करोड़ ((86 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंच गई, जो संपर्क रहित भुगतान के लिए बढ़ती स्वीकृति और प्राथमिकता को दर्शाता है।

हमारे वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेष

भारत में वित्तीय सेवा उद्योग में भारी परिवर्तन देखा गया है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यूपीआई, आधार ई-केवाईसी, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस), क्यूआर स्कैन एंड पे, डिजिटल प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स और इसी तरह की अन्य पहल जैसे उत्पादों ने पारंपरिक बैंकिंग परिचालन को बदल दिया है। बैंकिंग की समय अवधि बढ़ गयी है। अब हमारे पास डिजिटल-मोबाइल-कहीं भी-कभी भी बैंकिंग है। जहां कई पहलें उद्योग से उत्पन्न हुई हैं, वहीं सरकार और विनियामकों ने फिनटेक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंडिया स्टैक, अकाउंट एग्रीगेटर्स, पीयर टू पीयर (पी2पी) लेंडिंग प्लेटफॉर्म और 24x7 डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसी पहलें प्रमुख समर्थक साबित हुई हैं। भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र वास्तव में विकसित हुआ है और एक ऊंचे छलांग के लिए तैयार है।

अब मैं इस क्षेत्र में आरबीआई द्वारा की गई कुछ अन्य पहलों के बारे में बात करना चाहूंगा। **विनियमकीय सैंडबॉक्स** फ्रेमवर्क को अगस्त 2019 में नवोन्मेष को बढ़ावा देने की दृष्टि से जारी किया गया था। इसके साथ, रिज़र्व बैंक उन चुनिंदा समूह देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपना स्वयं का विनियामकीय सैंडबॉक्स पारिस्थितिकी तंत्र है। खुदरा भुगतान, सीमा पार भुगतान, एमएसएमई उधार और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम पर चार थीम-आधारित कॉहोर्ट के बाद, इस महीने की शुरुआत में एक थीम न्यूट्रल फिफ्थ कोहोर्ट की घोषणा की गई थी। यह फिनटेक स्पेस में नवोन्मेष की उपस्थिति को बढ़ाने की हमारी तीव्र इच्छा को दर्शाता है। हमारी विनियामकीय सैंडबॉक्स पहल से निकलने वाली सफलता की कहानियों में अन्य बातों के अलावा, 'ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए फ्रेमवर्क' और हाल ही में लॉन्च किया गया UPI123Pay शामिल है, जिसका उद्देश्य 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को संरक्षित और सुरक्षित तरीके से यूपीआई का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है।

रिज़र्व बैंक ने पहली बार खुदरा भुगतान को और अधिक उन्नत बनाने के उद्देश्य से **हार्बिन्जर 2021 (HaRBinger 2021)** नामक एक **वैश्विक हैकाथॉन** का आयोजन किया। इसमें उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली। हमें 363 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें 22 विदेशों से थे जिनमें यूएसए और यूके जैसे देश शामिल थे। इस अभ्यास ने हमें रचनात्मक प्रतिभा पूल की एक झलक दी, जो भारत के पास है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है कि भारत फिनटेक स्पेस में नेतृत्व प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है। मैं समझता हूं कि हार्बिन्जर 2021 (HaRBinger 2021) के विजेता भी अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए इस ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं।

हाल ही में, आरबीआई ने बेंगलुरु में एक सहायक कंपनी के रूप में **रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच)** की स्थापना की है। हब में निजी क्षेत्र और डोमेन विशेषज्ञों से लिए गए एक प्रतिष्ठित निदेशक मंडल हैं। आरबीआईएच वर्तमान में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आगे चलकर, आरबीआईएच खुद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बेंचमार्क बनाएगा।

हमने इस विकसित और गतिशील क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनवरी 2022 से आरबीआई में एक नया फिनटेक विभाग भी बनाया है। इस विभाग का उद्देश्य न केवल नवोन्मेष को बढ़ावा देना है, बल्कि इससे जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान करना भी है। अंतर-विनियामकीय मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अलावा वित्तीय क्षेत्र और बाजारों के लिए व्यापक प्रभाव वाले फिनटेक क्षेत्र में रचनात्मक नवोन्मेषों और अनुकूल वातावरण की सुविधा से संबंधित सभी मामलों को इस विभाग द्वारा निपटाया जा रहा है।

इसके अलावा, जैसा कि आप जानते होंगे, आरबीआई अब थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में **केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)** के चरणबद्ध कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय रूप से

[5] एनपीसीआई वेबसाइट

[6] भारतीय रिज़र्व बैंक - भुगतान प्रणाली संकेतक (जुलाई 2022)

काम कर रहा है। इससे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

फिनटेक; आगे का रास्ता

यह सर्वविदित है कि फिनटेक सेवा प्रदान करने के मामले में दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने में योगदान देता है। अपने अनुकूलित उत्पादों और ग्राहक इंटरफेस के माध्यम से, वे एक समृद्ध और निर्बाध उपभोक्ता अनुभव प्रदान करते हैं। पारंपरिक रूप से सेवा से वंचित या कम सेवा वाले सेगमेंट में ऋण और वित्तीय समावेशन तक पहुंच में सुधार के अलावा, उनके पास बाजार पहुंच और उत्पाद की पेशकश की एक श्रृंखला में सुधार करने की भी क्षमता है।

भारत में, फिनटेक द्वारा निभाई जा सकने वाली सबसे परिवर्तनकारी भूमिकाओं में से एक पारंपरिक उधारदाताओं के साथ साझेदारी में ऋण सुपुर्दगी का क्षेत्र है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। उचित लागत पर ऋण की समय पर उपलब्धता, विशेष रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों और एमएसएमई के लिए, हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

इस तरह के ऋण का लाभ उठाने में वर्तमान में जुड़ी प्रमुख चुनौतियों में से एक यह है कि यह प्रतिवर्तन समय के साथ बड़े पैमाने पर कागज आधारित प्रक्रिया है। कभी-कभी इसके लिए बैंक शाखाओं में बार-बार जाना पड़ता है और बोझिल दस्तावेज संबंधी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसमें उधारदाताओं के लिए उच्च परिचालन लागत और उधारकर्ताओं के लिए अवसर लागत शामिल है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और आरबीआई की फिनटेक पहलों को आगे बढ़ाते हुए, भारत में कृषि-वित्त के डिजिटलीकरण की परिकल्पना रिज़र्व बैंक और रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब के बीच की गई थी। यह विचार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों को कागज रहित और परेशानी मुक्त तरीके से प्रदान करने और टर्नअराउंड समय को कम करने एवं बैंक शाखाओं में बार-बार जाने से बचने के लिए था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब ने ग्रामीण ऋण तक निर्बाध और त्वरित पहुंच के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया तैयार की है। नए केसीसी ऋण और ऐसे ऋणों के नवीनीकरण के लिए एक सीमा तक (₹1.60 लाख) प्रति उधारकर्ताओं दोनों के लिए इस नवोन्मेष पर आधारित एक प्रायोगिक परियोजना मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। आगे चलकर, प्रायोगिक परियोजना से मिली सीख के आधार पर, केसीसी ऋणों के डिजिटलीकरण को इन दोनों राज्यों के सभी जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव है। आखिरकार, हमारी इच्छा ग्रामीण और कृषि ऋण पर विशेष जोर देने के साथ पूरे देश के लिए समाज के सभी वर्गों के लिए घर्षण रहित ऋण की सुविधा हेतु एक एकीकृत और मानकीकृत प्रौद्योगिकीय मंच को विकसित और संचालित करना है। और अगर हम अगले एक वर्ष में ऐसा कर पाते हैं, तो यह भारत की विकास गाथा और भारत@2047 की यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर होगा।

आरबीआई द्वारा तकनीक-सक्षम विनियामकीय नवोन्मेष का एक अन्य उदाहरण अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क है। यह एक सुरक्षित और कुशल तरीके से संस्थानों में अपने वित्तीय डेटा को डिजिटल रूप से एक्सेस करने और साझा करने के लिए लाखों कम सेवा वाले ग्राहकों को सशक्त बनाने की क्षमता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित संस्थाओं को शामिल करने के लिए फ्रेमवर्क का विस्तार किया गया है। यह ग्राहकों को अपने वित्तीय डेटा पर नियंत्रण हासिल करने और क्रेडिट, बीमा, निवेश सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों को अपने स्वयं के लाभ के लिए उपयोग करने में मदद करने हेतु एक प्रगतिशील कदम है। केंद्रीकृत केवाईसी (सीकेवाईसी) और वीडियो केवाईसी डिजिटल और लागत प्रभावी तरीके से ग्राहकों की सहज ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए अन्य सक्षमकर्ता हैं। हम इन पहलों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

रिज़र्व बैंक सभी हितधारकों के समर्थन से ऐसी और पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में और हितधारकों के सहयोग से आज बाद में तीन रोमांचक नए उत्पाद लॉन्च किए जा रहे हैं। इनमें से दो 'यूपीआई लाइट' के माध्यम से छोटे मूल्य के लेन-देन की सुविधा और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़कर यूपीआई के फीचर सेट को बढ़ाने से संबंधित हैं। तीसरी पहल भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) का उपयोग करके सीमा पार आवक बिल भुगतान को सक्षम बनाना है।

फिनटेक संस्थाओं के उद्भव और उनके अभिनव उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता ने वित्तीय सेवाओं में मौजूदा भागीदारों को अपने बाजार हिस्सेदारी, मार्जिन और ग्राहक आधार को बनाए रखने में चुनौती दी है। मौजूदा कंपनियां विभिन्न रणनीतियों को अपनाकर इन चुनौतियों का जवाब दे रही हैं, जिसमें फिनटेक कंपनियों में निवेश करना और उनके साथ साझेदारी करना शामिल है। वे नई वास्तविकताओं के अनुकूल होने के लिए अपनी आंतरिक क्षमताओं को भी बढ़ा रहे हैं।

फिनटेक द्वारा लाए गए कई परिवर्तनों का समावेशन बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं की और पैठ बनाने के मामले में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही, इन घटनाक्रमों ने एक ऐसे युग की शुरुआत भी की है जहां भारी मात्रा में उपभोक्ता डेटा उत्पन्न किया जा रहा है और कुछ संस्थाओं (तथाकथित बिगटेक) द्वारा अपने विशाल ग्राहक आधार के बूते लाभ उठाया जा रहा है। इस तरह के घटनाक्रम संकेंद्रण जोखिम और संभावित स्पिलओवर संबंधी चिंता पैदा करते हैं क्योंकि वित्तीय प्रणाली के साथ उनके जुड़ाव का स्तर आने वाले वर्षों में मजबूत होता है। इसलिए, प्रतिस्पर्धा, बाजार और व्यापार आचरण, परिचालन सुदृढ़ता, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों के लिए संभावित जोखिमों पर करीब से ध्यान देने की जरूरत है।

जैसा कि हमने देखा है, हाल के दिनों में जिस तरह से डिजिटल लेंडिंग ने रफ्तार पकड़ी है वह अभूतपूर्व था। जहां इसने विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया है, वहीं इसने कई चिंताओं को भी उजागर किया है जो कि ब्याज दरों, अनैतिक वसूली प्रथाओं और डेटा गोपनीयता की समस्याओं के बारे में शिकायतों के एक समूह के माध्यम से प्रकट हुई हैं। रिज़र्व बैंक ने इन समस्याओं को सक्रिय रूप से हल करने का प्रयास किया है और जून 2020 की शुरुआत में, हमारी विनियमित संस्थाओं को विनियामकीय दिशानिर्देश प्रदान किया गया था। इस दिशानिर्देश में, अन्य बातों के अलावा, अनिवार्य है कि डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म उन बैंकों/एनबीएफसी के नामों का खुलासा करें जिनकी ओर से वे ऋण प्रदान कर रहे थे। डिजिटल उधार[7] पर हाल ही में जारी विनियामक दिशानिर्देश एक तरफ ग्राहक संरक्षण और व्यापार आचरण और दूसरी तरफ नवोन्मेष का समर्थन करने के बीच एक सुविचारित संतुलन बनाते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जहां नवोन्मेषों का बहुत स्वागत है, वहीं उन्हें जिम्मेदार होना होगा और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करते हुए वित्तीय प्रणाली की दक्षता एवं सुदृढ़ता को बढ़ाना होगा। निष्पक्ष और पारदर्शी अभिशासन के साथ मजबूत आंतरिक उत्पाद और सेवा आश्वासन ढांचे, ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और फिनटेक संस्थाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। विनियमित संस्थाओं द्वारा उनकी आउटसोर्स की गई गतिविधियों पर उचित परिश्रम और निरीक्षण के स्तर को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इससे शुरुआती चरण में ही जोखिमों को सक्रिय रूप से कम करने में मदद मिलेगी।

मैं डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स के बेलगाम तेजी से बढ़ने के संबंध में कुछ भौतिक चिंताओं को भी चिह्नित करना चाहता हूं। विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्रीन-लाइटिंग (श्वेतसूचीकरण) और उचित परिश्रम की प्रक्रिया का पालन करने के बाद सुरक्षा का आश्वासन सुनिश्चित करना समय की मांग है। आरबीआई, अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर, इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठा रहा है तथा जरूरत पड़ने पर और कदम उठाएगा।

अभिशासन और आचरण

जहां हम प्रौद्योगिकीय प्रगति और नवोन्मेष का समर्थन करना जारी रख रहे हैं, वहीं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अभिशासन और आचरण के मुद्दों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए। आखिरकार, किसी भी फिनटेक गतिविधि या कारोबार की स्थिरता ग्राहक सुरक्षा, बेहतर साइबर सुरक्षा तथा सुदृढ़ता, वित्तीय अखंडता का प्रबंधन और मजबूत डेटा सुरक्षा से संबंधित है।

---

[7] https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=54187; https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12382&Mode=0

मैं फिनटेक समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आरबीआई नवोन्मेष को प्रोत्साहित और समर्थन देना जारी रखेगा। साथ ही, हम उम्मीद करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र अभिशासन, व्यापार आचरण, विनियामक अनुपालन और जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क पर ध्यान देगा। बड़ी संख्या में पहले से मौजूद मौजूदा संस्थाओं के अलावा आगे का फिनटेक रोड लगातार बढ़ते ट्रैफिक का गवाह बनेगा। इसलिए, यह जरूरी है कि इस सड़क पर चलने वाला प्रत्येक भागीदार अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करे।

निष्कर्ष

एक संधारणीय वित्तीय दुनिया सिर्फ हमारे लिए नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस यात्रा में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। आरबीआई का ध्यान हमेशा एक सुगम वातावरण प्रदान करके नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने पर रहा है। साथ ही, वित्तीय स्थिरता के संरक्षक के रूप में, आरबीआई भी किसी भी अनुचित जोखिम बढ़ने के प्रति सतर्क रहता है और उस पर कार्रवाई करता है। मुझे यकीन है कि फिनटेक भागीदार इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ेंगे।

भारत में हमारे पास जो अद्भुत प्रतिभा आधार है और हाल के वर्षों में हमने डिजिटल एवं फिनटेक स्पेस में जो विशाल छलांग लगाई है, मुझे विश्वास है कि भारत इस क्षेत्र में भावी सोच को आकार देने के लिए अच्छी स्थिति में है। चूंकि हम एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हैं, इसलिए मैं आप सभी की आगे की सुरक्षित और सुखद यात्रा की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत के लिए हरित सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान

वित्तीय डोमेन में 'बिगटेक': प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को संतुलित करना

डेट म्यूचुअल फंड में बाज़ार प्रतिलाभ और प्रवाह

भारत में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय देयताएं - एक आकलन

*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

आक्रामक और समकालिक मौद्रिक सख्ती ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं को और कमजोर कर दिया है क्योंकि वित्तीय बाजार बिक गए, निवेशक डर गए और जोखिम भरी आस्तियों को छोड़ दिया। भारत में, व्यापक आर्थिक गतिविधि लचीली बनी हुई है और घरेलू मांग में तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है क्योंकि संपर्क-गहन क्षेत्रों में उछाल का सामना करना पड़ रहा है। मजबूत ऋण वृद्धि और मजबूत कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करते हैं। सहज गति और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति अपने सितंबर के उच्च स्तर से कम होने के लिए तैयार है, हालांकि जिद्दी रूप से। ये कारक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की संभावनाओं को मजबूत करेंगे।

भूमिका

19 सितंबर, 2022 से शुरू होने वाले सप्ताह के बाद, जब आठ केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरों को संचयी 500 आधार अंकों से बढ़ाने में यूएस फेड का मिलान किया - और दूसरा दरों में कटौती करके दूसरे रास्ते पर चला गया - तूफान के बादलों ने क्षितिज को गहरा कर दिया, जिससे दुनिया खतरनाक पॉली -क्राइसिस में चली गई। वित्तीय बाजार बिक गए, निवेशक डर गए और जोखिम भरी संपत्तियों को छोड़ दिया, विश्व बैंक ने विनाशकारी मंदी की चेतावनी दी, और हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करने वाले जीवन-यापन के संकट के बारे में आगाह किया है। 200 से अधिक वर्षों के वैश्वीकरण को विखंडन, मुद्रास्फीति का स्तर और उसकी दृढ़ता जो चार दशकों में नहीं देखी गई उससे खतरा है। जैसे ही केंद्रीय बैंक मुद्रास्फ़ीति को नियंत्रण में लाने के लिए कृतसंकल्प होते हैं, बेदाग अवस्फीति'[1] की उम्मीदें फीकी पड़ जाती हैं। परिवार और व्यवसाय उम्मीद खो देते हैं और दर्द के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या बहुत अधिक या बहुत कम करने के जोखिम हैं? यूएस फेड की संघीय खुला बाजार समिति (एफओएमसी) का मानना है कि 'मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बहुत कम कार्रवाई करने की लागत बहुत अधिक कार्रवाई की लागत से अधिक है'।[2] फिर भी कई प्रतिभागियों ने यह भी नोट किया कि वर्तमान अत्यधिक अनिश्चित वैश्विक आर्थिक और वित्तीय वातावरण में, आर्थिक दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से आगे सख्त होने की गति को कैलिब्रेट करना महत्वपूर्ण होगा। स्पष्ट रूप से, जोखिम दो तरफा हो गए हैं और पहले की तुलना में अधिक संवेदनशीलता है कि मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के कारण कुल मांग पर संचयी संयम मुद्रास्फीति को लक्ष्य तक लाने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक हो सकता है। जैसा कि मार्क ट्वेन ने एक बार लिखा था, "आप जिस चीज को नहीं जानते हैं वह आपको नहीं मारती है बल्कि वह चीज आपको मारती है जिसे आप निश्चित रूप से सच नहीं मानते हैं।"

1980 के दशक की शुरुआत में, 1990 के दशक में और 2013 की गर्मियों में जब अमेरिका ने मौद्रिक नीति को सख्त कर दिया था या इसके बारे में बात की थी, उभरते और विकासशील देश फिर से विशेष रूप से जोखिम में हैं और एक बेहद चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण का सामना कर रहे हैं। यह आशंका है कि उच्च भोजन, उर्वरक और ऊर्जा की कीमतों का घातक कॉकटेल, अत्यधिक मुद्रा मूल्यह्रास, पूंजी उड़ान, और वैश्विक विकास में तेज मंदी इन देशों में 70 मिलियन से अधिक लोगों को घोर गरीबी में धकेलने जा रही है। एक प्रभावशाली दृष्टिकोण से, इन अतिव्यापी संकटों के मानवीय परिणाम विनाशकारी हैं। [3] हालांकि, तुलनात्मक रूप से, इस बार वे मुकाबला करते दिख रहे हैं। वे मौद्रिक नीति को कसने में सबसे पहले निशाने पर थे, उनकी मुद्राएं उनके उन्नत अर्थव्यवस्था समकक्षों की तुलना में कम गिर गई हैं, और उनके मूल सिद्धांतों और समष्टि आर्थिक नीति के ढांचे में पिछले एपिसोड[4] के सापेक्ष सुधार हुआ है, जिसमें बड़े विदेशी मुद्रा भंडार

---

* इस आलेख को डॉ. जी.वी. नधानियल, शशि कांत, कुणाल प्रियदर्शी, हर्षिता केशन, जेसिका मारिया एंथोनी, कौस्तुभ, पंकज कुमार, सत्यार्थ सिंह, प्रशांत कुमार, इप्सिता पाढ़ी, आयुषी खंडेलवाल, जोबिन सेबेस्टियन, रोहन बंसल, सुधांशु गोयल, प्रियंका सचदेवा, अक्षरा अवस्थी, युवराज कश्यप, सत्यम कुमार, दीपिका रावत, आशीष संतोष खोब्रागडे, सविता पारिक, निवेदिता बनर्जी, राजेंद्र नाना चव्हान, शिवांगी मिश्रा, विनीत कुमार श्रीवास्तव, डॉ. समीर रंजन बेहरा, डॉ. देब प्रसाद रथ और माइकल देबब्रत पात्र ने तैयार किया है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

1 मार्टिन वुल्फ।

2 एफओएमसी कार्यवृत्त, 12 अक्टूबर 2022।

3 डेविड माल्पस, अध्यक्ष, विश्व बैंक का 28 सितंबर 2022 को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषण।

4 अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की अपनी वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट 2019 में किए गए उल्लेख के अनुसार, उनमें से कई ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाया है और विदेशी मुद्रा हस्तक्षेपों के साथ उनका मेल किया है।

और गहरे स्थानीय वित्तीय बाजार हैं जो आघात को अवशोषित करने में मदद करते हैं। वास्तव में, आईएमएफ़ का अनुमान है कि उन्होंने 2022 की पहली छमाही में भंडार को 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम कर लिया है, लेकिन यह 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की उनकी संचयी होल्डिंग का एक छोटा सा अंश है। उनमें से कई के लिए, अमेरिकी डॉलर की अविश्वसनीय ताकत के मुकाबले उनकी मुद्राओं का अवतरण भी आरक्षित मुद्राओं द्वारा अनुभव किए गए गिरावट की तुलना में अधिक व्यवस्थित रहा है। हालांकि, फेड द्वारा दर वृद्धि के अगले 150 आधार अंक उनका परीक्षण करेंगे और इसलिए वे हाई अलर्ट पर रहेंगे। अमेरिका में सीपीआई मुद्रास्फीति के सितंबर 2022 के लिए रीडिंग में कमी के कोई संकेत नहीं दिखने के साथ, जो 12 अक्टूबर को जारी किया गया था, अमेरिका में वायदा बाजार नवंबर 2022 में लक्ष्य संघीय निधि दर में 75 आधार अंकों की वृद्धि में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, जिसमें लगभग 100 प्रतिशत संभावना है। अशांति तेज होने पर निवेशकों के अमेरिकी खजाने में भागने का जोखिम वास्तविक और मौजूद है।

सभी देशों के लिए, उन्नत और उभरते हुए समान रूप से, वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम बढ़ गए हैं और कुछ हाल ही में यूके में हुए हैं। आईएमएफ की अक्टूबर 2022 वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हमें कड़ी वित्तीय स्थितियों, बिगड़ती बाजार चलनिधि, और अति-निम्न ब्याज दरों और सस्ते क्रेडिट के वर्षों से बढ़ी हुई वित्तीय कमजोरियों के बारे में सचेत करती है। वास्तव में, जैसा कि जीएफएसआर बताता है, चार सीमांत अर्थव्यवस्थाएं पहले ही चूक कर चुकी हैं, आठ कम आय वाले देश (एलआईसी) ऋण संकट में हैं और 30 एलआईसी ऋण संकट के उच्च जोखिम में हैं। उनके सामने आने वाली वित्तीय स्थितियों के अव्यवस्थित रूप से कड़े होने का जोखिम इन न्यायालयों से वापस आने वाले पूंजी प्रवाह द्वारा बढ़ाया जाता है। एक तत्काल चिंता आक्रामक मौद्रिक नीति के कड़े होने के दूसरे क्रम के प्रभावों के बारे में है - वित्तीय बाजार में संक्रमण और क्रेडिट बाजारों में अचानक बंद होने से वर्तमान में अनुमान से अधिक गंभीर मंदी आ रही है।

एक अन्य आम जोखिम अत्यधिक बाढ़ और सूखे की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता है जो अब तक 2022 की विशेषता रही है। ये घटनाएँ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भू-राजनीतिक रूप से प्रेरित खतरों से टकराई हैं। वर्ष 2022 छठे सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ है।[5] आईएमएफ के विचार में, जलवायु परिवर्तन दीर्घकालिक विकास और समृद्धि के लिए एक बड़ा खतरा है, और इसका सभी देशों के आर्थिक कल्याण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन से जुड़े भौतिक जोखिमों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। वे ऐसे देश भी हैं जिन्हें सबसे अधिक लाभ होगा यदि विश्व तापमान वृद्धि पर लगाम लगाने में सक्षम होता है। इन अर्थव्यवस्थाओं को अपने उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के भौतिक प्रभावों के अनुकूल होने के लिए आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।[6]

दुनिया भर में मौद्रिक नीति के समकालिक कड़ेपन के विपरीत, जिसका पहले उल्लेख किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 सितंबर को 'परफेक्ट 50' दिया। और नीतिगत दर में वृद्धि को 5.90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया, भारतीय रुपये में पिछले दिन के बंद होने की तुलना में सराहना हुई, जबकि बांड की पैदावार स्थिर रही और इक्विटी ने मंदी की भावनाओं को उसी दिन 2 प्रतिशत बढ़ा दिया। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का विचार था कि 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के ऊपरी सहिष्णुता स्तर से ऊपर रहने की संभावना है, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है। जबकि वैश्विक दृष्टिकोण को काफी अनिश्चितता के रूप में देखा गया था, एमपीसी ने निर्णय लिया कि घरेलू आर्थिक गतिविधि अच्छी तरह से चल रही है और उपभोक्ता और व्यापार आशावाद के बीच वर्ष की दूसरी छमाही में उछाल की उम्मीद है। तदनुसार, यह महसूस किया गया कि मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर रखने, कीमतों के दबावों के विस्तार को रोकने, दूसरे दौर के प्रभावों को रोकने और मध्यम अवधि के विकास की संभावनाओं को समर्थन देने के लिए और अधिक अंशांकित मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता है। एमपीसी ने विकास का समर्थन करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति आगे बढ़ने वाले लक्ष्य के साथ संरेखित हो, समायोजन की वापसी के साथ दृढ़ रहने का निर्णय लिया।

---

[5] नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉसफेरिक एड्मिनिस्ट्रेशन, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, जुलाई 2022।

[6] जीएफएसआर, आईएमएफ, अक्टूबर 2022।

व्यापक आर्थिक गतिविधि लचीली बनी हुई है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। घरेलू मांग में तेजी आ रही है, ऑटो की बिक्री में तेजी आई है, उधार लेने की लागत में बढ़ोतरी के बावजूद अचल संपत्ति की बिक्री बढ़ रही है और संपर्क-गहन आतिथ्य सेवाओं में उछाल का अनुभव हो रहा है। बैंक क्रेडिट में दहाई अंकों की वृद्धि हो रही और माल और सेवा कर संग्रह में निरंतर वृद्धि अर्थव्यवस्था की बढ़ती औपचारिकता का संकेत दे रही है। भारतीय इक्विटी उन्नत और उभरते साथियों दोनों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बिकवाली घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से अधिक हो रही है। महामारी की अवधि के माध्यम से कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट मजबूत हो गए हैं। एक विचार यह है कि भारत उन कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की संभावना है जो वैश्विक तूफान के गुजर जाने के बाद खड़ी रह जाएंगी।

तो क्या भारत अलग हो रहा है? समय बताएगा। अभी के लिए, तुलनात्मक तुलना द्वारा यथोचित मजबूत मैक्रोफंडमेंटल का परीक्षण अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर के लगातार मजबूत होने के दोहरे झटकों द्वारा किया जा रहा है। इससे आयातित मुद्रास्फीति और रुपये के अवमूल्यन को संपार्श्विक क्षति हो रही है। भारत और विदेशों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा पूर्वानुमानों के आवधिक संशोधन के बावजूद वित्तीय बाजार में आम सहमति यह प्रतीत होती है कि भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2022-23 में 7 प्रतिशत या इसके करीब होगी।

हाल के कुछ घटनाक्रम इस विश्वास को प्रेरित करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति के अगस्त अंक में भविष्यवाणी की गई थी, 5जी को 1 अक्टूबर, 2022 को कई शहरों में भारत में लॉन्च किया गया था। 5जी प्रौद्योगिकी की शुरूआत उच्च डेटा गति, कम विलंबता, उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो सेवाओं और अत्यधिक विश्वसनीय संचार के साथ भारतीय विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर होने की संभावना है। 5जी टेलीसर्जरी और आपदाओं की वास्तविक समय की निगरानी, सटीक कृषि, खतरनाक औद्योगिक कार्यों जैसे गहरी खानों, अपतटीय गतिविधियों और इसी तरह में मनुष्यों की भूमिका को कम करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ भी उत्पन्न कर सकता है। दूसरा, भारत पुनर्जीवित हो रहा है। सितंबर 2022 को शुरू की गई राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी) का उद्देश्य रसद की लागत को सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों तक कम करना, देश और विदेश में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में दक्षता में वृद्धि करना है, जिससे मूल्य संवर्धन और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। समन्वय सुधार क्षेत्र की गति, मूल्य निर्माण और उद्यमिता को बढ़ावा देगा। नीति में सड़क परिवहन, रेलवे, विमानन, वाणिज्य मंत्रालयों और विदेश व्यापार में डिजिटल प्रणालियों का एकीकरण शामिल है; एक एकीकृत रसद इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म जो छोटे और चिकनी कार्गो आंदोलन को सुनिश्चित करेगा और वास्तविक समय के आधार पर गोपनीय रूप से जानकारी के आदान-प्रदान को सक्षम करेगा; और पारदर्शिता और पहुंच के माध्यम से रसद व्यवसाय में आसानी। एक सिस्टम सुधार समूह सभी रसद से संबंधित परियोजनाओं की निगरानी करेगा। इस नीति का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण पावरहाउस बनाना और लॉजिस्टिक्स हब बनने का मार्ग प्रशस्त करना है। तीसरा, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसरण में, देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) को 16 अक्टूबर, 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। डीबीयू स्व-सेवा मोड में 24x7X365 आधार पर एक कुशल, पेपरलेस, सुरक्षित और जुड़े वातावरण में बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद प्रदान करेंगे। वे वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के साधन भी होंगे।

इस पृष्ठभूमि के विपरीत, आलेख के शेष भाग को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे विकास को दर्शाता है। खंड III में घरेलू व्यापक आर्थिक स्थितियों का आकलन प्रस्तुत किया गया है । खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करता है, जबकि अंतिम खंड में लेख का समापन किया गया है।

II. वैश्विक परिदृश्य

इस लेख के पिछले संस्करण के बाद से वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम बढ़ गए हैं। ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि और उन्नत अर्थव्यवस्था (एई) केंद्रीय बैंकों के आक्रामक मार्गदर्शन ने वैश्विक सुधार के लिए वित्तीय स्थिरता

जोखिम को बढ़ा दिया है, जो 2022 की दूसरी तिमाही में रुकना शुरू हो गया है। दुनिया के कई हिस्सों में जीडीपी या तो सिकुड़ने लगी है या घटने लगी है। लंबे समय तक भू-राजनीतिक संघर्ष और कठोर सर्दियों की संभावना ने ऊर्जा और खाद्य मूल्य के आघात को बढ़ा दिया है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 11 अक्टूबर, 2022 को जारी अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में वैश्विक विकास दर 2021 में अनुमानित 6.0 प्रतिशत से घटकर 2022 में 3.2 प्रतिशत (जुलाई 2022 डब्ल्यूईओ अपडेट से अपरिवर्तित) और 2023 में 2.7 प्रतिशत (जुलाई 2022 के प्रक्षेपण से 0.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट) का अनुमान लगाया है [सारणी 1]। ये पूर्वानुमान वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली कई उथल-पुथल भरी चुनौतियों को दर्शाते हैं, जिनमें बहु-दशकीय उच्च मुद्रास्फीति, सख्त वित्तीय स्थिति, यूक्रेन में संघर्ष, कोविड-19 महामारी और चीन में मंदी शामिल है। इसके अलावा, वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.8 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है (जुलाई 2022 डब्ल्यूईओ अपडेट के सापेक्ष 0.5 प्रतिशत अंकों से संशोधित), फिर 2023 में 6.5 प्रतिशत तक कम हो गई (जुलाई 2022 डब्ल्यूईओ अपडेट के सापेक्ष 0.8 प्रतिशत अंकों द्वारा संशोधित) और 2024 तक 4.1 प्रतिशत

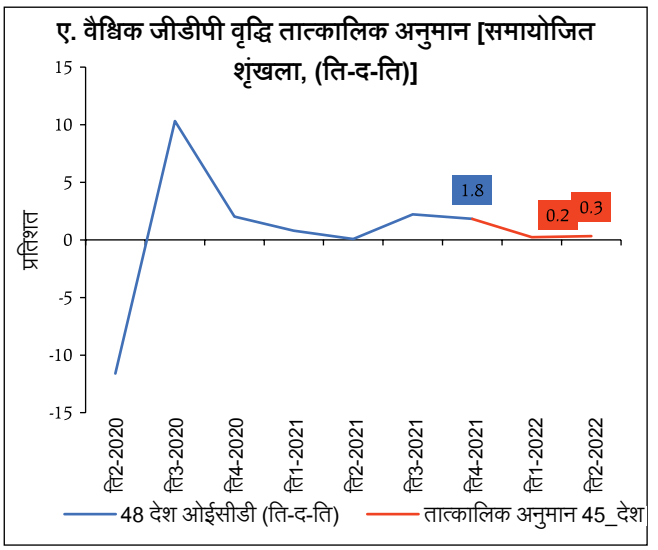
सारणी 1: जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान – चुनिंदा उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ (एई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई)

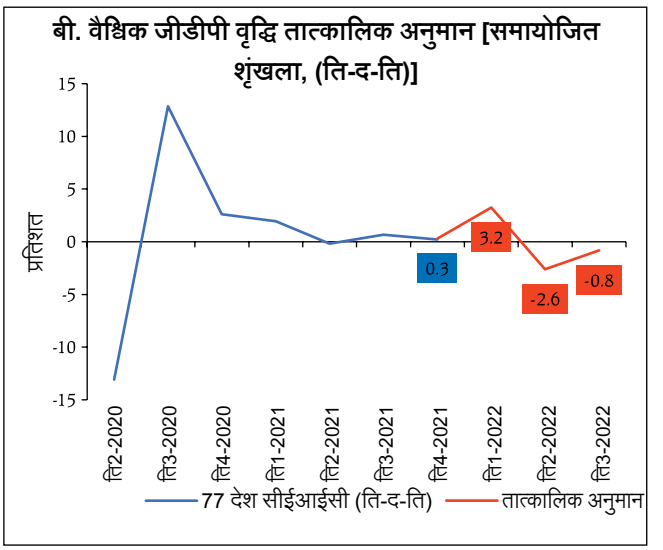
(प्रतिशत)

के लिए पूर्वानुमानित	2022		2023	
पूर्वानुमान का माह	अक्टूबर 2022	जुलाई 2022	अक्टूबर 2022	जुलाई 2022
विश्व	3.2	3.2	2.7	2.9
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ				
यूएस	1.6	2.3	1.0	1.0
यूके	3.6	3.2	0.3	0.5
यूरो क्षेत्र	3.1	2.6	0.5	1.2
जापान	1.7	1.7	1.6	1.7
उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएं				
ब्राज़ील	2.8	1.7	1.0	1.1
रूस	-3.4	-6.0	-2.3	-3.5
भारत	6.8	7.4	6.1	6.1
चीन	3.2	3.3	4.4	4.6
दक्षिण अफ्रीका	2.1	2.3	1.1	1.4

स्रोत: आईएमएफ।

चार्ट 1: वैश्विक जीडीपी के तात्कालिक अनुमान





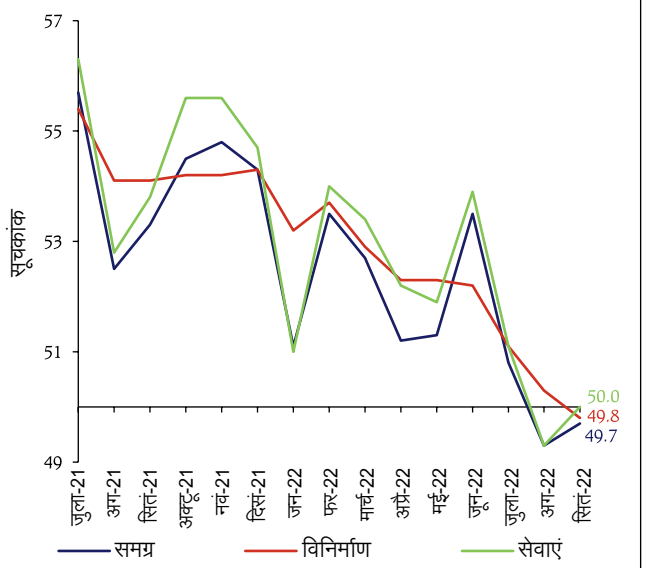
स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

तक आसानी से - यह विश्वास को दर्शाता है कि मुद्रास्फीति सख्त मौद्रिक नीति के साथ घट जाएगी। मॉडल-आधारित हमारे तात्कालिक अनुमान से संकेत मिलता है कि 2022 की दूसरी तिमाही में देखे गए संकुचन के 2022 की तीसरी तिमाही में विस्तारित होने की संभावना है (चार्ट 1:ए और बी)। [7]

उच्च आवृत्ति संकेतकों में, वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) सितंबर में मामूली रूप से बढ़कर 49.7 हो गया, जो अगस्त में 26 महीने का निचला स्तर 49.3 था। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई अगस्त में 50.3 से गिरकर सितंबर में 49.8 पर आ गया, जो जून 2020 के बाद पहली बार संकुचन क्षेत्र में पहुंच गया। मध्यवर्ती और निवेश वस्तुओं के क्षेत्रों में उत्पादन गिर गया जबकि व्यापार आशावाद 28 महीने के निचले स्तर पर गिर गया (चार्ट 2)।

सकारात्मक गति और अनुकूल आधार प्रभाव (चार्ट 3ए) के संयोजन से जुलाई 2022 में विश्व वस्तु व्यापार की मात्रा में 6.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो जून में 4.6 प्रतिशत थी। जहाजों की बढ़ती मांग के कारण बाल्टिक ड्राई इंडेक्स - शुष्क थोक वस्तुओं के लिए शिपिंग शुल्क का एक उपाय - सितंबर में

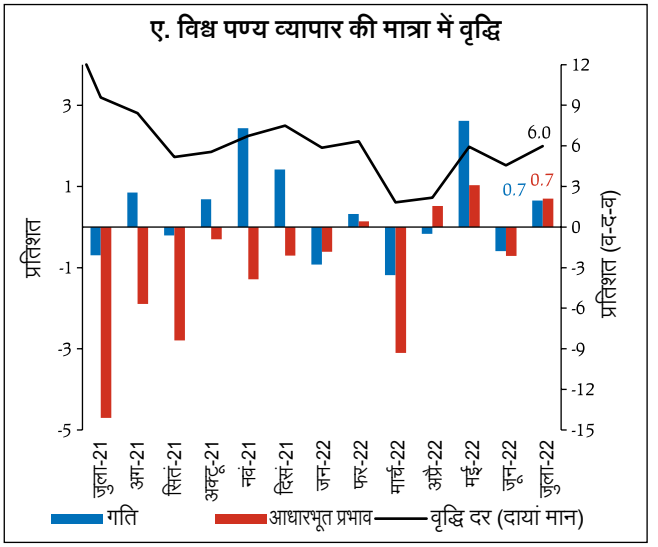
चार्ट 2: वैश्विक पीएमआई

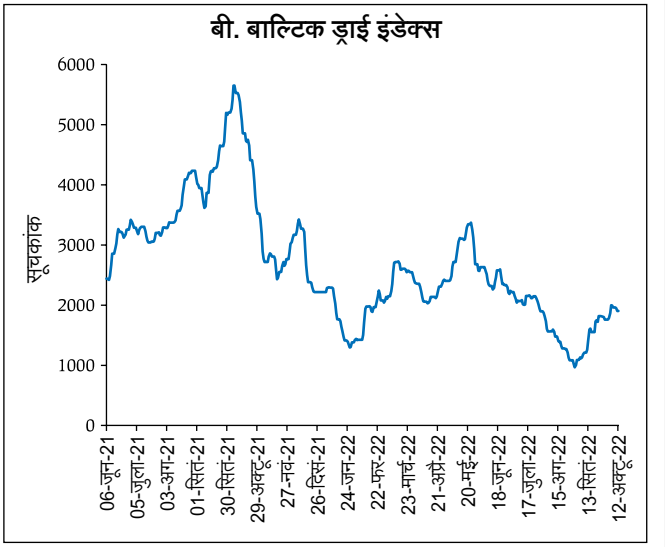


स्रोत: आईएचएस मार्किट।

82.4 प्रतिशत बढ़ गया, जो पिछले लगातार चार महीनों के लिए देखी गई गिरावट के विपरीत था (चार्ट 3 बी)। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, विश्व वस्तु व्यापार की मात्रा 2022 में 3.5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जो 2023 में 1.0

चार्ट 3: विश्व व्यापार और शिपिंग लागत





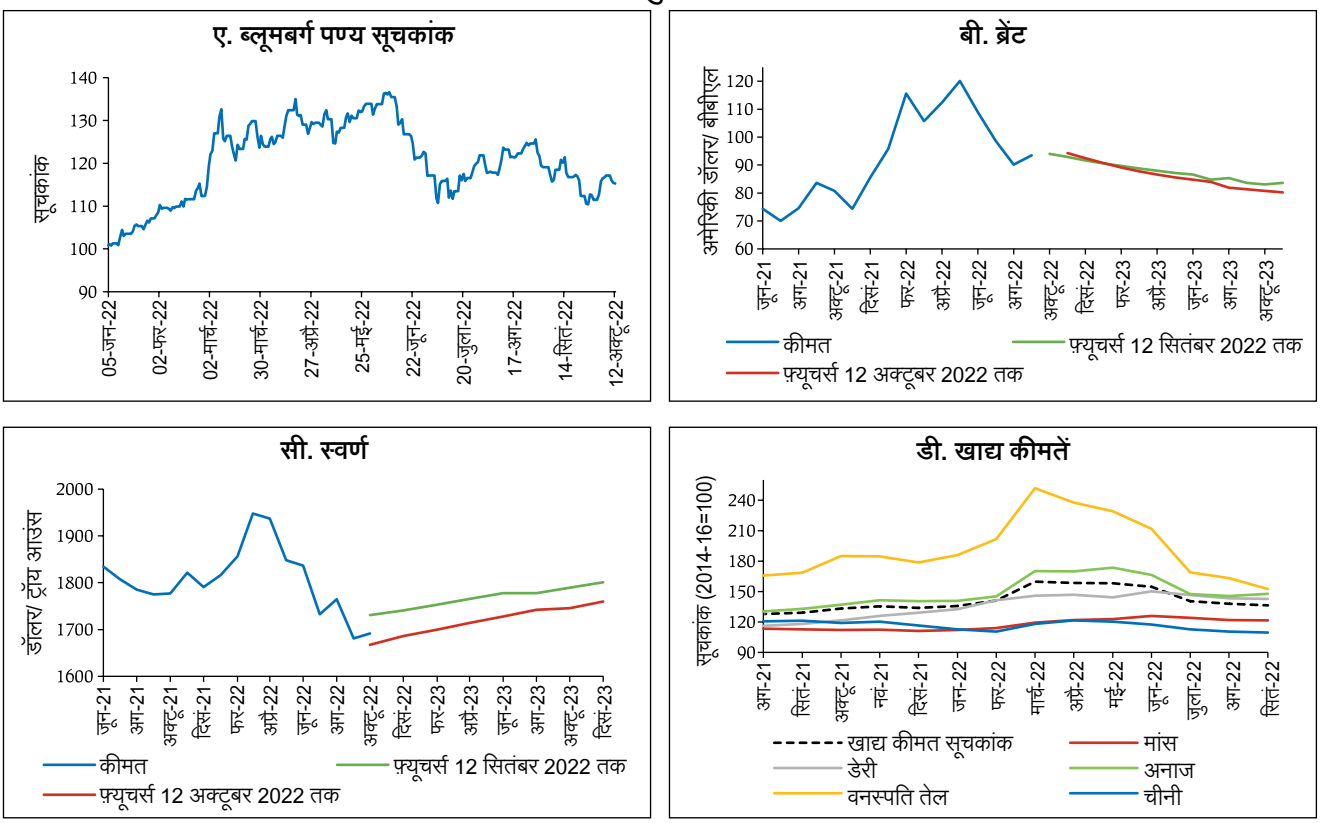
स्रोत: सीपीबी नीदरलैंड; और ब्लूमबर्ग।

[7] मॉडल-आधारित तात्कालिक अनुमान, वैश्विक संकेतकों जैसे पीएमआई विनिर्माण और वैश्विक आईआईपी *आदि* के साथ संवर्धित विभिन्न एआरआईएमए मॉडलों का औसत है। उपलब्ध होने पर बहिर्जात चरों के वास्तविक मूल्यों को तात्कालिक अनुमान उत्पन्न करने के लिए लिया गया था, अन्यथा, इसे चल औसत पद्धति का उपयोग करके आरोपित किया गया था। रमेश कुमार *और अन्य*, "नाउकास्टिंग ग्लोबल जीडीपी", आरबीआई बुलेटिन, जून 2022।

प्रतिशत तक धीमी हो जाएगी (2.4 प्रतिशत की गिरावट)। पीएमआई उप-सूचकांक भी लगातार सातवें महीने नए निर्यात कारोबार की मात्रा में गिरावट और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह में गिरावट का संकेत देते हैं।

वैश्विक कमोडिटी की कीमतें अस्थिर बनी रहीं, सितंबर के अंत तक 8.3 प्रतिशत की गिरावट आई क्योंकि वैश्विक विकास धीमा होने से मांग कम हो गई (चार्ट 4 ए)। कच्चे तेल की कीमतें सितंबर में औसतन 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करती हैं, जो 7 महीनों में उनका सबसे कम स्तर है, और वैश्विक मांग में कमी और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के जवाब में 3 अक्टूबर तक गिरावट जारी रही। ओपेक प्लस कार्टेल और संबद्ध उत्पादकों ने सामूहिक रूप से 5 अक्टूबर को उत्पादन को प्रति दिन 2 मिलियन बैरल या वैश्विक खपत के लगभग 2 प्रतिशत तक कम करने पर सहमति व्यक्त की (चार्ट 4 बी)। सोने की कीमतें सितंबर में 28 सितंबर को 1,618 अमेरिकी डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के निचले स्तर पर पहुंच गईं, जो अप्रैल 2020 के बाद से सबसे कम है, जो यूएस 10 साल के जी-सेक प्रतिफल (चार्ट 4 सी) में वृद्धि को दर्शाता है। अक्टूबर में अब तक सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव रहा है और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण इसमें मामूली तेजी आई है। एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक ने सितंबर 2022 में 1.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ अपनी लगातार छठी मासिक गिरावट दर्ज की, जो अनाज उप-सूचकांक (चार्ट 4 डी) को छोड़कर इसके सभी उप-सूचकांकों[8] में गिरावट से चिह्नित है। वनस्पति तेल की कीमतों में सुधार सबसे तेज रहा है क्योंकि वे मार्च 2022 में दर्ज ऐतिहासिक उच्च स्तर से 40 प्रतिशत तक गिर गए हैं।

चार्ट 4: पण्य वस्तु और खाद्य कीमतें



स्रोत: ब्लूमबर्ग; विश्व बैंक पिंक शीट; और एफएओ।

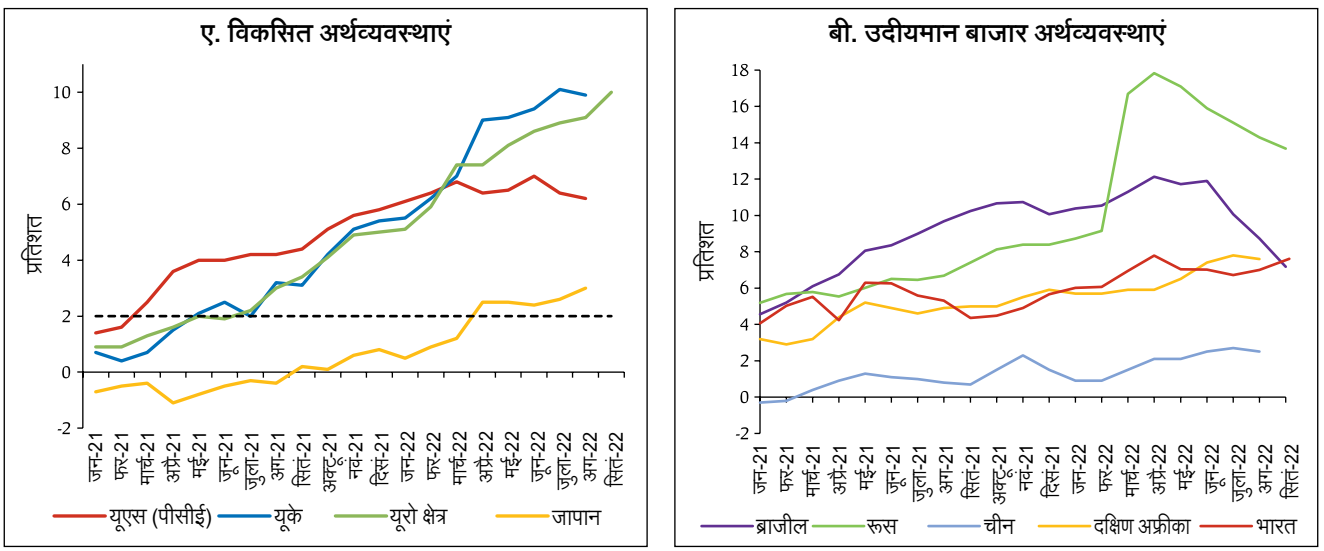
[8] खाद्य और कृषि संगठन उप-सूचकांकों में अनाज, वनस्पति तेल, डेयरी, मांस और चीनी मूल्य सूचकांक शामिल हैं।

उच्च मुद्रास्फीति अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रमुख नीतिगत चिंता बनी हुई है, भले ही कमोडिटी की कीमतों में हालिया गिरावट के कारण कई देशों में मुद्रास्फीति शिखर से नीचे आ गई है। अमेरिका की खुदरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर 2022 में घटकर 8.2 प्रतिशत रही जो अगस्त में 8.3 प्रतिशत थी। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) सूचकांक (फेड का पसंदीदा उपाय) पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त 2022 में सालाना आधार पर 6.2 प्रतिशत थी, जो अनुकूल आधार प्रभाव (चार्ट 5 ए) के कारण जुलाई में 6.4 प्रतिशत से मामूली रूप से कम थी। यूरो क्षेत्र में, वार्षिक मुद्रास्फीति सितंबर 2022 में 10.0 प्रतिशत के नए शिखर पर पहुंच गई, जो अगस्त में 9.1 प्रतिशत थी, जिसमें ऊर्जा, भोजन, शराब और तंबाकू शामिल थे। ब्रिटेन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में 9.9 प्रतिशत रही जो जुलाई के 10.1 प्रतिशत से मामूली कम है। ब्रिक्स[9] अर्थव्यवस्थाओं में, ब्राजील में मुद्रास्फीति अगस्त में 8.7 प्रतिशत से सितंबर में घटकर 7.2 प्रतिशत हो गई, जबकि रूस में यह अगस्त में 14.3 प्रतिशत से सितंबर में घटकर 13.7 प्रतिशत हो गई (चार्ट 5 बी)।

वैश्विक इक्विटी बाजारों ने सितंबर की दूसरी छमाही में बढ़त खो दी, एमएससीआई वर्ल्ड इक्विटी इंडेक्स अगस्त की तुलना में 9.7 प्रतिशत कम रहा। ईएमई उप-सूचकांक में गिरावट एई (चार्ट 6 ए) की तुलना में बहुत अधिक स्पष्ट थी। बॉन्ड बाजार में प्रमुख एई में 10 साल के जी-सेक प्रतिफल में सख्ती आई है, जो केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख को दर्शाता है। 10 साल के अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में सितंबर में 64 आधार अंकों की वृद्धि हुई, जबकि 2 साल की जी-सेक यील्ड में 79 बीपीएस की वृद्धि हुई, जिससे यील्ड वक्र में भारी उलटापन हुआ (चार्ट 6 बी)। फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण अमेरिकी डॉलर में सितंबर में तेजी जारी रही और यह 20 साल के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही, ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक में सितंबर में गिरावट आई, पूंजी बहिर्वाह (चार्ट 6 सी और 6 डी) से बढ़ गई।

बढ़ती मुद्रास्फीति के सामने फेड मौद्रिक नीति को कितने आक्रामक रूप से सख्त करेगा, इस पर दांव से प्रेरित विदेशी मुद्रा बाजारों में बढ़ी हुई अस्थिरता ने अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा दिया है, जबकि अन्य मुद्राओं को झटका लगा है (चार्ट 7)। ड्यूश

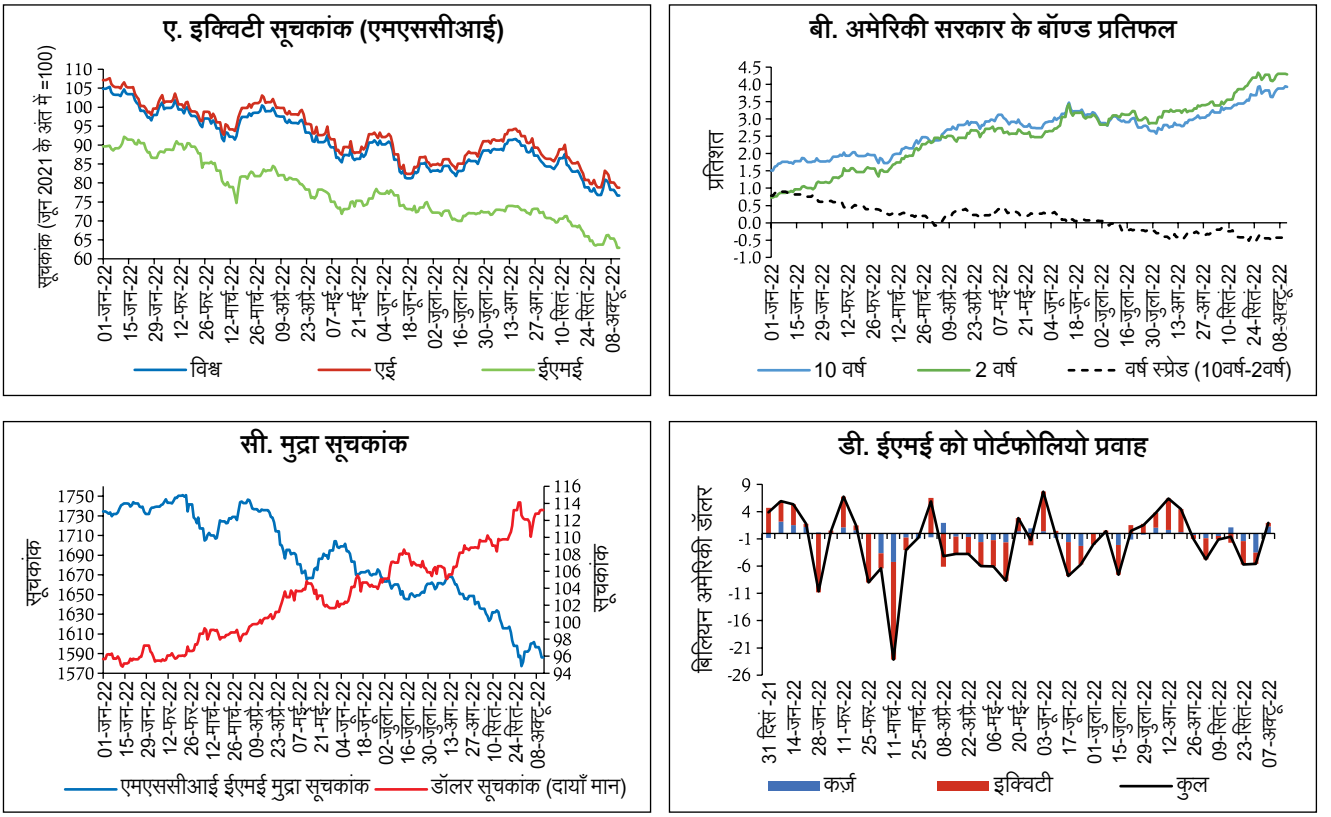
चार्ट 5: मुद्रास्फीति



स्रोत: ब्लूमबर्ग।

[9] ब्रिक्स से तात्पर्य है: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।

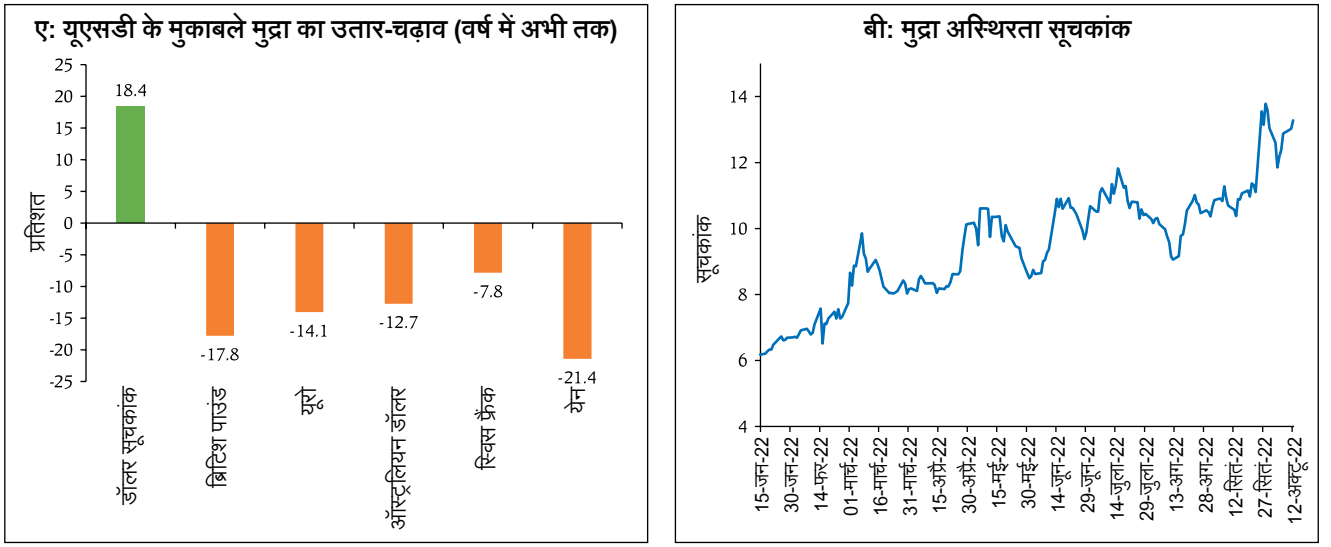
चार्ट 6: वित्तीय बाजार



स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

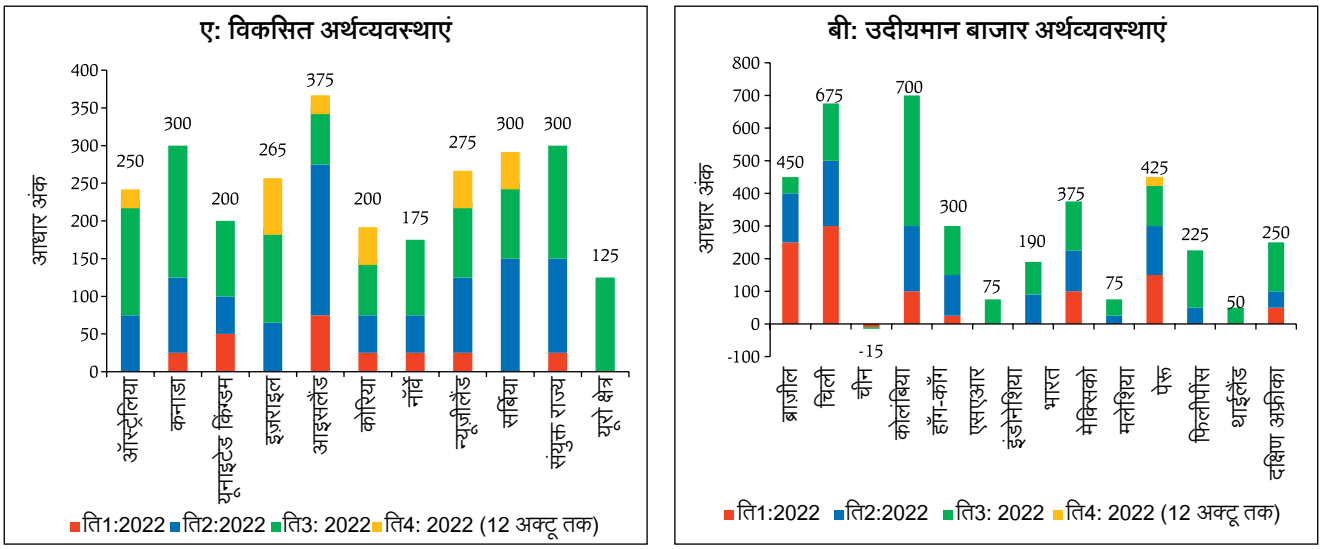
बैंक का मुद्रा अस्थिरता सूचकांक - प्रमुख जी 7 मुद्राओं का ऐतिहासिक अस्थिरता सूचकांक - अक्टूबर में कई महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया क्योंकि केंद्रीय बैंक ने चलनिधि आहरण जारी रखा।

चार्ट 7: मुद्रा बाजार आवर्तन



स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट 8: समकालिक नीतिगत वृद्धि



स्रोत: बीआईएस।

अधिकांश एई और ईएमई के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति के दबाव को तोड़ने के लिए सिंक्रनाइज़ मौद्रिक सख्ती जारी रखी (चार्ट 8)। सितंबर के महीने के दौरान, फेडरल रिजर्व ने फेडरल फंड दर की अपनी लक्षित सीमा में 75 बीपीएस की वृद्धि की, जो लगातार तीसरी 75 बीपीएस वृद्धि थी, अनुमानों से पता चलता है कि बेंचमार्क दर इस साल के अंत तक 4.4 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी और अगले साल 4.6 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और बैंक ऑफ कनाडा ने भी 75 बीपीएस दर वृद्धि के साथ अपनी मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया। स्वीडन ने अपनी नीतिगत दर में 100 बीपीएस की वृद्धि की और स्विट्जरलैंड ने 75 बीपीएस की दर वृद्धि के साथ यूरोप के नकारात्मक दर युग को समाप्त कर दिया। ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड ने अपनी नीतिगत दरों में 50-50 आधार अंकों की वृद्धि की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड ने अपनी नवीनतम बैठकों में अपनी नीतिगत दरों में 25-25 आधार अंकों की वृद्धि की है। दूसरी ओर, जापान ने उदार रुख बनाए रखते हुए अलग होना जारी रखा है।

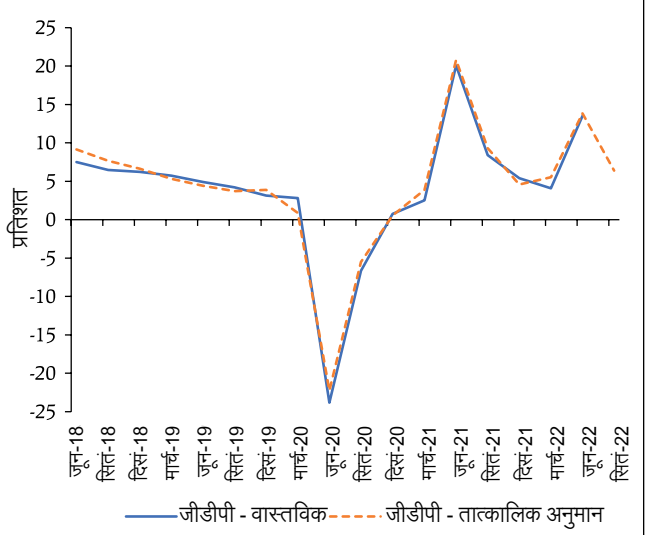
अधिकांश ईएमई केंद्रीय बैंकों ने भी नीतिगत सख्ती जारी रखी है। हंगरी, चिली और थाईलैंड ने अपनी नवीनतम बैठकों में अपनी नीतिगत दरों में क्रमशः 125 बीपीएस, 50 बीपीएस और 25 बीपीएस की वृद्धि की। अन्य ईएमई के विपरीत, तुर्की ने अगस्त और सितंबर में अपनी दरों में 100 बीपीएस की कटौती की और चीन उदार बना रहा, जबकि ब्राजील और चेक गणराज्य ने अपनी नवीनतम बैठकों में ठहराव बनाए रखा है।

III. घरेलू विकास

अनिश्चित और नाजुक वैश्विक आर्थिक माहौल में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया। कुल मांग के संकेतक से संकेत मिलता है कि त्योहारी सीजन की शुरुआत और दबी हुई मांग ने वृद्धि को मजबूत बनाए रखा। हमारा आर्थिक गतिविधि सूचकांक जो 27 उच्च आवृत्ति संकेतकों के साथ एक गतिशील कारक मॉडल (डीएफएम) को नियोजित करता है, अब दूसरी तिमाही: 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि को 6.4 प्रतिशत पर दर्शाता है (चार्ट 9) है।

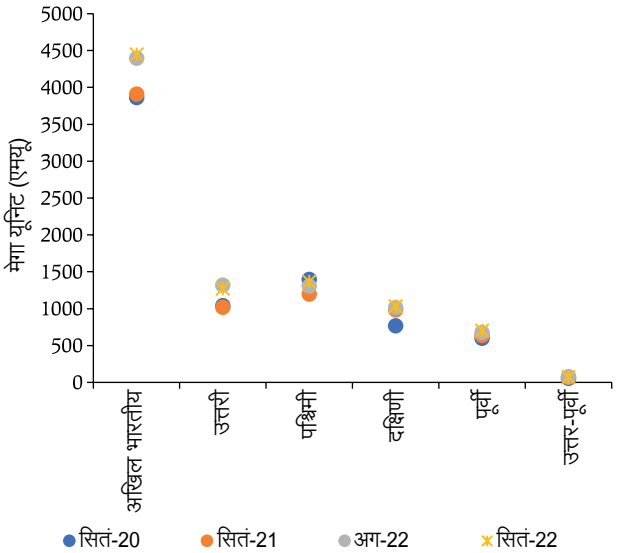
कई उच्च आवृत्ति संकेतक उच्च रहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी ने यात्रा, आतिथ्य और निर्माण क्षेत्रों को सहायता प्रदान की है। सितंबर में बिजली उत्पादन में तेजी आई (चार्ट 10)।

चार्ट 9: जीडीपी - वास्तविक और तात्कालिक अनुमान



स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 10: बिजली उत्पादन



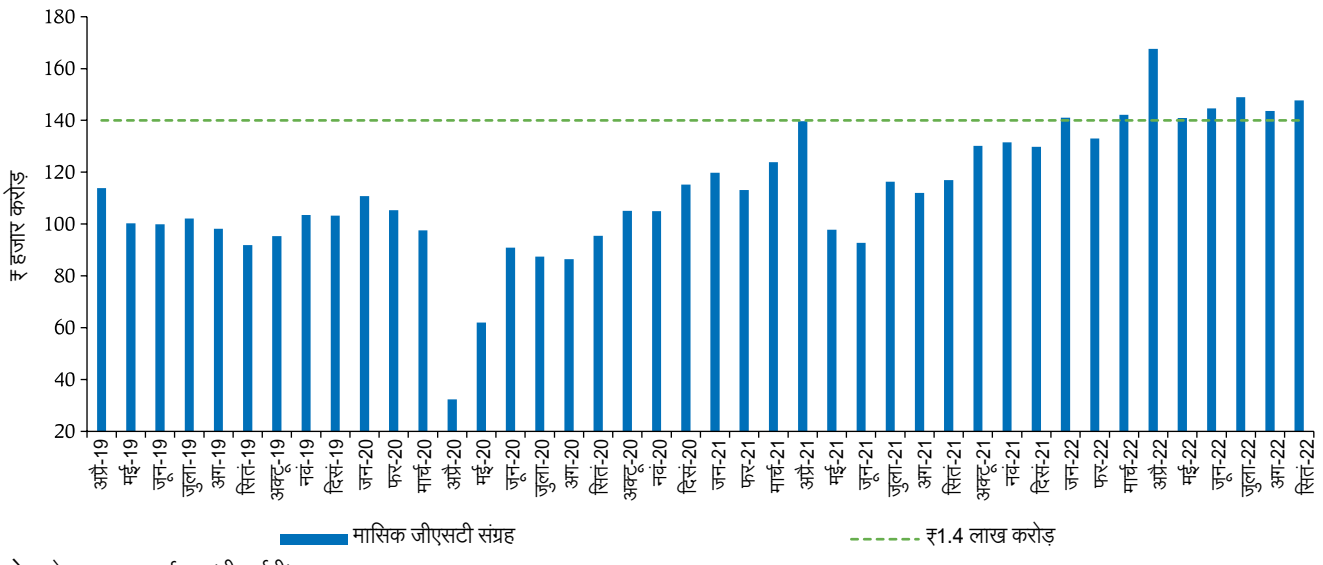
स्रोत: पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड।

जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्यों) ने 26.2 प्रतिशत की साल-दर-साल (वर्ष-दर-वर्ष) की मजबूत वृद्धि दर्ज की और सितंबर 2022 में 1.48 लाख करोड़ रुपये रहा, जो लगातार सातवें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक था (चार्ट 11)।

त्योहारी सीजन (चार्ट 12ए) से प्रेरित अर्थव्यवस्था में आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण सितंबर में ई-वे बिलों का उत्पादन 84 मिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर दर्ज किया गया। टोल संग्रह भी मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में दृढ़ता से बढ़ा (चार्ट 12 बी)।

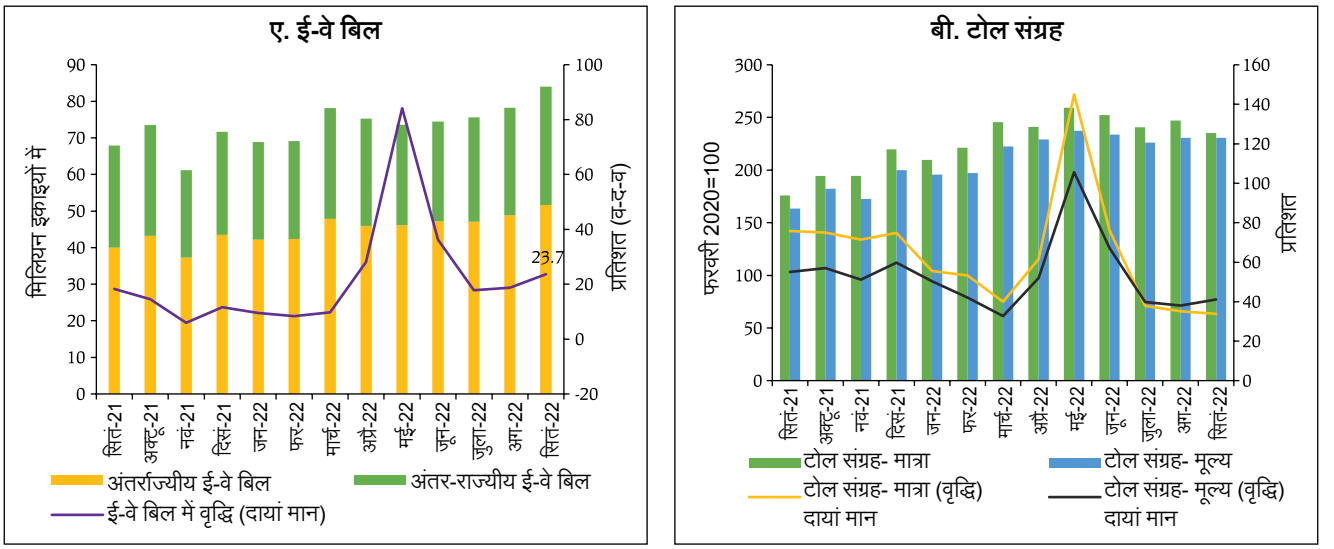
रिफाइनरियों के मौसमी रखरखाव के कारण सितंबर में सभी श्रेणियों में ईंधन की खपत कम हो गई (चार्ट 13 ए)। मांग में कमी और चिप की कमी में कमी ने सितंबर में

चार्ट 11: मासिक जीएसटी राजस्व



स्रोत: प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी)।

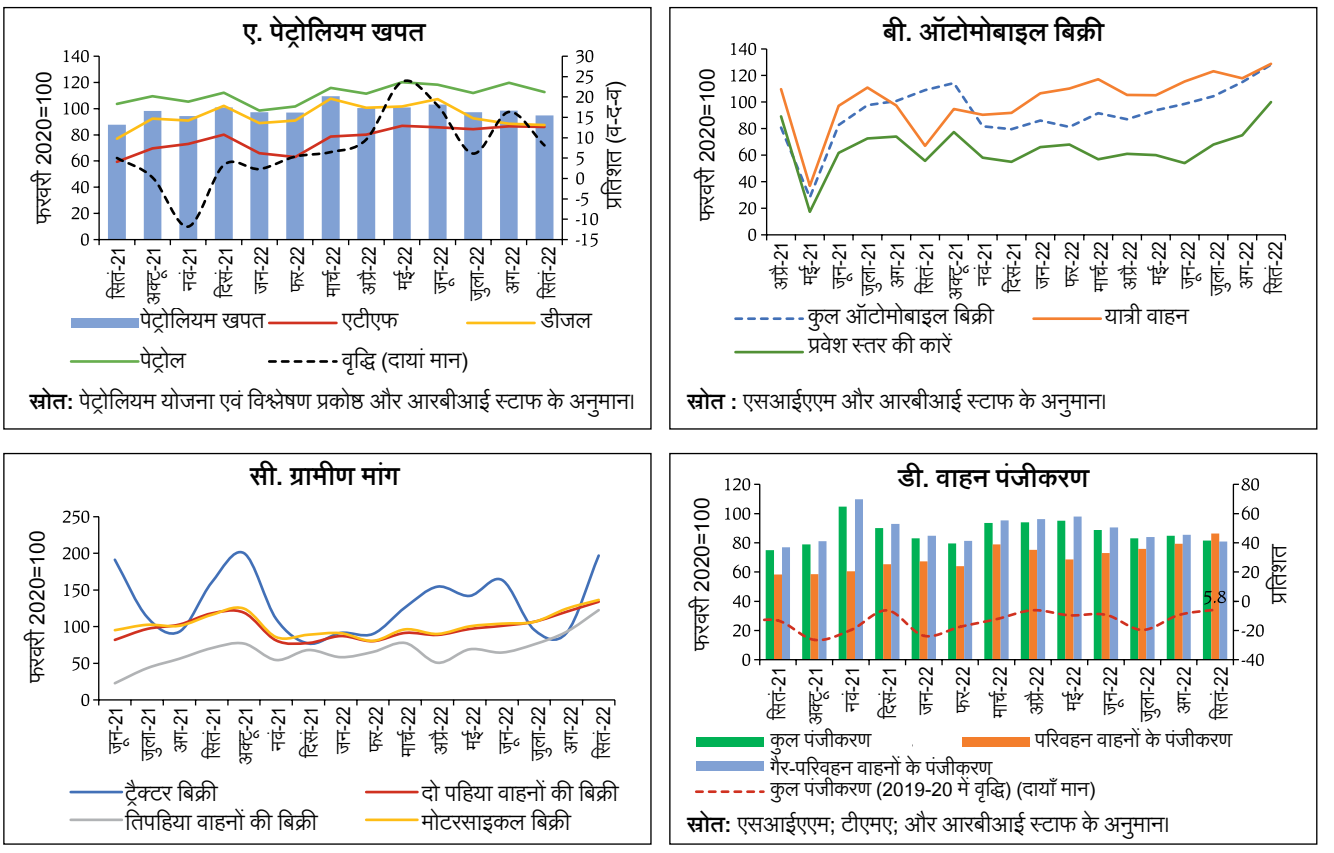
चार्ट 12: ई-वे बिल और टोल संग्रह



स्रोत: जीएसटीएन; आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

ऑटोमोबाइल थोक प्रेषण को ग्यारह महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। इससे एंट्री लेवल कार सेगमेंट और थ्री-व्हीलर्स की बिक्री महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गई (चार्ट 13बी)।

चार्ट 13: परिवहन क्षेत्र संकेतक



स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

स्रोत : एसआईएएम और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

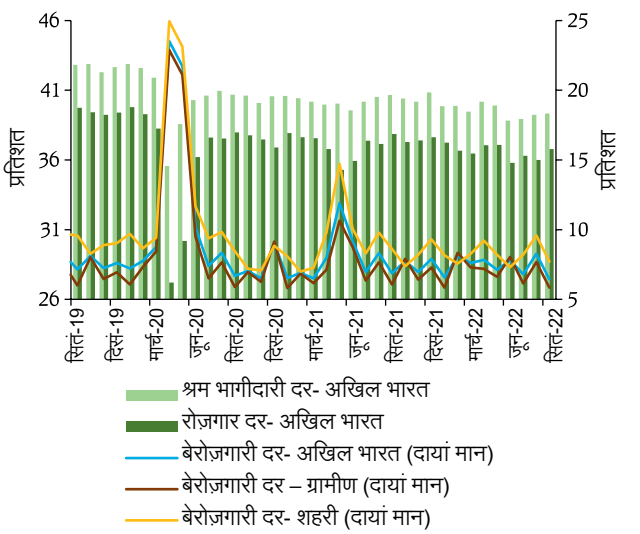
स्रोत: एसआईएएम; टीएमए; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

दोपहिया, तिपहिया और मोटरसाइकिलों की घरेलू बिक्री सालाना आधार पर और महामारी से पहले के स्तर पर बढ़ने के साथ ग्रामीण मांग संकेतकों में तेजी आई। घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री सितंबर में ग्यारह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई (चार्ट 13 सी)। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अनुसार, सितंबर में वाणिज्यिक वाहन बिक्री पंजीकरण में भी वृद्धि हुई, जिसमें थोक बेड़े (बल्क फ्लीट) खरीद के कारण भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई (चार्ट 13 डी)।

जिंसों और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में दोहरे अंकों की वृद्धि से एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़ी है। मूल्य सुधार के कारण सितंबर 2022 में मूल्य वृद्धि में क्रमिक गिरावट आई, यहां तक कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वॉल्यूम वृद्धि बनी रही।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, बेरोजगारी दर सितंबर 2022 में गिरकर 6.4 प्रतिशत हो गई, जो श्रम भागीदारी में मामूली सुधार और रोजगार दर में 36.8 प्रतिशत तक की वृद्धि की पृष्ठभूमि में अगस्त 2018 के बाद से सबसे कम है - पिछले चार महीनों में सबसे अधिक (चार्ट 14)।

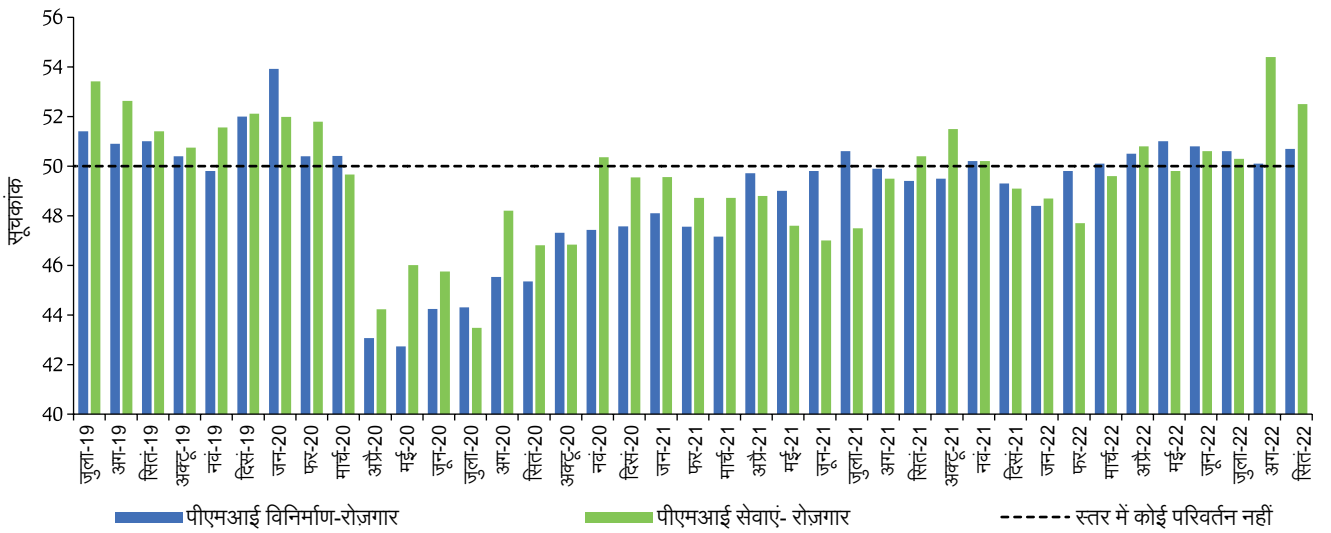
चार्ट 14: रोज़गार, बेरोज़गारी, श्रम भागीदारी दरें



स्रोत: सीएमआईई।

संगठित क्षेत्र के रोजगार परिदृश्य के संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्र के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) रोजगार उप-सूचकांक में लगातार सातवें महीने वृद्धि दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र रोजगार पीएमआई लगातार चौथे महीने विस्तारवादी क्षेत्र में बना हुआ है, हालांकि पिछले महीने 14 साल के उच्च स्तर से कम हो रहा है (चार्ट 15)।

चार्ट 15: पीएमआई रोज़गार सूचकांक



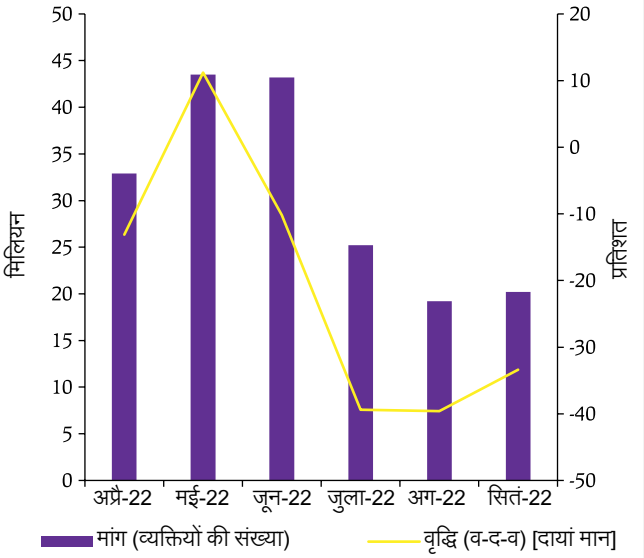
टिप्पणी: 50 से ऊपर का पीएमआई मान विस्तार इंगित करता है।
स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल ।

ग्रामीण क्षेत्रों में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम की मांग सितंबर में मामूली रूप से बढ़ी, जो खरीफ बुवाई की कमी को दर्शाता है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, इसमें 33.4 प्रतिशत की गिरावट आई, जो गैर-कृषि क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दर्शाता है (चार्ट 16)।

सितंबर में 3.8 प्रतिशत की क्रमिक गिरावट के बावजूद, 35.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत के व्यापारिक निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो धीमी बाहरी मांग के नॉक-ऑन प्रभावों को दर्शाता है (चार्ट 17)। हालांकि, 2022-23 की पहली छमाही के दौरान, 231.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक निर्यात ने 17.0 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर्ज की।

व्यापक श्रेणियों के संदर्भ में, पेट्रोलियम निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि हुई, जो पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात करों में कमी के प्रभाव को दर्शाता है। दूसरी ओर, गैर-तेल निर्यात सितंबर 2022 में लगातार दूसरे महीने सिकुड़ गया। इंजीनियरिंग वस्तुएं, जो निर्यात बास्केट का लगभग एक चौथाई हिस्सा हैं, में लगातार तीसरे महीने गिरावट आई है, जो लोहे और इस्पात उत्पादों पर लगाए गए निर्यात कर के प्रभाव को दर्शाती है (सारणी 2)। कपड़ा और सूती धागे अन्य प्रमुख समूह

चार्ट 16: मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग



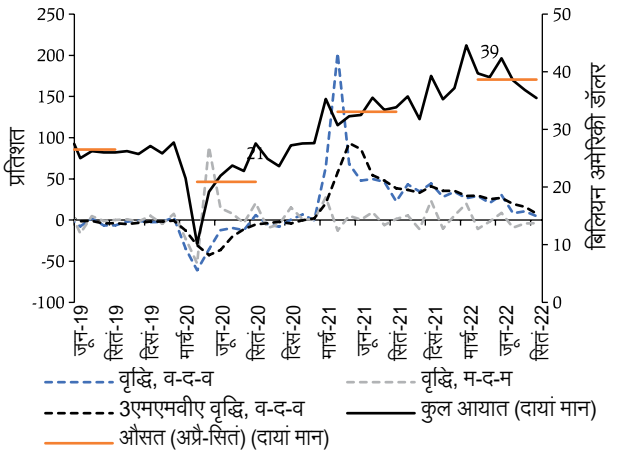
स्रोत: भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

थे जो अनुक्रमिक और वर्ष-दर-वर्ष दोनों आधारों पर अनुबंधित थे।

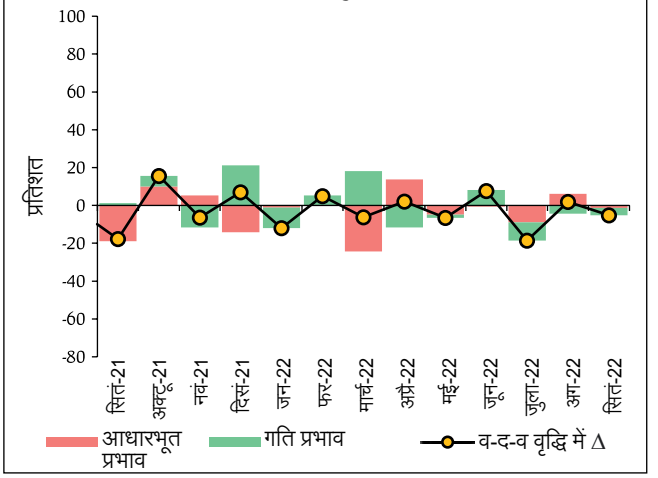
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और रत्न और आभूषणों के निर्यात द्वारा मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया गया था, बाद में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के कार्यान्वयन के बाद संयुक्त अरब अमीरात में मजबूत मांग से लाभ हुआ।

चार्ट 17: भारत का पण्य वस्तु निर्यात - सितंबर 2022

ए. भारत के पण्य वस्तु निर्यात में रुझान



बी. वर्ष-दर-वर्ष निर्यात वृद्धि में अनुक्रमिक परिवर्तन का वियोजन



टिप्पणी: 3एमएमवीए तीन महीने का चर मान औसत है।
स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सारणी 2: शीर्ष 10 निर्यातित वस्तुएं

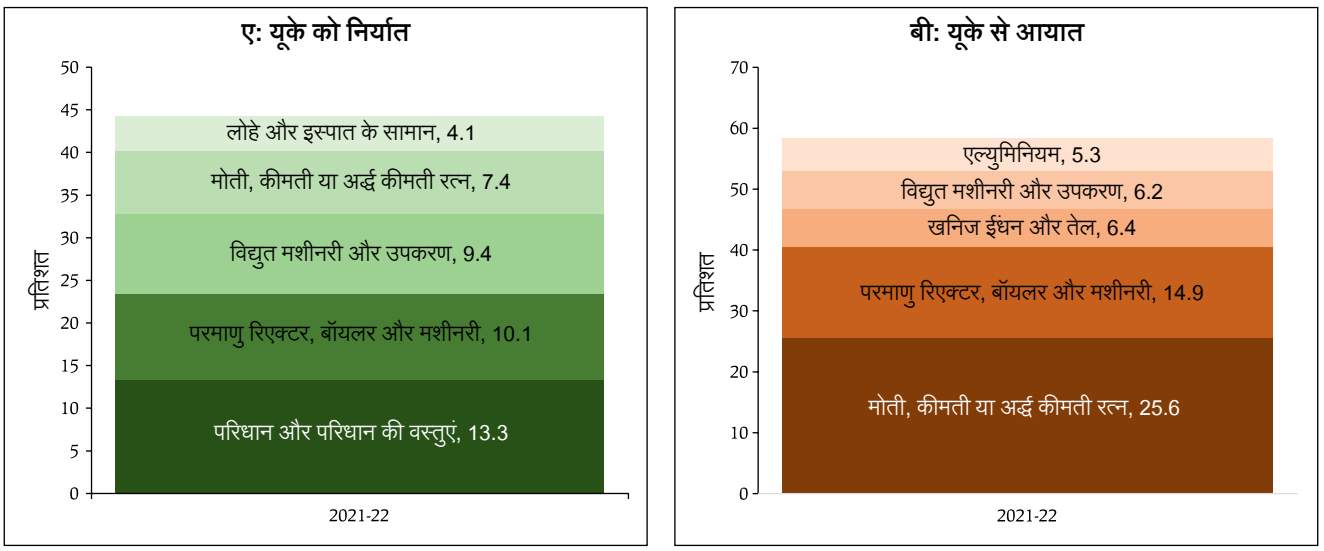
	सितंबर 2022				अप्रैल-सितंबर 2022	
शीर्ष 10 पण्य समूह	**हिस्सेदारी (प्रतिशत)**	**बिलियन यूएस$**	**व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)**	**माह-दर-माह वृद्धि**	**बिलियन यूएस$**	**व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)**
इंजीनियरिंग माल	24	8.4	-10.9	1.2	55.0	0.9
पेट्रोलियम उत्पाद	18	7.4	43.0	-12.5	51.2	79.3
रत्न एवं आभूषण	11	3.8	17.3	13.9	20.6	6.9
जैविक और अकार्बनिक रसायन	7	2.4	3.0	-6.1	15.9	14.0
दवा एवं औषधि	6	2.2	6.9	2.4	12.7	6.0
इलेक्ट्रानिक सामान	6	2.0	72.0	16.7	10.3	57.6
सभी तरह के कपड़ों के रेडीमेड वस्त्र	3	1.1	-18.1	-13.6	8.2	11.4
चावल	2	0.8	-39.0	-9.5	5.8	-20.6
सूती धागे/ कपड़े/ मेड-अप्स, हथकरघा उत्पाद *आदि*	2	0.8	1.6	-23.9	5.5	18.5
समुद्री उत्पाद	2	0.7	6.3	8.7	4.1	7.4
10 प्रमुख पण्य समूहों का कुल योग	84	29.6	7.8	-2.5	189.3	19.0
कुल निर्यात	**100.0**	**35.4**	**4.8**	**-3.8**	**231.9**	**17.0**

स्रोत: एमओसीआई।

भारत और ब्रिटेन ने जनवरी 2022 में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता शुरू की थी। पांचवें दौर की वार्ता जुलाई 2022 में संपन्न हुई थी। भारत ब्रिटेन के साथ एक व्यापारिक व्यापार अधिशेष चलाता है, जिसमें प्रमुख निर्यात परिधान और कपड़े, मशीनरी, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर हैं, जबकि यूके से आयातित प्रमुख वस्तुएं पत्थर, परमाणु रिएक्टर, खनिज ईंधन और तेल हैं (चार्ट 18)।

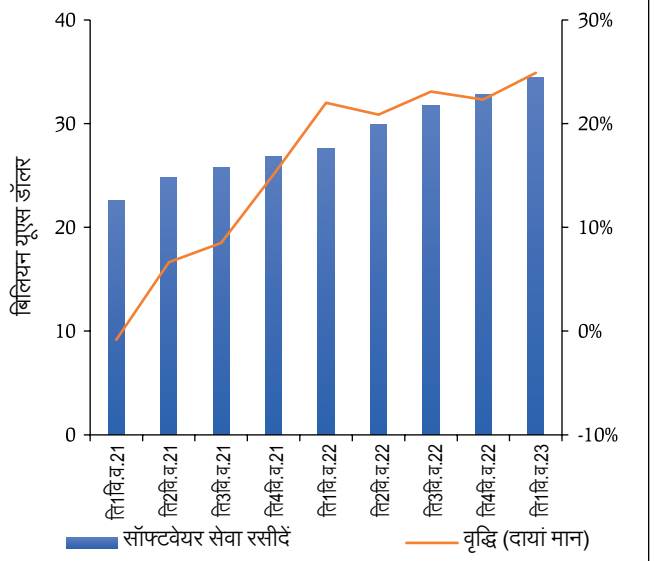
सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक की स्थिर वृद्धि देखी जा रही है, जो आंशिक रूप से मजबूत फॉरवर्ड बाहरी व्यापार संबंधों से बढ़ी है, जैसा कि भारत में सूचना

चार्ट 18: ब्रिटेन के साथ भारत का पण्य व्यापार



स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट 19: सॉफ्टवेयर सेवा प्राप्तियां



स्रोत: आरबीआई।

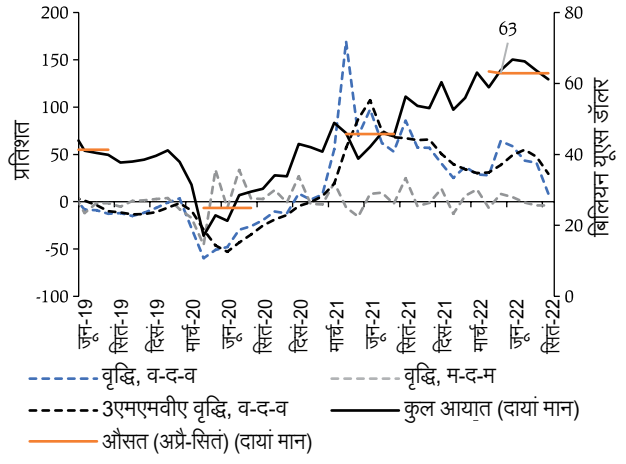
प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में विदेशी सहायक कंपनियों की निर्यात तीव्रता में परिलक्षित होता है। कुल सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं का हिस्सा दो-तिहाई से अधिक है (चार्ट 19)।[10] कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) 2021-22 के निर्यात पर रिज़र्व बैंक के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तरी अमेरिका कुल सॉफ्टवेयर निर्यात के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है, इसके बाद यूरोप[11] है। आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) सेवाएं महामारी में लचीली रही हैं।

सितंबर 2022 में लगातार पांचवें महीने भारत का व्यापारिक आयात 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा, हालांकि आयात वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.7 प्रतिशत तक कम हो गई और क्रमिक रूप से 3.8 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट 20)। 2022-23 की पहली छमाही के दौरान, आयात 38.6 प्रतिशत बढ़कर 380.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

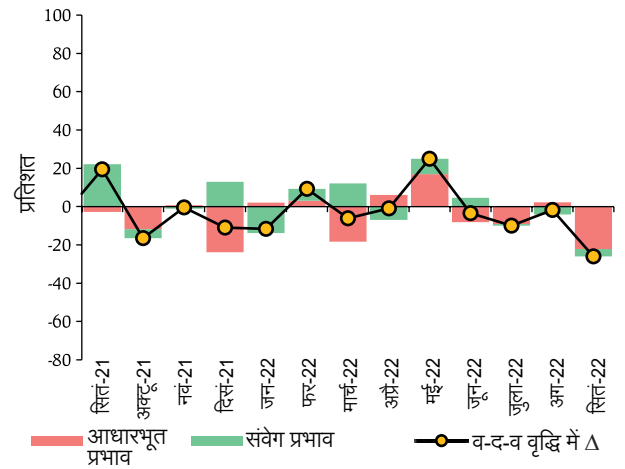
शीर्ष 10 प्रमुख कमोडिटी समूहों के विश्लेषण से पता चलता है कि कच्चे उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों, मशीनरी और रसायनों जैसी वस्तुओं में सितंबर में क्रमिक आधार पर संकुचन देखा गया (सारणी 3)।

चार्ट 20: भारत का पण्य वस्तु आयात - सितंबर 2022

ए: भारत के पण्य वस्तु आयात में रुझान



बी: वर्ष-दर-वर्ष आयात वृद्धि में अनुक्रमिक परिवर्तन का अपघटन



टिप्पणी: *3एमएमवीए तीन महीने का चल मान औसत है।

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

[10] भारतीय प्रत्यक्ष निवेश संस्थाओं की विदेशी देयताओं और आस्तियों पर संगणना: 2021-22; https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=54408

[11] कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के निर्यात पर सर्वेक्षण: 2021-22; https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=54338

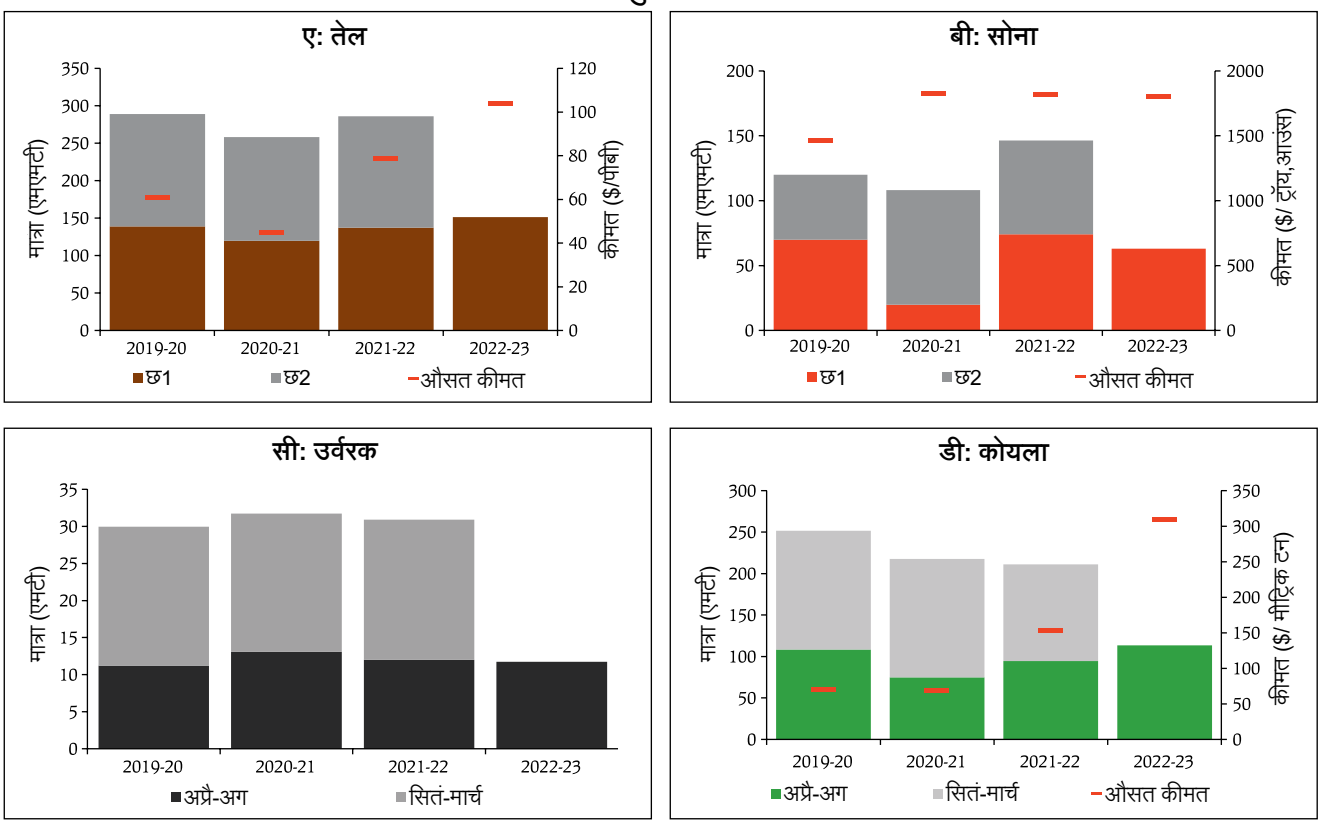
सारणी 3: शीर्ष 10 आयातित वस्तुएं

शीर्ष 10 पण्य समूह	सितंबर 2022				अप्रैल-सितंबर 2022	
	हिस्सेदारी (प्रतिशत)	बिलियन यूएस$	व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	माह-दर-माह वृद्धि	बिलियन यूएस$	व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)
पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद	26	15.9	-5.4	-17.9	115.3	65.8
इलेक्ट्रानिक सामान	12	7.1	3.8	-2.2	39.9	24.4
स्वर्ण	6	3.9	-24.6	8.3	20.3	-15.2
मशीनरी	6	3.7	16.5	-4.3	21.9	20.8
कोयला, कोक और ब्रिकेट्स इत्यादि	6	3.5	60.8	-22.3	30.3	153.6
परिवहन उपकरण	5	2.9	65.6	82.6	11.6	27.2
मोती, बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य रत्न	4	2.7	3.4	10.1	16.6	12.7
जैविक और अकार्बनिक रसायन	4	2.5	0.4	-15.7	18.8	34.0
वनस्पति तेल	3	2.0	-2.1	3.6	11.1	25.4
लौह और इस्पात	3	1.9	39.2	6.4	10.0	29.8
10 प्रमुख पण्य समूहों का कुल योग	75	46.0	3.8	-6.5	295.7	40.8
कुल निर्यात	**100.0**	**61.2**	8.7	-3.8	**380.3**	**38.6**

स्रोत: एमओसीआई।

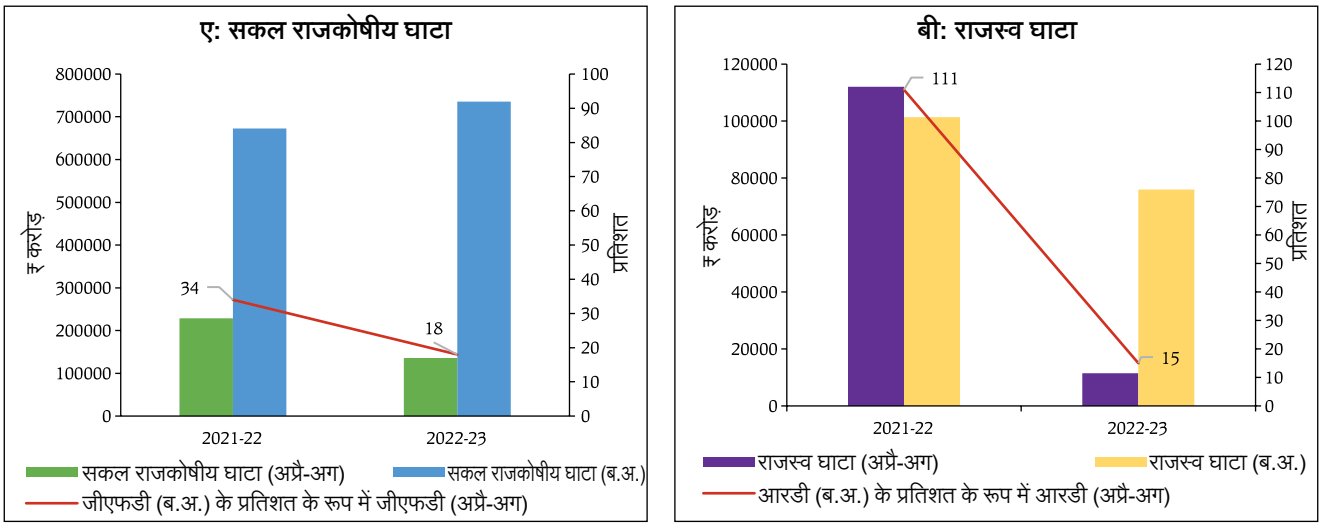
अप्रैल-सितंबर 2022-23 के दौरान तेल, सोना, उर्वरक और कोयले के आयात, जो भारत के कुल आयात का लगभग 41 प्रतिशत है, ने मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में एक मजबूत वृद्धि दर्ज की, जिससे व्यापार घाटे पर और दबाव पड़ा (चार्ट 21)।

चार्ट 21: प्रमुख पण्य आयात



स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईईएस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 22: अप्रैल-अगस्त के दौरान राज्यों के बजटीय घाटे में रुझान



टिप्पणी: डेटा 22 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), राज्यों के बजट दस्तावेज।

सितंबर 2022 में भारत का व्यापार घाटा 25.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो क्रमिक आधार पर मामूली रूप से कम था, लेकिन एक साल पहले की तुलना में लगभग 14.4 प्रतिशत अधिक था।

अप्रैल-अगस्त 2022-23 के दौरान राज्यों के राजकोषीय मापदंडों में सुधार हुआ, सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) और राजस्व घाटे (आरडी) दोनों में कमी के साथ- पूर्ण रूप से और साथ ही बजट अनुमान (बीई) के अनुपात में (चार्ट 22)।

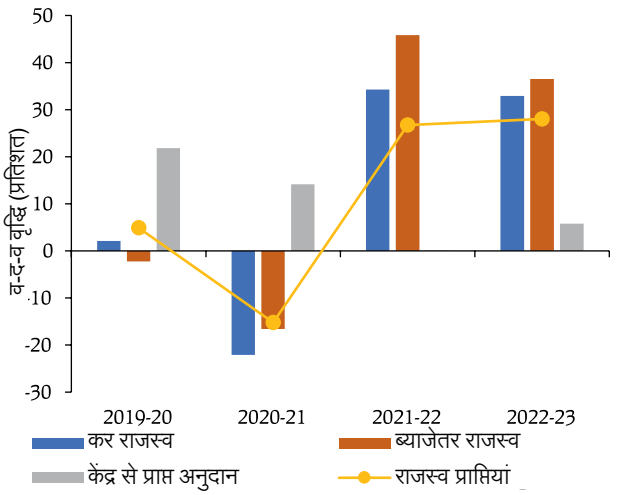
यह समेकन मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियों में 28 प्रतिशत की वृद्धि के माध्यम से हासिल किया गया है। कर राजस्व, जो इस अवधि में राजस्व प्राप्तियों का 76 प्रतिशत था, एसजीएसटी संग्रह में वृद्धि और केंद्र से कर हस्तांतरण में तेज वृद्धि के कारण 32.9 प्रतिशत की मजबूत गति से बढ़ा (चार्ट 23)। गैर-कर राजस्व में भी साल-दर-साल अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।

राज्यों की बात करें तो इस अवधि के दौरान पूंजीगत परिव्यय 6.5 प्रतिशत की मामूली दर से बढ़ा, जो 2022-23 की पहली तिमाही में गिरावट से उबर रहा है। राजस्व प्राप्तियों में मजबूत वृद्धि, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना के तहत ब्याज मुक्त 50 साल के ऋणों में वृद्धि और केंद्र द्वारा कर हस्तांतरण के फ्रंट-लोडिंग के साथ, राज्यों को 2022-23 की दूसरी छमाही में अपने पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि करने की उम्मीद है।

कुल आपूर्ति

दक्षिण पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) ने भारतीय उपमहाद्वीप से धीरे-धीरे वापस जाना शुरू कर दिया है। सीजन (1 जून - 30 सितंबर, 2022) के दौरान कुल बारिश लंबी अवधि (1971-

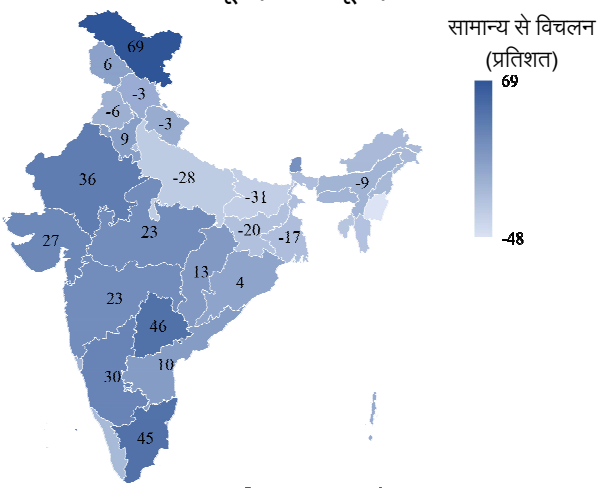
चार्ट 23: अप्रैल-अगस्त के दौरान राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में रुझान



टिप्पणी: आंकड़े 22 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।

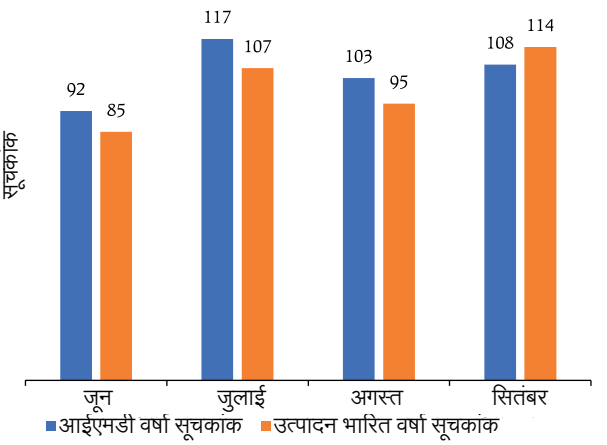
चार्ट 24: दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) 2022

ए. दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) का स्थानिक वितरण



स्रोत: आईएमडी।

बी. मासिक वर्षा सूचकांक



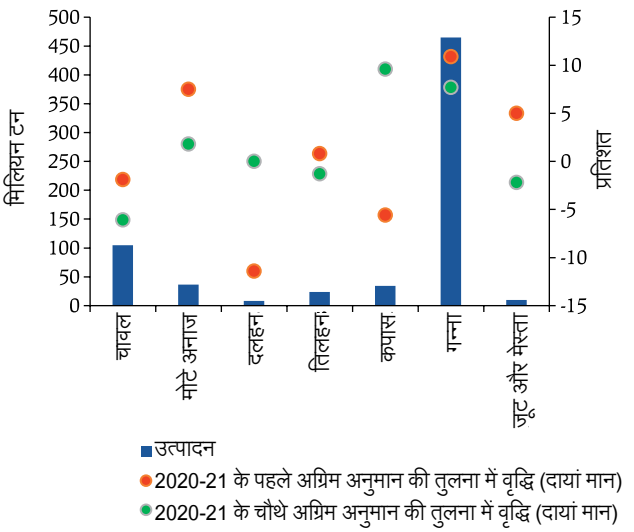
स्रोत: आईएमडी; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

2020) औसत (एलपीए) से 6 प्रतिशत अधिक थी। प्रारंभिक शुरुआत के बावजूद, हालांकि, वर्षा का अस्थायी और स्थानिक वितरण असमान था (चार्ट 24 ए)। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत (-18 प्रतिशत) को छोड़कर देश के अन्य सभी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। मौसम विभाग के 36 उपमंडलों में से 30 में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। उत्पादन भारित वर्षा सूचकांक (पीआरएन) सितंबर के महीने को छोड़कर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के कुल वर्षा सूचकांक से नीचे रहा (चार्ट 24 बी)। खरीफ की बुआई ने सितंबर में काफी तेजी पकड़ी और महीने के अंत तक, कुल बुवाई क्षेत्र 1102.8 लाख हेक्टेयर था, जो सामान्य बुवाई क्षेत्र से 1.8 प्रतिशत अधिक था, लेकिन पिछले साल के औसत से 0.8 प्रतिशत कम था।

वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ खाद्यान्न के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान (पहला एई) 149.9 मिलियन टन रखा गया था, जो 2021-22 के लिए पहले और चौथे अग्रिम अनुमानों की तुलना में क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत कम है। कम उत्पादन दक्षिण-पश्चिम मानसून के असमान स्थानिक और अस्थायी वितरण के प्रभाव को दर्शाता है, जिसमें प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण चावल और तिलहन सबसे अधिक प्रभावित होते हैं (चार्ट 25)। हालांकि, गन्ना और मक्का के क्रमशः तीसरे और चौथे वर्ष उत्पादन के रिकॉर्ड स्तर को छूने का अनुमान है।

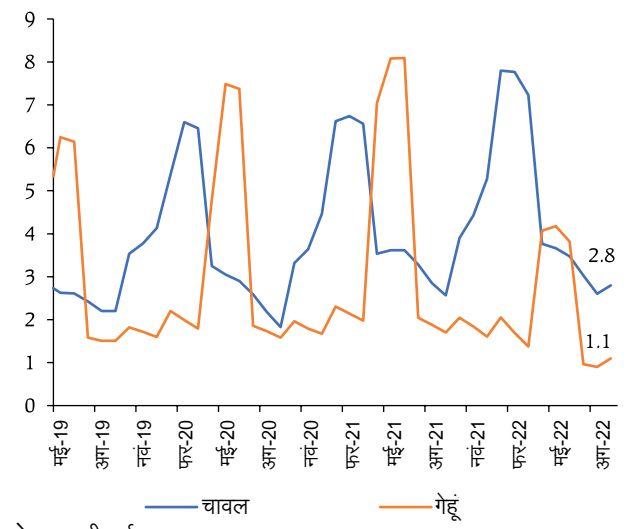
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 (13 अक्टूबर, 2022 तक) के दौरान चावल की खरीद 1.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 592.7 लाख टन रही। नए खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की शुरुआत अब तक 28.8 लाख टन की खरीद के साथ हुई है।

चार्ट 25: कृषि उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान



स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू)।

चार्ट 26: चावल और गेहूं के लिए स्टॉक टू नॉर्म अनुपात



स्रोत: एफसीआई।

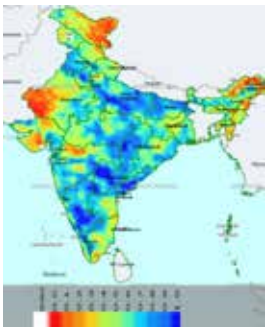
तिमाही बफर मानदंडों (अक्टूबर-दिसंबर) के अनुसार, चावल का स्टॉक स्तर 01 अक्टूबर 2022 तक आरामदायक (2.8 गुना) रहा। गेहूं के मामले में, 187.9 लाख मीट्रिक टन की संचयी खरीद से 227.5 लाख मीट्रिक टन का कुल स्टॉक हुआ, जो 1.1 गुना है; चालू तिमाही (ति. 3:2022-23) के लिए निर्धारित बफर मानदंडों से मामूली रूप से ऊपर (चार्ट 26)।

दक्षिण-पश्चिम मानसून का देर से पुनर्जीवित होना रबी के मौसम के लिए अच्छा संकेत है। जुलाई-सितंबर के दौरान अधिशेष वर्षा ने अनुकूल मिट्टी की नमी के स्तर और जलाशय भंडारण की स्थिति को जन्म दिया (चार्ट 27 ए)। 13 अक्टूबर तक जलाशय का स्तर पूरी क्षमता का 90 प्रतिशत था, जबकि पिछले साल का स्तर 83 प्रतिशत और दशकीय औसत 77 प्रतिशत था (चार्ट 27 बी)। सभी प्रमुख उर्वरक समूहों और बीज श्रेणियों की उपलब्धता अधिशेष में है, जिससे रबी की संभावनाओं को और उज्ज्वल किया जा रहा है (चार्ट 27 सी और 27 डी)।

देश के गरीब और कमजोर वर्गों के बीच पर्याप्त खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने "प्रधानमंत्री गरीब

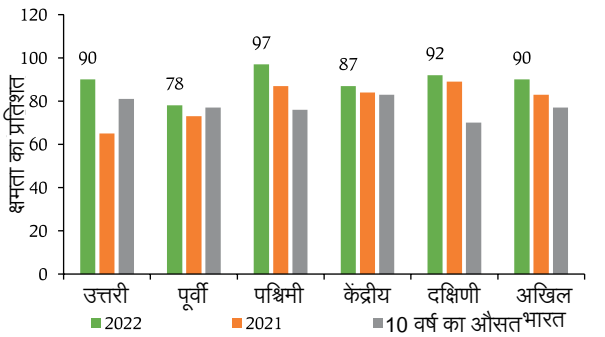
चार्ट 27: *रबी* 2022-23 - तैयारी और संभावनाएं

ए: मृदा आर्द्रता सूचकांक



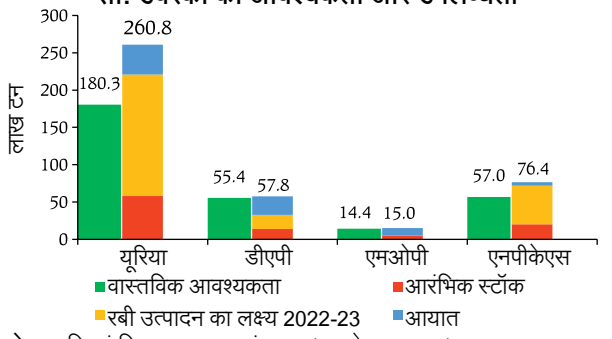
स्रोत: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)।

बी. जलाशय स्तर (13 अक्टूबर 2022)



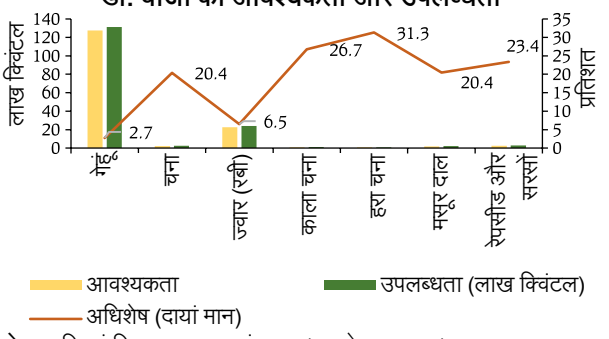
स्रोत: केंद्रीय जल आयोग।

सी: उर्वरकों की आवश्यकता और उपलब्धता



स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू)।

डी: बीजों की आवश्यकता और उपलब्धता

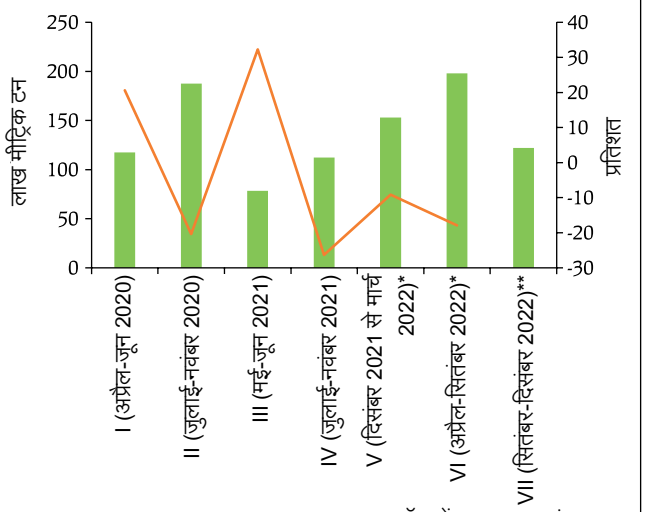


स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू)।

कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण VII)" को दिसंबर तक बढ़ा दिया है। 122 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के खाद्यान्न उठाव लक्ष्य के साथ, इसमें 44,762 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय व्यय शामिल है। चरण I से VI के तहत, अब तक (18 सितंबर 2022 तक) लगभग 927.8 एलएमटी खाद्यान्न (576.2 एलएमटी चावल और 351.6 एलएमटी गेहूं) उठाया गया है (चार्ट 28)।

औद्योगिक क्षेत्र में, हेडलाइन विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) पिछले दो महीनों की तुलना में कम गति से विस्तारवादी क्षेत्र में रहा। भविष्य के उत्पादन की उम्मीदें फरवरी 2015 के बाद से सबसे अधिक थीं, जबकि इनपुट कीमतें उप-घटक अक्टूबर 2020 के बाद से सबसे धीमी गति से बढ़ीं, जो कमोडिटी की कीमतों में हालिया गिरावट को दर्शाती हैं (चार्ट 29 ए)। सर्विसेज पीएमआई ने लगातार दूसरे महीने कारोबारी उम्मीदों को मजबूत करने का संकेत दिया, जो जनवरी 2015 के बाद से अपने उच्चतम मूल्य पर चढ़ गया। हेडलाइन पीएमआई सेवाएं विस्तारवादी क्षेत्र में बनी रहीं, हालांकि निरंतर इनपुट मूल्य दबाव, तेजी से प्रतिस्पर्धी माहौल और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा ब्याज दर में वृद्धि के

चार्ट 28: पीएमजीकेएवाई

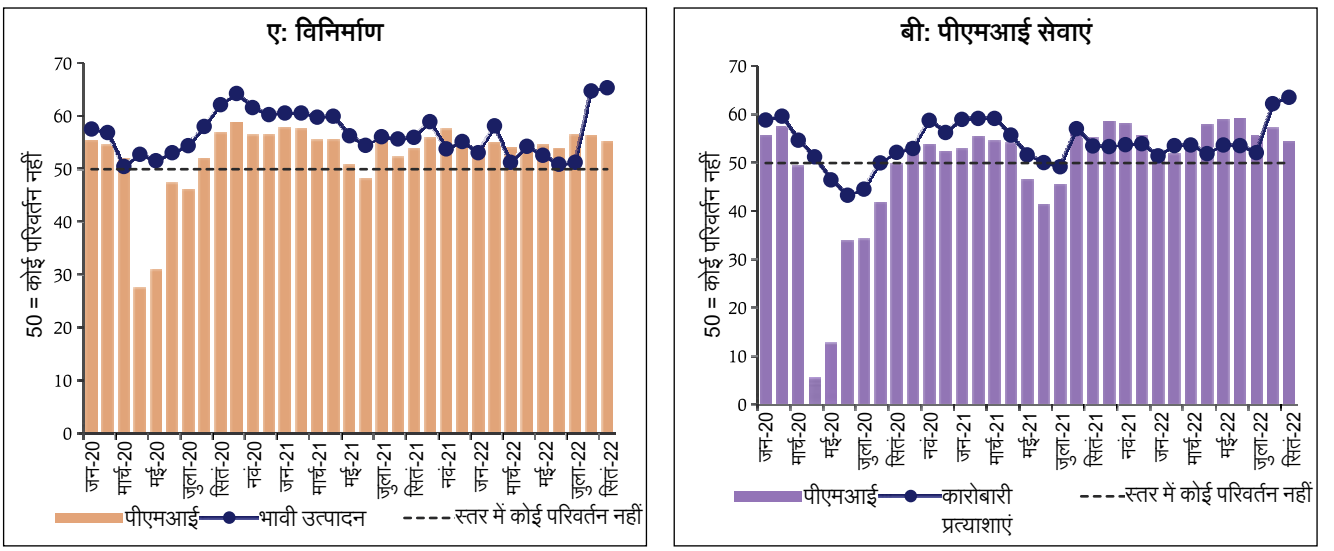


टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं। **अनुमानित आबंटन
स्रोत: एफसीआई।

प्रभाव के तहत पिछले महीने से मामूली रूप से कम रहीं (चार्ट 29 बी)।

सूचीबद्ध गैर-वित्तीय निजी कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा दर्ज किए गए उच्च कर-पश्चात लाभ[12] ने इसे उत्तोलन और लचीला प्रदर्शन

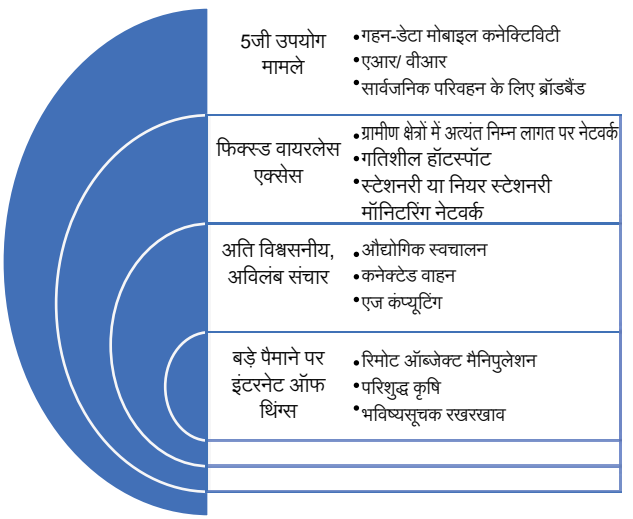
चार्ट 29: क्रय प्रबंधक सूचकांक



स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल।

[12] भारत सरकार ने सितंबर 2019 में घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया। घरेलू कंपनियों को 30 फीसदी की जगह 22 प्रतिशत आय कर देने का विकल्प दिया गया, जबकि नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों द्वारा किसी छूट का दावा नहीं किए जाने पर मौजूदा 25 प्रतिशत से नीचे 15 फीसदी कॉरपोरेट कर दे सकती हैं। हमारे अनुमान इस कराधान परिवर्तन से निवल लाभप्रदता पर 60 आधार अंकों के प्रभाव का आकलन करते हैं।

चार्ट 30: 5जी उपयोग मामले और उदाहरण एप्लिकेशन



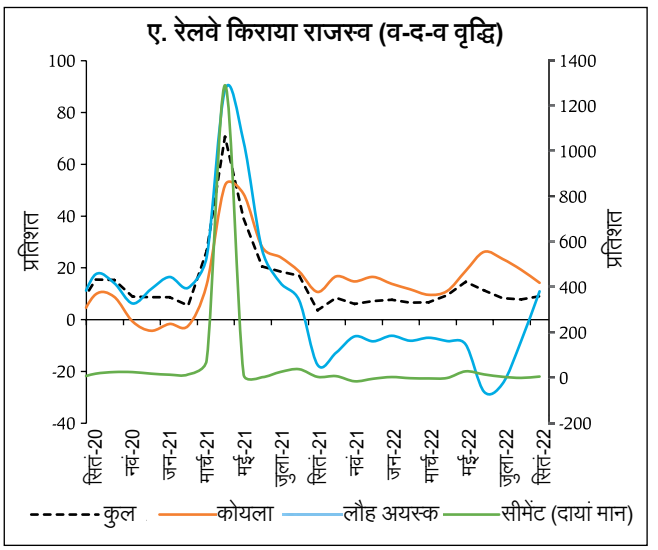
स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

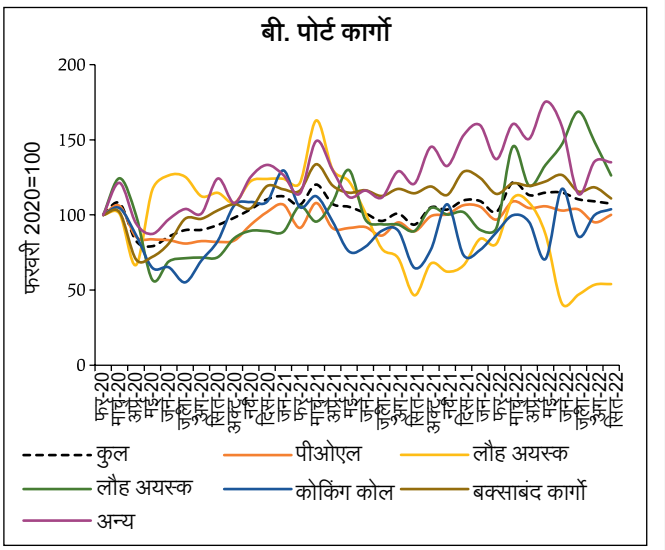
बनाए रखने में मदद की है। दूसरी तिमाही के उच्च आवृत्ति डेटा कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन का समर्थन करने वाली निरंतर मांग की स्थिति को दर्शाते हैं। अपग्रेड बनाम डाउनग्रेड की संख्या से मापा जाने वाला क्रेडिट अनुपात[13] 2022-23 की पहली छमाही में 5.5 गुना (2:2021-22 की छमाही के दौरान पांच बार) पर उच्च रहा, जो भारतीय उद्योग जगत की क्रेडिट गुणवत्ता में चल रहे व्यापक-आधारित सुधार की ओर इशारा करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिंसों की कीमतों में हालिया नरमी कंपनियों के मुनाफे के लिए अच्छी खबर है।

ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (जीएसएमए) के अनुमानों के अनुसार, 5 जी को अपनाने से, जो 2030 तक भारत में कुल कनेक्शन का एक तिहाई से अधिक होने की संभावना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 455 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2040 तक जीडीपी का 0.6 प्रतिशत) का योगदान करने की उम्मीद है। उच्च 4 जी अपनाने की दर (79 प्रतिशत) तेजी से 5 जी संक्रमण के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी, जो औद्योगिक स्वचालन, कनेक्टेड वाहनों, पूर्वानुमानित रखरखाव और सटीक कृषि के लिए महत्वपूर्ण है (चार्ट 30)।

सेवा क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र के संकेतकों का विस्तार बना हुआ है, रेलवे माल ढुलाई यातायात आय सितंबर 2022 में 9.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी है, जबकि पिछले महीने में यह 7.9 प्रतिशत थी (चार्ट 31 ए)। कोयला और लौह अयस्क प्रेषण में सालाना दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि खाद्यान्न और पिग आयरन में गिरावट आई। कंटेनरीकृत कार्गो और

चार्ट 31: रेलवे और कार्गो ट्रैफिक

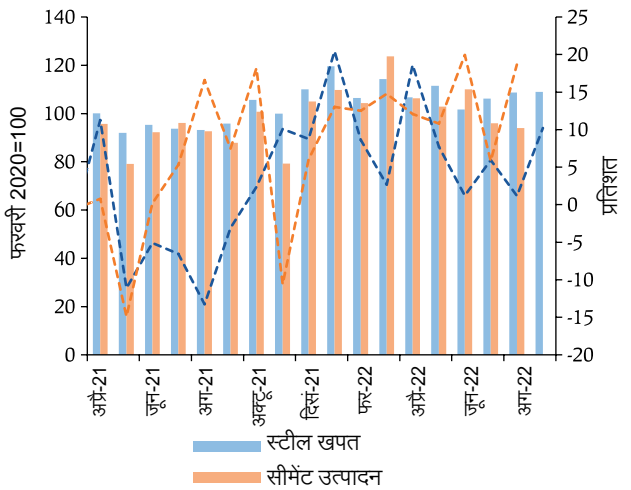




स्रोत: भारतीय पोर्ट संघ।

[13] https://www.crisil.com/en/home/newsroom/press-releases/2022/10/corporate-credit-quality-continues-to-be-strong-in-the-first-half.html

चार्ट 32: स्टील खपत और सीमेंट उत्पादन



स्रोत: संयुक्त प्लांट समिति और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

उर्वरक कच्चे माल टन भार में कमी के कारण प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात में सितंबर में मामूली कमी दर्ज की गई (चार्ट 31 बी)।

निर्माण क्षेत्र में सीमेंट उत्पादन और इस्पात की खपत में तेजी जारी रही। स्टील की खपत ने एक साल के लिए महामारी से पहले के स्तर पर निरंतर वृद्धि दर्ज की, जबकि सीमेंट उत्पादन अगस्त में कम हो गया क्योंकि विस्तारित मानसून ने निर्माण गतिविधि को धीमा कर दिया, फिर भी अगस्त 2019 की तुलना में इसमें दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 32)।

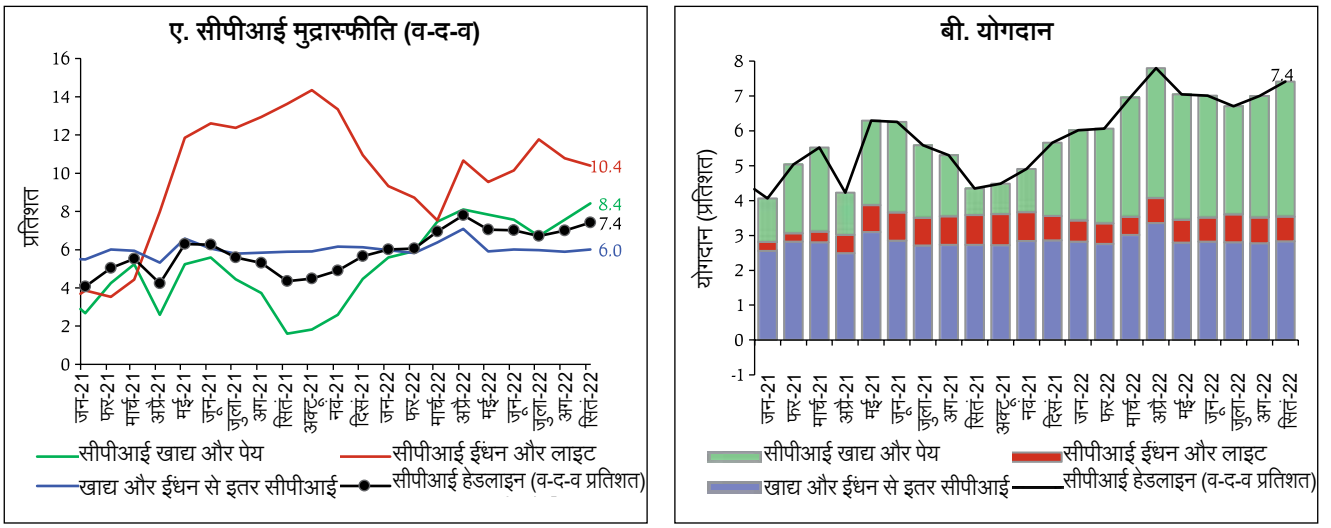
अक्टूबर (12 अक्टूबर तक) में घरेलू यात्री खंड में त्योहारी मांग में तेजी के साथ यात्री खंड में गतिविधि में एम-ओ-एम आधार पर वृद्धि हुई। कार्गो क्षेत्र में, हालांकि, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई दोनों के लिए अनुबंधित हुआ (सारणी 4)।

सारणी 4: उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएं

क्षेत्र	संकेतक	उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाओं की वृद्धि (व-द-व, प्रतिशत)				2019 की तुलना में वृद्धि			
		जून-22	जुला-22	अग-22	सितं-22	जून-22/ जून-19	जुला-22/ जुला-19	अग-22/ अग-19	सितं-22/ सितं-19
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	19.1	11.1	21.1	91.9	31.6	54.6	48.7	42.9
ग्रामीण मांग	दुपहिया वाहन बिक्री	23.4	9.6	17.0	12.9	-20.7	-8.6	2.9	4.7
	तीन पहिया वाहन बिक्री	183.9	72.8	65.3	73.4	-48.5	-43.8	-34.8	-23.7
	ट्रैक्टर बिक्री	-14.4	-15.3	-1.9		24.5	21.2	42.2	
होटल, व्यापार, यातायात, संचार	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	112.2	39.4			7.8	38.6		
	रेलवे माल ढुलाई यातायात	11.3	8.3	7.9	9.1	23.7	22.5	31	30.6
	पोर्ट कार्गो यातायात	12.2	15.1	8.6	15.0	14.6	6.9	8.6	13
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	40.4	18.8	4.8		4.4	-1.6	-9	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	0.5	-1.5	-5.0		-5.1	-9.4	-10.2	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	247.9	97.9	54.9		-10.5	-17.1	-12.9	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	753.6	487.7	256.9		-21.5	-18.1	-19.8	
	जीएसटी ई-वे बिल्स (कुल)	36.2	17.8	18.7	23.7	49.7	44.9	52.7	60.3
	जीएसटी ई-वे बिल्स (आंतर राज्य)	38.6	19.8	22.5	28.9	58.7	51.5	62.6	71.5
	जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतर राज्य)	32.2	14.7	12.9	16.2	36.4	35.2	38.7	45.3
	यात्री आगमन	1349.2	783.9	-37.8		-28	-21.7	-37.8	
विनिर्माण	इस्पात खपत	6.4	13.0	13.0	10.1	1.2	5.9	1.2	10.2
	सीमेंट उत्पादन	19.7	0.5	1.8		19.9	5.8	18.6	
पीएमआई सूचकांक	विनिर्माण	53.9	56.4	56.2	55.1				
	सेवाएं	59.2	55.5	57.2	54.3				

स्रोत: सीएमआईई; सीईआईसी आंकड़े; आईएचएस मार्किट; एसआईएएम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; और संयुक्त प्लांट समिति।

चार्ट 33: सीपीआई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और वाहक



टिप्पणी: अप्रैल-मई 2021 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना अप्रैल-मई 2020 के लिए इम्प्यूटेड सीपीआई सूचकांकों के आधार पर की गई थी।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

मुद्रास्फीति

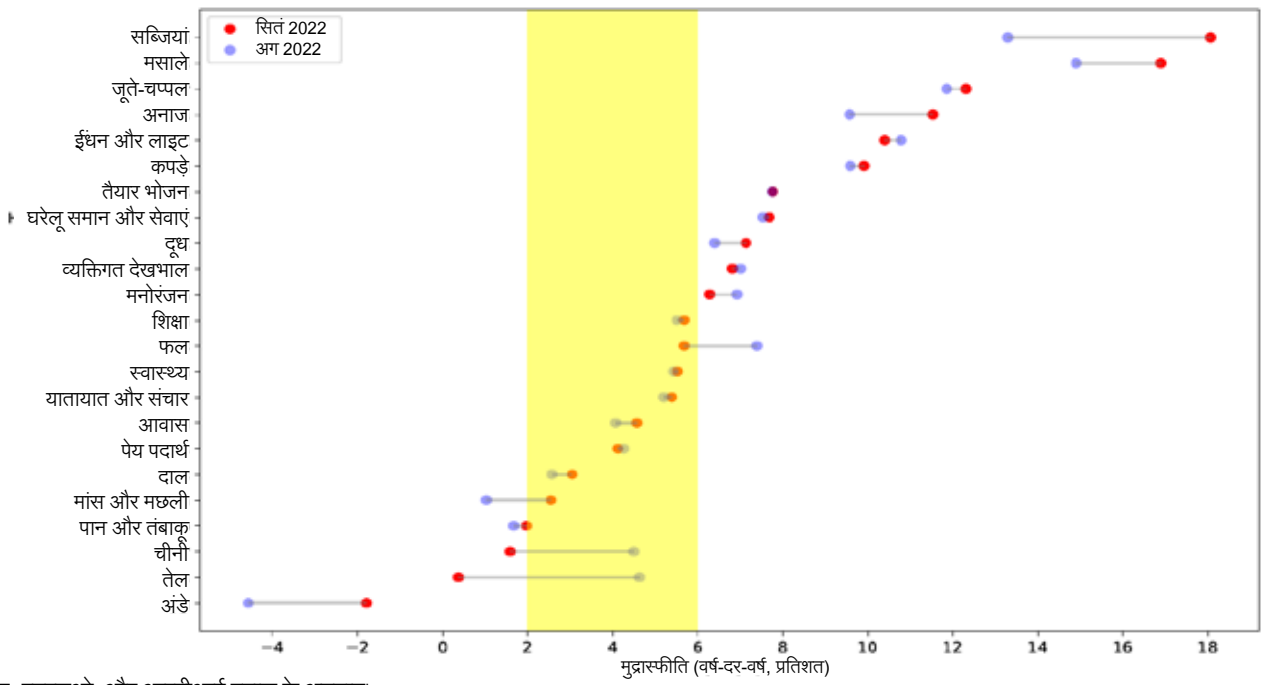
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को जारी आंकड़ों से पता चला है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में साल-दर-साल बदलाव से मापी गई मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 7.0 प्रतिशत थी (चार्ट 33 ए)। सितंबर में 40 आधार अंकों (बीपीएस) की यह वृद्धि लगभग 60 बीपीएस की सकारात्मक गति (सीपीआई में महीने-दर-महीने वृद्धि) के कारण हुई, जो आंशिक रूप से लगभग 20 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभाव (एक साल पहले कीमतों में महीने-दर-महीने बदलाव) से भरपाई हुई थी। सीपीआई के सभी तीन प्रमुख घटकों ने खाद्य और पेय पदार्थ समूह में 85 बीपीएस, ईंधन समूह में 39 बीपीएस और 'कोर' (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) श्रेणी में 33 बीपीएस की वृद्धि के साथ मूल्य दबाव को प्रतिबिंबित किया (चार्ट 33 बी)।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि से मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खाद्य मुद्रास्फीति एक महीने पहले के 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 8.4 प्रतिशत पर पहुंच गई (चार्ट 34)। सब्जियों, मसालों और अनाजों के मामले में कीमतों का दबाव सबसे अधिक देखा गया। मांस और मछली, दूध और दालों के मामले में भी उन्होंने बढ़त हासिल की। दूसरी ओर खाद्य तेलों, फलों, चीनी और गैर मादक पेय पदार्थों के मामले में कीमतों का दबाव नरम रहा। सकारात्मक गति के बावजूद, अंडे के संबंध में वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में बनी रही (चार्ट 35)।

ईंधन और प्रकाश श्रेणी में मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर 10.4 प्रतिशत रह गई, जो अगस्त में 10.8 प्रतिशत थी। एलपीजी और केरोसिन (पीडीएस) मुद्रास्फीति में तेज गिरावट को आंशिक रूप से अन्य ईंधन (उपले और जलाऊ लकड़ी और चिप्स) में मूल्य दबाव में वृद्धि से भरपाई की गई थी। मासिक वृद्धि में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद बिजली की कीमतों में सालाना आधार पर अपस्फीति बनी रही। सीपीआई में 6.8 फीसदी के भारांश के साथ, ईंधन समूह ने सितंबर में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 9.6 प्रतिशत का योगदान दिया।

सितंबर में कोर मुद्रास्फीति बढ़कर 6.0 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 5.9 प्रतिशत थी। मनोरंजन और मनोरंजन और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव जैसे उप-समूहों में मुद्रास्फीति में कमी देखी गई, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ, कपड़े और जूते, आवास, घरेलू सामान और सेवाएं, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार और शिक्षा में वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट 34: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (सितंबर *बनाम* अगस्त 2022)

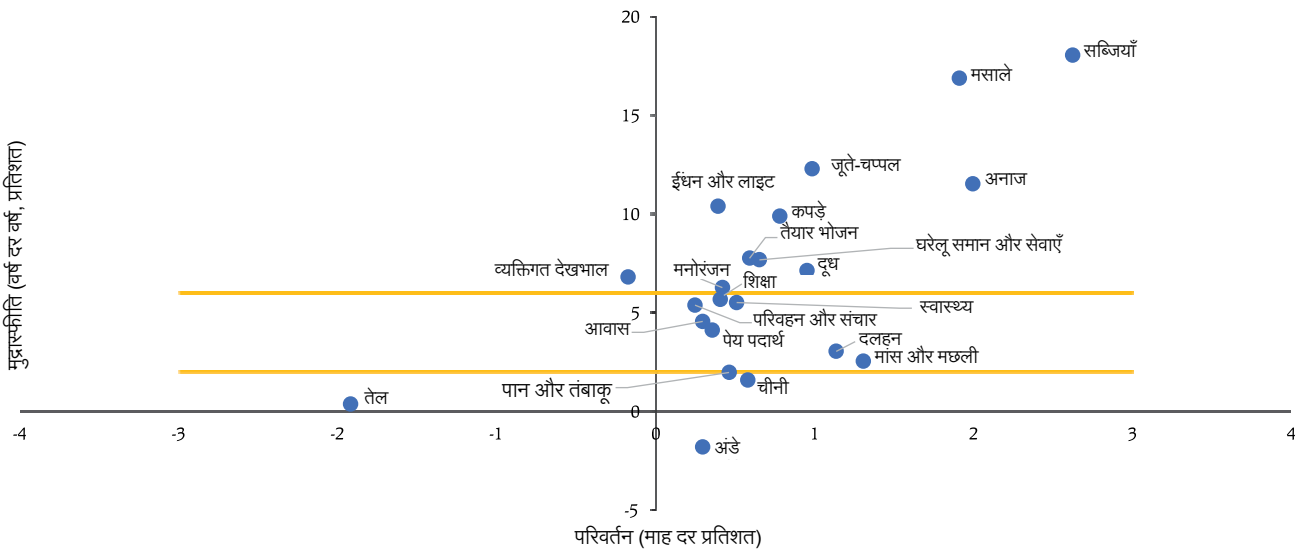


स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण मुद्रास्फीति 7.6 प्रतिशत थी, जो सितंबर 2022 में शहरी मुद्रास्फीति (7.3 प्रतिशत) से अधिक थी। राज्यों में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप ने 8 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति का अनुभव किया, जबकि गोवा, मणिपुर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे दर्ज की (चार्ट 36)।

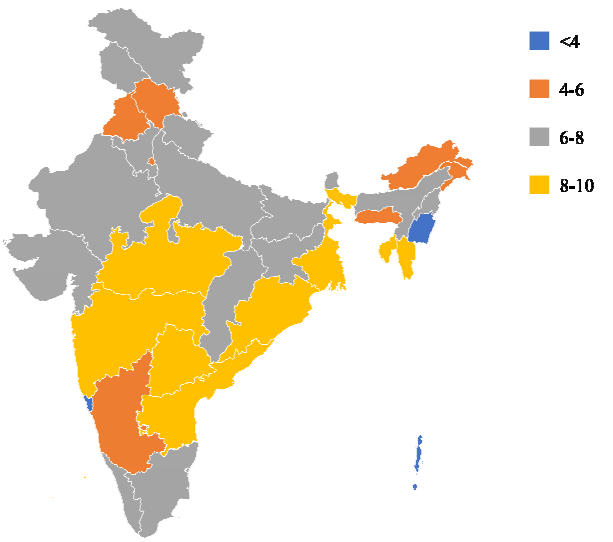
उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीसीए) के अक्टूबर तक (1-12 अक्टूबर) के उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य के आंकड़े मुख्य

चार्ट 35: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (व-द-व) और संवेग (माह-द-माह)



स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 36: राज्यों में सीपीआई-संयुक्त मुद्रास्फीति

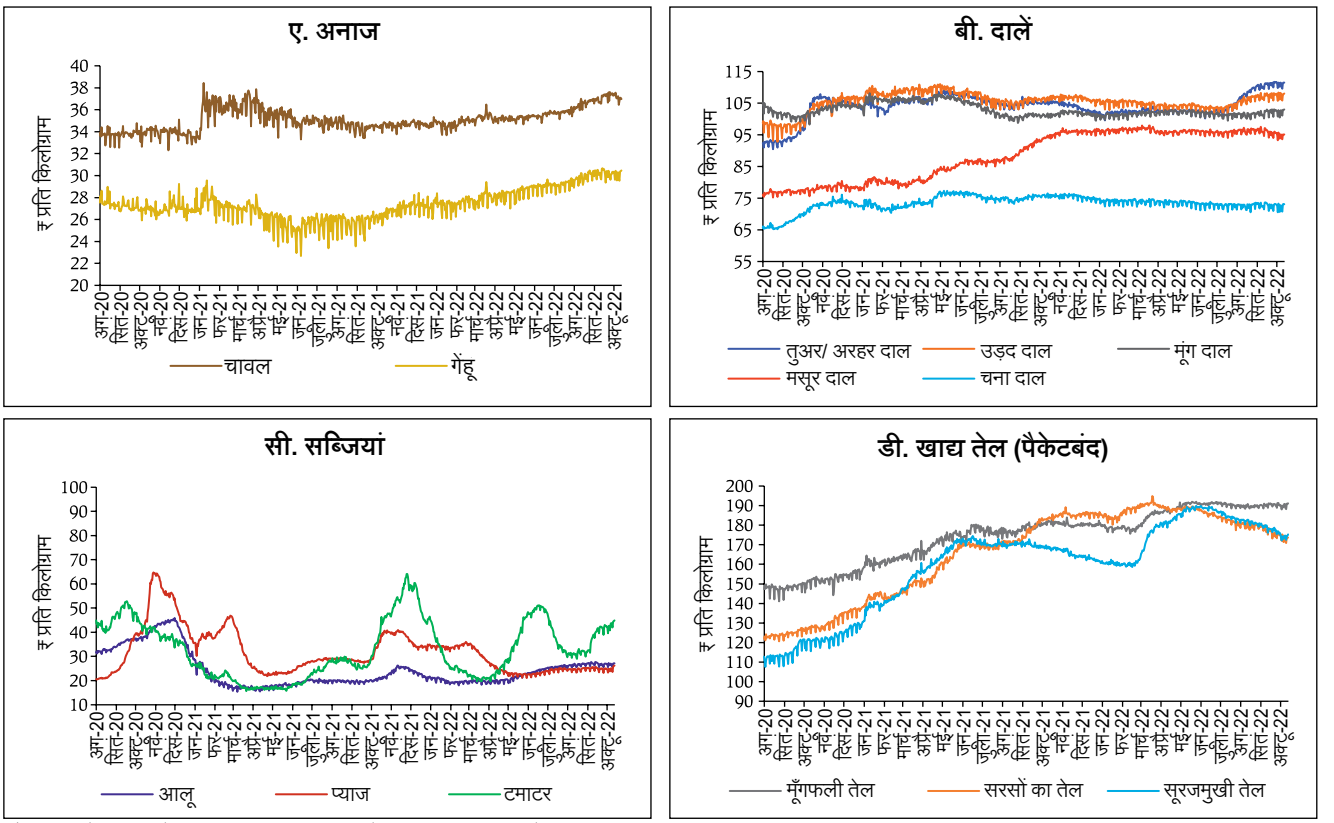


स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

रूप से गेहूं की कीमतों में गिरावट के कारण अनाज की कीमतों में नरमी की ओर इशारा करते हैं। तुअर के अलावा दालों की कीमतों में व्यापक गिरावट दर्ज की गई। खाद्य तेलों के भीतर सरसों तेल और सूरजमुखी तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही। प्रमुख सब्जियों में, प्याज और आलू की कीमतें सीमित स्तर पर बनी रहीं, जबकि प्रमुख टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में अगस्त-सितंबर में भारी बारिश के कारण टमाटर की कीमतों में तेजी जारी रही, जिसके परिणामस्वरूप मंडी की आवक कम हुई (चार्ट 37)।

चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतों में अक्टूबर में कोई बदलाव नहीं हुआ। केरोसिन की कीमतों में अगस्त की तुलना में सितंबर में नरमी आई, लेकिन अक्टूबर में यह स्थिर रही। एलपीजी की कीमतों को सितंबर और अक्टूबर में अब तक अपरिवर्तित रखा गया था (सारणी 5)।

चार्ट 37: डीसीए आवश्यक पण्य कीमतें



स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सारणी 5: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		अक्टू-21	सितं-22	अक्टू-22 ^	सितं-22	अक्टू-22
पेट्रोल	₹/लीटर	106.37	102.92	102.92	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	97.92	92.72	92.72	0.0	0.0
मिट्टी का तेल (सब्सिडी)	₹/लीटर	34.56	57.55	57.55	-8.3	0.0
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	907.71	1063.25	1063.25	0.0	0.0

^: 1-12 अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए।

टिप्पणी: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में औसत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिट्टी के तेल के लिए कीमतें, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

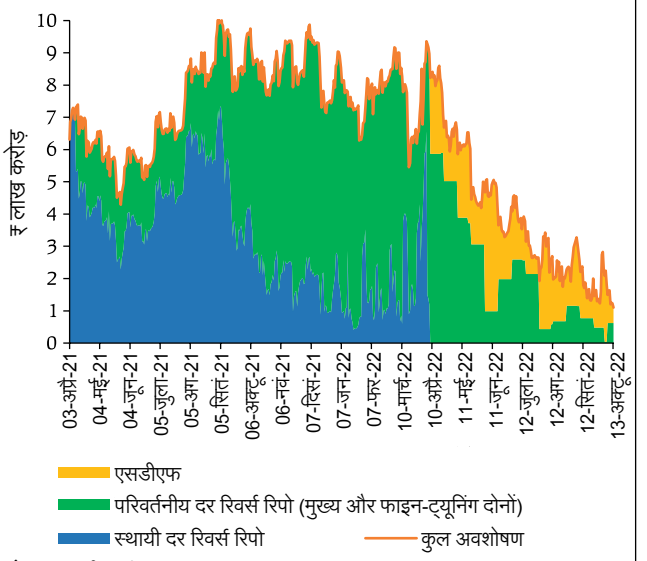
स्रोत: इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल); पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); तथा आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सितंबर 2022 में विनिर्माण और सेवाओं में इनपुट लागत का दबाव बढ़ गया, हालांकि धीमी गति से, जैसा कि पीएमआई में परिलक्षित होता है। विनिर्माण और सेवाओं में भी बिक्री कीमतें बढ़ीं, सेवा क्षेत्र ने दीर्घकालिक औसत से अधिक मूल्य वृद्धि दर्ज की।

IV. वित्तीय स्थितियां

विदेशी मुद्रा बहिर्वाह के साथ-साथ अग्रिम कर प्राप्तियों के बहिर्वाह ने सितंबर में अधिशेष चलनिधि की स्थिति को नियंत्रित किया। अक्टूबर की शुरुआत में सरकारी व्यय में आई तेजी से चलनिधि थोड़ी-बहुत बढ़ी। तदनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक अवशोषण 15 अगस्त से 14 सितंबर 2022 के दौरान ₹2.6 लाख करोड़ से 13 अक्टूबर 2022 तक सितंबर के दूसरे अर्धांश के दौरान ₹1.6 लाख करोड़ हो गया (चार्ट 38)। एकदिवसीय स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के माध्यम से ₹1.1 लाख करोड़ अवशोषित किए गए थे, जबकि शेष को परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो (वीआरआरआर) नीलामियों (मुख्य और फाइन-ट्यूनिंग दोनों) के माध्यम से संग्रहित किया गया था। कठोर चलनिधि स्थितियों के कारण भी बैंकों को सितंबर-मध्य से 13 अक्टूबर के दौरान रुक-रुक कर औसतन ₹15,482 करोड़ की सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का सहारा लेना पड़ा, जबकि अगस्त-मध्य से 14 सितंबर 2022 के दौरान यह राशि ₹2,654 थी। रिज़र्व बैंक ने चलनिधि तनाव को कम करने के

चार्ट 38: चलनिधि की स्थिति

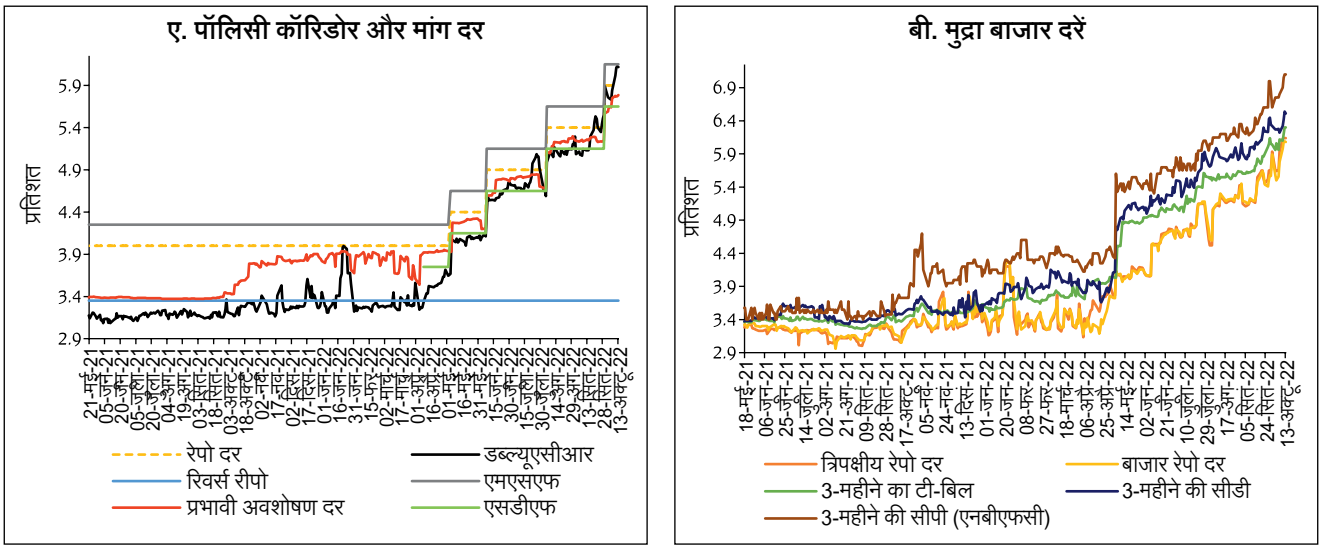


स्रोत: आरबीआई।

लिए 22 सितंबर 2022 को ₹50,000 करोड़ के लिए एकदिवसीय परिवर्तनीय रिपो दर (वीआरआर) नीलामी (प्राप्त बोलियां - ₹94,267 करोड़) 5.58 प्रतिशत की निर्दिष्ट दर पर आयोजित की। 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामियों में भी निराशा हाथ लगी, जो ₹2.0 लाख करोड़ की अधिसूचित राशि के मुकाबले मात्र ₹3,748 करोड़ की प्राप्त बोलियों से स्पष्ट है। अधिशेष चलनिधि में कमी को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर को मौद्रिक नीति वक्तव्य में पाक्षिक 14-दिवसीय मुख्य नीलामी के साथ 28-दिवसीय वीआरआरआर के विलय की घोषणा की। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने पुनः ज़ोर दिया कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार, अवशोषण के साथ-साथ चलनिधि के अंतर्वेशन के लिए विभिन्न परिपक्वताओं के फाइन-ट्यूनिंग परिचालन जारी रहेंगे। इसके अलावा, बैंकों के अतिरिक्त आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और अतिरिक्त सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का आहरण भी बैंकों को निधि प्रवाह असंतुलन से निपटने में मदद कर रहा है।

भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) ने सितंबर के दूसरे अर्धांश से 13 अक्टूबर 2022 के दौरान नीति रिपो दर (औसत) से 2 आधार अंक ऊपर ट्रेड किया, जो चलनिधि की नियंत्रित स्थिति को दर्शाता है (चार्ट 39ए)। इसी तरह संपार्श्विक खंड में दरों में वृद्धि हुई, त्रिपक्षीय और बाजार रिपो दरों में नीति रिपो दर से

चार्ट 39: पॉलिसी कॉरिडोर और और मुद्रा बाजार दरें



स्रोत: आरबीआई; ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

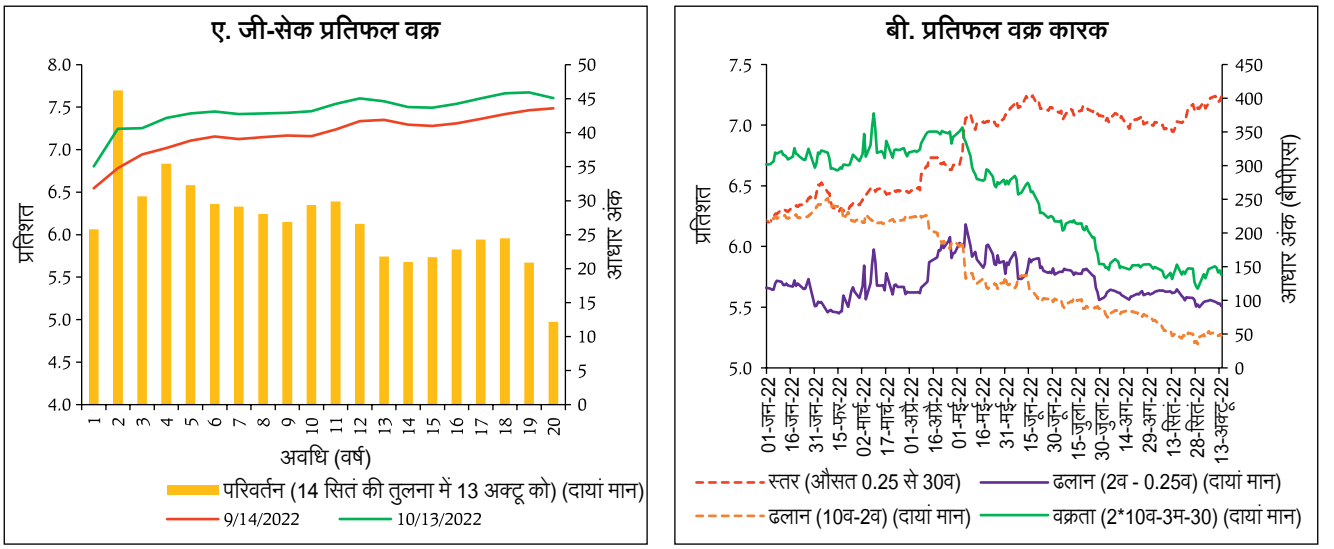
ऊपर ट्रेडिंग हुई (चार्ट 39बी)। मीयादी मुद्रा खंड में, 3-महीने के खजाना बिल (टी-बिल), 3-महीने के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और 3-महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर एमएसएफ दर से क्रमशः 13, 41 और 86 आधार अंकों की दर से कारोबार हुआ। प्राथमिक बाजार में, जमा प्रमाण-पत्र (सीडी) जारी करने के माध्यम से वर्ष 2022-23 की पहली छमाही (26 सितंबर तक) में निधि संग्रहण ₹2.96 लाख करोड़ पर मजबूत रहा है, जो कि 2021-22 की दूसरी छमाही में ₹1.73 लाख करोड़ से अधिक है, वृद्धिशील क्रेडिट उठाव को पूरा करने के लिए बैंकों की अतिरिक्त निधि की मांग को दर्शाता है। दूसरी ओर, 2022-23 की पहली छमाही (26 सितंबर तक) के दौरान बैंक क्रेडिट की मांग में सुधार होने से वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करने की संख्या घटकर ₹7.20 लाख करोड़ रह गई, जो 2021-22 की दूसरी छमाही में ₹10.09 लाख करोड़ थी।

नियत आय बाजार में पूरे प्रतिफल वक्र में बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई, नए 10-वर्षीय बेंचमार्क जी-सेक (7.26 जीएस 2032) पर प्रतिफल 13 अक्टूबर 2022 को 7.42 प्रतिशत पर बंद हुआ – जो कि 14 सितंबर के 7.13 प्रतिशत से अधिक है (चार्ट 40ए)। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा 75 आधार अंकों की दर वृद्धि और इसके तेजतर्रार मार्गदर्शन के बाद घरेलू प्रतिफल ने अमेरिकी राजकोष प्रतिफल में तीव्र वृद्धि का अनुसरण किया। रिज़र्व बैंक द्वारा नीति रिपो दर में वृद्धि से भी बॉन्ड प्रतिफल में मजबूती आई है। इसके बाद, जेपी मॉर्गन द्वारा अपने व्यापक रूप से ट्रैक किए गए इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड को शामिल करने से रोके जाने के बाद भी बाजार का रुख प्रभावित हुआ। कठोर मौद्रिक नीति के प्रति उच्च संवेदनशीलता प्रदर्शित करने वाले वक्र के शॉर्ट-एंड के साथ, प्रतिफल वक्र की ढलान में और गिरावट आई (चार्ट 40बी)। जबकि प्रतिफल वक्र के स्तर में ऊर्ध्वगामी बदलाव, अप्रैल से घटते ढलान के अनुरूप है (जैसा कि 10-वर्षीय से 2-वर्षीय स्प्रेड को घटाकर मापा जाता है), मई नीतिगत बैठक के बाद से वक्रता[14] में एक प्रत्यक्ष गिरावट स्पष्ट है, जो आगे चलकर नीति नियंत्रण की मंद प्रत्याशा दर्शाता है। कुल मिलाकर, प्रतिफल वक्र दीर्घावधि विकास की संभावनाओं में सुधार का सुझाव देता है।[15]

[14] प्रतिफल वक्र की वक्रता लघु, मध्यम और दीर्घावधि परिपक्वताओं पर प्रतिफल के बीच संबंध दर्शाती है। उच्च वक्रता का अर्थ है- वक्र की उच्च अवतलता, *अर्थात* प्रतिफल वक्र मध्यम से दीर्घावधि प्रतिफल की तुलना में लघु से मध्यम अवधि में ढालू है, और इसलिए प्रतिफल वक्र में एक उभार दिखाता है। वक्रता की गणना 10-वर्षीय प्रतिफल के 2 गुना से 30-वर्षीय और 3-महीने के प्रतिफल के योग को घटाकर की जाती है।

[15] पात्र, एम.डी., जॉइस, जे., कुशवाहा, केएम, और आई. भट्टाचार्य (2022)। 'अर्थव्यवस्था के बारे में प्रतिफल वक्र हमें क्या बता रहा है?' *आरबीआई बुलेटिन, जून।*

चार्ट 40: सरकारी प्रतिभूति बाजार में विकास



स्रोत: ब्लूमबर्ग; सीसीआईएल; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल में आम तौर पर सभी अवधियों में जी-सेक प्रतिफल और रेटिंग स्पेक्ट्रम के साथ वृद्धि हुई (सारणी 6)। प्राथमिक बाजार में, अगस्त 2022 में जारी कॉरपोरेट बॉन्ड की संख्या घटकर ₹45,159 करोड़ रह गई, जो पिछले महीने में ₹69,166 करोड़ थी और यह अगस्त 2021 में जारी ₹49,848 करोड़ से भी कम थी।

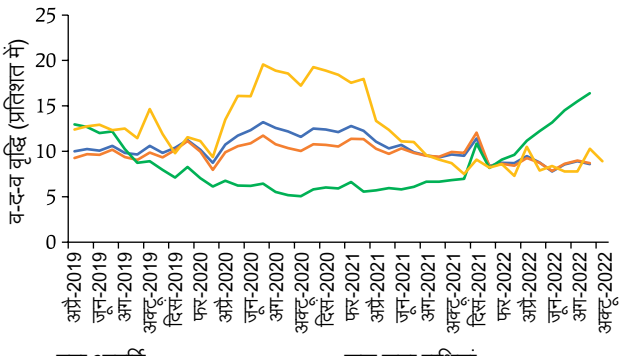
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर को छोड़ कर, आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 7 अक्टूबर 2022 की स्थिति में 8.9 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि हुई (एक वर्ष पूर्व 8.7 प्रतिशत) [चार्ट 41]। आरएम के सबसे बड़े घटक, संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में 8.3 प्रतिशत (एक साल पहले 8.9 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। 23 सितंबर 2022 को मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष

सारणी 6: वित्तीय बाजार - दर और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम मुक्त दर के आधार पर)		
	अग 17 - सितं 14 2022	सितं 15 -अक्टू 13, 2022	परिवर्तन (बीपीएस में)	अग 17 - सितं 14 2022	सितं 15 - अक्टू 13, 2022	परिवर्तन (बीपीएस में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉन्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	6.89	7.01	12	43	14	-29
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.35	7.75	40	43	47	4
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.46	7.70	24	31	23	-8
(iv) एए (3-वर्ष)	8.09	8.50	41	116	122	6
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	11.76	12.15	39	483	487	4

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफआईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

चार्ट 41: मौद्रिक और ऋण कुल राशियां



टिप्पणियां: 1. ये आंकड़े मुद्रा आपूर्ति, समग्र जमाराशियों और बैंकों के क्रेडिट के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं; और आरक्षित मुद्रा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
2. तथापि, आरक्षित मुद्रा के लिए अद्यतन आंकड़े 07 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार हैं, जबकि मुद्रा आपूर्ति के लिए 23 सितंबर 2022 की स्थिति के अनुसार हैं।
स्रोत: आरबीआई।

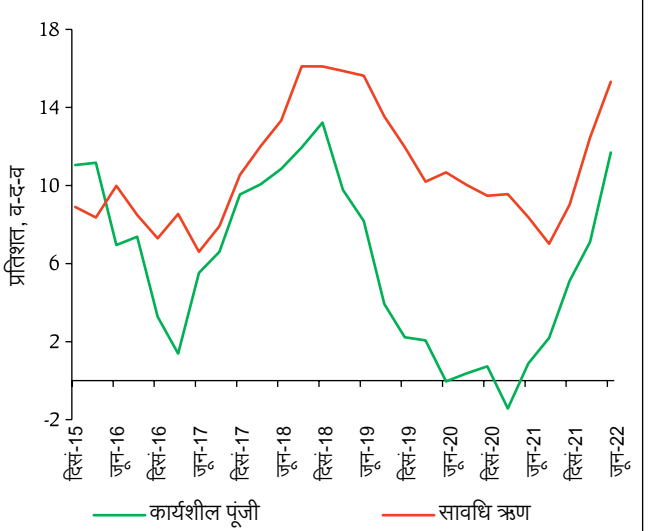
पहले 9.3 प्रतिशत), जिसका मुख्य कारण इसका सबसे बड़ा घटक - बैंकों के पास समग्र जमाराशियां थी - जो कि 8.7 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 9.4 प्रतिशत) तक बढ़ी। 23 सितंबर 2022 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का क्रेडिट 16.4 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 6.7 प्रतिशत) तक बढ़ गया, जो 18 अक्टूबर 2013 (16.3 प्रतिशत) के बाद से सर्वाधिक है।

मीयादी ऋण श्रेणी के कारण बैंक क्रेडिट वृद्धि में तेजी आई। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ, कार्यशील पूंजी[16] के लिए बैंक क्रेडिट में वृद्धि भी हाल के महीनों में बढ़ी है, जो मांग की स्थिति के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है (चार्ट 42)।

मई से सितंबर 2022 के दौरान, रिपो दर में वृद्धि के जवाब में बैंकों ने अपनी बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) में 140 आधार अंकों की वृद्धि की है। एससीबी ने इसी अवधि के दौरान निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की अपनी 1-वर्ष की मीडियन सीमांत लागत में 70 आधार अंकों की वृद्धि की है। ऋण कीमत निर्धारण के लिए बेंचमार्क दरों में ऊर्ध्वगामी संशोधन और ईबीएलआर से जुड़े ऋणों की हिस्सेदारी में वृद्धि ने उधार दरों में संचरण की गति में सुधार किया है।[17] इसके बाद, मई-अगस्त 2022 के दौरान नए और बकाया रुपए ऋणों पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएएलआर) में क्रमशः 82 आधार अंकों और 41 आधार अंकों की वृद्धि हुई (चार्ट 43)। 30 सितंबर की एमपीसी बैठक में नीति दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि के जवाब में, बैंकों ने अपनी रिपो-संबद्ध बेंचमार्क दरों में ऊर्ध्वगामी समायोजन करना शुरू कर दिया है।

बैंक खुदरा जमा दरों की तुलना में अपनी उधार दरों को तेजी से समायोजित कर रहे हैं। मई-सितंबर 2022 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मीडियन मीयादी जमा दर, जो नई जमाराशियों पर प्रचलित कार्ड दरों को दर्शाती है, में 26 आधार

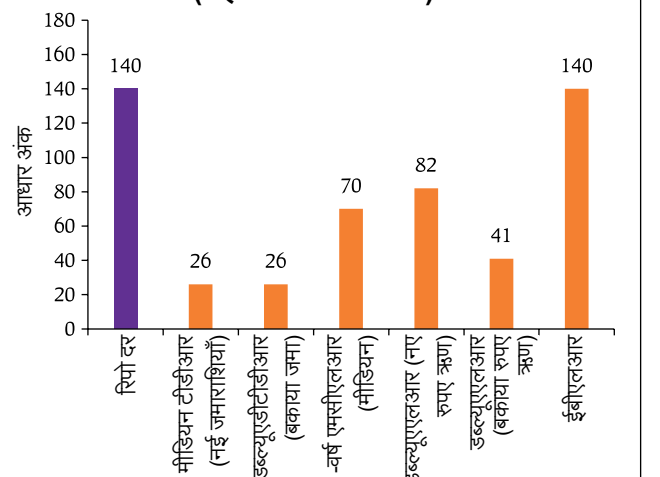
चार्ट 42: बैंक क्रेडिट वृद्धि: खाता प्रकार-वार



स्रोत: आरबीआई।

अंकों की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान घरेलू बैंकों की नई जमाराशियों पर मीडियन मीयादी जमा दर पर संचरण 27 आधार अंक हो गया। मीयादी खुदरा जमा दरों में प्रभाव-अंतरण की सीमा,

चार्ट 43: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरों में अंतरण (मई से सितंबर 2022)



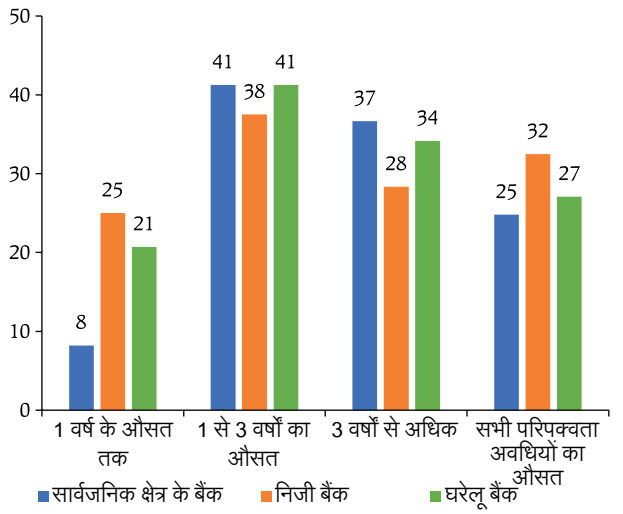
टिप्पणियाँ: 1. डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर अद्यतन डेटा अगस्त 2022 से संबंधित है और इसलिए सितंबर में रिपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर के लिए प्रभाव-अंतरण में नहीं दिखाई दी है।
2. ईबीएलआर पर डेटा 31 घरेलू बैंकों से संबंधित है।
3. परिवर्णी शब्द: डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर; एमसीएलआर: निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत; टीडीआर: सावधि जमा दर; ईबीएलआर: बेंचमार्क आधारित बाह्य उधार दर।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

[16] कार्यशील पूंजी को नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग ऋण के योग के रूप में प्राप्त किया गया है।

[17] जून 2022 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बकाया अस्थिर दर रुपया ऋणों में ईबीएलआर से जुड़े ऋणों की हिस्सेदारी 46.9 प्रतिशत थी जबकि एमसीएलआर से जुड़े ऋणों की हिस्सेदारी 46.5 प्रतिशत थी। एससीबी के कुल बकाया अस्थिर दर रुपया ऋण का 6.6 प्रतिशत हिस्सा आधार दर, बेंचमार्क मूल उधार दर और अन्य आंतरिक बेंचमार्क (मौद्रिक नीति रिपोर्ट, सितंबर 2022, https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21343) से संबद्ध है।

चार्ट 44: नई सावधि खुदरा जमा दरों में परिपक्वता-वार संचरण (मई-सितंबर 2022)



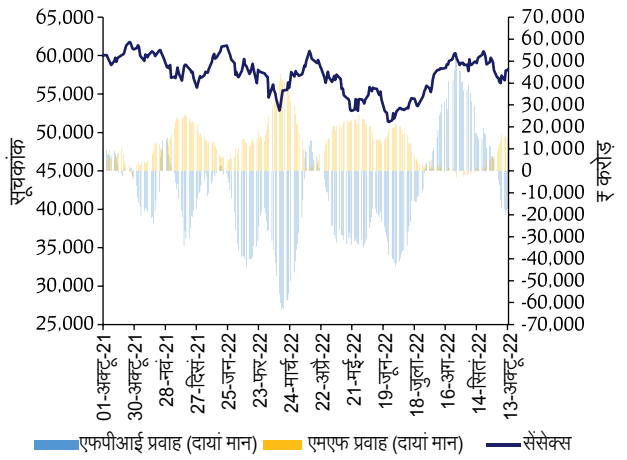
स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

हालांकि, लंबी अवधि की परिपक्वता अवधि के लिए अधिक रही है (चार्ट 44)। भारत सरकार ने भी 29 सितंबर 2022 को अल्प बचत लिखतों (एसएसआई) पर दरों की समीक्षा की है और उनमें 10-30 आधार अंकों तक ऊर्ध्वगामी संशोधन किया है। हालांकि मौजूदा ब्याज दरें, 2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए फॉर्मूला आधारित दरों से 44-77 आधार अंकों कम हैं।[18]

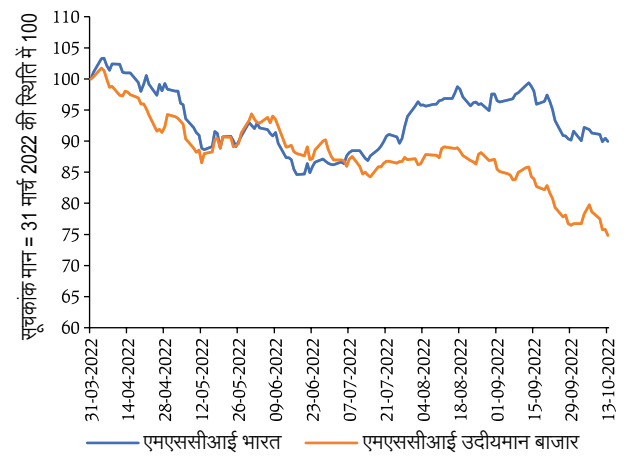
सितंबर 2022 के दूसरे अर्धांश में बीएसई सेंसेक्स में 4.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ घरेलू इक्विटी बाजार बिकवाली से गुजरा, क्योंकि प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में वृद्धि और वैश्विक वृद्धि पर चिंताओं ने बाजार के रुख को प्रभावित किया (चार्ट 45ए)। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) पिछले दो महीनों में निवल खरीदार बने रहने के बाद सितंबर 2022 में ₹13,406 करोड़ के निवल विक्रेता बन गए। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) से प्रवाह मजबूत रहा, जिससे इक्विटी खंड ₹14,120 करोड़ के कुल योग के साथ मजबूत बना रहा। हालिया सुधार के बावजूद, भारतीय इक्विटी बाजार समकक्ष ईएमई के मध्य एक बेहतर प्रदर्शनकर्ता बना हुआ है (चार्ट 45बी)।[19] अक्टूबर में इक्विटी बाजार अब तक अस्थिर रहे हैं। पहले सप्ताह में एफपीआई के निवल खरीदार बनने से बाजार में शुरुआत में तेजी आई; हालांकि, बाद में कमजोर वैश्विक संकेतों को देखते हुए बढ़त में कमी आई। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स अक्टूबर 2022 में अब तक 0.3 प्रतिशत गिरकर 13 अक्टूबर 2022 को 57,235 पर बंद हुआ है।

चार्ट 45: इक्विटी बाजार प्रदर्शन

ए. बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह



बी. एमएससीआई भारत बनाम एमएससीआई ईएम

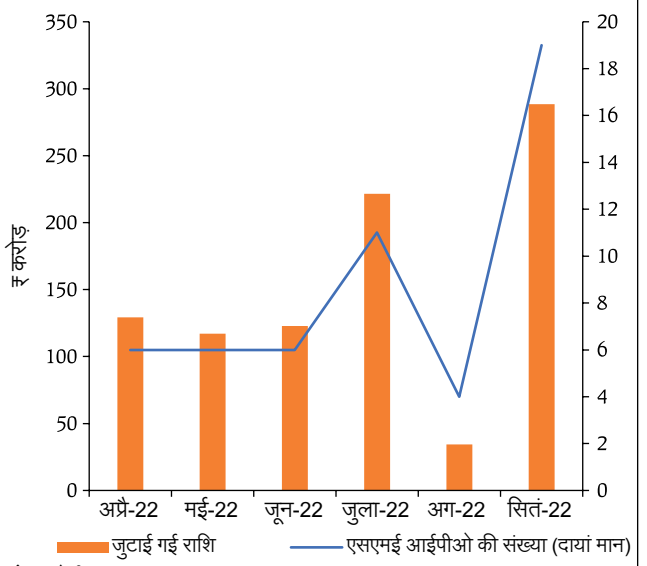


टिप्पणी: एफपीआई और एमएफ निवेश को 15 दिन के रोलिंग सम के आधार पर दर्शाया जाता है।
स्रोत: सेबी; ब्लूमबर्ग; एनएसडीएल।

[18] मौद्रिक नीति रिपोर्ट, सितंबर 2022, https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21343

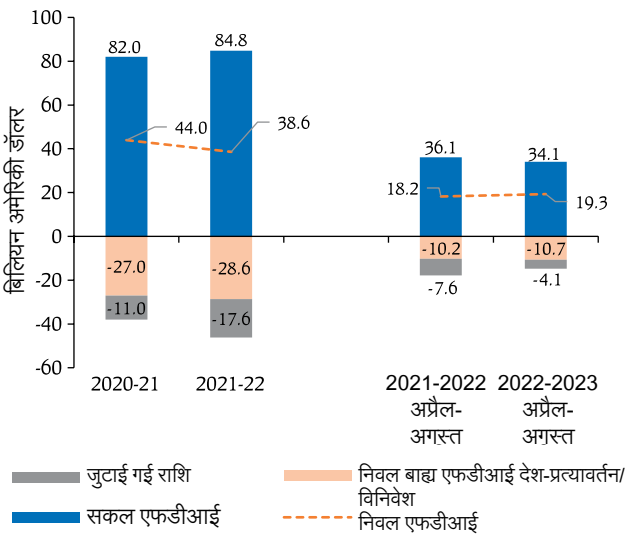
[19] चाइना $5 ट्रिलियन राउट क्रिएट्स हिस्टोरिक गैप विथ इंडियन स्टॉक्स - ब्लूमबर्ग

चार्ट 46: वर्ष 2022-23 में एसएमई आईपीओ



स्रोत: सेबी।

चार्ट 47: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश



स्रोत: आरबीआई।

वर्ष 2022-23 (सितंबर 2022 तक) में इक्विटी बाजारों के माध्यम से निधि जुटाने की योजना फीकी रही क्योंकि अभी तक केवल 17 कंपनियों ने मेनबोर्ड प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से ₹35,847 करोड़ जुटाए, जिसमें ₹20,000 करोड़ से भी अधिक राशि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जुटाई गई है। हालांकि मेनबोर्ड खंड में गतिविधि के विपरीत, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) खंड ने सितंबर 2022 में 19 कं पनियों (मई 2018 के बाद से उच्चतम संख्या) के साथ आईपीओ[20] के माध्यम से निधि जुटाने के साथ पर्याप्त गतिविधि प्रदर्शित की (चार्ट 46)। निवेशक आधार को व्यापक बनाने की दिशा में प्रगति, निवेशकों के लिए सूचना विषमता को कम करना तथा लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) प्लेटफॉर्म में पर्याप्त पश्च बाजार चलनिधि- उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा देने के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य कर सकती है। [21]

अप्रैल-अगस्त 2022 के दौरान सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 34.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो एक वर्ष पहले के स्तर से कम था (चार्ट 47)। हालांकि भारत से बाह्य एफडीआई में गिरावट के कारण, निवल एफडीआई एक वर्ष पहले के 18.2 अरब अमेरिकी डॉलर से इस अवधि के दौरान बढ़कर 19.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। विनिर्माण, संचार सेवाओं, कंप्यूटर सेवाओं, खुदरा और थोक व्यापार क्षेत्रों और वित्तीय सेवाओं को अप्रैल-अगस्त 2022 के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का प्रमुख हिस्सा प्राप्त हुआ।

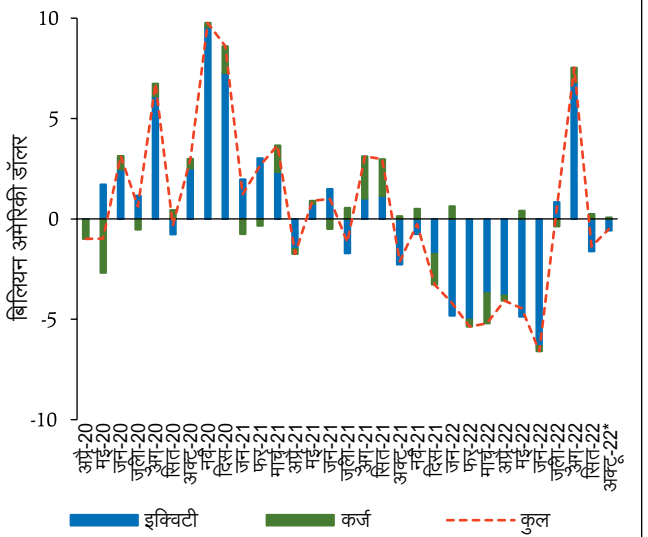
सितंबर के दूसरे पखवाड़े में एफपीआई द्वारा विनिवेश के कारण महीने के दौरान 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह हुआ (चार्ट 48)। वैश्विक बाजारों में अस्थिर रुख, वैश्विक मंदी की आशंका और यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा आक्रामक दरों में बढ़ोतरी ने जोखिम-विमुख रूखों को सक्रिय किया, प्रमुख ईएमई ने सितंबर में निवल बहिर्वाह दर्ज किया। अक्टूबर 2022 में (12 अक्टू तक) एफपीआई द्वारा निवल बिक्री 0.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

अप्रैल-अगस्त 2022 के दौरान भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का सकल संवितरण एक साल पहले के 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में कम होकर 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि निवल आधार पर (यानी चुकौती और अंतर-कंपनी उधारी को छोड़कर), ईसीबी ने पिछले वर्ष में 3.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल संवितरण की तुलना में 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया। अगस्त 2022 के दौरान पंजीकृत ईसीबी की भारित औसत

[20] सूचीबद्ध करने की तारीख के आधार पर।

[21] गांगुली, श्रोमोना (2022), "एसएमई एक्सचेंज इन इंडिया: एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ फर्म एट्रिब्यूट्स एंड आईपीओ कैरक्टरिस्टिक्स" आरबीआई वर्किंग पेपर शृंखला सं. 11।

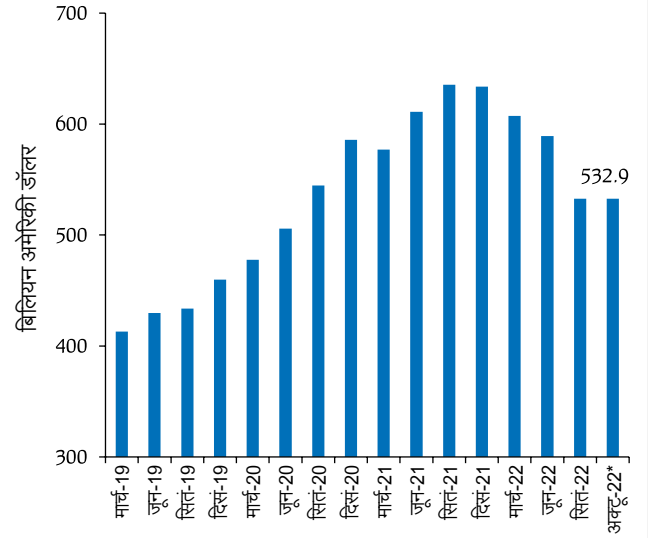
चार्ट 48: निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)



*12 अक्टूबर 2022 तक।

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)।

चार्ट 50: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां



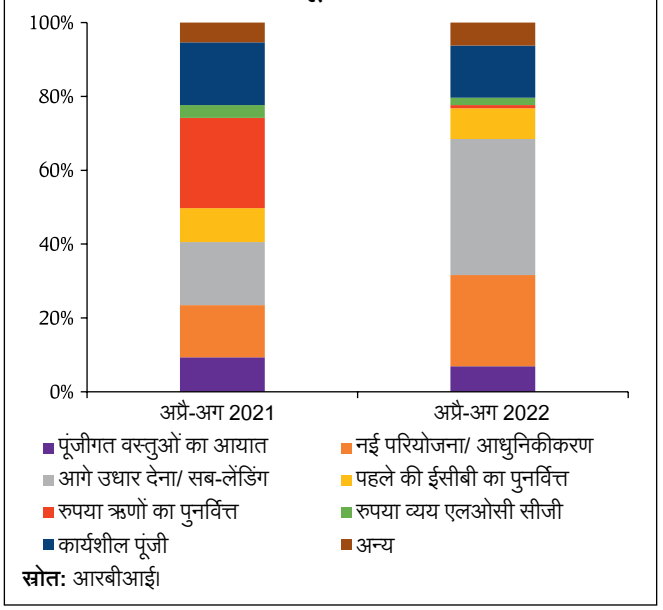
*7 अक्टूबर की स्थिति में।

स्रोत: आरबीआई।

परिपक्वता 7.3 वर्ष (जुलाई 2022 में 4.6 वर्ष) थी, जिसमें नई परियोजनाओं/ आधुनिकीकरण से संबंधित अधिक ईसीबी समझौते थे (चार्ट 49)।

7 अक्टूबर 2022 को 532.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां, 2022-23 के लिए पूर्वानुमानित आयात के 8.7 महीनों के बराबर था (चार्ट 50)। वर्ष 2022-23 में भंडार में अब तक 74.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई है; हालांकि, प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप हुई मूल्यांकन हानि के कारण मुख्यत: गिरावट आई। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनी मुद्राओं के समर्थन करने हेतु हस्तक्षेप से वैश्विक स्तर पर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में रिकॉर्ड गति से गिरावट आ रही है। आईएमएफ के सीओएफईआर के अनुसार, 2022 की पहली छमाही के दौरान[22] आरक्षित निधियों में लगभग 884 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है (चार्ट 51)।

चार्ट 49: ईसीबी एंड-यूज़ (अप्रैल-अगस्त 2022)

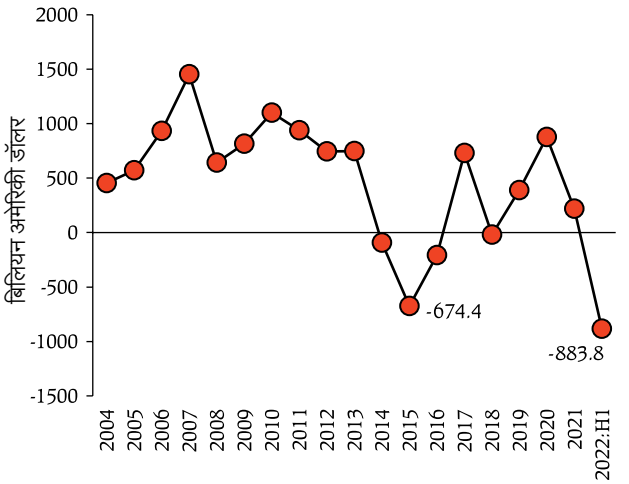


स्रोत: आरबीआई।

विदेशी मुद्रा बाजार में, एफपीआई इक्विटी बहिर्वाह और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण सितंबर 2022 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये (आईएनआर) में 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई। प्रमुख उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की तुलना में, हालांकि, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आईएनआर में मामूली मूल्यह्रास दिख रहा है (चार्ट 52)।

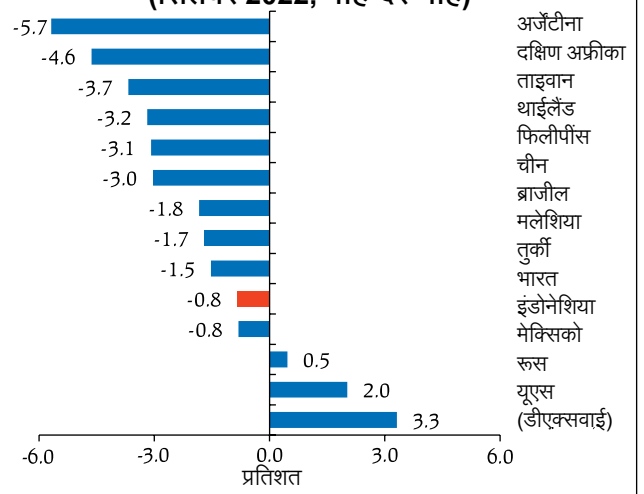
[22] आधिकारिक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां मुद्रा संरचना (सीओएफईआर), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी (आईएफएस)।

चार्ट 51: विश्व आधिकारिक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन



स्रोत: आधिकारिक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (सीओएफईआर) की मुद्रा संरचना, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी (आईएफएस)।

चार्ट 52: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और ईएमई मुद्राओं का उतार-चढ़ाव (सितंबर 2022, माह-दर-माह)



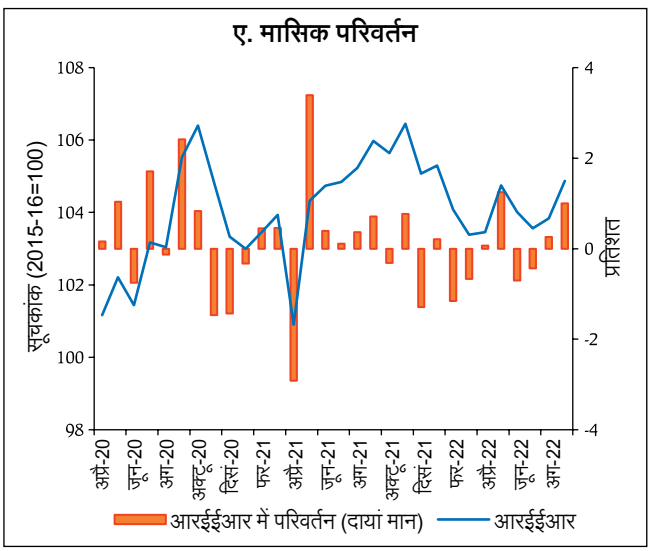
स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स: और आरबीआई स्टाफ की गणना।

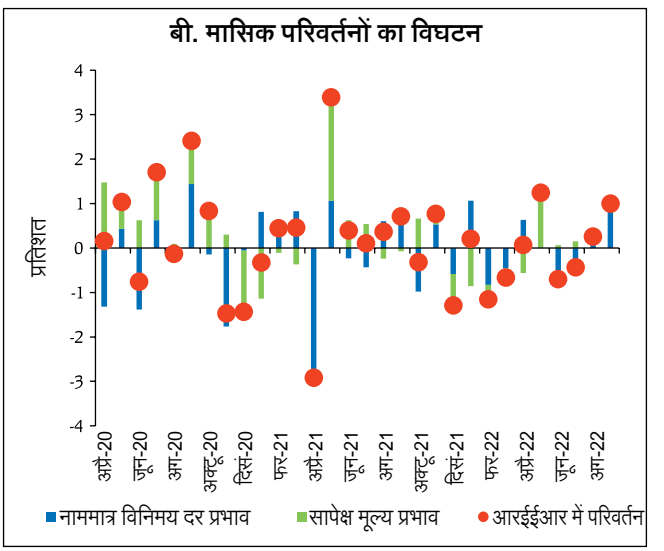
सितंबर 2022 में, मुख्य रूप से सांकेतिक प्रभावी शर्तों में आईएनआर में अधिमूल्यन के कारण वास्तविक प्रभावी शर्तों में आईएनआर में 1.0 प्रतिशत (माह-दर-माह) का अधिमूल्यन हुआ (चार्ट 53)।

भुगतान प्रणाली

सितंबर 2022 में विभिन्न भुगतान माध्यमों में डिजिटल लेन-देन जारी रहा। बड़े मूल्य और खुदरा माध्यम के तहत लेन-देन में एक वर्ष पूर्व उच्च आधार पर दहाई अंकों की वृद्धि (वर्ष-

चार्ट 53: 40 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में मासिक उतार-चढ़ाव





स्रोत: आरबीआई।

सारणी 7: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

(प्रतिशत)

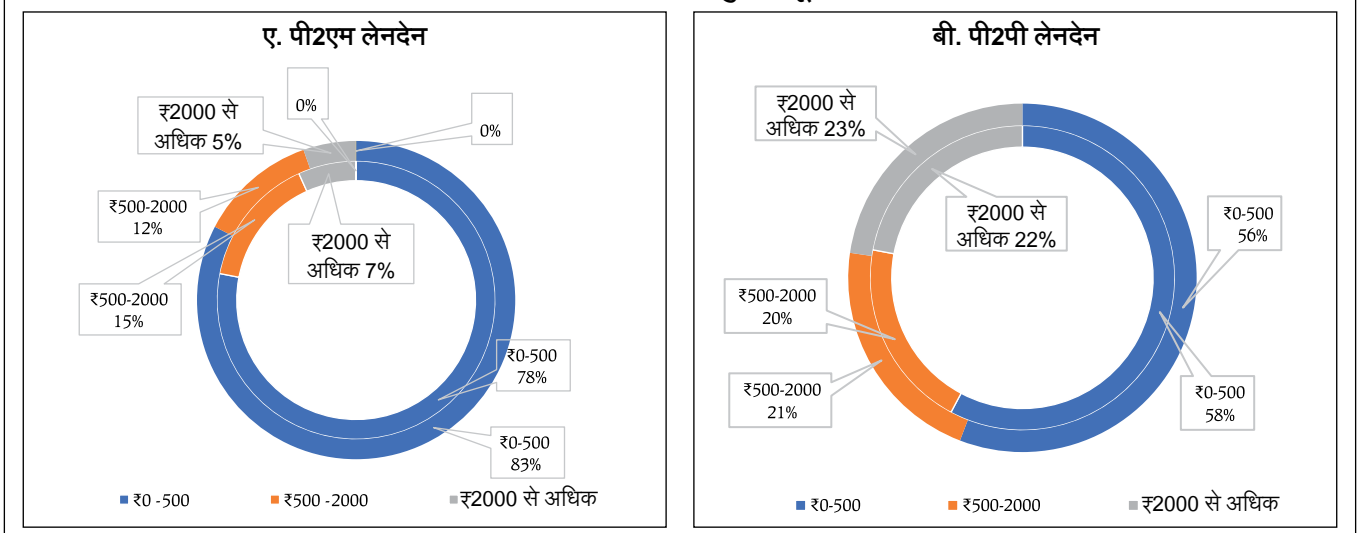
भुगतान प्रणाली संकेतक	लेनदेन मात्रा वृद्धि (व-द-व)				लेनदेन मूल्य वृद्धि (व-द-व)			
	अग-21	अग-22	सितं-21	सितं-22	अग-21	अग-22	सितं-21	सितं-22
आरटीजीएस	42.6	12.9	34.2	13.6	39.4	14.8	16.7	24.6
एनईएफटी	37.2	29.5	36.1	29.0	14.5	19.1	11.7	20.8
यूपीआई	119.6	85.1	103.1	85.5	114.2	67.9	99.0	70.5
आईएमपीएस	54.3	23.0	37.7	20.1	36.2	39.3	30.3	40.2
एनएसीएच	-2.3	14.3	-8.6	38.2	21.0	24.3	19.1	28.1
एनईटीसी	107.8	35.2	75.9	33.9	79.6	38.0	55.1	41.1
बीबीपीएस	177.6	48.5	156.8	49.5	172.5	56.1	206.7	36.8

स्रोत: आरबीआई परिपत्र, सितंबर 2022 ।

दर-वर्ष) दर्ज की गई (सारणी 7)। एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अप्रैल 2022 तक कम-से-कम किसी एक डिजिटल भुगतान माध्यम का उपयोग किया।[23]

एकीकृत भगुतान इंटरफेस (यूपीआई) आधारित भुगतानों में अत्यधिक वृद्धि को दर्शाते हुए, समकक्षीय [पीयर-टू-पीयर (पी2पी)] खंड में मात्रा और मूल्य दोनों में 63 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले सितंबर 2022 में पीयर-टू-मर्चेंट (पी2एम) भुगतान 112 प्रतिशत (मात्रा) और 103 प्रतिशत (मूल्य) तक बढ़ गए हैं।[24] पी2एम और पी2पी मात्रा का बड़ा हिस्सा ₹0-500 लेनदेन बैंड (अर्थात क्रमशः 83 प्रतिशत और 56 प्रतिशत) में है, इसके बाद ₹501-2000 स्लैब है (चार्ट 54ए और 54बी)। पी2एम खंड में ₹0-500 स्तर (स्लैब) में मात्रा का बढ़ना यूपीआई लेनदेन की बढ़ती समावेशिता को इंगित करता है जो ऑनलाइन लेन-देन संबंधी ट्रेल्स के निर्माण के माध्यम से छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्रों के लिए क्रेडिट तक पहुंच को बढ़ावा दे सकता है।

चार्ट 54: लेन-देन के आकार के अनुसार यूपीआई की संरचना



टिप्पणी: आंतरिक चक्र: अक्टूबर 2021 ; बाह्य चक्र: सितंबर 2022 ।
स्रोत: एनपीसीआई।

[23] मास्टरकार्ड न्यू पैमेंट्स इंडेक्स (एनपीआई) 2022, मास्टरकार्ड।

[24] इसके परिणामस्वरूप, यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र में पी2एम की हिस्सेदारी मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 50 प्रतिशत (अगस्त 2021 में 45 प्रतिशत से) और 22 प्रतिशत (अगस्त 2021 में 19 प्रतिशत से) बढ़ गई है।

कार्ड खंड में, ई-कॉमर्स केंद्रों पर क्रेडिट कार्ड लेनदेन का औसत टिकट आकार (₹5948), बिक्री केंद्र [पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस)] लेनदेन (₹3363) से 76 प्रतिशत अधिक है। टीयर-2 शहरों में ई-कॉमर्स उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या और नए ई-कॉमर्स मॉडल[25] के उदय के साथ, क्रेडिट कार्ड लेनदेन का उपयोग बढ़ने की संभावना है। सितंबर में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), बिलों के भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल और सुलभ प्लेटफॉर्म, में ऋण चुकौती और डायरेक्ट-टू-होम रिचार्ज उप-खंड में प्रभावशाली वृद्धि हुई।

विनियमन में तालमेल बिठाने के लिए, डेटा संग्रह और संचयन के मानकों पर अभिसरण के अलावा, रिज़र्व बैंक ने ऑफ़लाइन भुगतान एग्रीगेटर (पीए) को विनियामक फ्रेमवर्क में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।[26] रिज़र्व बैंक ने हितधारकों के सहयोग से तीन पहलें शुरू कीं। सबसे पहले एक यूपीआई लाइट फीचर (ऑन-डिवाइस वॉलेट का उपयोग करके बहुत कम मूल्य के लेनदेन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पूर्व-अनुमोदित भुगतान समाधान) का सूत्रपात है।[27] दूसरा, क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की सुविधा है, जिसका उद्देश्य यूपीआई उपयोग को और बढ़ावा देना है। तीसरा, बीबीपीएस के माध्यम से बिल भुगतान के आवक विप्रेषण की अनुमति देने का निर्णय है।[28]

एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल)[29] ने अंतरराष्ट्रीय भुगतान कंपनियों के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य सक्रिय भारतीय यूपीआई आईडी को दुनिया भर में चुनिंदा क्यूआर कोड स्थानों पर लेनदेन करने में सक्षम बनाना है।[30] रिज़र्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2022 को भारत के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पर एक अवधारणा नोट जारी किया, ताकि आम तौर पर सीबीडीसी के बारे में और विशेष रूप से डिजिटल रुपये (ईᖯ) - भारत के प्रस्तावित सीबीडीसी की नियोजित विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। यह भी संकेत दिया गया था कि रिज़र्व बैंक शीघ्र ही विशिष्ट उपयोग मामलों के लिए ईᖯ का प्रायोगिक शुभारंभ करेगा।

निष्कर्ष

भविष्य की ओर बढ़ते हुए, भारत शेष वर्ष में समग्र रूप से समुत्थान करने और इसमें बढ़ोतरी के लिए तैयार है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि की गति से 2022-23 की पहली तिमाही के लिए एनएसओ के अनुमानों में एम्बेडेड ड्रैग को कम करने और शेष तिमाहियों में सकारात्मक क्षेत्र में जाने की उम्मीद है, जिसमें मौसमी रूप से समायोजित आधार भी शामिल है। हालांकि यह प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर में स्पष्ट नहीं हो सकता है, तिमाही दर तिमाही वार्षिक दरें अंतर्निहित सुधार को दर्शाएंगी। संपर्क-गहन क्षेत्र संभावित रूप से कायाकल्प का नेतृत्व करेंगे क्योंकि महामारी के कारण संयम कम हो गया है। त्योहार से संबंधित खर्च घरेलू मांग के अन्य घटकों के लिए सकारात्मक बाह्यताओं के साथ पहले से ही खपत मांग को बढ़ा रहा है।

सहज गति और अनुकूल आधारभूत प्रभावों के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में सितंबर के अपने उच्च स्तर से सामान्यता आएगी, हालांकि यह हठात्मक रूप से होगी। इन सकारात्मक घटना-क्रमों के खाद्य और पेय पदार्थों द्वारा चालित होने की संभावना है, जिन्हें वर्ष की पहली छमाही में बार-बार आघात पहुंचे हैं। ये आवेग खंड III में दर्शाए गए दैनिक डेटा में पहले से ही स्पष्ट हैं। सितंबर में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के सभी घटकों में व्यापक आधार पर सहजता के कारण उल्लेखनीय गिरावट आई है। पण्य और आपूर्ति शृंखला दबावों में सन्निहित अंतरराष्ट्रीय मूल्य दबावों में कमी से भी लागत और कीमतों में गिरावट आने की संभावना है।

जबकि लगातार तीन तिमाहियों (सितंबर तक) के लिए सहिष्णुता बैंड के ऊपर हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति की निरंतरता अनिवार्य जवाबदेही प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करेगी, मौद्रिक नीति- मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ पुनः संरेखित करने पर केंद्रित है। इसमें दो चुनौतियाँ शामिल हो सकती हैं - पहला, इसे सहिष्णुता बैंड के भीतर लाना और दूसरा, इसके मध्य-बिंदु के आसपास लाना। महामारी विज्ञान और भू-राजनीतिक दोनों कारणों से निरंतर आघातों को देखते हुए यह पथ द्रुतगामी होगा,

---

[25] दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 9 सितंबर 2022।

[26] आरबीआई, 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य', सितंबर 2022।

[27] एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति, सितंबर 2022।

[28] आरबीआई परिपत्र, सितंबर 2022।

[29] एनआईपीएल ने वैश्विक भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर समूह, 'टेरापे' के साथ साझेदारी की। इसके अलावा, यह यूरोप में भुगतान सेवा प्रदाता 'वर्ल्डलाइन' के साथ भी जुड़ा।

[30] एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति, सितंबर 2022

लेकिन मुद्रास्फीति में कमी उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों में विश्वास उत्पन्न करेगी, ज़िंदादिली और निवेश की पुनर्पूर्ति करेगी और भारत के निर्यात की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगी। मौद्रिक नीति के लंबे और परिवर्तनीय अंतराल के साथ परिचालन और अनिश्चितताओं को देखते हुए, मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई कठिन और लंबी होगी। फिर भी, यदि हम सफल होते हैं तो हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की संभावनाओं को मजबूत करेंगे और बाकी दुनिया के साथ ऋणात्मक मुद्रास्फीति अंतर का आनंद उठाएंगे। इस सुखद परिणाम से विदेशी निवेशकों का पुनः उत्साहवर्धन होगा, बाजार स्थिर होंगे और स्थायी आधार पर वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करेगा। जैसा कि आईएमएफ की प्रबंध निदेशक, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने हाल ही में आईएमएफ-विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान एक मीडिया संबोधन में कहा: "इस अंधकार के मध्य भारत आशा की एक किरण कहलाने का हकदार है"।

*भारत के लिए हरित सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान**

अनुपम प्रकाश^, कौस्तव के. सरकार^ और अमित कुमार ^ द्वारा

कोविड के बाद की अवधि में पर्यावरणीय धारणीयता पर आर्थिक वृद्धि के प्रतिकूल प्रभावों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का पता लगाने में सकल घरेलू उत्पाद आधारित वृद्धि लेखांकन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, हरित जीडीपी का महत्व- जो पर्यावरणीय ह्रास और राष्ट्रीय आय लेखा के अनुमानों में प्राकृतिक संसाधनों के क्षय को समायोजित करता है, कई गुना बढ़ गया है। धारणीय विकास संकेतकों और संसाधन खपत संकेतकों पर चरों का उपयोग करते हुए, यह आलेख भारत के लिए हरित जीडीपी का अनुमान प्रदान करने का प्रयास करता है। भारत के लिए हरित जीडीपी का पथ वर्ष 2012 के बाद से स्पष्ट सुधार के साथ ऊर्ध्वगामी गति दर्शाता है।

भूमिका

जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बेमौसम बारिश और बाढ़, सूखा, तूफान, चक्रवात, सूनामी, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति; ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ती प्रवृत्ति, बढ़ते तापमान की विसंगतियाँ[1] और प्रदूषण का बढ़ता स्तर जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएँ हैं- जो जीवन और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। जलवायु परिवर्तन ने कुछ संक्रामक रोगों के प्रसार में भी योगदान दिया है - जलजनित रोग (जैसे, विब्रियो पैराहामोलिटिकस जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है), और मच्छर जनित रोग (जैसे, मलेरिया और डेंगू बुखार) दोनों में। यह पाया गया है कि जो लोग अधिक वायु प्रदूषण और खराब वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में रहते हैं, उनमें कोविड संक्रमण के कारण फेफड़ों में गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक है (वू *एवं अन्य*, 2020)। अमेरिका में 3,080 काउंटियों के विश्लेषण में, अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि कोविड-19 की बीमारी के कारण उच्च मृत्यु दर और पीएम2.5[2] का आपस में संबंध था।

आमतौर पर यह भी माना जाता है कि विश्व के कम समृद्ध और वंचित देशों, *यानी* विश्व के दक्षिणी हिस्से पर जलवायु परिवर्तन का अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में पांचवें स्थान पर है - जो इसे दुनिया भर में जलवायु के प्रति संवेदनशील देशों में से एक बनाता है[3] (एकस्टीन *और अन्य*, 2019)। यह मुख्य रूप से इसकी व्यापक तटरेखा, उत्पादन प्रणाली में जीवाश्म ईंधन के उच्च अनुपात और मानसून पर निर्भर कृषि पर जनसंख्या के महत्वपूर्ण आकार की निर्भरता के कारण है। विश्व बैंक के एक अनुमान[4] के अनुसार, "यदि जलवायु परिवर्तन पर काबू नहीं पाया गया तो भारत की जीडीपी लगभग 3 प्रतिशत तक कम हो सकती है और 2050 तक देश की लगभग आधी आबादी के जीवन स्तर को प्रतिकूल रूप से बिगाड़ सकती है।" भारत जैसी उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) के लिए, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अर्थव्यवस्था के लिए कुल उत्पादन लक्ष्यों के साथ-साथ धारणीय विकास लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए जाएं।

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की विशेष रिपोर्ट, 2018 के अनुसार: "वैश्विक औसत सतह के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि से समुद्र के स्तर में वृद्धि के साथ-साथ अन्य प्रभावों जैसे कि बाढ़, सूखा, लू, जैसे अधिक लगातार और तीव्र जलवायु और प्रचंड मौसम का अनुमान लगाया गया है। नवंबर 2021 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी26) ग्लासगो शिखर सम्मेलन के अंत तक, 151 देशों ने वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए नई जलवायु योजनाएं (राष्ट्रीय स्तर पर

^ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं।

* इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार और मत केवल लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

1 "तापमान विसंगति, औसत या आधारभूत तापमान के बीच का अंतर है। एक धनात्मक विसंगति इंगित करती है कि दर्ज किया गया तापमान आधार रेखा से अधिक गर्म था, जबकि एक ऋणात्मक विसंगति इंगित करती है कि दर्ज किया गया तापमान आधार रेखा से अधिक ठंडा था" (https://energyeducation.ca/encyclopedia/Global_surface_temperature_anomaly)।

2 पीएम2.5 को कणाकार तत्व [पार्टिकुलेट मैटर्स (पीएम)] के रूप में परिभाषित किया गया है जो 2.5 माइक्रोन से कम के समतुल्य व्यास वाली हवा में फैल सकते हैं।

3 "ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इस बात का विश्लेषण करती है कि मौसम से संबंधित नुकसान की घटनाओं (तूफान, बाढ़, गर्मी की लहरें आदि) के प्रभावों से देश और क्षेत्र किस हद तक प्रभावित हुए हैं।" कृपया विवरण के लिए https://www.germanwatch.org/en/cri देखें।

4 विश्व बैंक, 2018 । दक्षिण एशिया के हॉटस्पॉट: जीवन स्तर पर तापमान और वर्षा परिवर्तन के प्रभाव।

निर्धारित योगदान, या एनडीसी के रूप में जानी जाती हैं) प्रस्तुत की थीं। लक्ष्य को बनाए रखने के लिए इस दशक के अंत तक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए, देशों को वैश्विक उत्सर्जन में 55 प्रतिशत (यूएनईपी, 2021) तक कटौती करने की आवश्यकता होगी। 4 अगस्त 2022 को, भारत ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने और 2070 तक नेट-जीरो तक पहुंचने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को सूचित करने के लिए अपने एनडीसी को अद्यतन किया[6]।

एनडीसी को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि भारत प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित पर्यावरणीय और परिचालन लागत के प्रबंधन में अपनी प्रगति की नियमित निगरानी करे। हालांकि, भारत के मामले में सीमित अध्ययन हैं, जिन्होंने पर्यावरण संबंधी लेखांकन के लिए मूल्यांकन अनुमान प्रदान करने का प्रयास किया है। साथ ही, भारत में पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन भौतिक मात्राओं तक सीमित है। इसलिए, विभिन्न पर्यावरणीय लागतों की तुलना और मूल्यांकन का दायरा बहुत सीमित हो जाता है। इस आलेख का उद्देश्य विश्व बैंक और ब्रिक्स जैसे स्थापित वैश्विक डेटा स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, कण क्षति, संसाधन की कमी जैसे चरों के लिए, भारत के पर्यावरण संबंधी आंकड़ों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करके पर्यावरण और आर्थिक लेखा प्रणाली (एसईईए) द्वारा प्रदान किए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लेखा फ्रेमवर्क के आधार पर, भारत के लिए हरित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रारंभिक अनुमान के माध्यम से इस अंतर को पाटना है। किसी भी भारतीय डेटाबेस से पर्यावरण संकेतकों पर डेटा की अनुपलब्धता के कारण, यह इस स्तर पर सर्वोत्तम शुरुआती अनुमान है। हम हरित जीडीपी के अपने अनुमान का उपयोग करते हुए, यह समझने की कोशिश करते हैं कि भारत ने पर्यावरणीय गिरावट *की तुलना में* अपनी वृद्धि आकांक्षाओं के प्रबंधन में वर्षों से किस प्रकार प्रगति की है।

इस आलेख को निम्न रूप से संरचित किया गया है। खंड II संक्षेप में पर्यावरण प्रदूषण और एक अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद के बीच संबंध - विशेष रूप से पर्यावरणीय कुज़्नेट वक्र (ईकेसी) की समीक्षा करता है। खंड III हरित जीडीपी और मैटेरियल फुटप्रिंट के अनुमानों के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली की समीक्षा करता है। खंड IV भारत के लिए हरित जीडीपी के अनुमान और भारत में इसके पथ पर केंद्रित है। सतत विकास संकेतकों और संसाधन खपत संकेतकों पर चर का उपयोग करते हुए, यह आलेख भारत के लिए हरित जीडीपी का अनुमान प्रदान करने का प्रयास करता है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यय भी शामिल है। खंड V पर्यावरण संबंधी संकेतकों और अनुसंधान के संभावित क्षेत्रों पर डेटा प्रसार के लिए भावी रूपरेखा के साथ समाप्त होता है।

II. साहित्यिक समीक्षा

हालांकि कोविड महामारी से संबंधित लॉकडाउन और प्रतिबंधों से उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां गंभीर थीं, लेकिन इसने दुनिया के प्रमुख शहरों में पीएम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता में कमी के कारण वायु गुणवत्ता के संदर्भ में पर्यावरण को विशेष रूप से और धनात्मक तरीके से प्रभावित किया। कोविड के बाद, चीन, इटली, फ्रांस और स्पेन में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 20-30 प्रतिशत की कमी देखी गई, जबकि अमेरिका में इसी के उत्सर्जन में लगभग 30 प्रतिशत की कमी देखी गई (भट *एवं अन्य*, 2021)।

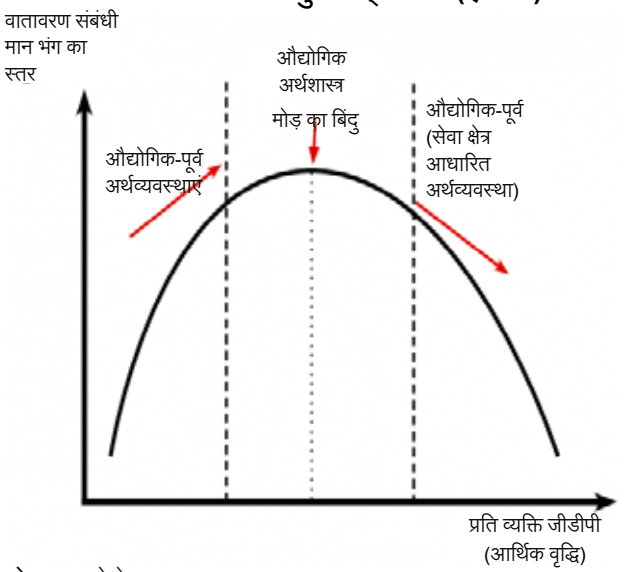
जीन एम. ग्रॉसमैन और एलन क्रुएगर ने ईकेसी[7] की अवधारणा को मानने के लिए साइमन कुजनेट द्वारा दी गई अवधारणा का इस्तेमाल किया, जिसमें पर्यावरणीय ह्रास और आर्थिक वृद्धि के बीच व्यवस्थित संबंध की व्याख्या की गई थी। व्यावहारिक रूप से, ईकेसी देश में देखे गए प्रदूषण के पथ को आर्थिक विकास की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दर्शाता है (चार्ट 1)। ईकेसी का तर्क है कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण स्तर और प्रति

[5] https://www.unep.org/news-and-stories/story/what-you-need-know-about-cop26-un-climate-change-conference/

[6] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1847812

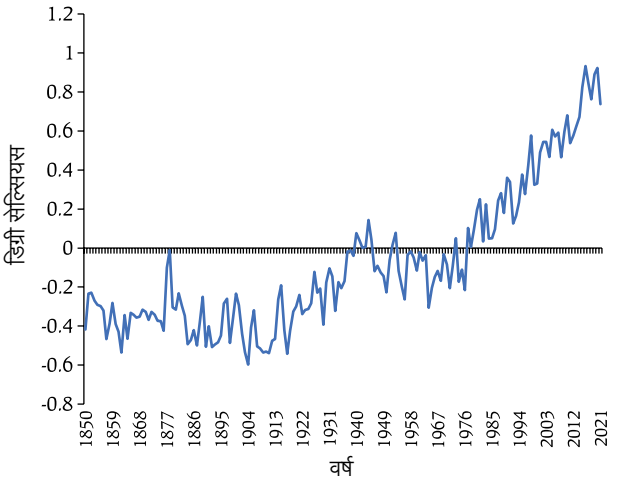
[7] ग्रॉसमैन और क्रूगर ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के कार्य के रूप में प्रदूषण के स्तर के मूल्यों का प्रयोग किया और प्रदर्शित किया कि कई भूखंड उलटे-यू-आकार के दिखाई देते हैं। इन अनुमानित प्रदूषण-आय पथों के उच्चतम स्तर अधिकांशतः किसी देश के 1985 डॉलर में 8000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय तक पहुँचने से पहले आते हैं (ग्रॉसमैन और क्रुएगर, 1995; पीपी.353)।

चार्ट 1: पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र (ईकेसी)



स्रोत: पानायोटो (2003)।

चार्ट 2: वैश्विक सतह तापमान विसंगति



टिप्पणी: डेटा 1961-1990 मेट ऑफिस हैडली सेंटर और ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय में जलवायु अनुसंधान इकाई के सापेक्ष तापमान विसंगतियों (डिग्री सेल्सियस) के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।
स्रोत: https://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut5/

व्यक्ति आय के बीच एक सकारात्मक संबंध प्रतीत होता है। हालांकि, आर्थिक वृद्धि प्रति व्यक्ति जीडीपी की एक निश्चित सीमा से परे, पर्यावरणीय सुधार की अनुमति देती है, जिससे प्रदूषण में कमी आती है (स्टर्न, 2018)। यह संबंध घंटी के आकार के एक वक्र से परिलक्षित होता है जो आर्थिक वृद्धि को पर्यावरणीय ह्रास से जोड़ता है।

पर्यावरण प्रदूषण में विशेष रूप से विश्व के उत्तरी हिस्से के देशों के योगदान को सही ठहराने के लिए ईकेसी के निष्कर्षों को बरकरार रखा गया था। हाल के शोध इस बात का प्रमाण देते हैं कि आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है (मनीजुक *और अन्य*, 2020)। यह भी पाया गया है कि ऐसा कोई एकल ईकेसी संबंध नहीं है, जो सभी प्रदूषकों को स्थान और समय के मद्देनजर स्पष्ट करता हो। ईकेसी संबंध स्थानीय वायु प्रदूषकों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कणाकार तत्वों के लिए सबसे विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। इसके विपरीत, वैश्विक जलवायु के लिए सबसे हानिकारक पदार्थ - कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के लिए ईकेसी परिकल्पना के समर्थन में बहुत कम सबूत हैं। जल प्रदूषण के लिए ईकेसी साक्ष्य भी मिश्रित हैं, और अनिर्णायक हैं (स्टर्न, 2004)।

ईकेसी पर सवाल उठाए जाने की पृष्ठभूमि में, पर्यावरणीय धारणीयता पर आर्थिक वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से कोविड के बाद की अवधि में सामने आए हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से दुनिया के गर्म होने और पृथ्वी की सतह के तापमान में तेजी से वृद्धि के बारे में सर्वसम्मति बढ़ रही है (चार्ट 2)। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज (जीआईएसएस) के एक विश्लेषण के अनुसार, "1880 के बाद से पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1° सेल्सियस (2° फ़ारेनहाइट) बढ़ गया है। दो-तिहाई वार्मिंग 1975 के बाद से हुई है, जो हर दशक में लगभग 0.15-0.20 डिग्री सेल्सियस की दर से हुई है।

वर्षों से, पर्यावरण लेखांकन के आसपास अनुसंधान विकसित हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का पता लगाने में जीडीपी आधारित वृद्धि लेखांकन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हरित जीडीपी का महत्व, जो पर्यावरणीय ह्रास और राष्ट्रीय आय लेखा के अनुमानों में प्राकृतिक संसाधनों को कम करने के लिए समायोजित करता है, कई गुना बढ़ गया है। शोध ने आगे न केवल आर्थिक निष्पादन बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय निष्पादन का भी पता लगाने के लिए वृद्धि लेखांकन के वैकल्पिक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1993 में एसईईए का मसौदा संस्करण प्रकाशित किया गया था: 'एसईईए फ्रेमवर्क पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन के लिए स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मानक है, जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के साथ इसके संबंधों को

व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है"[8]। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित मानकों में आर्थिक और पर्यावरणीय जानकारी को एकीकृत करने में मदद करता है।

वर्तमान आर्थिक चर्चाएं सामाजिक और आर्थिक निष्पादन के बीच संतुलन की ओर बहुत अधिक निर्भर हैं और कुछ हद तक पर्यावरणीय निष्पादन के साथ उनके संबंध की उपेक्षा कर रही हैं। वर्तमान में, वृद्धि लेखांकन मुख्य रूप से आर्थिक निष्पादन (वृद्धि दर, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी कर्ज, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व, *आदि)* और सामाजिक निष्पादन (गरीबी, असमानता, रोजगार का स्तर, जनसंख्या का पोषण स्तर, *आदि)* पर केंद्रित है। दूसरी ओर, जीडीपी में वृद्धि के लिए लेखांकन करते समय पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वृद्धि के प्रभाव पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए आर्थिक कल्याण के कुछ अन्य तरीके, मुख्य रूप से जीडीपी को आधार के रूप में उपयोग करते हैं और फिर विशिष्ट चरों के आधार पर समायोजन करते हैं। इनमें से कुछ सूचकांक हैं - धारणीय आर्थिक कल्याण सूचकांक, वास्तविक प्रगति संकेतक, हरित जीडीपी और वास्तविक धन। दूसरी ओर, कुछ ऐसे सूचकांक हैं जो आधार के रूप में जीडीपी का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन पर्यावरण और आर्थिक कल्याण के थोड़े-बहुत अनुमान पर पहुंचने के लिए पर्यावरणीय गतिविधियों, सामाजिक कल्याण, सामाजिक-पर्यावरण में सुधार और मानव पूंजी निर्माण को मापते हैं। उनमें से कुछ सूचकांक पारिस्थितिक पदचिह्न, व्यक्तिनिष्ठ भलाई, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता *आदि* हैं।

III. हरित वृद्धि और एंड मैटेरियल फुटप्रिंट का आकलन: कार्यप्रणाली

'हरित वृद्धि' पर एक उभरती बहस छिड़ रही है – जो वृद्धि प्रक्रियाओं को अधिक संसाधन-कुशल, स्वच्छ और अधिक आघात-सह बना रही है। हरित वृद्धि, या पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय आर्थिक वृद्धि को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है "संसाधनों की कमी और जलवायु संकट के कारण गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन की रणनीति"।[9] हरित जीडीपी पर्यावरणीय ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और राष्ट्रीय आय लेखा में संसाधनों और पर्यावरण की बचत के अनुमानों को ध्यान में रखती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, कोस्टा रिका, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, अमेरिका *आदि* कई देशों ने पहले ही हरित जीडीपी विकसित करने पर काम करना शुरू कर दिया है।

एसईईए से प्रेरित होकर, कई शोधकर्ताओं ने हरित जीडीपी को मापने के तरीकों और कौन से तत्व हरित जीडीपी अनुमान का हिस्सा बनने चाहिए, पर अध्ययन किया है (सारणी 1)। हरित जीडीपी गणना के एक सामान्य विचार में निम्न शामिल हैं: कार्बन उत्सर्जन लागत व उत्पन्न कचरे की अवसर लागत घटाना, और जीडीपी से प्राकृतिक संसाधनों की कमी की समायोजित बचत (स्टजेपनोविक, टॉमिक और स्केरे, 2017)। इसे और अधिक सामान्य रूप में रखने के लिए, हरित जीडीपी अनुमान में पर्यावरण प्रदूषण लागत और संसाधनों की कमी की लागत शामिल है (वांग, एफ, वांग, आर और वांग, जे, 2020)। इसके अलावा, न केवल पर्यावरण और संसाधनों की कमी पर व्यय की गई लागत को शामिल करके बल्कि संसाधनों और पर्यावरण की बचत को शामिल करके हरित जीडीपी अनुमान में सुधार किया गया था (क्वी, हुआंग और जी, 2021)। इस पेपर में हमने क्वी *और अन्य*, 2021 के बाद हरित जीडीपी अनुमान की सबसे व्यापक पद्धति को अपनाया है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण लागत, संसाधनों की कमी की लागत तथा संसाधनों और पर्यावरण की बचत शामिल है।

हरित वृद्धि को समझने के लिए संसाधनों का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग हरित वृद्धि में बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, हमने भारत में जीवाश्म ईंधन, बायोमास और धातु अयस्कों पर संसाधनों के उपयोग के लिए एक अनुमान प्रदान करने का प्रयास किया है।

[8] https://seea.un.org/content/homepage

[9] वर्ष 2005 में सियोल में आयोजित एशिया और प्रशांत में पर्यावरण और विकास (एमसीईडी) पर पांचवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अनुसार (https://www.unescap.org/our-work/environment-development/green-growth).

सारणी 1: हरित जीडीपी की कार्यप्रणाली पर साहित्य का चयन करें

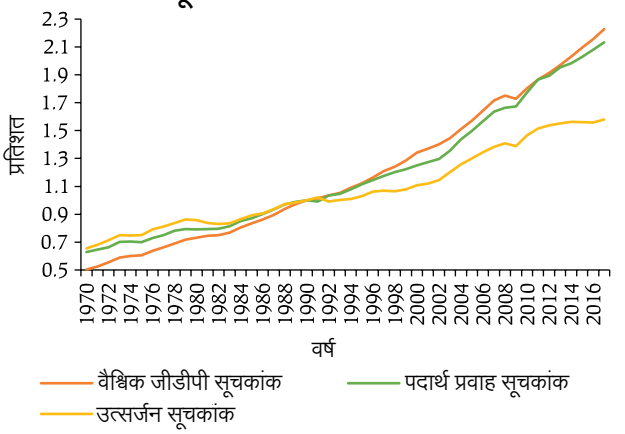
क्र.सं.	अनुसंधान लेख	कार्यरत पद्धति	चर का विवरण
1.	स्टेपानोविक , टॉमिक और स्केयर (2017)	हरित जीडीपी = जीडीपी - (केटीसीओ $_2$ * पीसीडीएम) - (वेस्ट * 74 किलोवाट * पेलेक्ट) - ((जीएनआई /100) * %एनआरडी)	• "जीडीपी: पारंपरिक जीडीपी • केटीसीओ $_2$: कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किलो टन में • पीसीडीएम: कार्बन के लिए औसत मात्रा-भारित मूल्य (पीपीपी में) • अपशिष्ट : कुल (वाणिज्यिक और औद्योगिक) अपशिष्ट (टन में व्यक्त) • चयन करें: 1 किलोवाट-घंटे के लिए मूल्य की गणना प्रत्येक देश के वाणिज्यिक और औद्योगिक मूल्य के माध्य के रूप में की जाती है। • एनआरडी: जीएनआई के प्रतिशत के रूप में प्राकृतिक संसाधनों की कमी की समायोजित बचत। • जीएनआई : सकल राष्ट्रीय आय।
2.	वांग, एफ, वांग, आर। और वांग, जे (2020)	• वायु प्रदूषण • अपशिष्ट जल प्रदूषण • ठोस अपशिष्ट प्रदूषण आरडीसी: • जीवाश्म ऊर्जा की कमी • जल संसाधन की कमी	वायु प्रदूषण: • "कार्बन उत्सर्जन प्रदूषण (कार्बन उत्सर्जन की मात्रा * रूपांतरण कारक) • एसओ2 उत्सर्जन प्रदूषण (एसओ2 उत्सर्जन *छाया मूल्य[10] की मात्रा) • अपशिष्ट जल प्रदूषण (अपशिष्ट जल निर्वहन की मात्रा * शासन लागत) ठोस अपशिष्ट प्रदूषण • ठोस अपशिष्ट निर्वहन से प्रदूषण (ठोस अपशिष्ट निर्वहन की मात्रा * शासन लागत) • ठोस अपशिष्ट भंडारण से प्रदूषण (ठोस अपशिष्ट भंडारण की मात्रा*शासन लागत) जीवाश्म ऊर्जा की कमी (जीवाश्म ऊर्जा की खपत की मात्रा * छाया मूल्य) जल संसाधनों की कमी (पानी की खपत की मात्रा * इकाई मात्रा की कीमत)"
3	क्वी, हुआंग और जी (2021)	हरित जीडीपी = जीडीपी- संसाधनों की लागत-पर्यावरण की लागत + संसाधनों और पर्यावरण की बचत	प्राकृतिक संसाधनों की कमी लागत: • "खेती की भूमि की कमी का मूल्य • वन संसाधन कमी मूल्य • जल संसाधन कमी मूल्य • ऊर्जा खपत मूल्य • खनिज संसाधनों की कमी मूल्य पर्यावरण गुणवत्ता गिरावट लागत: • वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • ठोस अपशिष्ट प्रदूषण • प्राकृतिक आपदा हानि संसाधन और पर्यावरण सुधार लाभ: • गार्डन हरित स्पेस के लाभ"

ब्रंटलैंड आयोग, 1987 ने सतत विकास को "भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने" के रूप में परिभाषित किया है। इस परिभाषा के अनुसार, संसाधन संरक्षण सतत विकास का मूल आधार बन जाता है। इस खंड में, इसलिए, सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई कुल घरेलू खपत (2010 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम) के अलावा, खपत की विभिन्न श्रेणियों जैसे जीवाश्म ईंधन, धातु, गैर-धात्विक खनिज आदि पर विचार किया गया है।

वैश्विक मैटेरियल फूटप्रिंट[10], जीडीपी और ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन समय के साथ तेजी से बढ़ा है और दृढ़ता से

[10] "सामग्री पदचिह्न" अंतिम खपत मांगों को पूरा करने के लिए निकाले गए कच्चे माल की कुल मात्रा को संदर्भित करता है।

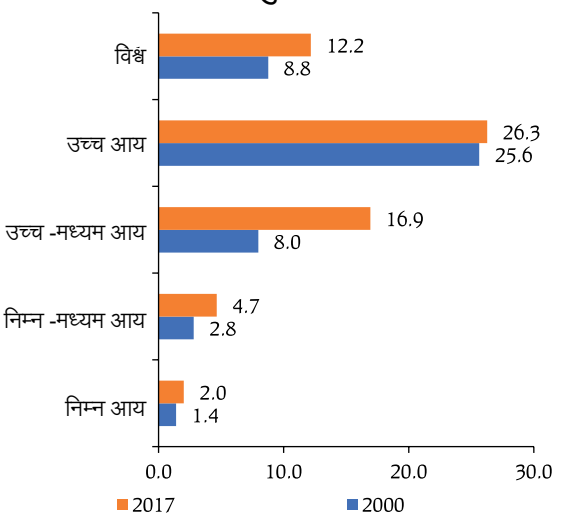
चार्ट 3 : प्रमुख वैश्विक आर्थिक और पर्यावरण सूचकांक में संगत परिवर्तन



टिप्पणी: 1.जीडीपी 2010 अमेरिकी डॉलर में स्थायी है।
2. आंकड़ों को वर्ष 1990 में संलग्न कर दिया गया है।

स्रोत : आरबीआई स्टाफ के आंकलन :
https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database; http://www.globalcarbonatlas.org and https://data.worldbank.org.

चार्ट 4 : विश्व 2000 और 2017 के लिए प्रति व्यक्ति माटेरियल फुटप्रिंट



स्रोत : https://unstats.un.org/

सहसंबद्ध बना हुआ है (चार्ट 3)। इस प्रकार, यह उल्लेख किया जा सकता है कि विकास को संसाधनों की खपत और पर्यावरणीय बोझ से अलग नहीं किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी के अनुसार, 2000 में लगभग 8.75 मीट्रिक टन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किसी व्यक्ति की जरूरतों (प्रति व्यक्ति मैटेरियल फूटप्रिंट) को पूरा करने के लिए किया गया था। 2017 में, वैश्विक प्रति व्यक्ति मैटेरियल फूटप्रिंट बढ़कर 12.18 मीट्रिक टन हो गया - 39 प्रतिशत की वृद्धि सेंट। उच्च आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति अधिकतम मैटेरियल फूटप्रिंट (2017 में प्रति व्यक्ति लगभग 26 मीट्रिक टन) का उपयोग करने का संदिग्ध अंतर है, जो उच्च-मध्य-आय वाले देशों (उसी वर्ष में प्रति व्यक्ति 17 मीट्रिक टन) से 55 प्रतिशत अधिक है। और कम आय वाले देशों के स्तर से 13 गुना अधिक (2017 में प्रति व्यक्ति 2 मीट्रिक टन) (चार्ट 4)। इन अवलोकनों (ईकेसी की अवधारणा के स्पष्ट विपरीत) ने मौजूदा वैश्विक विकास प्रक्रिया पर फिर से विचार करने और आवश्यक सुधार की मांग की।

IV. भारत में हरित विकास का अनुमान

भारत में पर्यावरण आर्थिक लेखा

2003 में स्थापित, प्राकृतिक संसाधनों के लेखांकन के संबंध में भारत में पहले की पहलों में से एक हरित इंडियन स्टेट्स ट्रस्ट (जीआईएसटी) है। जीआईएसटी ने एक परियोजना शुरू की - पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित राष्ट्रीय आय खातों के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हरित लेखा परियोजना (जीएआईएसपी)। जीएआईएसपी का लक्ष्य समायोजित राज्य राष्ट्रीय आय के वार्षिक अनुमानों पर पहुंचना है। परियोजना के पहले चरण में भारत में वन और वन उत्पादों, कृषि फसल भूमि, उप-मृदा संपत्ति, पारिस्थितिक पर्यटन, मीठे पानी के संसाधनों आदि के अनुमानों को शामिल करते हुए आठ रिपोर्टें तैयार की गईं। उन सभी रिपोर्टों ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक और विवरण लेखा पद्धति और अनुमान प्रदान किया। .

वन्यजीव मनोरंजक सेवाओं के लिए भुगतान करने की इच्छा के संदर्भ में एक अध्ययन ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पारिस्थितिकी

तंत्र सेवाओं को महत्व देने का प्रयास किया (बडोला और अन्य, 2010)। इसी तरह, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफ़एम) की एक अन्य परियोजना ने भारत में छह प्रमुख बाघ अभयारण्यों का आर्थिक मूल्यांकन प्रदान किया: कॉर्बेट, कान्हा , काजीरंगा , पेरियार , रणथंभौर और सुंदरबन। रिपोर्ट ने एक वर्ष में ₹50,000 से ₹1,90,000 प्रति हेक्टेयर की सीमा में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (क्षेत्र के संदर्भ में) से लाभ की गणना की। यह भी देखा गया कि इन भंडारों के लाभों का एक बड़ा हिस्सा अमूर्त था और इस प्रकार इसका हिसाब नहीं था (वर्मा और अन्य, 2015)।

हाल के वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और यूरोपीय संघ द्वारा एसईईए ढांचे के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र लेखांकन के लिए ज्ञान और लेखा प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए 2017 में नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज (एनसीएवीईएस) परियोजना शुरू की गई थी। यह परियोजना शुरू में पांच देशों - ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई थी। देशों को इन देशों में प्राकृतिक पूंजी के महत्व , पारिस्थितिकी और जैव विविधता की विविधता की उपस्थिति और इन देशों की जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) की प्रतिबद्धताओं के कारण चुना गया था।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने एनसीएवीईएस के तहत पर्यावरण लेखांकन के संकलन की शुरुआत की। प्राथमिक उद्देश्य एसईईए के अनुसार, भारत के स्टॉक और प्राकृतिक संपत्ति के प्रवाह का अनुमान प्रदान करना था। लेखांकन अनुमानों में भूमि, वन, आर्द्रभूमि, और भूमि, मिट्टी, जल, फसल विविधता और वन आवरण की गुणवत्ता का भी अनुमान शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए डेटा स्रोत और विस्तृत मूल्यांकन पद्धतियां हैं। फसल प्रावधान, इमारती लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उत्पादों का प्रावधान, कार्बन प्रतिधारण (जंगलों से), प्रकृति-आधारित पर्यटन और मिट्टी के कटाव की रोकथाम सेवाएं, एमओएसपीआई द्वारा प्रदान की जा रही हैं। इन सभी लेखांकन मूल्यांकनों को कुछ विशिष्ट वर्षों - 2005-06, 2011-12 और 2014-15 (भारत सरकार , 2021ए) के लिए प्रयास किया गया था।

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम) के सहयोग से 2018 में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस), उत्तराखंड सरकार द्वारा इसी तरह की एक परियोजना को अंजाम दिया गया था। उत्तराखंड राज्य के लिए खनिज, वन राज्य के वन संसाधनों के आर्थिक मूल्य और सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान का अनुमान लगाने के लिए। अध्ययन ने प्राकृतिक संसाधनों और राज्य की राजधानी (वर्मा *और अन्य*, 2018) पर प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुरूप सकल पर्यावरण उत्पाद (जीईपी) की रूपरेखा भी प्रदान की।

भारत में प्राकृतिक संसाधनों, वन और जल निकायों के मूल्यांकन की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थानों और समितियों द्वारा तैयार किए गए लेखांकन ढांचे और कार्यप्रणाली उपयोगी रहे हैं। हालाँकि, भारत जैसे विशाल देश के लिए इस तरह के लेखांकन अभ्यासों के विशाल आकार के कारण, भारत के लिए प्राकृतिक पूंजी के मूल्यांकन पर एक व्यापक आर्थिक डेटा श्रृंखला की तैयारी शायद अभी तक अमल में नहीं लाई जा सकी है। नतीजतन, लंबी अवधि के लिए भारत के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा प्राप्त करने के लिए, विश्व बैंक, ब्रिक्स और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए डेटा का सहारा लेना पड़ता है।

विश्व बैंक के अनुसार, भारत में पर्यावरणीय गिरावट प्रति वर्ष लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है - सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.7 प्रतिशत (विश्व बैंक, 2013)। मौजूदा आंकड़ों के आधार पर, हम भारत में हरित विकास की प्रवृत्ति और पथ को समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में, भारत में पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन भौतिक मात्राओं तक सीमित है (अर्थात् उत्पादन स्तर में परिवर्तन में प्रदर्शित मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन, आर्द्रभूमि क्षेत्र में परिवर्तन में दिखाई गई आर्द्रभूमि हानि आदि) और ये पर्यावरणीय चर आर्थिक शर्तों में परिवर्तित नहीं होते हैं। इसलिए, विभिन्न पर्यावरणीय लागतों की तुलना और मूल्यांकन का दायरा बहुत सीमित है। इस लेख का उद्देश्य विभिन्न

पर्यावरणीय लागतों का मूल्यांकन करके भारत के संदर्भ में हरित जीडीपी का व्यापक अनुमान देकर इस अंतर को भरना है।

डेटा और कार्यप्रणाली

भारत के लिए हरित जीडीपी माप पर पहुंचने के लिए, सतत विकास संकेतकों और संसाधन खपत संकेतकों के अलावा, हमने पर्यावरण संरक्षण पर सरकार द्वारा व्यय को भी शामिल किया है। सतत विकास संकेतकों में जीएनआई के प्रतिशत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड क्षति और कण उत्सर्जन क्षति शामिल है। जीएनआई के प्रतिशत के रूप में संसाधन खपत संकेतकों में ऊर्जा की कमी, खनिज की कमी, और शुद्ध वन की कमी की अवसर लागत शामिल है (निरंतर यूएस $ 2015)। फिर हमने मूल्यों को जीएनआई के प्रतिशत के रूप में स्थिर अमेरिकी डॉलर 2015 कीमतों पर पूर्ण संख्या में परिवर्तित कर दिया है। फिर इन परिवर्तित मूल्यों का उपयोग हरित जीडीपी के पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन पर पहुंचने के लिए किया गया है।

इस प्रकार, अनुमान की हमारी सामान्य रूपरेखा नीचे दी जा सकती है:

हरित जीडीपी = जीडीपी - (कार्बन डाइऑक्साइड क्षति + कण उत्सर्जन क्षति) - (ऊर्जा की कमी की अवसर लागत + खनिज की कमी + शुद्ध वन की कमी) + पर्यावरण संरक्षण पर व्यय

"कार्बन डाइऑक्साइड क्षति उत्सर्जित कार्बन की संख्या के 20 अमेरिकी डॉलर प्रति टन कार्बन का अनुमान है[11] ।

पार्टिकुलेट एमिशन डैमेज देश की आबादी के व्यास में 2.5 माइक्रोन से कम (पीएम2.5), परिवेशी ओजोन प्रदूषण और ठोस ईंधन के साथ खाना पकाने वाले घरों में पीएम2.5 की इनडोर सांद्रता के परिवेश सांद्रता के संपर्क में आने के कारण होने वाली क्षति है। नुकसान की गणना परित्यक्त श्रम, अकाल मृत्यु के कारण आय के रूप में की जाती है[12]। शुद्ध वन ह्रास की गणना इकाई संसाधन किराए के उत्पाद और प्राकृतिक वृद्धि पर फसल की अधिकता के रूप में की जाती है[13]। ऊर्जा की कमी शेष आरक्षित जीवनकाल (25 वर्ष पर कैप्ड) के लिए ऊर्जा संसाधनों के स्टॉक के मूल्य का अनुपात है[14]। इसमें कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। खनिज की कमी खनिज संसाधनों के भंडार के मूल्य का अनुपात शेष आरक्षित जीवन काल (25 वर्ष पर छाया हुआ) है। इसमें टिन, सोना, सीसा, जस्ता, लोहा, तांबा, निकल, चांदी, बॉक्साइट और फॉस्फेट शामिल हैं।[15] पार्टिकुलेट एमिशन डैमेज का डेटा 1990 के बाद ही उपलब्ध है और पर्यावरण संरक्षण डेटा पर खर्च का डेटा 2007-2020 की अवधि के लिए उपलब्ध है। पर्यावरण संरक्षण पर खर्च को छोड़कर इन सभी संकेतकों के लिए भारत के आंकड़े विश्व बैंक के विश्व विकास संकेतक (डब्ल्यूडीआई) डेटाबेस से संकलित किए गए हैं। ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन श्रृंखला से पर्यावरण संरक्षण पर व्यय के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। अंत में, 2015 की स्थिर कीमत पर 1971 से 2019 की अवधि के लिए हरित जीडीपी का अनुमान लगाया गया है।

हम अलग-अलग समय पर डेटा की उपलब्धता के आधार पर हरित जीडीपी के तीन उपायों- जी1, जी2 और जी3 की गणना करते हैं। इन उपायों को नीचे परिभाषित किया गया है:

1. जी1 = जीडीपी - (कार्बन डाइऑक्साइड क्षति) - (ऊर्जा की कमी की अवसर लागत + खनिज की कमी + शुद्ध वन की कमी); डेटा उपलब्धता: 1971-2019।
2. जी 2 = जी 1 - कण उत्सर्जन क्षति; डेटा उपलब्धता: 1990-2019।
3. जी 3 = जी 2 + पर्यावरण संरक्षण पर व्यय; डेटा उपलब्धता: 2006-2019।

हरित सकल घरेलू उत्पाद जी3 इस स्तर पर सबसे व्यापक उपाय है और इसमें सभी उपलब्ध जानकारी शामिल है जबकि जी1 सबसे कम व्यापक है। इसके अलावा, हमने जी1, जी2 और जी3 को जीडीपी से विभाजित करके हरित जीडीपी अनुपात जीआर1 , जीआर 2 और जीआर3 की गणना की है। ये अनुपात

[11] डब्ल्यूडीआई, विश्व बैंक के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड क्षति की लंबी परिभाषा।

[12] डब्ल्यूडीआई, विश्व बैंक के अनुसार कण उत्सर्जन क्षति की लंबी परिभाषा।

[13] विश्व विकास सूचकांक, विश्व बैंक के अनुसार निवल वन अवक्षय की लंबी परिभाषा।

[14] विश्व विकास सूचकांक, विश्व बैंक के अनुसार ऊर्जा की कमी की लंबी परिभाषा।

[15] विश्व विकास सूचकांक, विश्व बैंक के अनुसार खनिज की कमी की लंबी परिभाषा

हमें आर्थिक गतिविधियों के पारंपरिक माप यानी जीडीपी के संबंध में हरित जीडीपी के पथ का विश्लेषण करने में मदद करेंगे।

परिणाम और चर्चा

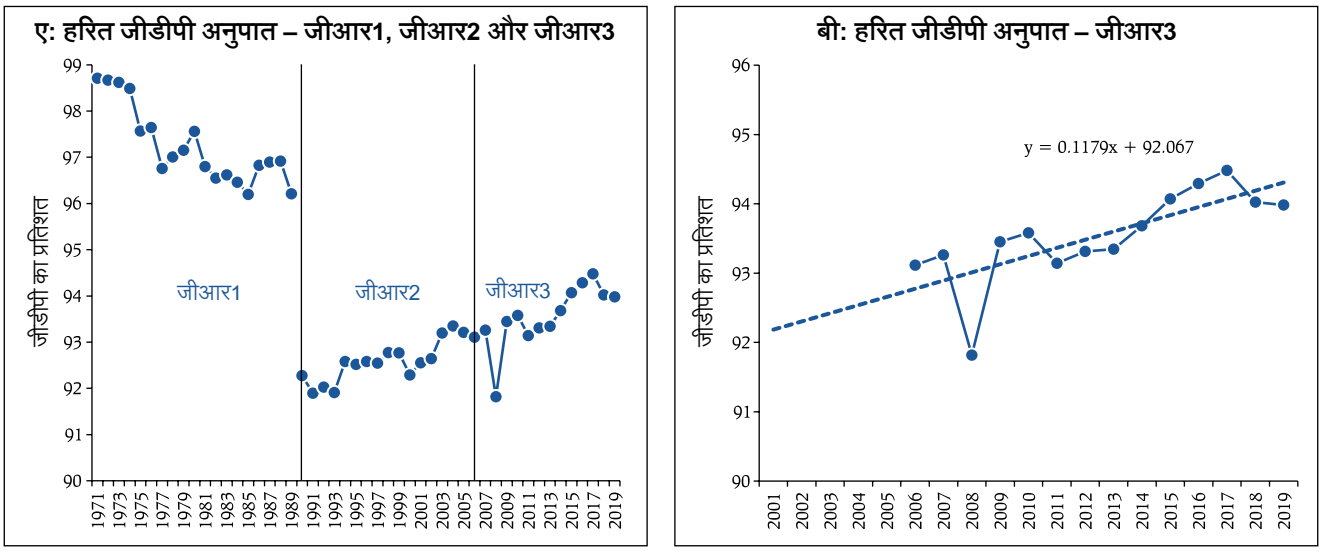
जी1, जी2 और जी3 पर आधारित हरित जीडीपी में वृद्धि का रुझान है। हरित जीडीपी जी1 1971 में ₹13.2 लाख करोड़ से बढ़कर 2019 में ₹167.7 लाख करोड़ हो गया, हरित जीडीपी जी2 1990 में ₹28.1 लाख करोड़ से बढ़कर 2019 में ₹165.8 लाख करोड़ हो गया, और हरित जीडीपी जी3 2006 में ₹72.1 लाख करोड़ से बढ़ गया 2019 में ₹165.9 लाख करोड़ (अनुबंध सारणी 1)।

लिफाफा दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, 1971 से 1989 की अवधि के लिए हरित जीडीपी अनुपात जीआर1, 1990 से 2005 के लिए जीआर2, और 2006 से 2019 के लिए जीआर3, प्लॉट किया गया है [चार्ट 5(ए)]। हम हरित जीडीपी अनुपात के पथ के आधार पर तीन व्यापक चरणों की पहचान करते हैं। 1971-1989 की अवधि के पहले चरण में, जीआर 1976, 1977-1980 और 1986 में कभी-कभी सुधार के साथ ज्यादातर गिरावट की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है, यह दर्शाता है कि इस चरण के दौरान विकास ने पर्यावरणीय लागत को बढ़ाया। इस अवधि के दौरान, वनों की कटाई, संसाधनों की कमी और कार्बन उत्सर्जन के कारण होने वाले नुकसान के मामले में पर्यावरणीय लागत की तुलना में उच्च आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। 1989 और 1990 के वर्षों में देखी गई अचानक गिरावट कणीय उत्सर्जन क्षति डेटा को शामिल करने के परिणामस्वरूप हुई।

दूसरे चरण (1990-2006) के दौरान, जो 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल[16] का गवाह बना, हरित जीडीपी अनुपात आम तौर पर एक ऊपर की ओर पथ का पालन करता था, क्योंकि भारत ने उच्च आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्यों के बीच संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया, पहले चरण में देखी गई नीचे की प्रवृत्ति थोड़ा ऊपर की ओर पथ में परिवर्तित हो गई।

तीसरा चरण (2006-2019) सभी उपलब्ध सूचनाओं के साथ हरित जीडीपी के पथ को दर्शाता है। वर्ष 2007 में तीव्र गिरावट और वर्ष 2008 में बाद में सुधार ऊर्जा और खनिज की कमी से समानांतर नुकसान[17] से उत्पन्न हुआ। इसके बाद, इस चरण में पहले चरण की तुलना में तेज प्रवृत्ति के साथ ऊपर की ओर गति देखी गई है।

चार्ट 5: भारत के लिए हरित जीडीपी अनुपात

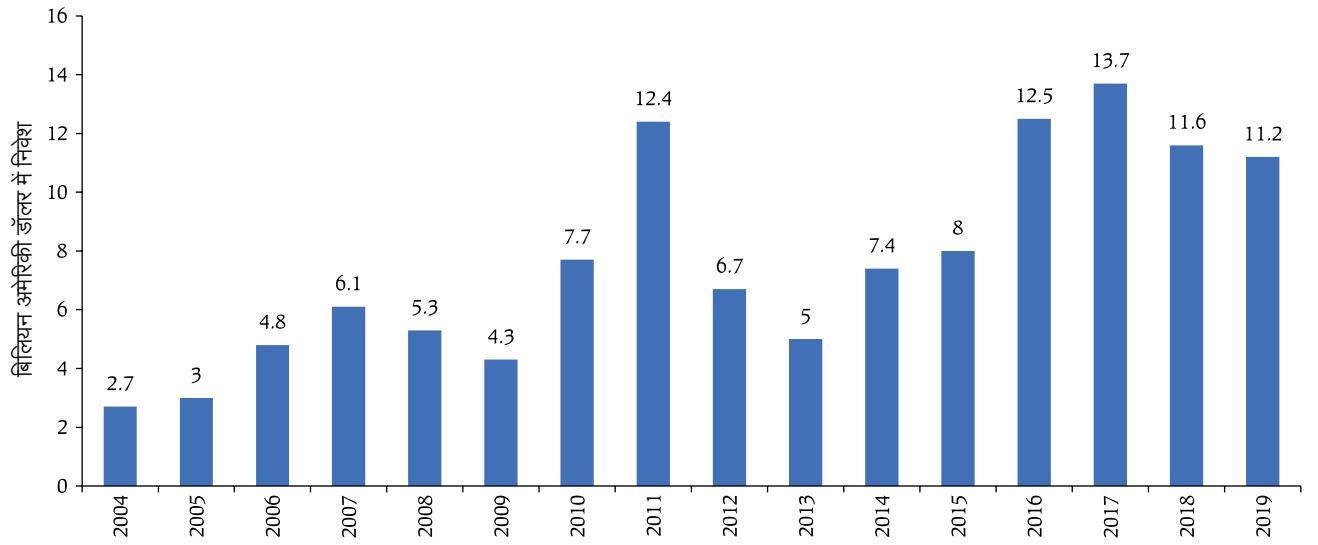


स्रोत: विश्व बैंक के डेटाबेस के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों का अनुमान।

[16] विवरण के लिए कृपया भारत में हरित पहलों वाला खंड देखें।

[17] वर्ष 2007 से 2008 तक, खनिज की कमी के कारण नुकसान ₹1.28 लाख करोड़ से बढ़कर ₹1.73 लाख करोड़ हो गया और फिर 2009 में घटकर ₹0.78 लाख करोड़ हो गया। 2007 से 2008 तक ऊर्जा की कमी के कारण नुकसान ₹1.37 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.18 लाख करोड़ हो गया और फिर 2009 में घटकर ₹1.12 लाख करोड़ हो गया।

चार्ट 6: भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में नया निवेश

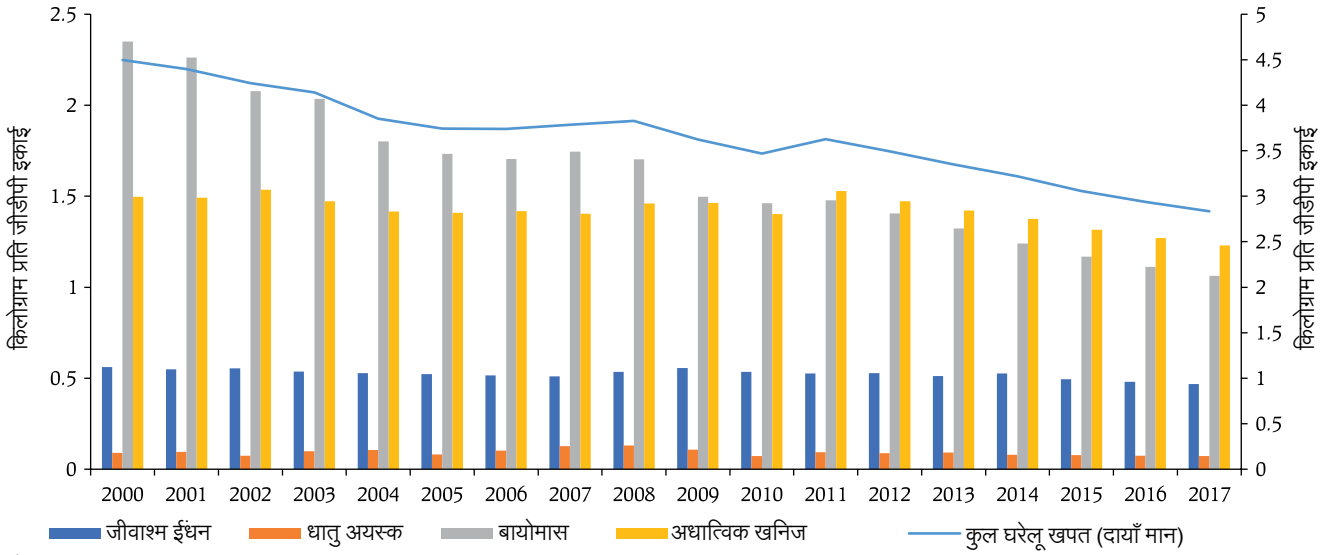


स्रोत: फ्रैंकफर्ट स्कूल-यूएनईपी केंद्र।

फ्रैंकफर्ट स्कूल - यूएनईपी केंद्र (2020) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में नया निवेश 2012 के बाद से काफी बढ़ गया है। 2012-2019 की अवधि के लिए वार्षिक औसत निवेश बढ़कर 9.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जो उससे पहले की अवधि में (2004-2011) 5.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट 6)।

संसाधनों का उपयोग (प्रति जीडीपी इकाई) पिछले कुछ वर्षों में घटा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार का संकेत देता है (चार्ट 7)। संसाधन उपयोग संकेतकों के लिए डेटा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी एसडीजी कंट्री प्रोफाइल से एकत्र किया गया है। डेटा सेट में जीवाश्म ईंधन, धातु अयस्क, फसल, फसल अवशेष, कोयला, बायोमास, गैर-धात्विक खनिज

चार्ट 7: भारत के मैटेरियल फूटप्रिंट



स्रोत: https://country-profiles.unstatshub.org/ind#goal-12

और कुल संसाधन निष्कर्षण के लिए खपत डेटा शामिल है। डेटा सेट में 2000 से 2017 तक की अवधि शामिल है और इसे भौतिक मात्रा में दर्शाया गया है।

भारत ने प्रत्येक वर्ष बीतने के साथ सकल घरेलू उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए संसाधनों की और कम मात्रा का उपयोग किया। संसाधन उपयोग में कमी (2000 में सकल घरेलू उत्पाद की 4.49 किलोग्राम प्रति इकाई से 2017 में सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई 2.83 किलोग्राम) मुख्य रूप से बायोमास उपयोग (चराई बायोमास, फसल और फसल अवशेष) और गैर-धात्विक खनिजों में कमी से प्रेरित है। 2000 में, बायोमास और गैर-धात्विक खनिज का उपयोग, जो क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई 2.35 किलोग्राम और सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई 1.49 किलोग्राम थे, उसे 2017 में क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई 1.06 किलोग्राम और सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई 1.23 किलोग्राम कर दिया गया है।

इस सुधार की वजह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न कचरे के पुनर्चक्रण में नीति निर्माताओं के बढ़ते प्रयासों, नकारात्मक बाह्यताओं को खत्म करने के लिए संपत्ति अधिकारों के कार्यान्वयन, ऊर्जा दक्षता मानकों और अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रणालियों में अपशिष्ट सामग्री के उत्पादन को कम करने के लिए तकनीकी प्रगति ज़िम्मेदार है। इन सभी कदमों ने न केवल संसाधनों की बर्बादी को कम किया है बल्कि संसाधनों को एक या दूसरे तरीके से पुनर्चक्रण करने में भी मदद की है।

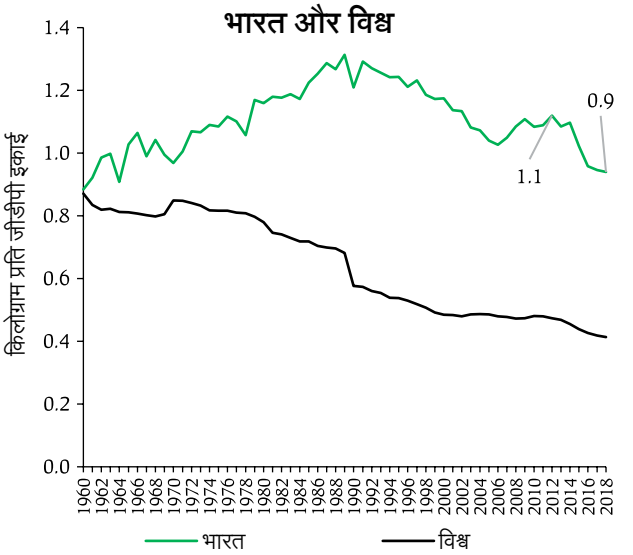
इसके अलावा, हाल की अवधि में भारत ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2012 में जीडीपी के 1.12 किलोग्राम प्रति यूनिट से घटकर 2018 में 0.93 किलोग्राम प्रति यूनिट (2015 में अमेरिकी डॉलर) हो गया (चार्ट 8)। यह प्रवृत्ति महामारी के दौर में भी शायद जारी रही जब आर्थिक गतिविधि धीमी हो गई थी।

हमारा मानना है कि भारत में हरित वृद्धि के मामले में हाल के वर्षों में हुई प्रगति को सरकार द्वारा कई पहलों और प्रभावी नीतियों से मदद मिली है।

हरित पहल- भारत

1980 के दशक तक, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम मुख्य रूप से अधिनियमों और कानूनों के

चार्ट 8: कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन - भारत और विश्व



स्रोत: विश्व बैंक।

माध्यम से की जाती थी। "जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974", "वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981", "राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995" इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम थे।

राष्ट्रीय नीतियों, मानकों और विनियमों के निर्माण के अलावा, 1985 में स्थापित पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) को सभी पर्यावरणीय गतिविधियों की योजना, प्रचार और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1992 में, प्रदूषण उपशमन पर राष्ट्रीय नीति और पर्यावरण और विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति और नीति वक्तव्य को केंद्र और राज्य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से पेश किया गया था।

भारत मई 1994 में "जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1992" और अक्टूबर 2014 में "आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल 2010" का हस्ताक्षरकर्ता बन गया। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जैव विविधता की रक्षा के लिए कदमों को लागू करने के लिए "जैविक विविधता अधिनियम 2002" (बीडी अधिनियम) को अपनाया। इसके अलावा, क्योटो प्रोटोकॉल में शुरू किए गए स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) ने भारत को जलवायु परिवर्तन की

दिशा में बेहतर स्थिति में लाने में मदद की। भारत ने सीडीएम को स्वीकार करने पर सकारात्मक संकेत दिया। सीडीएम के लिए संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में प्रगति हुई थी – जिससे भारत में बड़ी संख्या में सीडीएम परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ (चोपड़ा, 2017)।

सितंबर 2015 में, भारत सहित 193 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संकल्प के लिए प्रतिबद्धता जताई। जहां तक जलवायु संबंधी अंतरराष्ट्रीय समझौते और नीतियों का संबंध है, भारत ने हमेशा जिम्मेदारी दिखाई है। 2021 में सीओपी 26 में, इसने नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को बढ़ाने का संकल्प लिया

स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छता और पर्यावरण प्रदूषण पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए, खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने के लिए) और नमामि गंगे (गंगा नदी के प्रदूषण में कमी, संरक्षण और पुनर्जीवन) जैसी कुछ सरकारी पहल उल्लेखनीय हैं। इस चरण के दौरान प्रभावी नीतिगत पहलों ने सार्थक परिणाम देना शुरू कर दिया। 2021 में भारत का कुल वन आवरण बढ़कर 7,13,789 वर्ग किमी (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 प्रतिशत) हो गया जो 2013 में 6,97,898 वर्ग कि.मी. (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.23 प्रतिशत) था (भारत सरकार, 2021बी)। निजी संस्थाओं ने भी कम कार्बन उत्सर्जन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के संबंध में पहल के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता के लिए योगदान देना शुरू कर दिया है। हरित पहल, माल के उत्पादन के लिए हानिकारक संसाधनों (जैसे पारा, सीसा, आदि) का कम उपयोग और संसाधन दक्षता कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का एक प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। सरकार द्वारा हाल ही में की गई पहल और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा उत्तरदायित्व का बढ़ता प्रदर्शन भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश की वृद्धि में परिलक्षित हो रहा है।

भारत 2030 तक 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म विद्युत उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहा है, जिसमें गैर-जीवाश्म स्रोतों के 500 गीगावॉट का निर्माण भी शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उच्च हिस्से के अलावा, भारत प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) की बिक्री और ऊर्जा गहन फर्मों के लिए अनिवार्य ऑडिट जैसे उपायों के माध्यम से बेहतर ऊर्जा दक्षता को भी लक्षित कर रहा है। भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और पर्यावरण अभियान के लिए जीवन शैली जैसी पहलों के माध्यम से नेतृत्व कर रहा है। भारत के पास दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा (कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा) है और भारत की विशाल रेलवे प्रणाली इस दशक में निवल शून्य हो जाएगी। यह नई सौर पीवी क्षमता के लिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और इसने अपनी सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए 24.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को बैटरी निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इसके अलावा, प्रमुख तेल आयातकों और उपभोक्ताओं में से एक के रूप में, भारत ने 2025-26 से देश भर में गैसोलीन के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के प्रयासों में तेजी लाई है। इसके अलावा, हरित ऊर्जा पहल के एक भाग के रूप में, भारत ने हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है (रॉयटर्स, 2022)।

V. निष्कर्ष अवलोकन

प्रासंगिक डेटा की कमी को देखते हुए, इस पत्र में भारत के लिए हरित जीडीपी का अनुमान उपलब्ध वैश्विक डेटाबेस पर निर्भर करता है और पर्यावरण और आर्थिक लेखांकन के इस क्षेत्र में भविष्य के अनुसंधान के लिए शुरुआती बिंदु प्रदान करता है। भारत के लिए हरित सकल घरेलू उत्पाद का प्रक्षेपवक्र विशेष रूप से 2012 के बाद से स्पष्ट सुधार के साथ एक ऊपर की ओर गति को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, संसाधन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और मैटेरियल फूटप्रिंट, विशेष रूप से बायोमास और गैर-धात्विक खनिजों के मामले में, काफी सुधार के संकेत दिखा रहे हैं जो आगे चलकर हमारे निष्कर्षों का समर्थन करते हैं। इस प्रकार, हमारे अनुमान से व्यापक टिप्पणियों के आधार पर, हम कह सकते हैं कि जहाँ तक हरित वृद्धि का संबंध

है, भारत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है, जो यदि जारी रहा तो इसकी आबादी के सामान्य कल्याण के सुधार में योगदान देगा।

भारत के मामले में पर्यावरण संकेतकों से संबंधित डेटा की अनुपलब्धता अनुसंधान क्षेत्र में कार्य में शामिल होने के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है और हालांकि भारत में डेटा प्रसार[18] के लिए एक समर्पित ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके उपयोग को सुगम बनाने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, आगे के सुधारों के लिए ओईसीडी[19] और यूरोस्टैट[20] प्लेटफॉर्म को देखा जा सकता है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एक समर्पित घरेलू समूह का गठन किया जा सकता है (i) हरित जीडीपी के आकलन के लिए आवश्यक समय-श्रृंखला डेटाबेस प्रदान करना; (ii) नियमित आधार पर समय-समय पर भारत के लिए हरित जीडीपी का अनुमान जारी करना और (iii) ओईसीडी और यूरोस्टेट की तर्ज पर उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा प्रसार प्लैटफ़ार्म।

हाल की पहलों और उपलब्धियों के बावजूद, आगे जाकर जमीनी स्तर पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों के बीच विद्युत के प्रवाह का बेहतर समन्वय, और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए राष्ट्रव्यापी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का रोल आउट। कम कार्बन और जलवायु के अनुकूल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए पर्याप्त वित्त सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नीति और विनियमन में सुधार की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के महत्व और तात्कालिकता को देखते हुए, निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण में अपनी आवश्यक भूमिका निभाने के लिए वित्तीय नीति और विनियमन को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है (डेमेकास और ग्रिप्पा, 2021)। इस संदर्भ में, भारत के सामाजिक और विकास उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रणाली को हरित वित्तपोषण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है (आरबीआई, 2022)।

[18] https://data.gov.in/

[19] https://stats.oecd.org/

[20] https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

संदर्भ

Badola, R., S. A. Hussain, B. K. Mishra, B. Konthoujam, S. Thapliyal, and P.M. Dhakate. 2010. An Assessment of Ecosystem Services of Corbett Tiger Reserve, India. *The Environmentalist.* 30: 320-329.

Bhat, Shakeel Ahmad, Omar Bashir, Muhammad Bilal, Aamir Ishaq, Mehraj U. Din Dar, Rohitashw Kumar, Rouf Ahmad Bhat, and Farooq Sher. 2021. Impact of COVID-related Lockdowns on Environmental and Climate Change Scenarios. *Environ Res.* Apr; 195: 110839.

Chopra, Kanchan. 2017. Development and Environmental Policy in India: The Last Few Decades? Springer: 2017.

Demekas, Dimitri G. and Pierpaolo Grippa. 2021. Financial Regulation, Climate Change, and the Transition to a Low-Carbon Economy: A Survey of the Issues. WP/21/296. IMF Working Papers.

Eckstein, D, V. Künzel, L. Schäfer and M. Winges. 2019. German Climate Risk Index. German Watch. https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_14.pdf.

Frankfurt School-UNEP Centre. 2020. Global Trends in Renewable Energy Investment. FS-UNEP Collaborating Centre. Frankfurt am Main.

Government of India (GoI). 2021a. Ecosystem Accounts for India - Report of the NCAVES Project. MoSPI, 2021

Government of India (GoI). 2021b. *India State of Forest Report – 2021.* Forest Survey of India. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi.

Grossman, Gene M. and Alan Krueger. 1995. Economic Growth and the Environment. *The Quarterly Journal of Economics.* 110(2): 353-377.

International Monetary Fund. 2020. *Gross Domestic Product: An Economy's All.* Available at: https:// www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/gdp.html. Accessed on: March 08, 2022.

Kuznets, S. 1955. Economic Growth and Income Inequality. *American Economic Review* 45: 1–28.

Maneejuk, N, S. Ratchakom, P. Maneejuk and W. Yamaka. 2020. Does the Environmental Kuznets Curve Exist? An International Study. *Sustainability.* 12(21): 1-22.

Panayotou, T. 2003. Economic growth and the environment. Paper prepared for and presented at the Spring Seminar of the United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, March 3, 2003.

Qi, Shanzhong, Zhilei Huang and Lina Ji. 2021. Sustainable Development Based on Green GDP Accounting and Cloud Computing: A Case Study of Zhejiang Province, *Scientific Programming.* 2021. Doi: https://doi.org/10.1155/2021/7953164

R. Badola, S. A. Hussain, B. K. Mishra, B. Konthoujam, S. Thapliyal, and P.M. Dhakate. 2010. An assessment of ecosystem services of Corbett Tiger Reserve, India. Environmentalist 10, no. 1, 2010.

Reserve Bank of India. 2022. Discussion Paper on Climate Risk and Sustainable Finance. Reserve Bankof India. July 27, 2022.

Reuters. 2022. India plans to produce 5 mln tonnes of green hydrogen by 2030. February 17, 2022. Available at: https://www.reuters.com/business/energy/india-plans-produce-5-mln-tonnes-green-hydrogen-by-2030-20220217/#:~:text=India%20plans%20to%20manufacture%20five,export%20hub%20for%20the%20fuel. Accessed on: March 07, 2022.

Stern N. 2018. Public Economics as if Time Matters: Climate Change and the Dynamics of Policy. *Journal of Public Economics.* 162: 4-17.

Stern, David I. 2004. The Rise and Fall of Environmental Kuznets Curve. *World Development.* 32(8):1419-1439.

Stjepanović, Saša, Daniel Tomic, and Marinko Skare. 2017. A New Approach to Measuring Green GDP: A Cross-Country Analysis. *Entrepreneurship and Sustainability Issues.* 4(4): 574-590.

Verma, M., Verma, D. Negandhi, C. Khanna, A. Edgaonkar, A. David, G. Kadekodi, R. Costanza and R. Singh. 2015. "Economic Valuation of Tiger Reserves in India: A Value+ Approach," *Indian Institute of Forest Management,* Bhopal, India (2015): 190 – 195.

Verma, Madhu, Advait Edgaonkar, Swapan Mehra, Chandan Khanna, Prabhakar Panda and Kunal Bharat. 2018. Green Accounting of Forest Resources, Framework for Other Natural Resources and Index for Sustainable Environmental Performance for Uttarakhand State and Capacity Building on Environmental Statistics and Green Accounting. *Indian Institute of Forest Management and IORA Ecological Services*, October 2018.

अनुबंध सारणी 1: भारत के लिए हरित जीडीपी का अनुमान

(₹ लाख करोड़ में)

वर्ष	जी1	जी2	जी3
2019	167.752	165.839	165.860
2018	161.347	159.466	159.489
2017	152.176	150.410	150.434
2016	142.312	140.573	140.578
2015	131.275	129.547	129.555
2014	121.131	119.460	119.465
2013	112.477	110.819	110.823
2012	105.719	104.130	104.134
2011	100.049	98.563	98.568
2010	95.477	94.093	94.099
2009	87.909	86.605	86.609
2008	80.131	78.890	78.893
2007	78.918	77.731	77.735
2006	73.228	72.083	72.087
2005	67.916	66.783	
2004	63.094	61.972	
2003	58.467	57.328	
2002	53.981	52.835	
2001	51.999	50.847	
2000	49.521	48.372	
1999	47.965	46.821	
1998	44.153	43.022	
1997	41.536	40.417	
1996	39.947	38.858	
1995	37.179	36.104	
1994	34.658	33.584	
1993	32.336	31.259	
1992	30.964	29.880	
1991	29.378	28.286	
1990	29.216	28.107	
1989	27.769		
1988	26.403		
1987	24.078		
1986	23.143		
1985	21.944		
1984	20.907		
1983	20.171		
1982	18.786		
1981	18.203		
1980	17.306		
1979	16.146		
1978	17.013		
1977	16.053		
1976	15.103		
1975	14.845		
1974	13.729		
1973	13.586		
1972	13.159		
1971	13.238		

टिप्पणी: जीडीपी और जीएनआई दोनों आंकड़े 2015 के स्थिर अमेरिकी डॉलर में दिए गए हैं। रुपये में भारत के लिए हरित जीडीपी को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान औसत यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
स्रोत: विश्व बैंक डेटाबेस और ब्रिक्स प्रकाशनों के आधार पर आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

*वित्तीय डोमेन में 'बिगटेक': प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को संतुलित करना**

*विजय सिंह शेखावत^, अवधेश कुमार शुक्ला^, एसीवी सुब्रह्मण्यम^ और अभिषेक सिंह द्वारा लिखित^*

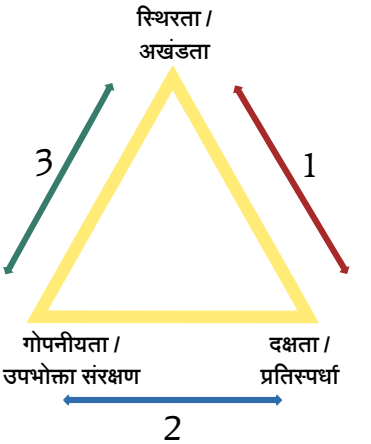
बिगटेक विशिष्ट रूप से अपने तकनीकी लाभ, बड़े उपयोगकर्ता आधार, वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यापक उपयोग और नेटवर्क-प्रभावों के साथ वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार हैं। यह लेख इस डोमेन में वैश्विक विनियामकीय प्रथाओं का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है जिसमें इकाई और गतिविधि-आधारित नियमों, दोनों को संरेखित करते हुए एक ढांचे के विकास को इंगित किया गया है। हालांकि, वित्तीय संस्थानों और तकनीकी कंपनियों के बीच बढ़ते जटिल अंतर्संबंधों के साथ, विनियामकीय ढांचे को नए जोखिम प्रसार चैनलों से उत्पन्न होने वाली सुभेद्यताओं को रोकने के लिए नवाचारों के साथ गति बनाए रखने की आवश्यकता है।

भूमिका

पिछले दो दशकों में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी-केंद्रित कंपनियों का तेजी से उदय हुआ है। वित्तीय क्षेत्र में, फिनटेक ने अपने नवाचारों के साथ वित्तीय मध्यस्थता के पारंपरिक चैनलों को बाधित किया है, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की है, और वित्तीय सेवाओं को वितरित करने के लिए दायरे और पैमाने को बदल दिया है। वे अक्सर बैंकों / बीमा कंपनियों जैसे मौजूदा भागीदारों के साथ सहयोग करते हैं, जिससे अधिक वित्तीय समावेशन, बेहतर प्रक्रिया दक्षता, कम लेनदेन और परिचालन लागत होती है। गैर-वित्तीय क्षेत्र में, अलीबाबा, अमेज़ॅन, फेसबुक, गूगल और टेनसेंट जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियां, जिन्हें आमतौर पर 'बिगटेक' के रूप में जाना जाता है, पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ी हैं। उनके द्वारा तैयार डेटा नेटवर्क की मजबूत प्रकृति के फायदों के आधार पर, कई बिगटेक ने वित्तीय सेवाओं की पेशकश करते हुए फिनटेक जगत में कदम रखा है, जिसमें भुगतान, धन प्रबंधन, बीमा और उधार शामिल हैं।

विश्व के विनियामक फिनटेक के लाभों को पहचानते हैं और एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, वे वित्त में बिगटेक के प्रवेश से नए जोखिम तत्वों से भी अवगत हैं। बेहतर सेवा पहुंच और वित्तीय समावेशन के लाभों के बावजूद, विनियामक विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा और बाजार स्पर्धात्मकता, उपभोक्ताओं के डेटा गोपनीयता अधिकारों और वित्तीय मध्यस्थता / स्थिरता (एफएसआई 2021 ए) पर बिगटेक के प्रभाव के बारे में सावधान हैं। वे दक्षता को बढ़ावा देने, डेटा गोपनीयता की रक्षा करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है (चित्र 1)। उक्त के परिणाम स्वरूप, विनियामक, फिनटेक जगत में एक समान अवसर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपने विनियामकीय ढांचे को बिगटेक (बीआईएस 2021) से जुड़ी संभावित जोखिमों को शामिल करते हुए संरेखित कर रहे हैं।[2]

चित्र 1: तीन उद्देश्यों को संतुलित करना - स्थिरता-दक्षता – गोपनीयता[3]



स्रोत: फेयेन एवं अन्य। पेट्रालिया एवं अन्य (2019) और कार्लेटी एवं अन्य (2020) के अनुसार।

---

^ लेखक पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) से हैं।

* टी के राजन, मुमप्र, डीओएस से प्राप्त मार्गदर्शन और प्रोत्साहन को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया जाता है। इसमें व्यक्त विचार लेखकों के हैं, न कि भारतीय रिज़र्व बैंक के।

1 "बिगटेक विनियमन: क्या चल रहा है?", सितंबर 2021, एफएसआई इनसाइट्स नंबर 36।

2 "वित्त में बिगटेक को विनियमित करना", एफएसआई ब्रीफ्स, बीआईएस बुलेटिन नंबर 45, अगस्त 2021।

3 *https://voxeu.org/article/policy-triangle-big-techs-finance*

इस संदर्भ में, यह अध्ययन वित्तीय डोमेन में बिगटेक के प्रवेश से उत्पन्न लाभों और चुनौतियों तथा उन्हें संतुलित करने हेतु विभिन्न क्षेत्राधिकारों के विनियामकीय और पर्यवेक्षी प्राधिकरणों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता है;

शेष अध्ययन निम्नानुसार संरचित है - खंड II वित्त में बिगटेक के प्रवेश और उनके द्वारा उत्पन्न संभावित चिंताओं पर चर्चा किया गया है। खंड III बिगटेक के उद्भव से वित्तीय स्थिरता, प्रतिस्पर्धा, परिचालन सुदृढ़ता और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकसित विनियामकीय परिदृश्य पर चर्चा किया गया है और खंड IV में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

II. वित्तीय डोमेन में बिगटेक का प्रवेश - जोखिम और चिंताएं

वित्त जगत में बिगटेक की गतिविधियां व्यापक फिनटेक नवाचार का एक विशेष विषय है। एक ओर जहां फिनटेक कंपनियों को मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं में संचालित करने के लिए स्थापित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बिगटेक फर्म गतिविधियों के एक व्यापक समुच्चय के हिस्से के रूप में वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। बिगटेक के मुख्य व्यवसाय सूचना प्रौद्योगिकी और परामर्श (जैसे, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स) से संबंधित हैं, जो उनके राजस्व का लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि इसकी तुलना में वित्तीय सेवाओं का हिस्सा उनके राजस्व (एफएसआई 2019) का लगभग 11 प्रतिशत है। सारणी 1 (ए और बी) में प्रमुख क्षेत्राधिकारों में विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए चुनिंदा बिगटेक की प्रविष्टि को दर्शाया गया है।

बिगटेक द्वारा प्रदान की जाने वाली तीन प्रमुख वित्तीय सेवाएं भुगतान, क्रेडिट प्रावधानीकरण और बैंकिंग हैं। बिगटेक के लिए, नियमों के अनुसार उन्हें वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सारणी 1 बी में दर्शाये अनुसार, बिगटेक को इन सेवाओं के लिए सहायक कंपनियों या स्वामित्व नियंत्रण के विभिन्न स्तरों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से लाइसेंस रखना होता है (रेस्टोय 2021)।

बिगटेक की व्यापकता उन्हें एक बड़ा ग्राहक आधार प्रदान करती है जो ग्राहकों के डेटा के कई पहलुओं तक पहुंच के साथ अपने प्लेटफॉर्मों / उत्पादों का उपयोग करने में लगे हुए हैं, जिससे मजबूत नेटवर्क प्रभाव उत्पन्न होते हैं। वित्त में बिगटेक का प्रवेश वित्तीय सेवाओं और उनकी मुख्य गैर-वित्तीय सेवाओं के बीच सशक्त पूरकता को भी दर्शाता है। सर्च इंजन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसी अपनी गैर-वित्तीय सेवाओं का उपयोग करके अपने ग्राहकों के आधार को देखते हुए, नवीन फिनटेक की तुलना में बिगटेक के लिए उत्पाद निर्माण और वित्तीय डोमेन में अपने पदचिह्न स्थापित करना अधिक आसानी से संभव है। यह फिनटेक जगत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समान अवसर प्रदान करने के मामले

सारणी 1 ए: बिगटेक कंपनियों द्वारा वित्तीय सेवा पेशकश

	मुख्य व्यवसाय	बैंकिंग #	ऋण प्रावधान	भुगतान	क्राउड फंडिंग	आस्ति प्रबंधन	बीमा
गूगल	इंटरनेट खोज/विज्ञापन			हाँ			
ऐप्पल	तकनीकी/उत्पादन हार्डवेयर			हाँ			
फेसबुक	सोशल मीडिया/विज्ञापन			हाँ			
अमेज़ॅन	ई-कॉमर्स/ऑनलाइन रिटेल		हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
अलीबाबा (एंट ग्रुप)	ई-कॉमर्स/ऑनलाइन रिटेल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
बायडू	इंटरनेट खोज/विज्ञापन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
जेडी.कॉम	ई-कॉमर्स/ऑनलाइन रिटेल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
टेनसेंट	टेक/गेमिंग और मैसेजिंग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
एनटीटी डोकोमो	मोबाइल संचार	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		
राकुटेन	ई-कॉमर्स/ऑनलाइन रिटेल	हाँ		हाँ		हाँ	हाँ
मर्केडो लिबर	ई-कॉमर्स/ऑनलाइन रिटेल		हाँ	हाँ		हाँ	

टिप्पणियाँ: 1. # बैंकिंग में लगी एक संस्था की मुख्य गतिविधि जमा लेना है, हालांकि नियम अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं।
2. "वाई" कम से कम एक अधिकार क्षेत्र में बिगटेक इकाई के माध्यम से और/या बिगटेक समूह के बाहर वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी में वित्तीय सेवा का प्रावधान।

स्रोत: " वित्त में बिगटेक : विनियामकीय दृष्टिकोण और नीति विकल्प", एफएसआई, मार्च 2021 और समाचार पोर्टल।

सारणी 1 बी: चयनित क्षेत्राधिकारों में बिगटेक कंपनियों द्वारा धारित लाइसेंस

धारित लाइसेंस	ब्राजील			चीन			यूरोपीय संघ			हांगकांग			यूके			यूएस		
	बी	पी	सी	बी	पी	सी	बी	पी	सी	बी	पी	सी	बी	पी	सी	बी	पी	सी
अमेज़ॅन									✓						✓			✓
ऐप्पल																		✓
फेसबुक									✓						✓			✓
गूगल									✓						✓			✓
एंट ग्रुप			✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓			✓			✓
बायडू *				✓*	✓	✓												
जेडी.कॉम *					✓	✓				✓*								
टेनसेंट *				✓*	✓	✓				✓		✓						
मर्केडो लिबर			✓															
एनटीटी डोकोमो							✓		✓						✓			
राकुटेन							✓		✓						✓			✓

☐ अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी या संयुक्त उद्यम में बाजार की उपस्थिति।

✓ बिगटेक के पास एक समूह के भीतर एक इकाई है, जो एक वित्तीय लाइसेंस रखती है।

☑ बिगटेक अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी या संयुक्त उद्यम दोनों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है और समूह के भीतर वित्तीय लाइसेंस धारक एक इकाई रखती है।

✓* इन बैंकों में बिगटेक की शेयरधारिता 50% से कम है।

टिप्पणी: बी- बैंकिंग लाइसेंस, पी - भुगतान लाइसेंस, सी- क्रेडिट लाइसेंस।

स्रोत: "वित्त में बिगटेक: नियामकीय दृष्टिकोण और नीति विकल्प" - एफएसआई, मार्च 2021।

में एक गंभीर बाधा है। तकनीकी लाभों के अलावा, बिगटेक में आमतौर पर प्रतिस्पर्धी दबावों का सामना करने के लिए वित्तीय शक्ति भी होती है।[4] इस पृष्ठभूमि में, बिगटेक द्वारा उत्पन्न प्रमुख जोखिमों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. सर्वप्रथम, बिगटेक की जटिल अभिशासन संरचना, प्रभावी निरीक्षण के लिए दायरे और इकाई-आधारित विनियमन डिजाइन को सीमित करती है।

2. दूसरा, बिगटेक वित्तीय सेवाओं के प्रावधान के लिए अपने प्रत्यक्ष जोखिम के माध्यम से जोखिम और परिपक्वता परिवर्तन कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। कभी-कभी यह छाया बैंकिंग गतिविधियों में भी परिणत अथवा लिप्त हो सकता है, जिससे वित्तीय स्थिरता कमजोर हो सकती है।

3. तीसरा, बिगटेक, तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के रूप में उनके व्यापक रूप से अपनाए जाने को देखते हुए, आम तौर पर अंतर्निहित मंच बन जाते हैं जिस पर कई सेवाओं की पेशकश की जाती है। यह विशिष्ट रूप से बिगटेक को आसानी से अंतर-प्रयोजनमूलक डेटाबेस प्राप्त करने की स्थिति में रखता है, जिसका उपयोग कर वे नवीन उत्पादों की पेशकश कर सकते हैं, जिसके कारण वे बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बन सकते हैं (मोएनजाक और संतिप्रभोब, 2021)।[5]

III. वित्त में बिगटेक से जोखिमों से बचने के लिए विनियामकीय ढांचे

दुनिया भर के विनियामकों ने वित्तीय क्षेत्र में बिगटेक और उनके व्यापार मॉडल की जांच बढ़ा दी है और बिगटेक द्वारा उत्पन्न जोखिमों से निपटने के लिए नीतिगत ढांचे को समायोजित करना आरंभ कर दिया है। वैश्विक विनियामकीय पहलों को मोटे तौर पर निम्नलिखित पांच प्रमुख आयामों (एफएसआई 2021 ए)[6] के आधार पर अंशांकित किया जा सकता है, अर्थात्,

[4] उदाहरण के लिए, जैसे-जैसे अधिक फिनटेक / बिगटेक वित्तीय डोमेन में आते हैं, व्यवसाय की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि प्रतियोगियों को अपने ग्राहकों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। फिनटेक या नई डिजिटल पेशकशों के साथ अक्सर विभिन्न छूट / इनाम दिये जाते हैं, जिससे उच्च नकदी व्यय होती है।

[5] डिजिटल युग में बिगटेक और गैर-बैंक वित्तीय सेवाओं को विनियमित करना - केंद्रीय बैंकिंग, 12 अप्रैल 2021।

[6] वित्त में बिगटेक के जोखिम और लाभों पर विस्तृत चर्चा के लिए देखें, उदाहरण के लिए, बीआईएस (2019), कार्स्टेंस (2018), क्रॉक्ससन एवं अन्य (2021) और एफएसबी (2019, 2020)।

ए) प्रतिस्पर्धा और बाजार स्पर्धात्मकता,

बी) डेटा सुरक्षा और डेटा-साझाकरण,

सी) व्यवसाय का संचालन,

डी) परिचालनगत सुदृढ़ता, और

ई) वित्तीय स्थिरता

III.ए प्रतिस्पर्धा और बाजार स्पर्धात्मकता **सुनिश्चित करना - प्रभुत्व को सीमित करना**

वित्तीय क्षेत्र में बिगटेक के आगमन के साथ, विश्व स्तर पर विनियामकों के लिए प्राथमिक चिंता प्रतिस्पर्धा और बाजार स्पर्धात्मकता को संरक्षित करना रहा है। बिगटेक को अपने मजबूत ग्राहक आधार के कारण प्रतिभागियों की विशिष्टता की अपेक्षा हो सकती है, संभावित या मौजूदा विक्रेताओं में भेदभाव कर सकते हैं, अपने स्वयं के उत्पादों को प्राथमिकता दे सकते हैं, अपनी सेवाओं को समीकृत कर सकते हैं, अंतर-उत्पाद सब्सिडी प्राप्त सकते हैं, या प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने के लिए डेटा के भंडार का दुरुपयोग कर सकते हैं (एफएसआई 2021 ए)। अपने डेटा नेटवर्क आधारित व्यापार मॉडल के माध्यम से, बिगटेक में प्रतिस्पर्धा और डेटा गोपनीयता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रमुख भागीदार बनने की क्षमता है। इसलिए, विनियामक प्राधिकरण डेटा तक समान पहुंच सुनिश्चित करके समान अवसर और प्रतिस्पर्धा को संरक्षित करने के लिए विनियम निर्धारित कर रहे हैं।

प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों को एहसास हो रहा है कि पारंपरिक घटनोत्तर दृष्टिकोण बिगटेक के मामले में अप्रभावी हो सकता है तथा वे घटना-पूर्व इकाई-आधारित नियमों पर ध्यान केंद्रित कर

सारणी 2: प्रमुख बिगटेक प्रतियोगिता दिशानिर्देश और चयनित अधिकार क्षेत्रों में प्रस्तावित विधान

क्षेत्राधिकार	क्षेत्राधिकार	दायरा	घटना-पूर्व या घटना -पश्चात?		लिखत			
			घ. पूर्व	घ. पश्चात	बीओपी	आईएनटी	टीपीपी	पीआरओ
चीन	प्लेटफ़ॉर्म एंटीमोनोपॉली दिशानिर्देश	सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। "आवश्यक सुविधाओं" के लिए अतिरिक्त प्रावधान, साथ ही प्रमुख प्लेटफार्मों द्वारा संभावित दुरुपयोग की पहचान करने के प्रावधान	✓	✓		✓	✓	✓
चीन	गैर-बैंक भुगतान सेवा प्रदाताओं पर विनियम*	व्यक्तियों और अन्य संगठनों के लिए भुगतान सेवाएं प्रदान करते हैं।	✓	✓		***	***	***
यूरोपीय संघ	डिजिटल बाजार अधिनियम (डीएमए)*	"द्वारपाल" एक मजबूत, दृढ़, और स्थायी आर्थिक और मध्यस्थता की स्थिति के साथ।	✓	✓**		✓	✓	✓
यूएस	प्रतिस्पर्धा और अविश्वास विधि प्रवर्तन अधिनियम* (सीएएलईआरए)	ऐसे "प्रमुख" फर्म जिनके पास कुल बाजार हिस्सेदारी का 50% या "महत्वपूर्ण" बाजार शक्ति से > है।	✓	✓	✓			
यूएस	सर्विस स्विचिंग एक्ट* (एक्सेस एक्ट) को सक्षम करके अनुकूलता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना	प्लेटफॉर्म, जो निम्नलिखित के लिए मानदंडों को पूरा करते हैं : (i) मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता (व्यक्तिगत या व्यवसाय); (ii) बाजार पूंजीकरण; और (iii) महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार का दर्जा रखने वालों को।	✓	✓**		✓		
यूएस	प्लेटफार्म प्रतिस्पर्धा और अवसर अधिनियम*	एक्सेस अधिनियम के समान दायरा।	✓		✓			
यूएस	अमेरिकन चॉइस एंड इनोवेशन ऑनलाइन एक्ट*	एक्सेस अधिनियम के समान दायरा।	✓	✓**		✓	✓	✓
यूएस	21वीं सदी के अधिनियम में भरोसे का टूटना*	निम्नलिखित का मूल्यांकन करके निर्धारित प्रमुख प्लेटफॉर्म (i) बाजार शक्ति की सीमा और स्थायित्व; (ii) सरकारी भागीदारी (संविदाएं आदि), (iii) विशिष्टता करार; (iv) नेटवर्क प्रभाव; और (v) लंबवत एकीकरण।	✓	✓**	✓		✓	
यूएस	बस्ट अप बिगटेक एक्ट*	प्लेटफॉर्म, जो निम्नलिखित के लिए मानदंडों को पूरा करते हैं (i) वार्षिक सक्रिय उपयोगकर्ता; और (ii) कुल राजस्व।	✓		✓		✓	

स्रोत: बिगटेक विनियमन: क्या चल रहा है? (इनसाइट्स नंबर 36 - सितंबर 2021), वित्तीय स्थिरता संस्थान, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स।
टिप्पणियाँ: * प्रस्तावित; ** पूर्व के उपाय (जैसे जुर्माना) बिगटेक के लिए विशिष्ट हैं।; *** यदि कोई गैर-बैंक भुगतान संस्थान बाजार हिस्सेदारी के मामले में कुछ शर्तों को पूरा करता है, तो पीबीसी अपने द्वारा किए जाने वाले कार्रवाइयों की पूर्व चेतावनी दे सकता है।
बीओपी = सबूत के बोझ को विनियामक से विलय या अधिग्रहण में शामिल फर्म के लिए स्थानांतरित करना; आईएनटी = तृतीय पक्षों के साथ अंतरसंचालनीयता; पीआरओ = व्यापार उपयोगकर्ताओं को उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने और पेशकश करने तथा प्लेटफॉर्म के बाहर अनुबंधों को समाप्त करने की अनुमति देना; टीपीपी = अपने और तीसरे पक्ष के उत्पादों या सेवाओं का समान व्यवहार।

रहे हैं, और इस प्रकार, बिगटेक को अपने व्यवसाय मॉडल को फिर से संरेखित करने की आवश्यकता है। प्रमुख बिगटेक द्वारा उत्पन्न संभावित प्रणालीगत जोखिमों को देखते हुए, प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं को सीमित करने के लिए सक्रिय कार्रवाई शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे प्रमुख क्षेत्राधिकारों में, इस बात के सबूत का बोझ कि विलय फर्म के लिए एक प्रमुख बाजार वाली स्थिति नहीं बनाएगा या उपभोक्ता के हितों का नुकसान होगा, अब विनियामक से स्थानांतरित होकर फर्मों पर चला गया है। इसके अलावा, प्रस्तावित नियमों में बिगटेक और तीसरे पक्षकारों के बीच पारस्परिकता की आवश्यकता होती है, जो उनके और तीसरे पक्षकारों के ऐप्स आदि के साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, अधिकांश क्षेत्राधिकरणों ने अपने बाजार प्रभुत्व की बारीकी से निगरानी करने के लिए बिगटेक पर घटना-पूर्व पर्यवेक्षी कार्रवाई तेज कर दी है।

सारणी 2 में अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन में अधिनियमित या प्रस्तावित प्रमुख अधिनियमों के प्रावधानों को सारांश में प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रमुख बिगटेक इन क्षेत्राधिकारों में स्थित हैं, इसलिए इन विनियमों से बिगटेक के व्यापार मॉडल को प्रभावित करने की संभावना है।[7]

III.बी डेटा सुरक्षा और डेटा-साझाकरण को सुरक्षित करना - ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करना

यूरोपीय संघ का जीडीपीआर (सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन) एक व्यापक नियामक ढांचा है, जो सामान्य रूप से डेटा संरक्षण और डेटा साझाकरण पहलुओं को देखता है। कई देशों ने यूरोपीय संघ के जीडीपीआर[8] के जैसे अपने डेटा संरक्षण व्यवस्था को संरेखित किया है। जीडीपीआर के तहत डेटा संरक्षण के "उद्देश्य विशिष्टता" और "सुरक्षा आवश्यकताओं" से संबंधित पहलू विशेष रूप से बिगटेक के लिए प्रासंगिक हैं। उद्देश्य विशिष्टता में उपयोगकर्ता के डेटा को एकत्र करने और संबंधित उपयोगकर्ता द्वारा सहमति दिए गए उद्देश्य के लिए उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यह अन्य प्लेटफॉर्मों से एकत्र किए गए ग्राहक डेटा का विश्लेषण करने के लिए नेटवर्क प्रभावों का उपयोग करने की बिगटेक की क्षमता को सीमित करता है। इसके अलावा, सुरक्षा आवश्यकता निर्दिष्ट करती है कि बिगटेक को उपयोगकर्ताओं के डेटा की सत्यता, गोपनीयता और उपलब्धता की रक्षा के लिए पर्याप्त संगठनात्मक उपाय करने चाहिए।[9] प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में डेटा संरक्षण और डेटा साझाकरण पहलुओं के अनुरूप के नियमों की प्रमुख विशेषताएं सारणी 3 में प्रस्तुत की गई हैं।

सारणी 3: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में डेटा संरक्षण और डेटा-साझाकरण दृष्टिकोण

डेटा सुरक्षा	यूरोपीय संघ	यूएस	चीन
व्यक्तिगत डेटा का संग्रह और उपयोग			
वैधता, निष्पक्षता, पारदर्शिता	हाँ	हाँ	हाँ
उद्देश्य विनिर्देश	हाँ	*	हाँ
सुरक्षा	हाँ	हाँ	हाँ
उपयोगकर्ता के डेटा अधिकार			
सहमति और पहुंच	हाँ	*	हाँ
सुधार और विलोपन	हाँ	*	हाँ
डेटा पोर्टेबिलिटी	हाँ	*	हाँ
डेटा साझा करना			
खुला बैंकिंग दृष्टिकोण	नियम के अनुसार	बाजार द्वारा निर्देशित	

टिप्पणियाँ: * अमेरिका में वर्तमान में इन पहलुओं को शामिल करने वाला कोई संघीय कानून नहीं है, लेकिन इन मुद्दों पर बहस जारी है;
स्रोत: बिगटेक विनियमन: क्या चल रहा है? (इनसाइट्स नंबर 36 - सितंबर 2021), वित्तीय स्थिरता संस्थान, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स।

डेटा सुवाह्यता/डेटा साझाकरण पर विनियम, उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए बिगटेक / फिनटेक से अपने व्यक्तिगत डेटा को वापस प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं या तकनीकी रूप से व्यवहार्य प्रारूप में अपने डेटा को तीसरे पक्ष को स्थानांतरित करने के लिए कहते हैं। यह ग्राहकों को ऐतिहासिक / व्यक्तिगत डेटा के नुकसान के बिना अपने पसंदीदा सेवा प्रदाता को चुनने में सक्षम बनाता है और इसलिए, बिगटेक[10] के प्रभुत्व को सीमित करता है। यूरोपीय संघ में डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए), चीन में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन (एसएएमआर) दिशानिर्देश जैसे विनियमों का उद्देश्य बिगटेक उपयोगकर्ताओं के

7 बिगटेक चीन और यूरोपीय संघ में प्रवर्तन कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका में, बिगटेक अपने बाजार प्रभुत्व (एफएसआई 2021 ए) को चुनौती देने वाले कई विधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

8 डेटा संरक्षण पर चीन का प्रस्तावित ढांचा यूरोपीय संघ के जीडीपीआर के साथ उच्च स्तर के संरेखण को दर्शाता है।

9 जीडीपीआर, आसान व्यापार प्रक्रिया स्वचालन, विश्वास और विश्वसनीयता में वृद्धि, संग्रहीत डेटा की बेहतर समझ, बेहतर डेटा प्रबंधन, संरक्षित और उन्नत उद्यम / ब्रांड प्रतिष्ठा को सक्षम बनाता है, और एक समान गोपनीयता वातावरण तैयार करने में मदद करता है (जॉन एडवर्ड्स, जनवरी 2021)।

10 एप्पल, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जैसे बिगटेक भी "ओपन-सोर्स, सर्विस-टू-सर्विस डेटा पोर्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म" बनाने के लक्ष्य के साथ अपनी डेटा ट्रांसफर परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।

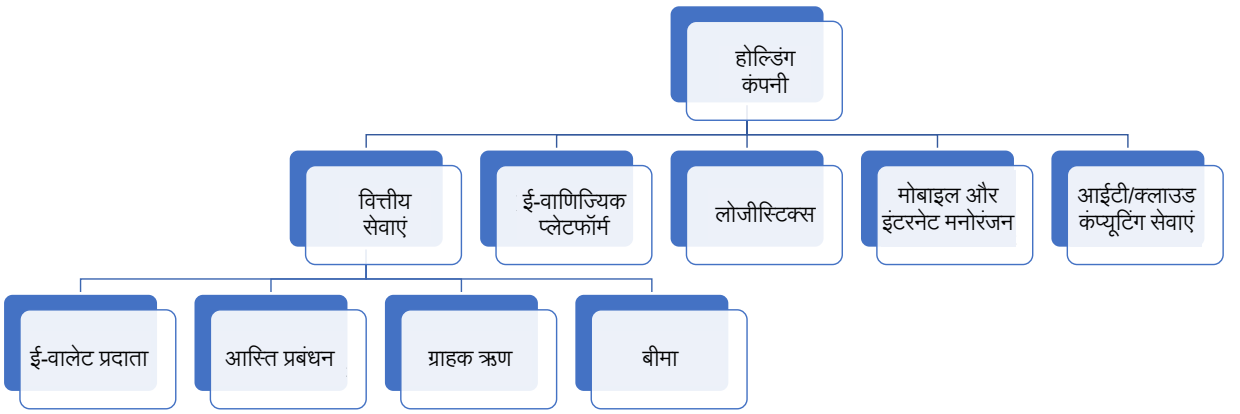
हितों की रक्षा करना है। उक्त विनियमों के लिए अति-आवश्यक विषय इस प्रकार है - (i) अधिक व्यापक खुली बैंकिंग व्यवस्था की दिशा में व्यापार मॉडल के डेटा सुवाह्यता और डेटा साझाकरण पहलू को तैयार करना, और (ii) व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना और उन्हें भ्रामक या भ्रामक प्रथाओं से बचाना।

III.सी व्यवसाय के संचालन पर नज़र रखना - प्रभावी अभिशासन

बिगटेक में अभिशासन संरचना जटिल है। अक्सर, वे विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न लाइसेंसों के तहत काम करने वाली अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि भुगतान, उपभोक्ता ऋण, धन प्रबंधन और बीमा। उनके पास शीर्ष पर एक होल्डिंग कंपनी या मूल कंपनी (समूह) के साथ एक एकीकृत व्यवसाय मॉडल है और अन्य सहायक कंपनियाँ सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करते हैं। इसके अलावा, ये बिगटेक व्यापार समझौतों / मेजबान देश के नियमों के आधार पर कई बार अधिकार क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करते हैं। मूल या होल्डिंग कंपनी, विनियामकीय / पर्यवेक्षी परिधि से बाहर हो सकती है और सहायक कंपनियों की वित्तीय-सेवा गतिविधियों से दूर हो सकती है। यह जटिल अभिशासन संरचना छाया बैंकिंग गतिविधियों के विस्तार की संभावना पैदा करती है, और इस प्रकार, व्यापक वित्तीय स्थिरता को कम करती है। एक बिगटेक फर्म की एक उदाहरणात्मक अभिशासन संरचना नीचे दिखाई गई है (चित्र 2)।

विभिन्न प्राधिकार क्षेत्रों में, बड़ी तकनीकें सहायक कंपनियों के माध्यम से या स्वामित्व नियंत्रण की अलग-अलग सीमा के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भुगतान, क्रेडिट और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस ले रही हैं। हालांकि, विनियामकीय प्रतिक्रिया इस प्रकार के दिशानिर्देश बनाने के लिए रही है, जो सामान्य हैं तथा जिनकी व्यापक प्रयोज्यता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के मामले में, भुगतान के प्राधिकरण और ई-मनी संस्थान के लिए दिशानिर्देश, "भुगतान सेवाएं (पीएसडी -2) - निर्देश" पर आधारित हैं।[11] इसके अलावा, ये दिशानिर्देश आवेदकों द्वारा सूचना प्राप्त करने और अनुपालन निर्दिष्ट करने में की गई गतिविधि के आधार पर आनुपातिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। यूके के मामले में, वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) ने भुगतान संस्थानों और ई-मनी संस्थानों को प्राधिकार प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करते हुए अपना दृष्टिकोण निर्धारित किया है।[12] एफसीए का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से कंपनी पर निर्बाध पर्यवेक्षी पहुँच (लाइसेंस / प्राधिकरण की मांग) की आवश्यकता और मूल और सहायक कंपनी (यदि कंपनी समूह / होल्डिंग संरचना का हिस्सा है) के कॉरपोरेट ढांचे पर स्पष्ट विवरण की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है। संक्षेप में, लाइसेंसिंग / प्राधिकरण दृष्टिकोण को पेशकश की गई सेवाओं की जटिलता के आधार पर 'आनुपातिकता' और 'लचीलेपन' द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।

चित्र 2: बिगटेक कंपनी की होल्डिंग संरचना को दर्शाने वाला योजनाबद्ध आरेख



स्रोत: मोएनजाक और संतिप्रभोब (2021), "डिजिटल युग में बिगटेक और गैर-बैंक वित्तीय सेवाओं को विनियमित करना", अप्रैल, सेंट्रल बैंकिंग

[11] https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/guidelines-on-authorisation-and-registration-under-psd2
[12] *https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fca-approach-payment-services-electronic-money-2017.pdf*

बिगटेक को उनके मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों में उनके प्रतिबंधात्मक व्यावसायिक प्रथाओं के लिए वैश्विक स्तर पर नियामकों द्वारा बारीकी से देखा जा रहा है। उपभोक्ता कल्याण की रक्षा के लिए बिगटेक के विरुद्ध अविश्वास नियमों का उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है। यूरोपीय संसद द्वारा अधिनियमित डिजिटल बाजार अधिनियम (डीएमए) और डिजिटल सेवाएं अधिनियम (डीएसए) जैसे कानूनों में पूरे डिजिटल परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। डीएमए स्पष्ट नियमों को निर्धारित करके बाजार द्वारपालों की गतिविधियों को विनियमित करेगा - "क्या करें" और "क्या न करें" की एक सूची - जिसका उद्देश्य उन्हें व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर अनुचित शर्तें लगाने से रोकना है। दूसरी ओर, डीएसए ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा और डिजिटल जगत को सुरक्षित बनाएगा।[13]

इसके अलावा, सिंगापुर, नीदरलैंड और हांगकांग जैसी अर्थव्यवस्थाओं ने नैतिक व्यावसायिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड/प्रबंधन द्वारा अधिक निरीक्षण के साथ कृत्रिम बुद्धि मॉडल के उपयोग के लिए अभिशासन, उत्तरदायित्व, उपभोक्ता संरक्षण आदि पर केंद्रित सिद्धांतों को निर्दिष्ट किया है।[14]

III.डी परिचालन सुदृढ़ता की निगरानी - व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करना

बिगटेक और वित्तीय संस्थानों के बीच अति महत्वाकांक्षी सहयोग वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में नए लिंकेज और निर्भरता का निर्माण कर रहा है। बिगटेक अपनी वित्तीय और गैर-वित्तपोषण सेवाओं दोनों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली को नई परिचालन जोखिम चुनौतियों में धकेल सकते हैं।

- वित्तीय सेवा प्रदाताओं के रूप में: बिगटेक फर्म अपने ग्राहकों को भुगतान सेवाएं प्रदान करती हैं और किसी भी सेवा रुकावट के परिणामस्वरूप वित्तपोषण गतिविधि में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
- गैर-वित्तीय सेवा प्रदाताओं के रूप में: बिगटेक फर्म अपनी गैर-वित्तपोषण सेवाओं से उत्पन्न परिचालन जोखिम के कारण वित्तीय स्थिरता के लिए अधिक खतरा पैदा करती हैं। केवल कुछ बड़ी तकनीक फर्में वैश्विक वित्तीय प्रणाली को प्रौद्योगिकी सेवाएं और बुनियादी ढांचा (जैसे, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स) प्रदान करती हैं।[15] इन फर्मों में से एक की विफलता, या किसी भी बड़ी तकनीक फर्म द्वारा दी जाने वाली सेवा की विफलता वित्तीय सेवाओं में एक महत्वपूर्ण घटना पैदा कर सकती है, जिसमें बाजारों, उपभोक्ताओं और वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

इन सेवाओं की महत्वपूर्णता से तात्पर्य यह है कि बिगटेक पहले से ही 'इतने - महत्वपूर्ण-हैं -कि विफल नहीं' हो सकते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक और सभी क्षेत्राधिकारों में नियामक एजेंसियां बिगटेक फर्मों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से उत्पन्न परिचालन जोखिमों और चुनौतियों को दूर करने के लिए नियमों पर चर्चा कर रही हैं। इनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है:

- **यूरोपीय संघ (ईयू) :** यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित डिजिटल परिचालन सुदृढ़ता अधिनियम (डीओआरए), वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल परिचालन सुदृढ़ता पर एक व्यापक ढांचा है। अनुपालन की जाने वाली सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करके, डीओआरए क्लाउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) सहित 'महत्वपूर्ण आईसीटी तृतीय पक्षकार प्रदाताओं' (सीटीपीपी) को विनियामकीय परिधि के भीतर लाता है। बिगटेक के लिए, डीओआरए दो तरीकों से प्रासंगिक है। सबसे पहले, अपने वित्तीय सेवाओं के संचालन में तीसरे पक्ष की सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के रूप में बिगटेक को तीसरे पक्ष के जोखिमों के मूल्यांकन और निगरानी पर तकनीकी मानकों का पालन करना होगा, जिसमें किसी तृतीय-पक्ष प्रदाता द्वारा जोखिम उत्पन्न किए जाने की स्थिति में न्यूनतम विघटनकारी निकास रणनीतियों का विकास भी शामिल है। दूसरा, तीसरे पक्ष की सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में बिगटेक जिन्हें "महत्वपूर्ण" माना जाता है (जैसे, क्लाउड कंप्यूटिंग), अतिरिक्त अपेक्षाओं और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन हो जाएंगे।

[13] *https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20211209STO19124/eu-digital-markets-act-and-digital-services-act-explained*

[14] फिनटेक के लिए नीतिगत कार्रवाइयां : अंतर-देशीय अवलोकन (इनसाइट्स नंबर 23 - जनवरी 2020), वित्तीय स्थिरता संस्थान, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स

[15] बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2020 के एक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया कि 70 प्रतिशत से अधिक बैंक और 80 प्रतिशत बीमाकर्ता आईएएएस (एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा) के लिए सिर्फ दो क्लाउड प्रदाताओं पर भरोसा करते हैं।

- **चीन:** चीन में, वित्तीय होल्डिंग कंपनियां (एफएचसी) ढांचा सभी एफएचसी को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों के आधार पर एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता के द्वारा परिचालन सुदृढ़ता को मजबूत करता है जो परिचालन और आईटी जोखिमों सहित विभिन्न जोखिमों की निगरानी करेगा।

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** संयुक्त राज्य अमेरिका में, संघीय बैंकिंग एजेंसियों के पास बैंकों के लिए महत्वपूर्ण तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं के रूप में बिगटेक की निगरानी करने के लिए निरीक्षण शक्तियां हैं। बैंक सेवा कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित महत्वपूर्ण सेवा प्रदाता कार्यक्रम, बैंकों को सेवा प्रदाताओं के रूप में बड़ी तकनीक कंपनियों के परिचालन सुदृढ़ता की देखरेख करता है। इसके अलावा, तीसरे पक्ष के संबंधों से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन पर फेडरल रिज़र्व बोर्डों का अंतर-एजेंसी मार्गदर्शन तीसरे पक्ष के संबंधों के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों के लिए जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को रेखांकित करता है और इन संबंधों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रबंधन से संबंधित उपायों को निर्धारित करता है।

- **यूनाइटेड किंगडम:** बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जुलाई 2021) में क्लाउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) और अन्य महत्वपूर्ण तीसरे पक्षों की एक छोटी संख्या पर वित्तीय संस्थानों की बढ़ती निर्भरता से उत्पन्न जोखिमों से निपटने के लिए अतिरिक्त नियामकीय उपायों का आह्वान किया है।

हालांकि महत्वपूर्ण सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में बिगटेक के उद्देश्य से विशिष्ट नियम हैं, सामान्य दृष्टिकोण आउटसोर्सिंग गतिविधियों (आईटी / क्लाउड-आधारित सेवाओं) पर नियमों को मजबूत करना रहा है। वित्तीय संस्थान की जोखिम क्षमता के अनुरूप प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत में अभिशासन, जोखिम मूल्यांकन और समुचित सावधानी, व्यापार निरंतरता, डेटा गोपनीयता और डेटा स्थानीयकरण, विशेषज्ञता के प्रबंधन आदि पर केंद्रित एक अच्छी तरह से परिभाषित आउटसोर्सिंग नीति ढांचे को सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर एक प्रमुख विनियामकीय शर्त यह है कि संस्थाओं को आउटसोर्स की गई सेवाओं से निर्बाध 'पर्यवेक्षी/ लेखा परीक्षा / डेटा' पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। विनियमों में संस्थाओं को मेजबान देश के विनियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है ताकि विदेशी क्षेत्राधिकारों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था/सेवा प्रदाताओं के मामले में निर्बाध पर्यवेक्षी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

III.ई वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना – संभाव्य प्रणालीगत प्रभाव को सीमित करना

बिगटेक कंपनियां अपने निपटान में धन के जोखिम परिवर्तन, वित्तीय प्रणाली के साथ अपने मुद्रा बाजार निधि (एमएमएफ) व्यवसाय के लिंकेज और अन्य छाया बैंकिंग गतिविधियों के माध्यम से वित्तीय स्थिरता के लिए एक प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, चीन में, एक बिगटेक समूह की वित्तीय सहायक कंपनियों में जोखिम परिवर्तन दो तरीकों से हुआ।

- सबसे पहले, बिगटेक समूह की एक ई-वॉलेट प्रदाता सहायक कंपनी ने अपने ग्राहकों को अपने ई-वॉलेट में 'बचे हुए जमाशेष' को स्वचालित रूप से एमएमएफ में अंतरित करने की अनुमति दी, जिसे बिगटेक की एक अन्य धन प्रबंधन सहायक कंपनी द्वारा प्रबंधित किया गया था। इन एमएमएफ ने बदले में अंतर बैंक सीडी, वाणिज्यिक पत्र, पुनर्खरीद समझौतों आदि में निवेश किया और इसलिए, वित्तीय प्रणाली के साथ संबंध स्थापित किए। ई-वॉलेट ग्राहकों की अपने ई-वॉलेट खातों में पैसा मुद्रा बाजार निधि में निवेश करने की क्षमता, और अपने ई-वॉलेट ऐप के माध्यम से मुद्रा बाजार निधि से पैसे को निर्बाध रूप से भुनाने की क्षमता ने वित्तीय स्थिरता को खतरे में डालने की क्षमता के साथ धन के जोखिम परिवर्तन का निर्माण किया।

- बिगटेक फर्मों की वित्तीय-सेवा सहायक कंपनियों द्वारा जोखिम परिवर्तन के दूसरे मामले में चीनी बिगटेक प्लेटफॉर्मों से जुड़े उधारदाताओं द्वारा सूक्ष्म-ऋणों का प्रतिभूतिकरण और बिक्री शामिल थी। उन्नत विश्लेषण का उपयोग करके, इन बिगटेक प्लेटफॉर्मों की सहायक कंपनियों ने व्यक्तिगत ग्राहक जोखिम प्रोफाइल के लिए अनुकूलित सूक्ष्म-ऋण प्रदान किया और बाद में इन

ऋणों को प्रतिभूतित किया और पैकेज किया तथा उन्हें पारंपरिक बैंकों सहित निवेशकों को बेच दिया। बैंकों को सूक्ष्म-ऋण की उत्पत्ति, पैकेजिंग और बिक्री के माध्यम से, चीनी बिगटेक प्लेटफॉर्म, निधियों के जोखिम परिवर्तन में लिप्त थे, क्योंकि बैंकों ने बिगटेक फर्मों से पैकेज किए गए ऋण खरीदने के लिए जमाकर्ताओं के पैसे का इस्तेमाल किया था।

बिगटेक द्वारा अभिनव वित्तीय उत्पाद, बैंकिंग प्रणाली में जोखिमों के संचरण के लिए नए चैनलों के माध्यम से संकट के दौरान आघात प्रसारित करने और सुभेद्यता बढ़ाने की संभावना के साथ, उनके अंतर्संबंधों को बढ़ा सकते हैं। इसे स्वीकार करते हुए, केंद्रीय बैंक और सभी क्षेत्राधिकारों के नीति निर्माता बिगटेक वित्तीय गतिविधियों के संभावित प्रणालीगत प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए नियम प्रस्तुत कर रहे हैं। बिगटेक कंपनियों से वित्तीय स्थिरता जोखिमों का हल करने के लिए दो प्रमुख नियामक उपाय सामने आए हैं।

- पहला विकल्प किसी बड़ी तकनीक फर्म को डिजिटल-बैंकिंग लाइसेंस जारी करना है, जहां बिगटेक की होल्डिंग कंपनी वित्तीय नियामक के दायरे से बाहर है। यह विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली बिगटेक की विधिक रूप से अलग सहायक कंपनियों को समेकित करेगा। डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस का डिजाइन काफी हद तक विनियामक के लाइसेंसिंग उद्देश्यों पर निर्भर करता है। यह बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने (जैसे, आस्ट्रेलिया, चीन और यूके), फिनटेक और नवाचार को बढ़ावा देने और ग्राहक बैंकिंग अनुभव को बढ़ाने (जैसे, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और यूके) के उद्देश्यों से लेकर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को पूंजी और वित्तीय सेवाओं (जैसे, चीन) तक पहुंच प्रदान करने तक हो सकता है।[16]
- दूसरा विकल्प बिगटेक की वित्तीय-सेवा सहायक कंपनियों पर एक होल्डिंग कंपनी संरचना लागू करना है और उस होल्डिंग कंपनी को वित्तीय विनियमन के अधीन करना है। सहायक कंपनियों को होल्डिंग कंपनी संरचना में संरचित करके, अभिशासन संरचना को सरल बनाया जा सकता है, और इससे वित्तीय विनियामक, जोखिम का आकलन कर सकते हैं तथा विभिन्न समस्याओं को समग्र रूप से दूर कर सकते हैं। वर्तमान में चीन को ऐसी सहायक कंपनियों के लिए वित्तीय होल्डिंग कंपनी ढांचा तैयार करने के लिए गैर-वित्तीय समूहों / बिगटेक की आवश्यकता है, जिनके पास वित्तीय डोमेन में दो या दो से अधिक सहायक कंपनियां हैं।

IV. निष्कर्ष

बिगटेक वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और अपने साथ अधिक वित्तीय समावेशन, कुशल संचालन और कम लेनदेन लागत का लाभ ला रहे हैं। हालांकि, वे प्रतिस्पर्धा, परिचालन सुदृढ़ता संबंधी विषयों और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम भी पैदा करते हैं।

विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा, डेटा संरक्षण, व्यापार के संचालन, परिचालन सुदृढ़ता और वित्तीय स्थिरता के क्षेत्रों में बिगटेक द्वारा प्रस्तुत नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में कई विनियामकीय पहल की गई हैं। भारत में, महत्वपूर्ण भुगतान मध्यस्थों को औपचारिक विनियमित / पर्यवेक्षित ढांचे में लाने की दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं। भुगतान संग्राहक /भुगतान गेटवे के लिए जारी किए गए निर्देश और भुगतान प्रणाली संचालकों द्वारा भुगतान और निपटान से संबंधित गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लिए फ्रेमवर्क इसी दिशा में एक कदम है। भारत में भुगतान स्वीकृति के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भी पहल की जा रही है। भारत ने भुगतान डेटा के स्थानीय भंडारण को भी अनिवार्य कर दिया है और अपने स्वयं के डेटा संरक्षण विधि को कानून बनाने की प्रक्रिया में भी है।

[16] विस्तृत चर्चा के लिए कृपया डिजिटल बैंकिंग (नीति आयोग) पर चर्चा पत्र देखें।

वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में बिगटेक और फिनटेक की बढ़ती प्रमुख भूमिका को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) की आउटसोर्सिंग पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि आईटी गतिविधियों जैसे आईटी बुनियादी ढांचे, नेटवर्क सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लिकेशन सेवा प्रदाता, आदि[17] की आउटसोर्सिंग में संबंधित जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। विभिन्न देशों में हाल में किए गए पहल बिगटेक द्वारा उत्पन्न प्रासंगिक जोखिमों का निपटान करने में महत्वपूर्ण कदमों का प्रतिनिधित्व करती है।

मुख्य रूप से, नियामक इस बात की सराहना करते हैं कि बिगटेक गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों को अकेले इकाई-विशिष्ट या गतिविधि-विशिष्ट नियमों के माध्यम से पर्याप्त रूप से आँका / प्रबंधित नहीं किया जा सकता है। विनियमों/विनियामकीय ढांचे में उन जोखिमों की भी गणना की जानी चाहिए जो बिगटेक समूहों के भीतर ठोस अंतर्संबंधों और वित्तीय संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदाताओं के रूप में उनकी भूमिका के कारण उत्पन्न होते हैं। बिगटेक से जोखिमों से निपटने की दिशा में नियामकीय दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण आदर्श बदलाव, इकाई और गतिविधि-आधारित नियमों के मिश्रण के साथ नियामकीय ढांचे को अंशांकित करने में निहित है। वित्तीय गतिविधियों में शामिल होल्डिंग कंपनियों को बनाने की आवश्यकताएं, गतिविधि-विशिष्ट लाइसेंस, डेटा संरक्षण की आवश्यकताएं, सुरक्षा, तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों के साथ समान व्यवहार, डेटा पोर्टेबिलिटी आदि बिगटेक द्वारा उत्पन्न जोखिमों को सीमित करने के लिए अच्छी तरह से संकेत देते हैं। इसके अलावा, जैसे-जैसे वित्तीय क्षेत्र के साथ बिगटेक की अंतर-संबंध विकसित होती है, प्रतिस्पर्धा की रक्षा और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नियमों को डिजाइन / अद्यतन करने हेतु प्रतिस्पर्धा (एकाधिकारी व्यापार विरोधी), डेटा, अभिशासन और वित्तीय अधिकारियों के बीच घनिष्ठ सहयोग की अपेक्षा होती है।

इसके अलावा, चूंकि बिगटेक विभिन्न प्राधिकार क्षेत्रों में काम करते हैं, इसलिए नीतिगत विकास की अंतरराष्ट्रीय स्थिरता की तलाश करने के लिए पहले से ही एक सम्मोहक स्थिति है। उक्त के आलोक में, अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकायों द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए हैं कि मौजूदा वित्तीय विनियमन (विशेष रूप से भुगतान में) नए गैर-बैंक भागीदारों की गतिविधि को ठीक से शामिल करते हैं। हालांकि, इकाई और गतिविधि-आधारित दृष्टिकोण दोनों पर सटीक अंशांकन करने और देश-विशिष्ट स्थितियों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियामकों की चिंताओं को वित्तीय नवाचारों को दबाए बिना दूर किया जा सके।

उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की अब तक विनियामकीय प्रतिक्रियाएं भुगतान हेतु बुनियादी ढांचे और डिजिटल पहचान डेटा को विकसित करके सक्षम वातावरण बनाने के लिए रही हैं। ईएमडीई वित्तीय प्राधिकारियों ने नवाचार का समर्थन करने के लिए नीति निर्धारण हेतु समर्पित इकाइयों (जैसे, नवाचार हब, सैंडबॉक्स आदि) को विकसित किया है। इसके साथ ही, ईएमडीई में नियमों को मौजूदा वित्तीय संस्थानों के साथ बिगटेक द्वारा बनाए जा सकने वाले नए अंतर-संबंधों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।

[17] भारतीय रिज़र्व बैंक: आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश का मसौदा, दिनांक 23 जून, 2022 (https://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=4156)

References

Bank for International Settlements (2019), "Bigtech in Finance: Opportunities and Risks", *Annual Economic Report*, Chapter III, June. *https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e3.htm*

Bank for International Settlements (2021), "Regulating Bigtechs in Finance", August, *BIS bulletin* No. 45. *https://www.bis.org/publ/bisbull45.pdf*

Carstens, A. (2018): "Bigtech in Finance and New Challenges for Public Policy", Keynote address at the FT Banking Summit, December. *https://www.bis.org/speeches/sp181205.htm*

Croxson, K., J. Frost, L. Gambacorta and T. Valletti (2021), "Platform-based Business Models and Financial

Inclusion". *https://www.dcfintechweek.org/wp-content/uploads/2021/10/Jon-Frost-Karen_Croxson-et-al-Platform-based-business-models-and-financial-inclusion-Oct-2021.pdf*

Financial Stability Board (2019), "Bigtech in Finance: Market Developments and Potential Financial Stability Implications", December. *https://www.fsb.org/2019/12/bigtech-in-finance-market-developments-and-potential-financial-stability-implications/*

Financial Stability Board (2020), "Bigtech Firms in Finance in Emerging Market and Developing Economies - Market Developments and Potential Financial Stability Implications", October. *https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P121020-1.pdf*

Financial Stability Report (2021), Bank of England, July. *https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability-report/2021/july-2021*

FSI (2020), "Policy Responses to Fintech: A Cross-Country Overview", January, *FSI Insights on policy implementation* no. 23. *https://www.bis.org/fsi/publ/insights23.pdf*

FSI (2021a), "Bigtech Regulation: What Is Going On?", September 2021, *FSI Insights on policy implementation* no. 36. *https://www.bis.org/fsi/publ/insights36.htm*

FSI (2021b), "Bigtechs in Finance: Regulatory Approaches and Policy Options", March, *FSI Briefs* No. 12. *https://www.bis.org/fsi/fsibriefs12.htm*

Moenjak and Santiprabhob (2021), "Regulating Bigtech And Non-Bank Financial Services in the Digital Era", 12thApril, *Central Banking*. *https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/7820121/regulating-big-tech-and-non-bank-financial-services-in-the-digital-era*

NITI Aayog (2021), "Digital Bank: A Proposal for Licensing and Regulatory Regime for India", November. *https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-11/Digital-Bank-A-Proposal-for-Licensing-and-Regulatory-Regime-for-India.24.11_0.pdf*

Reserve Bank of India (2017), "Report of the Working Group on Fintech and Digital Banking". *https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/WGFR68AA1890D7334D8F8F72CC2399A27F4A.PDF*

*डेट म्यूचुअल फंड में बाज़ार प्रतिलाभ और प्रवाह**

डॉ. मयंक गुप्ता^, सत्यम कुमार^, सुब्रत कुमार सीत ^ और अभिनंदन बोराड ^ द्वारा

भारत में कर्ज़-उन्मुख म्यूचुअल फंड (एमएफ) का पैमाना पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। यह अध्ययन डेट म्यूचुअल फंडों में प्रवाह के वाहकों की जांच करता है। यह डेट एमएफ में निवल प्रवाह और डेट एमएफ पर प्रतिलाभ के बीच संबंध की जांच करता है। हम सीआरआईएसआईएल मानदंड सूचकांक का उपयोग करके एक सूचकांक बनाकर डेट एमएफ़ प्रतिलाभ को प्रतिरूपित करते हैं। इसके अलावा, डेट म्यूचुअल फंडों पर प्रवाह और प्रतिलाभ के बीच संबंध का विश्लेषण बाजार के विभिन्न बुनियादी सिद्धांतों की उपस्थिति में किया जाता है। अध्ययन में पाया गया है कि प्रतिलाभ प्रवाह का कारण बनता है लेकिन इसके विपरीत नहीं।

भूमिका

भारत में ऋण प्रतिभूतियों की मात्रा में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इस बाजार-आधारित वित्तीय मध्यस्थता प्रणाली के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्ज़-उन्मुख एमएफ द्वारा समर्थित है, जो ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। ये कर्ज़-उन्मुख एमएफ सरकार और कॉर्पोरेट की लघु-अवधि और लंबी-अवधि की प्रतिभूतियों की सदस्यता लेते हैं, जैसे, टी-बिल, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य विकास ऋण (एसडीएल), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी)। और कॉर्पोरेट बॉन्ड। इसके अलावा, वे त्रि-पक्षीय रिपो (टीआरईपीएस) और बाजार रिपो वाले भाग में भी सक्रिय भागीदार हैं, मुख्य रूप से ऋण देने वाले पक्ष में।

हालांकि अतीत में इक्विटी म्यूचुअल फंड से प्रतिलाभ आम तौर पर अधिक रहा है, डेट म्यूचुअल फंड ने खुद के लिए एक जगह बनाई है क्योंकि कुछ निवेशक शेयर बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता से बचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा, एक स्थिर और नियमित आय निवेशकों को डेट एमएफ को तरजीह देने के लिए प्रेरित करती है। हालाँकि, ऋण जोखिम या चूक का जोखिम मौजूद है क्योंकि जारीकर्ता ब्याज या मूल भुगतान पर चूक कर सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, अध्ययन ने डेट एमएफ के लिए निवल प्रवाह और डेट एमएफ पर प्रतिलाभ के बीच संबंध को समझने का प्रयास किया है, क्या भारत में प्रवाह प्रतिलाभ को प्रभावित करता है और/या प्रतिलाभ प्रवाह को प्रभावित करता है। डेट म्यूचुअल फंडों पर समग्र प्रतिलाभ आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए, यह क्रिसिल मानदंड सूचकांकों पर मासिक डेटा का उपयोग करके एक सूचकांक का निर्माण करके प्राप्त किया जाता है, जिसके आधार पर डेट म्यूचुअल फंड योजनाओं के प्रदर्शन का पता किया जाता है। इसके अलावा, अध्ययन ऋण स्प्रेड, आउटपुट/अर्थव्यवस्था की स्थिति, प्रतिस्पर्धी बचत लिखत पर प्रतिलाभ की दर, चलनिधि और मुद्रास्फीति दर पर जानकारी शामिल करके बाजार के मूल सिद्धांतों की उपस्थिति में इस संबंध का अनुमान लगाता है।

शेष आलेख निम्नानुसार व्यवस्थित है। खंड II डेट एमएफ पर शैलीबद्ध तथ्यों की चर्चा करता है। खंड III डेट एमएफ में प्रवाह के निर्धारकों पर चर्चा करता है। खंड IV निवल प्रवाह और डेट एमएफ पर प्रतिलाभ के बीच संबंधों के विश्लेषण को कवर करता है। अंत में, खंड V समापन टिप्पणियों की रिपोर्ट करता है।

II. शैलीबद्ध तथ्य

ऋण प्रतिभूतियों और डेट म्यूचुअल फंड उद्योगों का उदय

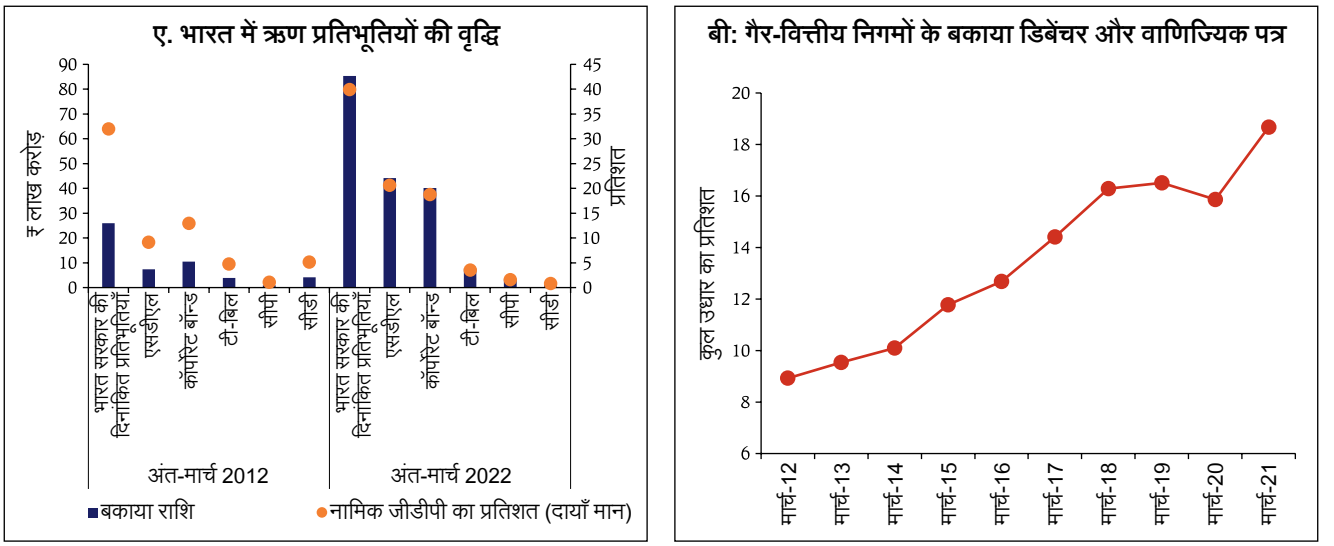
पिछले दशकों ने ऋण प्रतिभूतियों में काफी वृद्धि देखी है (चार्ट 1ए)। कॉर्पोरेट के ऋण वित्तपोषण में ऋण प्रतिभूतियों का हिस्सा भी काफी बढ़ गया है (चार्ट 1बी)। विविध वित्तपोषण तंत्र होने के कई फायदे हैं, जैसे जोखिमों का कुशल वितरण और वित्तपोषण के एकल स्रोत पर कम निर्भरता।

ऋण प्रतिभूतियों की बढ़ती मात्रा और डेट म्यूचुअल फंडों में बचत के बढ़ते अभिनियोजन के दोहरे विकास आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि वे एक-दूसरे की वृद्धि को सुदृढ़ करते हैं। वर्षों से, डेट

^ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं।

* लेखक श्री संजय हांसदा के प्रोत्साहन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेखक कौस्तव सरकार, चैताली भौमिक, अमित पवार और आंतरिक विचार कर्ता को उनकी व्यावहारिक टिप्पणियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। क्रिसिल से डेटा समर्थन की भी विधिवत सराहना की जाती है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

चार्ट 1: ऋण प्रतिभूतियों में वृद्धि



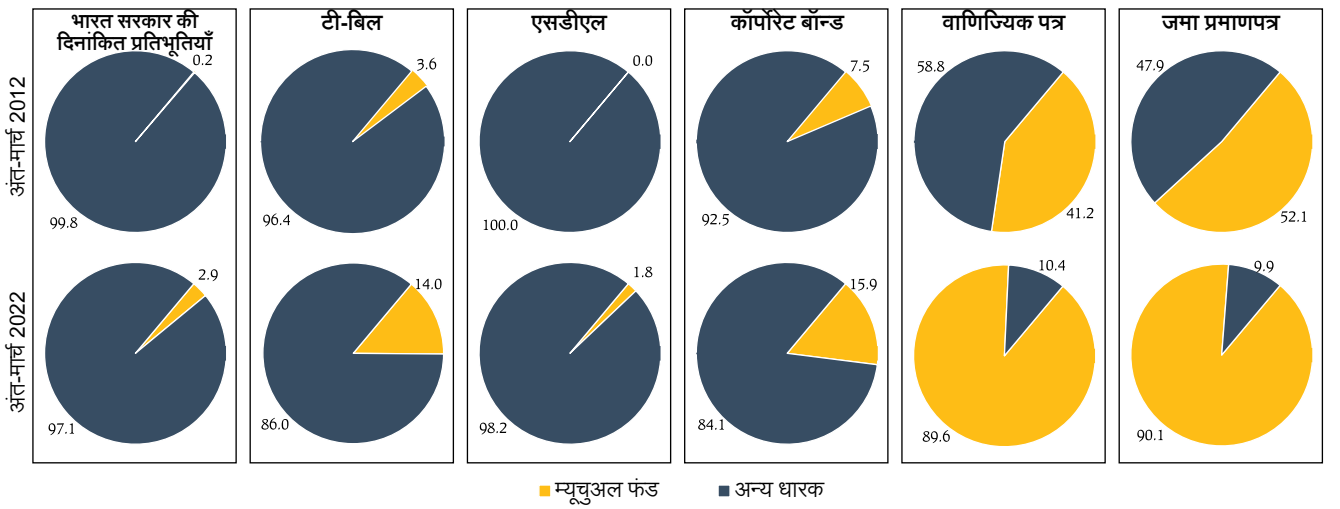
स्रोत: आरबीआई; सेबी; सीएमआईई प्रोवेस्स; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

एमएफ सरकार और कॉर्पोरेट की ऋण प्रतिभूतियों के वित्तपोषण की एक बड़ी राशि का मध्यस्थता कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान दे रहे हैं (चार्ट 2)।

डेट म्यूचुअल फंड का पैमाना और दायरा

डेट म्यूचुअल फंडों के प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) सितंबर 2022 के अंत में ₹12.6 लाख करोड़ थीं, जो मार्च 2012 के अंत में ₹3.7 लाख करोड़ से बढ़कर, 12.2 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज कर रही हैं (चार्ट 3)। हालांकि, समग्र म्यूचुअल फंड उद्योग में डेट म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित आस्तियों का हिस्सा इस अवधि के दौरान 63.8 प्रतिशत से घटकर 32.8 प्रतिशत हो गया साथ ही म्यूचुअल फंड की अन्य श्रेणियों, जैसे इक्विटी, संतुलित और अन्य योजनाओं में वृद्धि हुई।

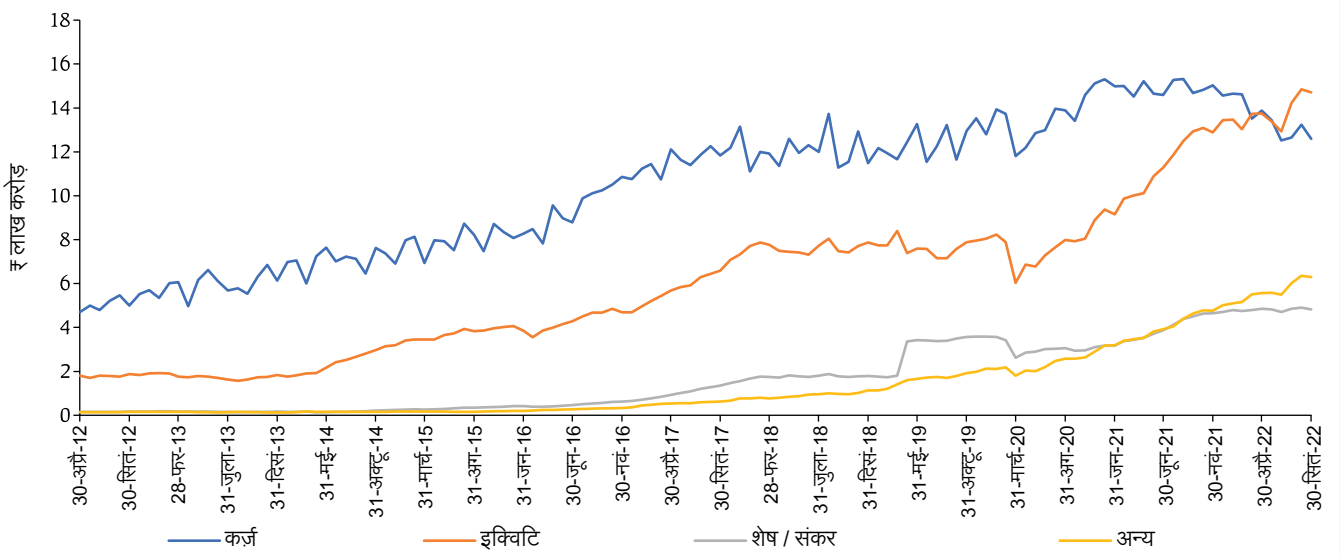
चार्ट 2: बकाया ऋण प्रतिभूतियों में म्यूचुअल फंड का हिस्सा



टिप्पणी: (1) एमएफ के शेयर की गणना कुछ मामलों में एक अनुमानित आंकड़ा दर्शाती है।
(2) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

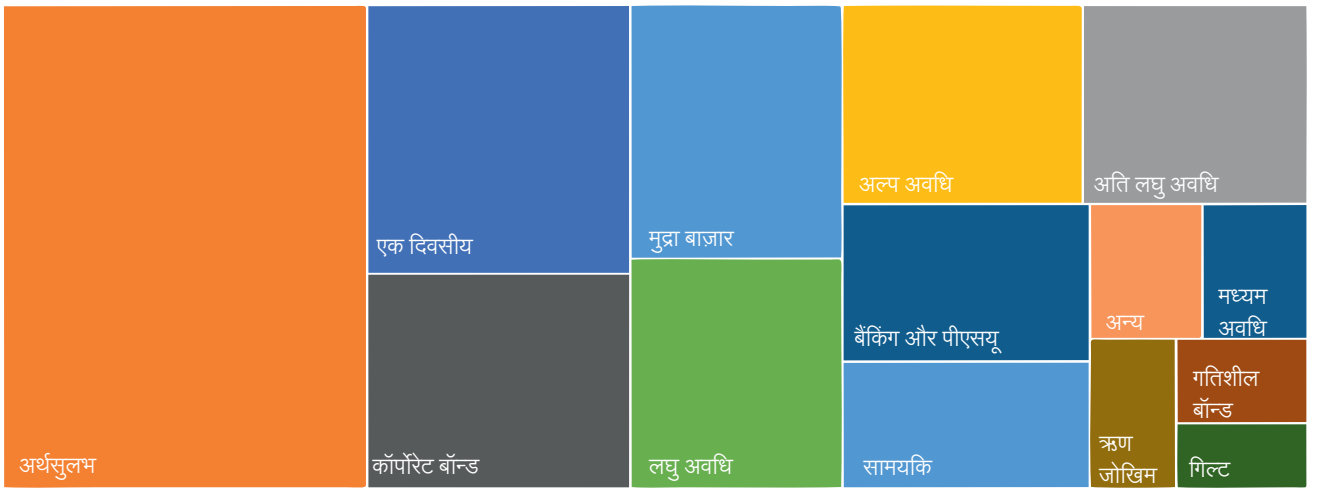
चार्ट 3: म्यूचुअल फंड का एयूएम



स्रोत: एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई)।

असीमित अवधि वाली ऋण योजनाएं[1], यानी निरंतर आधार पर निवेशकों द्वारा अभिदान और पुनर्खरीद के लिए उपलब्ध योजनाएं, सितंबर 2022 के अंत में डेट एमएफ के पास रखे गए एयूएम का 98.5 प्रतिशत हिस्सा हैं। असीमित अवधि वाली ऋण योजनाओं की श्रेणी में, अर्थसुलभ निधि , यानी, 91 दिनों तक की परिपक्वता वाली कर्ज़/मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों में निवेश के साथ निधियों की अधिकतम हिस्सेदारी 28.4 प्रतिशत है (चार्ट 4 और अनुबंध 1)।

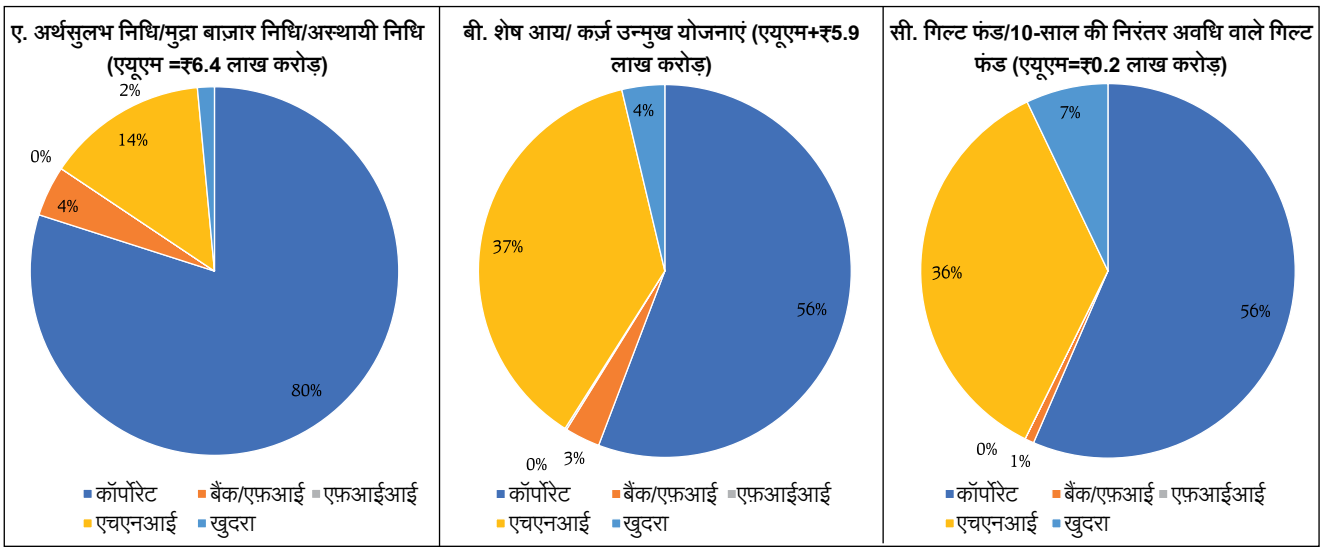
चार्ट 4: सितंबर 2022 के अंत में डेट म्यूचुअल फंड का योजना-वार एयूएम



टिप्पणी: अन्य में दीर्घावधि की निधियां, मध्यम अवधि से दीर्घावधि की निधियां , निश्चित अवधि की योजनाएं, पूंजी संरक्षण-उन्मुख योजनाएं, अवसंरचना कर्ज़ निधि और अन्य डेट फंड योजनाएं शामिल हैं। गिल्ट में 10 साल की निरंतर अवधि वाले गिल्ट फंड और गिल्ट फंड शामिल हैं।
स्रोत: एएमएफआई।

[1] इन योजनाओं की कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं होती है। निवेशक निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर इकाइयों को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, जिसे दैनिक रूप से घोषित किया जाता है। ओपन-एंड योजनाओं की प्रमुख विशेषता चलनिधि है।

चार्ट 5: जून 2022 के अंत में निवेशक-वार डेट म्युचुअल फंड का विभाजन

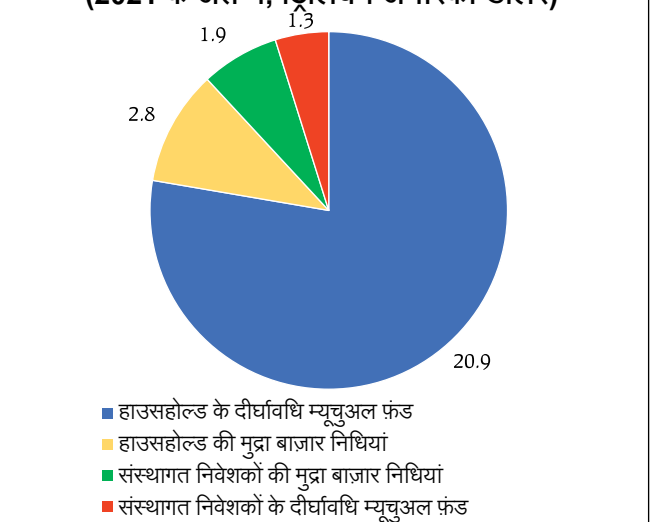


स्रोत: एएमएफ़आई।

जून 2022 के अंत में, कॉर्पोरेट्स निवेशकों का सबसे बड़ा वर्ग बना रहा, जिन्होंने ₹12.5 लाख करोड़ के डेट म्यूचुअल फंडों के एयूएम में ₹8.5 लाख करोड़ का योगदान दिया, जो आमतौर पर छोटी अवधि के निधियों में निवेश करते हैं। उच्च मालियत वाले व्यक्ति (एचएनआई) निवेशकों का दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है, जो एयूएम के ₹3.2 लाख करोड़ के लिए जिम्मेदार है और अपेक्षाकृत लंबी अवधि के फंड के पक्ष में है क्योंकि उनके निवेश के उद्देश्य कॉर्पोरेट्स से अलग होने की संभावना है (चार्ट 5)।

भारतीय परिदृश्य के विपरीत, खुदरा निवेशकों के पास अमेरिका में पर्याप्त मुद्रा बाज़ार निधि आस्तियों सहित अधिकांश एमएफ आस्तियां (लगभग 88 प्रतिशत) हैं (चार्ट 6)। संस्थागत निवेशक ज्यादातर मुद्रा बाज़ार निधियों[2] में एमएफ आस्तियों (लगभग 12 प्रतिशत) का अपेक्षाकृत कम हिस्सा रखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि अधिक विकसित पूंजी बाजार वाले देशों में अधिक विकसित निधि उद्योग[3] होते हैं। हालांकि, जिन देशों में बैंकों ने ऐतिहासिक रूप से वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र (जैसे, जापान) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहां हाउसहोल्ड विनियमित निधियों की तुलना में बैंकिंग उत्पादों को पसंद करते हैं। 2021 में, म्यूचुअल फंड स्वामित्व के वार्षिक निवेश कंपनी संस्थान (आईसीआई) सर्वेक्षण में पाया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 59.0 मिलियन, या 45.4 प्रतिशत हाउसहोल्ड के पास एमएफ़[4] है। जबकि इक्विटी आस्तियां एमएफ आस्तियों का प्रमुख हिस्सा हैं, अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती उम्र वाली आबादी के कारण डेट एमएफ में प्रवाह में वृद्धि देखी जा रही है।

चार्ट 6: अमेरिका में म्यूचुअल फंड निवल आस्तियां (2021 के अंत में, ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर)



टिप्पणी: दीर्घावधि म्युचुअल फंड में इक्विटी, बॉन्ड और संकर निधियां शामिल हैं।
स्रोत: निवेश कंपनी संस्थान।

[2] https://www.icifactbook.org/pdf/2022_factbook.pdf

[3] https://www.ici.org/system/files/2021-05/2021_factbook.pdf

[4] https://www.ici.org/system/files/2021-10/per27-12.pdf

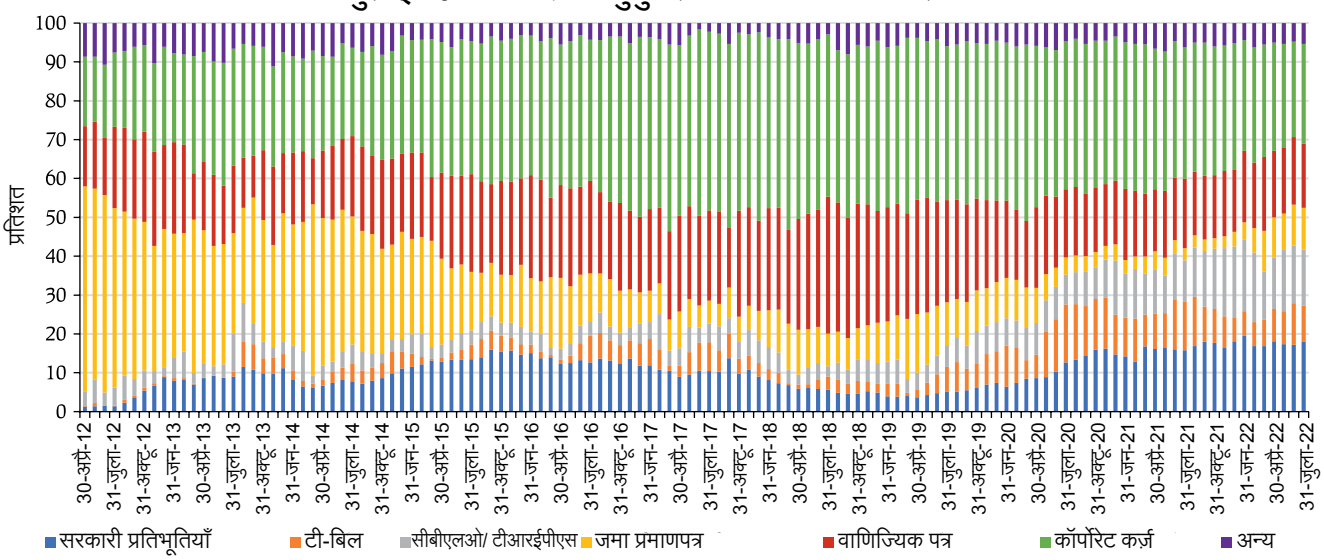
म्यूचुअल फ़ंड के ऋणपोर्टफोलियो

भारत में म्यूचुअल फंडों के कुल ऋणपोर्टफोलियो (कर्ज़, संतुलित निधि आदि सहित) में पिछले कुछ वर्षों में संरचनात्मक परिवर्तन देखा गया है; सीडी ऋणपोर्टफोलियो का अधिकतम हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन तब से अन्य ऋणलिखतों में अपना हिस्सा खो दिया है। वर्तमान में, म्यूचुअल फंड अपने अधिकांश ऋणपोर्टफोलियो को कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखते हैं, जो कॉर्पोरेट्स की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं (चार्ट 7)। म्यूचुअल फंडों के पोर्टफोलियो में सीपी का भी बड़ा हिस्सा है। हालांकि, हाल की अवधि में, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएफ़एस) प्रकरण[5] और कोविड-19 महामारी के जोखिम के बीच, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सीपी के लिए संयुक्त आवंटन जुलाई 2018 के अंत में 77 प्रतिशत के शिखर से जुलाई 2022 के अंत में 42.2 प्रतिशत पर आ गया है। । इसके अलावा, ऋण जोखिम निधियां, यानी एए और कम रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में कुल आस्तियों के न्यूनतम 65 प्रतिशत वाले फंड ने निवेशकों के बीच ज्यादा दिलचस्पी पैदा नहीं की है और अप्रैल 2019 से एयूएम में लगातार गिरावट देखी जा रही है।

इस बीच, म्यूचुअल फंडों ने सरकारी प्रतिभूतियों, टी-बिलों और टीआरईपीएस[6] में अपने निवेश में काफी वृद्धि की है। म्यूचुअल फंड के ऋण पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों (टी-बिल सहित) का अनुपात हाल की अवधि में बढ़ा है, जो जुलाई 2022 के अंत में 27.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

कुछ हद तक टीआरईपीएस में निवेश में वृद्धि को एकदिवसीय फंड की बढ़ती लोकप्रियता से समझाया जा सकता है, यानी ऐसे फंड्स जो एक दिन की परिपक्वता वाली एकदिवसीय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं - जैसा कि टीआरईपीएस और एकदिवसीय फंड के एयूएम में एमएफ़ के निवेश में सह-गति से संकेत मिलता है (चार्ट 8)। अर्थसुलभ निधियों से एकदिवसीय निधियों की वरीयता में एक उल्लेखनीय बदलाव के बीच, एकदिवसीय फंड्स का एयूएम अप्रैल 2019 और जुलाई 2022 के बीच लगभग दस गुना बढ़ गया है। यह बदलाव मुख्य रूप से सेबी द्वारा उन निवेशकों पर वर्गीकृत निकास भार[7] लागू करने का परिणाम है, जो अपने

चार्ट 7: जुलाई 2022 के अंत में म्युचुअल फंड का डेट पोर्टफोलियो आबंटन



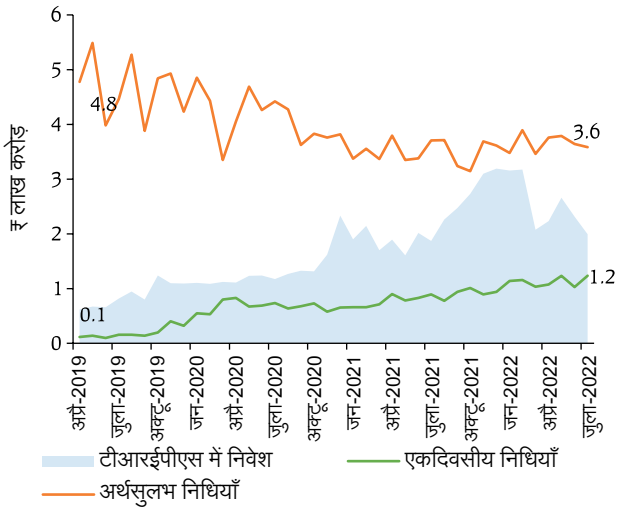
टिप्पणी: उपर्युक्त चार्ट में सरकारी प्रतिभूतियों में टी-बिल शामिल नहीं हैं।
स्रोत: सेबी।

[5] 2018 के दौरान, आईएल एंड एफएस, एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली मुख्य निवेश कंपनी (सीआईसी-एनडी-एसआई) ने सीपी, अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) और बैंक ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की, जिसके परिणामस्वरूप आईएल एंड एफएस और कुछ अन्य एनबीएफसी की रेटिंग में गिरावट आई।

[6] पूर्ववर्ती संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व (सीबीएलओ)।

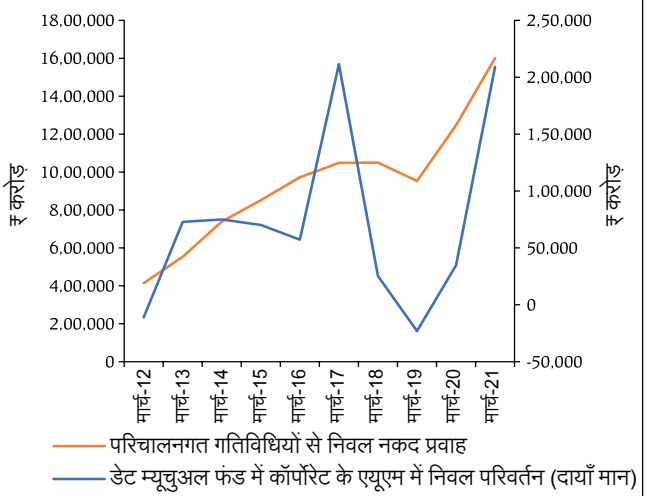
[7] क्रमिक निकास प्रभार का अर्थ है अभिदान की तारीख और मोचन की तारीख के बीच समय अंतराल के आधार पर निकास प्रभार की प्रयोज्यता, यानी, यदि कोई निवेशक अभिदान के छठे दिन बाहर निकलने वाले निवेशक की तुलना में सदस्यता के एक दिन के भीतर एमएफ से बाहर निकलता है तो उच्च निकास भार लागू होता है।

चार्ट 8: अर्थसुलभ निधियों की तुलना एक दिवसीय एयूएम; और टीआरईपीएस में म्युचुअल फंड का निवेश



स्रोत: सेबी; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

चार्ट 9: गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट के नकद प्रवाह और डेट म्यूचुअल फंड में प्रवाह के बीच संबंध



स्रोत: एएमएफआई; सीएमआईई प्रोवेस्स; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

निवेश[8] के सात दिनों के भीतर अर्थसुलभ निधि से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा, म्यूचुअल फंडों को एकदिवसीय योजनाओं में तत्काल पहुंच की सुविधा[9] प्रदान करने की अनुमति देने की सेबी की पहल ने एकदिवसीय फंड्स[10] का आकर्षण बढ़ा दिया है।

III. डेट फंड प्रवाह के निर्धारक: कुछ चर्चा

गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट्स द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह ने हाल की अवधि में डेट एमएफ में कॉर्पोरेट्स के एयूएम में निवल परिवर्तन को अच्छी तरह से ट्रैक किया है (चार्ट 9)। मजबूत परिचालन प्रदर्शन उच्च नकदी प्रवाह में तब्दील हो जाता है और म्यूचुअल फंड सहित वित्तीय लिखतों में कॉर्पोरेट्स द्वारा उच्च बचत और निवेश में तब्दील होने की उम्मीद की जा सकती है।

एकदिवसीय फंड्स के मामले को छोड़कर, अल्पकालिक डेट म्यूचुअल फंड योजनाओं में निधियों का प्रवाह आपस में एक उच्च सकारात्मक सहसंबंध प्रदर्शित करता है (चार्ट 10.ए)। डेट म्यूचुअल फंड और निगम कर भुगतान के मासिक निवल प्रवाह के बीच एक उच्च नकारात्मक सहसंबंध मौजूद है (आर = -0.67)। इसके अलावा, डेट एमएफ में प्रवाह में कुछ मौसमी स्वरूप रहा है। तिमाही के अंत के दौरान, कॉर्पोरेट कर भुगतान में वृद्धि के साथ, डेट म्यूचुअल फंडों में प्रवाह कॉर्पोरेट द्वारा मोचन के कारण कम या नकारात्मक हो जाता है (चार्ट 10बी)।

डेट एमएफ पर कोविड-19 का प्रभाव मार्च 2020 में और बढ़ गया था क्योंकि यह कर फाइलिंग महीने के साथ मेल खाता था। कोविड -19 के दौरान बढ़ी हुई अस्थिरता ने मोचन दबाव और चलनिधि दबाव को जन्म दिया, जो सतही कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों द्वारा बढ़ा दिया गया था। इसने कुछ डेट एमएफ योजनाओं को भी बंद कर दिया, जिसने घरेलू वित्तीय बाजारों में चिंताओं को बढ़ा दिया और अन्य डेट एमएफ द्वारा इसी तरह की समाप्ति की आशंका पैदा की। इसके बाद, चलनिधि के दबाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एमएफ (एसएलएफ-एमएफ) के लिए ₹50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा के साथ सामने आया, जिससे वित्तीय बाजारों में विश्वास बहाल करने में मदद मिली।

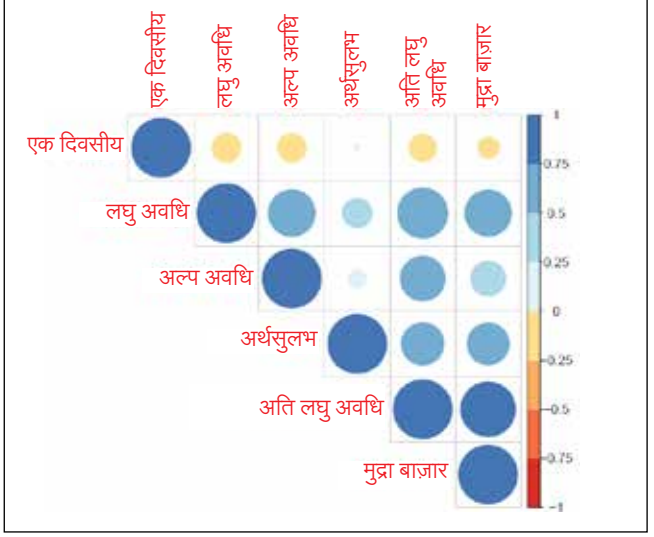
2021-22 की दूसरी छमाही और 2022-23 की पहली छमाही की हाल की अवधि में, बॉन्ड प्रतिफल में मजबूत होने के

[8] 20 सितंबर, 2019 को दिनांकित 'चलनिधि और एकदिवसीय फंड्स के लिए जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और अल्पावधि जमा में निवेश को नियंत्रित करने वाले मानदंड' पर सेबी का परिपत्र।

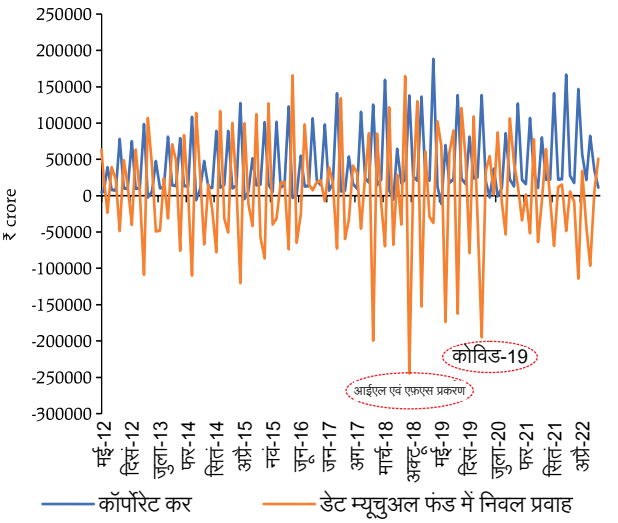
[9] त्वरित पहुँच सुविधा एक विकल्प है जो निवेशकों को मोचन अनुरोध देने के थोड़े समय के भीतर अपनी निधि तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है।

[10] 30 जुलाई, 2021 को दिनांकित 'अदावी मोचन और लाभांश राशि का अभिनियोजन और एकदिवसीय फंड में त्वरित पहुंच सुविधा' पर सेबी का परिपत्र।

चार्ट 10.ए: अल्पावधि उन्मुख डेट म्युचुअल फंड योजनाओं में प्रवाह के बीच परस्पर-सहसंबंध



चार्ट 10.बी: कॉर्पोरेट कर भुगतान और डेट म्यूचुअल फंड में निवल प्रवाह के बीच सहसंबंध



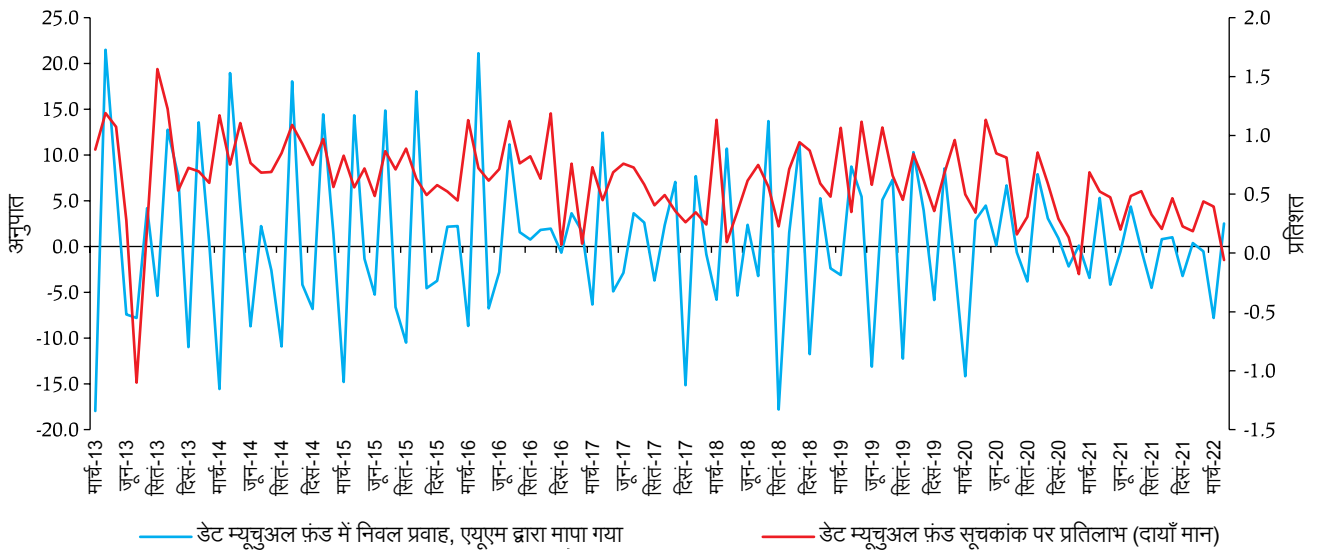
टिप्पणी: चार्ट 14.ए में वृत्त का आकार सहसंबंध की डिग्री को दर्शाता है, जबकि रंग सहसंबंध के संकेत को दर्शाता है।
स्रोत: एएमएफआई; महालेखा नियंत्रक; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

बीच कीमत जोखिम से बचने के लिए निवेशकों के दूर रहने के कारण डेट एमएफ़ में निवल मोचन देखा गया।

IV. डेट म्यूचुअल फंड्स पर निवल प्रवाह और प्रतिलाभ के बीच संबंध

हाल के वर्षों में, वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में डेट म्यूचुअल फंडों की प्रमुखता बढ़ती जा रही है। तदनुसार, ऐसे गैर-बैंकिंग मध्यस्थों से उत्पन्न होने वाली वित्तीय प्रणाली में किसी जोखिम के प्रभाव-विस्तार की संभावना बढ़ गई है। इसलिए, डेट म्यूचुअल फंड में निवेशकों के व्यवहार स्वरूप और प्रवाह और प्रतिलाभ के बीच संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है (चार्ट 11)। इसका उद्देश्य यह समझना है कि क्या बॉन्ड की कीमतों में तेज गिरावट (या डेट एमएफ पर कम प्रतिलाभ) म्यूचुअल फंड

चार्ट 11: डेट एमएफ प्रवाह और प्रतिलाभ के बीच संबंध



स्रोत: एएमएफआई; क्रिसिल; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

निवेशकों द्वारा मोचनों को बढ़ा सकती है और/या क्या तीव्र मोचन का कोई प्रकरण बॉन्ड की कीमतों पर महत्वपूर्ण गिरावट का दबाव डाल सकता है (और डेट एमएफ के निवल आस्ति मूल्य को कम कर सकता है)।

जैसे-जैसे डेट म्यूचुअल फंड उद्योग और गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता तेजी से बढ़ती है, निधियों के प्रवाह और प्रतिलाभ के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। यद्यपि इक्विटी म्यूचुअल फंडों के लिए प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है, डेट म्यूचुअल फंडों के प्रवाह के निर्धारकों पर साहित्य भारतीय संदर्भ में सीमित है।

फॉर्च्यून (1998) का सुझाव है कि यूएस (1985-1996) में, ऋण-प्रकार के फंडों में निवल मुद्रा प्रवाह ऋण प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ का पूर्वसूचक होता है, जबकि इक्विटी फंड प्रवाह इक्विटी या बॉन्ड पर प्रतिलाभ की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि सुरक्षा प्रतिलाभ का फंड प्रवाह पर समकालीन और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

यूएस के संदर्भ में एक अन्य अध्ययन 1992-2005 की अवधि के डेटा का उपयोग करता है और इसमें देखा गया कि बॉन्ड फंड निवेशक उन फंडों की तरफ जाते हैं जो कच्चे प्रतिलाभ के बजाय जोखिम-समायोजित आधार पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं (झाओ, 2005)। लेखक ने देखा कि कमजोर लंबी-अवधि के इक्विटी बाज़ार प्रतिलाभ सरकारी प्रतिभूति फंडों में निवेशकों के निवेश में वृद्धि करते हैं इसमें देखा गया कि ज्यादातर बॉन्ड फंड निवेशक खर्च के प्रति संवेदनशील हैं; वे उच्च परिचालन व्यय वाले फंड से बचते हैं।

भारतीय संदर्भ में, एक अध्ययन ऋण और इक्विटी फंड प्रवाह दोनों में मौसमी कारकों की उपस्थिति की पहचान करता है (मधुमती एवं अन्य, 2012)। इसमें देखा गया कि जुलाई 2005 से अगस्त 2012 की अवधि के दौरान बाजार की मात्रा और अस्थिरता डेट म्यूचुअल फंड प्रवाह को प्रभावित करती है।

इसके मद्देनजर, डेट म्यूचुअल फंडों पर निवल प्रवाह और प्रतिलाभ के बीच संबंध को समझने के लिए एक अनुभवजन्य अभ्यास किया गया है, यानी, क्या प्रवाह भारत में प्रतिलाभ को और/या प्रतिलाभ प्रवाह को प्रभावित करता है। इसके अलावा, खंड के दूसरे भाग में, हम विभिन्न बाजार के मूल सिद्धांतों की उपस्थिति में इन गतिकी का पता लगाते हैं, जो बहिर्जात चर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, भारत में अब तक इसी तरह के विषय पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

डेटा और कार्यप्रणाली

मार्च 2013 से मार्च 2022 की अवधि के लिए भारतीय पारस्परिक निधि संघ (एएमएफआई) से निवल प्रवाह पर मासिक डेटा प्राप्त किया जाता है। प्रवाह में बढ़ती प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए पिछले महीने के निवल एयूएम द्वारा निवल प्रवाह को सामान्यीकृत किया जाता है (रेमोलोना एवं अन्य, 1997)। इसके अलावा, मौसमी विविधताओं को नियंत्रित करने के लिए निवल सामान्यीकृत प्रवाहों को अ-मौसमीकृत किया गया है।

डेट म्यूचुअल फंड पर प्रतिलाभ के लिए एक प्रॉक्सी पर पहुंचने के लिए, हम क्रिसिल मानदंड सूचकांक पर मासिक डेटा का उपयोग करके एक भारित औसत सूचकांक बनाते हैं, जिससे समान प्रकार की डेट म्यूचुअल फंड योजनाओं के प्रदर्शन का पता लगाया जाता है। ऐसा करते समय, निहित धारणा यह है कि डेट म्यूचुअल फंड पर वास्तविक प्रतिलाभ उनके संबंधित क्रिसिल मानदंड सूचकांक पर प्रतिलाभ का पता करेगा। इस अभ्यास के लिए, हम 15 अलग-अलग क्रिसिल मानदंड सूचकांक का उपयोग करते हैं, जैसे, क्रिसिल एकदिवसीय सूचकांक, अर्थसुलभ निधि सूचकांक, अति-अल्पकालिक डेट सूचकांक, अल्प अवधि सूचकांक, मुद्रा बाज़ार सूचकांक, अल्पावधि बॉन्ड फंड सूचकांक, मध्यम-अवधि डेट सूचकांक , मध्यम से दीर्घावधि डेट सूचकांक, दीर्घावधि डेट सूचकांक, संयुक्त बॉन्ड सूचकांक, कॉर्पोरेट बॉन्ड संयुक्त सूचकांक, अल्प अवधि क्रेडिट जोखिम सूचकांक, बैंकिंग और पीएसयू डेट सूचकांक, गतिशील गिल्ट सूचकांक और 10-वर्षीय गिल्ट सूचकांक[11]। ये सूचकांक, जो 15 प्रकार के ओपन-एंडेड डेट म्यूचुअल फंड[12] के लिए मानदंड के रूप में उपयोग किए जाते हैं, इसका कुल अप्रैल 2019-मार्च 2022[13] के दौरान ऐसे म्यूचुअल फंड के तहत धारित प्रबंधन के तहत औसत आस्तियों के भार का उपयोग करके किया जाता है। क्रिसिल अर्थसुलभ

[11] ये सूचकांक मुद्रा बाजार और ऋण प्रतिभूतियों वाले अंतर्निहित पोर्टफोलियो के कूपन और कीमत प्रतिलाभ का पता लगाना चाहते हैं।

[12] ये डेट म्युचुअल फंड के तहत धारित कुल एयूएम का लगभग 90 प्रतिशत हैं।

[13] म्यूचुअल फंड योजनाओं की नई श्रेणियों पर एएमएफआई का डेटा केवल अप्रैल 2019 से उपलब्ध है, जबकि ऐसी योजनाओं के लिए क्रिसिल के मानदंड सूचकांक डेटा पूर्व अवधि के लिए भी उपलब्ध हैं।

सारणी 1: सारांश सांख्यिकी

चर	एन	माध्य	माध्यिका	एसडी	सहसंबंध गुणांक	एडीएफ टेस्ट
प्रवाह	109	0.66	0.74	5.36	0.33***	-6.06***
प्रतिलाभ	109	0.62	0.62	0.35		-4.62***

टिप्पणी: *पी<0.1; **पी<0.05; ***पी<0.01.
स्रोत: आरबीआई स्टाफ की गणना।

निधि सूचकांक का समग्र सूचकांक में लगभग 33 प्रतिशत का उच्चतम भार है।

सारांश आंकड़े बताते हैं कि प्रतिलाभ की तुलना में मासिक प्रवाह की अस्थिरता अधिक होती है। सहसंबंध गुणांक सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है जो सुझाव देता है कि प्रवाह और प्रतिलाभ एक साथ चलते हैं। स्थिरता के परिणाम सारणी 1 में दिखाए गए हैं। दोनों श्रृंखलाएं स्थिर हैं।

प्रवाह और प्रतिलाभ के बीच अंतर-अस्थायी संबंध का आकलन करने के लिए, एक घटाया हुआ द्विभाजित वीएआर मॉडल[14] तैनात किया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

$$\boldsymbol{y_t = A_0 + A_1 y_{t-1} + A_2 y_{t-2} + \varepsilon_t} \quad ...(1)$$

जहां $\boldsymbol{y_t} = \begin{bmatrix} F_t \\ R_t \end{bmatrix}$ और $\boldsymbol{A_0}$, $\boldsymbol{A_1}$ और $\boldsymbol{A_2}$ गुणांक मैट्रिक्स हैं। F और R क्रमश: प्रवाह और प्रतिलाभ दर्शाते हैं। ग्रेंजर कारण टेस्ट प्रभाव की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी क्या प्रतिलाभ प्रवाह की सूचना रखते हैं या इसके विपरीत।

एक घटाए हुए द्विभाजित वीएआर मॉडल के परिणाम सारणी 2 में प्रस्तुत किए गए हैं। अंतराल की लंबाई का चयन बायेसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया (बीआईसी) के आधार पर किया गया था, जो 2 पर अंतराल चयन दिखाता है। प्रवाह एक महीने के विलंबित प्रतिलाभ से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है [सारणी 2(1)] । प्रवाह दो महीने के अंतराल तक मजबूत स्वतःसंबंध प्रदर्शित करता है। प्रवाह समीकरण के लिए आर^2 0.31 है जिसका अर्थ है कि पिछले प्रतिलाभ वास्तव में वर्तमान प्रवाह में योगदान करते हैं। हालांकि, प्रतिलाभ पिछले महीनों के प्रवाह से प्रभावित नहीं होते हैं [सारणी2 (2)], लेकिन एक महीने के विलंबित प्रतिलाभ से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, प्रतिलाभ समीकरण के लिए

[14] चरों के आपसी गतिशील संबंध और एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया को समझने के लिए, वीएआर एक स्वाभाविक विकल्प है।

सारणी 2: प्रवाह और प्रतिलाभ का वीएआर-(2) विश्लेषण

चर	निर्भर चर	
	प्रवाह	प्रतिलाभ
	(1)	(2)
प्रतिलाभ		
(-1)	4.60***	0.23**
	(3.43)	(2.25)
(-2)	0.47	-0.03
	(0.34)	(-0.24)
प्रवाह		
(-1)	-0.61***	-0.01
	(-6.26)	(-0.76)
(-2)	-0.39***	-0.01
	(-4.08)	(-1.30)
स्थिर	-1.80	0.49***
	(-1.56)	(5.57)
अवलोकन	107	107
आर^2	0.31	0.06
समायोजित आर^2	0.28	0.02
अवशिष्ट मानक त्रुटि (डीएफ़ = 102)	4.47	0.34
एफ-सांख्यिकी (डीएफ = 4; 102)	11.22***	1.65

टिप्पणी: *पी<0.1; **पी<0.05; *** पी <0.01। टी-सांख्यिकी कोष्ठकों में रिपोर्ट की जाती हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ की गणना।

आर^2 कम है, जिसका अर्थ है कि प्रतिलाभ की व्याख्या करने के लिए प्रवाह की क्षमता सीमांत है।

प्रवाह और प्रतिलाभ के बीच ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट के परिणाम सारणी 3 में रिपोर्ट किए गए हैं। शून्य परिकल्पना कि "प्रतिलाभ प्रवाह के ग्रेंजर-कारण नहीं है" सांख्यिकीय महत्व के एक बहुत उच्च स्तर पर खारिज कर दिया गया है, यह सुझाव देता है कि प्रतिलाभ के पिछले मूल्यों में वर्तमान प्रवाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। हालांकि, हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहते हैं "प्रवाह प्रतिलाभ के ग्रेंजर-कारण नहीं हैं", जिसका अर्थ है कि प्रवाह के पिछले मूल्य में वर्तमान प्रतिलाभ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार, प्रवाह और प्रतिलाभ के बीच एकतरफा ग्रेंजर कारणता स्थापित होती है, यानी प्रतिलाभ के पिछले मूल्य वर्तमान प्रवाह को प्रभावित करते हैं लेकिन इसके विपरीत नहीं।

सारणी 3: प्रवाह और प्रतिफल के बीच करणीयता का परीक्षण

	प्रवाह प्रतिलाभ के ग्रैंजर-कारण नहीं बनते	प्रतिलाभ प्रवाहों के ग्रैंजर-कारण नहीं बनते
एफ़ सांख्यिकी	0.86	6.16***

टिप्पणी: *पी<0.1; **पी<0.05; ***पी<0.01.
स्रोत: आरबीआई स्टाफ की गणना।

नैदानिक परीक्षण के लिए, हम वीएआर-(2) मॉडल के अवशिष्ट में क्रमिक सहसंबंध की जांच के लिए प्रतिकृति टेस्ट और वीएआर-(2) मॉडल के अवशिष्ट में विषमविसारिता की जांच के लिए एआरसीएच टेस्ट लागू करते हैं। वीएआर-(2) मॉडल के अवशिष्टों में कोई विषमविसारिता और क्रमिक सहसंबंध नहीं पाया गया। अवशिष्ट में संरचनात्मक विराम के परीक्षण के लिए, हम संचयी योग (सीयूएसयूएम) परीक्षण लागू करते हैं। अवशेषों में कुछ भी संरचनात्मक नहीं देखा गया (अनुबंध 2)। आवेग प्रतिक्रिया कार्य अनुबंध 3 में प्रस्तुत किए गए हैं, जो निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

घटाए-हुए द्विभाजित वीएआर और कार्य-कारण परीक्षण में सुधार के रूप में, हम बाजार के मूल सिद्धांतों की उपस्थिति में डेट म्यूचुअल फंड पर प्रवाह और प्रतिलाभ के बीच संबंध का विश्लेषण करते हैं। ऐसा करने के लिए, हम निम्नलिखित चरों को शामिल करते हैं, ऋण/चूक जोखिम को मापने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड, अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, प्रतिस्पर्धी बचत लिखत पर प्रतिलाभ की दर को मापने के लिए बैंकों की औसत बचत और मीयादी जमा दर पर, चलनिधि की स्थिति को मापने के लिए आरबीआई की चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत बकाया औसत राशि और सीपीआई मुद्रास्फीति दर[15] (सारणी 4)। अर्थव्यवस्था चर की स्थिति को समझने के लिए, हम वृद्धि चक्रों की अवधारणा का उपयोग करते हैं। वृद्धि चक्र को दीर्घकालीन प्रवृत्ति वृद्धि दर से अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर के विचलन के माध्यम से उच्च और निम्न वृद्धि चरणों (सामान्य आर्थिक गतिविधि के स्तरों में विस्तार और संकुचन के बजाय) के वैकल्पिक अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। वृद्धि चक्र में संकुचन आर्थिक गतिविधियों में मंदी का संकेत देता है जबकि विस्तार आर्थिक गतिविधियों में उछाल का संकेत देता है। इस प्रकार, 0 (संकुचन) और 1 (विस्तार) का प्रतिनिधित्व करने वाले एक डमी चर का उपयोग किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए, हम पहले आईआईपी (लॉग) श्रृंखला के चक्रीय घटक को निकालते हैं। हॉड्रिक-प्रेस्कॉट (एचपी) फिल्टर (हॉड्रिक एवं प्रेस्कॉट, 1980) सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विलयन पद्धतियों में से एक है। हालांकि, किंग और रेबेलो (1993) के अनुसार, एचपी फिल्टर दृढ़ता, परिवर्तनशीलता और सह-गति के उपायों को गंभीरता से बदल देता है। नतीजतन, हम बैक्सटर एंड किंग (1999) और क्रिस्टियानो और फिट्जगेराल्ड (2003) द्वारा प्रस्तावित बैंड-पास फिल्टर का उपयोग करते हैं। बैंड पास फिल्टर 6 तिमाहियों (18 महीने) और 32 तिमाहियों (96 महीने) के बीच आवधिक उतार-चढ़ाव के साथ समय श्रृंखला के घटकों को बनाए रखता है, जबकि उच्च (अनियमित) और कम आवृत्तियों (प्रवृत्ति) पर घटकों को अवरोधित करता है। ये फ़िल्टर आवृत्ति क्षेत्र में प्रवृत्ति-चक्र अपघटन और चौरसाई समस्या का समाधान करते हैं। हमारे काम में, हम प्रवृत्ति और चक्रीय घटक को अलग करने के लिए असममित क्रिस्टियानो-फिट्ज़गेराल्ड फ़िल्टर (सीएफ़) का उपयोग करते हैं। सीएफ़ फ़िल्टर प्रत्येक अवलोकन के लिए अलग-अलग भार डालता है और इसलिए फ़िल्टर असममित है। डेटिंग एल्गोरिदम लगाने से पहले चक्रीय घटक को मानकीकृत किया गया है। हम विस्तार और मंदी की पहचान करने के लिए हार्डिंग-पगन एल्गोरिथम (2002) का उपयोग करते हैं।

विभिन्न समष्टिआर्थिक चरों का चयन मौजूदा साहित्य के आधार पर किया गया है [जैसे कि कोप्सच एवं अन्य (2015)], और सामान्य समझ। बाजार के मूल सिद्धांतों की उपस्थिति में, यदि हम पूर्व में प्राप्त प्रतिलाभ से प्रवाह से एकतरफा कारण प्राप्त करते हैं, तो यह वास्तव में दिखाएगा कि यह वह प्रतिलाभ है जो डेट म्यूचुअल फंड प्रवाह को संचालित करता है। डेट म्यूचुअल फंड का प्रवाह सामान्य रूप से प्रतिलाभ के बदले में है। बाजार के मूल सिद्धांतों को शामिल करते हुए निम्नलिखित प्रतिगमन समीकरणों का उपयोग किया जाता है:

सारणी 4: बहिर्जात चर का विवरण

बाज़ार आधार	प्रत्येक संकेतक का माप
क्रेडिट स्प्रेड	5-वर्षीय एएए कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल 5-वर्ष जी-सेक प्रतिफल (सीएस) का निवल
आर्थिक गतिविधि	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी); डमी चर के रूप में उपयोग किया जाता है।
प्रतिलाभ की प्रतिस्पर्धी दर	बैंकों की बचत और सावधि जमा पर प्रतिलाभ की औसत दर ($\bar{r}$)
चलनिधि की स्थिति	निवल चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत बकाया राशि को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एलएएफ) द्वारा बढ़ाया गया
मुद्रास्फ़ीति	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन

[15] एक अन्य मॉडल में, हमने अतिरिक्त वीआईएक्स को बहिर्जात चर में से एक के रूप में उपयोग किया था, हालांकि हमारे परिणाम मोटे तौर पर पहले के परिणामों के समान ही रहे।

$$\text{Flow}_t = = \eta + \sum_{i=1}^{m} \theta * Ret_{i-1} + \sum_{i=1}^{m} \lambda * Flow_{i-1} + \mu^* (CS) + \rho * (\bar{\iota}) + \omega * (LAF) + \psi * (CPI) + \varepsilon \quad \ldots (2)$$

$$\text{Rett} = \alpha + \sum_{i=1}^{m} \beta * Ret_{i-1} + \sum_{i=1}^{m} \gamma * Flow_{i-1} + \delta^* (CS) + \tau * (\bar{\iota}) + \varphi * (LAF) + \varsigma^* (CPI) + \varepsilon \quad \ldots (3)$$

CS, $\bar{\iota}$, LAF और CPI स्थिर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिए अलग-अलग हैं। (2) में सभी i के लिए शून्य परिकल्पना कि बाज़ार सिद्धांतों की उपस्थिती में जहां प्रतिलाभ डेट फंड प्रवाह का ग्रेंजर कारण नहीं है उसे H_0: $\theta_i = 0$ द्वारा टेस्ट किया जाता है। इसी तरह, (3) में सभी i के लिए शून्य परिकल्पना कि जहां डेट फंड प्रवाह प्रतिलाभ का ग्रेंजर कारण नहीं है उसे H_0: $\gamma_i = 0$ द्वारा टेस्ट किया जाता है।

बाजार के मूल सिद्धांतों की उपस्थिति में प्रवाह-प्रतिलाभ संबंध की दिशा की रिपोर्ट करने वाले परिणाम सारणी 5 में प्रस्तुत किए गए हैं। प्राप्त परिणाम पहले के परिणामों के समान हैं।

परिणाम इस परिकल्पना को खारिज करते हैं कि पिछले प्रतिलाभ वर्तमान प्रवाह के ग्रेंजर कारण नहीं हैं। यह दर्शाता है कि बाजार के मूल सिद्धांतों की उपस्थिति में प्रवाह दो अंतराल तक स्वत:-सहसंबंध प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, प्रवाह एक महीने के विलंबित प्रतिलाभ और क्रेडिट स्प्रेड से प्रभावित होते हैं। डेट म्यूचुअल फंडों में बचत/निवेश के पीछे प्राथमिक उद्देश्य मूलधन की सुरक्षा है और ऋण जोखिम में कोई भी वृद्धि डेट म्यूचुअल फंडों के प्रवाह के अवरोध के रूप में कार्य करती प्रतीत होती है। सारणी 5 (2) दर्शाती है कि हम पिछले प्रवाह की शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहते हैं जो वर्तमान प्रतिलाभ का ग्रेंजर कारण बनता है। प्रतिलाभ एक महीने के अंतराल प्रतिलाभ और सीपीआई से प्रभावित होते हैं। मुद्रास्फीति में वृद्धि से केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के सख्त होने की उम्मीद बढ़ जाती है, जिससे बॉन्ड के प्रतिफल में वृद्धि हो सकती है और बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आ सकती है (प्रतिफल और कीमतों के बीच विपरीत संबंध के कारण)। बॉन्ड की कीमतों में गिरावट का मतलब म्यूचुअल फंड में धारित राशि पर प्रतिलाभ में गिरावट है। सारणी2 की तुलना में प्रवाह और प्रतिलाभ के लिए आर^2 और समायोजित आर^2 में मामूली वृद्धि हुई है, जो यह सुझाव देता है कि बहिर्जात चर वर्तमान प्रवाह और वर्तमान प्रतलाभ में भिन्नता की व्याख्या करने में ज्यादा योगदान नहीं देते हैं।

सारणी 5: बाज़ार आधार की उपस्थिति में प्रवाह और प्रतिलाभ का वीएआर-(2) विश्लेषण

चर	निर्भर चर	
	प्रवाह	प्रतिलाभ
	(1)	(2)
प्रतिलाभ		
(-1)	4.41***	0.23**
	(3.25)	(2.13)
(-2)	0.95	-0.03
	(0.69)	(-0.24)
प्रवाह		
(-1)	-0.65***	-0.01
	(-6.57)	(-0.75)
(-2)	-0.41***	-0.01
	(-4.17)	(-1.27)
बाज़ार आधार (बहिर्जात चर)		
सीएस	-5.03*	0.21
	(-1.71)	(0.93)
आईआईपी	0.82	0.001
	(0.93)	(0.01)
$\bar{\iota}$	0.51	-0.02
	(1.06)	(-0.48)
एलएएफ़	-0.68	-0.004
	(-0.61)	(-0.04)
सीपीआई	-0.30	-0.09*
	(-0.49)	(-1.89)
स्थिर	-2.35*	0.50***
	(-1.92)	(5.21)
अवलोकन	107	107
आर^2	0.35	0.10
समायोजति आर^2	0.29	0.02
अवशिष्ट मानक त्रुटि (डीएफ़ = 97)	4.44	0.35
एफ-सांख्यिकी (डीएफ = 9; 97)	5.76***	1.18

टिप्पणी: *पी<0.1; **पी<0.05; *** पी <0.01। टी-सांख्यिकी कोष्ठकों में।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ की गणना।

V. निष्कर्ष

डेट एमएफ में प्रवाह मौसमी रूप से प्रदर्शित होता है, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में, मुख्य रूप से कर भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए, हर तिमाही के अंत में कॉर्पोरेट द्वारा मोचन देखा जाता है। अनुभवजन्य अभ्यास से पता चलता है कि पिछले प्रतिलाभ में डेट एमएफ में मौजूदा प्रवाह के बारे में जानकारी होती है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। घटते प्रतिलाभ की अवधि के कारण डेट एमएफ से निकासी हो सकती है। बाजार के विभिन्न बुनियादी सिद्धांतों की मौजूदगी में भी यह सच है। इनमें से कुछ मौलिक बाजार संकेतक भी प्रवाह और प्रतिलाभ के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। क्रेडिट स्प्रेड को प्रवाह से विपरीत रूप से संबंधित पाया गया है, और सीपीआई मुद्रास्फीति को प्रतिलाभ के साथ विपरीत रूप से जुड़ा हुआ पाया गया है।

संदर्भ

Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: approximate band-pass filters for economic time series, *The Review of Economics and Statistics*, 81(4), 575-593.

Christiano, L. J., & Fitzgerald, T. J. (2003). The band pass filter, *International Economic Review,* 44(2), 435-465.

Fortune, P. (1998). Mutual funds, Part II: Fund flows and security returns. *New England Economic Review*, 3-22.

Harding, D., & Pagan, A. (2002). Dissecting the cycle: a methodological investigation. *Journal of monetary economics*, *49*(2), 365-381.

Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1980). Postwar US Business Cycles: An Empirical Investigation [Discussion paper No. 451]. *Centre for Mathematical Studies in Economics and Management Science, Northwestern University, Evanston, 111.*

King, R. G., & Rebelo, S. T. (1993). Low frequency filtering and real business cycles. *Journal of Economic dynamics and Control*, *17*(1-2), 207-231.

Kopsch, F., Song, H. S., & Wilhelmsson, M. (2015). Determinants of mutual fund flows. *Managerial Finance.*

Madhumathi, R., Gopal, N., & Ranganatham, M. (2012, December). Determinants of Debt and Equity Mutual Fund Flows in India. In *XI Capital Markets Conference* (pp. 21-22).

Remolona, E. M., Kleiman, P., & Gruenstein Bocain, D. (1997). Market returns and mutual fund flows. *Economic Policy Review,* 3(2).

Zhao, X. (2005). Determinants of flows into retail bond funds. *Financial Analysts Journal*, *61*(4), 47-59.

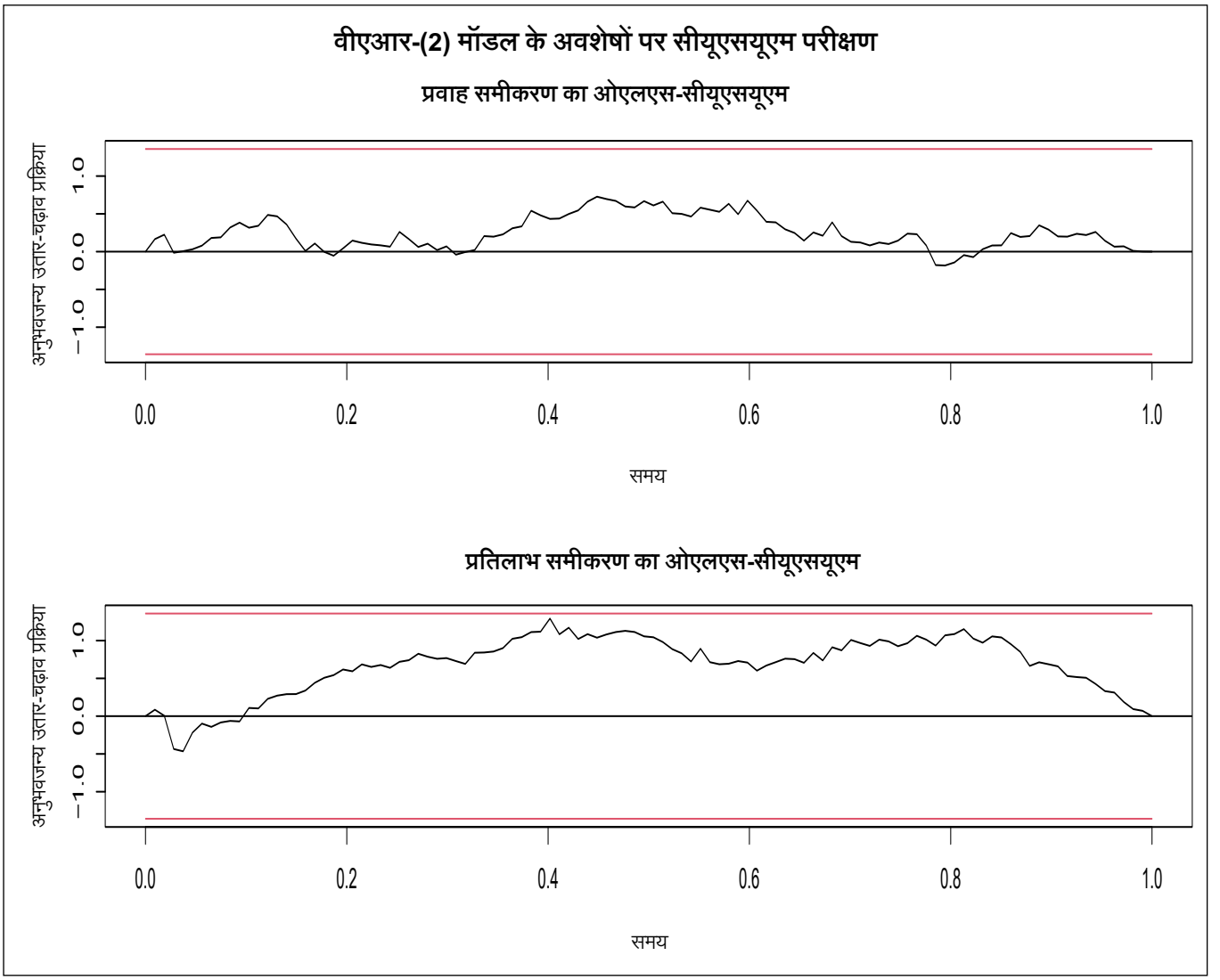
अनुबंध 1
कर्ज़ योजनाओं का वर्गीकरण

श्रेणी योजना	योजना की विशेषताएं	एयूएम अंत-सित. 2022 (₹ करोड़)
असीमित अवधि वाली योजनाएं		
एक दिवसीय निधि	1 दिन की परिपक्वता वाली एकदिवसीय प्रतिभूतियों में निवेश।	1,41,320
अर्थसुलभ निधि	केवल 91 दिनों तक की परिपक्वता अवधि के साथ कर्ज़ और मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों में निवेश।	3,52,213
अति-लघु अवधि की निधि	कर्ज़ और मुद्रा बाज़ार लिखतों में निवेश जैसे पोर्टफोलियो की मैकाले अवधि 3- 6 महीने के बीच है।	89,481
लघु अवधि निधि	कर्ज़ और मुद्रा बाज़ार लिखतों में निवेश जैसे पोर्टफोलियो की मैकाले अवधि 6- 12 महीने के बीच है।	95,673
मुद्रा बाज़ार निधि	1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश।	1,07,379
अल्पावधि निधि	कर्ज़ और मुद्रा बाज़ार लिखतों में निवेश जैसे पोर्टफोलियो की मैकाले अवधि 1 वर्ष-3 वर्ष के बीच है।	97,272
मध्यम अवधि की निधि	कर्ज़ और मुद्रा बाज़ार लिखतों में निवेश जैसे पोर्टफोलियो की मैकाले अवधि 3 वर्ष-4 वर्ष के बीच है। प्रत्याशित प्रतिकूल परिस्थितियों में पोर्टफोलियो मैकाले की अवधि 1 वर्ष से 4 वर्ष है।	28,204
मध्यम से दीर्घावधि निधि	कर्ज़ और मुद्रा बाज़ार लिखतों में निवेश जैसे पोर्टफोलियो की मैकाले अवधि 4 वर्ष-7 वर्ष के बीच है। प्रत्याशित प्रतिकूल परिस्थितियों में पोर्टफोलियो मैकाले की अवधि 1 वर्ष से 7 वर्ष है।	8,927
दीर्घावधि निधि	कर्ज़ और मुद्रा बाज़ार लिखतों में निवेश जैसे कि पोर्टफोलियो की मैकाले अवधि 7 वर्ष से अधिक है	2,828
गतिशील बॉन्ड	अवधि भर में निवेश।	22,084
कॉरपोरेट बॉन्ड फंड	कॉर्पोरेट बॉन्ड में न्यूनतम निवेश- कुल आस्तियों का 80% (केवल एए+ और उससे अधिक रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में)	1,12,783
क्रेडिट रिस्क फंड	कॉर्पोरेट बॉन्ड में न्यूनतम निवेश- कुल सआस्तियों का 65% (केवल एए और नीचे के रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में)	25,821
बैंकिंग और पीएसयू फंड	बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और नगरपालिका बांडों के कर्ज़ लिखतों में न्यूनतम निवेश - कुल आस्ति का 80%	77,678
गिल्ट फंड	जी-सेक में न्यूनतम निवेश- कुल आस्ति का 80% (परिपक्वता के दौरान)	15,700
गिल्ट फंड 10 साल की निरंतर अवधि के साथ	जी-सेक में न्यूनतम निवेश- कुल आस्ति का 80% जैसे पोर्टफोलियो की मैकाले अवधि 10 वर्ष के बराबर है	1,499
अस्थायी फंड	अस्थायी दर लिखतों में न्यूनतम निवेश (स्वैप/डेरिवेटिव्स का उपयोग करके अस्थायी दर एक्सपोजर में परिवर्तित नियत दर लिखत सहित) - कुल आस्ति का 65%	62,812
सीमित अवधि वाली योजनाएं		
निश्चित अवधि की योजना	सीमित अवधि वाली निधियां जो ब्याज दर के जोखिम को खत्म करती हैं और केवल उन प्रतिभूतियों में निवेश करके प्रतिफल को सुनिश्चित करती हैं जिनकी परिपक्वता निधि की परिपक्वता से मेल खाती है।	15,134
पूंजी संरक्षण उन्मुख योजनाएं	सीमित अवधि वाली संकर निधियां जो कर्ज़ लिखतों और इक्विटी व्युत्पन्नी का पोर्टफोलियो बनाते हैं।	630
अवसंरचना कर्ज़ निधि	निवेश माध्यम जो अवसंरचना क्षेत्र में निवेश करते हैं।	2,068

अनुबंध 2

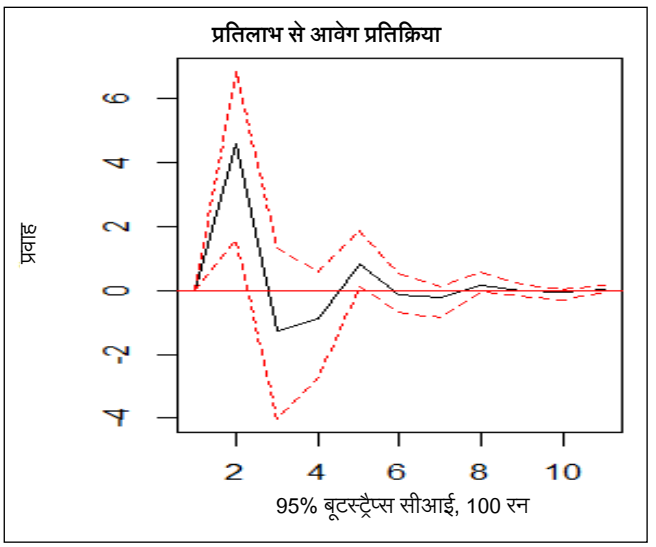
टेस्ट	सांख्यिकी	पी मूल्य
प्रतिकृति	30.61	0.16
एआरसीएच वीएआर	56.82	0.90

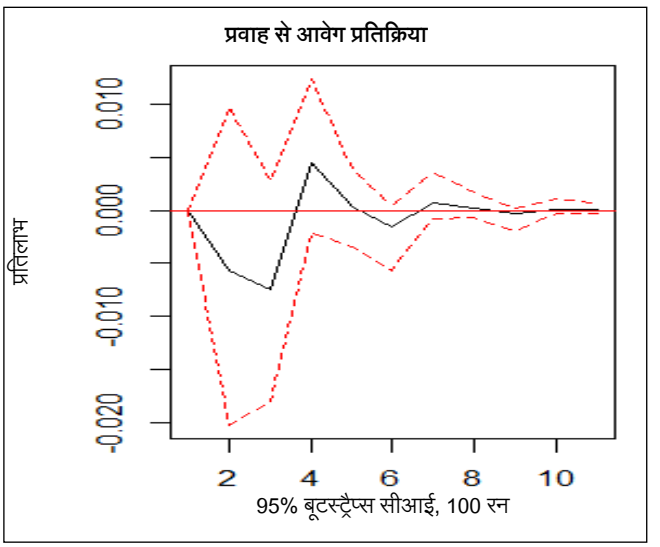
टिप्पणी: *पी<0.1; **पी<0.05; ***पी<0.01.



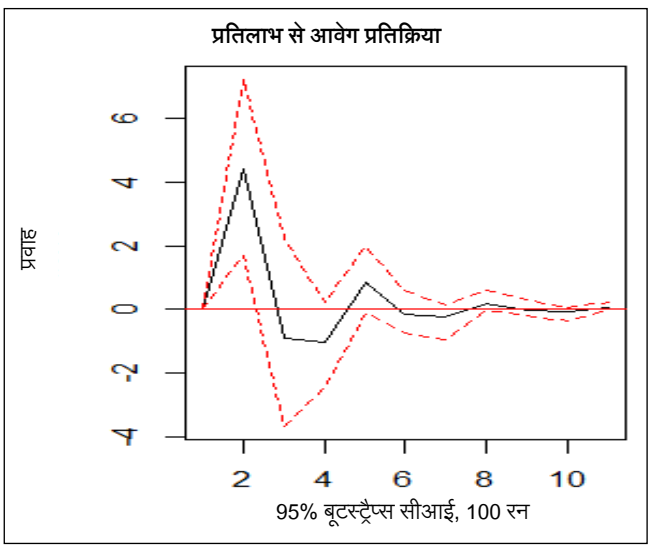
अनुबंध 3

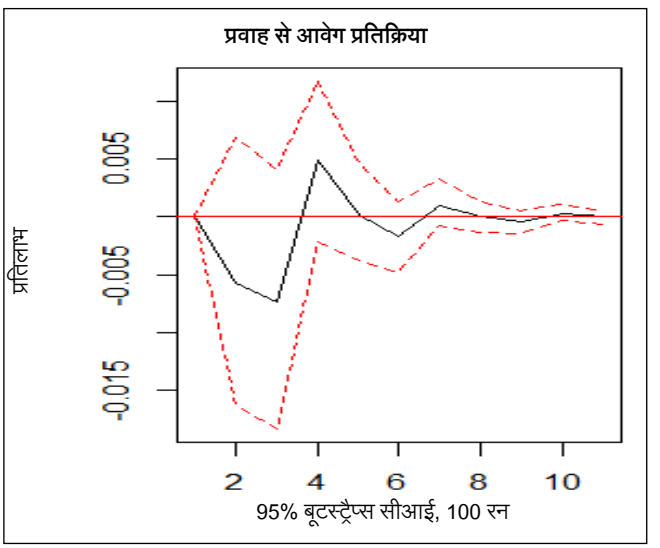
(ए) प्रवाह और प्रतिलाभ के आवेग प्रतिक्रिया प्रकार्य (समीकरण 1)





(बी) प्रवाह और प्रतिलाभ के आवेग प्रतिक्रिया प्रकार्य (समीकरण 2 और 3)





टिप्पणी: स्थिरता जांच इंगित करती है कि वीएआर की स्थिरता स्थितियों की पुष्टि करने वाले इकाई वृत्त के बाहर कुछ नहीं है।

*भारत में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय देयताएं - एक आकलन**

ऋचा रावत^, तरुण कुमार सक्सेना^ और विवेक कुमार^ द्वारा

यह अध्ययन घरेलू उधार के निर्धारकों (जिसे जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात के रूप में मापा जाता है) की जांच करता है और वैश्विक वित्तीय संकट और महामारी काल सहित विभिन्न काल-खंड में घरेलू उधार के सातत्य का आकलन करने के लिए भेद्यता सूचकांकों को सृजित करता है। यह देखा गया है कि भारत के लिए अनुमानित भेद्यता स्कोर आमतौर पर कम रहा है जो दर्शाता है कि पिछले तीन दशकों के दौरान घरेलू क्षेत्र की वित्तीय देनदारियां स्थायी सीमा के भीतर रहीं।

भूमिका

बचत के रूप में वित्तीय संसाधनों के आपूर्तिकर्ता के रूप में घरेलू क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) 2022 के अनुसार, सकल बचत में घरेलू क्षेत्र (एचएच) की हिस्सेदारी 78.5 प्रतिशत थी और इस क्षेत्र ने 2020-21 के दौरान आधार मूल्यों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) में 43.5 प्रतिशत का योगदान दिया। जहाँ, एचएच सेक्टर वित्तीय बचत के रूप में अर्थव्यवस्था में अग्रणी ऋणदाता है, वहीं यह वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के रूप में सबसे प्रमुख कर्जदार भी है। विकास के उद्देश्यों को देखते हुए, एचएच क्षेत्र के लिए किफायती ऋण तक पहुंच तरलता की कमी को कम कर सकती है और उन्हें अपनी खपत को सुगम बनाने में सक्षम बना सकती है। इसलिए एचएच द्वारा उधार लेना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी ओर, धारणीय स्तरों से अधिक उधार लेने के मामले में एचएच क्षेत्र द्वारा अत्यधिक लीवरेज वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जिससे आर्थिक व्यवधान पैदा हो सकता है। वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड महामारी जैसे बाहरी झटकों से यह और बढ़ सकता है जो एचएच की आय और उधार पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संस्थागत स्रोतों से एचएच वित्तीय देनदारियां 2020-21 की चौथी तिमाही में तेजी से बढ़कर 39.5 प्रतिशत हो गईं, जबकि 2019-20 की चौथी तिमाही में यह 35.4 प्रतिशत थी। इस संदर्भ में, इसकी स्थिरता का आकलन करने के लिए अपेक्षाकृत बड़ी समयावधि के लिए भारत में परिवारों (हाउसहोल्ड) के उधार लेने की प्रवृत्ति का आकलन करना महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत अध्ययन संबंधित साहित्य की इसी कमी को दूर करने का एक प्रयास है।

यह पहले ही प्रलेखित किया जा चुका है कि एचएच क्षेत्र की ऋण वृद्धि हाल के वर्षों के दौरान स्थिर और तीव्र रही है। टिप्पणीकारों ने इंगित किया है कि 2021-22 की शुरुआती तीन तिमाहियों में विस्तार और छंटनी की वैकल्पिक अवधि के कारण एचएच क्रेडिट वृद्धि में निरंतर तेजी के परिणामस्वरूप घरेलू (हाउसहोल्ड) दबाव (एसबीआई, 2021) हो सकता है। इसलिए, ऋण वृद्धि के निर्धारकों की पहचान करने से उपयुक्त नीति प्रतिक्रिया तैयार करने में मदद मिलेगी। अपनी वित्तीय स्थिरता के लिए एचएच क्षेत्र का आकलन आर्थिक विकास की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है क्योंकि एचएच की ऋणग्रस्तता कुल व्यय की संवेदनशीलता को प्रभावित करती है जो समष्टि आर्थिक और समग्र वित्तीय स्थिरता दोनों के लिए मायने रखती है (रामादुरई, 2017)। साथ ही, एचएच उधारों का स्तर और वितरण व्यापक अर्थव्यवस्था (ज़बाई, 2017) में झटके के लिए कुल मांग और कुल आपूर्ति की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इन महत्वपूर्ण चैनलों को देखते हुए, यह आलेख उन आनुभविक कारकों की पहचान करके साहित्य को पूरक बनाता है जो भारत में जीडीपी की तुलना में घरेलू (एचएच) ऋण अनुपात की प्रवृत्ति को निर्धारित करते हैं और दबाव की अवधि के दौरान घरेलू उधारी की स्थिरता की जांच करने के लिए भेद्यता सूचकांकों का निर्माण करते हैं।

डी वैनी और लिटन (1995) द्वारा अग्र-संकेतक मॉडल और वित्तीय अनुपात का उपयोग करके एचएच वित्त के डोमेन के भीतर

^ लेखक सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग से हैं।

* आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के कौस्तव सरकार और ईशु ठाकुर को उनकी व्यावहारिक टिप्पणियों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

दिवालियापन के मापन से संबंधित समस्याओं का पता लगाया गया। ले और अन्य, (2012) ने दिखाया कि एचएच उधार में बड़े पैमाने पर उछाल होने पर आवास बाजार में गिरावट और मंदी अधिक गंभीर होती है। मेनियागो और अन्य, (2013) ने दक्षिण अफ्रीका में वेक्टर त्रुटि सुधार (वीईसी) मॉडल का उपयोग करके घरेलू उधार में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों की जांच की और दिखाया कि घर की कीमतें, घरेलू बचत, सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू खपत और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) सकारात्मक रूप से घरेलू उधार में मजबूत वृद्धि से जुड़े थे। उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू उधारी के व्यापक आर्थिक निर्धारकों का अध्ययन करते हुए इसी तरह के निष्कर्ष समद और अन्य, (2020) द्वारा भी रिपोर्ट किए गए थे। इस प्रकार, यह आलेख एचएच उधारों की स्थिरता के आनुभविक मूल्यांकन से संबंधित बृहत साहित्य में अवस्थित है।

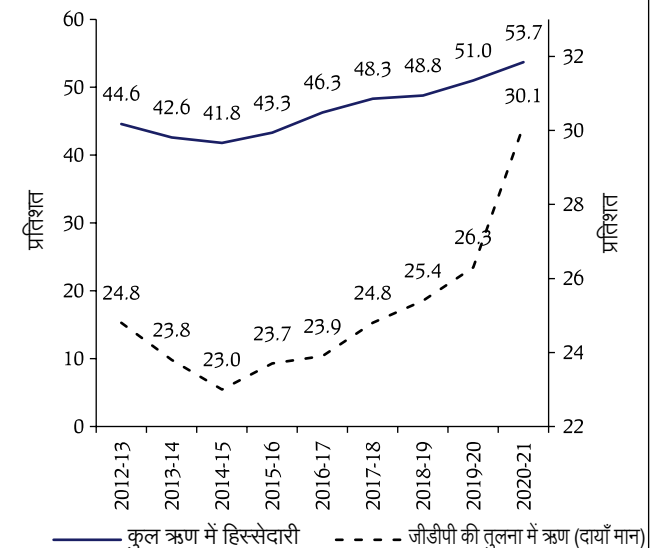
शेष आलेख निम्नानुसार संयोजित किया गया है: खंड 2 भारतीय एचएच की ऋणग्रस्तता के बारे में वर्गीकृत तथ्यों से संबंधित है और यह अंतर-देशीय तुलना (विशेष रूप से ब्रिक्स देश) प्रस्तुत करता है। खंड 3 कई स्थिरता संकेतकों को देखकर एचएच उधारों की स्थिरता का मूल्यांकन करता है। खंड 4 आनुभविक रूप से प्रमुख घटक प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करके घरेलू उधार के निर्धारकों की जांच करता है और घरेलू वित्तीय देनदारियों की स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए भेद्यता सूचकांक की गणना करता है। खंड 5 इस आलेख का समापन है।

2. कुछ वर्गीकृत तथ्य

2.1 घरेलू क्षेत्र (एचएच) की ऋणग्रस्तता:

एचएच उधार में, एचएच ऋण के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करने वाली संस्थागत एजेंसियों[1] सहित, संस्थागत और गैर-संस्थागत ऋण शामिल हैं। एचएच क्षेत्र को दिए गए कुल संस्थागत ऋण में से 70 प्रतिशत से अधिक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिया जाता है। अन्य संस्थागत स्रोत सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कॉरपोरेशन (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) हैं। संस्थागत स्रोतों से एचएच क्षेत्र की

चार्ट 1 घरेलू क्षेत्र को एससीबी से प्राप्त ऋण



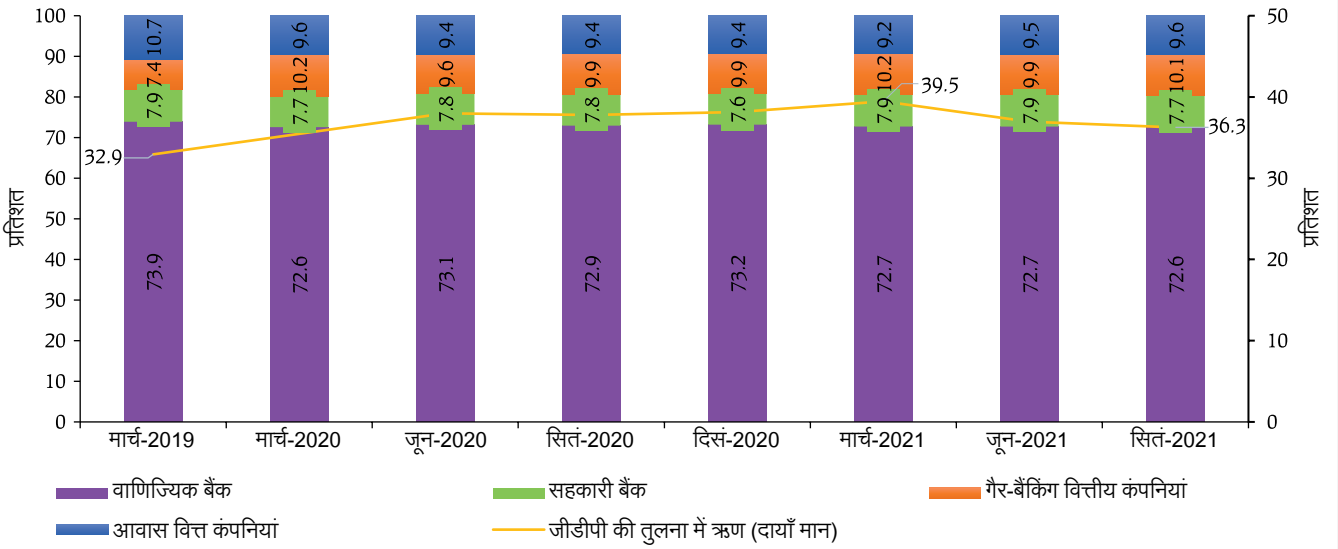
स्रोत: डीबीआईई (आरबीआई) और लेखकों के अपने आकलन

कुल उधारी मार्च 2019 में 62 लाख करोड़ रुपये से 28.3 प्रतिशत बढ़कर सितंबर 2021 में 79 लाख करोड़ रुपये हो गई है। यह आलेख एससीबी से एचएच के क्रेडिट पर केंद्रित है जो कि एचएच को ऋण का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। सकल घरेलू उत्पाद में एससीबी से एचएच को ऋण की हिस्सेदारी मार्च 2015 में 23 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2021 में बढ़कर 30.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट 1)।

एनबीएफसी, एचएफसी और अन्य द्वारा गैर-बैंकिंग ऋण का हिस्सा हाल की अवधि में बढ़ा है। इन सभी संस्थानों (एससीबी, एनबीएफसी, एचएफसी और सहकारी बैंकों) से एचएच के उधार की हिस्सेदारी मार्च 2019 में जीडीपी के 32.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 में जीडीपी का 35.4 प्रतिशत हो गई। महामारीके पहले चरण के लॉकडाउन में, घृहस्थ परिवार जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और उन्होंने नौकरियों के नुकसान के कारण अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लिया था, जिससे एक तिमाही (जून 2020) के भीतर यह अनुपात 38.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। बढ़ती हुई यह प्रवृत्ति मार्च 2021 तक जारी रही जब यह 39.5 प्रतिशत थी, उसके बाद, एचएच क्रेडिट जीडीपी अनुपात में गिरावट शुरू हो गई (चार्ट 2)।

[1] अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस) 2019 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में एचएच नकद ऋण का 87.1 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में एचएच नकद ऋण का लगभग 66.2 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों द्वारा दिया गया है।

चार्ट 2 : संस्थागत स्रोतों से घरेलू क्षेत्रों को प्राप्त ऋण

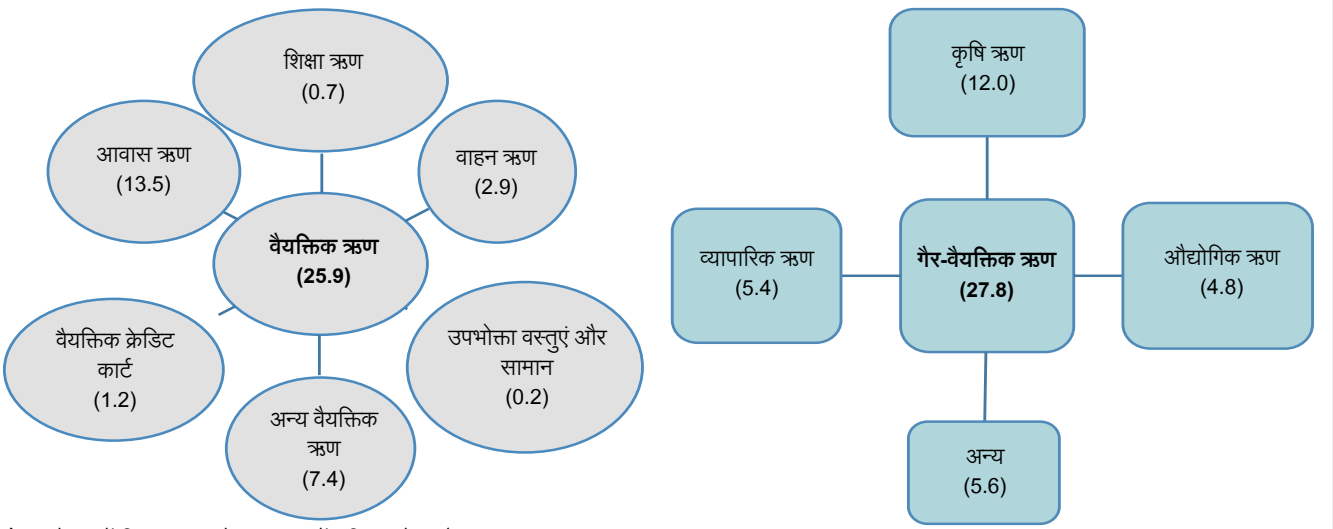


स्रोत: तिमाही हाउसहोल्ड वित्तीय बचत (आरबीआई) और लेखकों के आकलन

2.2 घरेलू क्षेत्र (एचएच) के ऋण का गतिविधिक संघटन:

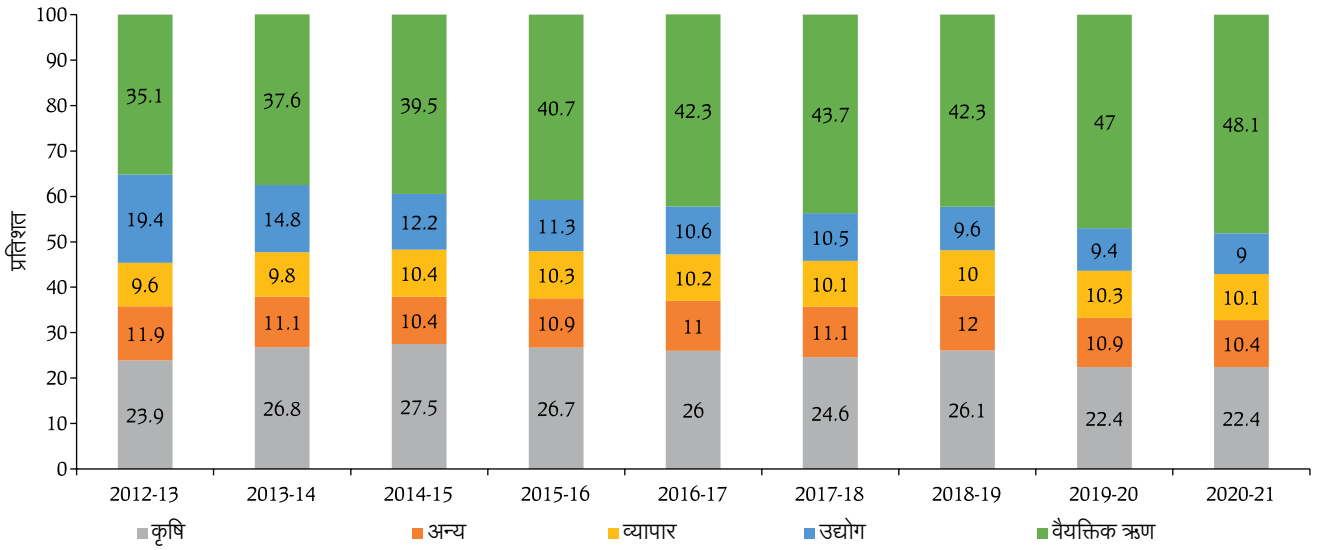
एससीबी द्वारा एचएच क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), गैर-निगमित उद्यम जैसे मालिकाना और साझेदारी की चिंताएं, संयुक्त देयता समूह, एनजीओ, ट्रस्ट और समूह आदि सहित वैयक्तिक और गैर-वैयक्तिक ऋण शामिल हैं। मार्च 2021 में, वैयक्तिक ऋण कुल बैंक ऋण का 25.9 प्रतिशत था और इसमें मुख्य रूप से आवास ऋण, वाहन ऋण, क्रेडिट कार्ड और शैक्षिक ऋण शामिल थे; एचएच क्षेत्र के लिए गैर-वैयक्तिक ऋण कुल बैंक ऋण का 27.8 प्रतिशत है और इसमें मुख्य रूप से कृषि ऋण, औद्योगिक ऋण और व्यापार ऋण शामिल हैं (चार्ट 3)।

चार्ट 3: चार्ट 3: घरेलू क्षेत्र को बैंक ऋण: मार्च 2021 तक वैयक्तिक और गैर-वैयक्तिक ऋण



नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल ऋण में प्रतिशत शेयर हैं।
स्रोत: डीबीआईई (आरबीआई)।

चार्ट 4: एससीबी द्वारा हाउसहोल्ड को प्रदत्त ऋण बकाया – संघटन



स्रोत: डीबीआईई (आरबीआई)

घरेलू क्षेत्र के कुल ऋण में वैयक्तिक ऋण का हिस्सा हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। मार्च 2021 में एचएच ऋण में वैयक्तिक ऋण 48.1 प्रतिशत तक बढ़ गया, जो मार्च 2019 में 42.3 प्रतिशत था, यानी महामारी के दौरान उसकी हिस्सेदारी में उल्लेखनीय रूप से 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 4)। मार्च 2021 में कृषि गतिविधियों के लिए ऋण की हिस्सेदारी 2018-19 के 26.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर 22.4 प्रतिशत हो गई और पिछले 9 वर्षों की अवधि के दौरान घरेलू क्षेत्र के कुल ऋण में व्यापार लगभग 10 प्रतिशत रहा।

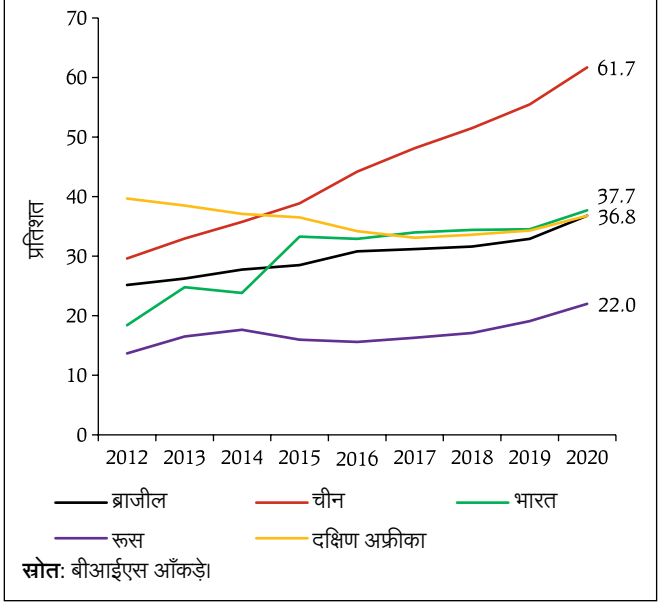
2.3 ब्रिक्स देशों में घरेलू (हाउसहोल्ड) उधारी की स्थिति से तुलना

घरेलू क्षेत्र के जीडीपी अनुपात में भारत का क्रेडिट उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपने साथियों के साथ गति बना रहा है, हालांकि, आंतरिक ताकतों में चिह्नित विषमताएं- एचएच की जमा राशि, खपत / व्यय का पैटर्न, प्रयोज्य आय और जनसांख्यिकीय लाभांश, उन्हें चालित कर रही हैं। ऐसे कारकों के अनुभवजन्य महत्व का आकलन करने के लिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स देशों) के लिए विश्व बैंक और बीआईएस डेटाबेस में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अंतर-देशीय विश्लेषण किया गया है।

2.3.1 ब्रिक्स में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घरेलू ऋण और जमाराशि

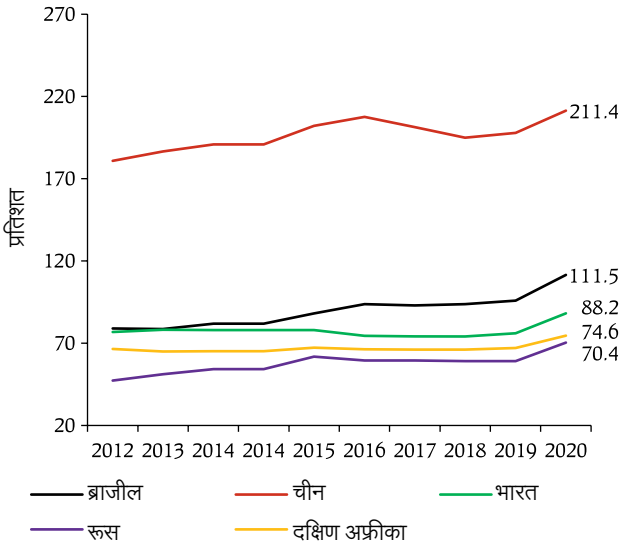
बीआईएस डेटा (चार्ट 5) के अनुसार घरेलू ऋण और जीडीपी का अनुपात चीन की तुलना में भारत में कम है लेकिन ब्रिक्स में अन्य तीन देशों की तुलना में अधिक है। भारत के लिए 2015 के बाद से अनुपात अपेक्षाकृत स्थिर है। 2020 में चीन के

चार्ट 5: जीडीपी की तुलना में घरेलू क्षेत्र के ऋण



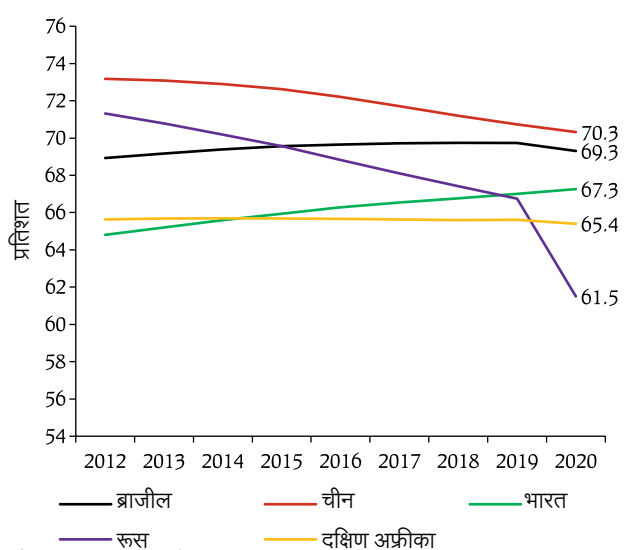
स्रोत: बीआईएस आँकड़े।

चार्ट 6: सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में व्यापक मुद्रा



स्रोत: डेटा कैटलग, विश्व बैंक।

चार्ट 7: कार्यशील आयु जनसंख्या का हिस्सा (डब्ल्यूएपी)



स्रोत: विश्व बैंक और ओईसीडी डाटाबेस।

61.7 प्रतिशत की तुलना में 37.7 प्रतिशत पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण के संबंध में भारतीय स्थिति मध्यम दिखाई देती है, लेकिन 2017 के बाद से दक्षिण अफ्रीका के साथ मेल खाती है। हाल ही में ब्राजील भी भारत के स्तर पर आ गया है।

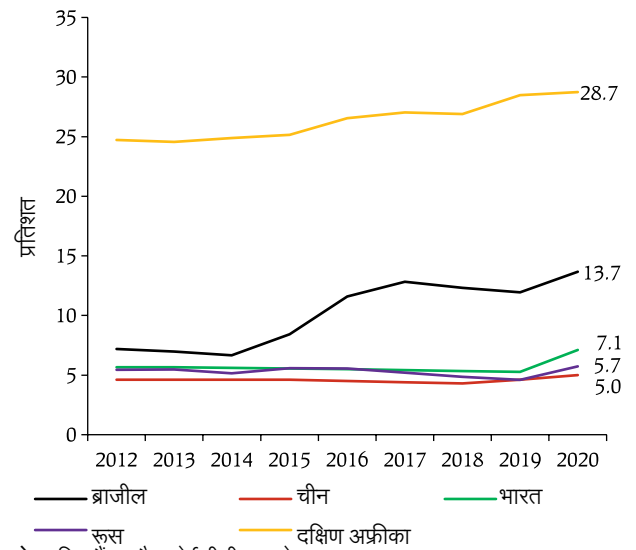
अन्य ब्रिक्स देशों के घरेलू क्षेत्र की जमाराशियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, तरलता के एक प्रॉक्सी उपाय के रूप में, सकल घरेलू उत्पाद के लिए स्थूल मुद्रा[2] के अनुपात पर विचार किया गया है। ब्रिक्स देशों (चार्ट 6) के बीच भारत का, जीडीपी की तुलना में स्थूल मुद्रा अनुपात, मामूली स्तर पर है। भारत में यह अनुपात अपेक्षाकृत स्थिर रहा है जिसे घरेलू क्षेत्र के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के अलावा अपने ऋण चुकाने का स्थिर साधन माना जा सकता है।

2.3.2 ब्रिक्स में कार्यशील आयु की आबादी और बेरोजगारी दर

एचएच की ऋण मांग जनसांख्यिकी पर भी निर्भर हो सकती है, जैसे कुल आबादी में कार्यशील आयु की आबादी[3] (डब्ल्यूएपी) का अनुपात और देश में बेरोजगारी दर। ब्रिक्स देशों में तुलनात्मक स्थिति नीचे चार्ट 7 और 8 में दिखाई गई है।

अन्य ब्रिक्स देशों के विपरीत भारत में कार्यशील आयु की आबादी (डब्ल्यूएपी) का अनुपात बढ़ रहा है और भारत में बेरोजगारी की दर ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में काफी कम है। वर्ष

चार्ट 8: बेरोजगारी दर



स्रोत: विश्व बैंक और ओईसीडी डाटाबेस।

[2] जैसा कि विश्व बैंक द्वारा परिभाषित किया गया है, व्यापक मुद्रा "बैंकों के बाहर मुद्रा का योग है; केंद्र सरकार के अलावा अन्य मांग जमा; केंद्र सरकार के अलावा अन्य निवासी क्षेत्रों का समय, बचत और विदेशी मुद्रा जमा; बैंक और ट्रैवेलर्स चेक; और अन्य प्रतिभूतियां जैसे कि जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र"।

[3] कामकाजी उम्र की आबादी में 15-64 साल (विश्व बैंक और ओईसीडी) के बीच के लोग शामिल हैं।

2012 में, भारतीय डब्ल्यूएपी 64.8 प्रतिशत था जो धीरे-धीरे बढ़कर 2020 में 67.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।

बेरोजगारी दर के साथ डब्ल्यूएपी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए घरेलू क्षेत्र द्वारा ऋण की मांग का विश्लेषण करने के लिए ऋण की पात्रता और बुनियादी जरूरतों के वित्तपोषण के आर्थिक बोझ दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रोजगार की निरंतर दर के साथ डब्ल्यूएपी में वृद्धि से घरेलू क्षेत्र को अपनी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद मिल सकती है।

2.3.3 ब्रिक्स में घरेलू व्यय (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)।

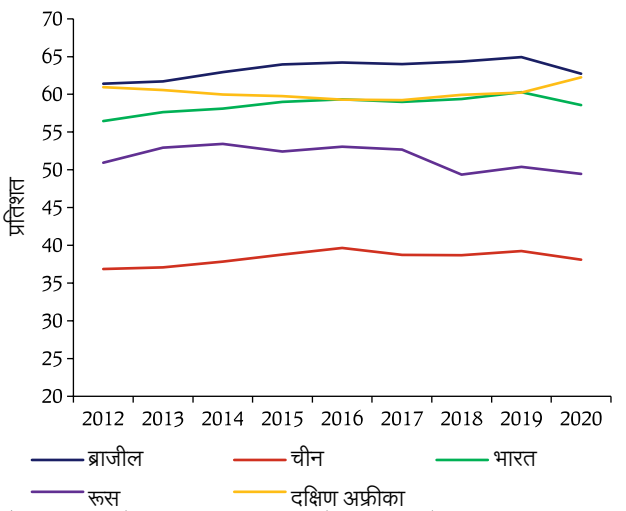
महामारी से पहले की अवधि में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू व्यय ने भारत के लिए अपेक्षाकृत स्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित की है (चार्ट 9)। सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की खपत व्यय का हिस्सा उत्तरोत्तर बढ़ रहा और 2012 में 56.5 प्रतिशत से 2019 में लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंच गया। हालांकि, 2020 में इसमें 58.6 प्रतिशत की तेज गिरावट देखी गई। फिर भी, चीन और रूस की तुलना में भारत में जीडीपी की तुलना में घरेलू व्यय अनुपात अधिक है।

3. घरेलू क्षेत्र उधार: स्थिरता संकेतक

3.1 कुल देशी बचत में घरेलू क्षेत्र का हिस्सा:

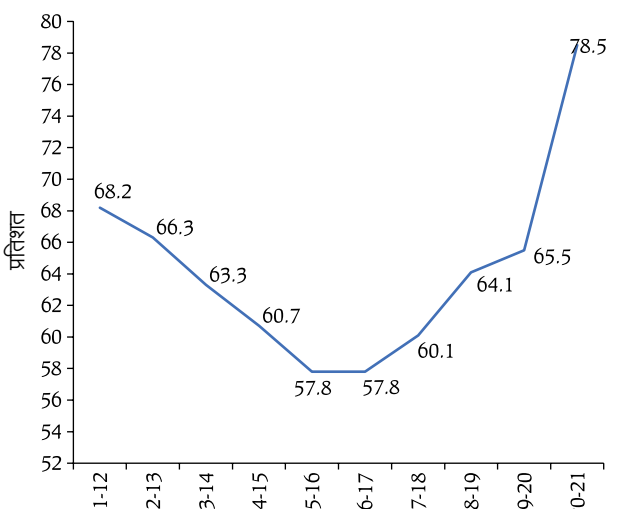
बचत उधार की स्थिरता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि यह संपत्ति के निर्माण में योगदान देता है जिसका उपयोग भविष्य की देनदारियों के निर्वहन के लिए किया जा सकता है। हाल की अवधि में, घरेलू क्षेत्र की देनदारियां बढ़ी हैं और संचित बचत के रूप में उनकी संपत्ति भी बढ़ी है। सकल घरेलू बचत (जीडीएस) में घरेलू बचत की हिस्सेदारी 2011-12 में 68.2 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 57.8 प्रतिशत हो गई, लेकिन उसके बाद 2020-21 में बढ़कर 78.5 प्रतिशत हो गई (चार्ट 10)। 2020-21 (चार्ट 11) में घरेलू क्षेत्र द्वारा कुल बचत में से 46.7 प्रतिशत भौतिक बचत के रूप में और 52.5 प्रतिशत वित्तीय बचत के रूप में है और ये इस क्षेत्र के लिए बचत का सबसे पसंदीदा स्रोत बन गए हैं।

चार्ट 9: जीडीपी की तुलना में घरेलू क्षेत्र का व्यय



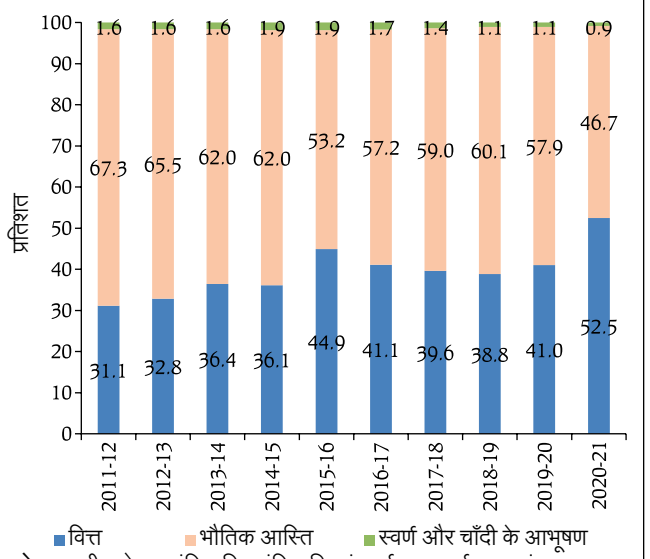
नोट: घरेलू उपभोग व्यय (पूर्व में निजी उपभोग) में हाउसहोल्ड से जुड़े गैर-लाभकारी संस्थानों के व्यय शामिल होते हैं, भले ही संबंधित देश द्वारा अलग से रिपोर्ट किया गया हो।

चार्ट 10: जीडीएस में घरेलू क्षेत्र की बचत का हिस्सा



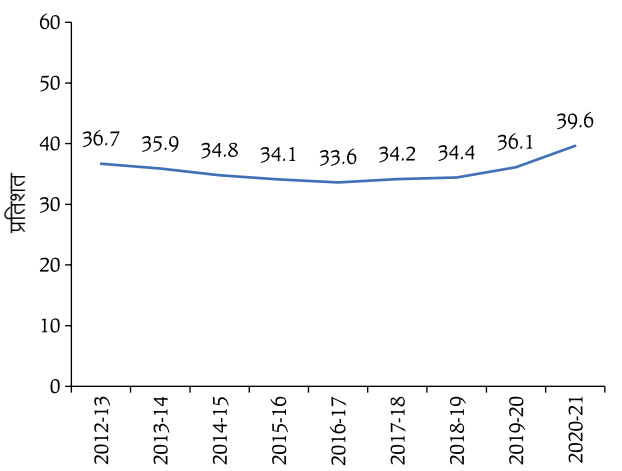
स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट 11: घरेलू क्षेत्र की बचत की संरचना



स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट 13: जीएफए की तुलना में जीएफएल अनुपात



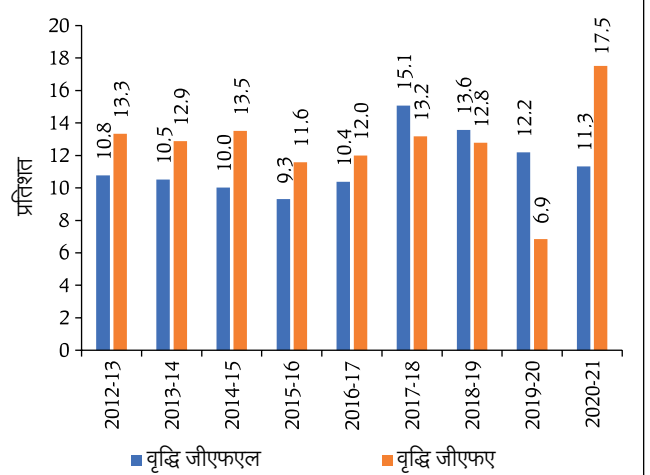
*जीएफएल में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और एचएफसी से ऋण और उधार शामिल हैं; जीएफए में जमाराशि, मुद्राराशि, जीवन बीमा और म्युचुअल फंड शामिल हैं।

स्रोत: निधि खातों का प्रवाह और त्रैमासिक घरेलू वित्तीय बचत (आरबीआई)।

3.2 सकल वित्तीय आस्ति (जीएफए) की तुलना में सकल वित्तीय देयता (जीएफएल) अनुपात:

लीवरेज के लिए परोक्षी के रूप में जीएफए की तुलना में जीएफएल का अनुपात, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बैलेंस शीट की ताकत को मापता है। 2019-20 में, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय देनदारियां उनकी वित्तीय आस्तियों (6.9 प्रतिशत) की तुलना में तेजी से बढ़ीं (12.2 प्रतिशत), जबकि इस क्षेत्र में, 2020-21 में वित्तीय आस्तियां (17.5 प्रतिशत) वित्तीय देनदारियों (11.3 प्रतिशत) से अधिक बढ़ीं (चार्ट 12)। स्टॉक के आधार पर, पिछले दशक के दौरान सकल वित्तीय देनदारियां उनकी सकल वित्तीय आस्ति के 40 प्रतिशत से कम रहीं (चार्ट 13)। साथ ही, घरेलू क्षेत्र को प्रदत्त ऋण का एक बड़ा हिस्सा आवास ऋण (लगभग 50 प्रतिशत) के रूप में है, जिसमें घर अंतर्निहित संपार्श्विक के रूप में काम करता है।

चार्ट 12: घरेलू क्षेत्र के जीएफएल और जीएफए में वृद्धि



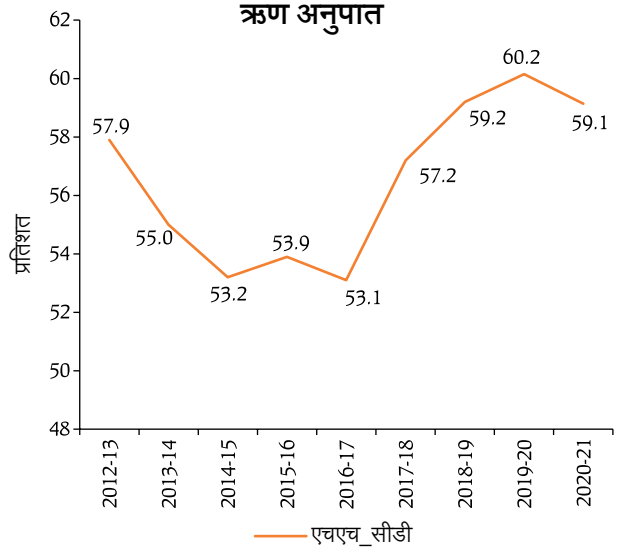
*जीएफएल में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और एचएफसी से ऋण और उधार शामिल हैं; जीएफए में जमाराशि, मुद्रा, जीवन बीमा और म्युचुअल फंड शामिल हैं।

स्रोत: निधि खातों का प्रवाह और त्रैमासिक घरेलू वित्तीय बचत (आरबीआई)।

3.3 जमाराशि की तुलना में घरेलू ऋण अनुपात:

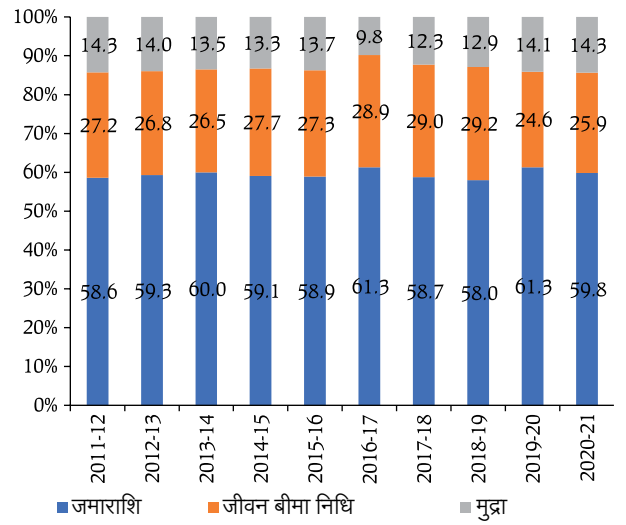
एससीबी के लिए घरेलू देनदारियों और उनके पास उनकी आस्ति को उनके बैंक क्रेडिट के अनुपात में बैंक जमाराशि में शामिल किया जा सकता है। यह अनुपात, क्रेडिट और जमाराशि के बीच असंतुलन; तरलता की उपलब्धता और ऋण पर निर्भरता; और तरलता वरीयताओं में बदलाव और ऋण की मांग के प्रति अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। घरेलू क्षेत्र की बैलेंस शीट में उत्पन्न होने वाले और बैंकिंग क्षेत्र में फैलने वाले किसी भी वित्तीय तनाव के प्रभाव का आकलन करने के लिए यह अनुपात महत्वपूर्ण है। यह अनुपात हाल के वर्षों में लगातार बढ़ रहा है और 2020-21 में 59.1 प्रतिशत तक पहुंच गया है, यह दर्शाता है कि घरेलू क्षेत्र अपने सीडी अनुपात (चार्ट 14) में निरंतर वृद्धि के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र के लिए शुद्ध ऋणदाता बना हुआ है। लगभग 60 प्रतिशत (चार्ट 15) के हिस्से के साथ प्रमुख तीन घटकों (बैंक जमा, जीवन बीमा

चार्ट 14: जमाराशि की तुलना में घरेलू क्षेत्र का ऋण अनुपात



स्रोत: स्रोत: डीबीआईई (आरबीआई) और लेखकों की गणना।

चार्ट 15: घरेलू क्षेत्र की वित्तीय पूंजी के प्रमुख घटक



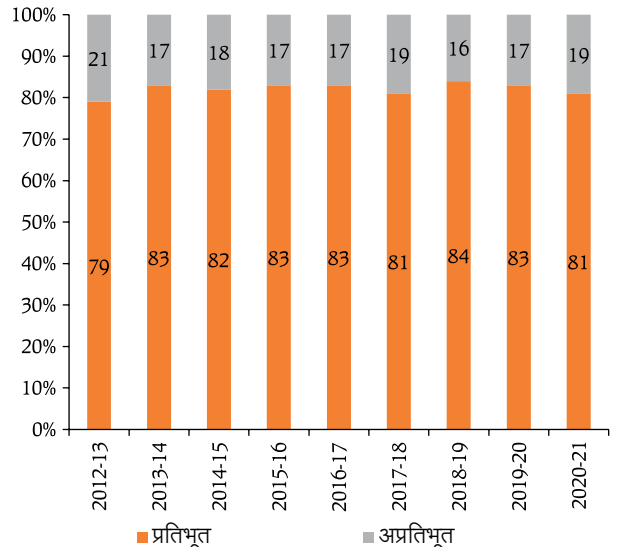
स्रोत: निधि लेखा का प्रवाह (आरबीआई)

निधि और मुद्रा) के बीच बैंक जमाराशि घरेलू बचत का मुख्य रूप है।

3.4 प्रतिभूत-अप्रतिभूत ऋणों और एनपीए की संरचना:

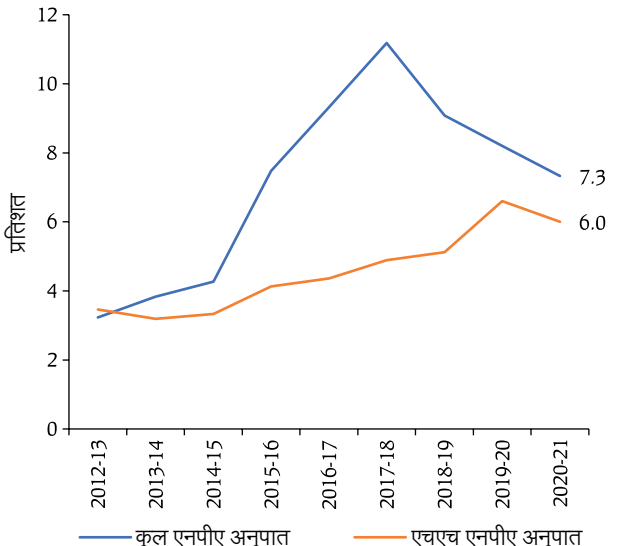
घरेलू देनदारियों का प्रमुख घटक बैंक ऋण है। घरेलू क्षेत्र के क्रेडिट का 4/5 से अधिक हिस्सा सुरक्षित और संपार्श्विक है। 2012-13 में कुल एचएच के क्रेडिट में सुरक्षित ऋण का हिस्सा 79 प्रतिशत था जो 2020-21 में बढ़कर 81 प्रतिशत हो गया (चार्ट 16)। इस क्षेत्र के लिए एनपीए अनुपात हाल के दिनों में 2014-15 में 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 6.6 प्रतिशत हो गया है, लेकिन 2020-21 में घटकर 6 प्रतिशत हो गया है और यह 2020-21 में 7.3 प्रतिशत समग्र एनपीए अनुपात से काफी नीचे गिर रहा है (चार्ट 17)।

चार्ट 16: एससीबी द्वारा प्रदत्त घरेलू क्षेत्र के ऋण की संरचना



स्रोत: बीएसआर1 वार्षिक सर्वेक्षण (आरबीआई) और लेखकों की गणना।

चार्ट 17: एनपीए अनुपात



स्रोत: डीबीआईई (आरबीआई) और लेखकों की गणना।

4. डेटा तैयारी, कार्यविधि और आनुभविक परिणाम

छह कारक अर्थात, भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर), कार्यशील आयु जनसंख्या में परिवर्तन (डब्ल्यूएपी), मुद्रास्फीति (आईएनएफ), जीडीपी की तुलना में घरेलू जमाराशि अनुपात (डीईपी_जीडीपी), पहले लैग में एचएच एनपीए अनुपात (एचएचएनपीए_लैग1), निजी अंतिम खपत जीडीपी अनुपात (एचएच_एक्सपीजीडीपी) के लिए एचएच व्यय के लिए परोक्षी के रूप में व्यय (पीएफसीई) जीडीपी अनुपात को जीडीपी की तुलना में घरेलू ऋण (सीआर_टीओ_जीडीपी) के कोवरियेट्स के रूप में माना जाता है, जो घरेलू क्षेत्र उधार का संकेतक है।

आंकड़े आरबीआई (डीबीआईई) और विश्व बैंक से लिए गए हैं। सभी रिग्रेसर और जीडीपी की तुलना में घरेलू ऋण अनुपात के लिए वार्षिक आँकड़े 2002 - 2021 की अवधि से संबंधित हैं। घरेलू क्षेत्र की वित्तीय देनदारियों के प्रवाह में परिवर्तन का अनुपात इसकी वित्तीय आस्तियों (एचएचएफएल/एफए अनुपात) के लिए लंबे समय - समय - अवधि 1990-2020 - तक उपयोग किया गया है। घरेलू क्षेत्र उधार संकेतक के साथ इन कारकों के संबंध की जांच करने से पहले, जोड़ीवार सहसंबंधों की गणना सभी चरों (सारणी 1, अनुबंध 1) के बीच की जाती है और बहुसंरेखता की समस्या की पहचान की जाती है। नतीजतन, सभी चुने हुए मैक्रो-इकोनॉमिक कारकों को विश्लेषण में रखना मुश्किल था। इसके अलावा, इस समस्या के कारण गुणांकों के अनुमानों में अधिक विचरण हो सकता था और उन्हें अविश्वसनीय भी बना सकता था। इन परिणामों से बचने के लिए, प्रिंसिपल कंपोनेंट रिग्रेशन (पीसीआर) को अध्ययन में नियोजित किया गया है (पहली बार केंडल, 1957 द्वारा सुझाया गया)। इस तकनीक के तहत मूल विचार, प्रमुख घटक विश्लेषण (पीसीए) का उपयोग करते हुए सहसंयोजकों के बीच ऑर्थोगोनलिटी का परिचय देते हुए डेटा के आयाम को कम करना है। वर्तमान अध्ययन में, इसे बिना किसी सूचना क्षय के सभी सहसंयोजकों का उपयोग करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ लागू किया गया है और बहुसंरेखता के कारण भ्रामक आउटपुट से बचा जा सकता है।

4.1 प्रमुख घटक प्रतिगमन (पीसीआर) विश्लेषण

सभी रिग्रेसरों का मूल्यांकन एचएच उधार संकेतक (सीआर टू जीडीपी) के साथ सहसंबद्ध के रूप में किया जाता है। पीसीआर लगाया जाता है और 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण पाया जाता है। यह मॉडल एचएच क्रेडिट और जीडीपी अनुपात (यानी, सीआर_टीओ_जीडीपी) में 80 प्रतिशत से अधिक भिन्नता की व्याख्या करता है। रिवर्स ट्रांसफ़ॉर्मेशन के माध्यम से, मूल प्रतिगमन गुणांक मूल कारकों के अनुरूप प्राप्त होते हैं।

अनुभवजन्य परिणाम बताते हैं कि डब्ल्यूएएलआर नकारात्मक रूप से एचएच के क्रेडिट से जीडीपी अनुपात से संबंधित है क्योंकि उधार लेने की लागत क्रेडिट मांग (एचओ एट अल, 2016) को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की उम्मीद है। घरेलू क्षेत्र ब्याज दरों में बदलाव के लिए अधिक सूक्ष्म है (डेबेल, 2004) और वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के साथ-साथ बढ़ी हुई निजी भागीदारी ने ऋणदाताओं के बीच मजबूत प्रतिस्पर्धा भी पैदा की है, जिससे उन्हें संभावित उधारकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए ऋण पर प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों की पेशकश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है (फुलवारी, 2018)। कामकाजी उम्र की आबादी में बदलाव और मुद्रास्फीति भी एचएच के उधार से विपरीत रूप से संबंधित पाई जाती है। एक स्थिर श्रम बाजार में वैप (ड्ब्ल्यू ए पी) में वृद्धि से एक प्रतिनिधि एचएच में वित्तीय खपत के बोझ को कम करने की उम्मीद है क्योंकि परिवार में अधिक वेतन अर्जक के जुड़ने के बाद इसकी आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा, उच्च मुद्रास्फीति, ब्याज दरों में वृद्धि कर सकती है, इस प्रकार ऋण की मांग को हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन यह एक अल्पकालिक मानदंड है। इसलिए, दोनों कोवरिएट्स में वृद्धि अल्पावधि में ऋण की आवश्यकता को दबा देती है। लैग्ड एनपीए भी निर्भर चर से नकारात्मक रूप से संबंधित हैं क्योंकि एचएच के एनपीए में कमी से उधारदाताओं (बैंकों) को एचएच उधारकर्ताओं की एक विस्तृत शृंखला को अधिक क्रेडिट प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एचएच डिपॉजिट टू जीडीपी और पीएफसीई_टीओ_जीडीपी सकारात्मक रूप से एचएच के क्रेडिट-जीडीपी अनुपात से संबंधित पाए गए हैं। जीडीपी के हिस्से के रूप में जमा (वित्तीय संपत्ति) में वृद्धि को बैंकों के लिए संरचनात्मक तरलता में वृद्धि के रूप में लिया जा सकता है जो अधिक लीवरेज के लिए जगह बनाता है और उपभोग व्यय में वृद्धि ऋण की मांग पैदा करती है।

एचएच उधार संकेतक के अनुमानित मूल्यों की पृष्ठभूमि में मानकीकृत रेसीड्यूअल को प्लॉट कर मॉडल की नैदानिक जांच की जाती है, जो यादृच्छिक रूप से यह दर्शाता है कि मॉडल श्रेष्ठतम आसंजन है।

4.2 स्थिरता विश्लेषण

भेद्यता को पूर्व-मौजूदा स्थितियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक प्रतिकूल झटके (डाहलहॉस और लैम, 2018) के हिट होने पर आर्थिक या वित्तीय संकट/तनाव की घटना को अधिक संभावना बनाते हैं। यह परिभाषा अन्य अकादमिक साहित्य (क्रिस्टेंसन और अन्य, 2015) के अनुरूप है। कई शोधकर्ताओं ने पहले कमजोरियों का आकलन करने के लिए ईएमई का विश्लेषण किया है। उनके दृष्टिकोण अक्सर समान होते हैं, जो आईएमएफ (आईएमएफ, 2002, 2004 और 2011) द्वारा शुरू की गई बैलेंस शीट दृष्टिकोण है। यह आलेख भी इसी विचार को नियोजित करता है लेकिन प्रधान (2018) के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जो 0 से 10 के पैमाने पर भेद्यता सूचकांक की गणना करने और इसकी व्यापक व्याख्या करने के लिए सरल एल्गोरिदम प्रदान करता है। भेद्यता सूचकांक (वीआई) की गणना हमारे अध्ययन के तहत दोनों संकेतकों के लिए की गई है - क्रमशः 2002-2021 और 1990-2020 के दौरान एचएच क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात और एचएचएफएल/ एफए अनुपात (अनुलग्नक 2)। बाद वाला अनुपात एचएच क्षेत्र में असंतुलन के प्रवाह पक्ष का आकलन करने में मदद करता है, यदि कोई हो। पूरी अवधि को अलग-अलग एपिसोड में उपयुक्त रूप से विभाजित किया गया है। विदेशी भुगतान संकट (1990-91 से 1994-95) से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि और 1995-96 से 2001-02 तक की सात साल की अवधि। शेष एपिसोड वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) (2002-03 से 2007-08) से पहले की अवधि, जीएफसी (2008-09 से 2011-12) के दौरान और जीएफसी (2012-13 से 2019-20) के बाद की अवधि का उपयोग करके एचएच एफएल/एचएच एफए अनुपात के लिए बनाए गए हैं। इसी तरह, 2002 से 2021 तक की पूरी अवधि के लिए एचएच क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात (सीआर_टीओ_जीडीपी) तीन एपिसोड के लिए निर्धारित किया गया है: 2002-03 से 2007-08; 2008-09 से 2011-12; और 2012-13 से 2020-21। चूंकि वार्षिक मूल्य महामारी-प्रेरित गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण भेद्यता सूचकांक में अस्थिरता को पूरी तरह से पकड़ने में सक्षम नहीं थे, इसलिए, एचएच उधार संकेतक (सीआर टू जीडीपी) के त्रैमासिक डेटा का उपयोग करके भेद्यता सूचकांक की अतिरिक्त गणना दो परस्पर अनन्य समय अवधियों पर विचार करते हुए की जाती है। पूर्व महामारी के रूप में (दिसंबर 2018 से मार्च 2020) और महामारी के बीच (जून 2020 से सितंबर 2021), प्रत्येक में छह तिमाहियां शामिल हैं।

सारणी 1: एचएच एफएल/ एफए अनुपात के लिए संगणित भेद्यता सूचकांक

अवधि	भेद्यता सूचकांक
1990-91 to 1994-95	5.21
1995-96 to 2001-02	3.36
2002-03 to 2007-08	4.91
2008-09 to 2011-12	4.85
2012-13 to 2019-20	4.81

लेखकों की गणना।

भेद्यता सूचकांक 0 से 10 तक माना जा सकता है। 5 से 10 तक का सूचकांक मूल्य वित्तीय जोखिम / भेद्यता के उच्च स्तर को इंगित करता है, जबकि 0 से 5 तक का मान भेद्यता की अनुपस्थिति को निर्दिष्ट करता है। नवीनतम अवधि के लिए दोनों भेद्यता सूचकांक (वार्षिक डेटा के आधार पर) 5 से कम थे, यह संकेत देते हैं कि भारत में एचएच उधार किसी भी स्थिरता संबंधी चिंताओं का संकेत नहीं देते हैं। वास्तव में, 1990-91 से 1994-95 की अवधि के अलावा, वित्तीय संपत्तियों के लिए एचएच वित्तीय देनदारियों के लिए भेद्यता सूचकांक हमेशा 5 से कम रहा है, यह दर्शाता है कि एचएच उधार आम तौर पर टिकाऊ रहे हैं (सारणी 1)। विदेशी भुगतान संकट के बाद के प्रकरण (1995-96 से 2001-02) के दौरान सूचकांक का मूल्य सबसे कम था। जीएफ़सी (2008-09 से 2011-12) की अवधि के दौरान, 4.85 पर सूचकांक मूल्य ने एचएच क्षेत्र के लिए कोई भेद्यता उत्पन्न नहीं की। महामारी के दौरान भेद्यता सूचकांक (तिमाही डेटा के आधार पर) 4.76 था, इस प्रकार यह अविचलित स्थिरता (सारणी 2) का संकेत देता है।

सारणी 2: सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में घरेलू क्षेत्र ऋण अनुपात के लिए संगणित भेद्यता सूचकांक

अवधि	भेद्यता सूचकांक
2002-03 to 2007-08	4.89
2008-09 to 2011-12	4.86
2012-13 to 2020-21	4.66
तिमाही आंकड़ों पर आधारित	
पूर्व-महामारी (दिसंबर-18 से मार्च-20)	4.96
महामारी के बीच (जून-20 से सितंबर-21)	4.76

लेखकों की गणना।

5. उपसंहार

इस पेपर में भारत में हाउसहोल्ड के उधार लेने की प्रवृत्ति की पड़ताल की गई ताकि यह समझा जा सके कि कौन से कारक घरेलू उधार को निर्धारित करते हैं और साथ ही कुल आर्थिक झटकों के कारण तनाव की अवधि के दौरान इसकी स्थिरता की जांच की गई। हमारे नतीजे बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी की तुलना में घरेलू ऋण के अनुपात में वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद और निजी अंतिम उपभोग व्यय की तुलना में घरेलू जमाराशि का अनुपात धनात्मक रूप से सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में घरेलू ऋण के अनुपात से संबद्ध पाया गया है, जबकि उधार दर, मुद्रास्फीति, पुराने एनपीए और कार्यशील आयु की आबादी में वृद्धि इसके साथ ऋणात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। स्थिरता सूचकांक से पता चलता है कि महामारी जैसे तनावपूर्ण समय सहित पिछले तीन दशकों में भारतीय परिवारों की उधारी स्थायी स्तरों के भीतर रही।

संदर्भ

Christensen, *et al.* (2015), "Assessing vulnerabilities in the Canadian financial system", *Bank of Canada, Financial system review,* June 2015.

Dahlhaus, T. and Lam, A. (2018), "Assessing Vulnerabilities in Emerging – Market Economies", Bank of Canada Staff Discussion Paper 2018-13, October 2018.

Debelle, G. (2004). Macroeconomic implications of rising household debt. BIS Quarterly Review, 3(153), 51–64. Retrieved from October 7, 2020.

De Vaney, S. A. and Lytton, R. H. (1995)," Household Insolvency: A review of household debt repayment, Delinquency and bankruptcy", *Financial Services review,* 4(2):137-156.

Fulwari, A. (2018), "A review of literature on the determinants of the demand for home loans", *International education and research journal, E-ISSN No: 2454-9916 | Volume: 4 | Issue: 4 | April 2018.*

Ho, S. F. C., Yusof, J. M., & Mainal, S. A. (2016). Household debt, macroeconomic fundamentals and household characteristics in Asian developed and developing countries. The Social Science, 11(18), 4358–4362

IMF (2002), "A Balance Sheet Approach to Financial Crisis", *Policy development and Review Department,* IMF, December 2002.

IMF (2004), "Debt-Related Vulnerabilities and Financial Crises—An Application of the Balance Sheet Approach to Emerging Market Countries", *Policy development and Review Department,* IMF, July 2004.

IMF (2011), "Managing Volatility: A Vulnerability Exercise for Low-Income Countries", *Policy development and Review Department,* IMF, Mar 2011.

Kendall, M. G. (1957), "A Course in Multivariate Analysis", Hafner, NY.

Leigh, D. *et al* – IMF (2012), "Dealing with HH debt", *World Economic outlook: Growth resuming, Dangers remain,* Ch 3, April 2012.

Meniago, C. *et al (2013),* "What causes household debt to increase in South Africa*", Economic Modelling, 33* (2013) 482-492.

Pradhan, K. (2018), "Assessment of India's Fiscal and External Sector Vulnerability: A Balance Sheet Approach", *The Journal of Applied Economic Research*, 12: 3 (2018): 308–332 Sage Publications Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/Washington DC/Melbourne; DOI: 10.1177/0973801018768988

Ramadorai, P. (2017)," Indian HH Finance", *Committee report,* Jul 2017.

Samad, K.A. *et al.* (2020), "Determinants of household debt in emerging economies: A macro panel analysis", Cogent Business & Management, 7: 1831765 (2020):1-14.

SBI (2021), "FY21 GDP estimates at -8% may see upward revision: FY22 deposit growth of banking system reveals periods of alternate expansion & contraction", *ECOWRAP,*13 (2021), pg 1-3.

Zabai, A. (2017), "HH Debt: recent developments and challenges", *BIS quarterly review,* Dec 2017.

अनुबंध 1

पीसीआर को लागू करने से पहले जोड़ीवार सहसंबंधों का मूल्यांकन किया जाता है और इसे निम्नलिखित मैट्रिक्स में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1 - सहसंबंध

	सीआर_टीओ_जीडीपी	एचएचएनपीए_एलएजी1	डब्ल्यूएएलआर	एचएच_ईएक्सपीजीडीपी	आईएनएफ	डब्ल्यूएपी	डीईपी_ जीडीपी
सीआर_टीओ_जीडीपी	1						
एचएचएनपीए_एलएजी1	-0.619	1					
डब्ल्यूएएलआर	-0.834	0.513	1				
एचएच_ईएक्सपीजीडीपी	0.321	0.833	0.302	1			
आईएनएफ	-0.184	-0.506	0.128	-0.659	1		
डब्ल्यू ए पी	-0.379	-0.119	0.497	-0.301	0.449	1	
डीईपी_ जीडीपी	0.874	-0.564	-0.825	-0.347	0.375	-0.267	1

प्रमुख घटक प्रतिगमन (पीसीआर) – पद्धति :

रैखिक प्रतिगमन मॉडल

$$Y = \beta X + €,$$

जहां वाई निर्भर चर पर टिप्पणियों का वेक्टर है, एक्स स्वतंत्र टिप्पणियों का मैट्रिक्स है, β प्रतिगमन गुणांक का वेक्टर है और € त्रुटियों का वेक्टर है।

पहला कदम चर को मानकीकृत करना है, दोनों निर्भर और स्वतंत्र चर।

पीसीआर करने के लिए, हम स्वतंत्र चर को उनके प्रमुख घटकों में बदल देते हैं।

गणितीय रूप से हम लिखते हैं

$$X'X = PDP' = Z'Z,$$

जहां D, X'X के आइजिन मानों का विकर्ण मैट्रिक्स है, P, X'X का आइजिनवेक्टर मैट्रिक्स है, और Z एक डेटा मैट्रिक्स (संरचना में X के समान) है जो प्रमुख घटकों से बना है। P ऑर्थोगोनल है ताकि P'P = I हो।

हमने मूल चर एक्स के भारित औसत के रूप में नए चर जेड बनाए हैं। यदि हम चर X1, X2 और X3 के साथ शुरू करते हैं, तो हम Z1, Z2 और Z3 के साथ समाप्त होंगे। चूंकि ये नए चर प्रमुख घटक हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ उनके सहसंबंध सभी शून्य हैं। गंभीर बहुसंयोजकता का पता बहुत छोटे आइजिन मूल्यों द्वारा लगाया जाएगा। मल्टीकोलिनियरिटी के डेटा से छुटकारा पाने के लिए, हम छोटे आइजिन मूल्यों से जुड़े घटकों (जेड) को छोड़ देते हैं। आमतौर पर, केवल एक या दो अपेक्षाकृत छोटे आइजिन मान प्राप्त किए जाएंगे।

उदाहरण के लिए, यदि तीन स्वतंत्र चर के साथ समस्या पर केवल एक छोटे आइजेन मान का पता लगाया गया था, तो हम जेड 3 (तीसरा प्रमुख घटक) को छोड़ देंगे। जब हम Z1 और Z2 पर Y को वापस करते हैं, तो मल्टीकोलिनियरिटी अब कोई समस्या नहीं है। फिर हम β के अनुमान प्राप्त करने के लिए अपने परिणामों को एक्स स्केल पर वापस बदल सकते हैं। इन अनुमानों की औसत वर्ग त्रुटि कम से कम वर्गों की तुलना में कम है।

गणितीय रूप से, अनुमान सूत्र बन जाता है:

$$\hat{\alpha} = (Z'Z)^{-1} Z'Y = D^{-1} Z'Y.$$

यह साधारण लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेसन है जो स्वतंत्र चर के अलग प्रकार पर लागू है। रिग्रेसन कोफिसियेंट के ये दो सेट α और β फार्मुला $\hat{\alpha} = P'\hat{\beta}$ and $\hat{\beta} = P\hat{\alpha}$ का उपयोग करता है। एक प्रमुख घटक को छोड़ना, संबंधित एलिमेंट को सेट करके α को शून्य के बराबर करने से पूरा किया जा सकता है। इसलिए, प्रमुख घटक प्रतिगमन को निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता है:

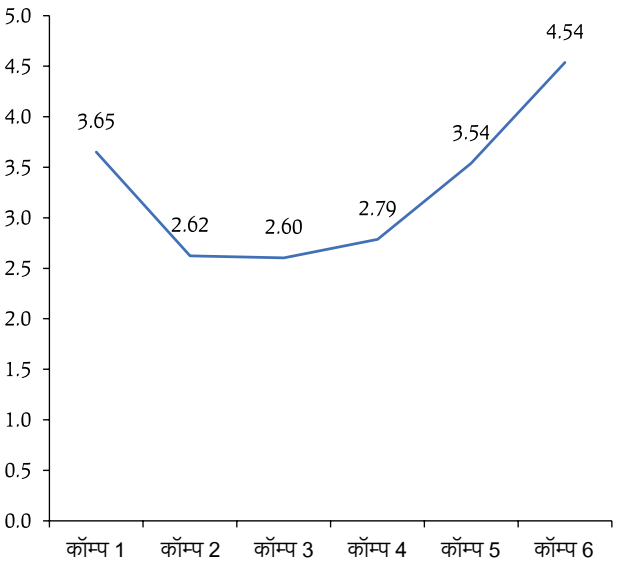
X मैट्रिक्स के एक प्रमुख घटक विश्लेषण को पूरा करें और Z में प्रमुख घटकों को बचाएं। Z पर Y के प्रतिगमन को □ का कम से कम वर्ग अनुमान प्राप्त करें। α के अंतिम एलिमेंट को शून्य के बराबर सेट करें।

$\hat{\beta} = P\hat{\alpha}$ का उपयोग करके मूल गुणांक में वापस बदलें।

परिणाम:

डेटा (प्रतिगामी) के ऑर्थोगोनल सेट प्राप्त करने के लिए प्रमुख घटक विश्लेषण किया जाता है। तीन घटक पीसी 1, पीसी 2 और पीसी 3 ने एक साथ डेटा सेट में 90% से अधिक भिन्नता

ग्राफ 1: आरएमएसईपी



की व्याख्या की। केवल तीन घटकों की पसंद को पूर्वानुमान की मूल माध्य वर्ग त्रुटि (आरएमएसईपी) का उपयोग करके क्रॉस मान्य किया जाता है (नीचे ग्राफ 1 देखें)। आरएमएसईपी घटक 3 (यानी कॉम्प 3) तक घट रहा है और फिर यह बढ़ने लगता है। इसलिए, केवल पहले तीन घटक चुने जाते हैं। चुने हुए घटकों का उपयोग करते हुए, छह कॉवरिएट्स के डेटा को तीन चर के साथ नए डेटा सेट में बदल दिया जाता है जो एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल होते हैं। वी 1, वी 2 और वी 3 (नए प्रतिगामी) पर जीडीपी के लिए एचएच क्रेडिट के लिए रैखिक प्रतिगमन चलाया जाता है।

पीसीआर को महत्व के 5% स्तर पर महत्वपूर्ण पाया जाता है। रिवर्स परिवर्तन प्रत्येक मूल चर के अनुरूप प्रतिगमन गुणांक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और ट्रांसफॉर्म्ड रिग्रेशन मॉडल जीडीपी में एचएच क्रेडिट में 80.32 प्रतिशत भिन्नता की व्याख्या कर सकता है।

सारणी 2: प्रतिगमन परिणाम

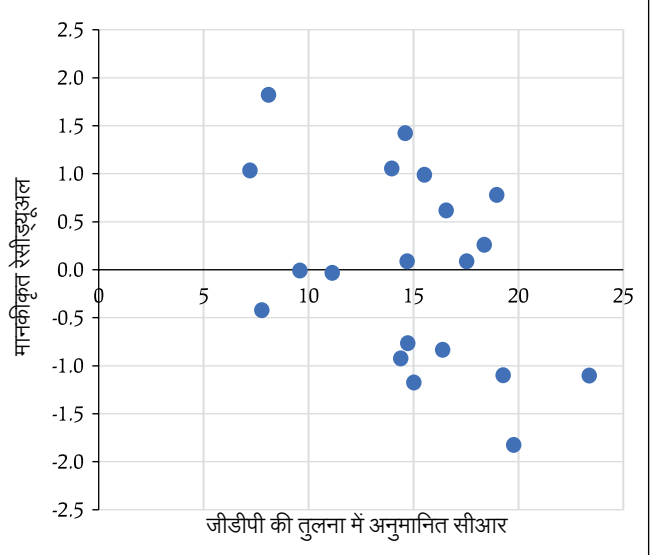
प्रतिगामी	प्रतिगमन गुणांक	प्रतिगमन के आंकड़े	
V1	-3.416	F (3,17)	278.36
V2	-5.264	*p* value	0.0355
V3	-1.057	समायोजित R-स्क्वेयर	0.8032

अंत में, निम्नलिखित प्रतिगमन मॉडल प्राप्त किया जाता है:

वाई = -1.713*डब्ल्यूएएलआर -1.097*ड्ब्ल्यूएपी - 0.292*आईएनाएफ + 1.687*डीईपी_जीडीपी - 0.69*एचएच एनपीए_एलएजी1 + 0.24* एचएच ईएक्सपी_जीडीपी

एप्लाईड पीसीआर की नैदानिक जांच पर भी काम किया जाता है। पीसीआर के सत्यापन के लिए, अनुमानित वाई मानों के खिलाफ मानकीकृत अवशिष्ट के प्लॉट का उपयोग किया जाता है और यादृच्छिक पाया जाता है जो पीसीआर अध्ययन को वैध ठहराता है।

ग्राफ 2: मानकीकृत रेसीड्यूअल बनाम अनुमानित मूल्य



अनुबंध- 2

स्थिरता विश्लेषण की पद्धति:

VI की गणना के लिए अंतर्निहित पद्धति निम्नानुसार है: प्रत्येक संकेतक के लिए पूरी अवधि को 5-10 वर्षों के छोटे और प्रासंगिक एपिसोड में उपयुक्त रूप से विभाजित करें। VI का निर्माण करने के लिए, प्रत्येक संकेतक के तहत सभी अवलोकन X_i को नए Z स्कोर में मानकीकृत किया जाता है –

$$Z_i = \frac{(X_i - \mu)}{\sigma}$$

जहां μ और σ एपिसोड के दौरान एक्स का औसत और मानक विचलन है। शून्य के करीब एक z-स्कोर इंगित करता है कि एक संकेतक औसत के करीब है। एक उच्च सकारात्मक मूल्य का अर्थ है खराब प्रदर्शन। प्रत्येक संकेतक के लिए सूचकांक प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक एपिसोड के दौरान z स्कोर को सामान्य वितरण के संचयी वितरण फ़ंक्शन में बदल दिया जाता है और इसे इतना स्केल किया जाता है कि मान 5 के औसत स्कोर के साथ केवल 0-10 के बीच हो सकते हैं। अंत में, VI प्रत्येक एपिसोड के लिए इन मूल्यों के भारित औसत को लेकर प्राप्त किया जाता है। 5 से 10 तक का सूचकांक उच्च स्तर के वित्तीय जोखिम / भेद्यता की उपस्थिति को इंगित करता है।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक शृंखला

विषय-वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	209
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	210
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	211
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	212
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	213
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	213
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	214
7	मुद्रा स्टॉक ($एम_3$) के स्रोत	215
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	216
9	कुल चलनिधि राशियां	216
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	217
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	217
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	218
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	218
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	219
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	220
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	221
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	222
	कीमत और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	223
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	223
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	223
21	थोक मूल्य सूचकांक	224
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	228
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	228
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	229
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	229
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	230
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	231
28	वाणिज्यिक पत्र	231
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	231
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	232

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	233
32	विदेशी मुद्रा भंडार	233
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	233
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	234
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	234
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	235
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	236
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	237
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	238
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	239
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	240
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	241
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	242
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	244
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	245
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	246
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	247
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	248
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	249
50 (ए)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार	250
50 (बी)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक	253

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2021-22	2020-21	2021-22		2022-23
		ति4	ति1	ति4	ति1
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	8.1	5.7	18.1	3.9	12.7
1.1.1 कृषि	3.0	2.8	2.2	4.1	4.5
1.1.2 उद्योग	9.8	11.6	40.4	1.0	6.0
1.1.3 सेवाएं	8.8	4.3	15.5	5.0	17.5
1.1ए अंतिम खपत व्यय	7.0	9.6	10.2	2.3	21.3
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	15.8	10.1	62.5	5.1	20.1
	2021-22	**2021**		**2022**	
		जुला.	अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	11.4	11.5	13.0	2.4	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	8.9	9.8	9.5	9.2	9.5
2.1.2 ऋण	9.6	6.1	6.7	14.5	15.5
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9.7	6.2	6.7	15.1	16.0
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	6.0	8.2	5.3	8.0	10.3
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	13.0	16.8	15.2	11.3	10.3
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	8.8	9.9	9.5	8.6	8.9
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.50	4.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.7	5.0	4.8	5.6	5.1
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.2	70.2	70.2	72.9	73.3
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	77.2	-8.9	-12.9	94.3	107.3
3.6 निवेश-जमा अनुपात	28.7	29.9	29.6	29.5	29.8
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	19.7	41.6	32.3	56.3	64.0
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.00	4.00	4.90	5.40
4.2 रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) दर*	-	-	-	4.65	5.15
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.25	4.25	5.15	5.65
4.5 आधार दर	4.25	4.25	4.25	5.15	5.65
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.25/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.75/8.80	7.75/8.80
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.45/7.00	6.55/7.00	6.55/7.00	6.70/7.50	6.80/7.65
4.8 बचत जमा दर	5.00/5.60	4.90/5.50	4.90/5.50	5.30/5.75	5.30/6.10
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	3.34	3.21	3.19	5.04	5.10
4.11 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	3.84	3.39	3.30	5.62	5.63
4.12 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	4.27	3.53	3.45	5.98	6.09
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	4.58	3.73	3.65	6.33	6.32
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ	6.86	6.22	6.27	7.32	7.17
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	76.18	74.39	74.13	79.42	79.91
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.01	88.39	87.20	81.17	79.62
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमिआ1-माह (%)	5.67	3.55	3.40	3.32	3.30
3-माह (%)	4.46	3.82	3.56	3.35	3.20
6-माह (%)	4.10	4.01	3.76	3.20	3.00
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.51	5.6	5.3	6.7	7.0
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.13	5.3	4.8	5.8	5.9
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	12.97	11.6	11.6	13.9	12.4
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	10.25	6.3	5.9	15.0	14.9
6.3.2 ईंधन और पावर	32.50	27.0	28.2	43.8	33.7
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	11.10	11.5	11.6	8.2	7.5
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	55.43	62.0	53.0	43.6	37.3
7.2 निर्यात	44.62	49.7	46.3	8.2	1.6

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

*: 8 अप्रैल 2022 दिनांकित प्रेस अधिसूचना सं.2022-2023/41के अनुसार।

#: 3 दिसंबर, 2021 से सभी पखवाड़ों के लिए बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2021-22	2021	2022				
		सितं.	सितं. 2	सितं. 9	सितं. 16	सितं. 23	सितं. 30
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3107637	2897815	3153398	3165151	3149963	3138282	3129317
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	15	15	11	13	11	13	12
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**3107652**	**2897829**	**3153409**	**3165163**	**3149974**	**3138295**	**3129329**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	128208	109138	115862	116586	115421	116022	115506
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2978927	2788032	3037228	3048294	3034297	3021854	3013438
1.2.3 रुपया सिक्का	518	659	319	284	256	419	385
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	–	–	–	–	–	–	–
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1794574	2097054	1485945	1460049	1474989	1469091	1457197
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	101	100	101	100	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	683437	638826	799726	779186	771796	767171	844913
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7123	7014	7716	7741	8060	7742	8247
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4121	3431	4363	4392	4272	4242	4176
2.1.1.7 अन्य बैंक	37589	38104	43326	42880	43341	43396	43949
2.1.1.8 अन्य	988819	1361253	564729	555600	580835	571142	474310
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	73343	48283	65941	70107	66543	75256	81458
2.1.2 अन्य देयताएं	1359254	1317715	1261541	1262074	1220705	1230814	1296275
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**3153828**	**3414769**	**2747486**	**2722123**	**2695695**	**2699905**	**2753473**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	15	15	11	13	11	12	12
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1243853	1491512	915949	874477	858358	869096	859889
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.2 राज्य सरकारें	670	7976	8776	15914	6178	6515	5611
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	94299	92382	96364	96337	107717	103965	112521
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–	35	–	–	–	–	35
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.6 नाबार्ड	24927	21830	4534	4534	4534	4534	4554
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.8 अन्य	8077	3757	27858	27858	31228	27575	16828
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	72741	44669	64790	69256	65811	74479	79217
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	–	–	–	–	–	–	–
2.2.5 निवेश	1491042	1578893	1431576	1434212	1424097	1414112	1415818
2.2.6 अन्य आस्तियां	218203	173701	197628	199522	197761	199615	258988
2.2.6.1 स्वर्ण	201354	166849	189792	190978	189070	190785	190458

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	बाज़ार स्थिरीकरण योजना		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अग. 1, 2022	-	-	-	-	1079	215676	–	185	-	-214782
अग. 2, 2022	-	-	-	-	1307	286943	-1141	675	-	-287452
अग. 3, 2022	-	-	-	-	1695	277871	-1500	510	-	-278186
अग. 4, 2022	-	-	-	-	1518	299271	1444	-	-	-296309
अग. 5, 2022	-	-	-	-	1295	255858	–	1385	-	-255948
अग. 6, 2022	-	-	-	-	3252	22648	–	-	-	-19396
अग. 7, 2022	-	-	-	-	137	3809	–	-	-	-3672
अग. 8, 2022	-	-	-	-	1523	175249	-7500	-	-	-181226
अग. 9, 2022	-	-	-	-	2203	40813	–	-	-	-38610
अग. 10, 2022	-	-	-	45530	1715	200045	-109	-	-	-243969
अग. 11, 2022	-	-	-	-	1905	211305	-160	-	-	-209560
अग. 12, 2022	-	-	-	22225	2786	129659	–	1115	-	-150213
अग. 13, 2022	-	-	-	-	729	4753	–	-	-	-4024
अग. 14, 2022	-	-	-	-	10	1159	–	-	-	-1149
अग. 15, 2022	-	-	-	-	60	3023	–	-	-	-2963
अग. 16, 2022	-	-	-	-	4580	50175	–	-	-	-45595
अग. 17, 2022	-	-	-	-	2315	155566	–	905	-	-154156
अग. 18, 2022	-	-	-	-	1595	183520	–	690	-	-182615
अग. 19, 2022	-	-	-	-	1681	125180	7400	250	-	-116349
अग. 20, 2022	-	-	-	-	516	39886	–	-	-	-39370
अग. 21, 2022	-	-	-	-	12	4365	–	-	-	-4353
अग. 22, 2022	-	-	-	-	2107	107279	–	-	-	-105172
अग. 23, 2022	-	-	-	-	2590	135686	–	-	-	-133096
अग. 24, 2022	-	-	-	-	2490	132406	-245	-	-	-130161
अग. 25, 2022	-	-	-	-	1561	144918	–	555	-	-143912
अग. 26, 2022	-	-	-	70331	4034	112050	–	-	-	-178347
अग. 27, 2022	-	-	-	-	45	5626	–	-	-	-5581
अग. 28, 2022	-	-	-	-	11	3329	–	-	-	-3318
अग. 29, 2022	-	-	-	-	3113	112464	-5000	465	-	-114816
अग. 30, 2022	-	-	-	-	2176	74466	–	-	-	-72290
अग. 31, 2022	-	-	-	-	2678	50988	–	-	-	-48310

एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा, एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेन्ट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2021-22	2021	2022	
		अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	17312	3747	-19049	-4254
1.1 क्रय (+)	113991	10887	19721	18858
1.2 विक्रय (-)	96679	7140	38770	23112
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	134629	28895	-152265	-35606
3 संचयी (मार्च के के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	17312	39639	-18802	-23056
(करोड़ ₹)	134629	297464	-152816	-188422
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	65791	49606	22019	20164

ii) मुद्रा वायदा भाग में परिचालन

मद	2021-22	2021	2022	
		अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	2370	560	1695	650
1.2 विक्रय (-)	2370	560	1695	650
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0	0	0	-150

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 अग. 2022 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	7365	15599	-8234
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	12311	2774	9537
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	8726	0	8726
4. 1 वर्ष से अधिक	10135	0	10135
कुल (1+2+3+4)	**38537**	**18373**	**20164**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2021-22	2021	2022					
		सितं. 24	अप्रै. 22	मई 20	जून 17	जुला. 29	अग. 26	सितं. 23
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	11	152	140	1009	7	139	4034	9657
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	–	0	0	0	0	1655	0	910
4. अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	32401	25396	31021	35521	49364	40314	40159	31039
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32412	25548	31161	36530	49371	42108	44193	41606

टिप्पणीः 1. अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा अर्थात एक्ज़िम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू /एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2021-22	2021	2022		
		अग. 27	जुला. 29	अग. 12	अग. 26
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3035689	2830825	3063746	3092123	3062479
1.1 संचलन में नोट	3105703	2916737	3156104	3185355	3154428
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	27270	26467	27868	27868	28048
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	98028	113121	120969	121843	120740
2 जनता की जमाराशियां	2271436	1972356	2240452	2173476	2221176
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	2212992	1926200	2183209	2116527	2163987
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	46156	57244	56949	57189
3 एम$_1$ (1 + 2)	**5307125**	**4803182**	**5304199**	**5265599**	**5283655**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	187061	174689	187061	187061	187061
5 एम$_2$ (3 + 4)	**5494186**	**4977871**	**5491260**	**5452660**	**5470716**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	15186605	14527245	15728149	15770249	15767768
7 एम$_3$ (3 + 6)	**20493729**	**19330427**	**21032348**	**21035847**	**21051423**
8 कुल डाकघर जमाराशियां	1008539	922935	1008539	1008539	1008539
9 एम$_4$ (7 + 8)	**21502268**	**20253362**	**22040887**	**22044386**	**22059962**

सं. 7: मुद्रा भंडार ($एम_3$) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		अग. 27	जुला. 29	अग. 12	अग. 26
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**6477629**	**6079314**	**6408664**	**6513767**	**6471313**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1450596	1191232	1098524	1140114	1103484
1.1.1 सरकार पर दावे	1490991	1578932	1444172	1443640	1437305
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1489324	1575852	1438088	1437497	1432494
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1667	3080	6083	6142	4811
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	40394	387700	345648	303526	333820
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	40352	387658	345606	303483	333778
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	5027033	4888082	5310141	5373653	5367829
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**12616520**	**11610171**	**13116787**	**13165715**	**13206634**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	16571	8616	34706	25810	32969
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	12599950	11601555	13082081	13139905	13173665
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	11891314	10897601	12369350	12425718	12458658
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	690201	686084	695813	697652	698350
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18435	17871	16918	16535	16657
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**4854063**	**4857809**	**4805020**	**4799313**	**4735246**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4442479	4514459	4393436	4387729	4323662
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4442720	4514703	4393676	4387970	4323902
3.1.2 विदेशी देयताएं	241	244	240	240	240
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	411583	343350	411583	411583	411583
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**28013**	**27210**	**28611**	**28611**	**28791**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**3482496**	**3244077**	**3326734**	**3471558**	**3390561**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1308500	1316710	1332885	1353728	1309430
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	2173996	1927368	1993849	2117830	2081132
$एम_3$ (1+2+3+4-5)	**20493729**	**19330427**	**21032348**	**21035847**	**21051423**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		अग. 27	जुला. 29	अग. 12	अग. 26
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	5307125	4803182	5304199	5265599	5283475
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	12081049	11274247	12322838	12302367	12318768
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	20634885	19421406	21254776	21380171	21386969
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3035689	2830825	3063746	3092123	3062299
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	17266157	16306345	17780186	17753788	17797971
1.2.1 मांग जमाराशियां	2212992	1926200	2183209	2116527	2163987
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	15053166	14380144	15596977	15637262	15633984
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6773925	6471065	7018640	7036768	7035293
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	176718	64693	176718	229249	229249
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	8279241	7909079	8578338	8600494	8598691
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	46156	57244	56949	57189
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	274594	238080	353600	477310	469509
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	20080599	18691441	20597841	20760283	20793478
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	6477629	6079314	6408664	6513767	6471313
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1450596	1191232	1098524	1140114	1103484
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	5027033	4888082	5310141	5373653	5367829
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	13602969	12612127	14189177	14246516	14322165
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	39581	25388	44374	35517	42676
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13563389	12586739	14144802	14210999	14279489
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	952181	976083	1047900	1055263	1089302
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27210	28611	28611	28611
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4705191	4772483	4598008	4585262	4533815
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4514459	4393436	4387729	4323662
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	262711	258025	204572	197533	210153
2.4 पूंजी खाता	3021858	2962739	3155746	3327259	3294575
2.5 अन्य मदें (निवल)	1157060	1106989	813938	666726	674361

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2021-22	2021	2022		
		अग.	जून	जुला.	अग.
	1	2	3	4	5
1 एन एम$_3$	**20630753**	**19421406**	**20907432**	**21254776**	**21386969**
2 डाकघर जमाराशियां	594633	543748	594633	594633	594633
3 एल$_1$ (1 + 2)	**21225386**	**19965154**	**21502065**	**21849409**	**21981602**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	49578	25923	51690	52881	24000
4.1 सावधि मुद्रा उधार	1824	4244	2136	1924	1654
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	39170	16775	41045	43145	20143
4.3 सावधि जमाराशियां	8584	4905	8509	7812	2203
5 एल$_2$ (3 + 4)	**21274964**	**19991078**	**21553755**	**21902290**	**22005602**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	66542	..	66542	..	..
7 एल$_3$ (5 + 6)	**21341506**	..	**21620297**	..	..

टिप्पणी : संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		अग. 27	जुला. 29	अग. 12	अग. 26
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3133716	2943946	3184715	3213966	3183039
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	876726	689090	892045	866978	819173
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	823632	641437	834457	809848	764114
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	46156	57244	56949	57189
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4068887	3679192	4134003	4137893	4059401
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	906895	454233	1044841	1075281	1016557
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	1450596	1191232	1098524	1140114	1103484
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1448972	1188194	1092483	1134014	1098716
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	–	–	–	–	–
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1488816	1575132	1437624	1437097	1432149
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1488816	1575132	1437624	1437097	1432149
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	508	720	465	401	345
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	40352	387658	345606	303483	333778
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1624	3038	6041	6100	4768
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-583282	-762387	-98057	-100350	-129603
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-560272	-745615	-88389	-90643	-119896
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	39581	25388	44374	35517	42676
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	–	–	1655	245	–
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	23010	16772	9668	9707	9707
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27210	28611	28611	28611
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4514459	4393436	4387729	4323662
2.3.1 सोना	322213	275932	314274	323525	316599
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4120283	4238544	4079180	4064222	4007081
2.4 पूंजी खाता	1254092	1212280	1387980	1422812	1390128
2.5 अन्य मदें (निवल)	54408	104429	-55096	-69084	-80698

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2021-22	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2021	2022				
		अग. 27	जुला. 29	अग. 5	अग. 12	अग. 19	अग. 26
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4068887	3679192	4134003	4110790	4137893	4123793	4059581
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3133716	2943946	3184715	3194996	3213966	3197449	3183219
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	876726	689090	892045	856403	866978	869218	819173
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	46156	57244	59391	56949	57125	57189
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1450596	1191232	1098524	1193043	1140114	1120260	1103484
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-560272	-745615	-88389	-194163	-90643	-87273	-119896
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	16571	8616	34706	33647	25810	33214	32969
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4514459	4393436	4386000	4387729	4342227	4323662
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27210	28611	28611	28611	28611	28791
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1308500	1316710	1332885	1336348	1353728	1313246	1309430

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		अग. 27	जुला. 29	अग. 12	अग. 26
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	16331874	15369949	16841141	16815691	16860072
1.1.1 मांग जमाराशियां	2072747	1790996	2042035	1975810	2022999
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	14259128	13578953	14799106	14839881	14837072
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6416607	6110529	6659598	6677946	6676683
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	176718	64693	176718	229249	229249
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7842520	7468424	8139508	8161935	8160390
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	274594	238080	353600	477310	469509
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	17575002	16467365	18437669	18560593	18623041
2.1.1 सरकार को ऋण	4728179	4591955	5013472	5071704	5066468
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	12846823	11875410	13424197	13488889	13556573
2.1.2.1 बैंक ऋण	11891314	10897601	12369350	12425718	12458658
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	11836304	10828800	12337006	12393621	12430897
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	11522	9363	15084	16094	16785
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	769	1324	825	776	790
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	943218	967121	1038938	1046300	1080339
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	262711	258025	204572	197533	210153
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	465464	459597	395107	392590	407115
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	133439	147101	131172	132987	133784
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	69314	54471	59363	62071	63178
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1268887	1488773	1031308	1010071	992537
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	683437	641437	834457	809848	764114
2.3.2 उपलब्ध नकदी	85926	101721	108463	109580	108528
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-499524	-745615	-88389	-90643	-119896
2.4 पूंजी खाता	1743595	1726288	1743595	1880276	1880276
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	756537	879845	735213	594919	615873
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	571535	501727	601122	596129	599617
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	26533	47624	11512	12761	2566

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	25 मार्च 2022 की स्थिति	2021	2022		
		अग. 27	जुला. 29	अग. 12	अग. 26
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4728948	4593279	5014297	5072480	5067259
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियां (गैर-एसएलआर)	-	-	155767	155713	183971
3 वाणिज्यिक पत्र	55315	81561	65956	63118	63292
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सरकारी उद्यम	7642	10668	9643	9548	9397
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	73814	69737	69316	69503	66885
4.3 अन्य	5152	5151	5039	5030	5042
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सरकारी उद्यम	117860	115114	100216	100223	101205
5.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	326188	313729	321684	316982	313520
5.3 अन्य	148753	145079	91718	91204	92149
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	34404	51791	38111	54242	59277
6.2 वित्तीय संस्थाएं	174090	152062	181488	180736	185602

टिप्पणी : कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के डेटा अंतिम हैं, और कॉलम (4) एवं (5) के डेटा अनंतिम हैं।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2021-22	2021	2022		2021-22	2021	2022	
		अग.	जुला.	अग.		अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	212	210	213	213	136	134	137	137
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**262674**	**238674**	**277258**	**281986**	**258649**	**234251**	**273313**	**278245**
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	194143	170669	189750	191920	190570	166520	186516	188767
1.2 बैंकों से उधार राशि	38369	49402	44571	45029	38317	49396	44372	44956
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	30162	18602	42937	45037	29762	18336	42425	44522
2 अन्य के प्रति देयताएं	**17832517**	**16746756**	**18429970**	**18568195**	**17380755**	**16311329**	**17986398**	**18126161**
2.1 कुल जमाराशियां	16899634	15935780	17398112	17418302	16465313	15517050	16972313	16993855
2.1.1 मांग	2117513	1830494	2088492	2068893	2072747	1790996	2042035	2022999
2.1.2 मीयादी	14782121	14105286	15309620	15349409	14392567	13726054	14930278	14970856
2.2 उधार	278985	243677	358861	474582	274594	238080	353600	469509
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	653898	567299	672997	675311	640848	556198	660484	662796
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**94299**	**91806**	**94387**	**98308**	**94299**	**91806**	**94387**	**98308**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अन्य	94299	91806	94387	98308	94299	91806	94387	98308
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	788725	761648	965461	894122	769363	743158	942920	872642
4.1 उपलब्ध नकदी	88732	103780	111672	111443	85926	101721	108463	108528
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	699993	657868	853789	782679	683437	641437	834457	764114
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**315282**	**249941**	**334895**	**349954**	**243637**	**195991**	**276885**	**292464**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	199434	176371	207109	219177	164240	141467	173373	181732
5.1.1 चालू खाते में	19733	26135	17015	18791	16691	23335	13871	16080
5.1.2 अन्य खातों में	179701	150236	190094	200386	147549	118131	159502	165651
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36905	22146	30718	29904	6982	6146	12456	13886
5.3 बैंकों को अग्रिम	39340	24127	39130	42331	35802	23695	37065	41828
5.4 अन्य आस्तियां	39603	27296	57938	58542	36613	24683	53991	55019
6 निवेश	**4874070**	**4734101**	**5158861**	**5213089**	**4728948**	**4593279**	**5014297**	**5067259**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4867102	4726753	5152646	5207133	4728179	4591955	5013472	5066468
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	6968	7348	6215	5955	769	1324	825	790
7 बैंक ऋण	**12259048**	**11236000**	**12735045**	**12829088**	**11891314**	**10897601**	**12369350**	**12458658**
7क खाद्यान्न ऋण	90827	104619	78064	73480	55011	68801	32345	27761
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	12016486	11032004	12489370	12588634	11651337	10695671	12126412	12220997
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	36070	32026	34760	34233	36055	32005	34745	34216
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	155796	122813	161899	158994	154212	121455	159962	156972
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	19537	19266	18685	17177	19157	19088	18453	16961
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	31160	29890	30331	30050	30554	29383	29778	29512

टिप्पणी : कॉलम (4) एवं (8) के डेटा अनंतिम हैं।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 25, 2022	2021	2022		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		अग. 27	जुला. 29	अग. 26	2022-23	2022
	1	2	3	4	%	%
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	**11891314**	**10897601**	**12369224**	**12457877**	**4.8**	**15.5**
II. खाद्यान्न ऋण	**55011**	**68800**	**32345**	**27761**	**-49.5**	**-59.7**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**11836304**	**10828801**	**12336880**	**12430116**	**5.0**	**16.0**
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**1461719**	**1358005**	**1529206**	**1540450**	**5.4**	**13.4**
2. उद्योग	**3156067**	**2867842**	**3182010**	**3194889**	**1.2**	**11.4**
2.1 सूक्ष्म और लघु[1]	532792	438790	557251	562518	5.6	28.2
2.2 मझौले	213996	162360	219327	220102	2.9	35.6
2.3 बड़े	2409279	2266692	2405433	2412269	0.1	6.4
3. सेवाएं	**3017258**	**2698121**	**3171546**	**3161533**	**4.8**	**17.2**
3.1 परिवहन परिचालक	155352	141179	155202	154843	-0.3	9.7
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20899	19658	20925	19697	-5.8	0.2
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	64378	60663	65089	64184	-0.3	5.8
3.4 शिपिंग	8436	7369	7306	7100	-15.8	-3.7
3.5 नौवहन	23979	29408	22498	23182	-3.3	-21.2
3.6 पेशेवर सेवाएं	116742	111643	118567	118689	1.7	6.3
3.7 व्यापार	696301	626210	720086	731760	5.1	16.9
3.7.1 थोक व्यापार	351213	324393	366135	381644	8.7	17.6
3.7.2 खुदरा व्यापार	345088	301817	353950	350116	1.5	16.0
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	291168	281588	294842	295212	1.4	4.8
3.9 गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[2] जिसमें से	1078447	895624	1163637	1144622	6.1	27.8
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	278979	262110	305509	294601	5.6	12.4
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	144121	83514	157764	151675	5.2	81.6
3.10 अन्य सेवाएं [3]	561556	524778	603395	602243	7.2	14.8
4 व्यक्तिगत ऋण	**3381699**	**3051522**	**3594016**	**3647906**	**7.9**	**19.5**
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	27628	19930	32175	32919	19.2	65.2
4.2 आवास	1684424	1534090	1769249	1785713	6.0	16.4
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	78730	63507	87991	92579	17.6	45.8
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	6161	5496	6473	6555	6.4	19.3
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	147789	131532	162706	167443	13.3	27.3
4.6 शिक्षा	82723	78787	85098	87456	5.7	11.0
4.7 वाहन ऋण	402689	372191	438973	444808	10.5	19.5
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	75311	72162	77325	78104	3.7	8.2
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	876244	773828	934025	952329	8.7	23.1
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र *(मेमो)*						
5.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां[4]	1484923	1372314	1535442	1543634	4.0	12.5
5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम[5]	1377848	1212113	1441472	1449953	5.2	19.6
5.3 मध्यम उद्यम [6]	351900	252123	367377	365946	4.0	45.1
5.4 आवास	616814	596950	606970	618053	0.2	3.5
5.5 शिक्षा ऋण	58118	58772	57499	58329	0.4	-0.8
5.6 नवीकरणीय ऊर्जा	3538	2019	4239	4253	20.2	110.7
5.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2483	3054	2535	2388	-3.8	-21.8
5.8 निर्यात ऋण	23330	23247	17637	16220	-30.5	-30.2
5.9 अन्य	37159	34373	47359	47202	27.0	37.3
5.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1180928	1029691	1244034	1268007	7.4	23.1

टिप्पणी : 1. डेटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर -खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण(एसआईबीसी) रिटर्न, के आधार पर है। जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल गैर खादय ऋण के लगभग 93 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और वृद्धि दर में कुछ बदलाव हुए हैं। टिप्पणी 3: चुनिंदा एससीबी द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए बैंकों की ऋण वृद्धि को समायोजित किया जाता है।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋणऔर पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 25, 2022	2021	2022		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		अग. 27	जुला. 29	अग. 26	2022-23	2022
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3156067	2867842	3182010	3194889	1.2	11.4
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	49135	48605	50525	50529	2.8	4.0
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	173246	147661	169002	161679	–6.7	9.5
2.2.1 चीनी	26307	19978	21764	20578	–21.8	3.0
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	18246	17067	16393	15961	–12.5	–6.5
2.2.3 चाय	5728	5459	5810	5923	3.4	8.5
2.2.4 अन्य	122965	105157	125034	119217	–3.0	13.4
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	18176	16019	17098	17330	–4.7	8.2
2.4 वस्त्र	224026	204275	213990	212355	–5.2	4.0
2.4.1 सूती वस्त्र	90384	80725	83098	82029	–9.2	1.6
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	3509	2508	3631	3583	2.1	42.9
2.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	38371	37469	38354	38537	0.4	2.8
2.4.4 अन्य वस्त्र	91761	83573	88907	88206	–3.9	5.5
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11573	10765	11428	11408	–1.4	6.0
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	16294	15318	16951	17036	4.6	11.2
2.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	40565	38314	41083	41066	1.2	7.2
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	107333	81024	113550	135396	26.1	67.1
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	196363	170671	210273	210782	7.3	23.5
2.9.1 उर्वरक	33160	25525	35530	35706	7.7	39.9
2.9.2 औषधि और दवाइयां	61093	51793	62263	63679	4.2	22.9
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	19622	23104	21485	20798	6.0	–10.0
2.9.4 अन्य	82486	70249	90995	90598	9.8	29.0
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	72013	60742	72485	73338	1.8	20.7
2.11 कांच और कांच के सामान	5952	5970	6088	6140	3.2	2.8
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	47910	48601	49356	50184	4.7	3.3
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	288531	282779	299621	298885	3.6	5.7
2.13.1 लोहा और स्टील	187584	193079	196997	199046	6.1	3.1
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	100946	89700	102624	99838	–1.1	11.3
2.14 सभी अभियांत्रिकी	167966	150440	165512	167379	–0.3	11.3
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	38179	34730	39505	39017	2.2	12.3
2.14.2 अन्य	129787	115710	126007	128363	–1.1	10.9
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	89896	86525	91404	90122	0.3	4.2
2.16 रत्न और आभूषण	80512	72654	73652	74484	–7.5	2.5
2.17 निर्माण	117724	120243	116875	117765	0.0	–2.1
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1195027	1093405	1214513	1213626	1.6	11.0
2.18.1 पावर	611410	568015	627053	621193	1.6	9.4
2.18.2 दूरसंचार	130318	111954	129063	131221	0.7	17.2
2.18.3 सड़क	270395	242663	279600	279752	3.5	15.3
2.18.4 हवाई अड्डा	6646	7483	8673	8745	31.6	16.9
2.18.5 बंदरगाह	8886	11413	8028	8474	–4.6	–25.7
2.18.6 रेलवे	10512	12921	11561	11746	11.7	–9.1
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	156860	138956	150534	152493	–2.8	9.7
2.19 अन्य उद्योग	253823	213829	248604	245384	–3.3	14.8

टिप्पणी : जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2020-21	2021	2022						
		जुला. 30	मई 27	जून 03	जून 17	जून 24	जुला. 01	जुला. 15	जुला. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	34	32	32	32	31	32	32	32
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	**125859.6**	**252315.7**	**126958.1**	**126099.8**	**126781.0**	**126829.8**	**125662.2**	**126226.0**	**126562.4**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**23736.9**	**54733.3**	**24062.9**	**24531.5**	**25476.7**	**25537.9**	**26231.7**	**24694.7**	**25244.6**
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4896.9	10392.1	5845.9	6123.1	6339.0	5984.1	6470.4	6406.5	6672.8
2.1.1.2 अन्य	13,899.4	31845.4	12752.4	12790.0	13391.9	13855.6	12664.9	12573.1	12841.3
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	2039.5	619.8	724.4	824.7	869.7	869.7	514.9	799.6
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4940.6	10456.4	4844.8	4893.9	4921.2	4828.5	6226.8	5200.3	4930.9
2.2 मीयादी देयताएं	**179957.5**	**333186.3**	**183687.5**	**181820.7**	**178448.5**	**176762.7**	**175599.2**	**174857.2**	**174258.9**
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	65333.7	109320.2	66131.9	65089.3	61653.1	60401.5	59195.7	57851.2	57194.2
2.2.1.2 अन्य	111960.2	220470.2	114205.7	113309.8	113389.1	112974.1	112997.3	113652.9	113721.1
2.2.2 बैंकों से उधार	630.0	1816.0	1024.3	998.3	994.8	994.8	976.7	948.0	939.1
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2033.7	1579.8	2325.6	2423.3	2411.5	2392.3	2429.5	2405.1	2404.6
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	63559.8	109436.1	61247.8	59463.5	59306.8	59486.6	59143.7	57306.1	56814.8
4.1 मांग	15691.8	21364.5	13228.8	13304.8	13449.4	13779.8	13485.2	12304.3	12659.5
4.2 मीयादी	47868.0	88071.5	48019.0	46158.7	45857.5	45706.8	45658.5	45001.8	44155.3
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	**8151.1**	**19148.6**	**10695.3**	**11263.7**	**11382.2**	**11058.8**	**11300.6**	**10318.6**	**10617.7**
5.1 उपलब्ध नकदी	570.3	1221.3	798.5	907.5	982.8	1230.4	720.3	897.7	773.1
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7580.8	17927.3	9896.9	10356.2	10399.4	9828.3	10580.4	9420.9	9844.6
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	**1148.1**	**2607.2**	**1227.5**	**1244.8**	**1372.1**	**1223.5**	**1184.0**	**1252.9**	**1282.1**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**64455.2**	**135219.6**	**71631.0**	**71747.5**	**70958.1**	**70895.2**	**70984.3**	**71053.8**	**71000.9**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**28835.7**	**38786.9**	**26130.0**	**23984.4**	**23731.8**	**23946.6**	**22976.4**	**21920.3**	**20905.9**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**114631.6**	**219632.8**	**119819.7**	**119486.4**	**118113.1**	**119438.2**	**118722.4**	**118465.3**	**118533.2**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**114612.1**	**219624.6**	**119798.9**	**119465.5**	**118092.2**	**119417.3**	**118701.5**	**118444.4**	**118512.3**
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	89429.1	171885.2	105636.7	104787.9	105785.2	104576.7	103769.3	103716.8	104735.3
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.5	8.2	20.9	20.9	20.8	20.8	20.8	20.9	20.9

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2021-22			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	अग. '21	जुला.'22	अग.'22(अ)	अग.'21	जुला.'22	अग.'22(अ)	अग.'21	जुला.'22	अग.'22(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**162.8**	**168.7**	**165.0**	**161.8**	**172.5**	**173.9**	**167.6**	**179.4**	**180.4**	**163.9**	**175.0**	**176.3**
1.1 अनाज और उत्पाद	146.4	150.4	147.6	144.9	155.2	159.5	149.2	159.3	162.1	146.3	156.5	160.3
1.2 मांस और मछली	200.4	206.5	202.6	202.3	210.8	204.0	208.2	217.1	210.8	204.4	213.0	206.4
1.3 अंडा	173.3	176.0	174.4	176.5	174.3	168.3	178.5	176.6	170.6	177.3	175.2	169.2
1.4 दूध और उत्पाद	158.3	159.0	158.6	157.5	166.3	168.0	158.8	167.1	168.4	158.0	166.6	168.1
1.5 तेल और चर्बी	192.2	172.4	184.9	190.9	202.2	198.1	171.9	184.8	182.5	183.9	195.8	192.4
1.6 फल	155.3	163.5	159.2	155.7	169.6	169.2	167.1	179.5	177.1	161.0	174.2	172.9
1.7 सब्जी	156.1	192.8	168.5	153.9	168.6	173.0	186.1	208.5	213.1	164.8	182.1	186.6
1.8 दाल और उत्पाद	164.1	164.4	164.2	162.8	164.4	167.1	163.5	164.0	167.2	163.0	164.3	167.1
1.9 चीनी और उत्पाद	117.4	119.1	118.0	115.2	119.2	120.2	116.8	121.5	122.2	115.7	120.0	120.9
1.10मसाले	171.2	167.5	170.0	169.8	191.8	195.6	165.8	186.3	189.7	168.5	190.0	193.6
1.11गैर नशीले पेय पदार्थ	167.8	154.7	162.3	167.6	174.5	174.8	154.0	159.8	160.5	161.9	168.4	168.8
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	173.0	175.8	174.3	171.9	183.1	184.1	174.1	187.7	188.9	172.9	185.2	186.3
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**190.3**	**196.5**	**191.9**	**190.2**	**193.2**	**193.7**	**196.1**	**198.6**	**198.7**	**191.8**	**194.6**	**195.0**
3 कपड़ा और जूते	**168.2**	**158.4**	**164.3**	**166.3**	**181.7**	**183.0**	**156.4**	**170.6**	**171.6**	**162.4**	**177.3**	**178.5**
3.1 कपड़ा	168.8	160.9	165.7	167.0	182.0	183.2	158.9	172.7	173.7	163.8	178.3	179.5
3.2 जूते	164.5	144.7	156.3	162.6	180.3	181.7	142.8	158.7	160.0	154.4	171.3	172.7
4 आवास	--	**163.0**	**163.0**	--	--	--	**162.4**	**167.8**	**169.0**	**162.4**	**167.8**	**169.0**
5 ईंधन और लाइट	**164.0**	**159.8**	**162.4**	**163.1**	**179.6**	**179.1**	**158.5**	**179.5**	**178.4**	**161.4**	**179.6**	**178.8**
6 विविध	**164.1**	**156.1**	**160.2**	**163.3**	**171.8**	**172.6**	**155.6**	**164.7**	**165.4**	**159.6**	**168.4**	**169.1**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	161.8	153.5	157.9	160.9	171.3	172.4	152.1	163.1	164.2	156.7	167.4	168.5
6.2 स्वास्थ्य	172.0	163.3	168.6	171.1	178.8	179.4	162.1	171.7	172.6	167.7	176.1	176.8
6.3 परिवहन और संचार	157.9	150.0	153.7	157.7	166.3	166.6	150.4	157.4	157.7	153.9	161.6	161.9
6.4 मनोरंजन	162.7	154.8	158.2	161.1	168.6	169.3	152.2	164.6	165.1	156.1	166.3	166.9
6.5 शिक्षा	168.4	160.1	163.5	167.5	174.7	175.7	160.4	169.1	169.9	163.3	171.4	172.3
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	161.3	160.8	161.1	160.3	169.7	171.1	159.5	169.8	171.4	160.0	169.7	171.2
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**164.5**	**163.1**	**163.8**	**163.6**	**174.3**	**175.3**	**162.2**	**172.3**	**173.1**	**162.9**	**173.4**	**174.3**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2021-22	2021	2022	
				अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	123.6	123.0	129.9	130.2
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1075	1066	1131	1140
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	–	1084	1074	1143	1152

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2021-22	2021	2022	
		अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	47999	47109	50784	51639
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	65426	64219	55994	56831

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

कमोडिटी	भारांक	2020-21	2021	2022		
			अग.	जून	जुला. (अ)	अग. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य वस्तुएँ	**100.000**	**139.4**	**136.2**	**155.4**	**153.8**	**153.1**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**160.7**	**155.4**	**181.5**	**177.5**	**178.6**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**167.3**	**161.7**	**182.5**	**178.9**	**181.7**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	163.5	161.1	170.7	172.6	177.0
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	187.6	171.5	225.9	208.7	216.5
1.1.1.3 दूध	4.440	156.9	157.0	164.2	164.4	164.5
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	164.0	158.7	175.3	173.1	171.2
1.1.1.5 मसाले	0.529	159.8	151.5	177.9	182.9	187.1
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	168.3	163.4	172.4	172.3	175.0
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**158.1**	**161.5**	**175.9**	**171.7**	**175.1**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	158.4	147.1	226.3	208.6	220.7
1.1.2.2 तिलहन	1.115	214.4	239.6	217.5	208.1	207.3
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	119.9	118.2	128.6	129.5	129.8
1.1.2.4 फूल	0.204	217.0	210.5	196.3	225.5	246.4
1.1.3 खनिज	**0.833**	**197.2**	**179.6**	**206.3**	**210.2**	**206.2**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	193.3	170.5	198.7	206.0	198.7
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	211.0	211.7	233.2	225.1	232.8
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	**2.410**	**110.3**	**97.1**	**176.4**	**167.5**	**155.2**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**124.6**	**117.9**	**167.1**	**165.6**	**157.6**
1.2.1 कोल	**2.138**	**129.0**	**127.7**	**130.9**	**130.9**	**130.9**
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	143.0	143.4	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.8	119.8	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	170.5	138.1	212.6	212.6	212.7
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**126.2**	**119.7**	**189.8**	**188.7**	**174.0**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**117.4**	**106.4**	**133.7**	**130.0**	**133.7**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**135.0**	**133.2**	**143.9**	**143.1**	**143.2**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**157.9**	**157.6**	**169.0**	**167.0**	**166.5**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	142.8	142.4	147.2	147.3	143.9
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस,मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	144.1	140.2	144.8	148.6	152.4
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	122.3	124.3	124.0	125.1	125.1
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	187.2	188.7	204.7	193.4	187.3
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	149.4	148.3	160.6	161.9	162.7
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	145.6	144.0	152.6	156.5	160.4
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	133.3	129.1	155.6	155.2	159.8
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	146.2	143.6	160.1	162.7	163.1
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	122.9	120.9	125.9	125.9	126.4
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	130.5	128.4	133.5	134.4	134.5
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	136.7	132.2	157.4	160.7	161.1
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	171.1	168.1	190.0	190.1	189.2
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	157.5	154.8	169.7	171.6	176.4
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	137.0	134.9	141.0	141.7	139.6
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	153.5	154.3	178.5	178.2	178.6
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	200.9	209.0	206.3	206.5	208.8
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**126.8**	**127.2**	**128.5**	**128.4**	**128.1**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	123.6	123.8	127.6	127.9	127.8
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	130.5	130.2	135.4	135.6	134.8
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	128.6	129.9	124.3	123.2	123.0
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	**0.514**	**160.2**	**160.6**	**164.0**	**164.8**	**164.6**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	160.2	160.6	164.0	164.8	164.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधार: 2011-12=100)

कमोडिटी	भारांक	2020-21	2021	2022		
			अग.	जून	जुला. (अ)	अग. (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**135.2**	**132.6**	**149.3**	**147.2**	**146.4**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	128.2	123.6	144.6	140.1	139.0
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	146.8	147.1	159.4	160.1	159.1
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	125.5	124.2	132.7	133.5	134.8
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	138.7	136.5	154.4	154.6	155.5
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	168.5	167.6	163.0	161.8	160.9
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	126.2	123.7	135.0	135.8	135.2
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	**0.814**	**143.1**	**142.0**	**146.7**	**147.3**	**148.6**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	142.0	141.3	145.2	146.1	147.2
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिटेड वस्त्र	0.221	145.8	143.8	150.5	150.5	152.2
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**119.2**	**118.4**	**122.5**	**122.9**	**123.3**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	103.4	103.0	107.3	107.5	107.1
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	141.5	139.7	141.2	141.5	140.8
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	121.0	120.3	124.8	125.3	126.4
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	**0.772**	**141.0**	**140.8**	**142.0**	**143.0**	**143.3**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	128.8	127.5	136.9	136.3	137.8
1.3.7.2 विनियर शीट,प्लायवुड का विनिर्माण,लॅमिन बोर्ड,पार्टिकल बोर्डऔर अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	141.9	140.9	140.8	142.3	142.0
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	193.9	193.8	203.0	202.3	203.2
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	134.1	138.7	133.8	135.5	136.2
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	**1.113**	**137.5**	**132.5**	**155.8**	**153.9**	**154.6**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	141.4	135.7	159.3	157.6	160.2
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	137.8	135.8	150.2	150.4	150.7
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	131.0	124.1	155.9	151.6	149.6
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**157.8**	**156.5**	**166.8**	**167.0**	**167.7**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	157.8	156.5	166.8	167.0	167.7
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	**6.465**	**133.5**	**130.3**	**148.3**	**147.2**	**146.7**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	143.8	137.6	166.6	166.0	162.9
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	129.6	128.1	143.3	141.9	143.6
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथेंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	140.3	136.9	150.8	146.6	144.4
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	132.1	130.1	144.4	144.0	144.7
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	130.4	126.8	143.4	143.3	145.1
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट,सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	128.1	128.4	139.6	140.6	141.3
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	130.3	126.3	144.4	145.0	144.2
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	106.6	103.7	117.2	115.6	115.1
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**135.9**	**134.1**	**139.8**	**139.9**	**141.0**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	135.9	134.1	139.8	139.9	141.0
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	**2.299**	**124.8**	**122.5**	**131.3**	**130.5**	**129.4**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब,रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	104.3	103.8	108.8	111.1	111.5
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	101.9	99.8	106.7	106.8	108.0
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	138.0	134.8	145.7	143.4	141.2
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**123.7**	**122.1**	**134.0**	**132.0**	**135.8**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	139.1	136.0	152.9	155.8	155.8
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	115.6	114.0	119.0	118.9	119.7
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	119.3	111.3	140.1	138.6	132.5
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.9	111.3	117.2	117.8	118.2
1.3.13.5 सीमेन्ट,चूना और प्लास्टर	1.645	126.4	125.5	139.0	134.3	141.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधार: 2011-12=100)

कमोडिटी	भारांक	2020-21	2021	2022		
			अग.	जून	जुला. (अ)	अग. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	129.2	128.9	133.8	134.4	134.9
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	122.2	121.5	123.8	124.6	126.2
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	90.6	87.7	103.9	104.5	105.4
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**140.1**	**135.9**	**150.0**	**148.9**	**148.6**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	150.8	142.2	158.1	163.0	163.1
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	147.7	142.9	172.2	156.9	169.7
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	119.1	116.9	127.4	128.0	127.1
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	137.4	132.9	151.6	149.9	149.1
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	157.5	156.4	162.3	157.2	153.6
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	133.7	128.7	145.5	147.5	146.6
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	141.7	135.9	147.8	156.7	154.4
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	155.9	151.6	174.3	174.0	172.6
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	139.7	134.6	149.8	145.2	142.1
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	118.9	118.8	128.2	127.0	128.2
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	159.0	155.8	169.9	168.5	172.9
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**130.5**	**130.6**	**140.0**	**140.3**	**140.2**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	123.9	124.1	134.6	133.7	135.4
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	156.2	157.2	165.8	164.5	162.1
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	96.1	96.8	98.2	100.0	98.0
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	117.5	117.4	136.0	139.2	137.8
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.2	108.2	112.5	112.3	112.6
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	136.5	135.7	142.6	144.3	144.9
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**113.7**	**113.0**	**116.6**	**116.2**	**117.0**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	106.0	103.7	116.0	117.2	116.4
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.7	134.6	134.9	134.9	134.9
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	121.7	119.3	128.0	128.6	129.5
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	0.641	102.1	103.0	99.6	97.7	100.2
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	108.4	107.1	112.8	112.9	113.1
1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घडी	0.076	145.6	145.7	152.6	149.6	149.5
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	106.1	104.0	109.2	107.0	107.0
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	98.3	98.4	98.3	98.3	101.7
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**122.3**	**121.8**	**128.6**	**127.5**	**128.5**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	119.7	119.5	125.2	124.3	126.7
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	121.8	120.7	131.7	132.1	132.8
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	103.1	101.0	112.5	112.9	115.6
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	140.7	138.8	150.6	145.7	142.6
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	114.5	113.8	116.8	117.0	116.8
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	128.4	127.7	134.3	134.6	134.9
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	113.2	114.5	115.8	115.6	117.0
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**120.0**	**119.6**	**125.1**	**125.5**	**125.7**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन,एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	119.2	119.7	126.9	125.8	125.7
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	122.1	121.0	127.0	127.6	127.9
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	115.1	114.9	117.7	117.7	117.6
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	118.1	117.3	121.3	123.7	124.9
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	74.2	75.1	78.5	78.2	78.8
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने –उतारने वाले उपकरण	0.285	120.0	119.5	125.6	126.4	126.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(समाप्त)*

(आधार: 2011-12=100)

कमोडिटी	भारांक	2020-21	2021	2022		
			अग.	जून	जुला. (अ)	अग. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	133.4	134.7	142.6	143.5	142.3
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	128.4	127.0	135.0	136.5	136.4
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	114.2	115.3	118.7	119.6	119.6
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	78.2	78.4	84.5	83.8	84.1
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	130.1	129.0	129.1	128.0	130.1
1.3.18.13 कपड़ा,परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	125.3	122.9	126.5	126.7	128.4
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	134.7	134.1	138.4	138.9	139.0
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	66.6	66.2	68.5	68.2	68.6
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**122.7**	**121.8**	**127.8**	**127.5**	**128.2**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	122.6	121.5	126.5	126.3	126.8
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	122.7	122.1	129.2	128.9	129.7
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**131.7**	**131.0**	**135.5**	**136.2**	**136.5**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली –वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.9	158.9	159.1	163.5	163.5
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टाक	0.110	104.4	104.9	104.0	103.9	105.5
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	131.0	130.1	135.6	136.0	136.3
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	137.2	136.4	139.9	140.8	140.8
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	135.9	132.6	147.7	149.2	150.5
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**150.1**	**149.0**	**157.0**	**157.7**	**156.5**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	150.1	149.0	157.0	157.7	156.5
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**137.9**	**133.3**	**139.6**	**144.3**	**143.9**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	136.0	131.2	137.7	142.7	142.3
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	192.3	183.4	175.4	175.4	190.5
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	140.4	138.7	147.8	148.9	149.3
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	150.9	151.5	160.1	160.9	159.3
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	171.8	171.3	173.5	171.3	172.0
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**163.8**	**160.1**	**177.4**	**174.4**	**176.0**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2020-21	2021-22	अप्रैल-जुलाई		जुलाई	
				2021-22	2022-23	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	118.1	131.6	123.9	136.3	131.5	134.6
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	101.0	113.3	106.5	113.0	104.6	101.1
1.2 विनिर्माण	77.63	117.2	131.0	122.1	134.6	131.0	135.2
1.3 बिजली	7.99	157.6	170.1	172.4	195.1	184.7	188.9
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	118.1	129.5	125.1	138.8	128.5	131.7
2.2 पूंजीगत माल	8.22	75.9	88.7	78.6	96.7	92.4	97.8
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	124.7	143.9	136.3	149.2	143.7	148.9
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	124.7	148.2	139.0	150.9	144.4	150.1
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	101.2	113.8	98.4	117.7	118.7	121.5
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	142.1	146.7	140.8	141.2	145.9	143.0

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-अगस्त			
	2022-23 (बजट आकलन)	2022-23 (वास्तविक)	2021-22 (वास्तविक)	बजट आकलन के लिए प्रतिशत	
				2022-23	2021-22
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**2204422**	**816898**	**793493**	**37.1**	**44.4**
1.1 कर राजस्व (निवल)	1934771	700094	644843	36.2	41.7
1.2 करेतर राजस्व	269651	116804	148650	43.3	61.2
2 गैरेतर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	**79291**	**31527**	**15179**	**39.8**	**8.1**
2.1 ऋण की वसूली	14291	6967	6808	48.8	52.4
2.2 अन्य प्राप्तियां	65000	24560	8371	37.8	4.8
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	**2283713**	**848425**	**808672**	**37.2**	**40.9**
जिसमें से:	3194663	1137698	1104813	35.6	37.7
4 राजस्व व्यय					
4.1 ब्याज भुगतान	940651	338637	278371	36.0	34.4
5 पूंजी व्यय	750246	252328	171868	33.6	31.0
6 कुल व्यय (4+5)	**3944909**	**1390026**	**1276681**	**35.2**	**36.7**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**990241**	**320800**	**311320**	**32.4**	**27.3**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1661196**	**541601**	**468009**	**32.6**	**31.1**
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	**720545**	**202964**	**189638**	**28.2**	**27.2**

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2022-23।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2021-22	2021	2022					
		अग. 27	जुला. 22	जुला. 29	अग. 5	अग. 12	अग. 19	अग. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	5310	5990	10785	11428	12026	12171	13313	14723
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16705	14559	29993	35008	36339	33210	27422	24936
1.3 राज्य सरकारें	31320	59757	59800	58800	58250	58250	59250	54450
1.4 अन्य	72109	145396	127831	121432	117932	113541	111572	107259
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	70130	103967	102435	103721	105001	103475	103132	96493
2.2 प्राथमिक व्यापारी	63669	54959	99496	99464	101179	99984	98737	99375
2.3 राज्य सरकारें	15763	16510	38887	38187	39687	39687	39887	37587
2.4 अन्य	69259	117804	117743	113193	106183	105353	102567	105787
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	112386	109084	118731	113731	113343	110293	111085	106984
3.2 प्राथमिक व्यापारी	160461	102355	179050	178252	178930	181375	179899	184586
3.3 राज्य सरकारें	22836	19265	27925	26571	29246	30159	30970	27419
3.4 अन्य	118392	101340	127465	132209	132860	134420	135121	135463
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	289362	144913	123995	129551	63805	145547	146032	151970
4.4 अन्य	659	201	1189	338	1331	515	409	841
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	758339	850986	1040141	1031995	1030977	1021919	1012956	995062

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
अग. 3	9000	121	32740	2718	40	8982	2718	11700	98.63	5.5586
अग. 10	9000	135	44562	1318	27	8982	1318	10300	98.62	5.5949
अग. 17	9000	140	35058	3883	45	8967	3883	12850	98.63	5.5598
अग. 24	9000	157	43700	1739	32	8961	1739	10700	98.62	5.5998
अग. 30	9000	106	37012	2525	32	8975	2525	11500	98.61	5.6341
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
अग. 3	7000	126	26479	1519	24	6981	1519	8500	97.15	5.8886
अग. 10	7000	105	23938	17	43	6983	17	7000	97.11	5.9630
अग. 17	7000	97	22330	2021	24	6979	2021	9000	97.14	5.9099
अग. 24	7000	111	17933	3491	45	6959	3491	10450	97.10	5.9896
अग. 30	7000	98	13820	2129	69	6980	2129	9109	97.05	6.0890
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
अग. 3	5000	174	28259	2911	16	4763	2911	7675	94.15	6.2300
अग. 10	5000	156	21232	1639	44	4974	1639	6613	94.12	6.2599
अग. 17	5000	161	21759	858	31	4953	858	5811	94.18	6.1980
अग. 24	5000	195	23238	1293	68	4881	1293	6174	94.12	6.2701
अग. 30	5000	140	19959	4104	57	4979	4104	9083	94.07	6.3199

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
अगस्त	1, 2022	3.35-4.95	4.73
अगस्त	2, 2022	3.25-4.85	4.66
अगस्त	3, 2022	3.25-4.85	4.65
अगस्त	4, 2022	3.25-4.80	4.59
अगस्त	5, 2022	3.30-5.35	5.00
अगस्त	6, 2022	4.00-5.40	4.44
अगस्त	8, 2022	3.50-5.65	5.10
अगस्त	10, 2022	3.50-5.30	5.08
अगस्त	11, 2022	3.25-5.25	5.05
अगस्त	12, 2022	3.50-5.50	5.17
अगस्त	17, 2022	3.50-5.30	5.07
अगस्त	18, 2022	3.50-5.30	5.06
अगस्त	19, 2022	3.50-5.32	5.13
अगस्त	20, 2022	4.10-5.10	4.40
अगस्त	22, 2022	3.80-5.35	5.08
अगस्त	23, 2022	3.80-5.35	5.12
अगस्त	24, 2022	3.80-5.30	5.08
अगस्त	25, 2022	3.80-5.40	5.13
अगस्त	26, 2022	3.80-5.45	5.15
अगस्त	29, 2022	3.80-5.45	5.15
अगस्त	30, 2022	3.80-5.70	5.21
सितंबर	1, 2022	3.80-5.65	5.30
सितंबर	2, 2022	3.80-5.35	5.08
सितंबर	3, 2022	4.00-5.30	4.72
सितंबर	5, 2022	3.80-5.30	5.11
सितंबर	6, 2022	3.80-5.35	5.08
सितंबर	7, 2022	3.80-5.25	5.08
सितंबर	8, 2022	3.80-5.30	5.06
सितंबर	9, 2022	3.80-5.40	5.14
सितंबर	12, 2022	3.80-5.30	5.12
सितंबर	13, 2022	3.80-5.35	5.13
सितंबर	14, 2022	3.80-5.35	5.12
सितंबर	15, 2022	3.80-5.40	5.16

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2021	2022			
	अग. 27	जुला. 15	जुला. 29	अग. 12	अग. 26
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	64222.13	235248.52	249062.16	242172.94	237146.80
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	6332.44	20150.94	29372.29	23947.26	26979.70
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.27-4.31	5.38-6.19	5.33-6.38	5.59-6.35	5.66-6.51

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2021	2022			
	अग. 31	जुला. 15	जुला. 31	अग. 15	अग. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	391504.85	381468.70	374226.45	411152.10	410076.80
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	73288.65	46218.50	48380.15	63123.35	87514.55
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.15-12.83	4.95-12.13	5.05-12.40	5.51-13.69	5.64-13.66

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2021-22	2021	2022					
		अग. 27	जुला. 22	जुला. 29	अग. 5	अग. 12	अग. 19	अग. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	14515	12845	25768	21115	16625	19389	15243	20329
2 नोटिस मुद्रा	2122	1311	518	4246	4193	864	8916	511
3 मीयादी मुद्रा	515	483	351	318	533	394	1245	501
4 त्रिपक्षीय रिपो	618526	577354	589701	724049	601582	606519	786837	697741
5 बाजार रिपो	383844	301952	449231	515023	424608	442384	561452	470547
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	4373	4152	2947	183	2652	1213	5851	1820
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	70694	91965	98204	88394	77956	88686	94756
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	51300	47477	59173	70519	83929	78653	68894	67005
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5570	5068	4603	5865	6323	5371	4022	3366
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4690	3081	3823	2921	5828	5850	3243	5470
10.2 182-दिवसीय	3440	4605	4651	5438	4904	3023	2927	6151
10.3 364-दिवसीय	3530	5220	2107	1597	1523	2384	2839	2895
10.4 नकदी प्रबंधन बिल								
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	68530	65450	74357	86341	102507	95282	81925	84888
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	–	5128	336	442	2608	671	786	297

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2021-22		2021-22 (अप्रै-अग.)		2022-23 (अप्रै-अग.)*		अग. 2021		अग. 2022*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**164**	**138894**	**47**	**46663**	**67**	**19524**	**15**	**20546**	**8**	**945**
1ए प्रीमियम	154	136893	44	45821	59	18548	14	20298	5	849
1.1 पब्लिक	121	112567	38	45870	47	18199	14	20517	5	875
1.1.1 प्रीमियम	119	111314	38	45180	44	17565	14	20298	4	827
1.2 राइट्स	43	26327	9	792	20	1325	1	30	3	71
1.2.1 प्रीमियम	35	25580	6	641	15	983	–	–	1	22
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	**28**	**11589**	**10**	**5389**	**13**	**3102**	**–**	**–**	**1**	**279**
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	28	11589	10	5389	13	3102	–	–	1	279
3.1.1 पब्लिक	28	11589	10	5389	13	3102	–	–	1	279
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	**192**	**150484**	**57**	**52052**	**80**	**22625**	**15**	**20546**	**9**	**1224**
4.1 पब्लिक	149	124157	48	51260	60	21301	14	20517	6	1153
4.2 राइट्स	43	26327	9	792	20	1325	1	30	3	71

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकडे कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2021-22	2021	2022				
			अग.	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	3147021	247634	302579	302037	330740	305993	269875
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	422004	33381	39725	39064	42362	38441	33923
1.1 तेल	करोड ₹	503850	34535	60009	65991	83170	66238	45464
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	67472	4655	7878	8535	10653	8321	5715
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	2643171	213098	242570	236046	247570	239755	224411
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	354533	28725	31847	30529	31709	30119	28208
2 आयात	करोड ₹	4572775	334520	459199	488999	517980	527379	492457
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	613052	45093	60288	63244	66344	66252	61901
2.1 तेल	करोड ₹	1207803	70054	153230	148571	166299	168219	140817
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	161810	9443	20117	19215	21300	21133	17701
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	3364972	264466	305969	340428	351681	359160	351640
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	451242	35650	40170	44029	45044	45120	44201
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1425753	-86886	-156620	-186962	-187240	-221385	-222583
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-191048	-11712	-20562	-24180	-23982	-27812	-27978
3.1 तेल	करोड ₹	-703953	-35518	-93221	-82580	-83129	-101980	-95354
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-94339	-4788	-12239	-10680	-10647	-12811	-11986
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-721800	-51368	-63399	-104382	-104110	-119405	-127229
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-96709	-6924	-8324	-13500	-13335	-15000	-15993

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2021	2022					
		अक्टू. 1	अग. 26	सितं. 2	सितं. 9	सितं. 16	सितं. 23	सितं. 30
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	**करोड ₹**	**4723970**	**4480681**	**4413659**	**4384380**	**4351017**	**4352850**	**4333987**
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	**637477**	**561046**	**553105**	**550871**	**545652**	**537518**	**532664**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	4264251	3982307	3926994	3896690	3866549	3864518	3846882
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	575451	498645	492117	489598	484901	477212	472807
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	278316	316599	305654	307563	304491	306807	305964
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	37558	39643	38303	38644	38186	37886	37605
	मात्रा (मैट्रिक टन)	744.77	781.29	781.29	781.29	781.29	783.16	785.35
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	13657	13658	13658	13658	13658	13658	13658
	करोड ₹	142576	142411	141897	141022	141030	142476	141787
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	19240	17832	17782	17719	17686	17594	17427
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	38826	39363	39114	39105	38948	39050	39354
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	5228	4926	4902	4910	4880	4826	4826

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2021-22	2021	2022		2021-22	2022-23
		अग.	जुला.	अग.	अप्रै.-अग.	अप्रै.-अग.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	**139022**	**141523**	**135397**	**134683**	**2441**	**1435**
1.1 एफसीएनआर (बी)	16918	19331	15878	16017	-1142	-901
1.2 एनआर (ई) आरए	100801	102667	97925	96952	2464	906
1.3 एनआरओ	21303	19525	21594	21713	1119	1430

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2021-22	2022-23	2021	2022	
		अप्रै-अग.	अप्रै-अग.	अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**38587**	**18221**	**19285**	**5115**	**5385**	**305**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1. 1.1.2)	**56231**	**25861**	**23405**	**6004**	**6021**	**1103**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	**84835**	**36087**	**34073**	**8162**	**6978**	**4603**
1.1.1.1.1 इक्विटी	59684	27000	24289	6306	5044	2450
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	1698	286	466	174	60	27
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	42932	17570	18535	4587	4155	1974
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	14143	8792	4936	1471	756	376
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	910	352	352	73	73	73
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19347	7490	7696	1556	1556	1556
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5805	1597	2089	300	378	597
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	**28605**	**10226**	**10668**	**2158**	**957**	**3500**
1.1.1.2.1 इक्विटी	27189	9990	9984	2086	895	3292
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	1416	236	684	72	62	208
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**17644**	**7640**	**4120**	**889**	**636**	**798**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	10061	3917	2278	567	497	589
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3379	1408	1439	282	282	282
1.1.2.3 अन्य पूंजी	7604	3635	1670	429	174	326
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3400	1320	1268	389	317	399
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**-16777**	**1691**	**-6823**	**2906**	**362**	**7446**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	–	–	–	–	–	–
1.2.2 एफआईआई	-14071	2111	-6669	3128	458	7532
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	–	–	–	–	–	–
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2706	420	154	222	96	86
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**21809**	**19911**	**12463**	**8021**	**5747**	**7751**

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2021	2022		
		अग.	जून	जुला.	अग.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**19610.77**	**1965.35**	**1984.68**	**1982.44**	**2667.81**
1.1 जमाराशियां	830.05	58.04	72.49	79.96	72.02
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	112.90	7.39	14.54	11.65	12.24
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	746.57	46.31	65.03	59.71	53.53
1.4 उपहार	2336.29	191.05	222.77	216.33	221.31
1.5 दान	16.55	0.75	1.12	1.18	1.57
1.6 यात्रा	6909.04	574.22	1043.08	1015.27	1469.73
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3302.37	284.83	304.85	292.72	330.70
1.8 चिकित्सा उपचार	37.79	2.93	4.39	4.29	4.95
1.9 विदेश में शिक्षा	5165.33	780.26	240.86	276.03	467.52
1.10 अन्य	153.88	19.60	15.55	25.30	34.25

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2020-21	2021-22	2021	2022	
			सितंबर	अगस्त	सितंबर
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	93.92	93.13	93.92	92.29	93.05
1.2 रीर	103.46	104.66	105.98	103.83	104.87
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.59	93.55	94.11	93.66	94.28
2.2 रीर	102.96	103.48	104.63	102.54	103.30
6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	88.45	87.03	87.86	87.24	88.27
1.2 रीर	101.84	102.27	103.70	103.74	105.23
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.00	98.39	99.33	98.63	99.80
2.2 रीर	100.00	100.42	101.83	101.87	103.33

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

मद	2021-22	2021	2022	
		अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1086	90	96	83
1.2 राशि	28851	2247	2316	1875
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	18	1	1	0
2.2 राशि	11035	600	300	0
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1104	91	97	83
3.2 राशि	39886	2847	2616	1875
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	8.00	5.68	4.64	7.30
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.71	1.29	1.28	1.63
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-10.50	0.00-10.00	0.00-11.15	0.00-10.00
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉर्पोरेट विनिर्माण	12244	731	296	773
II. कॉर्पोरेट -बुनियादी संरचना	17023	956	288	540
ए) परिवहन	1597	0	36	36
बी) ऊर्जा	8215	3	60	504
सी) पानी और सफ़ाई व्यवस्था	10	2	0	0
डी) संचार	1258	500	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	0	0	0	0
एफ)अन्वेषण खनन और रिफाइनरी	4691	450	164	0
जी) अन्य उप -क्षेत्र	1252	1	28	0
III. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र	1570	36	118	66
IV. अन्य संस्थाएं	609	0	303	0
ए) एसई जेड़ में इकाई	9	0	3	0
बी) सिडबी				
सी) एक्जिम बैंक	600	0	300	0
V. बैंक	100	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबी एफ सी के अलावा)	4	0	0	0
VII. एनबीएफसी	7995	1081	1611	480
ए) एनबीएफसी -आई एफ सी/ए एफ सी	5621	600	340	50
बी) एनबी एफ सी -एमएफआई	93	0	51	0
सी) एनबीफसी - अन्य	2282	481	1220	430
VIII. गैर -सरकारी संगठन	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था	0	0	0	0
X. अन्य	341	44	0	16

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	अप्रै.-जून 2021			अप्रै.-जून 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**344159**	**312289**	**31870**	**429226**	**424631**	**4595**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**180111**	**173552**	**6559**	**230988**	**254881**	**-23893**
1.1 पण्य	**97448**	**128163**	**-30715**	**122968**	**191524**	**-68556**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**82663**	**45389**	**37275**	**108019**	**63357**	**44663**
1.2.1 सेवाएं	56217	30408	25808	76100	45024	31076
1.2.1.1 यात्रा	1597	2885	-1289	4705	6299	-1593
1.2.1.2 परिवहन	6733	6616	117	9855	11780	-1924
1.2.1.3 बीमा	772	428	344	916	510	406
1.2.1.4 जीएनआईई	203	236	-32	170	207	-37
1.2.1.5 विविध	46912	20243	26669	60454	26230	34225
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	27602	2466	25136	34476	3784	30692
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	12962	11635	1327	17751	14303	3448
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1201	1118	83	1660	1514	146
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	807	310	497	961	439	522
1.2.2 अंतरण	20917	1904	19013	25651	2800	22851
1.2.2.1 आधिकारिक	23	232	-209	31	245	-214
1.2.2.2 निजी	20894	1672	19222	25620	2555	23065
1.2.3 आय	5530	13077	-7547	6268	15532	-9264
1.2.3.1 निवेश आय	3929	12366	-8437	4577	14749	-10172
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1601	711	890	1691	783	908
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**164048**	**138656**	**25392**	**197716**	**169750**	**27966**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**102726**	**90770**	**11956**	**106275**	**107310**	**-1035**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	23689	12135	11554	23044	9449	13595
2.1.1.1 भारत में	23147	5910	17237	22492	6211	16281
2.1.1.1.1 इक्विटी	17773	5818	11955	16795	5797	10999
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4378		4378	4584		4584
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	997	92	905	1114	415	699
2.1.1.2 विदेश में	542	6225	-5683	552	3238	-2686
2.1.1.2.1 इक्विटी	542	2532	-1989	552	1193	-641
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	845	-845	0	876	-876
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	2849	-2849	0	1169	-1169
2.1.2 संविभाग निवेश	79036	78634	402	83231	97861	-14630
2.1.2.1 भारत में	77499	77121	378	82548	97207	-14659
2.1.2.1.1 एफआईआई	77499	77121	378	82548	97207	-14659
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	69769	68832	937	72768	87798	-15029
2.1.2.1.1.2 ऋण	7730	8289	-559	9780	9410	370
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1537	1513	24	683	654	29
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**16564**	**13727**	**2837**	**26628**	**18929**	**7698**
2.2.1 बाह्य सहायता	1891	1605	286	3232	1423	1809
2.2.1.1 भारत द्वारा	13	16	-3	11	23	-12
2.2.1.2 भारत को	1879	1589	290	3221	1400	1820
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	3370	2756	614	3130	6005	-2875
2.2.2.1 भारत द्वारा	736	293	443	216	138	78
2.2.2.2 भारत को	2634	2463	171	2914	5867	-2953
2.2.3 भारत को अल्पावधि	11303	9366	1937	20266	11502	8764
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	9259	9366	-107	17484	11502	5982
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	2044	0	2044	2782	0	2782
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**28916**	**24851**	**4065**	**49574**	**30533**	**19041**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	28916	24827	4089	49574	30018	19556
2.3.1.1 आस्तियां	16216	14610	1606	35834	16375	19458
2.3.1.2 देयताएं	12700	10217	2483	13741	13643	97
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	11212	8686	2525	12287	11937	349
2.3.2 अन्य	0	25	-25	0	514	-514
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	57	-57	0	59	-59
2.5 अन्य पूंजी	15842	9251	6591	15239	12919	2320
3 भूल-चूक	0	**81**	**-81**	**522**	0	**522**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**31870**	**-31870**	0	**4595**	**-4595**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)		31870	-31870	0	4595	-4595

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	अप्रै.-जून 2021			अप्रै.-जून 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**2538726**	**2303632**	**235094**	**3313079**	**3277608**	**35471**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1328609**	**1280223**	**48386**	**1782929**	**1967352**	**-184423**
1.1 पण्य	**718833**	**945407**	**-226574**	**949158**	**1478320**	**-529162**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**609775**	**334816**	**274960**	**833771**	**489032**	**344739**
1.2.1 सेवाएं	414688	224311	190377	587397	347531	239866
1.2.1.1 यात्रा	11778	21283	-9505	36320	48618	-12298
1.2.1.2 परिवहन	49664	48803	861	76068	90923	-14855
1.2.1.3 बीमा	5696	3160	2536	7067	3936	3131
1.2.1.4 जीएनआईई	1500	1739	-239	1314	1596	-282
1.2.1.5 विविध	346050	149325	196724	466628	202458	264170
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	203612	18192	185420	266112	29209	236902
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	95612	85825	9787	137013	110398	26614
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	8856	8247	609	12811	11683	1129
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	5951	2286	3664	7419	3390	4029
1.2.2 अंतरण	154296	14044	140252	197995	21616	176379
1.2.2.1 आधिकारिक	171	1712	-1541	241	1894	-1653
1.2.2.2 निजी	154125	12332	141793	197753	19722	178032
1.2.3 आय	40791	96460	-55669	48379	119885	-71506
1.2.3.1 निवेश आय	28979	91217	-62238	35330	113844	-78514
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	11812	5244	6568	13049	6041	7008
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1210117**	**1022811**	**187306**	**1526118**	**1310256**	**215862**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**757768**	**669572**	**88196**	**820308**	**828297**	**-7989**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	174747	89517	85230	177871	72934	104937
2.1.1.1 भारत में	170748	43594	127154	173612	47943	125670
2.1.1.1.1 इक्विटी	131103	42917	88185	129638	44743	84895
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	32292	0	32292	35379	0	35379
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	7354	677	6676	8596	3200	5396
2.1.1.2 विदेश में	3999	45923	-41924	4259	24992	-20733
2.1.1.2.1 इक्विटी	3999	18675	-14676	4259	9206	-4947
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	6231	-6231	0	6763	-6763
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	21017	-21017	0	9023	-9023
2.1.2 संविभाग निवेश	583021	580055	2966	642437	755362	-112926
2.1.2.1 भारत में	571680	568891	2789	637168	750316	-113148
2.1.2.1.1 एफआईआई	571680	568891	2789	637168	750316	-113148
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	514658	507747	6911	561680	677686	-116006
2.1.2.1.1.2 ऋण	57022	61143	-4121	75489	72631	2858
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	11341	11164	177	5268	5046	222
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**122188**	**101261**	**20927**	**205533**	**146111**	**59422**
2.2.1 बाह्य सहायता	13953	11840	2112	24946	10985	13962
2.2.1.1 भारत द्वारा	95	120	-26	87	177	-89
2.2.1.2 भारत को	13858	11720	2138	24859	10808	14051
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	24860	20333	4528	24160	46348	-22188
2.2.2.1 भारत द्वारा	5430	2164	3265	1664	1062	603
2.2.2.2 भारत को	19431	18169	1262	22495	45286	-22790
2.2.3 भारत को अल्पावधि	83375	69088	14287	156427	88778	67648
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	68300	69088	-788	134952	88778	46173
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	15076	0	15076	21475	0	21475
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**213303**	**183319**	**29984**	**382650**	**235676**	**146974**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	213303	183137	30166	382650	231704	150945
2.3.1.1 आस्तियां	119616	107769	11847	276591	126397	150194
2.3.1.2 देयताएं	93687	75367	18319	106059	105308	752
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	82703	64074	18629	94837	92139	2697
2.3.2 अन्य	0	182	-182	0	3971	-3971
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	419	-419	0	456	-456
2.5 अन्य पूंजी	116858	68240	48618	117627	99718	17910
3 भूल-चूक	0	**598**	**-598**	**4032**	0	**4032**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**235094**	**-235094**	0	**35471**	**-35471**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	235094	-235094	0	35471	-35471

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	अप्रै.-जून 2021			अप्रै.-जून 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**180110**	**173529**	**6581**	**230985**	**254856**	**-23872**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**153664**	**158571**	**-4907**	**199069**	**236548**	**-37480**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**97448**	**128163**	**-30715**	**122968**	**191524**	**-68556**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	97369	120278	-22909	122522	181035	-58513
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	79	0	79	446	0	446
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		7885	-7885		10489	-10489
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**56217**	**30408**	**25808**	**76100**	**45024**	**31076**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	83	9	73	321	28	293
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	58	127	-70	48	432	-384
1.अ.ख.3 परिवहन	6733	6616	117	9855	11780	-1924
1.अ.ख.4 यात्रा	1597	2885	-1289	4705	6299	-1593
1.अ.ख.5 निर्माण	583	892	-309	739	730	9
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	772	428	344	916	510	406
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1201	1118	83	1660	1514	146
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	191	1972	-1781	332	2251	-1919
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	28489	3017	25473	35521	4436	31085
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	12962	11635	1327	17751	14303	3448
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	647	804	-157	946	1252	-306
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	203	236	-32	170	207	-37
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	2698	669	2029	3137	1284	1853
1.आप्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**5530**	**13077**	**-7547**	**6268**	**15532**	**-9264**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1601	711	890	1691	783	908
1.आ.2 निवेश आय	2962	12106	-9143	3404	14387	-10983
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1511	7318	-5807	2047	9391	-7343
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	143	1852	-1709	62	1604	-1542
1.आ.2.3 अन्य निवेश	45	2935	-2890	102	3378	-3276
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	1264	1	1263	1193	15	1178
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	966	260	706	1173	362	811
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**20916**	**1882**	**19034**	**25648**	**2776**	**22872**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20894	1672	19222	25620	2555	23065
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	20074	1183	18891	24969	1806	23163
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	820	489	331	651	749	-98
1.इ.2 सामान्य सरकार	22	210	-187	28	221	-193
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**116**	**170**	**-54**	**141**	**230**	**-88**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	7	56	-49	19	132	-113
2.2 पूँजी अंतरण	109	114	-5	123	98	25
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**163933**	**170379**	**-6446**	**197578**	**174140**	**23438**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**23689**	**12135**	**11554**	**23044**	**9449**	**13595**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	23147	5910	17237	22492	6211	16281
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	22150	5818	16332	21379	5797	15582
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	17773	5818	11955	16795	5797	10999
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	4378		4378	4584		4584
3.1.अ.2 ऋण लिखत	997	92	905	1114	415	699
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	997	92	905	1114	415	699
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	542	6225	-5683	552	3238	-2686
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	542	3376	-2834	552	2069	-1517
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	542	2532	-1989	552	1193	-641
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		845	-845		876	-876
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	2849	-2849	0	1169	-1169
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		2849	-2849		1169	-1169
3.2 संविभाग निवेश	**79036**	**78634**	**402**	**83231**	**97861**	**-14630**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	77499	77121	378	82548	97207	-14659
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	69769	68832	937	72768	87798	-15029
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	7730	8289	-559	9780	9410	370
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1537	1513	24	683	654	29
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**3544**	**4841**	**-1297**	**5267**	**7658**	**-2391**
3.4 अन्य निवेश	**57663**	**42898**	**14765**	**86036**	**54577**	**31459**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	11212	8711	2501	12287	12452	-165
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	25	-25	0	514	-514
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	11212	8686	2525	12287	11937	349
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	22966	20502	2464	43650	25509	18141
3.4.3अ भारत को ऋण	22217	20192	2025	43423	25349	18074
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	749	310	439	227	160	66
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	32	63	-30	74	184	-110
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	11303	9366	1937	20266	11502	8764
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	12150	4257	7894	9760	4931	4829
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	**31870**	**-31870**	0	**4595**	**-4595**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	31870	-31870	0	4595	-4595
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**163933**	**170379**	**-6446**	**197578**	**174140**	**23438**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	97575	84443	13132	100722	104158	-3436
4.2 ऋण लिखत	54207	49808	4399	87096	60456	26640
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	12150	36127	-23977	9760	9526	233
5. निवल भूल-चूक		**81**	**-81**	**522**		**522**

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(करोड़ ₹)

मद	अप्रै.-जून 2021			अप्रै.-जून 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**1328602**	**1280058**	**48544**	**1782907**	**1967166**	**-184259**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**1133522**	**1169718**	**-36197**	**1536555**	**1825851**	**-289296**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**718833**	**945407**	**-226574**	**949158**	**1478320**	**-529162**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	718253	887242	-168989	945715	1397359	-451644
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	580	0	580	3443	0	3443
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	58165	-58165	0	80961	-80961
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**414688**	**224311**	**190377**	**587397**	**347531**	**239866**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	610	68	542	2474	213	2261
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	424	938	-514	367	3334	-2967
1.अ.ख.3 परिवहन	49664	48803	861	76068	90923	-14855
1.अ.ख.4 यात्रा	11778	21283	-9505	36320	48618	-12298
1.अ.ख.5 निर्माण	4303	6581	-2278	5705	5637	68
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	5696	3160	2536	7067	3936	3131
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	8856	8247	609	12811	11683	1129
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1412	14547	-13135	2560	17373	-14813
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	210155	22252	187903	274180	34244	239936
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	95612	85825	9787	137013	110398	26614
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	4776	5933	-1157	7303	9666	-2363
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1500	1739	-239	1314	1596	-282
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	19901	4934	14967	24215	9910	14305
1.आप्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**40791**	**96460**	**-55669**	**48379**	**119885**	**-71506**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	11812	5244	6568	13049	6041	7008
1.आ.2 निवेश आय	21852	89299	-67446	26277	111052	-84775
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	11143	53979	-42836	15804	72484	-56680
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	1051	13662	-12610	476	12377	-11902
1.आ.2.3 अन्य निवेश	336	21651	-21316	789	26078	-25289
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	9322	7	9315	9209	113	9096
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	7127	1918	5209	9053	2792	6261
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**154289**	**13879**	**140410**	**197973**	**21430**	**176543**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	154125	12332	141793	197753	19722	178032
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	148076	8724	139352	192727	13938	178789
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	6049	3608	2441	5026	5784	-757
1.इ.2 सामान्य सरकार	164	1547	-1383	219	1709	-1489
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**854**	**1253**	**-399**	**1092**	**1773**	**-681**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	51	413	-363	145	1016	-871
2.2 पूँजी अंतरण	803	839	-37	947	756	190
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**1209270**	**1256817**	**-47547**	**1525048**	**1344140**	**180908**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**174747**	**89517**	**85230**	**177871**	**72934**	**104937**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	170748	43594	127154	173612	47943	125670
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	163395	42917	120477	165017	44743	120274
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	131103	42917	88185	129638	44743	84895
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	32292	0	32292	35379	0	35379
3.1.अ.2 ऋण लिखत	7354	677	6676	8596	3200	5396
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	7354	677	6676	8596	3200	5396
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	3999	45923	-41924	4259	24992	-20733
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	3999	24906	-20907	4259	15969	-11710
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	3999	18675	-14676	4259	9206	-4947
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	6231	-6231	0	6763	-6763
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	21017	-21017	0	9023	-9023
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	21017	-21017	0	9023	-9023
3.2 संविभाग निवेश	**583021**	**580055**	**2966**	**642437**	**755362**	**-112926**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	571680	568891	2789	637168	750316	-113148
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	514658	507747	6911	561680	677686	-116006
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	57022	61143	-4121	75489	72631	2858
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	11341	11164	177	5268	5046	222
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**26144**	**35709**	**-9565**	**40653**	**59109**	**-18455**
3.4 अन्य निवेश	**425358**	**316442**	**108916**	**664087**	**421264**	**242823**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	82703	64257	18447	94837	96111	-1274
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	182	-182	0	3971	-3971
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	82703	64074	18629	94837	92139	2697
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	169413	151235	18177	336919	196897	140022
3.4.3अ भारत को ऋण	163889	148951	14938	335168	195659	139509
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	5524	2284	3240	1751	1238	513
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	238	462	-224	571	1417	-846
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	83375	69088	14287	156427	88778	67648
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	89629	31400	58229	75333	38060	37273
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**235094**	**-235094**	**0**	**35471**	**-35471**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	235094	-235094	0	35471	-35471
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**1209270**	**1256817**	**-47547**	**1525048**	**1344140**	**180908**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	719775	622906	96869	777448	803969	-26521
4.2 ऋण लिखत	399867	367417	32450	672267	466640	205627
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	89629	266494	-176865	75333	73531	1802
5. निवल भूल-चूक	**0**	**598**	**-598**	**4032**	**0**	**4032**

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2021-22		2021		2022			
			जून		मार्च		जून	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	132765	493987	125560	467984	132765	493987	134283	489605
1.2 अन्य पूंजी	78807	27673	74052	25696	78807	27673	79976	27719
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	211573	521661	199612	493680	211573	521661	214259	517324
2.1 इक्विटी	1110	156381	3146	176203	1110	156381	8153	135476
2.2 ऋण	9533	114124	4766	108708	9533	114124	2461	110966
2 संविभाग निवेश	10642	270505	7912	284911	10642	270505	10614	246442
3.1 व्यापार ऋण	18561	118157	7875	102106	18561	118157	21270	126894
3.2 ऋण	10474	195761	13607	189980	10474	195761	6543	192103
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	42081	140994	35904	143096	42081	140994	30242	137445
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	19858	32203	19427	12344	19858	32203	19504	30929
3 अन्य निवेश	90974	487115	76813	447526	90974	487115	77559	487371
4 रिज़र्व्स	607309		611075		607309		589155	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	920498	1279281	895412	1226117	920498	1279281	891585	1251136
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)	-358783		-330705		-358783		-359551	

नोट: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि का हिस्सा और पुनर्निवेशित आय शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2020-21	2021	2022		वि.व 2020-21	2021	2022	
		अग.	जुला.	अग.		अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	33.01	2.51	3.39	3.30	206873112	15362952	21126044	20028644
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	12.22	0.96	1.33	1.33	142072939	10388877	14218681	13493765
1.1.1 आउटराईट	6.22	0.50	0.71	0.75	8793301	730532	851204	888832
1.1.2 रेपो	3.08	0.24	0.34	0.32	51015712	3479766	5764070	5251883
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.92	0.22	0.28	0.25	82263926	6178579	7603407	7353051
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	19.91	1.48	1.93	1.89	59775826	4599545	6272728	5970122
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.88	0.06	0.13	0.09	5024347	374530	634635	564757
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)	–	–	–	–	–	–	–	–
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2078.39	166.52	189.26	188.08	128657516	10164296	11551440	11665583
1.1 ग्राहक लेनदेन	2063.73	165.34	188.06	186.92	113319292	8940380	9927091	10274480
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	14.66	1.18	1.20	1.16	15338225	1223916	1624349	1391103
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	577934.74	45370.66	74673.64	77757.95	42728006	3277624	4267239	4288963
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	9.76	1.05	0.68	0.54	575	61	40	30
2.2 एपीबीएस $	12573.33	722.32	1259.99	1162.46	133345	10305	12511	9662
2.3 आईएमपीएस	46625.25	3797.12	4608.30	4669.09	4171037	320203	444541	445989
2.4 एनएसीएच जमा $	18757.82	2075.99	1892.88	1940.04	1281685	98119	119677	128480
2.5 एनईएफटी	40407.29	3218.73	4018.39	4166.76	28725463	2209818	2627354	2631639
2.6 यूपीआई @	459561.30	35555.45	62893.40	65819.06	8415900	639117	1063117	1073162
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	11.99	1.14	1.62	1.63	177	17	18	17
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	12189.49	1008.32	1217.97	1247.15	1034444	85436	100581	102824
3.1 भीम आधार पे @	227.73	21.99	21.26	17.57	6113	462	621	516
3.2 एनएसीएच नामे $	10754.74	876.81	1067.05	1097.38	1026641	84818	99754	102100
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1207.02	109.52	129.66	132.20	1689	155	207	209
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	61782.93	5493.00	5481.80	5481.30	1701851	142600	180371	174516
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	22398.82	1904.71	2348.34	2447.83	971638	77733	115856	112358
4.1.1 पीओएस आधारित $	11124.59	984.62	1220.69	1330.54	380643	32969	41767	44943
4.1.2 अन्य $	11274.23	920.08	1127.64	1117.30	590994	44764	74089	67414
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	39384.11	3588.29	3133.47	3033.47	730213	64867	64515	62159
4.2.1 पीओएस आधारित $	22967.10	2119.63	2053.40	2012.17	451550	41177	41211	40585
4.2.2 अन्य $	16417.00	1468.66	1080.07	1021.30	278663	23690	23304	21574
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	65782.75	5259.90	6195.34	6177.69	279416	22362	25309	24625
5.1 वालेट	53013.86	4227.08	4855.87	4877.42	220183	17746	18775	18495
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	12768.89	1032.82	1339.48	1300.27	59233	4617	6534	6131
5.2.1 पीओएस आधारित $	1116.16	132.27	85.43	83.90	19546	1110	1285	1177
5.2.2 अन्य $	11652.73	900.54	1254.05	1216.37	39687	3507	5250	4953
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6999.12	588.62	588.67	575.81	6650333	533903	579727	548385
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6999.12	588.62	588.67	575.81	6650333	533903	579727	548385
6.2 अन्य	0.00	–	–	–	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	724689.03	57720.50	88157.42	91239.89	52394049	4061924	5153226	5139314
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	726767.42	57887.02	88346.69	91427.97	181051565	14226220	16704666	16804896
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	719768.30	57298.40	87758.02	90852.16	174401233	13692317	16124940	16256512

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2021-22	2021	2022		वि. व. 2021-22	2021	2022	
		अग.	जुला.	अग.		अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	507531.37	39029.40	68451.32	72227.76	14973493	1136503	1786719	1827748
1.1 इंट्रा-बैंक $	40805.69	3244.29	4902.42	6590.62	2726363	201774	323929	363782
1.2 इंटर-बैंक $	466725.68	35785.12	63548.90	65637.14	12247129	934729	1462790	1463966
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	40726.59	3561.18	3765.16	3537.74	83159996	6537169	7396630	7351640
2.1 इंट्रा-बैंक @	9583.32	814.17	934.78	932.41	52142582	4087618	4450729	4304970
2.2 इंटर-बैंक @	31143.27	2747.01	2830.38	2605.33	31017413	2449550	2945902	3046670
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	65240.43	5684.73	5774.19	5766.61	3111946	262881	272103	268788
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	62.37	5.02	6.95	7.46	3130	248	342	359
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	64851.61	5652.37	5731.82	5723.84	3097739	261683	270609	267289
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	326.45	27.35	35.42	35.31	11076	949	1152	1141
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	91.17	6.52	2.26	2.19	728	64	22	21
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	79.42	5.50	2.25	2.16	557	42	22	21
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	11.75	1.02	0.01	0.03	171	22	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11126.04	1061.82	1082.22	1021.48	299776	26830	29517	26193
5.1 एईपीएस @	11126.04	1061.82	1082.22	1021.48	299776	26830	29517	26193

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	जून 2022 तक	2021	2022	
		अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	9912.93	9771.97	10077.33	10128.50
1.1 क्रेडिट कार्ड	736.27	639.34	802.56	779.91
1.2 डेबिट कार्ड	9176.66	9132.63	9274.77	9348.59
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	15553.69	13682.92	15604.53	15661.77
2.1 वालेट @	12787.93	11510.97	12922.65	12948.75
2.2 कार्ड @	2765.76	2171.94	2681.89	2713.02
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.52	2.41	2.54	2.54
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	2.20	2.14	2.20	2.20
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	0.31	0.27	0.34	0.34
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	9.16	6.31	10.97	11.31
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	60.70	48.16	68.19	70.58
6 भारत क्यूआर @	49.72	43.52	45.21	47.49
7 यूपीआई क्यूआर *	1727.34	1142.06	2014.22	2092.54

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड़ शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक शृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2020-21	2021		2022	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**181237**	**14405**	**18175**	**14893**	**13932**
	बकाया	**1259585**	**1224772**	**1397878**	**1412766**	**1426737**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**132687**	**10143**	**13855**	**10676**	**9753**
	बकाया	**867494**	**847119**	**969847**	**980523**	**990274**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	39748	2252	4475	3018	3568
	बकाया	205888	194738	226701	229719	233287
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	276	-23	-366	-15	-20
	बकाया	3419	3037	3200	3185	3165
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	166	57	2	-1	-777
	बकाया	175	40	150	149	-628
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	12211	1135	1228	1146	933
	बकाया	221379	220277	232747	233892	234825
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	21009	1950	1929	1615	1490
	बकाया	97051	94750	114134	115749	117239
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	41470	3798	3926	3438	3217
	बकाया	207557	203597	241034	244474	247690
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	108205	107099	116043	116819	117578
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7473	7418	7931	7967	7996
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7227	7267	6983	6964	6944
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	84652	81813	110077	112724	115172
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	17807	974	2662	1475	1338
	बकाया	132029	130683	151885	153359	154697
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	-1	0	4
	बकाया	-25	-24	-25	-25	-22
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**34860**	**3647**	**3978**	**3691**	**3583**
	बकाया	**286863**	**282483**	**321027**	**324713**	**328337**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	17361	1843	1860	1626	1585
	बकाया	135348	133016	150513	152139	153724
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-3	0	0	0	0
	बकाया	159	157	158	158	158
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-7911	-470	-426	-193	940
	बकाया	-6776	-6194	-8455	-8648	-7708
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	25340	2274	2544	2258	1019
	बकाया	147942	145422	168720	170978	171996
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	41	0	0	0	23
	बकाया	-114	-147	-114	-114	-90
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	32	0	0	0	16
	बकाया	-74	-103	-74	-74	-58
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	10378	10332	10279	10274	10315
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**13690**	**615**	**342**	**526**	**596**
	बकाया	**105228**	**95170**	**107004**	**107530**	**108126**

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं। अर्थात सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2021			2022	
	जून	सितं	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**7882533**	**8235318**	**8439811**	**8529036**	**8784931**
1. वाणिज्यिक बैंक	35.99	37.82	35.40	37.75	38.04
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.34	0.35	0.27	0.29	0.33
3. बीमाकृत कंपनियां	25.83	24.18	25.74	25.89	26.34
4. म्यूच्युअल फंड	2.82	2.91	3.08	2.91	2.32
5. सहकारी बैंक	1.82	1.50	1.82	1.81	1.84
6. वित्तीय संस्थाएं	1.43	1.17	1.69	0.94	1.09
7. कॉरपोरेट	1.39	0.72	1.37	1.47	1.52
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	1.79	1.81	1.66	1.56	1.43
9. भविष्य निधियां	4.04	3.77	4.33	4.60	4.77
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	17.11	16.98	16.92	16.62	16.06
11. अन्य	7.43	8.79	7.73	6.15	6.30
11.1 राज्य सरकार	1.67	1.67	1.69	1.82	1.84

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2021			2022	
	जून	सितं	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**4028849**	**4153508**	**4257578**	**4410250**	**4472011**
1. वाणिज्यिक बैंक	33.75	35.94	34.41	34.39	34.22
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.39	0.44	0.40	0.38	0.41
3. बीमाकृत कंपनियां	29.67	27.50	28.85	28.42	28.39
4. म्यूच्युअल फंड	1.74	1.97	1.91	1.82	1.89
5. सहकारी बैंक	4.12	3.60	4.07	4.04	4.06
6. वित्तीय संस्थाएं	1.79	1.72	1.73	1.72	1.73
7. कॉरपोरेट	1.45	1.32	1.70	1.82	1.98
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	21.09	18.27	20.66	20.79	20.52
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.88	0.85	0.83	0.80	0.79
11. अन्य	5.10	8.38	5.40	5.81	5.99
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.18	0.19	0.20	0.21

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2021			2022	
	जून	सितं	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**901327**	**763582**	**692869**	**757198**	**1022053**
1. वाणिज्यिक बैंक	52.25	50.22	47.01	51.14	53.14
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.82	1.33	1.53	4.20	2.49
3. बीमाकृत कंपनियां	4.75	4.12	6.29	6.58	5.34
4. म्यूच्युअल फंड	19.93	17.72	13.72	14.01	14.86
5. सहकारी बैंक	1.60	1.32	1.49	1.79	1.34
6. वित्तीय संस्थाएं	2.56	2.12	2.36	3.53	3.73
7. कॉरपोरेट	3.00	2.40	3.13	3.47	4.27
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.15	0.72	0.49	0.40
9. भविष्य निधियां	0.10	0.37	0.85	0.21	1.70
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	2.58	2.63	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	11.42	17.62	22.89	14.59	12.72
11.1 राज्य सरकार	7.97	12.64	18.92	11.54	10.99

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (सं.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**4265969**	**4515946**	**5040747**	**5410887**	**6523916**	**7160694**
1.1 गतिविधियां	2537905	2635110	2882758	3074492	3906147	4254004
1.1.1 राजस्व	1878417	2029044	2224367	2446605	3259401	3242247
1.1.2 पूंजी	501213	519356	596774	588233	636062	922982
1.1.3 ऋण	158275	86710	61617	39654	10684	88775
1.2 गैर गतिविधियां	1672646	1812455	2078276	2253027	2526514	2810847
1.2.1 राजस्व	1555239	1741432	1965907	2109629	2334608	2602289
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	724448	814757	894520	955801	1082302	1244457
1.2.2 पूंजी	115775	69370	111029	141457	189487	177328
1.2.3 ऋण	1632	1654	1340	1941	2419	31230
1.3 अन्य	55417	68381	79713	83368	91255	95843
2. कुल प्राप्तियां	**4288432**	**4528422**	**5023352**	**5734166**	**6489736**	**7039032**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3132201	3376416	3797731	3851563	3834126	4682025
2.1.1 कर प्राप्तियां	2622145	2978134	3278947	3231582	3175594	3829889
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1652377	1853859	2030050	2012578	2100982	2514708
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	965622	1121189	1246083	1216203	1071552	1311449
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	4146	3086	2814	2800	3060	3732
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	510056	398282	518783	619981	658532	852135
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	33220	34224	36273	31137	39830	33198
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	69063	142433	140287	110094	54861	201138
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	20942	42213	44667	59515	21151	19581
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	48122	100219	95621	50578	33710	181557
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**1064704**	**997097**	**1102729**	**1449230**	**2634928**	**2277532**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	617123	144792	387091	571872	890012	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	195816	-144847	325987	190241	107494	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	429585	844375	710119	868676	1690394	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	689821	794856	795845	971378	1778062	1620936
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	35038	71222	88961	209232	455724	367863
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	45688	42351	51004	38280	47300	45504
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-6436	18423	-18298	10411	-3450	5051
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	17792	25138	66289	-14227	29050	28868
3ख.1.6 नकद शेष	-22463	-12476	17395	-323279	34179	121663
3ख.1.7 अन्य	287268	49653	96014	548753	239540	86132
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	*27.7*	*26.4*	*26.7*	*26.6*	*33.0*	*32.1*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	*27.9*	*26.5*	*26.6*	*28.2*	*32.9*	*31.6*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	*20.3*	*19.8*	*20.1*	*18.9*	*19.4*	*21.0*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	*17.0*	*17.4*	*17.4*	*15.9*	*16.1*	*17.2*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	*6.9*	*5.8*	*5.8*	*7.1*	*13.3*	*10.2*

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बज़ट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अग. 2022 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	760.98	29	1549.15	26	2448.92	9
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	276.68	2	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	460.24	6	835.08	2	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	394.44	3	328.43	1
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	893.51	23	128.47	7
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	351.53	9	-	-	-	-
13	केरल	148.81	4	1008.06	4	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	12.30	7	176.79	23	149.99	13
17	मेघालय	135.10	9	71.60	7	-	-
18	मिज़ोरम	77.42	2	56.70	9	97.53	2
19	नगालैंड	107.08	7	193.02	4	125.12	2
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	862.44	28	-	-	-	-
23	राजस्थान	3104.26	9	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	921.26	30	1154.03	26	301.75	4
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	अग. 2022 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9654	951	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2104	3	0	0
3	असम	3681	72	0	0
4	बिहार	6526	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	5946	0	1	4308
6	गोवा	794	382	0	0
7	गुजरात	8415	559	0	0
8	हरियाणा	1417	1415	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
11	झारखंड	1011	0	0	0
12	कर्नाटक	10699	0	0	40019
13	केरल	2494	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	1066	0	0
15	महाराष्ट्र	54228	1175	0	18000
16	मणिपुर	58	117	0	0
17	मेघालय	910	64	8	0
18	मिज़ोरम	305	55	0	0
19	नगालैंड	1484	39	0	0
20	उड़ीसा	15169	1705	98	43975
21	पुदुचेरी	393	0	0	873
22	पंजाब	4210	0	8	0
23	राजस्थान	0	0	129	4900
24	तमिलनाडु	7797	0	18	5682
25	तेलंगाना	6594	1443	0	0
26	त्रिपुरा	810	15	0	1700
27	उत्तराखंड	3597	0	116	0
28	उत्तरप्रदेश	3991	157	0	0
29	पश्चिम बंगाल	10547	775	239	0
	कुल	**162835**	**9992**	**616**	**119456**

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23						2022-23 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
						जून		जुलाई		अगस्त			
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	50896	41915	46443	36692	10500	9630	8000	7130	7000	6130	36890	32395
2	अरुणाचल प्रदेश	767	767	563	530	-	-	-	-20	-	-	-	-20
3	असम	15030	14230	12753	10753	2000	2000	2000	2000	2400	2400	6400	6400
4	बिहार	27285	24685	28489	24334	-	-	-	-	3000	3000	3000	2250
5	छत्तीसगढ़	13000	10500	4000	913	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	3354	3054	2000	1450	100	100	-	-	-	-150	100	-50
7	गुजरात	44780	33280	31054	13554	4000	2500	4500	3300	3500	2300	12000	5100
8	हरियाणा	30000	25550	30500	20683	8000	5625	4000	2745	3000	2450	18000	11170
9	हिमाचल प्रदेश	6000	3755	4000	1875	-	-430	1000	570	1500	1200	2500	1340
10	जम्मू और कश्मीर	9328	6020	8562	5373	-	-	1250	750	-	-	2250	1750
11	झारखंड	9400	8900	5000	3191	-	-200	-	-	-	-300	-	-500
12	कर्नाटक	69000	61900	59000	49000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	केरल	28566	23066	27000	18120	1500	1500	-	-1000	6000	4000	7500	2500
14	मध्य प्रदेश	45573	38773	22000	13900	2000	2000	-	-	2000	-	4000	2000
15	महाराष्ट्र	69000	50022	68750	40790	10000	3500	-	-1800	-	-1700	30000	17500
16	मणिपुर	1302	1044	1476	1326	150	150	250	190	-	-90	650	425
17	मेघालय	1777	1587	1608	1298	200	200	200	150	200	150	600	500
18	मिज़ोरम	944	677	747	447	100	100	90	90	200	150	540	425
19	नगालैंड	1721	1366	1727	1222	400	400	250	250	226	-24	876	626
20	उड़ीसा	3000	500	0	-6473	-	-1000	-	-	-	-500	-	-3000
21	पुदुचेरी	1390	790	1374	841	-	-	200	200	-	-	200	200
22	पंजाब	32995	23467	25814	12428	-	-1742	5100	4100	6500	5100	14600	8658
23	राजस्थान	57359	44273	51149	38243	6500	3688	5000	4000	5000	4000	20000	14688
24	सिक्किम	1292	1292	1511	1471	-	-	150	150	-	-	150	150
25	तमिलनाडु	87977	76796	87000	72500	8000	6150	8000	6500	11000	9500	27000	21528
26	तेलंगाना	43784	37365	45716	38667	7000	6370	5000	4370	4500	3870	16500	13245
27	त्रिपुरा	1916	1631	300	0	-	-125	-	-	-	-	-	-125
28	उत्तराखंड	75500	59185	62500	42355	-	-2733	-	-1000	2500	1500	2500	-3733
29	उत्तरप्रदेश	6200	5208	3200	1800	-	-	-	-	-	-	-	-
30	पश्चिम बंगाल	59680	50180	67390	45199	5000	4500	8000	6500	1000	-500	16500	8000
	कुल	798816	651777	701626	492483	65450	42183	52990	39175	59526	42486	222756	143422

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि करोड़ में)

मद	2019-20				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**238613.6**	**476724.8**	**386450.4**	**530769.8**	**1632558.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.8*	*9.8*	*7.5*	*10.3*	*8.1*
I. वित्तीय आस्तियां	**398076.7**	**567753.2**	**517351.0**	**924069.3**	**2407250.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*8.1*	*11.7*	*10.1*	*18.0*	*12.0*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	12239.0	296625.6	124015.7	451698.3	884578.5
(ए) बैंक जमाराशि	-10550.9	278124.4	116211.9	444044.6	827830.0
i. वाणिज्यिक बैंक	-13293.8	269475.4	66666.7	446006.7	768855.0
ii. सहकारी बैंक	2742.9	8649.0	49545.2	-1962.1	58975.0
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22789.9	18501.2	7803.7	7653.7	56748.5
2. जीवन बीमा निधियाँ	117873.1	108209.1	110373.8	37714.2	374170.2
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ़ सहित)	104681.1	98426.3	103356.1	193739.0	500202.5
4. मुद्रा	61244.1	-26104.8	86832.6	160690.2	282662.1
5. निवेश	43936.8	43018.8	22655.1	-11953.8	97656.9
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	23303.5	38382.2	19191.1	-19191.1	61685.7
(बी) इक्विटि	18648.2	2172.4	936.2	4981.0	26737.8
6. छोटी बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	57038.5	46514.1	69053.6	91117.2	263723.4
II. वित्तीय देयताएँ	**159463.1**	**91028.5**	**130900.6**	**393299.5**	**774691.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*3.2*	*1.9*	*2.6*	*7.7*	*3.9*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	159429.6	90994.9	130867.1	393266.0	774557.6
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	140261.4	58074.4	114905.9	196581.1	509822.8
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	135754.1	57135.0	87377.4	202214.2	482480.6
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	19168.2	32920.5	15961.2	196684.8	264734.8
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-519.7	22976.7	29930.7	198264.3	250652.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	17033.0	8093.1	-15710.4	-3093.1	6322.6
iii. बीमा कंपनियाँ	2655.0	1850.8	1740.9	1513.6	7760.2
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-1.0

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(जारी..)*

(राशि करोड़ में)

मद	2020-21				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**600422.5**	**573643.2**	**481433.5**	**719844.5**	**2375343.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*15.5*	*12.1*	*8.8*	*12.5*	*12.0*
I. वित्तीय आस्तियां	**805869.5**	**612224.3**	**651241.3**	**1092617.4**	**3161952.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*20.8*	*13.0*	*12.0*	*19.0*	*16.0*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	297412.4	278631.7	158172.2	525550.7	1259767.1
(ए) बैंक जमाराशि	281191.3	264565.3	147096.0	527056.7	1219909.2
i. वाणिज्यिक बैंक	279010.5	262033.7	143558.6	471730.9	1156333.7
ii. सहकारी बैंक	2180.8	2531.6	3537.3	55325.8	63575.6
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	16221.1	14066.4	11076.3	-1506.0	39857.9
2. जीवन बीमा निधियाँ	123291.4	142365.7	156438.6	141120.0	563215.8
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ़ सहित)	119666.9	110916.6	108512.2	207604.5	546700.1
4. मुद्रा	202432.7	21286.9	91456.0	66800.5	381976.1
5. निवेश	6249.8	-12956.4	67659.3	63624.0	124576.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	-16021.0	-28837.7	57675.4	51267.0	64083.8
(बी) इक्विटि	18599.4	8291.5	5307.1	6333.3	38531.2
6. छोटी बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	55760.7	70924.2	67947.4	86862.2	281494.6
II. वित्तीय देयताएँ	**205447.0**	**38581.1**	**169807.8**	**372772.9**	**786608.8**
जीडीपी का प्रतिशत	*5.3*	*0.8*	*3.1*	*6.5*	*4.0*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	205490.3	38624.3	169851.0	372816.9	786782.5
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	211058.8	13213.0	139622.0	284732.6	648626.4
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	211259.3	13213.8	140514.3	242476.0	607463.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-5568.6	25411.3	30229.0	88084.4	138156.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-15450.4	21627.1	15921.2	61326.1	83424.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	10516.6	2875.1	13048.5	25336.1	51776.2
iii. बीमा कंपनियाँ	-634.8	909.2	1259.3	1422.2	2955.9
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.0	134.4
3. सामान्य सरकार	-77.0	-77.0	-77.0	-77.0	-308.0

सं. 50(ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(समाप्त)*

(राशि करोड़ में)

मद	2021-22				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**519781.2**	**358325.2**	**453302.7**	**636259.8**	**1967668.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*10.1*	*6.4*	*7.2*	*9.6*	*8.3*
I. वित्तीय आस्तियां	**382780.7**	**547346.2**	**834009.6**	**796341.7**	**2560478.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*7.5*	*9.7*	*13.2*	*12.0*	*10.8*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	-84377.1	202652.1	425821.4	151374.9	695471.4
(ए) बैंक जमाराशि	-106507.3	197301.2	422819.5	140297.2	653910.7
i. वाणिज्यिक बैंक	-108037.7	195617.4	418642.9	145510.5	651733.1
ii. सहकारी बैंक	1530.4	1683.8	4176.7	-5213.3	2177.6
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22130.2	5350.9	3001.9	11077.7	41560.7
2. जीवन बीमा निधियाँ	114617.8	127356.0	103154.9	95681.7	440810.4
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ़ सहित)	126469.7	108777.0	91543.9	254877.2	581667.9
4. मुद्रा	128660.2	-68631.2	62793.3	146845.0	269667.4
5. निवेश	24929.6	82305.4	69760.9	50980.8	227976.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	14573.0	63151.3	37912.2	44963.7	160600.1
(बी) इक्विटि	4502.5	13218.5	27808.2	3084.1	48613.3
6. छोटी बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	71423.1	93829.6	79877.9	95524.7	340655.3
II. वित्तीय देयताएँ	**-137000.5**	**189021.0**	**380706.9**	**160081.8**	**592809.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*-2.7*	*3.4*	*6.0*	*2.4*	*2.5*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	-137021.8	188999.7	380685.6	160060.6	592724.1
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	-113662.5	134166.1	320160.2	153323.3	493987.0
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	-108061.2	135728.8	317452.5	152364.2	497484.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-23359.3	54833.7	60525.5	6737.3	98737.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-31118.4	28880.1	29479.8	-31016.3	-3774.8
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7132.0	24403.8	29494.8	37436.2	98466.8
iii. बीमा कंपनियाँ	627.1	1549.8	1550.9	317.4	4045.2
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	-12.5	-12.5	-12.5	-12.5	-50.0

टिप्पणियां: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत निवल वित्तीय आस्तियों के प्रवाह को संदर्भित करती है, जो हाउसहोल्ड द्वारा धारित वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन को घटाकर उनकी वित्तीय देयताओं में परिवर्तन को दर्शाती है।
2. छोटी बचत और पीपीएफ में संशोधन मुख्य रूप से लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार के मासिक डेटा से प्राप्त तिमाही आंकड़ों के कारण होता है।
3. 2021-22 के लिए बैंक जमा में संशोधन का श्रेय बीएसआर-2 के अनुसार कुल जमा में हाउसहोल्ड की कम हिस्सेदारी को दिया जाता है।
4. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना 31 जून, 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के अनंतिम अनुमानों के आधार पर की गई है।
5. पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग के बराबर नहीं हो सकते हैं।

सं. 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ में)

मद	जुला.-2019	सितं-2019	दिसं-2019	अप्रै.-2020
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**16315506.3**	**16632816.5**	**17010694.5**	**17180616.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*84.7*	*85.4*	*86.2*	*85.6*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	8858293.4	9136417.9	9252629.8	9696674.3
i. वाणिज्यिक बैंक	8131543.2	8401018.6	8467685.3	8913692.0
ii. सहकारी बैंक	726750.2	735399.2	784944.4	782982.3
(बी) जीवन बीमा निधि	3883609.7	3930727.6	4049902.5	3884771.5
(सी) मुद्रा	2010842.9	1984738.1	2071570.7	2232261.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1404631.5	1412654.1	1468727.6	1197092.9
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**6370092.6**	**6461087.5**	**6591954.6**	**6985220.6**
जीडीपी का प्रतिशत	*33.1*	*33.2*	*33.4*	*34.8*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5148115.0	5206189.4	5321095.3	5517676.4
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	4668496.4	4725631.3	4813008.7	5015222.9
ii. सहकारी बैंक	478956.2	479656.9	506946.6	501074.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1221977.5	1254898.1	1270859.3	1467544.1
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	451922.3	474899.0	504829.7	703094.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673312.1	681405.2	665694.8	662601.7

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(जारी.)*

(राशि करोड़ में)

मद	जुला.-2020	सितं-2020	दिसं-2020	अप्रै.-2021
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**18039169.4**	**18606364.4**	**19333484.1**	**20168953.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*94.9*	*98.6*	*100.8*	*101.9*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	9977865.6	10242430.9	10389526.9	10916583.6
i. वाणिज्यिक बैंक	9192702.5	9454736.2	9598294.8	10070025.7
ii. सहकारी बैंक	785163.1	787694.7	791232.1	846557.9
(बी) जीवन बीमा निधि	4102000.7	4274424.9	4551882.0	4718718.2
(सी) मुद्रा	2434693.7	2455980.6	2547436.6	2614237.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1343752.0	1443784.4	1648999.0	1730461.0
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7190710.8**	**7229335.1**	**7399186.1**	**7772003.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*37.8*	*38.3*	*38.6*	*39.3*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5728735.3	5741948.3	5881570.2	6166302.8
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5226482.2	5239696.0	5380210.4	5622686.4
ii. सहकारी बैंक	500870.2	500865.3	499968.8	542221.2
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1461975.5	1487386.9	1517615.9	1605700.3
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	687643.6	709270.7	725191.9	786518.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673118.3	675993.4	689041.8	714377.9

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(समाप्त)*

(राशि करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

मद	जुला.-2021	सितं-2021	दिसं-2021	अप्रै.-2022
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**20508115.7**	**21057343.4**	**21673261.7**	**22104312.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*97.4*	*95.9*	*95.0*	*93.4*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	10810076.3	11007377.6	11430197.1	11570494.3
i. वाणिज्यिक बैंक	9961988.0	10157605.4	10576248.3	10721758.8
ii. सहकारी बैंक	848088.3	849772.1	853948.8	848735.5
(बी) जीवन बीमा निधि	4894238.5	5105262.1	5175997.5	5287980.3
(सी) मुद्रा	2742897.3	2674266.1	2737059.4	2883904.4
(डी) म्यूचुअल फंड	1855000.1	2064363.5	2126112.0	2152140.5
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7634981.2**	**7823980.9**	**8204666.6**	**8364727.1**
जीडीपी का प्रतिशत	*36.3*	*35.6*	*36.0*	*35.3*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	6052640.2	6186806.3	6506966.5	6660289.7
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5514625.2	5650354.1	5967806.6	6120170.8
ii. सहकारी बैंक	536604.9	535027.3	537720.1	538664.3
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1582341.0	1637174.6	1697700.1	1704437.4
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	755399.6	784279.7	813759.5	782743.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	721510.0	745913.7	775408.5	812844.7

टिप्पणी: 1. डेटा को केवल चुनिंदा वित्तीय लिखतों के लिए संकलित किया गया है(बैंकिंग क्षेत्र, एनबीएफ़सी और एचएफ़सी से ऋण) जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।

2. जीडीपी अनुपात के रूप में डेटा की गणना 28 फरवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान पर आधारित है।

3. हो सकता है कि कॉलम में दिए गए अंकों को पूर्णांकन के कारण कुल योग में न जोड़ा जाए।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्ज़िम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामि ल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थांओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंति म उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकडें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।
2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।
4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।
1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।
2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अतंरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान
1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान
'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओं/शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।
हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का सकेंतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -
   - बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।
   - जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए है, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया हैं।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बज़ट 2020-21 से लिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपार्श्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (**https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618**) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डाटा https://dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2022	₹350 एक प्रति (कांउटर पर) ₹400 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,800 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,600 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,840 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,880 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2021-22 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2021-22	₹575 एक प्रति (कांउटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (कांउटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (कांउटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8 अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (कांउटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (कांउटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 2, 2020	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 42, सं. 1, 2021	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (कांउटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in)।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

@ इलेक्ट्रानिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते है, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेशः

1. बिकी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक सस्थांओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अकं उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मंबुई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का सपंर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेलः spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मंबुई - 400 001।

   एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' **2 महीने के अंदर भेजी जाए**।
7. **कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।**